

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन

खण्ड 1

प्रारम्भिक तथा विकास मॉडल

II Meaning of 'Under-Developed' Country

'कम-विकसित' देश-परिभाषा :

कम विकसित देश जिसे वह सवने है और जिसे हम उन्नत या विकसित देश कह सकते हैं, इसमें अर्थशास्त्रियां में बहुत मतभेद है इस संबंध में हम उचित परिभाषा देने से पहले 'कम-विकसित' होने के माप-दण्ड तथा कुछ प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करें

1 साइमन कुजनेट्स :

कुजनेट्स के अनुसार कम-विकसित देश व विकसित देशों में वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जा सकता है

(1) "प्रथम, 'कम विकसित' देश वे देश हैं जो वर्तमान तकनीकी ज्ञान व जानकारी के अनुरूप वांछित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते " अगर हम इस परिभाषा को मानें तो हर देश कम-विकसित हो जायेगा क्योंकि कोई भी देश क्षमतानुसार उत्पादन नहीं कर पाता

(11) दूसरे, 'कम विकसित देश वे देश हैं जिनमें आर्थिक उन्नति के स्तर किसी अन्य उन्नत देश के स्तर से नीचे हो '

इस परिभाषा के अनुसार केवल एक देश को छोड़कर अन्य समस्त देश कम-विकसित देश हो जायेंगे

(111) तीसरे, 'एक कम विकसित देश वह देश है जो अपने देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को उचित जीवन स्तर प्रदान करने में असफल होता है तथा जिसमें देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को गरीबी व कमी का सामना करना पड़ता है '

कुजनेट्स इस परिभाषा को उचित मानते हैं

2. प्रो. जे. के. मेहता

प्रो. जे. के. मेहता विकसित व कम-विकसित देशों में Biological organic

1. Simon Kuznets : 'Under-developed Countries and the Pre-Industrial phase in the Advanced Countries —an attempt at Comparison. of : A. N. Agarwal and S. P. Singh. Economics of Under-developed Countries.' P. 135-153.

2. J. K. Mehta . Foreword to H. C. Gupta's book on "Problems and Process of Economic policies in under-developed Countries" p. (ii) (iii)

growth (जोवन विकास) के आधार पर वर्गीकृत किया उनका कथन है कि हर जीव या चेतनायुक्त पदार्थ 'उत्पत्ति, विकास, ह्रास तथा अन्त' के क्रम से गुजरता है

'कम विकसित देश एक बच्चे की भाँति हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं परन्तु विकासशील हैं,' जबकि, 'एक विकसित देश अब पूर्ण रूप से विकसित है और विकास नहीं कर रहा है'

उपरोक्त परिभाषा की निश्चित ही आलोचना की जा सकती है क्योंकि यह कहना गलत होगा कि विकसित देश वे हैं जिनमें विकास बन्द हो गया है

अपनी इस परिभाषा के साथ प्रोफेसर मेहता ने दो और मुख्य बातें कही हैं

(1) एक कम विकसित देश हमेशा विकासशील हो नहीं होता कभी-कभी बीच-बीच में विकास रुक सकता है परन्तु 'युवा अस्थिरता का जोश' उस देश को विकास पथ पर अवश्य ले जाएगा

(11) वैसे तो हर विकसित देश स्वैंगिक अवस्था को पहुँच कर समाप्त हो सकता है, परन्तु तकनीकी ज्ञान वृद्धि तथा विज्ञान में उन्नति के कारण यह बुढ़ापा अनिश्चित काल तक टाला जा सकता है

3 B M Niculescuc वी एम निक्यूलेसक्यू :

श्री निक्यूलेसक्यू के अनुसार हर देश के विकास की एक सीमा होती है हर देश U S A की भाँति उन्नत नहीं हो सकता जब तक कोई देश अपने विकास को चरम सीमा तक नहीं पहुँच जाता तब तक वह देश कम विकसित समझा जाना चाहिए और जब वह देश इस सीमा तक पहुँच जाए (चाहे वह U S A के बराबर पहुँच पाए या नहीं) वह विकसित समझा जाना चाहिए उन्होंने कहा

'यह अजीब बात होगी कि एक पूर्ण विकसित व्यक्ति खरगोश को कम-विकसित माना जाए केवल इसलिए कि हाथो उससे बहुत बड़ा होता है'

4 Oskar Lange आसकर लैंग

आसकर लैंग के अनुसार

एक कम विकसित देश वह है जिसमें पूँजी की मात्रा इतनी नहीं है

B M Niculescuc : 'Under-developed, Backward or Low Income
Economic Journal, Sept. 1955 p 546-48.

Oskar Lange : Essays in Economic Planning p. 33.

कि वह वर्तमान श्रमशक्ति का वर्तमान तकनीकी स्तर पर पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता

5 Ragner Nurkse रैगनर नर्कस

नर्कस भी उन दश दो कम विकसित मानते हैं जिनमें प्राकृतिक साधनों व जनशक्ति को पूर्ण उपयोग करने के लिए पूँजी की कमी हो परन्तु वे यह कहते हैं कि "पूँजी विकास के लिए आवश्यक तो है परन्तु उसका होना ही पर्याप्त नहीं होता"

6 Dr Eugene Staley डा० यूजीन स्टैली

कम विकसित देश वे हैं जिनमें व्यापार गरीबी है जो कि किसी अस्थायी सबट के कारण नहीं होती वरून दीर्घस्थायी कारणों में मौजूद रहती है

7-8-9. U N-O, Meier & Baldwin, Benjamin Higgins संयुक्त राष्ट्र, मेयर तथा बाल्डविन, बेन्जामिन हिगिन्स.

इन्होंने कम विकसित देश उन्हें कहा है जो कुछ जाने माने विकसित देश (U. S A कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिमी योरोप व आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड) के अनुपात में कम आय उत्पन्न करते हैं और जहाँ प्रति व्यक्ति आय भी कम है

10 Walter Krause वाल्टर क्रॉज

कम विकसित देश वह हैं जहाँ विकसित देशों के अनुपात में आम जनता के उपभोग व जीवन-आपन के स्तर नीचे हैं

11 Bauer and Yamey . बायर तथा यामे

कम विकसित देश वे हैं जहाँ तकनीकी व वैज्ञानिक उन्नति के फल को कृषि व

Ragner Nurkse : Capital Formation in under-Developed countries p 1.

Eugene Staley The Future of Under-developed countries

U N. O : U N Measures for Economic Development.

Meier & Baldwin Economic Development p 26

Benjamin Higgins Economic Development 4-7

Walter Krause . Economic Development : Wadsworth Co. p 6

1. P.T. Bauer and B S Yamey. The Economics of Under-developed Countries * p. 3.

उद्योगों में बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया गया हो इन देशों में 'जीवन निर्वाह' स्तर पर अधिकांश उत्पादन होता है यहाँ के वातावरण अनुचित होत है औद्योगिक उन्नति सापेक्षिक रूप से महत्वहीन रहती है इन देशों में सम्पूर्ण गणिका पूर्ण एशिया (जापान को छोड़कर) पूर्ण दक्षिणी अमेरिका (अर्जेन्टाइना को छोड़कर) पूर्वी योरोप तथा दक्षिणी योरोप को शामिल कर सकते हैं इस प्रकार में विश्व की तीन चौथाई जनसंख्या इन देशों में रहती है

12 Jacob Viner जैकब वाइनर

यह वे देश होने हैं जहाँ प्राकृतिक साधनों पूँजी व शक्ति का उपयोग करके जनसंख्या का जीवन स्तर ऊँचा किया जा सकता है तथा अगर उस देश का जीवन स्तर ऊँचा हो तो और जनसंख्या को उस देश में बढ़ाया जा सकता है इस प्रकार स वाइनर का आशय है कि कम विकसित देश वे हैं जहाँ प्रतिव्यक्ति आय कम है और बढ़ाई जा सकती है

इस प्रकार से हमने भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन किया। पुस्तक के वर्तमान लेखक एक व्यापक परिभाषा, कम-विकसित देशों की विशेषताओं को अध्ययन करने के पश्चात् उन्हीं विशेषताओं के आधार पर देंगे

III कम विकसित होने के माप दण्ड

Measurement of under-development

1. Low Per-capital Income ? क्या निम्न प्रति व्यक्ति आय कम विकसित होने का मापदण्ड है ?

विश्व में आज विकसित व कम विकसित देशों की आय में बहुत अधिक अन्तर है आज दुनियाँ के 2/3 व्यक्ति 500 रु० वार्षिक से कम पाते हैं

-
2. Jacob Viner : Economics of Development : A. N. Agarwal & S. P. Singh op. cit. p. 9-31.

इस मन्त्र को निम्नलिखित तालिका आधुनिकतम स्थिति दर्शाती है —

देश का वर्गीकरण	प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय आय डालरों में	दश की संख्या	विश्व का प्रतिशत क्षेत्रफल	विश्व की जनसंख्या	विश्व की आय का प्रतिशत
(A) उच्च आय के देश	750 डालर से ऊपर	36	43.6	28.6	82.00
(B) मध्यम श्रेणी आय के देश	300—750	33	8.2	6.5	5.4
(C) कम आय के देश	100—300	53	21.4	14.1	4.8
(D) बहुत कम आय के देश	0—100	36	26.4	50.8	7.8
		158	100.00	100.00	100.00

Economic Times 1 Feb 1968

\$ one = Rs 7.50

अकेले संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका विश्व की 41 प्रतिशत आय का मालिक है जब कि अन्य देशों में यह वितरण इस प्रकार है

U S A	41 %
पश्चिमी योरोप	22 %
U. S S R	11 %
अन्य योरोपीय देश	6 %
दक्षिणी अमेरिका	4 %
अफ्रीका	2 %
एशिया	11 %

1968 में (डालर में)

कुवैत (4000), संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका (3847), स्वीडेन (2801), कनाडा (2686), स्वीटजरलैंड (2519), डेन्मार्क (2340), भारत (70)

1935 में

आय	देश
1200—1500	ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लम्बेम्बर्ग

For 1968 Figures Life 11-November 1968 P 74 80

1965 figures : Kindlebergu op cit

with adjustment on the basis of latest available data in newspapers.

1000—1250	यू० के०, पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी, नार्वे, बेल्जियम, फ्रान्स
800—1000	आइसलैंड, फिनलैंड, नॉरवे, यू एम एम आर
500—800	ऑस्ट्रिया, प्यूरटो रिको, वेनेजुएला, इजराइल, आइरलैंड
500 के लगभग	जापान, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली
350—500	ट्रिनीदाड, होबेगो, मार्टा, जमाइका, पनामा, ग्रीस, साइप्रस
200—300	कोस्टारिका, मेक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल, वारबेडोन, यूगोस्लाविया, कोलम्बिया, ब्रिटिश गियाना, सीरिया, अल्जीरिया, मलाया, मारोको, फिलीपीन्स
150—200	होन्डुरास, टर्की, घाना, एल्सालेबेडार, रोडेशिया, मोटेमाना
100—150	पीरू, इन्डोनेशिया, ट्यूनीसिया, जार्जन, ब्राजील, लका, फारमोसा, मोरक्को, परागुए
75—100	मूडान, थाईलैंड, वेन्या
0—75	भारत, कांगो, नाइजीरिया, युगांडा, पाकिस्तान, बर्मा, इन्डोनेशिया व अन्य समस्त देश

क्या प्रति-व्यक्ति आय विकास या कम विकास की निशानी है ?

Benjamin Higgine ने 500 डालर से कम प्रतिव्यक्ति आय पाने वाले देशों को कम विकसित माना है जबकि W W. Rostow ने 200 डालर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम आय वाले देशों को कम विकसित देश माना है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय अवश्य ही भिन्न-भिन्न देशों की उन्नति की अवस्था का मापदण्ड है परन्तु हमको इसमें अनावश्यक रूप में व्यापक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए (We sold not read too much between lines) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निम्नलिखित कारणों से सापेक्षिक तुलना का सही मापदण्ड नहीं होती

- (1) कम विकसित देशों में देश के बड़े भाग में बहुधा 'Nonmonetized transaction' या बदला बदली सौदे होते हैं इस कारण राष्ट्रीय आय जितनी होती है उससे कम आंकी जाती है
- (11) ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से उत्पादनकर्ता स्वयं अपनी वस्तुओं के उपभोगकर्ता होते हैं इस कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुयें राष्ट्रीय आय में आंकी नहीं जाती, और राष्ट्रीय आय कम आंकी जाती है

- (iii) इन देशों में शिफ्टा की कमी के कारण बहुत में बृष्क व छोटे उत्पादन वर्ता Input output का हिसाब नहो रख पाते उसी प्रकार में व विसावट (Depreciation) का हिसाब नही रखते
- (iv) सबसे प्रमुख बात तो इस सब में यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तुलना इसलिए बठिन हो जाती है कि विश्व के भिन्न-भिन्न देशों की विदेशी विनिमय दरें आन्तरिक मूल्य स्तरों के अनुकूल नहीं होती अगर समस्त देशों की विदेशी विनिमय दरें Fluid होती या लचीली होती तो वास्तविक स्थिति को दर्शाती
- (v) कई देशों में (जैसे कुवैत) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तो अधिक है परन्तु अन्य हर दृष्टिकोण में वे कम विकसित हैं
- (vi) भिन्न-भिन्न देशों में राष्ट्रीय आय आकने की अलग अलग सांख्यिकीय पद्धतियाँ होती हैं कम विकसित देशों में बहुत त्रुटियाँ भी होती हैं
- (vii) कम विकसित देशों में कुछ लोग करो में बचने के लिए उत्पादन व आय छिपा जाते हैं
- (viii) Max Millikan का कथन है कि 1950 में जहाँ एशिया के भिन्न-भिन्न देशों की राष्ट्रीय आय प्रतिव्यक्ति 58 डालर आकी गई थी वास्तव में 200 डालर रही होगी और Hagan का कथन है कि बर्मा की राष्ट्रीय आय लगभग 300% से कम आकी गई
- (ix) इन देशों में बहुत सा श्रम बगैर वेतन के कार्य करता है (जैसे स्वयं का मकान बनाना या परिवार के सदस्यों द्वारा ही कार्य करना) इससे भी राष्ट्रीय आय के अनुमान कम रहते हैं

इस सब कठिनाइयों के होते हुए भी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आँकड़े सापेक्षिक विकास की स्थिति को जानने के लिए अत्यन्त सहायक होने हैं Boitinski (बोईटिन्सकी) का कथन है कि किसी देश के समस्त भागों में द्रव्य की क्रय-शक्ति एक तो नहीं होती है फिर भी हम एक ही प्रति व्यक्ति आय की दर निकाल लेते हैं उसी प्रकार से विश्व की भी हम एक देश मानकर एक ही मुद्रा में प्रति व्यक्ति आय निकाल कर तुलना कर सकते हैं परन्तु फिर भी यह पूर्ण सही माप-दण्ड नहीं है

- 2 Is low rate of growth a sign of under-development ? क्या विकास की नीची दर कम-विकसित होने की निशानी है ?
- कम विकास की दर को हम कम-विकसित देश होने से सम्बन्धित नहो कर सकते

निम्न तालिका में हम 1962-67 के बीच भिन्न-भिन्न देशों की विकास की दर दर्शाते हैं। इस तालिका से जाहिर होगा कि स्वीटजरलैंड, जर्मनी, यू.के., डेन्मार्क, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस तथा यू.एस.ए. जैसे देश भी कम-विकसित कहलायेंगे जो सर्वथा अनुचित है।

1962-67

देश	प्रति वर्ष विकास दर	देश	प्रति वर्ष विकास दर
जापान	8.5	स्वीडन	3.4
फारमोसा	7.5	कनाडा	3.4
ग्रीस	6.7	ऑस्ट्रिया	3.4
द० कोरिया	6.3	पाकिस्तान	3.3
स्पेन	5.7	बेल्जियम	3.2
इरान	4.7	इजराइल	3.0
थाइलैंड	4.7	मलेशिया	3.0
द० अफ्रीका	4.3	डेन्मार्क	3.0
नार्वे	4.2	यू.के.	2.2
टर्की	4.1	प० जर्मनी	2.2
नीदरलैंड (हालैंड)	4.0	चिली	2.1
इटली	3.8	स्वीटजरलैंड	2.1
फ्रांस	3.7	वनेजुएला	1.5
यू.एस.ए.	3.5	भारत	1.2
मक्सिको	3.4	अर्जेंटीना	1.1
थाइलैंड	3.4	ब्राजील	0.5

इसलिए हम कम-विकास दर को कम-विकसित देश की निशानी नहीं मान सकते।
 'The decisive factor is not the speed but the distance already covered by an economy' (1)

For these latest figures See Life Nov, 1968 p /4

(1) See Miss Ishrat Husain Economic factors in Economic Growth Ch, I,

- 3 Are Poor natural resources an index of under-development ? क्या प्राकृतिक साधनों की निर्धनता कम-विकसित होने की निशानी है ?

इस दृष्टिकोण को भी हम नहीं अपना सकने अफ्रीका के देश, भारत तथा प्राचीन प्राकृतिक साधनों में भण्डार देश हैं परन्तु वे देश आस्ट्रेलिया तथा इजरायल के मुकाबले में कम-विकसित हैं जापान भी एक ऐसा देश है जिसने बगैर किसी महत्वपूर्ण उच्च मात्र की उपनिवेश के प्रत्यक्ष संपर्क से विकास किया है मानव का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है

- 4 Is lack of capital or low capital ratio to per head of population an index of under-development ? क्या प्रतिव्यक्ति पूँजी की मात्रा का निम्न अनुपात कम विकसित होने का माप देता है ?

यह निश्चित रूप से नहीं है कि जहाँ प्रति व्यक्ति पूँजी अधिक होगी वह देश शीघ्र विकसित हो जाएगा परन्तु पूँजी विद्या के लिए आवश्यक अवस्था है परन्तु उसके होने से ही विकास नहीं हो जाता है आज अगर कम विकसित देशों को सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बराबर पूँजी दी जाती तो यह देश उस देश के बराबर नहीं हो जायेंगे जैसे कि प्रो० नक्स ने कहा है 'Economic development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions and historical accidents Capital is a necessary but not a sufficient condition of progress.' अर्थात् विकास मानव क्षमता पर, सामाजिक मनोवृत्ति तथा राजनैतिक स्थितियों और आकस्मिक ऐतिहासिक योग पर निर्भर करता है

5. Is age of a country an indication of underdevelopment ? क्या देश की 'आयु' विकास से सम्बन्धित होती है ?

मन अध्ययनकर्ता इस प्रश्न को नहीं मानने अन्यथा जहाँ भारत, चीन व मिस्र को विकसित माना जाएगा वहाँ सयुक्त राष्ट्र अमेरिका कम विकसित देश होगा यह बात सर्वथा अमान्य है

6. Is degree of industrialization an index of development ? क्या कम औद्योगिक होना कम विकसित होने की निशानी है ?

इसको भी हम कम विकसित होने का आधार नहीं मान सकते न्यूजीलैंड, डेनमार्क तथा आस्ट्रेलिया में “प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन से औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन कम रहता है,” परन्तु यह देश निश्चित ही विकसित हैं जापान में तथा इजराइल में उपरोक्त देशों में अधिक उद्योग है पर वे उपरोक्त देशों के अनुपात में प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम पाते हैं. इसलिए यह आधार भी उपयुक्त नहीं है

7 Is low ratio of income from export to national income an index of under-development ? क्या निर्यात का कुल आय का कम अनुपात में होना कम-विकसित देश की निशानी है ?

यह कहा जाता है कि कम-विकसित देशों के निर्यात कुल राष्ट्रीय आय का बहुत कम अनुपात होता है, जबकि विकसित देश निर्यात से राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग प्राप्त कर लेते हैं

परन्तु यह आधार भी सर्वमान्य नहीं हो सकता क्योंकि वेनेजुएला तो अपनी राष्ट्रीय आय का 90 प्रतिशत भाग पेट्रोल के निर्यात से प्राप्त करता है कांगो तथा चिली भी निर्यात में बहुत भाग प्राप्त करते हैं, परन्तु देश कम विकसित हैं

8. Is high density of population an index of under-development ? क्या जनसंख्या का अधिक घनत्व कम विकसित देश की निशानी है ?

बहुधा यह कहा जाता है कि कम विकसित देश वे हैं जहाँ (i) जन्म व मृत्यु दर अधिक है तथा (ii) जहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है परन्तु यह मापदण्ड नहीं माना जा सकता बहुधा कई कम विकसित देशों में जन्म दर अधिक नहीं है, और कई कम विकसित देशों में घनत्व की कमी है (जैसे अफ्रीका में)

कुल मिलाकर कम विकसित देशों का मापदण्ड हम इन सब मापदण्डों को मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं. कम विकसित देशों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उन्नत देशों के अनुपात में कम होती है तथा साथ ही यहाँ बहुधा (i) प्रति व्यक्ति पूँजी संचय कम होता है (ii) जन्म व मृत्यु दरें अधिक रहती हैं (iii) प्राथमिक उद्योगों में अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं, (iv) औद्योगीकरण कम रहता है (v) तथा प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा होता है.

IV Economic Growth vrs Development.

आर्थिक वृद्धि व विकास

अंग्रेजी पुस्तकों में 'Economic Growth' तथा 'Economic Development' में अन्तर किया जाता है—हानाँकि दोनों शब्द पर्यायवाची शब्दों की तरह में ही प्रयोग में लाए जाते हैं हिन्दी में 'आर्थिक विकास' शब्द चल पड़ा है और ऐसे अंतर का प्रश्न नहीं उठता है फिर भी हम अंग्रेजी भाषा में जो Economic Growth तथा Economic Development में अन्तर निकाला जाता है उसका अध्ययन करेंगे

Joseph Schumpeter जोसेफ शम्पीटर

जोसेफ शम्पीटर सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हम बीसवीं सदी में विकास पर महत्वपूर्ण विचार दिए वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने Growth व Development में अन्तर निकाले शम्पीटर का मकसद है कि जो उन्नति धीरे-धीरे Data (या जाने माने तत्वों) के परिवर्तनों के कारण होती है वह Growth हुई जैसे अगर अगले वर्ष में 2 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ती है और इसके कारण 2% उत्पादन बढ़े तो यह Growth हुई परन्तु जब साहसी अपनी क्रियाओं द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाते हैं तो वह अर्थ व्यवस्था को सक्षमक वृद्धि ही नहीं करते वरन् अर्थ व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन ला देते हैं उनके अनुसार "अगर एक छोटी फुटकर विक्री की दुकान धीरे-धीरे एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में परिणत हो जाती है तो यह Growth हुई विकास तो केवल क्रान्तिकारी (Revolutionary) तथा अविरल (Discontinuous) परिवर्तनों में होता है"

शम्पीटर के अनुसार Development, Growth से अधिक महत्वपूर्ण होता है

C P Kindleberger : सी पी किण्डलबेर्जर

किण्डलबेर्जर भी Development को Growth में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं उनका मकसद है कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी देश में Growth तो हो सकती है परन्तु Development हो ही न रहा हो Growth का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होना है जबकि Development का अर्थ न केवल

Joseph Schumpeter के विचारों के लिए उनका माहल देखिए

C P Kindleberger ; Economic Development p 1 & 15

उत्पादन में वृद्धि से होता है वरन् उसका अर्थ यह भी होता है कि इस अतिरिक्त उत्पादन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी व सत्यागत परिवर्तन भी हो रहे हैं

इस प्रकार से Growth का अर्थ आय में वृद्धि होता है और Development का अर्थ संरचना व उत्पादन परिवर्तनों से होता है फिर भी Growth से ही Development नापा जाता है

'Economic growth is generally thought of as unidimensional and is measured by increases in income. Economic development involves as well structural and the functional changes. In the absence of effective measures of the latter, however, states of development are estimated by levels of income and the rates of development by the growth of income'

Mrs Ursula Hicks श्रीमती उर्सुला हिक्स :

श्रीमती हिक्स का कथन है कि Growth विकसित देशों की समस्या है, जबकि Development कम-विकसित देशों की समस्या है। विकसित देशों में साधनों का लगभग पता लग चुका होता है उनका प्रयोग भी लगभग पूर्ण रहता है, जबकि कम विकसित देशों में इन साधनों का प्रयोग करना ही मुख्य कार्य होता है

Everyman's Dictionary :

सामान्यतया Economic Development का अर्थ Economic Growth ही होता है परन्तु Growth में हम प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन नापते हैं, तो Economic Development में हम उन समस्त आर्थिक, सामाजिक व अन्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो स्वयं Growth लाते हैं

Growth नापी जा सकती है तथा यह पूँजी या थम शक्ति व्यापार व उपभोग में वृद्धि नापती है, जबकि Development हम उसे कहेंगे सामाजिक तकनीकी व अन्य वे समस्त घटकों के परिवर्तन जो Growth लाते हैं, नापने हैं

Meier and Baldwin भीयर तथा बाल्डविन

भीयर तथा बाल्डविन Growth व Development को पर्यायवाची शब्द ही मानते हैं परन्तु वे Development उन परिवर्तनों को मानते हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में आते हैं उनके अनुसार ऐसे तो हर व्यापार-वक्र में आय में परिवर्तन हो जाते हैं परन्तु Economic Development के अन्तर्गत हम कम से कम 25 वर्षों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं Economic Development के अन्तर्गत हम प्राकृतिक साधनों, पूँजी निर्माण, जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी उन्नति कार्यकुशलता व संगठन में होने वाले समस्त परिवर्तनों का अध्ययन कर लेते हैं

“The course of economic development is not a story; it is a plot, and we should discover the interconnections” अर्थात् हमारे विकास के भिन्न भिन्न घटकों का सहसंबंध का अध्ययन Economic Development का अध्ययन हुआ जबकि राष्ट्रीय आय में परिवर्तनों में अध्ययन Growth हुआ

भीयर तथा बाल्डविन व कुजनेट्स वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि को विकास की निशानी मानते हैं जबकि Jacob Viner जेकब वाइनर तथा H. F. Williamson एच एफ विलियमसन प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने को विकास की निशानी मानते हैं

प्रथम अर्थशास्त्रियों का कथन है कि अगर राष्ट्रीय वृद्धि के साथ जनसंख्या की वृद्धि में समानता हो जाती है तो यह कहना मलत होगा कि विकास हुआ ही नहीं परन्तु वर्तमान लेखक के मत में Viner तथा Williamson की विचारधारा अधिक उपयुक्त है इनका कथन है कि जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती और उन व्यक्तियों की कुल संख्या कम नहीं होती जो कि एक सीमा से नीचा जीवन-स्तर व्यतीत कर रहे हैं, हम विकास नहीं मान सकते

1. Meier & Baldwin : op cit : ch I

2. Viner : op cit p 15

3. Williamson : ch I of Economic Development Principles and Patterns : Introduction . Ed williamson Buterlick.

अध्याय : 2

कम-विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of Under-developed Countries

भाग (1)

- 1 निम्न प्रतिशत आय (प्रथम अध्याय में उल्लेख हो गया)
- 2 पिछड़ी कृषि-रोपण अर्थव्यवस्था
- 3 जनमरण संबंधी पिछड़ी अर्थव्यवस्था :
 - (1) कम-विकसित देशों की जनसंख्या सबसे अधिक है
 - (2) कम विकसित देशों में जन्मदर का अविश्व होना कारणों का विरलेपण
 - (3) कम-विकसित देशों में मृत्यु दर की अधिकता
 - (4) उच्च जन्म व मृत्यु दरों व आर्थिक वरवादी
 - (5) कम-विकसित देशों में जनसंख्या के शिक्षा स्तर
 - (6) कम-विकसित देशों में असंतुलित आहार, व निम्न आय
 - (7) कम-विकसित देशों में जनसंख्या का व्यवसायिक अनुपात
 - (8) कम-विकसित देशों में घनत्व की समस्या
 - (9) आशावादी व निराशावादी विचारधाराएँ
- 4 कम विकसित देशों में कम बचतों व कम पूँजी निर्माण का दुष्प्रभाव, कम बचतों के कारण पूँजी निर्माण और दुष्प्रभाव पूर्ण पक्ष व माँग पक्ष
- 5 कम विकसित देश व बेरोजगारी;
 - (i) बेरोजगारी के अनुमान
 - (ii) कम-विकसित देश व अर्ध बेरोजगारी
 - (iii) छद्म बेरोजगारी
 - (iv) कम-विकसित देशों में "उन्नति काल की बेरोजगारी"
 - (v) सरचना संबंधी बेरोजगारी
 - (vi) कम-विकसित देशों में मौसमी बेरोजगारी
 - (vii) शिक्षित लोगो की बेरोजगारी
 - (viii) मौसमी व अन्य बेरोजगारी

कम विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of Under-developed Countries

- I निम्न प्रति व्यक्ति आय उसका उल्लेख प्रथम अध्याय में हो चुका है
- II Backward Agriculture रिछड़ी कृषि-रोपण अर्थ-व्यवस्था

कम-विकसित देशों में कृषि ही मुख्य उत्पादन का जरिया तथा कृषि ही मुख्य रोजगार प्रदान करने वाला व्यवसाय होती है जहाँ विकसित देशों में 15 से 25 प्रतिशत व्यक्ति ही कृषि में कार्यरत रहते हैं वहाँ कम विकसित देशों से यह प्रतिशत 65 से 95 तक पाई जाती है फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जहाँ विकसित देशों में दस में से एक या दो व्यक्ति कृषि करके स्वयं व अन्य को अच्छा खाना दे सकते हैं वहाँ 10 में से 7 या 8 व्यक्ति भी अपनी खाद्यान्न सब्धी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते जहाँ 1840 में U S A. में दो कृषक एक अन्य व्यक्ति के लिए और पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न कर देते थे. आज 15 अन्य व्यक्तियों के लिए उत्पादन कर सकते हैं

कृषि सब्धी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार होती हैं —

- (1) कृषि क्षेत्र में भूमि पर कार्यरत व्यक्ति निरपेक्ष रूप से आवश्यकता से अधिक होते हैं अर्थात् बहुतों की सीमान्त उत्पादकता शून्य रहती है खेतों पर कार्यरत कुछ व्यक्तियों को हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन में अन्तर नहीं आएगा
(आगे बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी संबंधी विशेषता देखिए)
- (II) कृषि-क्षेत्र के अधिकांश व्यक्ति बहुत कम पूँजी से कार्य करते हैं, बहुत कम आय प्राप्त करते हैं तथा उनकी बचतें व पूँजी निर्माण बहुत ही कम रहती है
- (III) देश में सर्वाधिक कृषि-उत्पन्न दालों व सब्जियों की ही होती है तथा जनता का अधिकांश व्यय भी इसी पर होता है

(iv) अधिकांश निर्यात भी कच्चे माल का होता है क्योंकि औद्योगिक उन्नति कम रहती है

(v) कृषि में एक तो पूँजी भी कम होती है दूसरे जो भी पूँजी होती है उसका भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे रहने के कारण पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता

(vi) कृषि में पिछड़ी तकनीक, पुराने बिस्म के औजार तथा बहुत ही सीमित मात्रा में अच्छे औजारों का प्रयोग किया जाता है जहाँ स्वीटजरलैंड में प्रति 1000 हेक्टर 85 ट्रैक्टर हैं (प० जर्मनी 81, नीदरलैंड 45, यू० के० 60) वहीं टर्की में केवल 2 हैं U S A में प्रति 115 व्यक्ति पर एक ट्रैक्टर है, जबकि भारत में प्रति 21000 व्यक्ति व इन्डोनेशिया में प्रति 2,70,000 व्यक्ति पर एक ट्रैक्टर है

(vii) कृषि क्षेत्र के पास खान्दानों को संचित रखने तथा उपज के लिए यातायात के साधनों की नितान्त कमी रहती है कृषि उपज को विपणन करने की सुविधाएँ भी कम रहती हैं बीच के मध्यस्थ लोग कृषि की उपज को किमानों से खरीदने व बेचने में शोषण करते हैं

(viii) कृषि को साख का नितान्त अभाव रहता है बैंकों से सहायता राशियाँ मिलती ही नहीं हैं दीर्घकालीन विनियोजन कार्यों के लिए भी धन की कमी रहती है देशी बैंक उधारी क्या देते हैं सम्पूर्ण कृषि-क्रियाओं को गिरवी रख लेते हैं

(ix) देश में भूचरण होता रहता है, वन सम्पत्ति का अनकूततम प्रयोग नहीं हो पाता तथा खाद व उर्वरक का बहुत कम प्रयोग हो पाता है जहाँ नीदरलैंड में प्रति हेक्टर 500 पौंड उर्वरक प्रयोग हो पाता है, या जर्मनी, यू० के० व अन्य स्थानों पर लगभग 200 300 पौंड प्रयोग में आता है प्रयोग होता है भारत में यह केवल 3 पौंड है या टर्की में केवल 1 पौंड

(x) कृषक बहुत अधिक ऋणग्रस्त रहते हैं

References : Meier & Baldwin, Benjamin Higgner Leibenstein, H W. Singer, W. A. Lewis, Kindleberger, Bauer & Yamey, D B Singh, D. S Nag, I Z Hussain, U N Publications, तथा अन्य references के लिए पुस्तक के दूसरे भाग में कृषि संबंधी अध्याय देखिए

- (XI) कम विकसित देशों में भू-नियम अत्यन्त घुटिपूर्ण होते हैं वड़े किसानों जमींदारों के पास बहुत सारा होता है जबकि असह्य कृषक भूमिहीन मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं
- (XII) समस्त कृषि क्षेत्र सदियों में स्थगित अवस्था में पड़ा है यहाँ के लोग पुरानी आस्थाओं, मान्यताओं, अवधारणाओं, रीति-रिवाजों आदि में फस रहे हैं
- (XIII) कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम रहती है विकसित देशों के मुकाबले में कम विकसित देशों में उपज प्रति एकड़ केवल 1/10 से 1/4 भाग ही रहती है भारत में ही फार्म उत्पादकता लकड़ा, जावा, मिला की केवल आधी तथा बाजोल की 1/7 भाग ही है
- (XIV) संक्षेप में कम विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में रत व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति उपज बहुत कम होती है, यर्थात् उत्तरी अमेरिका व योरोप में प्रति व्यक्ति कृषि उपज 10 से 20 गुनी अधिक रहती है जहाँ विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कृषि उपज लगभग 2½ से 3 टन है वहाँ एशिया में यह केवल 1/4 टन है व अफ्रीका में केवल 1/7 टन ही है

कम विकसित देशों में कृषि भी व्यापार चक्रों से व्याप्त रहती है बहुधा इन देशों में कृषि मौसम की मेहरबानी पर निर्भर रहती है इसीलिए Umbreit, Hunt तथा Kinter का बयान है कि कम-विकसित देशों में कृषि "Prince to pauper and pauper to prince cycles" से व्याप्त रहती है (अर्थात् आज के राजकुमार कल भिखारी, या आज के भिखारी कल राजकुमार बन जाते हैं)

कम विकसित देशों में कृषि कई बेरोजगारी स्थितियों का शिकार रहती है (1) कृषि की खेती योग्य भूमि की पूर्ति बेरोजगारी रहती है (2) कृषि की उपज की मांग वृद्धि के उपरान्त कृषि उपज की पूर्ति में अनुपातिक वृद्धि नहीं होती अर्थात् कृषि पूर्ति, मांग व मूल्य वृद्धि के उपरान्त भी नहीं बढ़ती (3) कृषि-क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की पूर्ति भी बेरोजगारी होती है अर्थात् कृषि क्षेत्र में लगे बहुत से श्रमिक अर्ध-बेरोजगारी व कम आय होते हुए भी इसी काम में लगे रहते हैं और दूसरे स्थानों की गणितीय नहीं होते

इसलिए कम-विकसित देशों में विकास के लिए कृषि की उन्नति सर्वप्रथम आवश्यक होती है

III Demographic Characteristics Of Under-developed Countries. कम-विकसित देशों की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ :-

1 प्रस्तावना :

यह स्पष्ट होना चाहिए कि कम-विकसित देशों में जनसंख्या-वृद्धि की दर अधिक होती है और इन देशों में जनसंख्या भी अधिक रहती है, परन्तु यह बात ध्यान रखनी है कि कम-विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दरें विकसित देशों में अधिक होती हैं, परन्तु यद्यपि जनसंख्या-वृद्धि दर विकसित देशों में अधिक नहीं रहती क्योंकि वहाँ जन्म दरें कम होती हैं और मृत्यु दरें भी कम होती हैं।

इस कम-विकसित व विकसित देशों में जनसंख्या में आसपास व वृद्धि दर को निम्नलिखित तालिका में अध्ययन कर सकते हैं।

साल 1925, 1950 वर्ष पहले केवल एक वर्ष के लिए दिया गया है।

Population in (Million) (साल लाख में)

	1650	1750	1850	1900	1950	1955
विश्व	470	694	1094	1550	2500	2690
अफ्रीका	100	100	100	120	199	216
उत्तरी अमेरिका	1	1	26	81	168	183
दक्षिणी अमेरिका	7	10	33	63	163	182
एशिया (संघों छोड़)	257	437	657	857	1380	1490
जपान	23	32	32	45	84	90
ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड			5	5	10	11
यूरोप	103	144	274	423	574	606

U. N. Population Bulletin no. 1

विश्व में	1650 — 1850 के बीच	4%	प्रतिवर्ष वृद्धि
" "	1850 — 1900	" "	7%
" "	1900 — 1950	" "	9%

1920-1950

इन वर्षों के बीच विश्व की जनसंख्या	9	प्रतिशत	प्रतिवर्ष बढ़ी
अफ्रीका की	13	"	" "
उत्तरी अमेरिका की	13	"	" "
दक्षिणी " "	1.9	"	" "
एशिया की	.8	"	" "
जापान की	1.4	"	" "
यूरोप की	6	"	" "
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की	1.4	"	" "

2 कम विकसित देशों में जन्म दर का अधिक होना :

कम विकसित देशों में जन्म दर निश्चित ही विकसित देशों के मुकाबले में अधिक होती है 1961 में विश्व के भिन्न-भिन्न देशों में जन्म दर इस प्रकार रही - यह जन्म दर प्रति-हजार व्यक्ति की गई है.

14. स्वीडन

15-20 लक्जम्बर्ग, जापान, बेल्जियम, डेनमार्क, नार्वे, यू. के, प. जर्मनी, फ्रान्स, फिन्लैंड, आस्ट्रिया, इटली, ग्रीस,

20-25. स्पेन, आइरलैंड, नीदरलैंड, भारत, अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, यू. एस. ए. रूस, पुर्तगाल.

30-35. पीरू, चिली, पुर्टो रिको

35-40. थाइलैंड, लक्सा, फारमोसा

40-45. आर्डन, मलाया, ब्रिटिश गुयाना, जमाइका, पनामा, कोस्टारिका, कोलम्बिया, होन्डुरास, ट्यूनीशिया,

45-50. इक्वेडोर, एल. सेल्वेडोर, मेक्सिको, वेनेजुएला, भियेटनाम.

56. घाना.

60. नाइजीरिया.

60 प्रति हजार से ऊपर जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यह पुनरुत्पादन की अधिकतम जीव विज्ञान संबंधी सीमा है

इन देशों में जन्म दर अधिक होने के निम्नलिखित कारण होते हैं

- (1) इन देशों में बहुधा विवाह कम आयु में कर दिया जाता है जहाँ विकसित देशों में बच्चे पैदा करने की आयु (15-55) में बहुधा 10-15 वर्ष गैर शादी शुदा स्थिति में निकाल देते हैं परन्तु कम विकसित देशों में प्रजनन शक्ति की पूरी आयु बच्चे पैदा करने के प्रयोग में आ जाती है
- (ii) इन देशों में शिक्षा की कमी, झूठी शर्म की भावना, धनाभाव, झूठी धर्मान्यता आदि के कारण परिवार नियोजन की रीतियाँ कम अपनाई जाती हैं बहुत से गरीब व्यक्ति इस सब में अधिक जानकारी भी नहीं रखते
- (iii) इन देशों में भी राज्य ने हाथ के वर्षों में ही परिवार नियोजन प्रसार करना शुरू किया है और आपरेशन व दवाओं तथा अन्य उपकरणों की सुविधा दी है जनता में इस सब में जागरूकता भी नहीं है
- (iv) कुछ Biological facts भी ऐसे हैं जो अधिक जन्म को उत्पन्न करते हैं जैसे
 - (a) इन देशों में गरीब जनता अधिक रहती है और वे अच्छे किस्म का भोजन प्राप्त नहीं करते जिन व्यक्तियों को उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता उनके जिगर कमजोर रहते हैं जिससे शरीर के जो estrogens रहते हैं वे neutralize नहीं होते और उनकी अधिकता से प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है
 - (b) गरीब लोगों की मनोरंजन के साधनों की कमी के कारण भी "यौनिक क्रिया" ही मनोरंजन के साधन रह जाते हैं इससे वे अधिक बच्चे पैदा कर लेते हैं
- (v) इन देशों में मृत्युदर भी अधिक रहती है इससे बहुत देशों में बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं और इसी कारण गरीबों को अधिक बच्चे पैदा करना पड़ता है
- (vi) भारत जैसे कम-विकसित देश में हर स्त्री लड़का पैदा करना जीवन की 'साध' मानती है इस कारण अगर कहीं लड़कियाँ अधिक होती हैं तो लड़के की चाह में और बच्चे पैदा करते जाते हैं
- (vii) इन देशों में puberty (लड़कियों के मासिक धर्म शुरू होने की आयु) कम होती है क्योंकि यह उष्ण देश है इसलिए बच्चे भी अधिक होते हैं

3 कम विकसित देशों में मृत्युदर की अधिकता होना •

कम-विकसित देशों में मृत्युदर भी अधिक रहती है जहाँ विकसित देशों में 5 से 10 प्रति हजार व्यक्ति वर्ष में मरते हैं वहाँ कम-विकसित देशों में यह प्रतिशत 15 से 23 प्रति हजार प्रति वर्ष तक होती है

निम्नलिखित में हम सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं

5 से 8 प्रति हजार प्रति वर्ष → फारमोसा, इजराइल, जार्डन, फिलीपीन्स, ग्रीस
→ जापान, ट्रिनिडाड टोबैगो, आइसलैंड, नीदरलैंड,
कनाडा

8—12 „ „ → स्पेन, बूगोस्लाविया, फ्रिंश, गुयाना, लक्सा, जमाइका, मॉन्ट, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, इटली, ग्वाया, डेनमार्क, स्वीटजरलैंड, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, स्वीडेन, मेक्सिको, पुर्तगाल, फ्रांस

11—14 „ „ „ → पश्चिमी जर्मनी, पोल, कोलम्बिया, लक्जेंबर्ग, बेल्जियम, यू के, ऑस्ट्रेलिया, आइरलैंड

14—17 „ „ „ → इक्वेडोर, वेनेजुएला

17 से ऊपर „ „ „ → बर्मा (19), भारत (20), टर्की (20), घाना (23), नाइजीरिया (20)

इन देशों में मृत्युदर अधिक होने के निम्नलिखित कारण होते हैं इन देशों में अधिकतर जनसंख्या को सतुलित आहार नहीं मिलता जिसके कारण इनके शरीर में बीमारी को न आने देने और उसने लड़ने की क्षमता कम होती है इससे इन देशों में प्रति डॉक्टर पर हजारों मरीज निर्भर रहते हैं जिसके कारण इलाज में समुचित ध्यान नहीं मिलता, तीसरे गरीबी के कारण अधिकतर गरीब जनता अच्छा व पूरा इलाज नहीं कर पाती, चौथे इन देशों में जनसाधारण के रहन-सहन के स्तर तथा सफाई के स्तर बहुत गिरे रहते हैं जिससे वातावरण बीमारो युक्त रहता है पाचवें इन देशों की बहुत बड़ी जनता शिक्षा के कारण रोगों के प्रति अवहेलना करती है और बाद में वात ग्रस्त हो जाती है छठे बहुत से बच्चे व माताएँ प्रसव काल में मर जाती हैं या असतुलित आहार के कारण मर जाती हैं, सातवें इन देशों में महामारियों के प्रकोप से भी लोग मर जाते हैं

4 ऊँची जन्म व मृत्यु दरें व आर्थिक बरबादी .

(1) ऊँची जन्म व मृत्युदरों के रहने से जनसंख्या भले ही तीव्र गति से न बढ़ती हो परन्तु इससे पूँजी निर्माण रुकता है जब बच्चे होने के परचात् युवा-अवस्था में पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं तो वे केवल उपभोक्ता के रूप में ही जिन्दा रहकर मर जाते हैं और स्वयं उत्पादन में योगदान नहीं दे पाते इससे देश में बचतें कम होती हैं और पूँजी निर्माण भी कम रहता है

(2) कम-विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दर दोनों का घटाने के प्रयत्न जब किए जाते हैं तो पहले मृत्यु दर घट जाती है चाहे से ही प्रयत्नों से मृत्यु दर आधी गिर जाती है जब कि जन्म दर इतनी तीव्रता से नहीं घटती यह सक्रामक फल होता है ('Transition period') और इसमें कम-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की समस्या और गम्भीर हो जाती है

(3) इसकी अन्य हानियाँ यह होती हैं कि देश में उन्नत तकनीक नहीं अपनाई जा सकती अधिकांश जनता अशिक्षित रहती है

(4) देश में बेरोजगारी तथा अर्ध-बेरोजगारी की समस्या भी गम्भीर बनी रहती है

(5) देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के स्तर निम्न बने रहते हैं

5 कम-विकसित देशों में जनसंख्या के शिक्षा स्तर

आज विकसित देशों में केवल 5 प्रतिशत जनता अशिक्षित है परन्तु कम-विकसित देशों में 63 प्रतिशत जनता अशिक्षित रहती है हम इसके गम्भीर परिणाम समझ सकते हैं इससे इन देशों में बेरोजगारी, कम कार्य कुशलता, कुशल व्यक्तियों की कमी व अकुशल की अधिकता तथा निम्न उत्पादन, निम्न राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय बनी रहती है इसी कारण देश में बचतों का अपव्यय तथा जन्म व मृत्यु दरें भी अधिक रहती हैं

6 कम विकसित देशों में असंतुलित आहार व निम्न आयु :

कम विकसित देशों में आज व्यापक भुखमरी फैली हुई है Le Gros ने अपनी पुस्तक 'Four Thousand million mouths to Feed' में लिखा है कि सन् 2000 में विश्व में व्यापक भुखमरी फैलेगी, जो केवल समस्त भूमि पर आधुनिकतम तकनीक के अपनाए जाने पर ही टाली जा सकती है

आज विश्व में 50 करोड़ व्यक्ति स्थायी रूप से भूख में पीड़ित हैं और अन्य 150 करोड़ व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता

जहाँ एक व्यक्तिको प्रतिदिन 3000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है और 40 प्रकार के भिन्न-भिन्न तत्वों (जैसे विटामिन, नमक, धातुये, एनजाइम्स), वहाँ F A O (Food & Agriculture organisation) की 1951 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की 1,9 जनसंख्या ही यह मात्रा प्राप्त करती है और 8-9 भाग इसे प्राप्त नहीं करता मनुष्य को अगर 1000 कैलोरीज प्रतिदिन से कम मिले तो वह शीघ्र ही हड्डियों का ढाँचा रह जायेगा, Hitler के Concentration Camps (बिजली के तारों से घिरे कैदियों के कठघरे) में इतनी ही मात्रा में खाना दिया जाता था

विश्व में आज भुखमरी के तीन बड़े क्षेत्र हैं

- (1) प्रथम ये देश है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जैसे भारत, चीन, व सुदूर-पूर्वीय देश
- (II) वे कम-विकसित देश जहाँ घनत्व कम है पर गरीबी व कारण भुखमरी है जैसे अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका
- (III) विकसित देशों के गरीब वर्ग

कम विकसित देशों में मुख्य समस्या प्रोटीन की कमी की है बच्चे व गर्भवती स्त्रियाँ प्रोटीन की भुखमरी से पीड़ित हैं कम-विकसित देशों में अगले बीस वर्षों में भिन्न भिन्न देशों में 50 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक कैलोरीज की मात्रा में वृद्धि आवश्यक होगी जिसका अधिकांश भाग कृत्रिम साधनों से प्राप्त करना पड़ेगा

आयु.:

जहाँ विकसित देशों में औसत आयु 60 से ऊपर ही होती है वहाँ कम-विकसित देशों में 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच रहती है निम्न तालिका में 1968 में औसत आयु (Life expectancy) इस प्रकार है

ऑस्ट्रेलिया, यू० के०, यू० एम० ए०	73 वर्ष
फ्रांस	69 "
जापान	65 "
लंडन	60 "
भारत	50 "
अफ्रीकी देश	20-45 "

भारत में 1811-20 के बीच पुरुषों की औसत आयु केवल 19.4 वर्ष व स्त्रियों की केवल 20.9 थी। इतनी अधिक स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाने के परिचाय ही यह दर अब 1951-60 के बीच क्रमशः 42 व 40.6 आई।

जहाँ यू. एम. ए. में 1000 में से 25 बच्चों की एक वर्ष की आयु से पहले मरते हैं वहाँ कम विकसित देशों में 100 में 200 बच्चे मर जाते हैं। भारत में 1000 में से 150 बच्चे एक वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं जब कि नाइजीरिया में तो 500 बच्चे मर जाते हैं।

7 कम-विकसित देशों में जनसंख्या का व्यवसायिक अनुपात

निम्नलिखित तालिका विकसित व कम विकसित देशों के बीच जनसंख्या का व्यवसायिक वर्णन करती है। जैसा कि जाहिर है कम विकसित देशों में अधिकांश जनता प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है और विकसित क्षेत्र में इसका उल्टा रहता है। यह कितनी आश्चर्यजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कम विकसित देशों में 10 में 6 से 8 व्यक्ति कृषि में लगे रहते हैं फिर भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं उगा पाते।

प्रतिशत में

कार्य	यू. एम. ए.	यू. के.	जापान	भारत
कृषि	12.5	5.0	19.4	72.0
उद्योग	30.6	43.0	29.3	9.7
निर्माण कार्य	6.4	6.2	6.6	1.0
मानायात व संचार	7.7	7.1	7.4	1.5
व्यापार	19.0	14.1	16.5	5.1
सेवाएँ	23.8	23.8	20.8	10.8
	100.0	100.0	100.0	100.0

8 कम विकसित देशों में घनत्व की समस्या :

विश्व में आज भी हर देश में अर्थशास्त्रियों को माल्यम के भय का भूत सता जाता है। जहाँ 1900 में विश्व जनसंख्या केवल 155 करोड़ थी, वृद्धा 1975 में 385 करोड़ सम्भावित है। अन्य अनुमान इस प्रकार हैं :

सन् 2000 में 627 करोड़

सन् 2065 में 1000 करोड़

सन् 3090 में इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल खड़े होने की जगह मिलेगी

सन् 4250 में पृथ्वी पर मनुष्यों का भार स्वयं पृथ्वी के बराबर हो जाएगा

सन् 2000 में 65 प्रतिशत जनसंख्या कम विकसित देशों में होगी 1950 और 1980 के बीच अनुमान है कि एशिया की जनसंख्या 50 प्रतिशत, दक्षिणी अमेरिका की 92 प्रतिशत, अफ्रीका की 46 प्रतिशत तथा उन्नत देशों की 30 प्रतिशत बढ़ जाएगी इन्हीं कारणों से श्री बी थार सेन (मृतपूर्व अध्यक्ष, F. A. O.) तथा Prof Rene Dumont ने 1975-1980 के बीच भारत, पूर्वी पाकिस्तान, ब्राजील, पोलैंड व बोलिविया में अकाल की भविष्यवाणी की है

श्री माइकल रॉबर्ट (Michael Robert) ने अपनी पुस्तक 'The state of man' नामक पुस्तक में भी उल्लेख किया है उन्होंने बताया कि 1951 में विश्व में 56 करोड़ वर्गमीटर क्षेत्रफल को तत्कालिक 235 करोड़ की जनसंख्या में बाँटने तो प्रति व्यक्ति 15 एकड़ भूमि हिस्से में आती जिसमें 5 एकड़ जंगल, 4 एकड़ रेगिस्तान, 2 एकड़ रतीली भूमि, व 2 एकड़ वर्षाणी भूमि शामिल थी खेती योग्य केवल 15 एकड़ भूमि थी एक मदी याद यह माना आधी से भी कम रह जाएगी

अशाखादी विचारधारा

अगर कम विकसित देशों में परिवार नियोजन व्यापक रूप में अपना लिया जाय ता इन देशों में जनसंख्या की समस्या इतनी गंभीर न रहे थी विन्स्टन चर्चिल का कथन हमें ध्यान में रखना चाहिए

“हर वक्त शुरू में ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ता है परन्तु कोई भी वृद्ध आकाश को नहीं छू पाता”

IV Vicious circle of low savings and low capital-formation कम बचतों व कम पूँजी निर्माण का दुश्चक्र

कम-विकसित देश, प्रो० रेगनर नर्वम के प्रसिद्ध शब्दों में, गरीबी, कम बचत, कम पूँजी निर्माण, कम विनियोजन व रोजगार तथा कम आय के दुश्चक्र में फँसे हैं प्रो० नर्वम के शब्दों में “एक गरीब देश अपनी गरीबी के कारण ही गरीब रहता है” उन्होंने कहा “The path to economic development

जनसंख्या समस्या समाधान व नीति अगले भाग में है

is paved with vicious circles", जिसका भावार्थ यह है कि विकास की राह में बहुत से अवरोध, भवरें व रुकावट हैं प्रो० नक्स ने कहा कि जिस प्रकार ने एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण अनुचित भोजन न ले सकने के कारण कमजोर रहता है और कमजोरी के कारण कम कमाता है, तथा कम आय के कारण कमजोरी के दुश्चक्र में फँसा रहता है, उसी प्रकार में कम-विकसित देश कम वचत व कम पूँजी निर्माण के दुश्चक्र में पड़ा रहता है

कम वचतें

(1) कम-विकसित देशों में वचत की मात्रा, विकसित देशों के मुकाबले में बहुत कम होती है जहाँ विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का 18 से 25 प्रतिशत तब बचा कर लेते हैं कम-विकसित देश अपनी आय का मुश्किल से 5 से 10 प्रतिशत तब ही बचा पाते हैं जर्मा, इण्डोनेशिया, थाइलैंड, व फिलीपीन्स 1950 में अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 3 प्रतिशत बचा पाते थे

निम्नलिखित तालिका में कम वचतों की स्थिति दर्शायी गई है

देश	वचत का राष्ट्रीय आय के रूप में प्रतिशत
जापान	38
ऑस्ट्रेलिया	26
नार्वे	25
यू एस ए, कनाडा, पश्चिमी योरोप, स्वीडेन	17-25 प्रतिशत के बीच
थी लका	11
भारत	10

(2) इन देशों में कम पूँजी निर्माण का मुख्य कारण गरीबी है Meier and Baldwin भीयर तथा बाल्डविन के अनुसार कम विकसित देशों में आय के पिरामिड (Δ जो इस रूप का होता है) केवल 5 प्रतिशत व्यक्ति वचत करते

(1) UNESCO 1951 . Volume and Distribution of National income in Under developed Countries
p 45

(2) Yojna 29 th December 1968 p 22

हैं और वही वही तो केवल 2 प्रतिशत ही वचत कर पाते हैं ¹

(3) विश्व के विकसित व कम-विकसित देशों में औसत आय में बहुत अन्तर है. अमीर देशों के अमीर व्यक्तियों तथा गरीब देशों के गरीब व्यक्तियों की आय में तो 'जमीन व आसमान' के अन्तर बड़े जा सकने हैं आज विश्व के कम-विकसित देशों में 63 प्रतिशत व्यक्ति रहने हैं पर वे विश्व की 13 प्रतिशत आय के ही भागीदार हैं ²

(4) हमारे प्रतिनिधि देश के अन्दर ही आय के अन्तर बहुत अधिक रहने हैं जैसे भारत में 60 प्रतिशत जनसंख्या देश के केवल 35 प्रतिशत धन की भागीदार 20 प्रतिशत देश की 55 प्रतिशत धन के भागीदार हैं व बाकी के 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत धन के गानिक हैं ³

(5) कम विकसित देशों में न केवल दबनों की मात्रा कम है वरन् बहुत कुछ वचतें real estates (मकान व जमीन) आने बाँझों के रूप में मात्रा कर ली जाती हैं वचत करने वाले बहुत बड़े जमींदार और व्यापारी होने हैं यह अपनी वचतों को व्याज पर देने, और मट्टे खराने के कार्य में ले लेते हैं ⁴

(6) कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाएँ ऐसी हैं जिन्हें वचतों का सही प्रयोग नहीं हो पाता उदाहरणतया इण्डोनेशिया जैसा गरीब देश जहाँ व्यापक रूप से गरीबी है वहाँ कुछ वर्षों पूर्व वहाँ के तत्कालिक राष्ट्रपति विश्व की मदद में बड़ी मस्जिद तथा कुछ अन्य भवन बनाने में तब थे भारत में भी पिछले 10-12 वर्षों में नगरों में लाखों २० की लागत में गंगास्वामी मन्दिर बन रहा है

(7) कुछ अर्थशास्त्रियों का दान है कि कोई भी देश जितना गरीब नहीं होता कि वह अपनी राष्ट्रीय आय का 12 प्रतिशत मग नहीं देना सके Egbert de Vries तथा Elmer या कहें हैं कि

(1 & 4) : Meier and Baldwin Economic Development : P. 311 ft

(2) cf Dr O S Shrivastava Economics of Wages, Productivity and Employment 1968 p 37 Kailash Pustak Sadan, Gwalior.

(3) : Simon Kuznets : "Economic Growth and Income Inequality."

Egbert de Vries of International Bank of Reconstruction and Development and Elmer of Mutual Security programme of U.S.A. quoted in "Capital formation and foreign investment in under developed countries." by C. Wolf Jr. and S. C. SuPrin.

“गरीबी ने गरीब देशों को युद्धों में रत होने से नहीं रोका इन गरीब देशों में कहीं-कहीं 60 प्रतिशत वचत चमत्ता गरीबों तक में पाई गई है जहाँ चाह है वहाँ वचन अधिक हो सकती है” इन देशों की 40 प्रतिशत आय सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों द्वारा विनाशिता में खर्च कर दी जाती है

पूजी निर्माण और दुश्चक्र

एक तो इन देशों में बचते कम हैं और जितनी बचनें हैं उन सबका पूजी-निर्माण नहीं हो पाता इसका कारण है कि पूजी-निर्माण की पूर्ति और माँग दोनों की ओर दुश्चक्र है

(1) पूर्ण पक्ष की ओर कम पूजी निर्माण से कम विनियोजन होता है→कम विनियोजन से कम उत्पादन होती है→कम उत्पादन में रोजगार वृद्धि कम होती है→कम रोजगार में कम आय होती है→कम आय से बचते कम होती है क्योंकि उपभोग-जमता अधिक होती है→कम बचतों में पुन कम पूजी निर्माण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है

इस प्रकार में कुल राष्ट्रीय आय व प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय कम पूजी-निर्माण के कारण व परिणाम बन जाते हैं

(2) माँग पक्ष की ओर में भी दुश्चक्र पुरा रहता है देश में जो कुछ भी माँग रहनी है वह प्राथमिक आवश्यकताओं की रहती है शय्य वस्तुएँ बगैर बिकी रहती है या कम बिकती है इन कारणों से विनियोजन-कर्ताओं की माँग भी कम रहती है उत्पादन-कर्ताओं की माँग की कमी में पूजीसंचय भी कम रहता है

(3) पूजी निर्माण की कमी के कारण औद्योगीकरण की योजनायें कार्यान्वित नहीं की जा पाती अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में यह समस्या और गम्भीर रहती है इस कारण यह देश पुरानी मशीनों से पुरानी तकनीक में कार्य करते रहते हैं और इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात करने में पीछे रहते हैं

(4) कई कम विकसित देशों में तो इतना पूजी निर्माण भी नहीं होता कि जनसंख्या को उसी स्तर पर कायम रखा जा सके Colin Clark के अनुसार 1 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय का 4% विनियोजन की

आवश्यकता, जनसंख्या को समान स्तर पर रखने के लिए ही होती है इनका अनुमान है कि अगर इन देशों में सही माने में व्यापक रूप में तथा आवश्यक मात्रा में विकास करना हो तो राष्ट्रीय आय का 20 प्रतिशत से विनियोजन होना ही चाहिए

(5) इन देशों में न केवल ' भौतिक पूँजी निर्माण ' की कमी है बल्कि " सामाजिक पूँजी-निर्माण " की भी बहुत कमी है कम विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग की सुविधाएँ कम रहती हैं शिक्षित, कुशल, तबनीकी ज्ञान रखने वाले स्वस्थ व दीर्घायु व्यक्ति समाज की पूँजी होते हैं, अतः प्रशिक्षित, अनुकूल व उत्पादक मूल्य ज्ञान वाले व्यक्ति पूँजीनिर्माणकर्ता के स्थान पर उपभोगकर्ता अधिक होते हैं Prof Simon Kuznets (साइमन कुजनेट्स) इनीलिए कहते हैं कि " भौतिक पूँजी में तो अधिक इन देशों में सामाजिक पूँजी की कमी है "

(6) एक और अन्य कारण जिससे इन देशों में पूँजी-निर्माण कम होता है, वह यह है कि इन देशों में कुशल साहसियों की कमी है :

"Capital creation may be said to be rather pulled from the side by imaginative entrepreneurs than pushed from the supply side by passive accumulation of Capital "

→Howard Ellis

प्रयत्न अगर बचत करने वाले बचत नहीं करते तो कुशल साहसी बचतों की चेतना से है

(7) Mrs Joan Robinson का भी इसी प्रकार कथन है कि कुशल साहसी ऐसी पद्धति निबाल लेते हैं (जैसे मनुष्य पूँजी-प्रणाली) जिसमें पूँजी-निर्माण हो सके "Where enterprise leads, finance follows."

Simon Kuznets : Towards a theory of Economic growth in R. Leckacsmán (Ed) National policy for Economic welfare at Home and Abroad. p. 39-40

Howard Ellis : The Fixing of Economic Dev in developing areas. The Indian Journal of Economic Jan. 1956 p 256-68.

Mrs. Joan Robinson : Cf . The Accumulation of Capital.

V Unemployment and Under-employment in Under-developed countries कम-विकसित देशों में अर्ध बेरोजगारी व बेरोजगारी

कम-विकसित देश व बेरोजगारी :

कम-विकसित देशों में विकसित देशों की भाँति पूर्णरूप से अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या अधिक व्यापक नहीं है इन देशों में Cyclical (चक्रीय) Frictional (मर्घपातमक) तथा Technological (तकनीकी) बेरोजगारी की समस्या प्रधान समस्या नहीं होती, फिर भी इस प्रकार की बेरोजगारी सख्या में बहुत अधिक होती है, आते प्रतिशत में यह मात्रा कम ही क्यों न हो इस संबंध में कुछ आँकड़े नीचे दिए जा रहे हैं

देश	सन्	नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल सख्या	अन्य
भारत	1961	11%	6%	/	
"	1968			150 लाख	11 लाख शिक्षित
प० पाकिस्तान	1955	64% बड़े शहर 35% नगरीयक्षेत्र	22%		
पू० पाकिस्तान	"	103% बड़े शहर 60% नगरीयक्षेत्र	31%		
फिनीपीन्स	1959	कुल आवादी के	71%		
	1961	" " "	86%		
	1962	" " "	95%		
ईराक	1956	" " "	100%		
इटली	1959	" " "	87%		
ग्राजोल	1957	" " "	52%		
Ecafe Region आजकल 10 से 15 प्रतिशत जनता बेरोजगारी से पीड़ित है					

कम विकसित देश व अर्ध बेरोजगारी :

कम-विकसित देशों में समस्या यह नहीं कि "कितने व्यक्ति" बेरोजगार हैं, बल्कि समस्या यह है कि व्यक्ति "कितनी मात्रा में" बेरोजगार है "The question is

not" how many persons are unemployed, but "how much" they are unemployed

समस्या बेरोजगारी की संख्या से इतनी संबंधित नहीं जितनी "बेरोजगारी की मात्रा में है" (The problem is not of volume of unemployment but of degree of unemployment)

कम-विकसित देशों में समस्या यह नहीं है कि देश में प्राकृतिक साधनों व जनशक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाए बल्कि मुख्य समस्या रोजगार से आय-वृद्धि की है

इन देशों में प्राथमिक क्षेत्र में तो कार्य मिल जाता है परन्तु द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) तथा तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) काम की बहुत कमी रहती है इन देशों में रोजगार प्रदान करना ही समस्या नहीं है बल्कि रोजगार के तकनीकी स्तर, उत्पादकता तथा Capital-output ratio पूँजी उत्पादन दर सुधारना होता है

कम-विकसित देशों में बहुत से व्यक्ति Self-employed होते हैं, अर्थात् अपने द्वारा संचालित कार्यों में लगे रहने हैं इन देशों में कुशल व्यक्तियों की कमी व अकुशल व्यक्तियों की बेरोजगारी की स्थिति रहती है कभी कभी तो साहसियों और पूँजी की कमी के कारण शिक्षित व कुशल व्यक्तियों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है (Lack of co-operant factors becomes an important cause of unemployment and under-employment.

छिपेबी-बेरोजगारी Disguised unemployment :

Also known as (i) Under-employment (ii) Latent unemployment, (iii) Partial unemployment, (iv) Part-time employment, (v) Insufficient employment, and (vi) Abnormal unemployment

कम-विकसित देशों में छिपेबी-बेरोजगारी की स्थिति मौजूद रहती है यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति काम तो करता रहता है परन्तु वह उसकी योग्यता व क्षमता से बड़ी कम आय देता है इस प्रकार के रोजगार में जनशक्ति का पूर्ण प्रयोग नहीं होता

कृषि-क्षेत्र में यह बेरोजगारी अधिक व्यापक रहती है यह स्थिति वह है जहाँ कि किसानों के परिवार के सभी सदस्य एक खेत पर कार्य करते हैं जबकि अगर कुछ

लोग खेत पर से कार्य से हटा भी लिए जाएँ तो उत्पादन में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा इस दशा में हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों की सीमान्त उत्पादकता 'शून्य' रहती है यह बेरोजगार Self employed व्यक्तियों में अधिक होते हैं प्रर्थशास्त्री च्यांग सीह Chiag Hsieh ने तीन प्रकार की अर्ध बेरोजगारी बताई है

- (i) Under - employment अर्ध बेरोजगारी अर्धबेरोजगारी की स्थिति वह होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य कर पाता है इस प्रकार की अर्धबेरोजगारी साफ देख सकती है और बहुत हद तक मापी भी जा सकती है
- (ii) Disguised under-employment छिपेबेरी अर्ध-बेरोजगारी कम-विकसित देश पिछड़े किरम की व्यवस्था और प्राथमिक श्रम-नियोजन में उत्पादन करते हैं अगर इनमें सुधार किये जाएँ (परन्तु पूँजी की मात्रा, देश की संसागत संरचना व भूमि वितरण व्यवस्था वही रहे) तो निश्चय ही उनमें से कुछ व्यक्ति बेरोजगार हो जाएँगे इन व्यक्तियों को हम Disguised under-employed मान सकते हैं
- (iii) Potential under-employment • जब उत्पादन पद्धति में तकनीकी सुधार व समस्त संरचना व व्यवस्था सम्बन्धी सुधार किए जाएँ तो जो लोग बेरोजगार होंगे उन्हें हम बेरोजगारी से पहले potentially unemployed मानेंगे (जैसे कृषि-क्षेत्र में माना 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं अगर इस क्षेत्र में नई तकनीक, नए भूमि सुधार, नए औजार व मशीनीकरण, तथा नई व्यवस्था अपनाकर कार्य करें तो माना अब केवल 500 व्यक्ति काम कर उतना ही उत्पादन कर सकत है तो हम कहेंगे कि 500 व्यक्ति potential under-employment से पीड़ित हैं)

कम विकसित देशों में "उन्नति काल में बेरोजगारी "

Under-employment of expansion •

Prof Moises T de la pena के विचार — इटली के इस प्रर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान खींचा इस प्रकार की बेरोजगारी कम-विकसित देशों में विकास-काल में उत्पन्न होती है, जबकि अधिकांश बेरोजगारियाँ मन्दी काल

में उत्पन्न होती है कम-विकसित देशों में जब विवास्त के लिए अधिकाधिक माना में मुद्रा-प्रसार किया जाता है तो देश में मुद्रा स्फीति फैलती है महंगाई के कारण कुछ उद्योगों में शिथिलता से बेरोजगारी उत्पन्न होती है गावों के रहने वाले महंगाई के कारण गांवों से शहरों की ओर आते हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ाते हैं

संरचना संबंधी बेरोजगारी : Factor dis-equilibrium and structural unemployment :

Prof R. S. Eckhaus' के विचार — कम-विकसित देशों में श्रम व उत्पादन के अन्य प्रयोगों की गतिहीनता या गतिशीलता की कमी के कारण लोग श्रम बेरोजगारी से पीड़ित बने रहते हैं और अन्य स्थानों पर रोजगार पाने के प्रयत्न नहीं करते गरीबी, अज्ञानता, धर्मबन्धन, जाति-भेदभाव के कारण रोजगार पाने का प्रयत्न नहीं करते

इन देशों में निम्नकारणों से भी बेरोजगारी बनी रहती है

- (I) एकाधिकारी कम उत्पादन करके बेरोजगारी बनाए रखते हैं
- (II) देश में पूर्ति लोचदार नहीं होती और मूल्य वृद्धि होने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा पाती और रोजगार वृद्धि नहीं हो पाती
- (III) देश में आविष्कार व नव-प्रवर्तन कम होते हैं और उत्पादकता कम रहने में बाजार-विस्तार नहीं होता और रोजगार वृद्धि नहीं हो पाती
- (IV) इन देशों में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सवधी जानकारी कम होती है, वे अपने बाजारों की क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते इसलिए इन कारणों से बेरोजगारी बनी रहती है

कम-विकसित देशों में मौसमी बेरोजगारी : Seasonal unemployment, कम-विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में मिर्चाई आदि की सुविधा कम होने के कारण, किसान साल के अन्य महीनों में बेरोजगार रहते हैं, बहुत से उद्योग कुछ महीनों में ही चलते हैं और बाकी महीनों में व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं

कृषि क्षेत्र के व्यक्ति पूँजी की कमी तथा बहुत हद तक अपनी अकर्मण्यता व गतिहीनता के कारण अन्य काम नहीं पाते

अन्य बेरोजगारियाँ व कम विकसित देश :

1. Fractional unemployment. इन देशों में श्रम अपना स्थान पाने के लिये संघर्ष करता है और कम विकसित देशों में आए दिन हड़तालों व तालाबन्दी के कारण बेरोजगारी हो जाती है

2. Unemployment of the educated persons कम विकसित देशों में यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साक्षरता प्रतिशत कम होते हुए भी शिक्षित लोग बेरोजगार रहते हैं इन देशों में कुछ कोटि के व्यक्तियों की कमी रहती है (जैसे तकनीकी व्यक्ति) और कुछ कोटि के व्यक्तियों की अधिकता रहती है (जैसे कला सहाय के शिक्षितों की) भारत में तो तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों का भी भविष्य सुनिश्चित नहीं है और इन्हें भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ जाता है

इन देशों में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

- (1) विद्यार्थियों की संख्या वृद्धि के हिसाब से रोजगार की वृद्धि न होना
- (11) शिक्षित व्यक्ति हमेशा white collar Jobs या "कुर्सी की नौकरियाँ" चाहते हैं, शारीरिक परिश्रम की नौकरियों की चाह का कम होना
- (111) कला सहाय में विद्यार्थियों की अधिकता रहती है भारत में 1962-63 में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी

कला सहाय	42.7 प्रतिशत
विज्ञान	30.4 "
वारिज्य	10.0 "
इजीनीयरिंग व टेक्नालाजी	5.4 "
मेडिकल	3.9 "
कृषि	2.5 "
कानून	2.3 "
शिक्षा	2.0 "
अन्य	6 "
	<hr/> 100

(Eastern Economist Annual No. 1965. p. 1427)

शिक्षित लोगों की बेरोजगारी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथा खतरनाक होती है दुर्भा-

See . Dr. O. S. Srivastava : Employment Aspects of Planning in Madhya Pradesh in "Development Potential of Madhya Pradesh, Ed. Dr. D. S. Nag. p. 169 sf"

व्यपूर्ण इसलिए कि शिक्षा में इतना समय और धन व्यय करने के पश्चात् रोजगार न पा सकने में समय व धन का अपव्यय होता है। खतरनाक इसलिए कि शिक्षित व्यक्ति अपनी बेरोजगारी को भाग्य का दोष नहीं मानते व जानते हैं कि उनकी यह बेरोजगारी Socio-politico economic-defects या सामाजिक-राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था में दोषों के कारण है और फिर वे उस सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें रोजगार नहीं दे सकती। वैसे भी वह राष्ट्र जो अपनी युवा शक्ति का उपभोग नहीं कर सकता शीघ्र कुटिल हो जाता है।

कम-विकसित देशों में अर्थ-रोजगार या अर्थ-बेरोजगारी के अनुमान :

आधुनिकतम अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान, फिलीपीन्स, मिथ, इन्डोनेशिया में 20 से 25 प्रतिशत व्यक्ति अर्थ-बेरोजगारी से पीड़ित हैं। दक्षिणी इटली में 45 प्रतिशत व उत्तरी इटली में 28 प्रतिशत व्यक्ति अर्थ-बेरोजगारी से पीड़ित हैं। दुनियाँ के अधिकांश कम-विकसित देशों में 25 से 60 प्रतिशत तक लोग अर्थ-बेरोजगारी से पीड़ित हैं।

भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों में 1/4 व्यक्ति कृषि की आवश्यकताओं से अधिक है। भारत में जिन क्षेत्रों में मिर्चाई की सुविधाएँ मौजूद हैं वहाँ साल के 4 से 6 महीनों तथा जहाँ सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं वहाँ तो 8 महीनों तक कुछ व्यक्ति अर्थ-बेरोजगारी से पीड़ित हो जाते हैं। तृतीय योजना के अन्त तक देश में 1-5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे और 1.5 करोड़ व्यक्ति अर्थ-बेरोजगारी से पीड़ित थे।

अध्याय : 3

कम-विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of under-developed countries

(भाग 2)

6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का असंतुलन.

(1) कुछ ही वस्तुओं के निर्यात (Narrow base of exports)

(11) निर्यात व राष्ट्रीय आय का भाग ✓

(111) कम विकसित देशों की निर्यातित वस्तुओं के मूल्यों में उच्चावचन से इन देशों को हानि

(1V) कम विकसित व प्रतिकूल भुगतान की शर्तें

(V) निर्यात वृद्धि कम, आयात अधिक

7. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बुझभाव Backwash effects of international trade.

✓ 8. Duality : दुहरापन : विकसित व अविकसित होना. ✓

9. अर्ध-विकसित मौद्रिक व्यवस्था.

10. राजकोपीय क्षेत्र व पिछड़ापन,

11. कम विकसित देश व प्राकृतिक साधन.

12. बाह्य मितव्ययताओं की कमी.

13. सहस्रियों व अन्य सहायक उत्पादन के अंगों की कमी.

14. पिछड़ी तकनीक व कम उत्पादकता.

15. अयोग्य, अशुद्ध तथा उदासीन शासकीय प्रशासन.

16. सामाजिक पिछड़ापन.

अध्याय : 3

कम-विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of under-developed countries

(भाग 2)

IV International Trade Imbalances

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलन

1 Narrow base of exports - कुछ ही वस्तुओं के निर्यात.

कम विकसित देशों के अधिकांश निर्यात एक या दो वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं यह स्थिति कम विकसित देशों के लिए हितकारी नहीं है क्योंकि अगर उस वस्तु विरोध का कम उत्पादन हुआ या कम माँग के कारण मूल्य गिरे तो इन देशों की आय एकदम गिर जाती है निम्नलिखित तालिका में इस वस्तु स्थितिको दर्शात की गई है ¹

देश \	वस्तु	कुल निर्यात का प्रतिशत
1. वेनेजुएला	तेल (पेट्रोल)	96 प्रतिशत
2-4. इरान, २० अरेबिया, कुवैत, वेने	तेल	90 प्रतिशत
5. मिश्र. यू० ए० आर)	रई	६० "
6 मलयेशिया	टीन व रबर	75 "
7. लका	चाय व रबर	75 "
8-9 बर्मा-थाईलैंड	चावल	75 "
10. कोलम्बिया	काफी	75 "
11. पाकिस्तान	जूट	70 "
12. बोत्सेविषा	टिन	70 "
13-14. रोडेसिया, जिम्बो	ताँबा	55 "
15-16. आस्ट्रेलिया, यूरेगुए.	ऊँ	50 "

1. U N. . Measures for the Economic development of under-developed countries 1951 P 71

अफ्रीका के अधिकांश देश रूई, ताँबा, मूँगफली व कोको के निर्यात से 40 से 80 प्रतिशत तक आय कमाने हैं

2. निर्यात से राष्ट्रीय आय का भाग : Export as a percentage of national income

कम विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का 10 से 42 प्रतिशत तक निर्यात से कमाते हैं. इस सम्बन्ध में स्थिति यह है टर्की (10) कोलम्बिया (12) इराक (13) मेक्सीको (17) निकारागुआ (27) क्यूबा (34) वियतनाम (36) तथा लंका (42) ¹

3. कम-विकसित देशों की निर्यातित वस्तुओं के मूल्यों में उच्चावचन से इन देशों की हानि : Fluctuations in the prices of goods sold by under-developed countries.

कम-विकसित देशों की निर्यातित वस्तुओं के मूल्यों में बहुत उच्चावचन हो जाते हैं मूल्यों में इन परिवर्तनों से रोजगार व निर्यात आय में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण राज्य व निजीक्षेत्र की आय, लाभ, मजदूरी आदि में भी परिवर्तन हो जाते हैं

1929-1932 की महान मंदी के काल में चाय व रबर के मूल्य $1/5$ से $1/3$ तक गिर गए थे 1901-1950 के बीच निर्यातित वस्तुओं के मूल्यों में 27 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन हुए ²

4. कम विकसित देशों की भुगतान की शर्तें विपक्ष में हो जाती हैं. Terms of trade of under-developed countries go against

“भुगतान-शर्तों” का अर्थ आयात-निर्यात मूल्य-परिवर्तन संबंध से होता है जैसे अगर किसी कम-विकसित देश के निर्यातित व आयातित वस्तुओं की मात्रा (जैसे 1 एजिन आयात, 100 रूई गाठ निर्यात) उतनी ही रहे, पर आयात की वस्तु का मूल्य बढ़ जाए या और निर्यात की वस्तु का मूल्य गिर जाय तो “भुगतान की शर्तें” विपक्ष में हो जाती हैं ³

1. Meier and Baldwin :—Op. cit P. 310.

2 Dr. O. S Shrivastava : op. Cit : p 60-65

3. I. M. F. : Fund policies and procedures in relations to the Compensatory Financing of Commodity Fluctuations 1960

1950 के अनुपात में 1961 में कम-विकसित देशों की "भुगतान की शक्ति" 14 प्रतिशत गिर गई विकसित व कम-विकसित देशों की स्थिति इस प्रकार रही

	निर्यात की मात्रा	निर्यात का मूल्य
1 विकसित देश	112% वृद्धि	19% वृद्धि
2 कम-विकसित देश	57% वृद्धि	4% कमी

5 निर्यात वृद्धि कम, आयात अधिक : Unfavourable balance.

(1) 1956 में विश्व निर्यात 1,00,000 मिलियन डालर से बढ़कर 2,00,000 मिलियन डालर हो गया विकसित देशों का भाग 66 प्रतिशत से बढ़कर 69.5 प्रतिशत हो गया व कम-विकसित देशों का भाग 28 प्रतिशत से घटकर 19.5 प्रतिशत रह गया ¹

(2) 1928-57 के बीच कम-विकसित देशों के निर्यात 50 प्रतिशत बढ़े, पर आयात 100% बढ़ गए ²

(3) 1950-1962 के बीच विकसित देशों के निर्यात 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़े, समाजवादी देशों के निर्यात 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़े, पर कम-विकसित देशों के निर्यात केवल 3.4% प्रतिवर्ष बढ़े और आजकल तो केवल 2.2% प्रतिवर्ष ही बढ़े ³

(4) 1970 में कम-विकसित देशों को 80,000 लाख डालर का व्यापार असंतुलन भुगतान पड़ेगा 1953-61 में deficit पाँच गुने बढ़ गए ⁴

(5) आजकल कुल निर्यात आय का 11 प्रतिशत तो ऋणों के व्याज व भुगतान में ही चला जाता है भारत तो 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष Debt service charge में दे देता है ⁵

References

1. World Economic Survey : 1966
2. U. N. Statistical year Book 1966 : Reviewed in Free Press Journal 5 July 1967.
3. Ecafe region survey : Report in Patriot 24-3-1966.
4. U. N. Economic Survey of Asia and the Far East. 1957
5. U. N. Instability in Export Markets of developed Countries 1952. p. 6.

(6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिकूल भुगतान मंतुलन के निम्नकारण रहते हैं¹ .

- (i) कृषि का पिछड़ापन कृषि उपज की सचय की कठिनाईयाँ.
- (ii) निर्यातित वस्तुओं के भावों में कमी तथा कृत्रिम वस्तुओं से प्रतियोगिता
- (iii) आयातित वस्तुओं के भावों में वृद्धि तथा विकास के लिए मशीनों का भारी मात्रा में आयात
- (iv) विकसित देशों में कम-विकसित देशों से आयात पर प्रतिबन्ध व अधिक माना में कर.
- (v) कम-विकसित देशों की वस्तुओं का अपेक्षाकृत किस्म में अछड़ा न होना व महँगा होना
- (vi) देश में उत्पादन कम होना जिससे निर्यात के लिए कम वस्तुओं का उपलब्ध होना
- (vii) इन देशों द्वारा 'अद्रव्य आयातों' की अधिकता होना, अर्थात् तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन, जहाज आदि के प्रयोग, व सार्वजनिक ऋण के व्याज व मूलधन के लिए निर्यात का बड़ा अंश चला जाना

VII Backwash effects of international trade . अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दुष्प्रभाव .

आज कम-विकसित देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के *Backwash effects* में पीड़ित हैं Prof Gunnar Myrdal ने यह शब्द प्रयोग में लाए उन्होंने बताया कि जहाँ विकसित देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्य सपकों में कम-विकसित देशों में विकास कारक तत्वों व मनोवृत्ति को जन्म दिया, वही पर इन देशों ने कम-विकसित देशों में कुछ अन्य ऐसी मनोवृत्तियाँ व तत्वों को उत्पन्न किया जो विकास में बाधक हैं. यह तत्व है कम-विकसित देशों द्वारा विकसित देशों के उत्पादन की जटिल पद्धतियों की नकल करना या विकसित देशों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना कम-विकसित देशों के पास इतनी पूँजी तो होती नहीं है परन्तु वे अनावश्यक रूप से विकसित देशों जैसे कच्चे माल, उत्पादन पद्धतियों व संगठन पद्धतियों का प्रयोग करने लगते हैं जो सर्वथा हानिकारक होता है

प्रोफेसर मृडाल का कथन है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जहाँ लाभ होते हैं (Spread effects) वहाँ बहुधा वे चीजें जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान नहीं देते उनमें लापरवाही के कारण विकास नहीं हो पाना और इनमें backwash effects या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं इन चीजों में पूँजी नहीं लगाई जाती अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने ही कम-विकसित देशों में दुहरी अव्यवस्था (duality) उत्पन्न कर दी है

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन इस प्रकार रहा है कि विकसित देशों या साम्राज्यवादी देशों का तो विकास हुआ पर अधीनस्थ कम-विकसित देशों में वही पिछड़ापन बना रहा यहाँ आय वृद्धि के गुणक प्रभाव नहीं हुए जिसमें अन्य चीजों का विकास हो सकता विकसित देशों ने कम-विकसित देशों में व्यापार करके लाभ कमा कर अपने देश के लिये पूँजी निर्माण किया

Prof Hla Myint के अनुसार कम-विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास के अध्ययन से हमको पता चलता है कि विकसित देश ही सारे लाभ उठाने हैं उनके शब्दों में

"अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने कम-विकसित देशों को सिवाय नई-वस्तुओं की माँग करने के कोई और शिक्षा नहीं दी"

संक्षेप में, इन दोनों अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकसित देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने कम-विकसित देशों को निम्न हानियाँ पहुँचाई हैं जो आज विकास में बाधक हो जाती हैं

- (1) विकसित देशों ने कम-विकसित देशों में केवल कच्चे माल या कच्चे खनिज आयात किए जिनके मूल्यों में अधिक उच्चावचन के कारण इन देशों का व्यापार चक्रों की हानियाँ उठानी पड़ीं

1. Gunnar Myrdal Economic Theory and under-developed Regions, London 1957
2. H W. Singer International Development, Growth & Change p 12-15
- 3 B Higgins - Economic Development; Ch 15
- 4 H Myint, "The gains from international trade and the backward Countries," Review of Economics studies, Vol XXII No 2

- (11) कम-विकसित देशों के प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग किया गया तथा उन्हें गरीब बना दिया गया
- (111) विदेशी मुद्रा की आय से कम-विकसित देशों का विकास नहीं किया गया
- (1V) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से व अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी विनिर्माण से कम-विकसित देशों से विकसित देशों की ओर घन गया उदाहरणतया दक्षिणी अमेरिका से 1925 से 1929 तक के बीच 6600 लाख डालर तो लाभ के रूप में बाहर गए जबकि पूँजी के रूप में 2300 लाख डालर ही आए 1950 में यह लाभ की मात्रा 7550 लाख डालर बाहर गए जबकि पूँजी की आमद केवल 330 लाख डालर रही

VIII Duality अर्थव्यवस्था का एक साथ विकसित तथा अविकसित होना, दुहरापन.

कम-विकसित देश 'कुल मिलाकर ही' कम विकसित होते हैं Arthur lewis के शब्दों में In a sea of stagnation, there are islands of development अर्थात् 'पिछड़ेपन के समुद्र के बीच विकास के कुछ टापू मौजूद रहते हैं.'

इन देशों में विकास एक तरफा होता है (Lop-sided development) देश की अधिकांश जनसंख्या पिछड़े किस्म के गावों में रहती है जबकि इन देशों के आधुनिकतम शहरों की भाँति शहर मौजूद रहते हैं देश के असह्य अनपढ़, शिवादी, तथा पुराने आचार-विचार के व्यक्तियों के बीच सुशिक्षित तथा आधुनिक आचार-विचार वाले व्यक्ति (Sophisticated) होते हैं छोटी-छोटी दुकानों के साथ बड़े बड़े आधुनिक "डिपार्टमेंटल स्टोर्स" मौजूद रहते हैं, देश में कुछ आधुनिक व बड़े कार्मांस व दयान के आसपास छोटे छोटे खेत मौजूद रहते हैं यहाँ पर छोटे उद्योगों के साथ बड़े से बड़े उद्योग भी पाए जाते हैं

1 F. A. Mehta : "The Effects of Adverse income terms of trade on the Secular Growth of under-developed Countries "Indian Economic Journal, July, 1956.
 2 Jan 1957.

See : (1) W. Arthur Lewis "Development with unlimited supply of labour see lewis model in following pages.

(11) O. S. Shrivastava, "Economics of wages, productivity Employment" Karish pustak Sadan, Gwalior p 53.

उन्नत क्षेत्रों में साम्प्रदायिक, यातायात शिक्षा व स्वास्थ्य, आवास व रहन-सहन की सुविधाएँ मौजूद रहती हैं इन क्षेत्रों में आर्थिक प्रतियोगिता तीव्र रहती है (Marginal profits are equal in all such islands of development)

कम-विकसित देशों में इस प्रकार से उन्नत तथा पिछड़े दोनों क्षेत्र रहते हैं पिछड़े क्षेत्र (Subsistence sector) में पुराने प्रकार की अर्थव्यवस्था तथा पारम्परिक धर्म विभाजन ही मौजूद रहता है, जबकि उन्नत क्षेत्र में आधुनिकतम विनिमय-मण्डलियों में कार्य होता है पिछड़ा क्षेत्र उन्नत क्षेत्र का भी विकास रोकता है, क्योंकि विकसित क्षेत्रों का बाजार इन कम-विकसित क्षेत्रों में विकसित नहीं हो पाता कम-विकसित क्षेत्र की जनसंख्या कम उत्पादक, गरीब, आसानी से नए कार्य व कार्य पद्धतियाँ न मोख सकने वाली होती है इस क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, बचत व पूँजी की कमी, निम्न उत्पादकता के कारण माँग की कमी रहती है जिसके कारण विकसित क्षेत्र के उद्योग पनप नहीं पाते

IX Under-developed money market · Presence of non-monetized Sector . अर्धविकसित मुद्रा व्यवस्था

कम विकसित देशों में मुद्रा बाजार अधिक विकसित नहीं होने इन देशों में "Call loans" बाजार का अभाव होता है इन देशों में "वित्त बाजार" भी कम-विकसित रहता है देश के भिन्न भिन्न मुद्रा बाजारों में सहसम्बन्ध बहुत कम रहता है, और देश के भिन्न भिन्न बाजारों में व्याज की दरों में एकरूपता नहीं होता नगण्य मुद्रा बाजार तक न आपसी सहयोग की कमी रहती है

इन देशों में Deposit banking प्रणाली भी कम प्रचलित होती है जबकि U S. A तथा U K में चरान मुद्रा में तीन चार गुनी मात्रा में माँग निक्षेप होते हैं, कम विकसित देशों में व आधी मात्रा में भी नहीं होते

कम-विकसित देशों में अधिकाधिक व्यक्ति अपने धन को अपने पास रखते हैं और बैंकों का प्रयोग कम करते हैं इन देशों में केन्द्रीय बैंक देश के अधिकारों साथ निर्माणाकर्ताओं को नियमित करने में प्रभावहीन रहता है. इन देशों में बैंक दर में परिवर्तनों तथा खुले बाजार की नीतियों में उतारो प्रभावशाल नहीं हो पाते.

इन देशों में मुद्रा-बाजार में मौसमी शिथिलता तथा तेजी मौजूद रहती है. इस कारण फण्डों के खोती बाल में व्याज की दर अधिक रहती है और अन्य

समय गिर जाती है। इन देशों में बहुधा विशिष्ट प्रकार की बैंकिंग की संस्थाओं का अभाव रहता है। देश में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली, उपभोग साख प्रदान करने वाली, विक्रय वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएँ तथा स्वीकृति गृह व कटौती गृहों की कमी रहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा का अभाव रहता है। यहाँ देशी बैंकर शोषण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी रखने वाले व्यक्ति मोने, चाँदी के रूप में धन रखते हैं। मट्टों व भूमि के व्यापार में धन लगाते हैं। यहाँ उपभोग के लिए अधिक उधार लिया व दिया जाता है और उत्पादन के लिये पूँजी का अभाव बना रहता है। ये बैंकर देश के नियंत्रण से बाहर बने रहते हैं।

X Backwardness in Fiscal sector : राजकोपीय क्षेत्र व पिछड़ापन

कम-विकसित देशों में प्रत्यक्ष करो से उतनी आय प्राप्त नहीं होती जितनी कि अप्रत्यक्ष करो से प्राप्त होती है। U S. A. एवं U K. तथा जापान जैसे विकसित देशों में आय करो से कुल राज्य की आय का क्रमशः 78, 57 तथा 50 प्रतिशत भाग प्राप्त हो जाती है, भारत में 1968-69 में प्रत्यक्ष करो से केवल 24 प्रतिशत आय प्राप्त हुई। 1950-51 में यह 36 प्रतिशत थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कम-विकसित देशों में अप्रत्यक्ष करो से आय प्राप्त करने की विशेषता रहती है। भारत की प्रथम योजना काल में अप्रत्यक्ष करो से 1373 करोड़ रु० की आय हुई थी जो 1966-67 से 1968-69 के तीन वर्षों में ही 4478 करोड़ हो गई।

कम-विकसित देशों में कर व्यवस्था लोचदार नहीं रहती, यर्थात् जैसे-जैसे इन देशों में आय बढ़ती है, वैसे-वैसे करो से आय नहीं बढ़ पाती। भारत में जी० एस० सोहरा के अनुसार केन्द्रीय करो की यह लोच 613 है तथा केन्द्र व राज्य दोनों की कर आय लोच 833 है।

कम-विकसित देशों में प्रत्यक्ष करो से कम आय प्राप्त होने तथा कर व्यवस्था के कम लोचदार होने के मुख्य कारण यह है कि इन देशों में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। बहुत से व्यक्ति उचित रूप से हिसाब-किताब नहीं रखते और कर प्रशासन की ढील में तथा भ्रष्टाचार के कारण कर-वचन भी बहुत होता है। भारत में उदाहरणतया, केवल एक प्रतिशत व्यक्ति ही आय-कर देते हैं और केवल 7 प्रतिशत राष्ट्रीय आय पर आय-कर दिया जाता है। शेष 99 प्रतिशत व्यक्ति और 93 प्रतिशत आय पर आय कर नहीं दिया जाता।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त कम विकसित देशों में घर का अधिकांश भार शहरी क्षेत्र पर रहता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या रहती है परन्तु वह केवल देश में लगने वाले 15 प्रतिशत घर ही देती है। शहरी क्षेत्र के 25 प्रतिशत व्यक्ति देश में 85 प्रतिशत घर देने हैं। इन देशों में ऊँची आय के लोगों पर घर भार भी अधिक रहता है। भारत में अधिकतम आय-घर 89.5 प्रतिशत हो जाता है जब कि प्रोफेसर काल्ज़ार ने बताया कि देश में अधिकतम आय-घर की मात्रा 45 प्रतिशत हो रहे

कृषि क्षेत्र सबसे कम घर देता है। इसका कारण यह नहीं है कि कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है बल्कि यह भी होता है कि इस क्षेत्र पर जो लगान द्वारा आय प्राप्त होती है वह बेमौजदार पड़ती होती है। लगान से प्राप्त आय अपने आप आय-वृद्धि के साथ बढ़ती नहीं है। उदाहरणतया, नेपाल में जहाँ 1952 में कुल आय का 42% भाग लगान से प्राप्त हुआ वहाँ 1958 में केवल 24% भाग प्राप्त हुआ। अफगानिस्तान में 1951 में लगान का कुल आय में से योगदान 12% से घटकर 1959 में 3% रह गया और भारत में यह प्रतिशत क्रमशः 1939 में 20% तथा 1968 में 7% हो पाया।

कम-विकसित देशों में न्यूनतम छूट की मात्रा भी अधिक उँची रहती है। कम-विकसित देशों में यह छूट प्रति व्यक्ति आय का 11 गुना से लेकर 19 गुना तक पाई गई है।

XI Under-developed natural resources : कम-विकसित प्राकृतिक साधन

बहुधा यह कहा जाता है कि कम-विकसित देशों में साधनों की कमी रहती है, परन्तु यह बात ठीक नहीं है। वास्तव में पिछड़ी तकनीक, भूगर्भ व प्राकृतिक साधनों संबंधी व्यापक सर्वेक्षणों की कमी के कारण ही इन देशों में साधनों के प्रयोग की कमी रहती है। तकनीक, पिछड़ेपन तथा पूँजी, साहसियों और कुशल व्यक्तियों की कमी के कारण जो प्राकृतिक साधन हैं, उनका पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता।

W. S. Woytinsky तथा E. E. Woytinsky के अनुसार केवल सिचाई सुविधाओं के बढ़ा देने से ही ईराक में खेतीकर भूमि की मात्रा 6 मिलियन एकड़

W. S. Woytinsky and E. E. Woytinsky, world population and production, Twentieth century fund, N Y 1953

See chapter on "Natural Resources" in next last.

से बढ़कर 20 मिलियन एकड़ हो जाएगी सीरिया में भी 4 मिलियन एकड़ भूमि से बढ़ कर खेती योग्य भूमि 10 मिलियन एकड़ हो जाएगी तथा टर्की में 25 से 40 मिलियन एकड़ हो जाएगी भारत में अभी भी 75 मिलियन एकड़ भूमि खेतिहर बनाई जा सकती है

A L Banks के अनुसार कम-विकसित देशों में पानी से पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त की जा सकती है परन्तु इस साधन का बहुत कम प्रयोग हो पाता है अफ्रीका में विश्व की बिजली उत्पादन करने के लिए 44% पानी है, परन्तु उसने इस शक्ति का केवल 1% (या 1/10 प्रतिशत) ही प्रयोग किया है यूरोप अपनी पानी की शक्ति का 60% तक प्रयोग कर लेता है जबकि दक्षिणी अमेरिका में केवल 3% प्रयोग होता है और एशिया में 13% प्रयोग हो पाता है

कम-विकसित देशों में शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण खनिज हो जो यहाँ नहीं मिलता हो वन सम्पत्ति भी अपार है घन की कमी, यातायात की सुविधाओं की कमी, साहसियों की कमी या एकाधिकारियों के कारण इनका पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता विदेशी साहसियों ने इन्हें अपने देश के स्वार्थ के लिए ही प्रयोग किया आज भी बहुत से प्राकृतिक साधन पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। निम्नलिखित तालिका में भूमि के प्रयोग की कमी को दर्शाया गया है

1 अमेरिका, अफ्रीका, न्यूगिनी, मेडगास्कर, बोर्नियो	1000	लाख एकड़
2. टर्की, मिथ, इरान, ईराक, सीरिया, इजराइल, लेबेनान	जोर्डन	850 " "
3 यूरोप में (इस को छोड़कर) केवल	15	" "
4. दक्षिणी अमेरिका	70	" "
5. सोवियत	10	" "

कई अन्य कारणों से भी प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। इनमें यह मुख्य है (1) अन्याय सगत भू-नियम, (2) जाति व रंग-भेद नीति, (3) अस्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा स्वास्थ्यप्रद सुविधाओं की कमी (4) राज्य की उदामीनता (5) बाजार की सीमितता तथा तकनीक का पिछड़ापन होता है।

1. A L Banks Ed : The development of tropical and sub-tropical countries 1954. P. 70
See : Charles E kellog : Food soil and people 1951, unescs. p. 23.

XII Absence of external economies बाह्य मितव्ययिताओं की कमी (Or Lack of economic and social overheads)

External economies या बाह्य मितव्ययिताये वे होती हैं जिनके प्रदान करने में अर्थव्यवस्था की समस्त या बहुत सी शक्तियों को लाभ होता है। इन मितव्ययिताओं में देश की मडकें, रेलें, बन्दरगाह, संचार-माधन, डिजनी, सिचाई सुविधाएँ, बैंकों व साख्त सुविधाएँ, शक्ति सुविधाएँ, शिक्षा व ट्रेनिंग सुविधाएँ तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ शामिल हैं। इनको हम आर्थिक व सामाजिक गिरोपरो भी कहते हैं। कम-विकसित देशों में इनकी सरत कमी रहती है।

निजीक्षेप इन बाह्य मितव्ययिताओं के वगैर विकास नहीं कर सकता। इसलिए इन बाह्य मितव्ययिताएँ (Infra structure or social and economic overheads) को प्रदान करना चाहिए क्योंकि इनके प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के पास न तो इतना धन होता है और न तो इतनी प्रेरणा ही होती है। इनकी कमी के कारण विकास में बाधा होती है।

XIII Lack of enterprise and initiative and other co-operant factors. साहसियों तथा उत्पादन में अन्य सहायक अंगों की कमी :

कम-विकसित देशों में सम्पीटर की कम्पता के साहसियों की नितान्त कमी होती है। यहाँ पर साहसियों का पैरा भी कुछ परिवारों और वह भी कुछ जाति-विशेषों तक सीमित रहता है इसके कारण देश का व्यापक विकास नहीं हो पाता इन देशों में बजाय इसके कि बहुत से साहसी दीर्घकालीन विकास में रुचि रखते हो, वास्तव में बहुत ही थोड़े से साहसी होते हैं जोकि मछु के व्यापार, मूदखोरी करने, वितरण क्रियाओं में धन लगाने में तथा सम्पत्ति के व्यापार में लगे रहते हैं इन देशों में बहुधा 'एकाविकारी साहसी' पद्धति रहती है और यह साहसी प्राकृतिक साधनों व देश की जनशक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं।

साहसी मनोवृत्ति की कमी तो राज्य में भी रहती है। इन देशों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी कमी रहती है। संगठनकर्ता व संचालक, आयोजक व प्रबंधक, तथा कृशल मौद्रिक व राजनीतीयनीति विशेषज्ञों की कमी रहती है।

XIV Backward Technology & Low Productivity पिछड़ी तकनीक व कम उत्पादकता

पिछले पृष्ठ में हम देख चुके हैं कि कम-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की मात्रा कम होती है। इसी कारण इन देशों में उत्पादन तकनीक भी पिछड़ी रहती है इन देशों में पूँजी की कमी व जनशक्ति की अविश्वसनीयता रहती है इस कारण यह देश श्रम-गहन तकनीक अपनाते हैं जो बहुधा पिछड़ेपन के कारण कम उत्पादक होती है इसके अतिरिक्त इन देशों में शिक्षा की कमी व अनुसंधान की कमी के कारण प्रशिक्षित व्यक्ति कम रहते हैं और इन कारणों से भी उन्नत तकनीक नहीं अपनाई जा पाती। इस कारण कम उत्पादकता रहती है

कम-विकसित देशों में उत्पादकता मजदूरी घाँकड़ों की कमी रहती है, परन्तु जो भी घाँकड़े हैं उनमें पता लगता है कि कम-विकसित देश बहुत पीछे हैं

“भारत में 1939 में 1959 के बीस वर्षों में उत्पादकता 1% प्रतिवर्ष से बढ़ी जबकि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में इसी काल में उत्पादकता तिगुनी दर से बढ़ी “ यह स्थिति सर्वथा पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था की द्योतक है। विकास के शुरू के काल में उत्पादकता वृद्धि की अधिक संभावनाएँ रहती हैं जबकि विकसित होने पर यह दर गिर जाती है (जैसे किसी बच्चे के कद में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वयस्क कम बढ़ते हैं)।”

रूस में उत्पादकता आयोजन के प्रथम 25 वर्षों में तो 7.5% प्रतिवर्ष से बढ़ी (1928-1955)।

कम-विकसित देशों में उत्पादकता कम होने के मुख्य कारण यह हैं

- (1) इन देशों में पूँजी की कमी के कारण ‘सेफ़ेड हैड’ मशीनें, जिन्हें विकसित-देश नई मशीनें लगाने के बाद बेच देते हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ मशीनों की मरम्मत व अच्छी हालत में बनाए रखने की कमी रहती है, इसके अलावा यहाँ पर घिसावट कोपों की कमी के कारण पुरानी मशीनों का नई मशीनों से उचित प्रतिस्थापन नहीं होता

- (11) यहां के उद्योगों का अनुकूलतम आकार नहीं होता अधिकांश उद्योग छाटे होने हैं जिसकी वजह से बाह्य मितव्ययताओं की कमी होती है
- (111) श्रम की शारीरिक कमजोरी, कार्य-कुशलता की कमी, उनके निम्न रहन सहन के स्तर, अशिष्टा, अन्धविश्वासों, और उत्साह की कमी के कारण भी उत्पादकता कम रहती है
- (1V) इन देशों में राज्य, श्रम सच व उत्पादनकर्ताओं में भी उत्पादकता वृद्धि के प्रति उदासीनता पाई जाती है
- (V) इन देशों में मजदूरी कम होती है श्रम को कार्यानुसार वेतन नहीं मिलता यहां पर वेतन इतने कम रहते हैं कि श्रमिकों में अधिक मात्रा उत्पन्न करने की समता व इच्छा का अभाव रहता है श्रमिकों को लाभ में उचित हिस्सा नहीं मिलता इन देशों में श्रम आन्दोलन कमजोर रहता है और श्रम नेता बहुधा अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं इससे श्रम सच सघर्ष में अधिक विश्वास रखते हैं उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग नहीं करते
- (VI) बेरोजगारी, श्रम की गतिशीलता की कमी व रहन सहन के निम्न स्तर के कारण व्यक्तिगत व सामाजिक उत्पादकता कम रहती है
- (VII) इन देशों में कुशल साहसियों व संगठनकर्ताओं की भी कमी रहती है.
- (VIII) इन देशों में बाजार मकुचित रहते हैं. अतुल्य आवश्यकताओं और बगैर बिके सामान की स्थिति इन देशों में रहती है.

XV Inefficient, Corrupt and apathetic Governmental machinery अयोग्य, अष्ट तथा उदासीन शासकीय प्रशासन .

कम-विकसित देशों में बहुत अधिक राजनैतिक अस्थिरता पाई जाती है. जनतन्त्र तथा तानाशाही यहाँ दोनों असफल होने नजर आते हैं. बहुत से कम-विकसित देशों ने हाल के 25-30 वर्षों में साम्राज्यवादी देशों से स्वतन्त्रता पाई है. कुछ देशों को छोड़ कर इन देशों में योग्य व उत्साही नेताओं का अभाव पाया गया है. बहुत से कम-विकसित देशों में आए दिन राजनैतिक तन्ना पलट (Coup de tat) होते रहते हैं. कम-विकसित देशों में कालान्तर में राजनैतिक नेता अपने या अपनी जाति, वर्ग या पार्टी के स्वार्थ हिन में लग जाते हैं. ये स्वयं अष्ट होते हैं और समस्त सरकारी व्यवस्था में अष्टाचार फैला देते हैं. इनकी कयती और

कर्मियों में अन्तर होता है और ये नेता (leaders) फिर (misleaders) गुमराह करने वाले बन जाते हैं पद सोलुपता में पड़े ये नेता, विकास की ओर कितना ध्यान दे सकते हैं

Prof Gunnar Myrdal ने 1968 में एक पुस्तक world Corruption की समस्या पर निकाली है उसमें उन्होंने लिखा है कि कम-विकसित देशों में विकसित देशों के मुकाबले में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है कम-विकसित देशों में एशिया व इण्डोनेशिया में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है

आज की स्थिति यह है कि बहुत से कर्मचारी व राजनैतिक नेता जिनके हाथ में सार्वजनिक धन व शक्ति है वे या तो अपनी शक्ति या धन या दोनों का दुरुपयोग करते हैं

Sir Winston Churchill ने एक बार कहा था

✓ 'एक नेता वह होता है जो आज यह कहे कि कल वह क्या करने वाला है और फिर कल यह कह सके कि वह प्रस्तावित कार्य क्यों नहीं कर सका'.

Shri Sanjiva Reddy ने (अध्यक्ष-लोकसभा, कांग्रेस अध्यक्ष, आन्ध्र के मुख्य-मंत्री व केन्द्र के मंत्री के महत्वपूर्ण पदों पर जो कार्य कर चुके हैं) एक बार कहा था

पहले वही व्यक्ति (राजनैतिक नेता या पदाधिकारी) भ्रष्ट समझा जाता था जिसे न्यायालय भ्रष्ट घोषित कर दे आज हर उस व्यक्ति को भ्रष्ट समझा जाता है जिसे न्यायालय यह घोषित न कर दे कि वह भ्रष्ट नहीं है

इन्हीं कारणों से जनता का उत्साह कम होता है और देश की मनोवृत्ति धन कमाने की होती है, विकास करने से ध्यान हट जाता है

XVI Inhibitory social factors सामाजिक पिछड़ापन व विकास में बाधाएँ

कम-विकसित देशों में बहुत से सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक तत्व हैं जो विकास में बाधक होते हैं. यहाँ के (विशेष रूप से एशिया के) व्यक्ति इस लोक से अधिक "परलोक" को सुधारने में अधिक रुचि रखते हैं ईश्वर पर अंधविश्वास उन्हें निर्लक्ष्य बनाता है, जातिवाद या धार्मिक प्रतिद्वन्द्वों के कारण व्यवसायिक गतिशीलता की कमी रहती है

शिक्षा के प्रति उदासीनता से रूढ़िवादिता, अयोग्यता तथा अज्ञानता बनी रहती है (उदाहरणतया भासी जिले में माताटीता बाघ का पानी जब सिंचाई के लिए छोड़ा गया तो कई किसानों ने उसका प्रयोग करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनके अनुसार 'उस पानी की विजन्ती निकल जाने में उसके गुण समाप्त हो गए थे,' बाढ़ में कई नेताओं को यह भ्रान्ति दूर करनी पड़ी)

इन्हीं कारणों से इन देशों में धार्मिक कार्यों में बहुत धन खर्च कर देते हैं तथा वक्तों को मस्याकरण करने के स्थान पर सोना चांदी के रूप में रखते हैं. इन्हीं कारणों से इन देशों में स्वास्थ्य व परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने में बाधा उत्पन्न होती है

अध्याय 4

आर्थिक विकास के मॉडलों का स्वभाव व महत्व

The nature and Importance of Economic growth models

- 1 मॉडल का अर्थ :
किन्डल वरजर, प्रो० मेहता, जी० मीयर, आदि.
- 2 मॉडलों के प्रकार :
 - (1) Aggregate models (कुल मॉडल)
 - (2) Sector models (क्षेत्रीय मॉडल)
 - (3) Inter-industry models (अन्तर-उद्योग मॉडल)
 - (4) Single period models (समय विशेष का मॉडल)
 - (5) Long period models (दीर्घकालीन मॉडल)
 - (6) Macro dynamic model (बृहद्-प्रवैगिक आर्थिक विकास मॉडल)
 - (7) Descriptive, mathematical and econometric models, (विरलेपखात्मक, गणित मॉडल तथा एकोनोमेट्रिक मॉडल).
 - (8) Linear and non-linear models.
 - (9) Closed and open models
3. विकास मॉडलों का महत्व व सीमाएँ :

आर्थिक विकास के मॉडलों का स्वभाव व महत्व

The nature and importance of economic growth models

I परिभाषा

श्री किण्डल बर्जर¹ के शब्दों में - 'एक आर्थिक मॉडल' विभिन्न परिवर्तनशील आर्थिक तत्वों व घटकों के बीच सह-सम्बन्ध को ग्याख्या करता है एक मॉडल प्रमुख तत्वों में कारण व परिणाम मन्व्य बनाता है हम मॉडल के अध्ययन से अर्थव्यवस्था की गति का अध्ययन कर सकते हैं बहुधा इस बात की शीघ्रता व सरलता से समझने के लिए हम बहुत सी अटिलताओं को निवाल देते हैं, अर्थात् कुछ सरल मान्यताओं के आधार पर अध्ययन करते हैं

हम अपने मॉडलों को गद्य में व्यक्त कर सकते हैं, या 'ज्योमेट्री' के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर वीजगणित व अक्षरगणित की भाषा में व्यक्त कर सकते हैं. मॉडल की विशेषता यह होती है कि आर्थिक तत्वों व घटकों के सह-सम्बन्ध को हम सांख्यिकीय द्वारा नाप सकते हैं ¹

प्रो० जे० के० मेहता² मॉडल बनाने से पूर्व हम, कुछ बे मान्यताएँ मानते हैं, जिनके आधार पर अर्थ-व्यवस्था चलती है इन मान्यताओं पर आधारित सह-सम्बन्धों को हम गणित के साँचों में ढाल देते हैं इन सह-सम्बन्धों के आधार पर एक साथ समीकरण बनाये जाते हैं और हल किये जाते हैं फिर इन गणित के सह-सम्बन्धों के समीकरणों से आर्थिक सम्बन्धों का निष्कर्षरूपी विश्लेषण हो जाता है (इसे हम उभी प्रकार में करते हैं, जैसे - एक भौतिक शास्त्री "ध्वनी तरंगों" को "रेडियो तरंगों" में बदल देते हैं और उन्हें सब तरफ फैलाकर पुन. "ध्वनी तरंगों" में बदल लेते हैं).

(1) C. P. Kindleberger : Economic Development : p. 40.

(2) J. K. Mehta : Economics of growth - p. 5.

हमारे मॉडल के कुछ Parameters (स्थिर राशियाँ) होते हैं और कुछ Variables (परिवर्तनशील राशियाँ) होते हैं. यह Parameters प्राकृतिक हो सकते हैं या उत्पादन-कर्ताओं व उपभोग-कर्ताओं के निर्णयों के आधार पर निर्धारित होते हैं. विकास मॉडलों में Parameters की सीमा में Variables निर्धारित होते हैं. जब हम अपने मॉडल में Variables का साम्य अध्ययन करते हैं तो यह स्थगिक मॉडल होता है और अगर हम इन परिवर्तनशील घटकों का परिवर्तन पथ अध्ययन करते हैं तो यह प्रवैगिक मॉडल हो जाता है.

हम मॉडलों में बहुधा "बृहद् प्रवैगिक तत्वों" को जो माँग और पूर्ति दोनों पक्षों के होते हैं तथा जो समाज की आय में परिवर्तन लाते हैं, अध्ययन करते हैं

प्रो. जी. मीयर :

प्रो. जी. मीयर के अनुसार 'A model provides a Systematic frame work for economic programming.'

प्रो. मीयर का कथन है ' एक आर्थिक मॉडल किसी भी आर्थिक इकाई (चाहे वह एक घर हो, या एक उद्योग हो या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो) को संचालित करने वाले संगठित सह-संबंधों का वर्णन करता है वैसे तो हमारे आर्थिक संबंधों का वर्णन हम करते ही रहते हैं परन्तु जब हम इन आर्थिक संबंधों को गणित के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वे explicit model होते हैं (स्पष्ट मॉडल) अन्यथा "शब्दों के माध्यम से विश्लेषण" को हम Implicit model उपलक्षित मॉडल कहेंगे

हर देश में कुछ आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं. हमारे आर्थिक मॉडल हमको इन्हीं लक्ष्यों के प्राप्त करने के रास्ते बतलाते हैं. The ultimate test of a model is that it should make the best use of the available information and analytical resources within the time available for its construction.

II मॉडलों के प्रकार व विभिन्न नाम .

1 Aggregate models (समष्टि मॉडल) ये वे मॉडल होते हैं जो

Cf : Gerald Meier : Leading Issues in Development Economics
Oxford 1964, p. 465-467.

समस्त अर्थव्यवस्था के लिए होने हैं इन मॉडलों में उत्पादन, उपभोग, विनियोजन तथा अन्य प्रयोगों को एक पूरा aggregate माना जाता है.

2. Sector models • (क्षेत्रीय मॉडल) ये वे मॉडल होने हैं जो केवल एक Sector विशेष में लागू होने हैं और इसी प्रकार में बनाए भी जाते हैं.

3. Inter-Industry models अन्तर-उद्योग मॉडल :

इन मॉडलों में हम यह अध्ययन करते हैं कि प्रत्येक Sector model का आपस में क्या संबंध है तथा इनका पूर्ण अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है.

4. A Single period model एक समय विशेष का मॉडल

एक समय विशेष के मॉडल में निम्नलिखित चार सह-सम्बन्धों के आधार पर विश्लेषण करते हैं और मॉडल बनाते हैं ये तो चार मह-सम्बन्ध हैं

(i) Capital-output ratio पूँजी-उत्पादन अनुपात

(ii) The investment demand schedule. विनियोजन-माँग तालिका.

(iii) The saving supply schedule बचत-पूर्ति तालिका.

(iv) The Population Growth relations. जनसंख्या वृद्धि संबंधानुपात.

5. The long-period model • दीर्घकालीन मॉडल •

किसी भी देश में ऐसा मॉडल नहीं बनाया जा सकता जो बहुत लम्बे काल के लिए उपयुक्त बना रहे. ऐसा मॉडल कभी नहीं बनाया जा सकता जिसके अनुसार एक

1-3 : See : Gerald Meier op. Cit

4 : Harvey Leibenstein : Economic Backwardness & Economic Growth p 195

5 . Prof Hoffmann : Cf. comments on Robertson's paper on "Stability and progress—Richer Country's Problem, First International Congress of International Eco. Association 1958". In I. E. A's : Stability & progress in world Economy : Ed. D. C. Hague.

देश गरीबी में अभीरी की पहुँच जाए अल्पकालीन मॉडल में Constant rates and ratios (अर्थात् उदाहरणतया पूँजी-उत्पादन अनुपात, या आय वचत अनुपात समान माने जा सकते हैं) की मान्यता की जा सकती है परन्तु दीर्घकाल में यह मान्यता गलत हो जाती है.

दीर्घकालीन मॉडल 'Straight line' के स्वभाव के नहीं हो सकते अर्थात् एक सी विकास दर के नहीं हो सकते इसलिए वास्तव में दीर्घकालीन मॉडल कई अल्पकालीन मॉडलों में तोड़ा जाता है या कई अल्पकालीन मॉडलों को मिलाकर ही एक दीर्घकालीन मॉडल बन सकता है. परन्तु हर अल्पकालीन मॉडल में rates and ratios (दरें व अनुपात) घलग-घलग होते हैं

6 Macro dynamic economic growth Models : बृहद-प्रवैगिक आर्थिक विकास मॉडल

ये मॉडल बहुत बृहद समष्टि या समग्र Large aggregates से संबंधित होते हैं इन मॉडलों में हम यह अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से विनियोजन व आय बढ़े कि साहमियों की अपनी आकांक्षाओं और अनुमानों के अनुसार नतीजे प्राप्त हो सकें परन्तु ये मॉडल सुस्थिर रूप से विकास की समस्याओं पर प्रकाश नहीं डालते. (They do not throw much light on the problem of stable growth)

बृहद-प्रवैगिक आर्थिक मॉडल से अधिक व्यवहारिक महत्व के Sectoral Models या क्षेत्रीय मॉडल होते हैं.

7 Descriptive mathematical and econometric models विश्लेषणात्मक, गणित मॉडल तथा ऐकोनोमेट्रिक मॉडल

पहले विकास संबंधी विचारों को तथा महत्वों की व्याख्या को साधारण व सरल भाषा में व्यक्त किया जाता था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार इसी रूप से व्यक्त किए गए थे. ये Implicit models या Descriptive models थे.

बाद में अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग किया जाने लगा. इससे descriptive models इतने लंबे होने लगे कि उनके सार को Mathematical model में परिष्कृत करना बहुत लाभदायक रहा. Mathematical model सक्षम होने के साथ साथ Precise या निश्चित या स्पष्ट भी थे

वेस न अपने माडल में Multiplier या गुणक का प्रयोग किया तत्परचात हरोड व डोमर न Accelerator का प्रयोग किया Prof Erich Schneider के शब्दा में गुणक तथा त्वरक का वाद में ज़र औपचारिक विवाद हो गया तब माडल और जटिल होत गए

8 Linear and Non linear Models

शुरू में माडल Linear हत य अर्थात् वह बतात य कि विकास का पथ सीधा है वाद में इस अवास्तविकता को छोड़ दिया गया और Non linear model बनाए जात लत इन माडलों में विकास की उच्चतम सामा व न्यूनतम सामाएँ रखा जाती है इन माडलों में विकास में Symmetry का मान्यता या विकास का यथा-संगत रूप में वढन की मान्यता के स्थान पर Asymmetrical रूप में वढता माना गया Non linear मान्यता वास्तविकता के प्रभाव का भी समावेश किया गया (Exogeneous shocks were taken note of) प्रो० हैबरलर के शब्दों में प्राज Econometric models इन ढर में बनाए जा रह ह जगे कि वास्तविकता से मोटरो के माडल निकल रह ह

9 Closed and open models बन्द व खुल माडल

निम्न माडलों में विकास पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता व माडल Closed model कह जात ह तथा निम्न माडलों में यह प्रभाव अध्ययन किया जाता ह व Open model होत ह

Closed model अवास्तविक होत ह पण उस मरत अध्ययन के लिए अध्ययन किए जात है

III Importance and limitations of growth models विकास माडलों की महत्ता का महत्त्व व सीमाएँ

विकास के हमेशा कुछ न य रहत ह किसी भी देश में विकास का सम्य देश में

Erich Schneider's quoted from his comments on prof perronx paper on The Quest for stability The real factors 1st conference of International conference of economists
I E A op cit Ed D C Hague

Gottfried Haberler quoted from D C Hague's op cit
The Quest for stability The monetary factors

पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना, अधिकतम आय का भूजन करना, प्रतिकूल भुगतान सतुलन को दूर करना या कुछ और भी हो सकता है।

विशाल मॉडल हमको बतलाते हैं कि किस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न विकास घटकों के बीच सह-संबंध है या होना चाहिए तथा वे यह भी बतलाते हैं कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कौन सा पथ सुगम व सरल है। अगर हम मॉडलों से सह-संबंधों के परिवर्तनों को माना में परिवर्तन का अन्दाज लगा सकें तो हम आवश्यक सुधार भी कर सकते हैं।

मॉडल हमेशा कुछ मान्यताओं पर आधारित रहते हैं अगर मॉडलों को वास्तविक होना है तो इन मान्यताओं को भी वास्तविक होना चाहिए अन्यथा मॉडल अवास्तविक रह जाएगा

सीमाएं

मॉडल अध्ययन पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं

- (1) अगर मॉडल अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित हो तो मॉडल भी अवास्तविक हो जायेंगे
- (11) मॉडलों में मुद्रा, बैंक, साख्त मुद्रा व मुद्रा संस्थाओं को, व्याज की दर तथा अन्य परिवर्तनों को मुख्य स्थान नहीं मिलता इनमें बचत व निवेश, उत्पादन अनुपातों को प्रमुख स्थान मिल पाता है प्रोफेसर हेयरलर के अनुसार इसके परिणाम निराशाजनक होते हैं।
- (111) प्रो जे के मेहता ने अपनी पुस्तक "Economics of growth" की प्रस्तावना में लिखा है 'गणित विश्लेषण का महत्वपूर्ण साधन है, परन्तु उमकी उम आर्थिक प्रष्टि विषय, जिसका उसे विश्लेषण करना है, उसे ही आच्छादित नहीं कर देना चाहिए "

See also : "We can-not approve of a model that yields income increasing at an exponential rate, nor any that makes it increase evenly and smoothly with mathematical precision, what is needed, therefore, is a model that gives us uneven oscillations of income around an unevenly rising trend "

प्रो० मेहता का कथन है कि हर वह मॉडल जो थाय पर्सनिबल को पूर्ण शुद्धता न बतलाता है हमको मान्य नहीं हो सकता मानव व्यवस्था को सभी भी पूर्ण शुद्धता से व्यक्त नहीं किया जा सकता

पूर्ण यथार्थता का मॉडल अवास्तविक होगा और वास्तविक मॉडल हम बना नहीं सकते

- (17) एवसी डोमर भी इसी प्रकार कहते हैं "हम विकास मॉडलों को व्यवहारिक पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग करने का प्रलोभन हमेशा रहता है पर ऐसा करने में हम गहरी खाइया में गिर सकते हैं. हमारे मॉडल जो विकास की दूर दिखाने हैं वे कागज पर ही रह जाती हैं. हमारी मायनाएँ बहुत गम्भीर रूप से अश्ववहारिक (Heroic abstractory) होती हैं

अध्याय : 5

एडम स्मिथ का विकास मॉडल

(Adam Smith on growth)

I प्रस्तावना

- 1 विकास भूमि, श्रम, पूँजी व संगठन के सहयोग का फल है
- 2 आर्थिक विकास श्रम विभाजन के विस्तार व सफलता पर निर्भर है
- 3 विकास के लिए निर्बाधवादी नीति या स्वतन्त्रता आवश्यक है राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए
- 4 विकास अधिक लाभ पर निर्भर है लाभ, मजदूरी व व्याज में सन्तुलन
- 5 विकास स्तुति होना चाहिए कृषि व उद्योग को समान महत्व
- 6 विकास के लिए स्वतन्त्र व्यापार आवश्यक है
- 7 'निम्नकोटि' के व्यक्तियों की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए
- 8 विकास प्रक्रिया उत्तरोत्तर और संचयी रूप से होने वाली प्रक्रिया है

II आलोचनात्मक समीक्षा

मॉडल के गुण

मॉडल के दोष -

एडम स्मिथ का विकास मॉडल

(Adam Smith on growth)

प्रस्तावना

एडम स्मिथ ने, जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने विकास दटाने वाले आर्थिक व सामाजिक तत्वों का गहन अध्ययन किया। Wealth शब्द का प्रयोग उन्होंने उस अर्थ में किया था जिसमें आज हम national income शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर एडम स्मिथ आज उस पुस्तक को लिखते तो उस पुस्तक का नाम 'National income of Nations' रखते।

एडम स्मिथ के विकास सबूतों सिद्धान्तों को हम निम्नलिखित विवेचना कर सकते हैं।

1 विकास, भूमि, श्रम, पूँजी व संगठन के सहयोग का फल है Growth is a function of land, labour, capital and organisation

एडम स्मिथ विकास को भूमि, श्रम, पूँजी व संगठन के सहयोग का फल मानते थे, भूमि निष्क्रिय होती है श्रम, भूमि में अधिक महत्वपूर्ण होता है पर पूँजी व श्रम में वे किसको महत्वपूर्ण मानते थे, इसका सही अन्दाज उनकी पुस्तक में नहीं मिलता क्योंकि कहीं उन्होंने श्रम को अधिक महत्वपूर्ण और वहाँ पूँजी को अधिक महत्वपूर्ण माना। श्रम के बारे में उन्होंने एक जगह लिखा

"श्रम ही वह पदार्थ है जो किसी राष्ट्र को वार्षिक उपभोग के लिए समस्त सुविधाओं और आवश्यकताओं को प्रदान करता है"

पर जैसे जैसे हम स्मिथ के विकास के सिद्धान्त का अधिक अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वे वस्तु व पूँजी को ही विकासकारक प्रमुख तत्व मानते थे (Capital was regarded by him as engine of growth)

1. देखिये,

Introduction to his book 'Wealth of Nations' (Edwin Cannan Edition) 1950

एडम स्मिथ विवेकपूर्ण व्यय व विफायतसारी या मितव्ययिता को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, उन्होंने लिखा

“पूंजी मितव्ययिता से बढ़ती है और फिजूलखर्ची व दुराचरण में घटती है मेहनत से अधिक मितव्ययिता ॥ पूंजी संचित होती है.”

“Capitals are increased by parsimony and diminished by prodigality and misconduct... . parsimony and not industry is the immediate cause of the increase of capital ”¹

एडम स्मिथ मुद्रा व श्रम-विभाजन के बाद, पूंजी को ही विकासकारक सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते थे उन्होंने लिखा

“यह जाहिर है कि किसी भी देश में उत्पादक श्रमिकों की संख्या उसी मात्रा में बढ़ सकती है जिस अनुपात में देश में पूंजी का संचय बढ़ सकता है .. देश में पूंजी वृद्धि या कमी के अनुपात में ही देश में उत्पादक श्रमिकों, उद्योगों, श्रम व भूमि का उत्पादन, वास्तविक धन व देशवासियों की आय बढ़ती या घटती है ”¹

2 आर्थिक विकास श्रम विभाजन के विस्तार व सफलता पर निर्भर है :

(Economic growth takes place through the principle of division of labour)

एडम स्मिथ के अनुसार विकास श्रम-विभाजन के विस्तार व सफलता पर निर्भर है वे श्रम-विभाजन को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने अपनी पुस्तक का पहला अध्याय ही ‘श्रम विभाजन’ पर लिखा उनके अनुसार श्रम-विभाजन वृहत् समाज के सहयोग का ही एक अंग है श्रम विभाजन विनिमय पर आधारित होता है और दोनों के होने से ही उत्पादन व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है श्रम विभाजन से ही श्रमिकों की दक्षता व कुशलता बढ़ती है उत्पादन का समय बचता है व अच्छी व अधिक वस्तुएँ कम लागत में बँठती हैं इसी से लाभ बढ़ते हैं, बाजार विस्तृत होते हैं तथा आविष्कारों की संख्या बढ़ती है

श्रम-विभाजन का विस्तार बाजार के विस्तार पर निर्भर करता है इसी कारण एडम स्मिथ बाजार विस्तार के लिए साम्राज्य के विस्तार की सिफारिश करते थे और अधिक पूंजी संचय की सलाह देते थे

1. See volume I Book. II.

2 Op Cit : Ibid.

- 3 विकास के लिए निर्बाधता नीति या स्वतन्त्रता आवश्यक राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए (Freedom and policy of laissez faire necessary for growth Role of the government to be minimum)

एडम स्मिथ का विश्वास था कि निजी क्षेत्र के विकास से ही देश का विकास होता है वे चाहते थे कि राज्य केवल देश में न्याय व सुरक्षा का प्रबन्ध करे तथा कुछ आवश्यक सार्वजनिक निर्माण कार्य भी (जैसे सड़क निर्माण, बन्दरगाह बनाना, नहरों व यातायात विस्तार) हाथ में ले स्यास्व्य व शिक्षा विकास का कार्य भी राज्य अपने हाथ में ले सकता है वे नहीं चाहते थे कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में दखल दे या स्वयं उद्योग चलाए क्योंकि राज्य के कर्मचारी अकुशल, लापरवाह, भ्राट तथा घकर्मण्य होते हैं राज्य चलाने वाले व्यापारिक जगत की दक्षतादिक्ता से परे रहते हैं इस कारण गलत काम करने हैं और फिगूलखर्ची करते हैं उन्होने कहा था

“The government are always and without any exception and greatest spendthrift in society.”¹

एडम स्मिथ बहुमुखी कर चाहते थे, पर वे लाभ पर कर नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें पूँजी निर्माण कम होता है. उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति अपने भले के लिये जो कार्य करेगा उससे देश में विकास होगा अगर हर व्यक्ति को अपना पेशा, विनियोजन चुनने और मूल्य निर्धारण करने की स्वतन्त्रता हो तो देश में आर्थिक विकास स्वयं होगा उन्होने कहा

“किसी भी देश को निम्नकोटि की बर्बरता से उच्चतमकोटि की समृद्धि की स्थिति में पहुँचाने के लिये सिवाय देश में शांति, कम प सरल कर, व उचित न्यय के दिसी और चीज की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में विकास तो प्राकृतिक रूप से होगा अर्थात् स्वयं जातिता होगा”²

4. विकास अधिक लाभ पर निर्भर है • लाभ व मजदूरी और व्याज • (Growth a function of high profits • profits vs wages and interest)

एडम स्मिथ लाभ व पूँजी निर्माण को परस्पर सम्बन्धित मानते थे. लाभ अधिक

1. Cf : His book. I op Cit Vol I

2 Cf • Book IV : Ch IX

होगे, पर उनको भय था कि दीर्घकाल में, प्रतियोगिता के कारण, लाभ कम होते जाएंगे. उन्होंने लिखा -

“जब स्टाक (पूंजी में वृद्धि) होती है, तो मजदूरी बढ़ती है, पर लाभ गिर जाते हैं जब बहुत से धनी व्यापारी अपनी पूंजी एक ही व्यापार या उद्योग में लगा देते हैं, तो उनकी परस्पर प्रतियोगिता से लाभ कम हो जाते हैं”¹

एडम स्मिथ का विश्वास था कि लाभ और मजदूरी में प्रतिकूल संबंध होता है. अर्थात् अगर मजदूरी कम हो तब ही लाभ अधिक होंगे. केवल एक नये उपनिवेश दोनों एकसाथ बढ़ सकते हैं. इसी डर उन्होंने अपनी पुस्तक में अधिक स्थानों पर कम मजदूरी देने की सफारिश की. उनका कथन था कि अगर मजदूरों को अधिक मजदूरी दी गई तो वे अधिक वच्चे पैदा करेंगे और इसलिए उनको जीवन निर्वाह के बराबर ही मजदूरी दी जाए ताकि लाभ अधिक रहे.

परन्तु अन्य स्थानों पर उन्होंने मजदूरों के अन्य सिद्धान्तों का भी विश्लेषण किया. कहीं कहीं पर तो उन्होंने मजदूरों के प्रति बहुत उदारता दिखाई. उनका कथन था कि अगर देश में विनियोजन की मात्रा व दर अधिक बनाई रखी जाए तथा अगर उत्पादन, उत्पादकता व रोजगार के स्तर ऊँचे रखे जाएँ तो अधिक मजदूरी दी जा सकती है और यह विकास में बाधक नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा

“यह आवश्यक है कि जो दूसरों को खिलाते हैं व कपड़े पहनाते हैं, वे स्वयं भी अच्छा खाएँ व पहने.”

परन्तु एडम स्मिथ को भय था कि दीर्घकाल में लाभ कम हो जाएंगे, मजदूरी जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर रह जायगी और अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाएगी, जिसके आगे विकास संभव नहीं होगा

5. एडम स्मिथ “संतुलित विकास” चाहते थे (Growth to be ‘balanced’) कृषि ■ उद्योग को समान महत्व :

आमतौर से यह धारणा है कि एडम स्मिथ औद्योगीकरण के प्रदल समर्थक थे. हालाँकि वे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति के युग के प्रथम दृष्ट थे, वे “फिजियो-क्रैट्स” के प्रभाव में थे, और कृषि को उन्नति को विकास में महत्वपूर्ण मानते थे. उन्होंने लिखा :

“जितने व्यक्ति कृषि में कार्य करते हैं, अगर उतने ही औद्योगिक

उत्पादन में भी लगा दिए जाएँ तो वे कभी भी उतना पुनरुत्पादन नहीं कर सकते. उद्योगों में प्रवृत्ति का कोई योगदान नहीं होता, सब कुछ मनुष्य ही करता है." ¹

कृषि के बाद, वे उद्योगों व व्यापार के विस्तार को विकास के लिए आवश्यक मानते थे, पर वे उद्योगों व व्यापार में लगे व्यक्तियों को धालाधडी व शोषण की प्रवृत्तियों के आलोचक थे. विकास के लिए वे बाह्य-मितव्ययिताओं के मृजन को आवश्यक मानते थे, अर्थात् यातायात संचार के साधनों का विकास चाहते थे. उनका विश्वास था कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र का विकास-कारक हो.

6. विकास के लिए स्वतन्त्र व्यापार आवश्यक : (Free trade promotes growth)

एडम स्मिथ मुक्त व्यापार के समर्थक थे और उनका विश्वास था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है. वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अनावश्यक नियमों, बन्दिशों, सटफरो और प्रतिबन्धों से मुक्त कराना चाहते थे जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में देश की आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ बाहर भेजी जाती हैं और आवश्यकतानुसार विदेशी वस्तुएँ मंगाई जा सकती हैं. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बाजार बढता है, श्रम विभाजन का विस्तार होता है, उत्पादन प्रणाली के विशिष्टीकरण में वृद्धि होती है तथा बहुउद्देशीय विनिमय बढ़ता है यह सब आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने लिखा :

"यह सब सम्भवतः परिवारों के मुखियों (Masters of families) का सिद्धान्त है कि जो कुछ वस्तु वे बाहर से सस्ता खरीद सकते हैं वह उन्हें घर पर महंगा नहीं बनाना चाहिए यह बात अगर एक व्यक्ति के लिए विदेकपूर्ण व अकलमंद बात है तो राज्य के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकती." ²

वे केवल सुरक्षा उद्योगों के लिए 'भरसख' की नीति को उचित मानते थे. क्योंकि वे 'सुरक्षा' को समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे. (Defence is more important than opulence).

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वे किसी विशेष मुद्रा-व्यवस्था को नहीं चाहते थे. वे तो केवल 'स्वर्णमान' चाहते थे. और वे सोने व चांदी के निर्यात या आयात पर

1. Ibid. p. 161.

2. Vol. I : Book II.

भी, वस्तुओं के निर्यात या आयात की भाँति, कोई प्रतिबन्ध नहीं चाहते थे। उनका विश्वास था कि स्वर्णमान स्वयं संचालित होता है। जैसे अगर देश में आयात अधिक होता है और स्वर्ण बाहर जाता है तो मूल्य गिर जाएँगे (वस्तुओं के बाहर से आने व मुद्रा की कमी से) और मूल्य गिरने से जोग देश की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और विदेशी भी देश से सामान मँगाएँगे, और निर्यात बढ़ेंगे, व आयात कम होंगे तथा स्वर्ण वापिस आ जाएगा। वे कहते थे .

“Look after trade and gold will look after itself.” (साप व्यापार पर ध्यान दीजिए सोना खुद अपने पर ध्यान रखेगा).

7. “निम्नकोटि” के व्यक्तियों की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो. (Population growth of the “inferior ranks” to be controlled)

एडम स्मिथ के “प्रकृतिवाद व आशावाद” के कारण वैसे तो उनका विश्वास था कि जनसंख्या जब कभी भी अधिक हुई तो मृत्यु दर की अधिकता से जनसंख्या का स्तर फिर सतुलित हो जाएगा, फिर भी वे चाहते थे कि “निम्न श्रेणी” के लोगों को जनसंख्या नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा विकास रुक जाएगा.

8. एडम स्मिथ विकास प्रक्रिया को उत्तरोत्तर और संचित रूप से बढ़ने वाली प्रक्रिया मानते थे. (Growth is a gradual and cumulative process).

एडम स्मिथ का विश्वास था कि एक बार विकास शुरू हो गया तो देश में विकास होता ही रहेगा. विकास की राह में कोई मन्दी की बाधा नहीं आयेगी. उनका विश्वास था कि माँग और पूर्ति सतुलित रहेंगे और पूर्ति अपनी माँग स्वयं पैदा कर लेगी, इस कारण देश में कभी बेरोजगारी का भय नहीं होगा

उन्होंने विकास की प्रक्रिया की अन्तर-खण्ड वृत्तीय रूप में सचित्रित माना (He emphasized that there is inter-sectoral relationship in growth) जो कि इस प्रकार होती है.

अगर हम अधिक बचत कर सकते हैं तो अधिक पूँजी निर्माण होगा, श्रम विभाजन में विस्तार होगा, अधिक विनियोजन होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, राष्ट्रीय व प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी, माँग या बाजार बढ़ेगा, विशिष्टीकरण

उन्नत होगा तथा इससे और अधिक धर्म विभाजन बढ़ेगा और वचत व पूँजी निर्माण में वृद्धि होगी

उनका विश्वास था कि स्थिर वास्तविक मजदूरी पर असीमित धर्म शक्ति जब तक प्राप्त है पूँजी निर्माण से विकसित हो सकता है और मजदूरी स्थिर रखना चाहिए व लाभ बढ़ते रहने देना चाहिए जब मजदूरी बढ़ेगी तब इस पद्धति से विकास रुक जाएगा ¹

C : आलोचनात्मक समीक्षा

मॉडल के गुण :

- (1) एडम स्मिथ ने वचता की वृद्धि के लिए जो मितव्ययिता से रहने की आवश्यकता बताई है वह आज के विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है
- (2) एडम स्मिथ ने पूँजी निर्माण को *engine of growth* बताया यह भी आज के विकासशील देशों को ध्यान देने योग्य बात है
- (3) एडम स्मिथ ने *growth from bottom* अर्थात् नीचे (आधार) से विकास की सिफारिश की, अर्थात् उन्होंने कृषि को सर्वप्रथम उन्नत करने की सिफारिश की यह बात आज भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है जहाँ कि 10 व्यक्तियों में से जो 7 व्यक्ति कृषि में लगे हैं वे न तो अपने लिए और न बाकी तीन व्यक्तियों के लिए उत्तम, पर्याप्त मात्रा में सतुलित आहार प्रदान कर पाते हैं और करोड़ों रुपये के प्रनाज बाहर से मँगाना पड़ता है जिससे हम विदेशों से मशीनें मंगा सकते थे
- (4) एडम स्मिथ ने विकास को सतुलित रूप में बढ़ाने की सिफारिश की, उनके मान्यन की यह अच्छाई थी कि उन्होंने धर्म विभाजन के विस्तार को महत्व दिया व अन्तर-सहवृत्तीय के निर्भरता को समझाया
- (5) कुछ हद तक हम उनकी निर्वाधवादी नीति को भी अच्छा मान सकते हैं भारत में ही राज्य के अधिकार वारखाने व व्यवसाय हानि में चल रहे हैं और पूँजी निर्माण के स्थान पर पूँजी ह्रास के कारण बने हुए हैं श्री ब्रह्मानन्द प्रसाद ने लिखा, "Adam Smith's adventuion for creation of suitable climate for

1 : इसकी और अधिक व्याख्या के लिए Nurkse-Lewis model देखिए.

a freer expression of 'self-interest' for achieving general well-being has some relevance for our conditions unimaginitive pursuance (of planning) can be the cause of showing down of entrepreneurial efforts and ultimately the econony may slide back to stagnation ¹

मॉडल की कमियाँ व दोष :

- (1) उन्होंने अपने विकास मॉडल म साहसी को महत्व नहीं दिया जो सर्वथा गलत था
- (2) वे राज्य को जो कम महत्व देते हैं वह ठीक नहीं हैं राज्य ही आज कम-विकसित देशो म विकास का कार्य शुरु करता है उसकी सहायता व प्रत्यक्ष कार्यों के वगैर आज के युग मे विकास संभव नहीं है
- (6) एडम स्मिथ के व्यापार चक्रों के सम्बन्ध में जो आशावादी विचार थे वे सर्वथा त्रुटिपूर्ण थे इनके विकास के सिद्धान्त म इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि व्यापार चक्र बँमे उत्पन्न होते हैं तथा इनको कैसे ठीक किया जा सकता है अथवा अर्थ-व्यवस्था मे स्थायित्व कैसे लाया जा सकता है वे यह नहीं मानते थे कि देश में कभी अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है. आज ऐसा विकास का सिद्धान्त जिसमें बेरोजगारी को दूर करने का समाधान न हो अर्थ-शास्त्र में कोई स्थान नहीं रखता.
- (4) वे अनावश्यक रूप से 'गतिहीन अर्थ व्यवस्था' Stationary state से भयभीत थे. उनका विश्वास था कि साधनों के पूर्ण रूप से उपयोग हो जाने पर तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण "स्थिर अर्थ-व्यवस्था" की स्थिति पर पहुँच जायेंगे. लाभ के गिरने पर अर्थ-व्यवस्था विकास हीन हो जाएगी और समस्त अर्थ-व्यवस्था का विकास दुखों की स्थिति से परिप्लुत हो जाएगा (*Progress of societies must end in shallows and miseries*

1. Brahmanand Prasad, Adam Smith and Economic growth and its relevance to India" | E Association's number on economic growth XIV

- (5) एडम स्मिथ का यह विचार था कि विकास में सब वर्गों का लाभ होता है मार्श ने गलत सिद्ध किया अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है तो समाज के कुछ हा वर्ग विकास का लाभ चलाते हैं

References

- 1 Adam Smith Wealth of Nations
- 2 " " " (Summary form in ' studies in Economic Development Ed Burnard Okun & R W Richardson, Holt Rinehart & Winston
- 3 Meier and Baldwin Economic development Theory History and policy
- 4 Benjamin Higgins Economic development
- 5 Kindleberger Economic development
- 6 Nasir Khan Problems of growth in an under developed Economy
- 7 Gide & Reist A History of Economic Thought
- 8 Alexander Gray The development of Economic Doctrine
- 9 Eric Roll History of Economic Thought
- 10 D Bright Singh Economic development
- 11 Haney History of Economic Thought
- 12 O H Taylor A
- 13 Spiegel (Ed) The development of Economic Thought
- 14 Frank Neff Economic Doctrine

अध्याय : 6

रिकार्डो का विकास मॉडल (Ricardian Growth Model)

I प्रस्तावना

II मॉडल के तत्व

1. विकास को जन्म पूँजी देती है
2. अधिक पूँजी निर्माण के लिए लाभ अधिक व मजदूरी कम होना चाहिए
3. लाभों को अधिक रखने के लिए वे चाहते थे कि राज्य लाभ पर कर न लगाए व उसके राजकोषीय कार्य कम से कम हो.
4. अधिक लाभ के लिए मुक्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक.

III मॉडल के गुण व दोष .

अध्याय : 6

रिकाडो का विकास मॉडल (Ricardian Growth Model)

I प्रस्तावना

श्री एच टेलर¹, रिकाडो को "अर्थशास्त्र का जनक" मानते थे उनके अनुसार एडम स्मिथ तो "अर्थशास्त्र के दादा" (Grand-father) थे. मिचर और बाल्डविन के अनुसार² "एडम स्मिथ जो कुछ विकास के सिद्धान्त में ठीक से नहीं समझ पाया उसी को रिकाडो ने ठीक से समझाया, (explained the theory of economic development in rigorous fashion)."

सी. पी. किण्डल बर्जर³ रिकाडो को विकास पर लिखने वालों में महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं उनका कथन है, "रिकाडो आय के वितरण व विदेशी व्यापार के सिद्धान्त में अधिक दिलचस्पी रखते थे उन्होंने विकास के सिद्धान्त प्रतिपादित करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया वे अपनी पुस्तक में यही बताते रहे कि अगर और अधिक खेती योग्य भूमि की खोज नहीं की जाती या विदेशों से सस्ते खाद्यान्न के मंगाने का प्रबन्ध नहीं होता तो विकास रुक जाएगा "

रिकाडो का विकास का सिद्धान्त न तो युक्ति सगत रहा और न तो उसकी ठीक से व्याख्या ही की गई उनके विकास मॉडल के मुख्य तत्व नीचे दिए जाते हैं

1. O. H. Taylor History of Economic Thought

2. Meier & Baldwin : Economic Development, Asia publishing House 1962 p 27-43.

3. Kindleberger : Economic Development. p 41-42.

II मॉडल के तत्व

(1) विकास को पूँजी सचय जन्म देती है (Capital is engine of growth)

किसी भी देश का आर्थिक विकास, रिकाडों के अनुसार, पूँजी की मात्रा पर निर्भर करता है अधिक पूँजी सचय अधिक लाभ पर निर्भर है, अधिक लाभ जीवन स्तर पर स्थिर मजदूरी पर निर्भर है, स्थिर मजदूरी खाद्यान्न की प्राप्ति पर निर्भर रहती है, खाद्यान्न की प्राप्ति भूमि की मात्रा या आयात पर निर्भर रहती है। उन्होंने लिखा :

“अगर किसी देश में श्रमिकों की मात्रा अधिक है, तो इसका अर्थ सही माने में यह है कि उन्हें काम पर लगाने के लिए पर्याप्त पूँजी नहीं है”¹

विकास में पूँजीपति का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है रिकाडों के अनुसार पूँजीपति ही संगठन करता है और जोखिम उठाता है वे ही बचत करके पूँजी निर्माण करते हैं वे ही जमींदार से भूमि लेकर उसे तगान देते हैं पूँजीपति ही श्रमिकों को रोजगार देते हैं व राष्ट्रीय आय बढ़ाते हैं

पूँजीपति ही विकास को जन्म देते हैं तथा उसे बनाए रखते हैं वे ही देश का औद्योगीकरण करते हैं पूँजीपति हमेशा अपने लाभ को अधिकतम रखना चाहते हैं इसके लिए नए आविष्कार करते हैं और बाजार का विस्तार करते हैं पूँजीपति अपने मूल्य भिन्न क्षेत्रों में लगे विनियोजन से समान सीमान्त लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वे अपने साधनों का अनुकूलतम वितरण करते हैं (They try to secure optimum allocation of resources)

रिकाडों के विचार में पूँजीपति के अतिरिक्त और कोई भी बचत करके पूँजी निर्माण नहीं करता—(भूमिपति भी नहीं) और इस कारण पूँजीपति के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति या संस्था विकास को न तो जन्म देता है और न आगे बढ़ाता है

1 Ricardo Notes on Malthus principles of Political Economy p 241.

- (2) अधिक पूँजी निर्माण के लिए लाभ अधिक व मजदूरी कम होना चाहिए
 (High capital accumulation is a function of high profits which in turn is a function of low wages always being equal to subsistence level)

रिकाडों का कथन था कि लाभ अधिक होने पर ही पूँजी निर्माण अधिक हो सकता है, और अधिक लाभ केवल कम मजदूरी रखने पर ही प्राप्त हो सकता है. रिकाडों लाभ व मजदूरी को एक दूसरे से प्रतिकूल दिशा में संबंधित मानते थे इसलिए वे चाहते थे कि मजदूरों को वास्तविक मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर आवश्यक स्तर पर स्थिर रहना चाहिए वे मान्यता के जनसंख्या मिथ्यान्त से भयभीत हो गए थे और विश्वास करते थे कि अगर मजदूरी की मात्रा बढ़ाई गई तो मजदूर और बच्चे पैदा कर लेंगे जिससे वास्तविक मजदूरी पुनः गिरकर जीवन निर्वाह स्तर पर आजाएगी

रिकाडों न केवल मजदूरी को जीवन निर्वाह के स्तर पर स्थिर रखना चाहते थे वरन् वे मजदूरों को "सामाजिक सुरक्षा" के लाभ देने के भी विपक्ष में थे (इसीलिए वे इंग्लैंड में Poor Laws को, जिसके अन्तर्गत बेरोजगारों को राहत दी जाती थी, समाप्त कराना चाहते थे) उनका कथन था

‘ एमे लोगो के खाने का प्रबन्ध करके आप मानवों की असीमित माँग को उत्पन्न करते हैं ’¹

रिकाडों को इस बात का कभी भी डर नहीं था कि मजदूरी को जीवन निर्वाह स्तर पर रखने से देश में कभी प्रभावशाली माँग कम होगी

रिकाडों के मॉडल में इन विवे सामान की कोई सर्वव्यापी समस्या नहीं है (There is no problem of a general glut of commodities in the Ricardian model) उनके विचार में राष्ट्रीय आय का जो भी भाग मजदूरी लगान, व्याज या लाभ के रूप में दिया जाता है, वह पूर्ण रूप से व्यय में आ जाता है और जो बचत होती है वे पूर्ण रूप से विनियोजित हो जाती है इस प्रकार वे व विकास के लिए मजदूरी को स्थिर रख जाने व लाभ को अधिकाधिक बढ़ाने की सिफारिश करते थे

1 P. Sraffa (Ed) The Works and Correspondence of David Ricardo. Cambridge University press, 1951 p. 125

(3) लाभों को अधिक रखने के लिए वे चाहते थे कि राज्य लाभ पर कर न लगाए व उसको राजकोषीय कार्य कम से कम हो (For maintaining high profits fiscal activities of the State should be minimum and profits should not be taxed)

(1) रिकाडों ने अपनी पुस्तक में विस्तार से अध्ययन किया कि किन मदों पर कर लगाना चाहिए और किन पर नहीं इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे लाभ पर कोई कर नहीं चाहते थे क्योंकि, उनके विचार से इससे पूँजी निर्माण पर बुरा असर पड़ता है (2) वे कच्चे माल पर भी इसी कारण से कर लगाने के विपक्ष में थे, क्योंकि इसके कारण मूल्य बढ़ेंगे जिसमें मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी, और फिर लाभ कम हो जाएँगे और यह कर भी लाभ पर कर हो जाएगा (3) इसी कारण से वे आवश्यक उपभोग वस्तुओं पर भी कर नहीं चाहते थे (4) वे तो लगान पर भी कर लगाने के विपक्ष में थे क्योंकि इससे अगर खेती में कमी की गई तो खाद्यान्न के भाव बढ़ेंगे और मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी जिसमें लाभ कम होंगे वे तो केवल विलासिताओं की वस्तुओं पर अधिक कर चाहते थे

(4) अधिक लाभ के लिए मुक्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक
(High profits—a function of free commerce and free international trade, based on comparative cost advantage)

रिकाडों विकास के लिए मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चाहते थे जिसमें कई लाभ होते हैं : (1) मुक्त व्यापार से सस्ते दामों पर खाद्यान्न मँगाया जा सकता है जिसमें मजदूरी दर नीची व लाभ ऊँचे रह सकते हैं (2) इसमें देश को प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सकता है व राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय धन-विभाजन के विस्तार से विशिष्टीकरण बढ़ता है (3) इससे राष्ट्रीय व विश्व आय में वृद्धि होती है इस आय से पूँजी निर्माण होती है और फिर और अधिक विनियोजन व आर्थिक विकास होता है रिकाडों के अनुसार मुक्त व्यापार से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, विलक्षण कुशलता पुरस्कृत होती है तथा प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम उपयोग व वितरण होता है, जिसमें आर्थिक विकास होता है

रिकाडों इन्हीं लाभों को ध्यान में रखकर, एडम स्मिथ की भाँति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार के तटकरों को नहीं चाहते थे वे भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए स्वर्णमान चाहते थे तथा स्वतन्त्र मुद्रा विनिमय प्रणाली चाहते थे

III आलोचनात्मक समीक्षा :

मॉडल के गुण

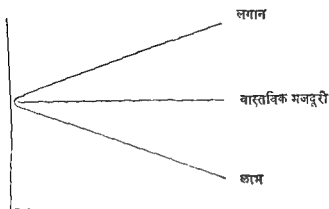
- (1) रिकाडों के मॉडल में पूँजी संचय पर अधिक महत्व दिया है और पूँजी संचय के लिए उन्होंने वचन बढ़ाने को महत्व दिया
- (2) लाभ को यात्रा को अधिक बनाए रखने के लिए भी वे अधिक जोर देते थे वे राज्य द्वारा व्यापारिक मस्यानो के लाभ पर प्रहार के पूर्ण रूप में विरोधी थे
- (3) उन्होंने जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने पर महत्व दिया है वह भी उचित है
- (4) रिकाडों का मॉडल Macro dynamic है अर्थात् यह गतिशील है परस्पर आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है तथा पूरी अर्थव्यवस्था के विकास का अध्ययन करता है

मॉडल के दोष रिकाडों के इन्हीं विचारों ने अर्थशास्त्र को 'निराशा का विज्ञान' की सजा दी। Schumpeter ने इसे a big detour कहा

- (1) रिकाडों ने अपने मॉडल में श्रम व तकनीक का विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसपर समुचित ध्यान नहीं दिया
- (2) वे घोर निराशा-वादी थे उन्हें बटनी हुई जनमस्या व घटती हुई उम्र का भय हमेशा सताता था व प्रकृति में कृपण मानते थे, और उनका विश्वास था कि अन्त में उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण 'मिर या गतिहीन व विकासहीन' अर्थ व्यवस्था, पहुँच जाने से भयभीत थे

(3) गतिहीन व विकासहीन अर्थव्यवस्था

रिकाडों का विश्वास था कि दीर्घकाल में मरणावस्था घटता जाएगा, मजदूरी को मौद्रिक माना बढ़ती जाएगी, क्योंकि माले का मूल्य उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार बढ़ता रहेगा (पर वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है) और लाभ गिरते जाते हैं लाभ के गिरने से पूँजी संचय भी गिर जाता है वगैर लाभ के पूँजी संचय संभव नहीं होगा इस प्रवृत्ति को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं .



रिकाडों ने इस प्रकार से भूमि की कमी व उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण स्थिर अर्थ-व्यवस्था की कल्पना की उन्होंने लिखा

‘जैसे-जैसे समाज में धन वृद्धि होती है और अधिक खाद्यान्न के उत्पादन के लिए अधिकाधिक भ्रादमी लगते हैं इससे लाभ गिर जाते हैं आवश्यकताओं के मूल्य बढ़ते हैं व मजदूरी बढ़ती है और जब कृषक की उपज का मूल्य उसके द्वारा दी जाने वाली मजदूरी के बराबर हो जाता है तो कृषि का आगे विस्तार बन्द हो जाता है और पूँजी संचय रुक जाता है श्रमिकों की माँग कम हो जाती है और इसके आगे जनसंख्या भी नहीं बढ़ पाती ”

Long indeed before this period, the very low rate of profits will have arrested all accumulation, and almost the whole produce of the country, after paying the labourers will be the property of the owners of land and the receivers of tithes and taxes ” (See —Principles of Political Economy Everyman's edition London 1911, p. 71-72

- (4) रिकाडों का कथन था कि ‘उत्पादन के अध्ययन से अधिक वितरण’ की समस्याओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है फिर भी आश्चर्य है कि व मजदूरों को कम मजदूरी देते रहने की ही सिफारिश करते रहते थे

धीरे उन्हें प्रभावशील माँग के गिरने और मन्दी व glut का भय नहीं था।

- (5) गरीब वर्ग की जनसंख्या को उन्होंने income elastic माना था, अर्थात् आय बढ़ने से जनसंख्या बढ़ जाएगी, पर अधिक आय वालों के यहाँ जन्म दर कम रहती है वे तो मान्यता से बढ़कर मान्यता से
- (6) उन्होंने विकास को जन्म देने में राज्य के महत्व को नहीं समझा।
- (7) उनकी गतिहीन अर्थव्यवस्था की कल्पना निर्मूल थी।



References : Adam Smith के अध्याय में उद्धृत references के अनुरिक्त यह और

- (1) Oswald St. Clair : A key to Ricardo
- (2) Nag, D. S. : Economics of under developed countries.
- (3) Mark Blaug : Ricardian Economic.

अध्याय 7

माल्थस का विकास मॉडल

Malthus on Economic growth

I प्रस्तावना

II मॉडल के मुख्य तत्व

- 1 विकास के लिए पूँजी आवश्यक
- 2 यम विभाजन, आंतरिक य
- 3 बाह्य बाजार का विस्तार आवश्यक
- 4 तकनीक उन्नति आवश्यक
- 5 देश में उचित राजनैतिक व सामाजिक स्थिति आवश्यक
- 6 जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक, जनसंख्या व विकास
- 7 विकास के लिए प्रभावशील मांग अधिक होना चाहिए व बचत को भी अधिकतम सोमा होना चाहिए
- 8 कम विकसित देश व विकास

III माल्थस के मॉडल की समीक्षा उनका आशावाद व उदारता

माल्थस का विकास मॉडल

Malthus on Economic growth

I. प्रस्तावना

माल्थस धर्मशास्त्र की आधार शिला रखने वाले परम्परागत धर्मशास्त्रियों के विमर्तियों में से एक थे. वे "जनसंख्या के धर्मशास्त्र" Economics of Demography के जनक थे. धर्मशास्त्र में वे निराशावादी प्रवृत्ति को भरने वाले माने जाते हैं. परन्तु यह दुर्भाग्य है कि हम माल्थस को केवल उनके जनसंख्या के सिद्धान्त से ही जानने हैं विकास सम्बन्धी उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे और अगर हम कहे कि वे केन्स के प्रेरणा स्रोत थे, तो गलत न होगा. उनका विकास मॉडल रिकार्डों की भाँति निराशापूर्ण नहीं था हम जो उनके विकास के सम्बन्ध में विचार पढ़ेंगे तो हमको स्वयं ही भ्रम पैदा हो जाएगा कि क्या यह विचार इतने पुराने धर्मशास्त्री के हो सकते हैं.

विकास मॉडल के मुख्य तत्व

1. विकास के लिए पूँजी आवश्यक . Growth, a function of capital एहम समय व रिकार्डों की भाँति वे भी विकास को जन्म देने और कायम रखने के लिए पूँजी संचय को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे. उन्होंने कहा

"पूँजी निरन्तर वृद्धि के बिना देश के धन में कमी भी निरन्तर व स्थायी वृद्धि नहीं हो सकती."

इस कारण माल्थस पूँजीपति के योगदान को विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं.

There is scarcely any inquiry more curious, or, from its importance more worthy of attention, than that which traces the causes which practically check the progress of wealth in different countries, and stop it, or make it proceed very slowly while the power of production remains comparatively undiminished, or at least would furnish the means of a great and abundant increase of produce and population

Principles of Political Economy, 2nd Ed (London : William Pickering 1836, IV. 309.

2. श्रम विभाजन, आन्तरिक व बाह्य बाजार का विस्तार आवश्यक :

extension of division of labour, and internal and external market necessary for growth.

वे भी श्रम विभाजन के विस्तार को महत्व देने थे। उनका कथन था "Internal and external commerce increases exchangeable value"

3 बाह्य मितव्ययिताएँ आवश्यक : Investment in economic and social overheads important for growth.

"बाह्य मितव्ययिताएँ" यह शब्द हमारे अर्थशास्त्र में मार्शल को देन है, पर बहुत पहले माल्थस ने देश में economic overheads (जैसे सड़क यातायात, सचय साधन बैंक आदि) के विकास पर बल दिया और वे Social overheads का मौजूद होना भी विकास के लिए आवश्यक मानते थे (Social overheads पर व्यय का अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग पर व्यय से है)

4 तकनीकी उन्नति आवश्यक : Technological advance necessary

माल्थस ने 'तकनीक' को विकास का एक अलग से महत्वपूर्ण घटक माना (Independent factor growth) उनका कथन था कि नई मशीन से वस्तुएँ सस्ती पैदा होती हैं, जिससे देश में प्रभावशील माँग बढ़ती है, तथा मालिकों के लाभ बढ़ने हैं और बाजार के विस्तार से श्रमविभाजन का विस्तार होता है अधिक माँग होने से देश में रोजगार वृद्धि होती है वे मशीनों के लगाने से बेरोजगारी फैलेगी, ऐसा नहीं मानते थे उन्होंने लिखा

'There is little reason to apprehend any permanent evil from the increase of machinery,'

5 Favourable state of politics and morals necessary, देश में उचित राजनैतिक व सामाजिक स्थिति आवश्यक *

माल्थस ने विकास के तीन मुख्य तत्व माने थे (1) अच्छी उपजाऊ भूमि, (11) पर्याप्त पूँजी व (111) अधिकाधिक उन्नत तकनीक, साथ ही उन्होंने विकास के लिए निम्नलिखित तत्वों को महत्वपूर्ण माना

(1) देश में अच्छा सविधान, अच्छे नियम तथा अच्छा प्रशासन

(11) निजी संपत्ति को बनाने की सुविधा व सुरक्षा

(iii) जनता में मेहनत की आदत

(iv) जनता का न्यायपूर्ण व सदाचारी होना (Rectitude of character and moral standard)

(v) उत्पादन व वितरण के कार्यों में समन्वय

6. जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक - Population control—a must

माल्थस ने विकास को अवरुद्ध करने में जनसंख्या वृद्धि को सबसे बड़ा दोषी माना। संक्षेप में हम उनका विश्व-विस्थाप 'जनसंख्या का सिद्धान्त' अध्ययन करें

माल्थस ने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकना न गया, तो वह 'ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन' में बढ़ेगी, अर्थात् 1 2 4 8 16 32 64 128 आदि के अनुपात में बढ़ेगी, और हर 25 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी इसके विपरीत खाना 'अर्थमेटिक प्रोग्रेशन' में बढ़ेगा, 1 2 3 4 के अनुपात में बढ़ेगा जनसंख्या की इस प्रकार से, खाने की वृद्धि से तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति है और जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो प्रत्यक्ष अवरोधों के कारण (बीमारियाँ, युद्ध, अकाल आदि) जनसंख्या पुन घट जायेगी माल्थस का विश्वास था कि उत्पत्ति में 'ह्रास नियम' के लागू होना पर जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से देश की जनसंख्या का बड़ा भाग हमेशा जीवन निर्वाह के बराबर स्तर पर रहेगा। माल्थस के इस विचारों को ऐसे शब्दों में आलोचना की गई कि उनके पहले या बाद में किसी अर्थशास्त्री के लिए इतने गंभीर अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया उनको "मानवता की आशाओं पर पानी फेरनेवाले काले राक्षस" तक कह डाला गया माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त की निम्नलिखित मुख्य आलोचनाएँ की गईं .

(1) विश्व के कई देशों में जनसंख्या 25 सालों में दुगुनी हुई है पर अगर हम पूरे विश्व को लें तो जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी नहीं होती अगर ऐसा हुआ होता तो आज विश्व में खड़े होने की जगह न होती शिक्षा के विस्तार से, स्त्रियों की सामाजिक उन्नति से, ऊँच स्तर के जीवन यापन की चाह के कारण, अच्छे खाने के कारण, Increased social capillarity (समाज में ऊपर जाने की चाह), तथा परिवार नियोजन सबधी उपकरणों की उपलब्धि के कारण जन्म दरों में भारी कमी आई है फलस्वरूप तो घटती जनसंख्या की समस्या सामने है

(ii) आधुनिक युग में पुराने युग की "औद्योगिक क्रांति" की भाँति "कृषि क्रांति" होने के लक्ष्य हैं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग, उत्तम

बीज की प्राप्ति, वडी सिंचाई योजनाओं के शुरू होने से तथा अन्य उर्वरकों की उपलब्धि से खाद्यान्न के उत्पादन में कई गुनी वृद्धि की सम्भावनाएँ सामने आई हैं। पिछले कुछ वर्षों पहले तक अमेरिका को अपनी आवश्यकता में अधिक खाद्यान्नो को बेचने की समस्या सामने थी।

(111) जनसंख्या वृद्धि से प्रत्यक्ष अवरोधों के परिणामस्वरूप मृत्युदर में वृद्धि का डर भी आज उतना नहीं है। चिकित्सा विज्ञान में चमत्कारी उन्नति, राज्य के कल्याणकारी कार्यों में विस्तार, व अन्तरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के कारण आज अकाल मौने नहीं होने दी जाती है।

(1V) आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या का स्थिर रहना जरूरी नहीं है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, तथा आस्ट्रेलिया में विश्व के कई अन्य देशों के मुकाबले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, फिर भी यह देश विश्व के प्रतिव्यक्ति आय के अनुसार, सबसे प्रमुख देशों में हैं। अधिक जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि दर से विकास दर गिरी नहीं और न ही अधिक विकास दर से जनसंख्या वृद्धि ही रुकी¹।

केवल जनसंख्या के सिद्धान्त के आधार पर माल्थस को निराशावाद का अवतार माना गया। परन्तु उनके न केवल 'विकास के सिद्धान्त' पर विचार बहुत ही सही थे, वरन् स्वयं जनसंख्या पर उनके विचार सही थे। अपने जनसंख्या सिद्धान्त के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के बाद उन्होंने जनसंख्या सम्बन्धी और जाँच व खोज की और धीरे धीरे उनके विचार वास्तविकता की ओर अधिकाधिक आ गए। विकास व जनसंख्या के संबंध के बारे में उन्होंने लिखा

"That a continued increase of population is a powerful and necessary element of increasing demand, will be readily conceded, but that the increase of population alone or more properly speaking, the pressure of population against limits of subsistence does not furnish an effective stimulus to the continued increase in wealth, is not only evident in theory but is confirmed by universal experience"² अर्थात्, जन-

1. Henry Villard Economic Development

2. Okun & Richard . Condensed version of Malthus principles
p 50.

संख्या वृद्धि से प्रभावशाली माँग बढ़ेगी परन्तु निरन्तर जनसंख्या वृद्धि से खाद्य सामग्रियों की कमी सामान्य आणविक और राष्ट्रीय आय की वृद्धि रुकेगी—यह बात न केवल सैद्धान्तिक रूप से ठीक है, वरन् समस्त विश्व के अनुभव पर भी आधारित है

कम-विकसित देशों (जिनमें उन्होंने एशिया व अफ्रीका को शामिल किया) में उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या को asset (पूँजी या विकास वर्धक) नहीं माना वरन् liability (उत्तरदायित्व) के रूप में देखा और कहा कि इन देशों में दरिद्र व अविश्वसनीय तथा भ्रष्टाचारपूर्ण व्यक्ति सर्वथा अधिक बच बच उत्पन्न करते रहते हैं और विकास में बाधक होते हैं इन देशों में जन्म व मृत्यु दर अधिक रहती है और बहुत से बच्चे युवा होने से पहले मर जाते हैं यह केवल उपभोगकर्ता रहते हैं और उत्पादन में वृद्धि योग्य होने से पहले ही मर जाते हैं

“Thus, there is nothing automatic about economic growth” according to Malthus “A high rate of capital accumulation and a sustained rate of economic growth will depend upon our capacity to control population, among other things”

उन्होंने यह भी लिखा

“A man whose only possession is his labour make can effectual demand if his labour is not wanted It will be found that those states often make the slowest progress in wealth where the stimulus arising from the population”¹ alone is the greatest. (अर्थात् एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति केवल उसकी श्रमशक्ति है, देश की प्रभावशाली माँग में जब तक वृद्धि नहीं कर सकता जब तक कि उसके श्रम की माँग न हो उन देशों में घन में वृद्धि (आय में वृद्धि) सबसे कम होगी जहाँ कि विकास को प्रवृत्त करने वाले तत्वों में जनसंख्या वृद्धि ही प्रमुख हो)

आज के युग में भी माल्थस के जनसंख्या और विकास सम्बन्धी विचार पूर्ण रूप से ठीक हैं अपने “जनसंख्या सिद्धांत के सातवें संस्करण में वे जनसंख्या नियंत्रण

व खाद्य सामग्री को हर 25 वर्षों में दुगुना कर सकने को भी संभव मानने लगे थे

7. विकास के लिए प्रभावशाली मांग अधिक रहना चाहिए

Growth, a function of high effective demand.

(Malthus 'Theory of glut and Malthus on optimum propensity to save.)

जब कि एडम स्मिथ व रिकार्डों, जे वी से के इस विचार से सहमत थे कि "हर पूर्ति अपनी मांग पैदा कर लेती है" और इस लिए कभी भी समस्त क्षेत्रों में या सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में मन्दी नहीं आ सकती, माल्थस इस बात को नहीं मानते थे उनका विश्वास था कि देश में प्रभावशाली मांग की कमी के कारण विकास रुकेगा और अगर प्रभावशाली मांग बनी रहे तो विकास होता रहेगा इसी विचार के लिए आज हम केन्स को अधिक श्रेय देते हैं, जब कि यह श्रेय वास्तव में माल्थस को मिलना चाहिए था उन्होंने लिखा

'Master manufacturers and merchants produce very largely and consume sparingly..... It is, therefore obvious that without an expenditure which will encourage commerce manufactures, and personal services, the possessors of land would have no sufficient stimulus to cultivate well. ...and a country rich and populous, would, with too parsimonious habits, infallibly become poor and comparatively unpeopled" 1

(अर्थात् थोड़ा उत्पादनकर्ता और व्यापारी आय तो बहुत करते हैं पर उपभोग कम करते हैं (सापेक्षिक रूप से) जाहिर है कि अगर अधिक व्यय के अधिक उद्योग, व्यापार व कृषि विस्तृत नहीं हो सकता एक देश, चाहे वह धनी व जनपूर्ण ही क्यों न हो, निश्चय ही अपनी कृपणता या अल्पव्ययी होने के कारण, गरीब व जनरहित हो जाएगा)

बचत की अधिकतम सीमा जबकि एडम स्मिथ व रिकार्डों बचत को हमेशा व हर स्थिति में एक गुण्य मानते थे, माल्थस ने बताया कि अधिक बचतों से बचत

व विनियोजन में असंतुलन हो जाएगा, और बेरोजगारी फैलेगी क्योंकि अतिरिक्त वस्तुओं के कारण उत्पादन रुक जाएगा इनके पूर्व के अर्थशास्त्री वचन और विनियोजन को बराबर मानते थे उनका कथन था कि अगर अधिकाधिक वचन को सचों को कम करके, प्राप्त करने के स्थान पर हम अधिकाधिक उत्पादिकता व आय से प्राप्त करें तो इसमें कोई हानि नहीं होगी उन्होंने लिखा

“The future of a country.. is made by..... savings, certainly, but by savings which are furnished from increased gains, and by no means involve a diminished expenditure on objects of luxury and enjoyment”¹

उन्होंने लिखा कि इस प्रकार की वचनो से लाभ व पूँजी निभाए दोनों कम हो जाएंगे इसलिए देश में वचनो को एक सीमा के बाद नहीं बढ़ने देना चाहिए .

“Where the state of demand for commodities was such as to afford much less than ordinary profits to the producer, and the capitalists were at a loss, where and how to employ their capitals to advantage, the saving from revenue to add still more to these capitals would only tend prematurely to diminish the motive to accumulation, and still further to distress the capitalists, with little increase of a wholesome and effective capital.

बेरोजगारी व मन्दी दूर करने के लिए, माल्थस ने अनुत्पादक उपभोग कर्ताओं को भी सह्यपूर्ण माना।

8. कम-विकसित देशों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा :

“An inferior mode of living is a cause and consequence of poverty” (निम्नजीवन यापन गरीबी का कारण का परिणाम होता है)

यह “धार्मिक दुष्चक्र” बाद में Ragner Nurkse ने जोरदार शब्दों में

समझाया वे उन्होंने कम-विकसित देशों के विकास की समस्याओं को two section model में अध्ययन किया, और वे सतुलित विकास चाहते थे उन्होंने लिखा था कि इन देशों में औद्योगिक क्षेत्र इसलिए विकसित नहीं हो पाता कि कृषि क्षेत्र गरीब होता है

भूमि सुधार इन देशों के लिए उन्होंने भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया पर साथ ही यह भी कहा कि एक सीमा के बाद अगर भूमि वितरण में समानता लाने की कोशिश की गई तो इससे धन वृद्धि के स्थान पर कमी आएगी अधिक समानता से भूमि में पूँजी लगाने वाले नहीं रहेंगे

“With an excessive proportion of small proprietors both of land and capital all great improvements in land, all great enterprizes in commerce and manufactures, as resulting from division of labour, would be at an end and the progress of wealth would be checked by a failure in the powers of supply” (पृ० 373)

माल्थस ने इन देशों के बारे में वह बातें भी कही जो हमारे काल में कोलिन क्लार्क (Colin Clark) ने कही अर्थात् (1) विकास जैसे जैसे बढ़ता है कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान कम हो जाता है (माल्थस प्र० 334) तकनीकी उन्नति से रोजगार बढ़ता है (प्र० 352) विकास की दर गिरने से बरोजगारी बढ़ती है (प्र० 312)

III माल्थस के मॉडल की समीक्षा उनका शाशावाद व उदारता

माल्थस के मॉडल की व्यापकता व महत्व को हम ऊपर के वर्णन को अध्ययन करके समझ ही गए हैं Warren S Thomson के अनुसार

“माल्थस मानव जाति के कल्याण में उतनी ही दिलचस्पी रखते थे जितनी कि कोई और रख सकता है परन्तु उनका उत्साह, वास्तविकता पर आधारित था वे अविवेकी निराशावादी नहीं थे उनको आशा व विश्वास था कि मानव जाति का आर्थिक स्तर ऊँचा होगा ”

माल्थस ने अपनी पुस्तक के सातवें संस्करण में लिखा

“जनसंख्या की समस्या जनसंख्या के बढ़ने से ही नहीं देखना चाहिए

यह तो हमेशा साबान से सम्बन्धित है आने वाले समय में आशा की जा सकती है कि जनसंख्या की वृद्धि की बुराईयाँ घटेंगी और हम आशा कर सकते हैं कि जनजीवन में उन्नति होगी "

"On the whole, therefore, though our future prospects respecting the mitigation of the evils arising from the principles of population may not be so bright as we could wish, yet they are far from being entirely disheartening, and by no means preclude that gradual and progressive improvement in human society which before the late wild speculations on this subject, was the object of national expectation..."

उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि हम एडम स्मिथ के आशावादी मानते हैं जब कि वे स्थिर ग्रंथ व्यवस्था" की कल्पना करते थे, और माल्थस को निराशावादी ग्रंथ-शास्त्री के रूप में याद करें, जबकि वे ऐसे नहीं थे

जबूरी के सम्बन्ध में भी उनके विचार रिकार्डों की भाँति न तो कठोर थे और थम विरोधी उन्होंने मालिका के स्वार्थ व लालच की भर्त्सना की 'Who treated their employees as chattels for their own good' अर्थात् जो अपने मजदूरों को अपने लाभ के लिए माल-व्यसबाब जैसा मानते थे वे थम को उचित हिस्सा दिलाने के पक्ष में थे

James Bonar के शब्दों में

"Of all the applications of the doctrine of Malthus, their approach to pauperism was probably, at the time, of the greatest public interest... Malthus is the father not only of the new poor law, but of all our latter day societies for the organisation of charity "



Other references . (than those mentioned previously)

- (1) James Bonar . Malthus & His works . p. 305
- (2) Coontz : Population theories & Economic Interpretation
- (3) Bowen : Population.
- (4) Spengler & Duncan : Population theory & policy
- (5) Duncan & Hauser . The Study of Population.

अध्याय II

जॉन स्टुअर्ट मिल का विकास मॉडल

John Stuart Mill on Growth

I प्रस्तावना

II विकास मॉडल

(A) जीवन के प्रारम्भिक वर्षों के आधार पर

1. विकास के मुख्य स्रोत भूमि, श्रम व पूंजी हैं.
2. मिल ने भौतिक वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन को ही विकासकारक माना.
3. मिल विकास के लिए पूर्ण प्रतियोगिता व्यवस्था व निर्बाधवादी नीति चाहते थे
4. विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व विनियोजन आवश्यक.
5. जनसंख्या नियंत्रण व 'मजदूरी कोष' बढ़ाना आवश्यक है.
6. राज्य को निजी विनियोजन प्रोत्साहित करने के लिए समस्त सहायता देना चाहिए.

(B) जीवन के उत्तरार्ध काल के विचार

1. वितरण के नियमों में परिवर्तन आवश्यक हो
2. उत्पादन पद्धति में मजदूरी पद्धति की समाप्ति तथा सहकारिता संघों की स्थापना.
3. लगान का समाप्त होना व कृषि विकास के लिए भू-सुधार आवश्यक.
4. कम-विकसित देशों के सम्बन्ध में विचार.

III समालोचना

जान स्टुअर्ट मिल का विकास मॉडल

John Stuart Mill on Growth

I प्रस्तावना

मिल ने अपने जीवन काल में एडम स्मिथ से भी अधिक श्याति पाई उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को परिपक्वता की सीमा तक पहुँचा दिया था उन्होंने एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो व जेम्स मिल के विचारों को सुधारा और अच्छी तरह से प्रस्तुत किया (Mill brought the writings of Adam Smith upto date, confirmed the doctrines of Malthus and wrote a "readable Ricardo, as also presented the ideas of his own father, James Mill.

II विकास मॉडल

(A) जीवन के प्रारंभिक वर्षों के विचारों के आधार पर :

1 विकास के मुख्य स्रोत भूमि, श्रम व पूँजी हैं

अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भाँति मिल भी विकास की भूमि, श्रम व पूँजी के सहयोग का प्रतिफल मानते थे जहाँ श्रम व भूमि उत्पादन के अनिवार्य घटक हैं, वहाँ पूँजी "आधुनिक उत्पादन पद्धति" के लिए अनिवार्य घटक है मिल का कथन था "उद्योग की उन्नति की सीमा पूँजी की मात्रा पर निर्भर है पूँजी ही समस्त आर्थिक क्रियाओं के उत्पन्न करने वाला उत्पादन घटक है जहाँ मनुष्य के श्रम से भूमि की वजरता नष्ट नहीं होती वहाँ पूँजी खाद का कार्य करती है " पूँजी की मात्रा अधिक होने के लिए, मिल वचता को प्रोत्साहित करने की सलाह देते हैं

मिल का विश्वास था कि अगर उत्पत्ति के ह्रास नियम लागू होने से बचना है तो श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि आवश्यक होगी शिक्षा के विकास से ज्ञान, बुद्धि और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है मिल ने श्रम की कार्य कुशलता, नैतिक आचार-विचार, व उत्पादकता को उन्नत करने पर विशेष बल दिया

2 मिल ने भौतिक वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन को ही विकास कारक माना : मिल सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को विकास कारक नहीं मानते थे. उनका विचार था कि केवल भौतिक वस्तुओं के निर्माण में ही विकास होता है उनका विचार था कि जब तक बुद्धि, योग्यता, और बौद्धिक व सांस्कृतिक उपलब्धियाँ भौतिक कल्याण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं होती तब तक हम इन गुणों को विकास-कारक नहीं मान सकते

“A country would hardly be said to be rich, except by a metaphor, however precious a possession it might have in the genius, the virtues or the accomplishments of its inhabitants, unless indeed they were looked upon as marketable articles by which it could attract the material wealth of other countries ”

3, मिल विकास के लिए पूर्ण प्रतियोगिता व्यवस्था व निर्बाधवादी नीति चाहते थे मिल का विचार था कि केवल पूर्ण-प्रतियोगिता की व्यवस्था में अधिकतम विकास की सम्भावनाएँ हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है इस व्यवस्था में ही न्याय और समानता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है. मिलका विचार था

“पूर्ण प्रतियोगिता व्यवस्था में कोई भी निरोध निश्चित ही पाप है, और उसको बढ़ावा देना निश्चित ही कल्याणकारी है”

मिल, अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भाँति पूर्ण स्वतन्त्रता में विश्वास रखते थे उनका Hedonistic principle (वह सिद्धान्त जिसके अनुसार आनन्द ही मनुष्य के सब कार्यों का अन्तिम लक्ष्य माना जाता है) में पूर्ण विश्वास था वे इस सिद्धान्त को “Golden rule of Jesus” अर्थात् “प्रभु ईसा मसीह का स्वर्ण सिद्धान्त” की भाँति पवित्र मानने थे उनका कथन था :

“व्यक्तिवाद ही जो कि मानव विकास में बिभ्रान्ता का चोतक है, समस्त विकास का श्रोत है और इसकी हमें “पूर्ण ईर्ष्या” में रक्षा करना चाहिए ”

मिल “व्यक्तिगत हित की भावना” को Achilles lance मानते थे (Achilles lance या माला वह माला था जिससे उत्पन्न घाव स्वयं ठीक हो जाते थे)

उनका विश्वास था कि व्यक्ति अपने हित करने के लिए समाज का अहित नहीं करेगा शिवा और सामाजिक भावना के विकास से हर व्यक्ति निजी स्वार्थ से ऊपर काम करेगा

4 विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व विनियोजन आवश्यक है :

वेस्टिगट व रिक्कार्डों की भाँति मिल का भी विश्वास था कि पूर्ण स्वतन्त्रता व तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कम-विकसित देशों को निश्चित लाभ होना है परन्तु वे नाए व प्रारम्भिक अवस्था के उद्योगों को आवश्यकानुसार संरक्षण देने के पक्ष में थे मिल का कथन था कि अगर कोई देश-विदेशों से मस्ती दर पर खाद्यान्न व कच्चे माल को मँगा सकता है तो इसमें देश में मजदूरी व लागत दोनों कम रहेंगे परन्तु वे यह नहीं चाहते थे कि साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों का शोषण करें उन्होंने लिखा

“अधीनस्थ देशों में आयोजन केवल अपने (साम्राज्यवादी देश) स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, वरन् इस प्रकार से करना चाहिए कि इस देश के लोगों का भी स्थायी कल्याण हो”

मिल ने किसी भी देश में गिरती हुई लाभ की दर को रोकने के लिए मलाह दी कि ऐसे देश को अपनी पूँजी विदेशों में लगाना चाहिए अगर स्वदेश में पूँजी की उत्पादकता कम हो (लाभ गिर रहा हो) तो विदेशों में पूँजी से भेजने से पूँजी की भीमान्त उत्पादकता बढ़ जायगी जब दश में अधिक लाभ की सम्भावनाएँ घट जाएँ तो ‘स्थिर अर्थ-व्यवस्था’ की स्थिति विदेशी व्यापार से लाभ कमाकर ही टाली जा सकती है

5. जनसंख्या नियन्त्रण व “मजदूरी के पक्ष” स्थान। आवश्यक :

मिल भी एटम स्मिथ की भाँति “स्थिर अर्थव्यवस्था” की सम्भावित स्थिति से भयभीत थे, और इस अवस्था को से जाने वाली चीज वे अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि को ही मानते थे

मिल पुत्रों से नाराज थे क्योंकि वे ही स्त्रियों पर, वगैर स्त्रियों की सहमति लिए, मानृत्व लाद देने हैं

मिल का विश्वास था कि विकास के लिए सीमित परिवार का होना अत्यन्त आवश्यक होता है मिल जैसे तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बड़े समर्थक थे, पर इस सन्दर्भ में वे इतना तक कह गए कि बहुत गरीबों व दीन-दरिद्रों (Poor and Indigents) को तो विवाह करने तक की अनुमति नहीं होना चाहिए मिल

अधिक बच्चे पैदा करने को "अधिक शराब पीने के व्यसन" से भी बुरा मानते थे इस कारण वे अधिक समय तक कुंवारे रहने व गरोबो का वन्ध्याकरण Sterilization and onanism of the proletariat) तक चाहते थे इसीलिए मिल का कथन था कि मजदूरों को चाहिए कि वे उत्पादनकर्ताओं से लाभ दबाएँ और जनसंख्या कम रखें ताकि वे देश में उत्पादन पद्धति को बनाए रख सकें, देश का विकास कर सकें और स्वयं मजदूरों को मजदूरी अधिक दे सकें

6 राज्य को निजी बिगियोन्कों को समस्त सहायताएँ देना चाहिए :

मिल का विश्वास था कि किसी देश का विकास बहुत हद तक देश की सरकार पर निर्भर करता है पर मिल राज्य को प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन व्यवस्था को हाथ में लेने में विवश थे वे चाहते थे कि राज्य (1) करो को कम रखे, (11) सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करे, (111) उचित भू-राजस्व प्रणाली स्थापित करे

वे चाहते थे कि देश में जितनी भी दकियानूसी मान्यताएँ व परम्पराएँ, जो विकास में अवरोधक हो, उन्हें राज्य दूर करने में मदद दे राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह देश में शिक्षा, कौशल व कला के विकास में सहायता करे राज्य को पूँजी निर्माण में भी किसी किस्म की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए यह बाधा अत्यधिक व अनावश्यक करो की वृद्धि से उत्पन्न होनी है

मिल धर्म संधों को भी विकास की राह में एक बाधा मानते थे वे चाहते थे कि इन संधों के स्थान पर मालिकों व श्रमिकों के सहकारी संधों की स्थापना होनी चाहिए

II मिल के जीवन के उत्तरार्ध काल में उनके विकास सम्बन्धी विचार

1. वितरण के नियमों में परिवर्तन :

जैसा कि सर्वविदित है कि मिल के जीवन के उत्तरार्ध में उनके विचार समाजवाद की तरफ झुक गए इस काल में उनका पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के नियमों में विश्वास कायम रहा परन्तु मानव निर्मित वितरण के नियमों से उनका विश्वास उठ गया और वे कहने लगे यह वितरण के नियम विकास में बाधक हैं उन्होंने लिखा

"उत्पत्ति के नियम व शर्तों का स्वभाव भौतिक सत्त्वों की भाँति अटल है उनमें किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारिता या वैकल्प नहीं है परन्तु यह बात वितरण के नियमों पर लागू नहीं होती यह तो केवल मानव सत्त्वों के हाथ की दात है"

मिल चाहते थे कि राज्य ऐसे नियम बनाए जिससे आर्थिक विकास के माध्य सामाजिक न्याय भी उत्पन्न हो। उन्होंने अपनी सामाजिक नीति की रूपरेखा इन शब्दों में व्यक्त की

‘सामाजिक विकास नीति का लक्ष्य है कि किस प्रकार में अधिकतम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और प्राकृतिक माधनों की सार्वजनिक मालिकियत को समन्वित रूप में वार्यान्वित किया जा सके और किस प्रकार से संगठित मेहनत के लाभ सब लोगों को प्राप्त हों’

2 मजदूरी पद्धति की समाप्ति तथा सहकारिता सघों की स्थापना :

मिल अब सोचने लगे कि ‘मजदूरी प्रणाली’ ही विकास में बाधक होती है मजदूर अपने श्रम द्वारा निर्मित वस्तुओं की उत्तमता पर प्रसन्न तब नहीं हो सकते जब प्रणाली में श्रमिक का व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है। मिल इसलिए चाहते थे कि श्रमिकों को, ममानता के आधार पर, महत्तम मज या सस्थान बनायें वे ही पूँजी के सामूहिक रूप से मालिक रहें तथा वे ही मैनेजरो को नियुक्त करें व निष्काल बाहर कर सकें

3 लगान समाप्त हो :

एडम स्मिथ व निर्वाधवादी अर्थशास्त्री लगान को प्रकृति के साधन के सहयोग प्राप्त करने का पारितोषिक मानते थे। भारुषस व रिक्कार्डों लगान को जनमख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न भूमि की कमी का व उत्पत्ति के ह्रास नियम के लागू होने का प्रतिफल मानते थे। सीनीयर इसे आकस्मिक लाभ के रूप में देखते थे परन्तु मिल, अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में, लगान को ‘गैर कमाई हुई आय’ कहने लगे और उनका कथन था इस आय पर कर लगाकर इस आय का ‘समाजीकरण’ कर लेना चाहिए

मिल कहते थे कि विकास के लिए (जिसमें सामाजिक न्याय भी स्थापित हो) निम्नलिखित सुधार कार्य आवश्यक हैं

- (1) किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में देने का अधिकार सीमित होना चाहिए
- (ii) देश में शिक्षा का अधिकारविक विकास किया जाना चाहिए और गरीबों व स्त्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना सुलभ बनाना चाहिए
- (iii) देश में जितनी भी भूमि पर कृषि न हो रही हो, राज्य को उसे तत्काल हाथ में लेकर छोटे किसानों में बाँट देना चाहिए और उन्हें सहकारिता के आधार पर कृषि करने को प्रोत्साहित करना चाहिए

(1V) ऐसे नियम बनाए जाएँ जिससे वे व्यक्ति जिनके पास कम साधन हो वे अगर बच्चे पैदा करें तो उसे अपराध माना जाय

4 कम-विकसित देशों के सम्बन्ध में विचार :

कम-विकसित देशों के विकास के सम्बन्ध में मिल ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जो इस प्रकार हैं

“ऐसे देशों में जहाँ पूँजी सचय कम हो, (जैसे एशिया के देशों में), जहाँ के लोग न तो बचत करते हो और न ही बचत के लिए मेहनत करते हो, जहाँ उत्पादन बहुत थोड़ी मात्रा में होता हो, जहाँ पूँजी की कमी के कारण शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ता हो, और जहाँ के व्यक्तियों में इतनी दूर दृष्टि न हो कि वे प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग कर सकें, उन देशों में सर्वप्रथम मेहनत व पूँजी-निर्माण बढ़ाना होगा और तदुपरान्त औद्योगीकरण आवश्यक होगा ”

“इसके लिए—अच्छी सरकार, सम्पत्ति की सुरक्षा, स्थायी व लाभ-दायक भूमि-सुधार, जन-शिक्षा व ज्ञान में वृद्धि, पुराने रीति-रिवाजों व ग्रन्थ विश्वासों को समाप्त करना,—विदेशी पूँजी का आयात करना आवश्यक होगा विदेशी पूँजी के आयात करने से देशवासियों द्वारा बहुत अधिक मितभ्ययिता के बगैर ही अधिक उत्पादन वृद्धि सम्भव हो सकेगी विदेशी सहायता, देशवासियों के समस्त उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत करती है, नये विचारों को जन्म देती है, पुरानी आदतों को तोड़ती है, नयी आवश्यकताओं को जन्म देती है, नयी लालनाओं को उत्पन्न करती है और देशवासियों को अपने भविष्य सुधारने के लिए अधिक चिन्तनकर्ता बनाती है ”

III. विकास सम्बन्धी विचारों की समालोचना

- (1) मिल का विकास मॉडल एडम स्मिथ व रिकार्डों के मॉडल से निश्चित ही अधिक उन्नत था जब कि प्रथम दो अर्थशास्त्रियों का मॉडल केवल “आर्थिक” था, मिल का मॉडल “सामाजिक-आर्थिक” मॉडल था

देखिए .

Principle of Political Economy, London 1842, 3rd Edition
p. 230-31.

- (11) मिन के विचार, अपनी पुस्तक के हर नवीन संस्करण के साथ, समाज-वादी होने गए. जहाँ वे पहले राज्य के हस्तक्षेप को विकास में अवरोध मानते थे वहाँ बाद में वे राज्य को विकास सबधी कई जिम्मेदारियाँ सौंपने लगे थे वे चाहते थे कि राज्य अधिकतम लोगों का अधिक कर्याण करे. उन्होंने बाद में राज्य को (1) मजदूरी दरों का नियमन करने, (2) सार्वजनिक कार्यों को करने, (3) शिक्षा व तकनीकी आविष्कारों को बढ़ावा देने, (4) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने व (5) गरीबों की सहायता करने के कार्य सौंपे, परन्तु उन्होंने Derived Development के सिद्धान्त को प्रतिपादित नहीं किया, अर्थात् राज्य को विकास की जिम्मेदारी नहीं सौंपी.
- (111) इतना होते हुए भी वे पूर्ण निराशावाद-रहित नहीं थे वे भी जनसंख्या वृद्धि के भय व उत्पत्ति 'हास नियम' के भय के कारण 'स्थैतिक अर्थ-व्यवस्था' के आने की पूर्ण सम्भावनाएँ देखते थे. उन्होंने तो इंग्लैण्ड के लिए 19 वीं सदी के अन्त तक ही इस अवस्था के आ जाने की भविष्यवाणी कर दी थी. उन्होंने तकनीक व साहसिक कार्यों को महत्व नहीं दिया था.

अध्याय : 9

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास मॉडल

The Classical Model of Growth

I प्रस्तावना

II मॉडल

1. भौतिक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि (जो भूमि, पूँजी व संगठन के सहयोग से होती है) से विकास होता है
2. पूँजी विकास का एजेंट होती है : बचतों का महत्व.
- 3 अधिक पूँजी निर्माण : अधिक लाभ पर निर्भर
4. अधिक लाभ के लिए मजदूरी कम होना चाहिए' जनसंख्या नियन्त्रित होना चाहिए.
5. विकास 'निर्माधवादी नीतियों' के अपनाने से ही संभव है
6. विकास "उत्तरोत्तर बढ़ने वाली प्रक्रिया है" इस प्रक्रिया में बेरोजगारी केवल अल्पकालिक विषदा मात्र है. Growth process is linear and homogeneous activity and there can be no under-employment equilibrium
7. लचीली मजदूरी दरों से बेरोजगारी दूर हो सकती है : स्थैतिक अवस्था का आना निश्चित है.

III समालोचना.

अध्याय : 9

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास मॉडल (संक्षेप में)

The Classical Model of Growth
(In nutshell).

I प्रस्तावना

यूरोप में १५ वीं सदी के उत्तरार्ध में तथा 19 वीं सदी के पूर्वाध में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। यूरोप जिस काल में 'Take off' (आत्म स्फूर्ति) की स्थिति से Sustained growth (निरन्तर विकास) की अवस्था में गया, उस काल के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्क्स प्रत्यक्ष द्रष्टा थे। इनके आर्थिक विकास सम्बन्धी विचार इन्हीं विकास की समस्याओं व तथ्यों से प्रभावित हुए थे। साथ ही साथ तत्कालिक प्रशासक व राजनीतिज्ञ भी इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों से बहुत प्रभावित हुए तथा उनके बताये हुए रास्ते पर चले, और इससे इन देशों में आर्थिक विकास हुआ।

हम इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों को संक्षेप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं।

II मॉडल के मुख्य तत्त्व

1. भौतिक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि, जो भूमि, पूँजी व सगठन के सहयोग से होती है, से विकास होता है :

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि को ही विकास का सूचक मानते थे। जब यह उत्पादन बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन भूमि, यम, पूँजी व सगठन के सहयोग के परिणामस्वरूप होता है। यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री 'सगठनवर्ता' और 'साहसी' में भेद नहीं निकालते थे और सगठनवर्ता को ही साहसी मानते थे। उन्होंने साहसी को उतना

महत्व नहीं दिया जितना कि आगे चलकर शम्पोटर ने दिया. “उन्नत तकनीक” को भी उन्होंने एक अलग से महत्वपूर्ण घटक नहीं माना

2. पूँजी “विकास का इंजन” : बचत का महत्व

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूँजी को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण त्रग मानते थे उनके अनुसार अगर देश में पूँजी निर्माण अधिक है तो विकास भी अधिक होगा

अधिक पूँजी निर्माण के लिए अधिक बचत होना आवश्यक होता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बचतों को व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार का गुण मानते थे इन अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि अगर भित्तब्यधिता से संचय करके अधिक बचत होगी (पर मात्स्यस ऐसा नहीं सोचते थे) तो अधिक पूँजी निर्माण व अधिक विकास होगा पूँजी निर्माण से ही उन्नत तकनीक अपनाई जा सकती है

3. अधिक पूँजी निर्माण : अधिक लाभ पर निर्भर :

प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों का कथन था कि अधिक पूँजी निर्माण तब ही संभव है जब कि पूँजीपति वर्ग को अधिक लाभ प्राप्त हो लाभ तथा लाभ की भाशा से ही विनियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है इसलिए इन अर्थशास्त्रियों का कथन था कि राज्य को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश के पूँजीपतियों के लाभ कम हो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसीलिए कम से कम कर लगाने की सिफारिश करते थे, और इसी कारण वे चाहते थे कि देश में श्रम-सघो को मजदूरी बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए

4. अधिक लाभ के लिए मजदूरी कम : मजदूरी में जनसंख्या वृद्धि भी कम होना चाहिये :

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री चाहते थे कि मजदूरी की दरों में वृद्धि नहीं होना चाहिए उनका मजदूरी के “जीवन निर्वाह मिथ्या” में पूर्ण विश्वास था उनका कथन था कि वास्तविक मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह के बराबर रह सकती है, उसमें अधिक नहीं हो सकती अगर वास्तविक मजदूरी को बढ़ा दिया गया (अर्थात् मजदूरी केवल उस समय बढ़ाना चाहिए जब खाद्यान्न का भाव बढ़े और जिस अनुपात में यह भाव बढ़े उसी अनुपात में “मौद्रिक मजदूरी” बढ़ाना चाहिए) तो इसमें वस्तुओं की लागत बढ़ेगी, फिर वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, फिर उनका आन्तरिक उपभोग कम होगा व निर्यात कम होंगे तथा इसके कारण उत्पादन कम करना पड़ेगा और फिर बेरोजगारी फैलेगी इसके परिचायक वास्तविक मजदूरी स्वयं कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी के दिनों में मजदूरी के स्तर अधिक नहीं

रह सकने हमारी ओर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था, कि मजदूरों बढ़ने से मजदूर वर्ग अधिक वच्चे पैदा करेंगे जिससे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी और उनकी इस पूर्ति वृद्धि से वास्तविक मजदूरों पुन गिर जाएंगी

इन्हीं सब कारणां से यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थम-सघो को विकास में बाधा डालने वाली संस्थाएँ मानने थे

5. विकास "निर्बाधवादी नीतियों" के अपनाने से ही संभव होगा.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि राज्य को आर्थिक मामलों में कम से कम दखल देना चाहिए उनके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह निजी क्षेत्र को विकास के हर संभव मदद दे उनके अनुसार राज्य को यह कार्य करना चाहिए

(1) देश में सम्पत्ति को बनाने की स्वतन्त्रता हो तथा उसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रबन्ध हो.

(111) कर कम से कम हो तथा राज्य को सार्वजनिक ऋण न्यूनतम मात्रा में लेना चाहिए यद्यपि इनमें कर भार भविष्य में बढ़ता है राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र में केवल शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व कुछ आवश्यक सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करना चाहिए

(111) देश में थम-सघो को मजदूरों बढ़ाने की स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करना चाहिए

(1४) देश में स्थायी सरकार की स्थापना होना चाहिए जिसकी प्रशासन पद्धति कुशल व भ्रष्टाचार रहित हो देश की वित्तीय संस्थाएँ विकसित हो व पूर्ण संगठित हो देश में उचित धन्य की प्रणाली होनी चाहिए व व्यापकपूर्ण भूमि-मालिकीय पद्धति हो.

(४) देश में जो भी धार्मिक या सामाजिक रीतिरिवाज विकास में बाधक हों, राज्य को चाहिए कि उनमें धीरे-धीरे समुचित सुधार हो

(vi) देश में पूर्णपत्तियों की उत्पादन की मात्रा, व विस्म निर्धारित करने, उसके लिए अपनी इच्छानुसार उत्पादन के अगो की मात्रा व मूल्य निर्धारित करने तथा मूल्य देने की स्वतन्त्रता होना चाहिए.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मतों को अगले अध्याय में देखिए

6. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास “उत्तरोत्तर बढ़ने” वाली प्रक्रिया है : इस प्रक्रिया में ‘बेरोजगारी केवल अल्पकालिक विपदा मान है

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मत में विकास प्रक्रिया Linear and homogeneous (सीधी और एक सी) होती है, अर्थात् अगर हम उत्पादन के अगो को मात्रा दुगुनी कर दे तो उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस मत को तो कई नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी मानते थे. मार्शल ने भी आर्थिक विकास को उसी रूप में होने की कल्पना की जिस रूप में एक वृक्ष धीरे-धीरे, परन्तु निरन्तर, बढ़ता रहता है

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस विचार को मार्क्स व शम्पीटर ने नहीं माना था. उनके अनुसार विकास Fits and starts अर्थात् कभी अधिक दर से व कभी कम दर से तथा कभी कभी तो पीछे हो जाने की प्रक्रिया के साथ साथ होता रहता है

There can be no under-employment equilibrium स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में बेरोजगारी सम्भव नहीं है

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट मत था कि अर्थ-व्यवस्था, अगर उसमें कोई ‘वाह्य’ हस्तक्षेप न हो तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेगी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी की समस्या को अध्ययन योग्य ही नहीं समझा प्रतिष्ठित व नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के दोषों को छिपाने के लिए इस समस्या के अध्ययन की अवहेलना करते रहे इन अर्थशास्त्रियों का मत था कि देश में बेरोजगारी केवल इसलिए उत्पन्न होती है कि श्रम-सम मजदूरी बढ़ा लेते हैं या इसलिए उत्पन्न होती है कि राज्य अधिक कर लगा कर उत्पादनकर्ताओं को पर्याप्त लाभ नहीं लेने देता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने रोजगार की समस्या को Micro या सूक्ष्म अर्थशास्त्र (From the point of view of individual firm) पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थितियों में अध्ययन किया

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ‘पूर्ण रोजगार’ को प्राप्त करने से अधिक “पूर्ण उत्पादन” की स्थिति को प्राप्त करने को अधिक महत्व देते थे.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार “Downward in Flexibility

of demand" अर्थात् माँग की कमी की स्थिति के न उत्पन्न होने के विरवास पर आधारित था। उनका विश्वास था कि माँग व उत्पादन एक ही राह पर आगे बढ़ते हैं जे० बी० से (J B Say) के इस कथन में कि "पूर्ण अमनी माँग स्वयं उत्पन्न कर लेती है" उनका पूर्ण विरवास था।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि अगर मजदूरी की दरों को तबोता रखा गया तो कभी भी बेरोजगारी न होगी, न उत्पादन में व विकास में रकावट आएगी।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री विकास पथ में सबसे बड़ी रकावट अधिक मजदूरी मानते थे "अधिक" का अर्थ उनके अनुसार जीवन निर्वाह से अधिक मजदूरी से था। उनका कथन था कि मजदूरी घटा दी जाए तो उत्पादन, रोजगार व विकास के ऊँचे स्तर बने रहेंगे। सब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियाँ म पीगू सर्वप्रथम प्रभावशील अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मजदूरी गिराने की सिफारिश की थी। उन्होंने मजदूरी दर कम रखने या घटाने के निम्नलिखित लाभ देखे।

- (1) इससे लागत घटेगी, व माँग बढ़ेगी, जिससे उत्पादन व रोजगार में वृद्धि होगी।
- (2) इससे लाभ व लाभ की आशा बढ़ेगी जिससे विनियोजन बढ़ेगा।
- (3) जब मजदूरी की दरें कम होंगी तो उत्पादनकर्ताओं की कम बल पूँजी की आवश्यकता होगी, इससे व्याज की दर कम रहेगी और लागत भी कम रहेगी।
- (4) कम मजदूरी की दर से निर्यात बढ़ेगा और देश में विदेशों से जो धन आएगा उससे विकास बढ़ेगा।
- (5) कम मजदूरी से उत्पादनकर्ता श्रमग्रहण तकनीक अपनाकर रोजगार बढ़ा सकेगें।

संक्षेप में, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि कम मजदूरी रखने व उत्पादनकर्ताओं को अधिक लाभ लेने देने से ही विकास सम्भव होगा।

7. विकास प्रक्रिया का अन्त - स्थिति आर्थिक स्थिति का उत्पन्न होना

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि जब तक किसी देश में, *जलसङ्कल्प*, मुलनात्मक रूप में कम है, तब तक भूमि से अनुपात से अधिक दर में उत्पादन प्राप्त हो सकेगा, परन्तु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती वैसे वैसे उत्पत्ति हानि नियम

प्रभावशील होता जाएगा जब अर्थ-व्यवस्था "परिपक्वता" की अवस्था में पहुँच जाएगी तब उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण थम लागत बढ़ जाएगी। इन अर्थ-शास्त्रियों को भय था कि थम लागते इतनी बढ़ जाएगी कि तकनीकी उन्नति के लाभ भी उनसे कम हो जाएँगे इसके कारण लाभ कम हो जाएँगे तब विनियोजन कम हो जाएगा, तकनीकी विकास रुक जाएगा, भ्रष्टाचारी कोष कम हो जाएँगे और स्वयं जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास मॉडल में "पूँजीवादी विकास व्यवस्था" का अन्त स्थगित स्थिति में पहुँचना होगा इस अवस्था में राष्ट्रीय आय, रोजगार, लाभ, पूँजी, व जनसंख्या सब स्थिर हो जाएँगे परन्तु यह "स्थगित अवस्था" समृद्धि की अवस्था रहेगी, जिसमें पूर्ण रोजगार सम्भव होगा

III समालोचना

(A) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण थे वे विकास की दीर्घकालीन समस्याओं में अधिक रुचि रखते थे उनकी अध्ययन शैली प्रवैगिक थी, उन्होंने विकास के घटको में चक्रीय सम्बन्ध अच्छी तरह समझा उन्होंने बतलाया कि उन्नत तकनीक अधिक विनियोजन पर आधारित होती है, अधिक विनियोजन अधिक लाभ पर निर्भर होता है, व अधिक लाभ उन्नत तकनीक पर आधारित होते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूँजी-निर्माण, बचत विनियोजन, लाभ, व राष्ट्रीय आय में परस्पर सह सम्बन्ध देखा।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सम्बन्धी विचारों में सबसे महत्वपूर्ण विचार पूँजी निर्माण पर जोर देना रहा उन्होंने पूँजी को विकास का एजेंट बनाया कुछ हद तक हम उनकी अग्रहस्तक्षेप की नीति को भी उचित ठहरा सकते हैं। आजकल कई कम-विकसित देशों में राज्य की मौद्रिक व राजकोपीय नीतियों से निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ताओं को ईमानदारी से आय कमाना सम्भव नहीं हो पाता

(B) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सम्बन्धी विचारों में बहुत सी त्रुटियाँ थी, जिनमें मुख्य यह है

- (1) उन्हें उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने का बेवुनियाद भय था। उन्होंने उन्नत तकनीक को अधिक ध्यान में नहीं रखा।
- (2) उनका जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि का डर भी निर्मूल था
- (3) उन्होंने व्यापार चक्रों और बेरोजगारी की समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया। आज के युग में कोई भी विकास नीतियाँ, जिनमें व्यापार

चक्रों से बचने की योजना न हो तथा जिनमें बेरोजगारी व अल्प बेरोजगारी की समस्या के समाधान की सम्भावना न हो, सफल नहीं हो सक्ती

- (4) मजदूरी कम रखकर पूंजी निर्माण करने तथा रोजगार व उत्पादन बढ़ाने की योजना आर्थिक, सामाजिक व नैतिक सभी दृष्टिकोणों से आज व्यवहारिक नहीं है। आज के युग में लचीली मजदूरी नीति से न तो रोजगार बढ़ सकता है और न उत्पादन. मजदूरी कम रखने से उत्पादकता कम रहती है प्रमावशील माँग गिरती है और देश में प्राथमिक दुश्चक्र अभेद्य बना रहता है ¹

1. देखिए : मजदूरी नीति सम्बन्धी अध्याय तथा केन्स का मॉडल.

माक्स का विकास मॉडल

(Marxian Model of Growth)

1 प्रस्तावना

2 मॉडल

- 1 विकास उत्पादन वृद्धि से होता है और उत्पादन भूमि, श्रम, पूँजी, संगठनकर्ता व तकनीक के सहयोग का प्रतिफल होता है
- 2 पूँजीवादी व्यवस्था में तकनीक आर्थिक विकास का एन्जिन है
- 3 उन्नत तकनीक अधिक विनियोजन से समभव है, और अधिक विनियोजन अधिक लाभ पर निर्भर है
- 4 अधिक लाभ कमाने के लिए पूँजीपति “अतिरिक्त मूल्य” प्राप्त करता है—कम मजदूरी देता है और बरोजगारी फैलाता है

5 जनसंख्या व विकास

- 6 कम मजदूरी से उपभोग गिरना है और इससे जय लाभ व विनियोजन गिरता है तो बड़ पूँजीपति छोटे पूँजीपति का शोषण करते हैं, और अंत में पूँजीवाद समाप्त हो जाता है (The Law of concentration of capital The Accumulation of capital The Law of crises The Theory of Economic Development Theory of Automatic Expropriation)

II Marxian Theory of Socio economic revolution

माक्स का सामाजिक आर्थिक क्रान्ति का सिद्धान्त

- 1 देश के आर्थिक सम्बन्ध ही सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक नैतिक व राजनैतिक सम्बन्ध निर्धारित करते हैं
- 2 विश्व में हर चीज परिवर्तनशील है
- 3 समस्त महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रान्ति से हो गते हैं

III Marxian Stages of Economic Growth

माक्स और उनकी विचारों की अवस्थाएँ

- 1 प्राथमिक और अल्पसंख्यक साम्यवाद
- 2 दास प्रथा
- 3 सामंतवादी सत्ता
- 4 पूँजीवाद
- 5 साम्राज्यवाद
- 6 समाजवाद
- 7 साम्यवाद

IV Critical Appraisal of Marxian Model

माक्स मॉडल की समालोचनाएँ

समालोचनाएँ तथा मोयर व बाल्डविन, ब्राजमिन हिगिंस एवं अन्य महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के विचार

मार्क्स का विकास मॉडल

Marxian Model of Growth.

1. प्रस्तावना :

मार्क्स 19 वीं सदी के सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री थे वे जेना यूनिवर्सिटी से डाक्टर की उपाधि प्राप्त करके समाचार पत्रों का सम्पादन, शिक्षण कार्य करते रहे। पर मुख्यतः बाद में वे लेखन का कार्य करते रहे उनका जीवन काल बहुत गरीबी में बीता

मार्क्स "वैज्ञानिक" समाजवाद के जनक थे उन्होंने जो कुछ लिखा उसने न केवल विकास अर्थशास्त्र में नया मॉडल दिया बल्कि विश्व में नई विकास व्यवस्था को ही जन्म दिया. "आज समाजवादी देशों में मार्क्स की आलोचना करना न केवल गलत है बल्कि पाप है"

2. मार्क्स का विकास मॉडल :

1. विकास उत्पादन की वृद्धि से होता है, जो कि भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन ॥ तकनीक के क्रियास्वरूप होता है. Production, function of land, labour, capital, organisation and enterprise.

परम्परागत (प्रतिष्ठित) अर्थशास्त्रियों की भाँति, मार्क्स भी उत्पादन की भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन व साहसी के कार्य का परीक्षण मानते थे. ग्रे (Alexander Gray) इसीलिए कहते हैं कि मार्क्स अन्तिम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे. मार्क्स इन उत्पादन के अंगों में श्रम को ही सर्वोपरि मानते थे. भूमि श्रम के बगैर निष्क्रिय होती है. पूँजी तो "सञ्चित श्रम" ही होती है. मार्क्स पूँजी व पूँजीवाद को विकास में महत्व मानते थे, क्योंकि इससे ही उन्नत तकनीक का अपनाया जाना सम्भव होता है. साहसी को भी महत्वपूर्ण योगदान मानते थे. साहसी ही अपने लाभ के लिए तकनीकी उन्नति लाता है तथा उत्पादन संचालन की व्यवस्था करता है.

2 पूँजीवादी व्यवस्था में तकनीक आर्थिक विकास का 'एन्जिन' है. Technical progress 'motor' of capitalistic growth.

मार्क्स ने तकनीकी उन्नति को विकास का 'एन्जिन' माना. उन्होंने तकनीकी उन्नति व विनियोजन में परस्पर पूरक सम्बन्ध देखा उनके अनुसार उन्नत तकनीक से अधिक पूँजी निर्माण होता है तथा फिर विनियोजन भी अधिक होता है. जहाँ विनियोजन अधिक होता है वहाँ ही उन्नत तकनीक अपनाई जा सकती है.

3. उन्नत तकनीक अधिक विनियोजन से सम्भव है : अधिक विनियोजन अधिक लाभ पर निर्भर है : Technical progress depends on investment Investment on the rate of profit

मार्क्स के अनुसार अधिकाधिक विनियोजन तब ही सम्भव होता है जबकि उत्पादनकर्ता अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं. अधिक लाभ में ही तो अधिक पूँजी निर्माण हो सकता है और तब ही अधिक विनियोजन करता व उन्नत तकनीक अपनाना सम्भव होता है. मार्क्स के अनुसार अधिक लाभ सर्वप्रथम श्रम के शोषण से प्राप्त होते हैं इसके लिए उत्पादनकर्ता (1) मशीनें लगाकर श्रमिकों में बेरोजगारी फैलाता है, (11) श्रमिकों की बेरोजगारी का लाभ उठा कर, उन्हें केवल जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी देता है, तथा बाद में वह (1) छोटे पूँजीपतियों का शोषण करता है और तदुपरांत वह (11) साम्राज्यवाद फैलाने में मदद देता है.

4. अधिक लाभ कमाने के लिए पूँजीपति "अतिरिक्त मूल्य" प्राप्त करता है. The rate of profits depends on the exploitation of workers by paying low wages.

मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद में द्रव्य का रूप पूँजी में परिणत हो जाता है, और द्रव्य एक शोषण का साधन बन जाता है. पूँजीवाद में पढ़ने के युग में विनिमय पद्धति इस प्रकार से थी - $C \rightarrow M \rightarrow C$. अर्थात् लोग वस्तु (Commodity or 'C') का उत्पादन करते थे. फिर उसे द्रव्य में परिणत करने थे (Money or 'M') तदुपरान्त फिर अपने लिए आवश्यक वस्तु खरीद लिया करते थे अर्थात् इस विनिमय प्रक्रिया में द्रव्य केवल 'माध्यम' के रूप में प्रयोग में लाया जाता था.

परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था में यह प्रक्रिया $M \rightarrow C \rightarrow M$ हो गई. जिन लोगों के पास द्रव्य होता है (चाहे वे उत्पादनकर्ता न हों) वे वस्तुएँ खरीद लेते हैं और उसे मँहगा बेचकर और अधिक धन कमाने का साधन बना लेते हैं.

इस पद्धति में वस्तु और अधिक धन बढ़ाने के लिए 'माध्यम' वनी। प्रथम प्रकार की व्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग use values या सन्तुष्टि बढ़ाने के लिए किया जाता था, द्वितीय में इसका प्रयोग धन बढ़ाने के लिए किया जाता है पहली पद्धति में उत्पादनकर्ता लाभान्वित होता है दूसरी में व्यापारी लाभान्वित होता है। प्रथम पद्धति में शोषण नहीं है, दूसरी पद्धति में है। मार्क्स प्रथम व्यवस्था चाहते थे।

अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) मजदूरी के सम्बन्ध में मार्क्स ने रिकार्डों का यह कथन माना कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम मूल्य के बराबर होता है। परन्तु श्रम को यह पूरा मूल्य नहीं मिलता। उसे तो केवल जीवन-निर्वाह के बराबर मजदूरी दी जाती है।

मार्क्स ने मजदूरी के सम्बन्ध में रिकार्डों की दूसरी बात को, (मजदूरी को केवल उनके जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी ही मिलना चाहिए) उन्होंने तिरस्कार करके नहीं माना।

मार्क्स ने बताया कि पूँजीवादी श्रम व्यवस्था में पूँजीपति मजदूरी कम देकर लाभ कमाता है। मजदूर जितना कार्य करता है उसको उतने कार्य का पारितोषिक नहीं मिल पाता। जैसे अगर एक श्रमिक 10 घण्टे कार्य करता है तो वह केवल 6 घण्टे के कार्य के बराबर वेतन पाएगा। 4 घण्टे के उत्पादन के मूल्य को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य (Surplus value) कहते हैं और पूँजीपति इस मूल्य को स्वयं रख लेते हैं।

मार्क्स का कथन है कि प्रत्येक उत्पादनकर्ता अपने इस शोषण धन (अतिरिक्त मूल्य) को बढ़ाना चाहता है और इसके दो उपाय हैं (1) एक तो मजदूरों से अधिक घण्टों तक कार्य कराया जाये इसको absolute increase in Surplus value (अतिरिक्त मूल्य में निरपेक्ष वृद्धि) कहेंगे। मार्क्स का कथन है कि पूँजीपति पहला तरीका नहीं अपनाता क्योंकि इसमें उसके द्वारा शोषण धन कमाने की रीति का भण्डाफोड होता है। (11) दूसरी रीति यह है कि पूँजीपति मशीनों को लगाकर श्रम की उत्पादकता बढ़ाता है परन्तु मजदूर का वेतन नहीं बढ़ाता। मार्क्स के अनुसार पूँजीपति की पूँजी दो प्रकार की होती है : Constant Capital या स्थिर पूँजी (जैसे कच्चा माल) इससे पूँजीपति को अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे प्रकार की पूँजी Variable capital या परिवर्तन योग्य पूँजी (जैसे श्रम) होती है और समस्त अतिरिक्त मूल्य इसी से प्राप्त होता है। अगर उद्योग में Organic composition अधिक है

(पूँजी अधिक व थम कम) तो उस उद्योग में लाभ कम रहेंगे परन्तु अगर उद्योग में Organic composition कम है (पूँजी कम, थम अधिक) तो लाभ अधिक होगा इसका कारण यह है कि समस्त लाभ तो थम से ही उत्पन्न होते हैं जब, मार्क्स कहते हैं कि पूँजीपति जब मशीन लगाकर थम की उत्पादन बढ़ाता है तो थम जा पहले 6 घंटे में उत्पादन करता था वह 4 घंटे में ही कर देता है और 'अतिरिक्त मूल्य' 4 घंटे के थम के स्थान पर 6 घंटे के उत्पादन मूल्य के बराबर हो जाता है,

इसके पश्चात् मार्क्स ने बताया कि पूँजीपति मशीनें लगाकर कई थमिकों को बेरोजगार कर देता है और देश में औद्योगिक अंश्रीय बैंकरो की सेना बन जाती है (Industrial reserve army of unemployed persons) इस बेरोजगारी के कारण मजदूरी की दर नीची बनी रहती है और थमिका के शोषण में अधिकाधिक अतिरिक्त धन कमाता है

“Accumulate, accumulate, accumulate, that is Moses and the Prophet.”

(अर्थात् धन संचित करते रहना ही पूँजीपति का धर्म रह जाता है।)

5 जनसंख्या व विकास :

मार्क्स ने 'जनसंख्या का भय' अधिक जन्मदर में नहीं देखा उनके अनुसार जनसंख्या समस्या खाद्य सामग्री की उपज की दर से अधिक बढ़ने से नहीं उत्पन्न होती बल्कि बेरोजगारी और गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, बेरोजगारी व गरीबी की बुराई स्वयं पूँजीवाद के कारण उत्पन्न होती है, मार्क्स के अनुसार देश में जिस प्रकार की उत्पादन व्यवस्था होगी उसी प्रकार का उस काल के लिए जनसंख्या का सिद्धान्त होगा उत्पादन व्यवस्था बदलेगी तो जनसंख्या के नियम भी बदल जाएँगे मार्क्स ने कहा

“The Law of population under industrial capitalism is the law of a relative surplus population.”

उन्होंने 'अधिक' जनसंख्या का यह कारण बताया

“मेहनतकरा जनता पूँजीपतियों को पूँजी संचित करने में सहायता देती है और साथ ही साथ अपने आप को अतिरिक्त या फालतू बना-

लेने का साधन भी पूँजीपति को प्रदान करती है यह है पूँजीवाद का जनसंख्या का सिद्धान्त¹

मार्क्स का कथन था कि धन व गरीब वर्ग की गरीबी का कारण जनसंख्या की अधिक जन्मदर नहीं होता उन्होंने समाजवाद में "जनसंख्या समस्या" की कोई सम्भावना नहीं देखी

6. कम मजदूरी से उपभोग गिरता है, क्योंकि उपभोग मजदूरी बिल पर निर्भर होता है इससे लाभ व विनियोजन कम होते हैं, फिर बड़े पूँजीपति छोटे पूँजीपतियों का शोषण करते हैं और अन्त में पूँजीवाद समाप्त हो जाता है.
(Wages fall and so do profits and investment : The Law of Concentration of capital / The Accumulation of Capital / The Law of Crises / The Theory of Economic development / Theory of automatic expropriation)

मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर मदी के सिद्धान्त को समझाया. मार्क्स के अनुसार गरीब वर्ग के मुकाबले में धनी वर्ग का उपयोग नगण्य होता है. अगर देश के बड़े वर्ग (गरीबों व मजदूरों) का उपयोग गिरेगा तो कुल प्रभावशील माँग भी गिरेगी और इस प्रकार से उत्पादन व राष्ट्रीय आय भी कम होगी मजदूरी स्तर जब तक गिरा रहेगा, विकास संभव ही नहीं हो सकता इस उपभोग के कम होने से ही औद्योगिक मदी आती है एक तरफ तो उत्पादनकर्ता अपना शोषण धन बढ़ाता और दूसरी ओर बेरोजगारी तथा गरीबी व दुःख बढ़ाता है

जब पूँजीपति थमिको का और अधिक शोषण नहीं कर पाते तो लाभ के लोभ में वे छोटे पूँजीपतियों को प्रतियोगिता में नहीं रहने देते

“बड़ा पूँजीपति छोटे पूँजीपतियों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार एक बड़े तालाब में बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है”

पूर्ण प्रतियोगिता नष्ट हो जाती है बड़े बड़े पूँजीपति एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और वे छोटे पूँजीपतियों को रहने नहीं देते

1 देखिये -

Eden & Cedar Pant translation N york 1929 p 697-8
Coont . op cit p 120-28 and 189.

“पूँजीपति एक Vampire (बड़ी चमगादड़) है जो दूसरो के खून पर जिन्दा रहता है और पनपता है और जितना अधिक खून चूसता है उतना ही मोटा होता जाता है।”

माक्स ने लिखा

“Along with the constantly diminishing number of magnets of capital who usurp and monopolise all advantages of this process of transformation grows the mass of misery, oppression, slavery, degradation, exploitation but with this too grows the revolt of the working class always increasing in numbers, disciplined, united, organised by the very mechanism of the process of capitalist production itself The monopoly of capital becomes a fetter upon the mode of production, who has sprung up and flourished along with, and under it. Centralisation of the means of production and socialisation of labour at last reach a point where they become incompatible with their capitalist integument This integument is burst asunder The knell of capitalist private property sounds. . The expropriators are expropriated ’¹

इन पंक्तियो का हिन्दी भावार्थ है

“वहे पूँजीपतियो की सख्या घीरे घीरे कम होती जाती है और वे आर्थिक विकास के परिवर्तनो के समस्त लाभो को हडप जाते है इसके विपरीत साथ-साथ बहून् मात्रा मे दुख, ज़ुल्म, गुलामी, दहन व शोषण बढ़ता है--इसके कारण सरया मे दहते हुए मजदूरो की घणावत (विद्रोह) बढ़ता है. ये अर्थिक अव सख्या मे ही अधिक नही

होते वरन् वे अधिक अनुशासित, संगठित व मंगुक्त होते हैं स्वयं पूँजीवाद ही इन्हें संगठित कर देता है—पूँजी का एवाधिकार होने से उत्पादन पद्धति में वन्धन पड़ता है उत्पादन के अर्थों के कुछ हाथों में केन्द्रित होने से ऐसी स्थिति आ जाती है कि सम्पूर्ण पद्धति पूँजीवाद के आवरण में छिप नहीं सकती. पूँजीवाद का पर्दाकाश हो जाता है. निजी सम्पत्ति व पूँजीवादी व्यवस्था की अर्थी के साथ घटने वाले घट्टे के स्वर गँजने लगते हैं शोषणवर्तियों का ही शोषण हो जाता है.

मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद एक अस्थिर व विस्फोट की सम्भावनाओं से भरी प्रणाली है. यह जिस रफ्तार से श्रमिकों को काम पर लगाती है उससे अधिक रफ्तार से श्रमिकों को बेकार करती है मार्क्स के अनुसार अगर पूँजीवादी "स्थिर तकनीक" अपनाये तो मजदूर किसी हद पूँजी सचय के साथ साथ अपनी स्थिति भी सँवारें रह सकते. परन्तु पूँजीपति तो अधिकाधिक मशीनें लगाते हैं और "बेकारों की सेना" को उत्पन्न कर देते हैं परन्तु जब इन पूँजीपतियों के शोषण से जनता नस्त हो जाती है तो उन्हें उखाड़ फकती है

‘What the capitalists produce after all, are their own grave-diggers’

‘पूँजीवादी वास्तव में अपनी कब्र खोदने वाले उत्पन्न करते हैं पूँजीवादी अब मजदूरों के ऊपर राज्य करने के लिए नाकाबिल हो गए हैं’

मार्क्स ने बताया कि जहाँ अल्पकाल में उन्नत तकनीक उत्पादनकर्ता के अतिरिक्त मूल्य व लाभ को बढ़ाते हैं, दीर्घकाल में उन्नत तकनीक से बेरोजगारों की सख्या बढ़ जाती है जिससे श्रमिकों का उपभोग कम होता है और इसके कारण उत्पादनकर्ता के लाभ कम होते हैं और विकास रुक जाता है पूँजीपति उन्नत तकनीक के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से, अपने निजी स्वार्थ के कारण, अनभिज्ञ रहते हैं केवल दीर्घकालीन महान मन्दी ही उन्हें मजदूरों की वास्तविक मजदूरी गिराने की मूर्खता की सचाई सामने लाती है, परन्तु तब तक उनका महाकाल उन्हें ग्रस्त कर चुकता है.

मार्क्स के अनुसार व्यापार चक्र केवल एक अल्पकालीन घटना नहीं होते वरन् वे तो दीर्घकाल में पूँजीवाद के समाप्त होने के अनिवार्य नियम के अंग हैं पूँजीपति इन परिस्थितियों में अपनी हानि को पूरा करने के लिए सट्टेबाजी का सहारा लेते

है और अधिक बर्बाद होते हैं इन्ही व्यापार चक्रों के कारण समस्त साख व्यवस्था और वित्तीय संगठन नष्ट हो जाता है

II Marxian Theory of Socio economic revolution मार्क्स का 'सामाजिक-आर्थिक' क्रान्ति का सिद्धान्त

1. देश के आर्थिक सम्बन्ध ही सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक व राजनैतिक सम्बन्ध निर्धारित करते हैं

मार्क्स के अनुसार देश की उत्पादन व्यवस्था से आर्थिक सम्बन्ध निर्धारित होते हैं (जैसे जमींदार और किसान, स्वामी व दास, पूँजीपति व मजदूर) यही सम्बन्ध किसी भी युग की सांस्कृतिक व्यवस्था, उसके नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विचार एवं समस्याओं का मुख्यतः निर्धारण करते हैं उत्पादन शक्ति में जब परिवर्तन होता है तो उत्पादन सम्बन्ध बदलता है और उत्पादन सम्बन्ध के परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन घटित होते हैं

वैसे उत्पादन सम्बन्ध भी उत्पादन शक्ति पर प्रभाव डालते हैं. वे वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर हैं. मार्क्स ने इनका उदाहरण दिया और बताया कि बिजली व मशीनों के आविष्कार ने ही सामन्तवाद को बदल कर पूँजीवाद को जन्म दिया इसी आधार पर मार्क्स ने लिखा

"The mode of production in material life determines the character of the Social political and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but on the contrary, their social existence determines their consciousness"

2. विश्व में हर चीज परिवर्तनशील है (Nothing, except constant change, is constant in this world)

मार्क्स के अनुसार परिवर्तन एक अनोखी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक घटना है, (Change is not an unique but a natural phenomenon) यही प्राकृतिक नियम है कि सब कुछ अपने आन्तरिक स्वभाव के कारण विभक्त व परिवर्तित होता है. मरि-मोर्टल के अनेक नए नए आविष्कारों के कारण, नवीन उत्पादक शक्तियों का जन्म स्वतः अचेत रूप में तथा मानव इच्छा से स्वतन्त्र रह

कर होता है "सामाजिक परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली का 'सामाजिक परिणाम' होते हैं"

3 समस्त महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रान्ति से ही आते हैं

यह समस्त परिवर्तनों में संघर्ष व उथल-पुथल भी होती है उत्पादन शक्तियों का विकास तथा उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन कुछ समय तक तो स्वाभाविक गति से तथा स्वतन्त्रतापूर्वक होता रहता है. पर जब वे सम्बन्ध परिपक्व अवस्था में पहुँच जाते हैं तो 'प्रसव की पीड़ा' की भाँति उत्पीड़न के परचात् नये सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं. पुराना वर्ग विकास में अलङ्घनीय (Insuperable) बाधा बन जाता है जब नया वर्ग इनको हटाना चाहता है तो पुराना वर्ग उनपर अत्याचार करता है परन्तु नया वर्ग उन्हें क्रान्ति के द्वारा अन्त में हटा ही देता है जब यह सम्बन्धों की बेड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं तब समाज की संरचना भी परिवर्तित हो जाती है

मार्क्स के अनुसार .

"नये विचार और सिद्धान्त नयी भौतिक परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं इनके द्वारा जन साधारण को भौतिक जीवन की त्रुटियाँ और आन्तरिक विरोधों का ज्ञान हो जाता है. जाये विचार जनता की निधि बनते हैं, तो वे सामाजिक परिवर्तनों के लिए बेशकीमती हो जाते हैं इनकी पृष्ठभूमि में ही जनता उन शक्तियों को विध्वंस कर सकती है जो समाज की प्रगति में बाधक हैं"

कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने परिपक्व होने के बाद ही समाप्त होती है मार्क्स के अनुसार

"उत्पादन के नवीन तथा उच्चतर सम्बन्ध तब तक कदापि उत्पन्न नहीं होते जब तक उनके अस्तित्व की भौतिक दशा में पुराने समाज के गर्भ में परिपक्व नहीं हो जाती हैं"

III Marxian Stages of Economic Growth मार्क्स और उनकी विकास की अवस्थाएँ

'Marx was a 'Stages-man' par excellence Hegel's thesis, anti-thesis, and synthesis becoming in Marxian Economics Feudalism, capitalism and socialism"

(Meier and Baldwin op. cit p 148)

मार्क्स ने Communist Manifesto में विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया। यह विकास की अवस्थाएँ पूर्ण रूप से मध्य पूर्ण होती हैं। इसीलिए रॉस्टोव ने (W. W. Rostow) ने अपनी सर्वप्रथम अवस्थाओं को A Non-communist Manifesto कहा।

मार्क्स की यह विकास की अवस्थाएँ इस प्रकार से थी

1. प्राथमिक और असभ्य साम्यवाद : (Primitive Communism)

मार्क्स का कथन था कि सर्व प्रथम मानव जाति असभ्य थी। वह जंगलों में जानवरों की तरह रहती थी और जो कुछ वे पाते थे (न कि पैदा करते थे) उस पर निर्वाह करते थे। बाद में कृषि आदि जो कुछ भी विकसित हुई उसके तरीके पुराने थे परन्तु इन 'समाज' में भी साम्यवाद था। समस्त उत्पादन व वितरण सामूहिक ढंग से होता था। यह साम्यवाद परन्तु, "गरीबी की स्थिति" का था।

2. दास प्रथा Slave Society.

इस प्रथा में भूमि कुछ लोगों के हाथ चली जाती है और इस युग में कृषि उत्पादन दासों द्वारा किया जाता है न केवल भूमि कुछ लोगों की सम्पत्ति रहती है वरन् स्वयं श्रमिक इन मालिकों की सम्पत्ति बन जाते हैं। वे अपना श्रम ही नहीं बेचते बल्कि स्वयं को भी बेच देते हैं।

3. सामन्तवादी समाज : (Feudal Society)

यह विकास की तीसरी पर कुछ ऊँची अवस्था होती है। इस प्रथा में श्रमिकों को दास के रूप में नहीं रखा जाता था, परन्तु वेतन आदि के रूप में रखा जाता था। उनकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं रहती थी। भूमि के मालिक जमींदार रहते थे, छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग चलने थे उत्पादन व्यवस्था कुछ उन्नत थी, सामाजिक व आर्थिक जीवन भी कुछ उन्नत था।

4. पूँजीवाद : (Capitalism)

मार्क्स ने पूँजीवाद को विकास की श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी माना। मार्क्स पूँजीवाद की विवाम में योगदान के बहुत प्रशंसक रहे। उनके अनुसार "पूँजीवाद ने संकुचित विचारधारा को कम किया। सामन्तवाद की राख पर पतननेवाले पूँजीवाद ने विश्व की जनता के बड़े भाग को गाँव की 'बेवकूफ़ भरो' जिन्दगी से छुड़ाया। पूँजीवाद ने सन्नत तकनीक दी और विशाल मात्रा में राष्ट्रीय आय व उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाएँ सामने लाईं कुछ ही पीढ़ियों में पूँजीवाद ने समस्त पिछले इतिहास से अधिक धन पैदा कर दिया।"

पूँजीवाद में उत्पादन के अगो के मालिक वे व्यक्ति हो गए जो या तो कुछ भी मेहनत नहीं करते या बहुत कम मेहनत करते हैं। जो सक्रिय है व उत्पादन की जान है (धर्मिक) उनसे उनके औजार छीन लिए गए। उनके रोजगार के मालिक पूँजीपति हो गए। ऐसी उत्पादन व्यवस्था में मजदूरी धर्म (Wage Labour) के आधार पर उत्पादन कराया जाता है। ऐसे उत्पादन से प्राप्त लाभों को पूँजीपति वर्ग ही हड़प लेते हैं।

पूँजीवादी उत्पादन पद्धति अधिकाधिक जटिल होती जाती है श्रम विभाजन पर आधारित इस पद्धति में वर्ग संघर्ष मुख्य अंग रहता है। मार्क्स ने लिखा

Freeman and slave, patrician and plebeian, baron and serf, guildmaster and journey man. in one word, oppressor and oppressed, Standing constantly in opposition to each other carried on an uninterrupted warfare, now open, now concealed, a warfare which always ended either in a revolutionary transformation of the whole Society or in the common ruin of the contending classes.”¹

(अर्थात् स्वतन्त्र व्यक्तियों व गुलामों में, सामन्तों और साधारण व्यक्तियों में, मालिक और दासों में, एकाधिकारियों व मजदूरों में, संक्षेप में शोषणकर्ता व शोषित व्यक्तियों में एक न समाप्त होने वाली लड़ाई, जो कभी प्रत्यक्ष व कभी छिपी हुई रहती है, चलती रहती है। इस लड़ाई में या तो एक नए क्रान्तिकारी समाज की स्थापना होती है या फिर दोनों बरबाद हो जाते हैं।)

मार्क्स ने अपनी इन अवस्थाओं में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद समझाया इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ यह हैं

- (i) ससार में पहले एक 'वाद' का जन्म होता है (first ■ thesis is propounded),
- (ii) फिर उसका प्रतिवाद होता है (Then there is anti-thesis),
- (iii) तत्पश्चात् इन दोनों का सम्वाद होता है (Then there is synthesis of both).

इस प्रकार का यह क्रम चरता रहता है उत्थान परिवर्तन और विनाश का यह क्रम विरोधी शक्तियाँ के कारण चलता है।

मार्क्स ने समझाया कि समाज में गुणात्मक एवं गणनात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होने हैं ये परिवर्तन धीरे-धीरे नहीं बरन् एकदम होने हैं

प्रत्येक द्वन्द्वात्मक परिवर्तन में हम ऊपर उठ जाते हैं। विकास की प्रक्रिया चक्रवत् नहीं होती बरन् घागे बढ़ाती है समस्त परिवर्तन क्रान्तिकारी रूप से आते हैं और समाज में जो कुछ भी परिवर्तन या विकास होता है वह विरोध एवं संघर्ष द्वारा ही होता है

“Force is the midwife of every old society pregnant with a new one.”

और उन्होंने कहा

“माता की प्रसव पीड़ा द्वारा ही बालक का अन्म होता है, उसी तरह क्रान्ति, (परिवर्तन रूपी शिशु) का अन्म समय समाज रूपी माता की प्रसव पीड़ा है ”

इस प्रकार मार्क्स का कथन है कि इतिहास का निर्माता वीर नायक नहीं बरन् वीर जनता होती है मेहनतकरा जनता का इतिहास ही विकास का इतिहास होता है

मार्क्स इस प्रकार से पूँजीवाद को विकास की अवस्थाओं की एक कड़ी मानते थे जिसकी दूटना पड़ेगा पूँजीवाद में वर्ग-संघर्ष रहेंगे और जब तक पूँजीवाद समाप्त नहीं होगा, वर्ग-संघर्ष भी समाप्त नहीं होगा

मार्क्स ने बताया कि पूँजीवाद के समाप्त होने से पहले पूँजीवाद साम्राज्यवाद का रूप लेगा, परन्तु कालान्तर में दोनों समाप्त हो जाएँगे

5. साम्राज्यवाद : (Imperialism)

मार्क्स ने साम्राज्यवाद को पूँजीवाद का विपुल रूप माना उनका कथन था कि पूँजीवाद नष्ट होने से पहले देश में एकाधिकारी पूँजीवाद का रूप लेता है तदुपरान्त वह अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवाद या साम्राज्यवाद का रूप लेता है। एक बड़े पूँजीपति देश के उत्पादन कर्ताओं के लाभ के लिए पूँजीपति देश के राज्य गरीब देशों को अपने आधिपत्य में लाने है।

यह पूँजीपति वर्ग अपना धन इन गरीब देशों में लगाते हैं पर उनका लक्ष्य उन देशों का आर्थिक विकास करना नहीं होता बरन् अपने देशों के लिए सस्ते कच्चे

माल के पूर्तिकर्ता के रूप में इन देशों का प्रयोग किया जाता है। पूँजीपति देशों के उत्पादनकर्ता अपने अधीनस्थ देशों के श्रम का शोषण करते हैं इनको न केवल जीवन निर्वाह के योग्य मजदूरी देते हैं। इनको संगठित नहीं होने देते

पूँजीवादी देशों के उत्पादनकर्ता उपनिवेशों के देशों में व्यापार की लूट से अपने देश के विकास के लिए पूँजी निर्माण करते हैं साम्राज्यवादी, इन देशों में सस्ता सामान लेते हैं और बहुधा उन्हीं के कच्चे माल से बने सामान को अधिक मूल्य पर बेचते हैं साम्राज्यवादी भुगतान की शर्तों को हमेशा अपने पक्ष में रखते हैं इन देशों से सस्ता खाद्यान्न मँगाकर अपने देश की मजदूरी बढ़ने से रोकते हैं इन देशों से आयातों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं जबकि अपने देशों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते

मार्क्स का कथन था साम्राज्यवादी देश इस प्रकार में अपने देश में पूँजीवाद के अन्त होने को केवल टाल सकते हैं, बचा नहीं सकते बाद में साम्राज्यवादी देश इन उपनिवेशों पर अपना अपना आधिपत्य जमाने के लिए संघर्ष युद्ध करते हैं और स्वयं नष्ट होते हैं दूसरी ओर गरीब देशों की गरीब जनता इनके खेलको समझ जाती है वे संगठित होते हैं और फिर वे इस साम्राज्यवादियों को समाप्त कर देते हैं अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष और युद्ध साधारण जनता में राष्ट्रीयता का उदय करते हैं और इसके साथ ही पूँजीपति तथा श्रमिक वर्ग का संघर्ष छिड़ जाता है। साम्राज्यवाद जब समाप्त हो जाता है तो पूँजीवाद पूरी तरह नष्ट हो जाता है और फिर समाजवाद आशा का सूर्य लेकर उदय होता है

6 समाजवाद : (Socialism)

पूँजीवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद समाजवाद का युग आएगा समस्त उत्पादन पूँजी-भूमि व उद्योग-राज्य के अधिकार व मालिकियत में आजाएँगे, देश व किसान व श्रमिक ही वास्तव में इनके मालिक होंगे, वे सामूहिक रूप से इन पर कार्य करेंगे और व्यय को काट कर जो कुछ लाभ होगा वह राज्य व श्रमिकों को मिलेगा राज्य प्रशासन व सुरक्षा आदि के व्यय को खर्च करने के पश्चात् लाभ के बाकी भाग से और अधिक पूँजी निर्माण करेगा और जनता के आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में लगाएगा, समाजवाद में सबको शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने व कार्यानुसार पारिश्रमिक पाने का अधिकार होगा वर्ग-संघर्ष, शोषण व असुरक्षा समाप्त हो जाएगी। समाजवादी देश अन्य देशों के पूँजीवाद व साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में सहायता देंगे

7 साम्यवाद . (Communism)

समाजवाद में जहाँ 'कार्यानुसार' वतन मिलना है, साम्यवाद में "आवश्यकता अनुसार" वतन मिलेगा समाजवाद सबके लिए इतनी समृद्धि ला देगा कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँगी ऐसी शापण विहीन तथा समृद्ध समाज में राज्य या शासन की ही आवश्यकता नहीं रहेगी और जब विश्व में सब जगह समाजवाद स्थापित हो जाएगा तब हमारी कल्पना का स्वर्ग यही आ जाएगा
(The state will wither away)

IV Critical Appraisal of Marxian Model

As a formal model Marxian economics is weak. The "internal contradiction" of the model are more pronounced than in capitalism itself (Meier and Baldwin op. cit p. 66)

मार्क्स का विकास मॉडल मार्क्स विकास के सबसे महान् "क्रान्तिकारी मॉडलों" में से एक है मार्क्स के मॉडल में कुछ बाने तो बहुत ही गलत हैं, जैसे

(1) मार्क्स का कथन है, पूँजीपतियों समस्त लाभ धर्म से प्राप्त होते हैं पूँजी से नहीं धर्म ही समस्त आय व लाभ का साधन है (High organic composition of more capital and less labour yields lesser surplus value than low organic composition of less capital and more labourers). अगर वास्तव में ऐसा है तो पूँजीपति मूर्ख होगा कि वह अधिवाधिक मशीनें लगाकर धर्मिक को बेरोजगार करे

(2) मार्क्स का कथन है अतःकाल में पूँजीपति मशीनें लगाकर व उन्नत तकनीक में लानाश्वित होता है, और दीर्घकाल में "तकनीकी बेरोजगारी" के कारण ही अल्प प्रभावशील माँग कम होती है तो पूँजीवादी लाभ समाप्त हो जाते हैं

यहाँ पर मार्क्स के तर्क वास्तविकता के विपरीत हैं. वास्तव में मशीनों में अल्प काल में बेरोजगारी उत्पन्न होती है दीर्घकाल में तो मूल्य सस्ते होने के कारण जो अधिक माँग उत्पन्न होती है उससे अधिक लोगों को वापिस काम मिल जाता है और स्वयं मशीन के निर्माण में व्यक्ति काम पर लग जाते हैं

"अगर हम पिछला इतिहास देखें तो पाएँगे कि विश्व में अप्रत्याशित रूप से तकनीकी उन्नति हुई है—यातायात में जानवरों से वायुयानों

तक, औजारों में पत्थर के टुकड़ों से स्वचालित स्कू-मशीनों तक, संचार में घुएँ द्वारा सूचना देने की रीति से रेडियो तक, मशीनों में हाथ से चलने वाली मशीनों से विजली की मशीनों तक, परन्तु जन-संख्या की वृद्धि के बाद भी आज कितने अधिक व्यक्ति खानों, मिल व कारखानों खेत व दुकानों व यातायात में कार्य कर रहे हैं दीर्घ-काल में तकनीकी बेरोजगारी केवल कोरी कल्पना का डर है।”¹

- (3) मार्क्स की बहुत सी भविष्यवाणियाँ सत्य नहीं निकलीं आज मजदूरों के वेतन केवल जीवन निर्वाह के बग़र नहीं हैं। उन्नत देशों में संगठित श्रमसंघों, राज्य के प्रयत्नों से मजदूरों के स्तर ऐसे हैं कि श्रमिक भी अच्छा जीवन यापन करते हैं उत्पादन में मजदूरों को लाभ में भी हिस्सा मिलता है मजदूरों का स्तर गुलामी का नहीं रह गया है उन्हें सामाजिक सुरक्षा के अधिकाधिक लाभ मिल रहे हैं (पेंसन, बेरोजगारी का भुआवजा, छुट्टियाँ, इत्यादि की सुविधाएँ, प्रोविडेंट फंड, मानव दिनों में लाभ आदि)
- (4) पूँजीवाद में तो अधिक भी पूँजीपति बन सकते हैं। समस्त देशों में तो बड़े बड़े संस्थानों के शेयर स्वयं श्रमिक भी अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं।
- (5) पूँजीवाद में आज सारे संस्थान “एकाधिकारी” संस्थान नहीं हैं। छोटे उत्पादनकर्ता आज भी हैं और वे बड़े उत्पादनकर्ताओं के द्वारा निगले नहीं गए हैं। उन्नत से उन्नत देशों में एकाधिकार विरोधी नियम हैं।
- (6) स्वयं समाजवादी देशों में श्रमिक संघर्ष करते हैं वहाँ बड़े पार्टियाँ अफसर व राजनीतिज्ञ ही बड़े पूँजीपति का रूप ले लेते हैं हंगरी व जेकोस्लोव्हेनिया के श्रमवर्ग का समाजवादी व्यवस्था के शिकंजे से निकलने या कम से कम उसे ढीला कर देने के आन्दोलन से हम परिचित हैं सच तो यह है कि विकसित देशों में समृद्धि में रहने के स्वयं श्रमवर्ग आदी हो गया है और आज बेमार ही समाजवादी देशों के व्यक्ति मार्क्स की भविष्यवाणी के पूरा होने की आशा रखते हैं।

1. Translated : See. p. 2 “Economics of Wages, Productivity and Employment” by Dr. O. S. Shrivastava, Kailash Pustak Sadan, Gwalior 1968.

(7) Meier & Baldwin के अनुसार

- (1) मार्क्स के हम इस विचार को नहीं मान सकते कि सभी परिवर्तन संघर्ष से आते हैं
- (11) मार्क्स का विज्ञान का सिद्धान्त "भावनात्मक" अविवेक है उम्में उनके क्रोध को भ्रमक है ¹

उन्होंने कहा

"Like all single factor theories, the Marxian interpretation of history has the appeal of simplicity and generality. But this is a multi-factor world, and truer though less spectacular explanation involve a recognition of complex interactions among many variables. The Marxian theory is too crude to pass the test of being able to predict accurately."

(8) Benjamin Higgins के अनुसार मार्क्स का कथन था कि समाजवाद उन देशों में आया जहाँ पूँजीवाद विकास की चरम सीमा पर आ जाता है परन्तु वास्तव में समाजवाद वहाँ आया है जहाँ पूँजीवाद विकसित नहीं हुआ था। आज विकसित देशों में मध्यम वर्ग के परिवार भी आगे बढ़ रहे हैं। जबकि समाजवादी देशों में न तो गरीबी पूर्ण रूप में दूर हुई है और न राज्य का ही अस्तित्व समाप्त हुआ है।

मार्क्स यह भी नहीं समझ पाए थे कि उन्नत तकनीक व बढ़ती हुई उत्पादकता की स्थिति में लाभ व मजदूरी दोनों एक साथ बढ़ते हैं

Higgins कहते हैं

"Marxian Model is based upon a diagnosis of the social situation of the 1840s and 1850's that was ideologically vitiated at its roots, hopelessly wrong in its prophecy of ever increasing mass misery, inadequately substan-

1. Meier & Baldwin op cit. 51-66.

tiated both factually and analytically.” अर्थात् मार्क्स का मॉडल 1840 व 1850 के बीच की आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर आधारित था इसकी बौद्धिक जड़ें दूषित थी, इनकी भविष्यवाणी कि अधिकांश जनता दुखी रहेगी पूर्णतया असत्य रही और सैद्धान्तिक विश्लेषण व ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर इनके मॉडल की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकी।¹

- (9) Subrathesh Ghosh के अनुसार ‘मार्क्स’ ने कभी भी विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया, परन्तु उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें विकास प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है. मार्क्स ‘शुद्ध अर्थ-शास्त्री’ तो नहीं थे उनके लिखने का उद्देश्य न तो अध्यापन संबंधी था और न ही वृद्धि सम्बन्धी था. (His objective were neither pedagogic nor intellectual) उन्होंने अपने किसी भी विचार को सामाजिक पहलू से अलग नहीं किया ” इसलिए उन्होंने आर्थिक कारणों का विकास में ज्यादा अध्ययन किया.
- (10) मार्क्स के जनसंख्या सम्बन्ध में विचार त्रुटिपूर्ण थे कि वे अधिक जनसंख्या को पूँजीवाद की समस्या ही मानते थे आज समाजवादी देश भी जनसंख्या नियन्त्रण की बात सोचते हैं. उनका यह कथन एकदम अवास्तविक है कि समाजवादी प्रथा अपनाई जाए तो जनसंख्या की अधिकता कभी सहमूस नहीं होगी और न ही जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक होगी
- (11) मार्क्स का यह भी कथन सही सिद्ध नहीं हुआ कि अगर विकासशील देशों ने साम्राज्यवादी हट जाएंगे तो विकास स्वयं शुरू हो जाएगा. हालांकि साम्राज्यवाद समाप्त होना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु कई देशों में साम्राज्यवादियों के जाने के बाद वे अपनी पूँजी भी वापिस ले गए या विदेशी पूँजी व तकनीकी सहायता के कम हो जाने से उनका विकास रुक हो गया

मार्क्स जैसे व्यक्ति के लिए निम्नलिखित बात कहना आश्चर्यजनक लगता है .

“समस्त देश एक जैसी पूँजी निर्माण व उत्पादन की क्षमता नहीं रखते. कुछ पिछड़े राष्ट्रों में जैसे तुर्की में न तो प्रेरणा और न ही इन बात की रूचि होती है.”²

1. Benjamin Higgins : op-cit. p. 117-120

2. See - 1 E A Number on Economic Growth Models.

इन देशों में तकनीकी उन्नति के कारण या व्यापारिक चक्रों के कारण बेरोजगारी नहीं आती बल्कि पूँजी की कमी व जनसंख्या की जन्म दर के अधिक होने के कारण होती है।

महत्व

ग्राम मासूम के विकास मॉडल को अपनाने में ही विक्रम नहीं हो सकता. स्वयं समाजवादी देशों में उन 'वर्ल्ड अर्थशास्त्र' (Vulgar Economics) के सिद्धान्त, जिनको मार्क्स ने तिरस्कार किया पूर्ण रूप से छोड़ नहीं जा सके वहाँ भी ग्राम बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है परन्तु यह सब कुछ होते हुए मार्क्स के मॉडल में महत्वपूर्ण तक व सुझाव है

Schumpeter के अनुसार

“No social scientist has so deeply understood the impact of capitalistic machine and shown in so grand a vision of its immense power to transform human civilization in the process of technical and social change”

Benjamin Higgins ने मार्क्स के मॉडल में निम्नलिखित तत्वों को महत्वपूर्ण बताया

- (1) उन्होंने ही बेरोजगारी की समस्या को सर्वप्रथम विकास मॉडल में स्थान दिया.
- (11) उन्होंने स्थायी विकास के लिए उपभोग व विनियोजन तथा बचत व विनियोजन में सन्तुलन रखने पर जोर दिया.
- (111) उन्होंने पूँजीवाद में विकास की ऐतिहासिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जो कि हमको किसी देश के विकास का भूत व भविष्य समझने में मदद करता है.

Nasir Khan

“Marx was the fist among the older economists who gave a model of expanded reproduction and introduced the cycle in his analytical scheme... This was a static economic analysis... ...He even guessed of 11—12 years of cycles. but formulated no precise trade cycle theory”

Meier Baldwin

मार्क्सवाद को हमको समझना चाहिए क्योंकि यह आज भी सबसे अधिक अपील करने वाला राजनैतिक धर्म है जो विकसित व विकासशील दोनों के भविष्य सुधारने में सहायक हो ¹



Marx Capital & Communist Manifesto

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1 Benjamin Higgins | op cit |
| 2 Meier & Baldwin | op cit |
| 3 D B Singh | op cit |
| 4 Nasir Khan | op cit |
| 5 Okun & Richardson | op cit |
| 6 J K Mehta | op cit |
| 7 Haney | op cit |
| 8 Gide & Rist | op cit |
| 9 A Gray | op cit |
| 10 Gric Roll | op cit |
| 11 Schumpeter | op cit |
| 12 Taylor | op cit |
| 13 Neff | op cit |
| 14 Joan Robinson | Marx as an Economist |
| 15 R N Mukerjee | समाज शास्त्र की विचार धारा |

नव-प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्री मार्शल

Neo-Classical Economist Marshall

A प्रस्तावना

B विकास पर विचार

1. राष्ट्रीय आय उत्पन्न के पाँचो अंगों के सहयोग का परिणाम है
2. कृषि व उद्योग का सापेक्षिक महत्व
3. जनसंख्या व पूँजी
4. मजदूरी, ध्यान, लगान व लाभ
5. विकास की प्रक्रिया सतत तथा धीमी
6. विकास की प्रक्रिया में कोई संघर्ष नहीं

नव-प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों का विकास मॉडल

Neo Classical Model As a whole

A प्रस्तावना

B विकास मॉडल

1. विकास पूँजी संचय पर निर्भर
2. इसके अनुसार (I) तकनीक की उन्नति (II) भ्रम विभाजन के विस्तार (III) लाभ की वृद्धि तथा (IV) उत्पादन के अंगों को सीमान्त उत्पादकता के सिद्धान्त के अनुसार कार्य पर लगा कर (V) राष्ट्रीय आय बढ़ाने में विकास होता है
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास आर्थिक विकास में सहायक
4. विकास प्रक्रिया समन्वित व संचयी होती है

C नव-प्रतिष्ठित अर्थ शास्त्रियों के विकास संबंधी विचारों की समीक्षा
कमियाँ

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल

Neo-Classical Economist Marshall

A प्रस्तावना

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में मार्शल मुख्य अर्थशास्त्री थे उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पुरानी शराब की नई बोतलों में भरा इन्होंने सर्वप्रथम तो अर्थशास्त्र को 'भौतिक कल्याण का शास्त्र' कहकर कल्याणकारी शास्त्र बनाया इसलिए मार्शल के अनुसार किसी देश के विकास का मापदण्ड यही नहीं होता कि उस देश में कितना उत्पादन होता है (या कितनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है) बरन् मापदण्ड यह है कि इसमें कितना सामाजिक कल्याण बढ़ता है .

इनके विकास सम्बन्धी विचारों को हम निम्न सूत्रों में बाँध सकते हैं

B विकास पर विचार

1. राष्ट्रीय आय उत्पादन के पाँचों अंगों के सहयोग का परिणाम है राष्ट्रीय आय की वृद्धि विकास सूचक है

मार्शल के विचार में उत्पादन के तीन प्रमुख साधन प्राकृतिक साधन, श्रम व पूँजी हैं उन्होंने सगठन और साहसी को भी महत्वपूर्ण माना, पर विकास प्रक्रिया में साहसी का जितना महत्व आगे शम्पीटर ने आँका था उतना मार्शल नहीं बता पाए श्रमकों उन्होंने उत्पादन का साधन व साध्य माना

मार्शल ने उत्पादन के अंगों के परस्पर प्रतियोगी व पूरक होने की बात कही कभी कभी यह अंग पूरक होने के स्थान पर प्रतियोगी हो जाते हैं, जैसे एक मशीन कुछ श्रमिकों को बेरोजगार कर देती है पर मार्शल के अनुसार अंत में सब उत्पादन के अंग एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं (जैसे विस्थापित श्रमिक बाद में मशीनों के उत्पादन में काम पा लेते हैं या मशीनों के कारण जो चीजें सस्ती होती उनसे बड़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए काम पा जाते हैं)

उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय आय को विकास का सूचक माना और उसकी सर्वप्रथम सर्वग्राह्य परिभाषा दी, जो इस प्रकार थी

"राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की वह वार्षिक शुद्ध आय है जिसको उस

देश के प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके उम देश के पूँजी व श्रम भौतिक व अर्थभौतिक वस्तुओं के रूप में एक वर्ष में पैदा करते हैं "

मार्शल ने बताया कि किसी देश का विकास उचित वितरण (सीमान्त उत्पादकता के अनुसार) पर ही निर्भर नहीं करता बरन सर्वप्रथम इस आय को बढ़ाने से बढ़ता है (We should not clamour too much for having a greater share from a cake but should try to increase the size of the cake itself) (यह मार्शल के शब्द नहीं हैं) .

इस प्रकार मार्शल अधिक राष्ट्रीय आय व उचित वितरण दोनों की विकास के लिए आवश्यक मानते थे

2 मार्शल ने भी तकनीक व श्रम-विभाजन का विकास प्रक्रिया में महत्व माना कृषि व उद्योग का सापेक्षिक महत्व :

मार्शल उन्नत तकनीक को बहुत महत्व देते थे इसके कारण वे तो यह भी मानते थे कि कृषि में भी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने में रोक जा सकता है और काफी समय तक टाला जा सकता है इस संबंध में उनके विचार रिकार्डों की भाँति निराशापूर्ण नहीं थे, और इसी कारण वे हर जनसंख्या वृद्धि को रिकार्डों की भाँति भय से नहीं देखते थे वे कहते थे 'भूमि की उर्वरता स्थिर नहीं है. वह समय, स्थान व तकनीक के साथ साथ बदलती है और उन्नत तकनीक से भूमि की उत्पादकता दुगुनी भी हो सकती है साथ संबंधी समस्या के संबंध में उन्होंने बताया कि समुद्र से मछली तो उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अनुसार प्राप्त हो सकती है मार्शल का ध्यान था कि "जहाँ उत्पत्ति में मनुष्य का योगदान अधिक होता है वहाँ उत्पत्ति वृद्धि नियम और जहाँ प्रकृतिका योगदान अधिक होता है वहाँ ह्रास नियम लागू होता है " इस प्रकार से अगर कृषि में मनुष्य का योगदान बढ़ा दिया जाए (अर्थात् उन्नत तकनीक अपनाई जाए) तो इसमें उत्पत्ति का वृद्धि नियम लागू हो सकता है

मार्शल उपरोक्त कारण से ही उद्योग की कृषि से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे मार्शल मशीनीकरण के पक्ष में थे क्योंकि इससे श्रम-विभाजन और विस्तृत किया जा सकता है इसकी वृद्धि में उत्पादकता व राष्ट्रीय आय, अर्थात् विकास बढ़ता है

Marshall . Principles of Economics & Economics of Industry
p 116, 434, 550-3
p 125-140 p 220.
p. 150-170.

मार्शल ने उत्पत्ति में ममता के नियम के कार्यान्वित होने की सम्भावना व्यक्त की।

3 जनसंख्या व पूँजी :

वे भी पूँजी-मन्त्र की विकास की सर्वप्रथम आवश्यकता मानते थे, इसी की माना वृद्धि से तकनीकी उन्नति संभव है

जनसंख्या के संवर्धन में मार्शल मान्यस के विचारों में सहमत नहीं थे शिवांत लोगो में वे बड़े परिदार की बुरा नहीं मानते थे. उनका पूर्ण विश्वास था कि अगर जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि (अच्छा स्वास्थ्य व अच्छी शिक्षा) होती है तो इसने देश में विकास धड़ेगा उनका विश्वास था कि उत्पत्ति-वृद्धि नियम के कार्यान्वित होने पर उत्पत्ति जनसंख्या से भी अधिक बढ़ाई जा सकती है

4 मार्शल के विकास मॉडल में मजदूरी, व्याज, लगान व लाभ :

(a) मार्शल ने जब वितरण की समस्याओं पर लिखा तब मार्क्स लिख चुके थे, इसलिए वे मजदूरी की जीवन निर्वाह के बराबर रखने की बात ही नहीं सकते थे फिर उनका मान्यस के जनसंख्या के सिद्धान्त में विश्वास भी नहीं था उन्होंने लिखा

“Free human beings are not brought upto their work on the same principles as a machine, a horse or a slave”

उन्होंने मजदूरी निर्धारण में मानवीयता दिखाने व न्याय करने की माँग देखी और उनके अनुसार “मजदूरी की अधिकतम दर मजदूरी की सीमान्त उत्पादकता व न्यूनतम मात्रा जीवन स्तर को ध्यान में रखकर निर्धारित होती है. व मजदूरी-प्रणाली ऐसी चाहते थे जिसमें श्रम की कार्यक्षमता व उत्पादकता बढ़े जिससे कि राष्ट्रीय आय बढ़े और विकास हो.

(b) व्याज को भी वे माँग व पूर्ति या सीमान्त उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होना मानते थे. व्याज को वे बचत व विनियोजन में साम्य लाने वाला तत्व मानते थे अगर कभी भी देश में विनियोजन की मात्रा के लिए अधिक पूँजी न हो तो व्याज की दर में वृद्धि हो जाती है और फिर इसी में बचतें बढ़ जाती हैं, व विनियोजन के लिए पर्याप्त पूँजी प्राप्त हो जाती है

लगान व सम्बन्ध मार्शल के विचार विचारों की भाँति ही थे

लाभ को वे जोखिम उठाने का पारितोषिक, व्यवसायिक योग्यता का पुरस्कार तथा मूल्य की स्थिति पर निर्धारित होने वाला तत्व मानते थे उनका विचार था

कि अल्पकाल में लाभ को दर मूल्य की अचिक्ता, साहसिकों की कमी के कारण ऊँची रहती है परन्तु दीर्घकाल में सामान्य मूल्य की प्राप्ति व साहसिकों की पूर्ति की अधिकता के कारण, लाभ की दर कम हो जाती है, वे लाभ को पूँजी-संचय का प्रमुख स्रोत मानते थे. इस कारण वे इसका अधिक होना चाहते थे

5. मार्शल विकास की प्रक्रिया को सतत तथा घीमी प्रक्रिया मानते थे मार्शल के विचारों पर डार्विन व स्पेन्सर की जीव-विज्ञान व सामाजिक क्रमिक विकास सिद्धान्तों का बहुत अधिक प्रभाव था मार्शल ने इसी कारण आर्थिक विकास प्रक्रिया को जीव-विज्ञान प्रक्रिया की भाँति देखा उन्होंने कहा

"The Mecca of the economists lies in the economic biology rather than economic dynamics."

(इसका भावार्थ है कि अर्थशास्त्री का निर्माण अर्थशास्त्र को जीव-विज्ञान की भाँति अध्ययन करने में है न कि गति विज्ञान के रूप में अध्ययन करने में)

उन्होंने लिखा

"यह सर्व विदित तथ्य है कि प्रकृति स्वेच्छा से छलांग मारकर आगे नहीं बढ़ती यही बात आर्थिक विकास के सम्बन्ध में भी लागू होती है "

उन्होंने आर्थिक विकास की तुलना जंगलों में पेड़ों की वृद्धि से की जो घीमे होती है (इस सम्बन्ध में आगे चलकर हम शम्पीटर के विचार पढ़ेंगे जो इन विचारों से विल्कुल भिन्न है)

बैसे तो Marshall के काल में ही बहुत से महत्वपूर्ण नव-प्रवर्तन तेजी से हो रहे थे फिर भी उनका कथन था कि विकास धीरे-धीरे ही होता है

उन्होंने कहा

"यह हो सकता है कि एक नव-प्रवर्तक अथवा एक सगठनकर्ता या एक प्रतिभावान पूँजीपति एक ही बार में पूरी अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दे, फिर भी अगर हम निकट से अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि इस कार्य की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी "

6 मार्शल विकास की प्रक्रिया में कोई संघर्ष नहीं देखते थे :

मार्शल यह मानते थे कि विकास प्रक्रिया में एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग

His Book VI P 335 onwards.

p. 6.

के विकास में सहायक होता है उनका विश्वास था कि इस प्रकार से हर उद्योग का विकास एक दूसरे उद्योग के विकास में पूरक व सहायक सिद्ध होता है

मार्शल ने हमको सर्वप्रथम "बाह्य मितव्ययिताओं का विचार दिया" यह बाह्य मितव्ययिताएँ वे हैं जो एक उद्योग के विकास से दूसरे को मिलाती हैं, जैसे याता-यात के विकास से सभी उद्योगों को लाभ होता है उनके इस विचार से "संतुलित विकास पद्धति" के प्रवर्तकों को बहुत बल मिला और आगे चलकर नवर्स ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर संतुलित विकास-पद्धति की सिफारिश की

मार्शल का विचार था कि अगर एक बार विकास-प्रक्रिया शुरू हो गई तो वह सचयी होगी, अर्थात् देश विकास-मय पर आगे बढ़ता जाएगा

नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विकास मॉडल

Neo-classical Model As a whole.

A प्रस्तावना

सन् 1870 के पश्चात् प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सम्बन्धी विचारों की प्रतिष्ठा कम हो गई. उन्होंने जिन बातों को विकास मॉडल का आधार बनाया था वे सही सिद्ध नहीं हुईं. जैसे उनको भय था कि गिरते हुए लाभ के कारण विकास रुक जाएगा और स्थिर अर्थ-व्यवस्था की दशा आ जाएगी जिसमें लगान अधिक व मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर रहेंगे पर तकनीकी उन्नति ने यह सब गलत सिद्ध कर दिया मजदूरी के स्तर उत्पादकता-वृद्धि के साथ बढ़े, लगान प्राप्त-कर्ता राष्ट्रीय आय का छोटा हिस्सा ही प्राप्त करते थे वैसे इन नव-प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों में विकसेल (Knut Wicksell) को भी स्थिर अर्थव्यवस्था का बहुत डर था, और मार्शल भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्ति में कमी की आशंका से ब्रिटेन में ऐसी स्थिति की कल्पना करते थे, फिर भी, यह डर सामान्य रूप में नहीं रह गया था

धाय वितरण के सिद्धान्त, या मूल्य सिद्धान्त अथवा सामान्य मामू के सिद्धान्त को अध्ययन करने में इन लेखकों ने समय परिधिको कम कर दिया अर्थात् इन्होंने अल्पकाल में विकास कारक तत्वों को अध्ययन किया.

B. विकास मॉडल .

1. विकास पूँजी संचय पर निर्भर :

उनके अनुसार उत्पादन में श्रम व पूँजी का अधिक महत्व होता है. पूँजी-संचय पर ही श्रम-विभाजन व तकनीक निर्भर रहते हैं. तकनीक की उन्नति पर ही आर्थिक

विकास निर्भर रहता है अगर कभी पूँजी की कमी हो तो, नव-प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों के अनुसार व्याज की दर बढ़ जाएगी और बचतें बढ़ जाएँगी इस प्रकार से वे पूँजी व विनियोजन में असाम्य की स्थिति को दूर करने के कार्य में व्याज को साम्य लाने वाला महत्वपूर्ण तत्व मानते थे

ल्युस के अनुसार :

“In Neo-classical model capital can be created by withdrawing resources from consumption goods industries. In this model an increase by a corresponding fall in the output of consumer goods, since scarce resources can do one or the other.”

(अर्थात् नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अगर देश में पूँजी की कमी है तो उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में लगी पूँजी को कम कर के उत्पादन क्षेत्र की पूँजी बढ़ाई जा सकती है) .

2. जैसा कि हम मार्शल के मॉडल में पढ़ चुके हैं, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार (1) तकनीक की उन्नति (II) भ्रम विभाजन के विस्तार (III) लाभ की वृद्धि, (जिसके लिए भ्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि आवश्यक होती है) तथा (IV) उत्पादन के अर्थों को सीमान्त उत्पादकता के सिद्धान्त के अनुसार कार्य पर लगाकर, (V) राष्ट्रीय आय बढ़ाने से विकास होता है

इन अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या वृद्धि को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह भय से नहीं देखा

3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास आर्थिक विकास में सहायक :

नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भाँति यह विश्वास था कि अगर ‘तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त’ के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार किया गया तो इससे देश में आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से देश की वास्तविक आय बढ़ती है वे भी यह मानते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास से नए बाजार खुलते हैं. इन बाजारों के खुल जाने

से देश को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, तथा इसके कारण देश में वचत व पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है

परन्तु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भाँति वे भुक्त या स्वतन्त्र व्यापार के कट्टर समर्थक नहीं थे वे चाहते थे कि या तो देश को अपनी "भुगतान की शर्तों" को सुधारना चाहिए (अपनी वस्तुओं के दामों को बढ़ाना व आयात की वस्तुओं का भाव कम करना) या फिर आयात व निर्यात पर कर लगाकर लाभ प्राप्त करना चाहिए

वे सरकार को भी उचित अवस्थानों में प्रदान करने की सिफारिश करते थे लेकिन आम तौर पर वे स्वतन्त्र व्यापार को ही अच्छा मानते थे इन विचारों को हम दो नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित उद्धरणों से आँक सकते हैं

एजवर्थ का कथन था :

‘ संरक्षण की नीति से आर्थिक लाभ व विकास बढ़ सकता है बशर्ते कि राज्य इतना विवेकी हो कि वह उन उद्योगों का सही चयन कर सके जिनको संरक्षण देना चाहिए तथा फिर वह अपने इस चयन पर कायम रहे.’

निकलसन का कथन था

“स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, ईमानदारों की नीति की भाँति, सर्वोत्तम नीति होती है.”

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री देश के विकास में विदेशी पूँजी के योगदान को भी महत्वपूर्ण मानते थे उन्होंने उधार लेने व कर्ज लेने के दृष्टिकोण से विकास काल को पाँच कालों में विभाजित किया

- (1) प्रथम काल इस काल में एक देश विदेश से पूँजी का शुद्ध आयातकर्ता होता है इस काल में देश के वस्तु व सेवाओं के आयात, निर्यात से (हम व्याज व लाभांश देनदारियों को छोड़ भी दें) अधिक रहते हैं.
- (11) द्वितीय काल इस काल में फिर देश की उन्नति इतनी हो जाती है कि उसके वस्तु व सेवाओं के निर्यात, आयात से अधिक होते हैं पर अगर पूँजी पर दिए जाने वाले व्याज व लाभांश को मिला दें तो विदेशी व्यापार का आधिक्य नहीं रहता (There is surplus of current exports over imports).

(111) तृतीय काल जब एक देश में विकास और आगे बढ़ता है तो वह देश पूँजी निर्यात करने की स्थिति में आ जाता है इस स्थिति में आयात में निर्यात अधिक रहते हैं, चाहे हम व्याज व लाभांश को भी शामिल कर ले चालू व्यापार खाते में इस प्रकार से देश आधिक्य प्राप्त करता है
 निर्यात = अधिक होता है = आयात + लाभांश व व्याज भुगतान से परन्तु इस काल में यह देश जितना विदेशी पूँजी पर व्याज व लाभांश देता है उसकी तुलना में उसको अपनी पूँजी (जो विदेशों में भेजी है) पर प्राप्त होने वाला व्याज व लाभ अधिक होता है इस प्रकार से कुल मिलाकर देश शुद्ध कर्जदार ही रहता है

(1V) चतुर्थ काल जब देश और आगे विकास करता है और चौथी अवस्था में पहुँचता है तो विदेशों से निर्यात आय व व्याज व लाभांश प्राप्त देश से जाने वाले धन में (आयात मूल्य व व्याज व लाभांश देनदारियाँ) अधिक रहती हैं। इस अवस्था में देश Young creditor बन जाता है

(V) पञ्चम काल इस काल में देश के विकास की परिपक्व अवस्था आती है और जितना धन जाता है उसमें कहीं अधिक आता है अर्थात् निर्यात आयात में अधिक व व्याज व लाभांश प्राप्त इन्हीं देनदारियों से बहुत अधिक होनी है इस प्रकार से देश एक Mature creditor बन जाता है

4. विकास प्रक्रिया समन्वित व संचयी होती है

(a) संचयी — इस सम्बन्ध में हम मार्शल के विचार पढ़ चुके हैं लगभग समस्त नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा भी मार्शल जैसी थी,

एक अन्य नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जे एस्. निकलसन का कथन था

“इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जो भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आविष्कारों में आते हैं, उन्हें धीरे-धीरे ही कार्यान्वित किया जाता है। आविष्कारों में अविरल छलांग में अधिक धीमे-धीमे होने की प्रवृत्ति होती है。”¹

इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, विकास से समस्त वर्गों को लाभ होता है, मार्स को भी भ्रांति वे वर्ग-संघर्ष की सम्भावना को नहीं देखते थे, उनको बेरोजगारी का भय

नहीं था। उन्होंने माना था कि आर्थिक प्रणाली में पूर्ण रोजगार उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता होती है, केवल अल्पकाल में बेरोजगारी हो सकती है पर दीर्घ काल में ऐसा नहीं होगा।

सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो कि इन अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा में किया वह यह था कि ये अर्थशास्त्रज्ञ यह नहीं मानते थे कि मजदूरी बढ़ने से लाभ कम हो जायेगा। इसका कारण यह था कि “इंग्लैंड में 1850 के बाद जब फैक्ट्री एक्ट लागू किये गए जिसके अन्तर्गत मजदूरी बढ़ाई व कार्य के घटे घटाए गए” तो सब अर्थशास्त्रियों ने आश्चर्य में देखा कि इससे उत्पादकता व लाभ बढ़े, और तब से “अधिक मजदूरी, सस्ती मजदूरी” सिद्धान्त सर्वमान्य बन गया। इस प्रकार से उन्होंने अर्थशास्त्र से यह एक महान निराशावादी व त्रुटिपूर्ण विचारधारा को हटा दिया।

(b) समन्वित :—मार्शल के विचार हम पढ़ हो चुके हैं। उन्हीं की भाँति एलिन यंग (Allyn Young) ने भी विकास के संबंधी व समन्वित होने पर बल दिया। उन्होंने कहा .

“विकास, श्रम-विभाजन पर निर्भर करता है, श्रम-विभाजन बाजार के विस्तार पर निर्भर होता है, बाजार का विस्तार स्वयं श्रम विभाजन पर निर्भर होता है। श्रम-विभाजन में विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है और लागत कम होती है। इसमें माधनों का भौगोलिक व व्यवसायिक वितरण (Allocation) उत्पन्न होता है और मजदूरी बढ़ती है। इस प्रकार से एक क्षेत्र व उद्योग का विकास एक दूसरे के विकास का कारण व परिणाम हो जाते हैं”¹

C. नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सम्बन्धी विचारों की समीक्षा

गुण :

(i) वे आशावादी थे .

1 हम मार्शल के आशावादी विचारों को पढ़ हो चुके हैं। संक्षेप में यह विचार इस प्रकार थे .

(2) जनसंख्या की वृद्धि हमेशा उस गति से नहीं बढ़ती जिस दर से माध्यम ने बताया था

1. O. S. Shrivastava, "Economics of Wages, Productivity and Employment", Kailash Pustak Sadan, Gwalior, P. 74, 1968.

- (b) तननीकी उन्नति में न केवल उद्योगों में बल्कि कृषि में भी उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार उत्पादन हो सकता है।
- (c) मजदूरी बढ़ने से लाभ कम नहीं होने और लाभ को अधिक रखने के लिए मजदूरी कम रखना उचित व आवश्यक नहीं है।
- (d) उनका विश्वास था कि स्प्रिंजर (पर उन्नत) तकनीक होते हुए भी मजदूरी अधिक रह सकती है, वशर्ते कि पूँजी-निर्माण अधिक हो और पूँजी-निर्माण को बढ़ाने के लिए उनका विश्वास था कि यह कभी भी ब्याज की दर को बढ़ाकर किया जा सकता है।

2 उन्होंने सर्वप्रथम बाह्य मितव्ययिताओं के महत्व को समझाया तथा सतुलित विकास की विचारधारा की नींव रखी।

कमियाँ

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों में कुछ कमियाँ भी थी जो इस प्रकार से रही

- (a) उन्होंने यह गलत मान्यता मानी थी कि इनके पूर्ण प्रतियोगिता वाली अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी नहीं रहेगी—यह बात केन्स ने अपने मॉडल में गलत सिद्ध की।
- (b) इन अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता भी ठीक नहीं थी कि केवल ब्याज की दर में आवश्यक परिवर्तन कर के पूँजी की माँग व पूर्ति या विनियोजन व वृद्धि में साम्य लाया जा सकता है।
- (c) इनके विकास के सचयी व समन्वयी होने के विचार भी सत्य नहीं हैं। विकास में वर्ग संघर्ष की सम्भावना को न मानना “आँख बन्द करके” बात करना है।

अध्याय : 12

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विकास मॉडल

The Neo-classical Model of Economic Growth

(मुख्य रूप से J. E Meade का)

1. प्रस्तावना
2. श्री मीड की मान्यताएँ
3. मॉडल
 - (a) विकास का प्रथम सूत्र व समीकरण
 - (b) „ „ दूसरे रूप में समीकरण.
 - (c) „ „ तीसरे रूप में समीकरण.
 - (d) विकास दर में परिवर्तन.
 - (e) स्थायी विकास पथ
 - (f) स्थायी विकास पथ में अलग दरें.
 - (g) वास्तविक विकास की दर.
4. आलोचना

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विकास मॉडल

The-Neo classical Model of Economic Growth

1 प्रस्तावना

नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री वे हैं जिन्होंने Micro-Statics (सूक्ष्म स्थैतिक) दृष्टि-कोण अपनाया जेवन्स मेन्जर एजवर्थ, मार्शल कनार्क, वालरा, (Walras) परेडो, रिक्मरीड किशर, पीगू तथा विबर्नल उनमें मुख्य हैं। इसी काल के वे अर्थशास्त्री जिन्होंने Micro analysis किया अथवा जो Institutionalists थे, वे नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में नहीं लिए गए हैं।

इन नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जटिल सूक्ष्म-स्थैतिक मॉडल जो निगमन नीति पर आधारित था, प्रस्तुत किया (They produced a complex and deductive micro Static model). उन्होंने उन घटकों व तत्वों का जो विकास करते हैं बड़ा ही सुलभा हुआ विश्लेषण किया। उन्होंने अपने मॉडल में सामाजिक राजनैतिक तत्वों का भी समावेश किया

उन्होंने गणित की तकनीक का प्रयोग करके Theorems प्रस्तुत की। उन्होंने बहुत सी नई Theorems प्रस्तुत की जो नई मान्यताओं व विश्वासों पर आधारित थी उन्होंने तर्क तथा तर्ज का समन्वय किया। उनके मॉडल की मुख्य बातें यह थी

- (1) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार “अधिक उपयोगिता” को प्राप्त करना या उत्पन्न करना विकास है Achievement of greater utility without distortion (paretian optionality of Marginal utility = Marginal cost) be interpreted as growth.

(1) See ' The Neo-classical Theory of Economic Growth ' E. Meade.

- (2) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही विकास व कल्याण वृद्धि की निशानी है.
- (3) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर देश में उचित सामाजिक राजनैतिक वातावरण मौजूद हो तो विकास हो सकता है उनका विचार था कि पूर्ण-प्रतियोगिता से ही विकास सम्भव है. नव-प्रतिष्ठित मॉडल 'पूर्ण-प्रतियोगिता मॉडल' है उनका विश्वास था कि एकाधिकारी व्यवस्था से Paretian optionality की स्थिति (सीमान्त आयोगिता = सीमान्त लागत) को नहीं पहुँच सकते.
- (4) नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल में तकनीक में परिवर्तन, रुचि, फैशन व उपभोग परिवर्तन, राज्य व मस्यामों की नीति में परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा परन्तु जनसंख्या सम्बन्धी परिवर्तनों को ध्यान में रखा.
- (5) नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सन्तुलित विकास के पक्ष में थे उन्होंने बड़ी मात्रा में विनियोजन करने पर जोर दिया (They emphasized the importance of indivisibilities or lumpy growth, through external economy and public works)
- (6) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि जब तक जनसंख्या अनुकूलतम स्तर तक नहीं पहुँच जाती तब तक विकास होता रहेगा. परन्तु तकनीकी उन्नति से स्वयं अनुकूलतम जनसंख्या स्तर बढ़ जाएगा परन्तु अन्त में, उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण (जिसका मुख्य कारण साधनों का ह्रास होगा) विकास रुक जाएगा. जनसंख्या के सम्बन्ध में कुछ अर्थशास्त्री तो, माल्थस की भाँति, जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि के प्रति आशंकित थे जबकि कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि नागरिकरण से जन्म दर में कमी आ जाएगी. वे शिक्षा को जन्म दर घटाने व विकास वृद्धि में सहायता करने का मुख्य साधन मानते थे.

-
- (2) "The Neo-classical Contribution to the Theories of Economic Growth." John Buttrick from "Theories of Economic Growth" Ed by Bert E Hoselitt A Free Press, Paperback Macmillan Company, 1965

Prof. J E Meade's Model .

केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो जे ई. मीड ने नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल की संरचना की है। यह मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :

- (I) देश में अर्थ व्यवस्था स्वतन्त्र प्रतियोगिता वाले अर्थ-व्यवस्था है, देश को इस अर्थ-व्यवस्था में राज्य के नियन्त्रण नहीं है.
- (II) देश में उत्पत्ति का बढि नियम लागू नहीं हो रहा है.
- (III) देश में पूर्ण रोजगार का साम्य मौजूद है.
- (IV) देश में मूल्य स्थिर है.
- (V) मांडल में केवल दो प्रकार की वस्तुओं की कल्पना की गई है और यह माना है कि उत्पादन में पूर्ण प्रतिस्थापन संभव है.
- (VI) देश में धन की भिन्न-भिन्न इकाइयाँ या मशीनों की इकाइयों की उत्पादकता समता एक सी मानी गई है और उन्हें एक दूसरे का पूर्ण रूप से पूरक माना है

The Model

- (a) Growth means more national income and is expressed by production function. विकास का अर्थ अधिक राष्ट्रीय आय का सृजन है और इसे हम "उत्पादन सूत्र" से बताते हैं :

$$Y = F' (K \ L \ N \ T)$$

Y = राष्ट्रीय आय

F' = (Function of) या परिणाम स्वरूप

K = पूँजी (Capital)

L = श्रम (Labour)

N = प्राकृतिक साधन (Natural resources)

T = Time or Technical progress. समय या तकनीकी उन्नति.

- (b) देश के प्राकृतिक साधन तो स्थिर होते हैं, इसलिए जिसमें K , L , T में परिवर्तन को परिणामस्वरूप होता है, हम सम्बन्ध को हम इस प्रकार बता सकते हैं. :

$$\Delta Y = V \Delta K + W \Delta L + \Delta Y'$$

- (i) Δ डेल्टा का अर्थ परिवर्तन से है ΔY का अर्थ है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन.

(ii) V का अर्थ पूँजी की सीमान्त उत्पादकता से है

$V\Delta K$ का अर्थ हुआ पूँजी की सामान्त उत्पादकता \times पूँजी की मात्रा में परिवर्तन

(iii) W का अर्थ है श्रम की सीमान्त उत्पादकता $W\Delta L$ का अर्थ हुआ श्रम की मात्रा में परिवर्तन या वृद्धि \times श्रम की सीमान्त उत्पादकता.

(iv) $\Delta Y'$ का अर्थ तकनीकी उन्नति के कारण उत्पादन में परिवर्तन से है. इस प्रकार में किसी वर्ष में शुद्ध उत्पादन में परिवर्तन (ΔY), पूँजी के स्टॉक में वृद्धि \times पूँजी की सीमान्त उत्पादकता + श्रम की संख्या में वृद्धि \times श्रम की सीमान्त उत्पादकता + तकनीकी उन्नति के कारण उत्पादन में वृद्धि के बराबर होता है

(c) अब उत्पत्ति की वार्षिक अनुपातिक विकास दर को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{VK}{Y} \cdot \frac{\Delta K}{K} + \frac{WL}{Y} \cdot \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta Y'}{Y}$$

(i) $\frac{\Delta Y}{Y}$ का अर्थ उत्पादन में अनुपातिक विकास दर से है जिसे अब Y से लिखेंगे

(ii) $\frac{\Delta K}{K}$ " पूँजी " " " " " " " K "

(iii) $\frac{\Delta L}{L}$ " श्रम " " " " " " " L "

(iv) $\frac{\Delta Y'}{Y}$ " एक वर्ष में तकनीकी परिवर्तन से है " R "

(v) $\frac{VK}{Y}$ का अर्थ Y के अनुपात के रूप में पूँजी की सीमान्त उत्पत्ति से है.

और इसे हम U से प्रस्तुत करेंगे.

(vi) $\frac{WL}{Y}$ का अर्थ Y के अनुपात में श्रम की सीमान्त उत्पादकता में परिवर्तन से है. इसे हम Q लिखेंगे.

(d) Factors on which changes in growth rate depends
अगर देश में जनसंख्या स्थिर है ($L=0$) तो विकास की दर इस प्रकार होगी :

$$Y = VS + R$$

अर्थात् विकास की दर बचत, पूँजी की सीमान्त उत्पादकता तकनीकी उन्नति पर निर्भर होगी और साम्य की स्थिति में $Y = \text{बचत} \times \text{पूँजी की सीमान्त उत्पादकता} + \text{तकनीकी उन्नति}$ ।

अगर जनसंख्या के स्थिरता के साथ तकनीकी उन्नति भी स्थिर हो तो विकास की दर VS में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होगी।

(e) Conditions of Steady Economic Growth. स्थायी विकास की आवश्यक स्थितियाँ।

नव-प्रतिष्ठित मॉडल में स्थायी विकास का आशय है कि राष्ट्रीय आय (Y), बचत (S), जनसंख्या (L), तकनीकी उन्नति (R), मजदूरी (Q), लाभ (U), लगान (Z) में होने वाली परिवर्तन दरें स्थिर हैं।

हम यह देख चुके हैं कि $Y = LK + QL + R$ के बराबर है। इनमें से U, Q तथा L व R को हम स्थिर मान चुके हैं इस प्रकार से अगर K भी स्थिर दर से बढ़े तो स्थायी दर से विकास होगा।

The growth rate of income will be constant if the growth rate of capital stock (K) is equal to the growth rate of national income (Y).

(f) Critical Growth Rates

इसका अर्थ यह होता है कि वास्तविक विकास दर या तो 'स्थायी विकास दर' से अधिक है या वह इससे कम है इस स्थिति में Y और K बराबर नहीं होते J. E. Meade का विश्वास था कि Critical growth rates में यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है कि वे स्थायी विकास की दर के बराबर हो जाएँ। अब हम इस सूत्र को $Y = U \cdot K + QL + R$ के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय में विकास की दर तीन अन्य दरों का भार-युक्त जोड़ है। ये तीन दरें हैं

(i) पूँजी स्टॉक में वृद्धि (K) जिसमें सीमान्त उत्पादकता का भार हो (U)

+(ii) श्रम की वृद्धि दर (L) जिसमें सीमान्त उत्पादकता का भार हो (Q)

+(iii) तकनीक में विकास दर (R)

(g) Real growth rate depends on the growth of real Income.

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल में विकास वास्तविक पूंजी में (K) वृद्धि का परिणाम होती है। विकास धर्म की उत्पादकता (Q) पूंजी की उत्पादकता (U) तथा तकनीकी उन्नति में वृद्धि (R) भी प्रभाव डालते हैं यह विकास दर (L) या जनसंख्या में वृद्धि दर से घटती है

इस प्रकार से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि दर को हम निम्नलिखित सूत्र से प्रस्तुत कर सकते हैं :

$$Y-L=UK-(L-Q)L+R$$

उपरोक्त समीकरण में जनसंख्या के depressant effect या विकास को गिराने के प्रभाव को अध्ययन किया गया है इस सूत्र में—(L-Q)L से हम उत्पत्ति में ह्रास नियम की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं¹

अगर हम Critical growth rate के लिए (a) का प्रयोग करें तो समीकरण इस प्रकार होगा

$$A=UA+QL+R$$

$$\text{or } A=\frac{QL+R}{L-U}$$

(1) इसी समीकरण को हम निम्नरूप में भी लिख सकते हैं .

$$Y-L=VS-(L-Q)L+R$$

यहाँ UK के स्थान पर VS रख दिया गया है क्योंकि U का अर्थ $\frac{VK}{Y}$ तथा K का अर्थ $\frac{\Delta K}{K}$ होता है.

$UK = \frac{VK}{Y} \times \frac{\Delta K}{K}$. हम यह भी जानते हैं कि $\frac{\Delta K}{K}$ वास्तव में SY या आय का वह भाग जो बचत हुआ है, होता है

इसलिए $UK = \frac{VK}{Y} \times \frac{SY}{K}$ or Y से Y तथा K से K काटने के बाद $UK=VS$

अगर स्थायी विकास दर में कुछ परिवर्तन होता है तो स्वयं ही वह पुनः उस स्तर पर आ जाएगी पूँजी-स्टाक की विकास दर भी साम्य के स्तर पर आएगी, अर्थात् $\frac{QL+R}{L-U}$ स्तर पर आएगी

अगर, हम मानने हैं, $KOR \frac{SY}{K} > \frac{QL+R}{L-U}$ तो निम्न प्रतिक्रिया होगी इस स्थिति में आय, पूँजी स्टॉक वृद्धि से कम दर से बढ़ेगी इससे बचतें कम होंगी और इससे पूँजी स्टॉक में भी कमी आ जाएगी इसके परिणामस्वरूप $\frac{SY}{K}$ फिर Critical level तक आ जाएगी

अगर इनका उल्टा होता है अर्थात् अगर $\frac{SY}{K} < \frac{QL+R}{L-U}$, तो आय, पूँजी स्टॉक से अधिक दर से बढ़ेगी बचतें बढ़ जाएंगी इससे $\frac{SY}{K}$ भी Critical level $\frac{QL+R}{L-U}$ तक बढ़ जाएगी

इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर तथा पूँजी-स्टॉक में वृद्धि दर दोनों $\frac{QL+R}{L-U}$ के बराबर हो जाएंगे.

Critical Appraisal

श्री जॉन बट्रिक. (John Buttrick) ने नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल की बहुत प्रशंसात्मक समीक्षा की है जिसमें मुख्य ये हैं :

- (i) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उनके काल के बाद के अर्थशास्त्रियों को बहुत गुमराह किया. उन्होंने बहुधा अर्थहीन समीकरण प्रस्तुत किए.
- (ii) उन्होंने साम्य को लाने वाले मॉडलों की रचना की. ये मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित मॉडल थे जिनमें यह गलत मान्यता थी कि समस्त उत्पादन इकायाँ स्वतंत्र होती हैं
- (iii) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता भी पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है कि उत्पादन में केवल उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा और उत्पत्ति वृद्धि के नियम की मान्यता की संभावना को ही निकाल दिया

उन्होंने अपने मॉडल में “अनिश्चितता” को कोई स्थान नहीं दिया उनकी भविष्य वास्तविकता से सम्बन्धित नहीं थी उनके मॉडल में समस्त सहसम्बन्धों को सुनिश्चित मान लिया था और यह कोई अच्छी बात नहीं थी वरन् एक कमजोरी थी ¹

नव प्रतिष्ठित मॉडल व्यावहारिक नहीं थे वे तथ्यों व वास्तविकता से दूर थे उनको समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए समाजशास्त्र के विषयों के लिए, उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए गणितीय समीकरण जटिल थे उन्होंने ऐसे समीकरण प्रस्तुत किए जिन्हें बहुत से अर्थशास्त्री समझ ही नहीं पाए और इस कारण आलोचना ही नहीं कर पाए.

उन्होंने जिन मान्यताओं पर मॉडल बनाया वे न केवल सही ही नहीं थी वरन् वे बड़ी लम्बी-लम्बी मान्यताएँ थी.

उन्होंने अपने मॉडल में से बहुत से तत्वों को बाहर निकाल फेंका—जैसे उन्होंने राज्य की नीति को ध्यान में नहीं रखा उनका मॉडल तो Robinson Crusoe मॉडल रहा. और जब कभी उनके मॉडल के अनुसूप विकास नहीं होता था तो उसका दोष वे किसी और को मढ़ देते थे



-
1. A model in the social sciences in which no stochastics are present i.e. one in which relationships among variables are presumed to be exact and in which the variables themselves can be measured, is a model constructed for heuristic rather than practical purposes,

जोसेफ एलोइस शम्पीटर का विकास मॉडल

Joseph Alois Schumpeter on Development

A प्रस्तावना

B विकास मॉडल

- 1 'आर्थिक वृद्धि' व 'आर्थिक विकास' में अंतर
- 2 उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी तकनीक, संगठन व साहसी के कार्य स्वरूप होता है पर विकास 'साहसी' का कार्य है
- 3 विकास, स्वेच्छित विनियोजन व प्रोत्साहित विनियोजन के परिणाम स्वरूप होता है साहसियों के नवीन प्रवर्तन से ही विकास उत्पन्न होता है
- 4 पूंजी संचय व वृद्धि विकास कारक अधिक पूंजी अधिक विकास
- 5 पूंजी की उपलब्धि के लिए मुद्रा बाजार विकसित होना चाहिये
- 6 विकास 'साख' या बैंकों द्वारा उधार दी जाने वाली पूंजी पर ही निर्भर है
7. साहसी लाभ के प्रलोभन में नवीन प्रवर्तन करते हैं. लाभ की मात्रा व माशा ही विकास बढ़ाने वाली क्रियाओं को जन्म देती है लाभ का महत्व
- 8 आर्थिक विकास Swarm-like movements के (झुण्ड या समूह रूप में) या spurts में (बड़े प्रयत्न के कारण) होता है तथा नवीन प्रवर्तन इकट्ठे के इकट्ठे (विस्फोटक रूप में) होते हैं (innovation occurs in clusters तेजी मन्दी का चक्र ही विकास की ओर ल जाता है
- 9 पूंजीवादी विकास व्यवस्था का अविष्य

C शम्पीटर के मॉडल की समीक्षा

- 1 बन्जामिन हिगिन्स, 2 ऑस्कर लेन्ज, 3 रिचर्ड बी क्लोमेन्स तथा फ्रान्सिस एस डूडी, 4 मियर तथा वाल्डविन, 5 हेनरी सी वेलिच, 6 हेबरलर

जोसेफ एलोइस शम्पीटर का विकास मॉडल

Joseph Alois Schumpeter on Development.

A प्रस्तावना

शम्पीटर ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रान्त (जो आज कल चेकोस्लोवकिया में है) पैदा हुए थे. उन्होंने रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी कोलम्बिया व अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालयों में पढ़ाया उनके विचारों के सिद्धान्तों को हम तीन पुस्तकों से लेते हैं

- (1) The Theory of Economic Development (1912)
- (11) Business Cycles (2 volumes, 1939)
- (111) Capitalism, Socialism and Democracy

बेन्जामिन हिगिन्स के अनुसार शम्पीटर बीसवीं सदी में विकास मॉडल देने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे

B विकास मॉडल

- (1) Meaning of 'Economic growth' and 'Economic development' शम्पीटर के अनुसार 'आर्थिक वृद्धि' व 'आर्थिक विकास' में अन्तर

शम्पीटर के अनुसार दो प्रकार की अर्थ व्यवस्थाएँ होती हैं एक स्थिर अर्थव्यवस्था (Static economy or circular flow) जिसमें हर आर्थिक अंग स्थिर रहता है, अर्थात् जनसंख्या में जितने व्यक्ति मरते हैं वस उतने ही पैदा होते हैं, या माँग, पूर्ति, रोजगार, विनियोजन, उत्पादन के अंगों का पारितोषिक आदि स्थिर रहते हैं ऐसी अर्थ-व्यवस्था हमेशा 'साम्य' की स्थिति में रहती है हर बेचने वाला अपना खरीदार पा लेता है, और एक वर्ष की आर्थिक गति-विधियाँ दूसरे वर्ष में भी होती हैं

"स्थिर व्यवस्था को (in circular flow) हम जीवात्माओं की

शरीर रचना से तुलना कर सकते हैं जिनमें खून निरन्तर एक ही रास्ते से एक ही स्फ़टार से बहता रहता है ”

ऐसी अवस्था में जो भी परिवर्तन होने हैं वे धीरे-धीरे होते हैं और इनमें विकास नहीं उत्पन्न होता है यह ‘क्रमिक उत्पत्ति’ evolutionary change विकास नहीं है केवल ‘क्रान्तिकारी परिवर्तनो’ से ही विकास का जन्म होता है उनके अनुसार :

“क्रमिक परिवर्तनो से, कालान्तर में, यथाकाल व्यवस्था से, एक छोटी फुटकर विक्री की दुकान एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में परिणत हो सकती हैं, पर यह तो स्थिर अर्थ-व्यवस्था की ही बात रहेगी केवल क्रान्तिकारी (revolutionary) तथा अविरल (dis-continuous) परिवर्तनो से ही विकास होता है और यही हमारे अध्ययन का विषय है ”¹

Schumpeter ने growth व development के बीच अन्तर निकाला उनके अनुसार growth में हमारा अभिप्राय देश की अर्थ-व्यवस्था में सख्यात्मक वृद्धि से है, जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक मॉन व उत्पादन का बढ़ जाना Development का अर्थ देश की अर्थ-व्यवस्था में गुणात्मक उत्पत्ति से है उन्होंने लिखा

‘By development, we shall understand only such changes in economic life as are not forced upon it from without but arise by its own initiative, from within.’²

(1) Theory of Economic Development : by Joseph Schumpeter. translated by Dr. Revers Opie from German : Oxford University Press, 1961 New York p. p 64, 7, 8, 63 & 62.

(2) “Nor will the mere growth of the economy, as shown by the growth of population and wealth be designated as a process of development. For it calls forth no qualitatively new phenomenon but only possesses of adaptation of the same kind as the changes in the natural data . It is . occurrence of the ‘revolutionary’ changes that is our problem. p. 62-63-64

देश में जब Data में परिवर्तन होते हैं अर्थात् जनसंख्या बढ़ जाती है या धीरे धीरे माँग बढ़ती है तो अर्थ-व्यवस्था भी धीरे-धीरे बढ़ती है इससे अर्थशास्त्रियों को कोई मतलब नहीं होता गुणात्मक परिवर्तनों से ही हमको मतलब होता है और वही विकास है।

ऐसी ही स्थिर परिस्थितियों से क्रान्तिकारी परिवर्तन आता है और अर्थशास्त्रियों का इसी प्रकार के विकास से सम्बन्ध होता है

2. उत्पादन भूमि, श्रम, पूँजी, तकनीक, संगठन व साहसी के कार्य स्वरूप होता है, पर 'विकास' साहसी का कार्य है.¹

शम्पीटर से पहले जे. बी. से, मटाजा, वालरा, व मार्शल ने साहसी के महत्व को बताया पर उतना नहीं जितना कि शम्पीटर ने स्थिर अर्थ-व्यवस्था में साहसी अपनी पूँजी प्रदान करने वाला, व्यवस्थापक, तकनीकी विशेषज्ञ, व खरीदने बेचने वाला होता है उस व्यवस्था में उसे सब चीजें निश्चित मिलती हैं पर गतिशील व्यवस्था में उसका कार्य महत्वपूर्ण होता है उसे New combinations of production (उत्पादन के नए समर्ग) जुटाने पड़ते हैं।

“स्थिर अर्थ-व्यवस्था में साहसी बहाव के साथ तैरता है, गतिशील व्यवस्था में उसे बहाव के विपरीत तैरना पड़ता है”

गतिशील अर्थ-व्यवस्था में साहसी को पुरानी व्यवस्था तोड़ कर नई व्यवस्था पैदा करना पड़ता है साहसी की स्थिति अर्थव्यवस्था में वही होती है जो कि युद्ध में युद्ध के 'कमान्डर' की होती है। ये साहसी हमेशा धनी वर्ग से ही नहीं आते, यह गरीब वर्ग से भी आते हैं

“यह साहसी सबसे विवेकपूर्ण, आत्मनिर्भर होता है। उसमें जूझने की प्रवृत्ति होती है, वह जीतने का संकल्प रखता है, और उसमें अपने आप को दूसरों से उत्तम साबित करने की इच्छा रहती है वह केवल लाभ के लिए ही कार्य नहीं करता बल्कि “सफलता” प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होता है।”

3. विकास, स्वेच्छित (Autonomous) विनियोजन व प्रोत्साहित (Induced) विनियोजन के परिणामस्वरूप होता है। साहसियों के नवीन प्रवर्तन (Innovations) से ही विकास उत्पन्न होता है.²

शम्पीटर के अनुसार साहसियों के नवीन प्रवर्तन कार्यस्वरूप जो स्वेच्छित

(1) साहसी के सम्बन्ध में देखिए उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 79 से 94 के बीच।

(2) Innovations के लिए देखिए उपरोक्त पुस्तक के पेज 66 व 156।

विनियोजन होता है, उससे तकनीकी उन्नति होती है और साधनों का और अधिक प्रचड़ा प्रयोग होता है। शम्पीटर के अनुसार यह नवीन प्रवर्तन पाँच प्रकार के हो सकते हैं

- (I) बाजार में नई वस्तु लाना,
- (II) नई उत्पादन पद्धति को जन्म देना जिससे अधिक व अच्छा सामान कम लागत में बने,
- (III) नए बाजार की खोज करना या उत्पन्न करना,
- (IV) बच्चे माल का नया स्रोत खोजना,
- (V) व्यवस्था का इस प्रकार से संगठन करना कि साहसी अपने क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर सके

इन नवीन प्रवर्तनों के कारण जो विनियोजन होता है वह Autonomous विनियोजन हुआ। अन्य उत्पादनकर्ताओं को भी इनके अनुसार अपने पुराने उत्पादन तरीकों को बदलना पड़ना है और उन्हें भी इन नवीनताओं को प्रपनाने के लिए जो विनियोजन करना पड़ना है वह induced investment कहलाता है और इन दोनों के परिणामस्वरूप विकास होता है।

4 पूँजी संचय व वृद्धि विकास कारक . अधिक पूँजी अधिक विकास¹

विकास, शम्पीटर के अनुसार, तब ही सम्भव होता है जब कि देश में पूँजी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है और इन्हीं से साहसी नवीन प्रवर्तनों को बाजार में लाता है। पूँजी वह उत्तोलन बण्ड है जिससे साहसी अपनी आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण पाता है (Capital is nothing but the lever by which entrepreneur subjects to his control the concrete goods which he needs) शम्पीटर के अनुसार "पूँजी के बगैर विकास नहीं होता, विकास के बगैर पूँजी निर्माण नहीं होना "

5. पूँजी की उपनधि के लिए मुद्रा बाजार विकसित होना चाहिए.²

शम्पीटर मुद्रा बाजार को पूँजीवाद का "मुख्यालय" (Headquarter of Capitalist System) कहते हैं इसी बाजार से साहसी पूँजी प्राप्त करते हैं। विकास इसी पूँजी बाजार या मुद्रा बाजार पर निर्भर करता है और विकास के साथ साथ इस बाजार का भी विकास होता है, और बाद में तो यह बाजार समस्त आय का स्रोत बन जाता है

(1) पूँजी सम्बन्धी विचारों को शम्पीटर की पुस्तक के पृष्ठ 116-122

(2) मुद्रा बाजार पर शम्पीटर की पुस्तक के पृष्ठ 124-127.

6 विकास 'साख' या बैंकों द्वारा उधार दी जाने वाली पूँजी पर ही निर्भर है.¹ जहाँ कि परंपरागत अर्थशास्त्री यह मानते थे कि पूँजीनिर्माण देश में बचतों की मात्रा पर आधारित है, शम्पीटर का कथन था कि यह पूँजी बैंको से उधार मिल सकती है बचत भी महत्वपूर्ण है, पर 'साख' उससे अधिक महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा :

“हम यह नहीं कहते कि मिक्के, नोट या बैंक जमा से ही विकास प्राप्त सकता है, और जानते हैं कि थम, कच्चे माल व मशीनों से ही उत्पादन होता है, पर यह चीजे तो साख से प्राप्त होती हैं.”

शम्पीटर के मॉडल में बैंकर ही सबसे बड़ा पूँजीपति है. बैंकर ही धन प्रदान करता है जिससे नवीन प्रवर्तन का लाना सम्भव होता है. (A banker is essentially a phenomenon of development.....He is the ephor of the exchange economy.) साख से देश में नई पूँजी व नई क्रयशक्ति का उदय होता है. यह गतिशील अर्थ-व्यवस्था को गतिशील रखने का प्रमुख साधन है.

शम्पीटर का कथन है कि साहसी वास्तव में जोखिम नहीं उठाता. जोखिम उठाने वाला तो बैंकर होता है.

“अगर एक नवीन उद्यम असफल होता है तो बैंकर, जिसने धन उधार दिया था, सकटग्रस्त होता है, साहसी की तो इज्जत सकट में आती है”

शम्पीटर का साहसी 'ऋणों' को पीठ पर लाद कर सफलता की ओर बढ़ता है' पूँजीवादी व्यवस्था में विकास इसी साख पर निर्भर है. धीरे-धीरे 'साख' समस्त विनियोजनों के लिए पूँजी का साधन हो जाती है, और फिर वे लोग भी, जो हमेशा यह अभिमान करते थे कि वे उधार नहीं लेते, साख लेकर विकास कार्यों में लग जाते हैं

7. साहसी लाभ के प्रलोभन में नवीन प्रवर्तन करते हैं. लाभ की मात्रा व आशा ही विकास बढ़ाने वाली क्रियाओं को जन्म देती है.²

लाभ का महत्व :

शम्पीटर के अनुसार स्थिर अर्थ-व्यवस्था में लाभ नहीं होते. इस व्यवस्था में तो

(1) साख पर देखिए पृष्ठ 71, 73, 101 107 तथा 137

(2) लाभ के सम्बन्ध में देखिए पृष्ठ 129, 153-154.

साहसी केवल "व्यवस्था का वेतन" पाते हैं, और ये सुनिश्चित होते हैं। गतिशील अर्थ-व्यवस्था में ही "प्रलोभन दायक लाभ विकास कार्यों के प्रेरणा स्रोत होने हैं शम्पीटर ने कहा

"विकास के बगैर लाभ नहीं होता, लाभ के बगैर विकास नहीं होता। पूँजीवादी व्यवस्था में लाभ के बगैर धन व सम्पत्ति व पूँजी संचय सम्भव नहीं है"

गतिशील व्यवस्था में कुछ साहसी कम व कुछ अधिक लाभ कमाते हैं, कुछ हानि भी उठा सकते हैं पर Circular flow (स्थिर व्यवस्था) में अगर "व्यवस्था का वेतन" बढ़ता है तो सबको प्राप्त होता है यह 'वेतन' कभी शून्य नहीं होता पर गतिशील व्यवस्था में लाभ शून्य हो सकता है जब कोई वस्तु नई होती है तो खूब लाभ होता है बाद में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है व नवीनता समाप्त हो जाती है और लाभ घट जाने हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, जब फिर कोई नवीनता उत्पन्न की जाती है तो लाभ फिर उदय हो जाते हैं शम्पीटर के अनुसार

'Profit is at the same time the child and the victim of development'

व्याज को शम्पीटर "Brake on development" विकास में रुकावट डालने वाला तत्व मानते हैं वे उसे Tax on profit (लाभ पर कर) मानते हैं पर वे व्याज को Condemn या निन्दा नहीं करते क्योंकि पूँजीपति के कार्य को वे महत्वपूर्ण मानते हैं।

8. आर्थिक विकास Swarm-like movements में (झुण्ड या समूह रूप में) या Spurts में (बड़े प्रयत्न के कारण) होता है तथा नवीन प्रवर्तन इकट्ठे के इकट्ठे (पिएडीभूत रूप) में होते हैं। (Innovation occurs in clusters) तेजी सम्बन्धों का चक्र ही विकास की ओर ले जाता है ¹

पिछले मॉडलों में हमने देखा था कि परम्परागत अर्थशास्त्री व नव-परम्परागत अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि विकास धीरे-धीरे वगैर किसी वर्ग को हानि पहुँचाए, सुनिश्चित रूप से होगा रहेगा पर शम्पीटर विकास को समझाने से एकदम बड़े प्रयत्न के कारण समूह रूप में एकदम बढ़ने वाली प्रक्रिया मानते

(1) व्याज के सम्बन्ध में देखिए पृष्ठ 158, 174, 175, 210, 211.

थे कुछ समय तक अर्थ-व्यवस्था स्थिर सी रहती है फिर एक-एक नवीन प्रवर्तन क्रियायें शुरू हो जाती हैं और हर इस प्रकार के 'बड़े प्रयत्न' के कारण अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ जाती है समस्त नवीन प्रवर्तन अविरल (discontinuous) रूप से होते हैं

नवीन प्रवर्तन और तेजी वाला •

एक बार जब नवीन प्रवर्तनों में स्वेच्छित विनियोजन होता है तो उसके नकल के रूप में अन्य विनियोजन भी प्रोत्साहित होने हैं सट्टे की क्रियायें भी बढ़ जाती हैं, बैंको के द्वारा साख निर्माण बढ़ जाता है इस काल में उपभोग वस्तुओं के उद्योगों के मुकाबले में पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अधिक विकास होता है नए उद्योग स्थापित होते हैं, नई वस्तुएँ बाजार में आती हैं और उत्पादन के नए तरीके निकलते हैं, पुराने उद्योग या तो दब हो जाते हैं या निम्न दर्जा स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रकार से जो औद्योगिक संस्थान हानि उठाते हैं उन्हें शम्पीटर "मृजनात्मक बरबादी" कहते हैं तेजी व विकास के काल में प्रभावशील माँग, नई वस्तुओं के आने से, बढ़ जाती है और इसके कारण लाभ बढ़ते हैं

मन्दी :

जब नए विनियोजन, जो कि नवीन प्रवर्तनों के परिणामस्वरूप हुए थे, समाप्त हो जाते हैं, तब फिर मन्दी आती है सट्टे के कार्य भी शिथिल हो जाते हैं, दूसरी ओर बाजार में नई वस्तुओं की माह सी आ जाती है, जिसके कारण मूल्य गिरने लगते हैं,

मूल्य इसलिए भी गिरने लगते हैं कि साहसी लोग अपने कार्य समाप्त हो जाने पर बैंको को ऋण वापिस करने लगते हैं, जिससे बाजार में मुद्रा का चलन कम हो जाता है,

मन्दी पहले पुराने संस्थान हानि उठाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी वस्तुओं की माँग पहले गिरती है

धीरे-धीरे मन्दी पूरी अर्थ-व्यवस्था में जा जाती है

पुनः विकास •

एक बार अर्थ-व्यवस्था में से कमजोर व्यापारिक संस्थान व साहसी निकल जाते हैं तो पुन नए साहसी उत्पन्न होने हैं या पुराने साहसी फिर से नवीन प्रवर्तन कार्यों में जुट जाते हैं

हर तेजी व मन्दी के चक्र से अर्थ व्यवस्था ऊँचे स्तर पर पहुँच जाती

उपरोक्त विवेचना के लिए देखिए पृष्ठ 62-65 तथा 232-33.

है. राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है और जन साधारण व अधिक वर्ग सस्ती चीजों से लाभान्वित होते हैं

विकास अविरल रूप से घिरावू भूत रूप में क्यों होता है :

शम्पीटर ने अपने इस विचार के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए :

- (1) पूंजीपति अपनी पूंजी बहुतना एकदम व एक साथ विनियोजित करते हैं
- (2) आर्थिक विकास एक पेड़ के विकास की भाँति धीरे-धीरे नहीं होता विकास की राह में हमेशा रुकावटें आती हैं व सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था ही कभी-कभी नीचे आ जाती है इसमें जब वह इन रुकावटों को दूर करती है तो फिर एकदम आगे बढ़ जाती है
- (3) मन्दी भी धीरे-धीरे नहीं आती मन्दी का कोई एक कारण नहीं है. हर मन्दी के अलग-अलग कारण हो सकते हैं. हर मन्दी के अलग-अलग परिणाम भी होते हैं. हर मन्दी में अलग-अलग वर्गों के लोग प्रभावित होते हैं. Sometimes there may be crisis without panic and sometimes there may be panic without crisis

इस प्रकार से जब विकास की तेजी आती है तो माहंगी कच्चे माल व पूंजीगत सामानों के लिए एकाएक व एकदम अधिदाधिक माना में 'आर्डर' देते हैं फिर उत्पादनकर्ता एकाएक व एकदम अपने उत्पादन कार्यों का विस्तार करते हैं, दूसरी ओर जब मजदूरों व कच्चे माल के बेचने वालों के पास नम-शक्ति बढ़ती है तब वे भी फुटकर व्यापारियों की विप्री दड़ते हैं. सब वर्गों को, युद्ध व मुद्रा स्कीति काल की भाँति लाभ प्राप्त होते हैं The symptoms of prosperity themselves finally become a factors of prosperity

और जब मन्दी आती है तो एक के बाद एक साहसी को हानि होने लगती है. समृद्धि ही मन्दी का कारण बन जाती है क्योंकि सामान की बहुतायत हो जाती है (The only cause of depression becomes this prosperity itself)

9 पूंजीवादी विकास व्यवस्था का भविष्य¹ :

शम्पीटर मार्क्स के विरुद्ध मे अधिक प्रभावित हुए थे, पर वे साम्यवाद को

-
- (1) तेजी व मन्दी के सम्बन्ध में शम्पीटर की उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 214 228 देखिए तथा पृष्ठ 255 तक.

नापसन्द करते थे “वे किस राजनैतिक व्यवस्था को पसन्द करते थे यह हमेशा अनिश्चित सा रहा”。 एक बार तो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के अन्तर्गत साम्यवाद के खिलाफ “सहकारी राज्य” की स्थापना की कोशिश करने की सिफारिश की कभी वे समाजवाद के आने की भविष्यवाणी करने थे

मार्क्स की भाँति शम्पीटर भी पूँजीवाद के उस योगदान की जो उसने विकास बढ़ाने में दिया, बहुत ही प्रशंसा करते हैं पूँजीवाद ने व्यक्तियों के सोचने विचारने व कार्य करने की पद्धति को वैज्ञानिक बनाया सामान्यवादी युग की मान्यताओं व उत्पादन की रीतियों को समाप्त किया

उन्होंने कहा

‘Capitalism exalted the monetary unit a unit of account and adopted a cost-profit calculus which facilitated the logic of business enterprise and development’

पूँजीवाद के पहले के युग में कोई भी व्यक्ति शासक वर्ग से अधिक धनी नहीं हो सकता था. पूँजीवाद में यह सम्भव ही नहीं बनूँ यथार्थ है । पूँजीवाद ने नई कला व जीवन यापन के उच्च तरीकों को जन्म दिया

“It chased away mystic and romantic ideas. Capitalist civilization is rationalistic and anti-heroic.”

पूँजीवाद ने नई उत्पादन रीतियाँ दी नई वस्तुएँ दी, नये सुख दिए, नई तकनीक दी, नया सामाजिक व औद्योगिक संगठन दिया तथा संचय में नई सम्यता दी इतना सब कहने के पश्चात् शम्पीटर कहते हैं कि पूँजीवाद में दोष भी इतने हैं कि विकास की यह पद्धति ही समाप्त हो जाती है.

उन्होंने कहा .

“पूँजीवाद के पक्ष में इतना कहने का आशय यह नहीं है कि मैं यह कहना चाहता हूँ पूँजीवादी पद्धति को रहने दिया जाए. यह पद्धति मानव जाति के कंधों से गरीबी का भार नहीं उठा सकती”

शम्पीटर भी, मार्क्स की भाँति कहते थे कि पूँजीवाद का अन्त सुनिश्चित है. बेरोजगारी, वस्तुओं की अधिकता व माँग की कमी, गिरते हुए लाभ आदि पूँजीवाद को समाप्त कर देंगे उनके इस सम्वन्ध में तर्क इस प्रकार थे .

- (1) पूँजीवाद में प्रतियोगिता 'पूर्ण' नहीं होती वरन् एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है। इसके राजनैतिक परिणाम गम्भीर होने हैं। बड़े उद्योगपति व व्यापारी जब छोटे उद्योगपति व व्यापारियों को प्रतियोगिता में नहीं रहने देते तो व्यक्ति राजनैतिक चुनावों में ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जो इनकी रक्षा करते हैं व बड़े पूँजीपतियों के समर्थन में होते हैं।
- (2) पूँजीवादी पद्धति में विनियोजक पूँजी शेयरों में लगाने व शेयरों के खरीदने व बेचने में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। अगर पूँजीपति कैपिटल के दीवारों व मशीनों में विनियोजन करने में अधिक दिलचस्पी लेते तो वे वास्तविक विनियोजन करते (Such investment takes life out of property and is responsible for bringing down fall of capitalism) इस कारण भी पूँजीवाद का पतन होता है।
- (3) इस प्रकार की पूँजीवादी व्यवस्था में 'साहसी' केवल 'व्यवस्थापक' या मैनेजर बनकर रह जाते हैं, और ये व्यक्ति गतिशील व्यवस्था को गतिहीन कर देते हैं, और जैसे शान्तिनाल में जेनेरल (General) का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसी तरह इस प्रकार की स्थिर व्यवस्था में साहसी महत्वहीन हो जाते हैं।
- (4) बेरोजगार व्यक्ति तथा देश के बुद्धिजीवी धीरे-धीरे पूँजीवादी व्यवस्था के वैरो हो जाते हैं। पूँजीवाद स्वीकृति विना रक्षाहीन रह जाता है। पूँजीपति अपने कुछ आलोचकों को धन में खरीद कर अपनी ओर कर सकते हैं पर वे सब आलोचकों को नहीं खरीद सकते हैं। बेरोजगार व्यक्तियों की वर्तमान कठिनाइयों से देश की राजनैतिक स्थिति शक्ति प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा को पूरी करने के लिये इनको उकसाते हैं और इसमें पूँजीवाद अर्थव्यवस्था के पैर उखड़ने लगते हैं। आए दिन झगड़े, हड़तालें, ताना बन्दियाँ व संघर्ष उत्पन्न होने हैं।
- (5) धीरे-धीरे जनता समाजवादी विचारधारा के व्यक्तियों को चुनकर सरकार बनाने का मौका देती है। वे समाजवादी विचारधारा के प्रशासकों को कार्य चलाने के लिए नियुक्त करते हैं।

- (6) ऐसे वातावरण में पूँजीपति वचन करने के लिए हतोत्साहित होते हैं।
 उन्हें अपने परिवार के लिए सम्पत्ति बनाने में डर लगता है (A business man's time horizon shrinks to his life expectation) वह अपने ही जीवन-काल तक ही अपनी भविष्य की योजना सीमित रखने लगता है।

इस कारण शम्पीटर कहते हैं

"Bourgeois order is now meek It is fighting defensive battle and now concedes demands of even small groups Its own thinking has now become subservient to the radical thinking "

वे इस कारण समाजवाद का आना निश्चित मानते हैं पर कहते हैं

"अगर एक डाक्टर यह कहता है कि उसका मरीज मर जायेगा, तो इसका अर्थ नहीं है कि वह यह चाहता भी है। इसी भाँति हम समाज-वाद से नफरत कर सकते हैं पर उसके आ जाने को रोक नहीं सकते हैं."

C : शम्पीटर के मॉडल की समीक्षा

1. बेन्जामिन हिगिन्स :

बेन्जामिन हिगिन्स शम्पीटर के मॉडल की बहुत सराहना करते हैं उनका कथन है कि शम्पीटर ने जो नवीन प्रवर्तनों का विकास शुरू करने में जो महत्व बताया है उनका विश्लेषण अद्वितीय है¹ वे भी शम्पीटर से सहमत हैं कि विकास अविरल रूप से ही होता है वे तो इस मॉडल को विकासशील देशों के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं इन देशों के स्वयं स्फूर्ति अवस्था में पहुँचने में साहसियों की कमी भी प्रमुख बाधक होती है हिगिन्स का कथन है, 'Tautological though the theory may be, there can be little doubt of its relevance (to under-developed countries)'

2. ऑस्कर लेन्ज (Oscar Lange)

शम्पीटर के इस विचार से कि विकास अविरल रूप से होता है, पूर्णतया

उपरोक्त पुस्तक के यह पृष्ठ मुख्य रूप से देखिए 61, 145-156, 161-62
 अध्याय X-XIV

(1) Benjamin Higgins : op cit p 135-36

(2) Oscar Lange : Review of Joseph Schumpeter's 'Business Cycle' in Review of Economics & Statistics No. 1941. p. 192.

सहमत है स्थिर अर्थ-व्यवस्था की स्थिति में जब अर्थ-व्यवस्था पहुँच जाते हैं तब ही साहसी नवीन प्रवर्तन करते- इसमें कोई सदेह नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में नवीन प्रवर्तन करने में कम से कम जोखिम होता है-

3. रिचर्ड वी. क्लोमेन्स तथा फ्रान्सिस एस. डूडी. (Richard V. Clemence and Francis S. Doody)

इनका भी विचार है कि विद्वान पिगडीभूत रूप में होता है। जब साम्य की स्थिति होती है तब ही नवीन प्रवर्तन होते हैं क्योंकि इसकी प्रेरणा इसी समय ही होती है तथा जोखिम भी कम से कम होता है।

4. मियर तथा बाल्डविन (Meier & Baldwin)

शम्पीटर के मॉडल की आलोचना मुख्यतया रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा उन्हीं कारणों से की जाती है जिन कारणों से मार्क्स के मॉडल की आलोचना होती है, अर्थात् इन अर्थशास्त्रियों को शम्पीटर द्वारा पूँजीवाद के भविष्य को अन्धकारमय बताया जाना अच्छा नहीं लगता मियर व बाल्डविन ने शम्पीटर के मॉडल की निम्नलिखित मुख्य आलोचनाएँ की

- (1) आज के युग में साहसी व नव-प्रवर्तक एक प्रादर्शभूत व्यक्ति नहीं रह गया है, उसके कार्य आज नित्यकर्म में आ गए हैं।
- (2) आज नव प्रवर्तन के अर्थ-व्यवस्था में आघातात्मक प्रभाव नहीं हो पाते आज के बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थान नव-प्रवर्तनों के अनुसार अपनी उत्पादन पद्धति को ठीक करने व यथाकाल व्यवस्था करने की क्षमता रखते हैं और नव प्रवर्तन मन्दी व तेजी नहीं ला पाते
- (3) किसी भी देश में मन्दी व तेजी के नव प्रवर्तन ही कारण नहीं होने। बहुत से वास्तविक (real), वित्तीय, मनोवैज्ञानिक तथा प्राकृतिक कारणों में भी मन्दी व तेजी का चक्र आता है
- (4) शम्पीटर ने अपने विकास मॉडल में "वचनो" को पूँजी-निर्माण का मुख्य स्रोत नहीं माना। उन्होंने 'साक्ष' के योगदान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया

मियर व बाल्डविन के अनुसार

"शम्पीटर ने जो विकास का चूल्हा सामाजिक आर्थिक विश्लेषण किया उसको सर्वत्र सराहा जाता है, परन्तु बहुत कम व्यक्ति उनके निष्कर्षों

(3) Clemence and Doody. The Schumpeterian System, Cambridge, Mass 1950. p 54,

को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. उनके तर्क उत्तेजक हैं, उनका विश्लेषण उद्दीपक है, पर वे पूर्णतया विश्वसनीय नहीं हैं. उनका विस्तोषण एकतर्फी है व उन्होंने कई बातों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया.

5. हेनरी सी. वेलिच (Henry C. Wallich)

इन्होंने अपने एक लेख (Some Notes Towards a Theory of Derived Development) में शम्पीटर के मॉडल का अध्ययन किया

उन्होंने लिखा कि शम्पीटर का सिद्धान्त “आन्तरिक एकता से परिपूर्ण है” (It is full of internal unity)” पर विकासशील देशों के लिए उतना प्रामाणिक महत्व का नहीं है इसके उन्होंने कई कारण दिए जिनको निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं

- (1) कम विकसित देशों में साहसियों की कमी नहीं रही है उन्हें तो अनुकूल आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक वातावरण नहीं मिलता. आज की परिस्थितियों में इन देशों में केवल राज्य ही विकास शुरू कर सकता है साहसी यह नहीं कर सकते
- (2) विकास जब एक अवस्था को पहुँच जाएगा तब ही साहसियों का महत्व होगा
- (3) इन देशों में बहुत से साहसी स्वार्थी तथा (estateminded) सम्पत्ति में विनियोजन करने वाले होते हैं. वे अपने लिए अवसर पैदा नहीं कर पाते और उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाते.
- (4) इन देशों में विकास ‘स्वयं स्फूर्ति’ की अवस्था में तब ही पहुँच सकता है जबकि देश में Social and Economic overheads (अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग तथा यातायात, संचार आदि) में पर्याप्त विनियोजन हो यह कार्य साहसियों के बस का नहीं है.
- (5) कम विकसित देशों में ‘नव प्रवर्तन क्रियाओं’ से अधिक महत्वपूर्ण विश्व के अन्य देशों में हुए नव प्रवर्तनों का देश में नकल कर के, या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने देश में अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है
- (6) शम्पीटर के मॉडल में शम्पीटर ने निर्वाधवादी नीति को अपनाने की

सलाह दी आज के युग में कम विकसित देशों में निर्वाध नीति के गम्भीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं

परन्तु हमका अर्थ यह नहीं कि 'शम्पीटर के साहसी' का इन देशों में कोई महत्व ही नहीं है स्वयं हेनरी सी बलिच ने कहा

“The de emphasis of the role of entrepreneurs in the theory of derived development does not imply that the entrepreneur does not fulfil a vital function”

6. हेबरलर (Haberler) :

शम्पीटर किसी के शिष्य नहीं थे और न उन्होंने कोई शिष्य छोड़ा. उनके विकास मॉडल में विश्लेषण था, पर कोई कार्यक्रम नहीं था, जैसा कि केन्स के मॉडल में था. बे वालरा (Walras) व मार्श से ही अधिक प्रभावित थे

“शम्पीटर ने हमको बहुत सी मौलिक तर्क व तथ्य दिए पर उनकी जटिलता व विभिन्नता के कारण उन में सार्वभौमिकता नहीं है”

See also

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Meier & Baldwin | : op cit. |
| 2. Benjamin Higgins | : op. cit. |
| 3. Spiegel | op. cit. |
| 4. Nag | : op cit. |

अध्याय : 14

केन्स का मॉडल

Keyne's Model

1. प्रस्तावना :

केन्स के विकास मॉडल की विवेचना.

A उपयोग नहीं गिरना चाहिये.

1. वचन क्यों अधिक व उपभोग क्यों कम होता है.

2. परिणाम.

3. उपभोग बढ़ाने के उपाय.

4. गुणक प्रभाव.

B I. निजी विनियोजन बढ़ाना चाहिए. इसके लिये व्याज की दर कम और पूँजी की कुशलता में वृद्धि होनी चाहिये.

B II सार्वजनिक विनियोजन से 'मन्दी की खाई' को भरना चाहिए.

2. केन्स के 'उत्पादन के अंगों को पुरस्कार' के सम्बन्ध में विचार.

1. भ्रष्टाचार कम नहीं होना चाहिए.

2. व्याज की दर कम होना चाहिये.

3. लगातार प्राप्तकर्ताओं को समाप्त होना चाहिये.

4. लाभ अधिक होना चाहिए.

3. केन्स के अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन व व्यापार के सम्बन्ध में विचार.

4. उपयुक्त मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ .

केन्स का मॉडल—सामाजिक अथवा पूँजीवादी, केन्स मॉडल की समीक्षा, कम विकसित देशों में केन्स के मॉडल का महत्व, विभिन्न अर्थ-शास्त्रियों के तर्क

1. दासगुप्ता.

2. एच० डब्ल्यू सिमर.

3. डॉ० बी० के० आर० बी० राव .

डॉ० राव द्वारा केन्स मॉडल की अन्य आलोचनाएँ, मिथर तथा बाल्डविन का विश्लेषण, जोसेफ शम्पीटर, केन्स मॉडल की अन्य सतिष्ठ समीक्षाएँ, गुण, दोष.

केन्स का मॉडल

Keyne's Model

1 प्रस्तावना

"Keynes dominates what has come to be known as the "New Economics" in much the same manner as Einstein dominates the "New Physics" —Dudley Dillard

केन्स (जॉन मेनार्ड तथा बाद में लार्ड) निश्चय ही बीसवीं सदी के महानतम अर्थशास्त्री हुए हैं। मार्क्स को अगर हम "Prophet of doom" या "तारा होने की भविष्यवाणी करने वाला" कह सकते हैं तो केन्स को "Prophet of boom" कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने यह बताया था कि विकसित पूँजीवादी देशों में किस प्रकार से मंदी को दूर करके पूर्ण रोजगार विकास की स्थिति कायम रखी जा सकती है। केन्स सही मायनों में २० वीं सदी के एडम स्मिथ कहे जा सकते हैं आज स्थिति यह है कि समस्त अर्थशास्त्री या तो केन्स के समर्थक हैं या केन्स के विरोधी, पर वे सब केन्स के रंग में रंगे हुए हैं।

केन्स के बाद केन्स की विचारधारा का बहुत लोगो ने बहुत तरीको से विश्लेषण किया, उसने सुधार किये तथा उन्हें सराहा केन्स के मॉडल को न केवल उन्नत देशों में सराहा गया तथा उस पर अमल किया गया वरन् समाजवादी देशों व कम विकसित देशों में भी केन्स की विचारधारा का गम्भीर अध्ययन किया गया Hicks (हिक्स), Harrod (हरोड) Tinbergen (टिबरजन) आदि Econometricians ने भी अपने मॉडलों को केन्स के मॉडल पर आधारित किया।

1929-30 की महान मंदी ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल व उनके भाषावाद को खोलता मिट्ट कर दिया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कथन था कि दीर्घकाल में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और अगर बेरोजगारी फैलती भी है तो मजदूरी की दर कम करके उसे बर्बाद भी फैलने से रोका जा सकता है उनका

विश्वास था कि "पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है" केन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की 'निर्वाचवादी' नीति का तिरस्कार किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में ही सुधार करके पूर्ण रोज़गार का विकास पाया जा सकता है। "जब युद्ध जीता जा सकता है तो शान्ति भी जीती जा सकती है" अर्थात् शान्ति काल में भी पूर्ण रोज़गार आ सकता है

केन्स के विकास मॉडल की विवेचना .

केन्स के अनुसार देश में पूर्ण रोज़गार बनाए रखने से ही विकास होगा। केन्स चाहते थे कि विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि देश में पूर्ण रोज़गार कायम रहे। केन्स के अनुसार देश में पूर्ण रोज़गार बनाए रखने के लिए देश में राष्ट्रीय आय में कमी नहीं आना चाहिए (Y) या राष्ट्रीय आय, केन्स के अनुसार, 'प्रभावशील माँग' के बने रहने पर निर्भर रहती है। आय शब्दों में देश में पूर्ण रोज़गार प्रदान करने वाले विकास के लिए $E = Y$ नहीं घटना चाहिए या $E < D$ (effective demand) अर्थात् प्रभावशील माँग नहीं घटना चाहिये।

(पृ० 168 पर दिया हुआ चार्ट प्रभावशील माँग को निर्धारित करने वाले तत्वों को बताता है।)

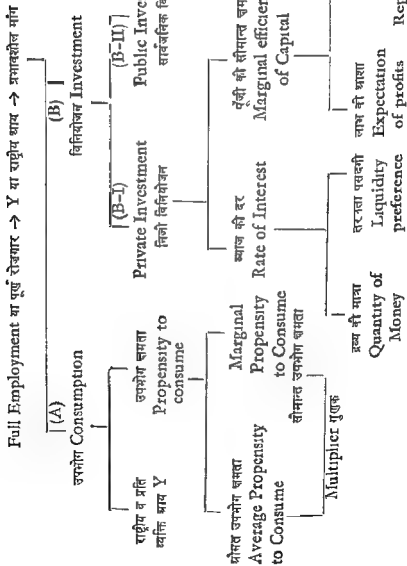
A उपभोग नहीं गिरना चाहिए. Consumption should not fall.

(1) केन्स ने बताया कि विकसित देश में जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, वैसे-वैसे उपभोग क्षमता घट जाती है और वचत करने की क्षमता बढ़ जाती है जब आय बढ़ती है तो पूरी खर्च नहीं हो पाती इसके कुछ कारण होते हैं (1) उन्नत जीवन स्तर को अपनाने में देर लगती है तथा कोई व्यक्ति उन्नत जीवन स्तर को उसी समय अपनाता है जबकि उसको इस बात का विश्वास हो जाए कि बड़ी हुई आय स्थायी रूप से रहेगी, (11) इसके अतिरिक्त, केन्स के अनुसार लोग स्वयं वचत करते हैं। यह वचत निम्नलिखित आठ उद्देश्यों से की जाती है :

- (1) भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए Motive of precaution
- (11) भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए Motive of foresight.
- (iii) व्याज कमाने के लिए Motive of price

Keynes . (इनको Canes के रूप में अर्थात् केन्स धोलेते हैं).

"The General Theory of Employment, Interest and Money."



(iv) धीरे-धीरे सुख प्राप्त करने के लिए : Motive of Improvement.

(v) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए Motive of Independence.

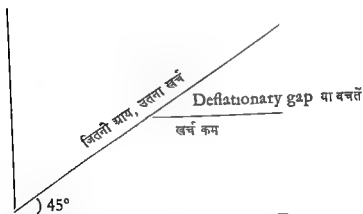
(vi) सट्टे के लाभ प्राप्त करने के लिए Motive of enterprise

(vii) उत्तराधिकारिया को देने के लिए Motive of Calculation

(viii) अपनी कजूसी को सतुष्ट करने के लिए Motive of advance

(2) परिणाम :

इन सब वक्तो का परिणाम यह होता है कि यह बचने Deflationary gap या मन्दी की खाई उत्पन्न कर देती है जब खर्च कम होत है तो देश में प्रभावशील माँग कम हो जाती है एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होता है. (हमारे कपड़ा पर खर्च, कपड़े बेचने वाले की आय होता है) बचत इस प्रकार में व्यक्तिगत गुण हो सकती है परन्तु सामाजिक दुर्गुण हो जाती है, इसके कारण ही समृद्धि में गरीबी पैदा होने लगती है निम्नलिखित चित्र इस स्थिति को दर्शाता है



(3) उपभोग बढ़ाने के उपाय :

केन्स के अनुसार अगर उपभोग को Unity रखा जाए, अर्थात् आय के अनुपात में बढ़ाया जाए तो मन्दी नहीं आएगी और विकास होता रहेगा उपभोग को हम दो रूप से बढ़ा सकते हैं

(1) Through objective changes या प्रत्यक्ष परिवर्तनों द्वारा और

(2) Through subjective changes या कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों द्वारा

पहली रीति के अन्तर्गत हम उपभोग निम्नलिखित तरीकों से बढ़ा सकते हैं .

- (1) ग्रामीरों पर कर लगा कर गरीबों को इस आय का हस्तान्तरण करें
- (II) वस्तुओं का मूल्य घटाएँ, जिसपरूप से गरीबों के उपभोग बढ़ाने को
- (III) एकाधिकारियों के लाना का कम किया जाए, जिससे वे कम मूल्य में और माँग बढ़ें
- (IV) मुद्रा स्फोटि न होने दी जाए तथा
- (V) राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा पर व्यय बढ़ा दें.

दूसरी रीति के अन्तर्गत, उपभोग बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उपभोग बढ़ाने के लिए समाज में, विज्ञापन व प्रचार से नई रचियों, फैशनो व आदतों को उत्पन्न किया जाए

(4) गुणक प्रभाव :

अगर उपभोग बढ़ सके तो इसके गुणक प्रभाव होते हैं 'गुणक प्रभाव' का अर्थ यह होना है कि उपभोग वृद्धि में जो विनियोजन पर प्रभाव होते हैं उससे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे केन्स का कथन है कि अगर देश में MPC (Marginal propensity to consume या सीमान्त उपभोग क्षमता) अधिक हो, गुणक भी अधिक होगा और विनियोजन में थोड़े से परिवर्तन से रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे अगर MPC कम है तो विकास कायम रखने या रोजगार कायम रखने के लिए, बहुत अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे

उपभोग का महत्व तो इतना अधिक है कि अगर MPC अधिक हो और जाहे विनियोजन (I) उतना ही रहे तो रोजगार बढ़ जाएगा पर अगर MPC स्थिर है तो I के बढ़ने पर रोजगार बढ़ाना कठिन होगा, जब तक कि I, MPC के कम होने की खाई पूरी न कर दें

केन्स का कथन है कि अल्पकाल में (जिसमें हमें पूर्ण रोजगार कायम करना है) इतना उपभोग बढ़ाना सम्भव नहीं होगा कि Deflationary gap पूर्ण रूप से घट जाए. इस लिए हमको विनियोजन बढ़ा कर यह 'अन्तर' पूरा करना पड़ेगा.

B. निजी विनियोजन बढ़ाना चाहिए. इसके लिए व्याज की दर कम और पूँजी की कुशलता में वृद्धि होना चाहिए.

विकसित देशों में उपभोग व्यय से ही पूर्ण रोजगार कायम नहीं रह सकता

उत्पादन की समस्त लागतें (या राष्ट्रीय आय) उपभोक्ताओं के ही पास नहीं पहुँच जाती इसमें से कुछ भाग राज्य के पास करो के रूप में व कम्पनियों के पास लाभांश के बाकी भाग के रूप में (depreciation allowances and undistributed profits) बचा रहता है यह तो विनियोजन के रूप में ही प्रभावशील माँग बढ़ा सकता है.

ब्याज की दर कम करना चाहिए (1)

विनियोजन बढ़ाने के लिए, कम ब्याज की दर सहायक होती है. ब्याज की दर या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ा कर कम की जा सकती है या फिर तरलता पसंदगी को कम कर के कम की जा सकती है. केन्स के अनुसार हर व्यक्ति अपने धन को कम या अधिक मात्रा में तरल रूप में (या नगद रूप में) रखना चाहते हैं. अगर उनसे यह तरलता पसंदगी छुड़ाना हो (या धन उधार लेना हो) तो उन्हें ब्याज का प्रलोभन देना पड़ेगा अगर समाज में तरलता पसंदगी अधिक है तो ब्याज अधिक होगा. और अगर कम है तो ब्याज की दर भी कम होगी

केन्स का कथन है कि ब्याज की दर उपरोक्त दोनों रीतियों से कम तो की जा सकती है परन्तु गिरती हुई ब्याज की दर से ही विनियोजन नहीं बढ़ जाता है अगर लाभ की आशा चीण हो तो शून्य ब्याज की दर पर भी लोग धन लेकर विनियोजन नहीं करेंगे इसलिए ब्याज की दर घटा कर विनियोजन, आय, रोजगार व विकास के स्तर न तो कायम रखे जा सकते और नहीं बढ़ाए जा सकते हैं.

पूँजी की सीमान्त कुशलता बढ़ाना चाहिए. (MEC)

केन्स ने रोजगार स्तर व विकास की रफ्तार को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो उपभोग को दिया था उसके पश्चात् उन्होंने M. E. C या पूँजी की सीमान्त कार्य कुशलता को महत्व दिया (The M. E. C is the rate at which prospective yields are expected.) M. E. C. वह दर है जिस दर से लाभ अपेक्षित होते हैं.

यह M. E. C या तो मशीनों की लागत मूल्य के कम करने से बढ़ेगी या फिर लाभ की आशा बढ़ने से बढ़ती है केन्स का कथन है कि मशीनों की लागत घटाना सरल कार्य नहीं है. इसके लिए तकनीकी उन्नति की आवश्यकता पड़ती है और यह स्वयं विनियोजन बढ़ाने से सम्भव होगा इसलिए लाभ की आशा बढ़ाना ही आवश्यक होगा.

केन्स के मॉडल में या अर्थशास्त्र में M E C का महत्वपूर्ण स्थान है M E C को अल्पकाल में बहुत अधिक परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है और दीर्घकाल में घटने की प्रवृत्ति होती है अगर M. E. C बढ जाय तो विनियोजन बढ जाना है

केन्स ने बताया कि विकास प्रक्रिया में M E C खल नायक का पार्ट अदा करती है (M E C is the villain of piece अर्थात् जब विकास प्रक्रिया में M E C का एकाणक खय होता है या जब M. E. C. गिरती है तो मंदी शुरू हो जाती है केन्स ने बताया कि लाभ की यह सम्भावित आशा (M E. C) बहुत कुछ उत्पादन कर्तियों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करती है अगर गिरती हुई उपभोग चमत्ता के कारण उत्पादनकर्ता निराश हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं तो M E C गिर जाती है

केन्स का कथन है कि अगर हम M E C बढा सकें तो निजी विनियोजन बढ सकता है परन्तु किसी भी व्यक्ति को डरा देना अधिक सरल है और डरे हुए व्यक्ति का पुन सामान्य स्थिति में लाना अधिक कठिन है व्यापारी केवल कह देने मात्र से या समझाने से ही आशावादी नहीं बन जाते. (It is much harder to make businessmen optimistic than to alarm them. It is not easy to make businessmen optimistic by mere persuasion.)

केन्स का यह कथन है कि आज के युग में यह बात उद्योग जगत में dormant capital owners (निष्क्रिय पूँजीपति या मालिक) होने की वजह से व्यापारिक ज्ञान कम होता है और ये लोग अफवाहों व व्यापारिक भय के जन्दी शिकार हो जाते हैं

इस कारण यह निश्चित है कि निजी विनियोजन इतनी मात्रा में नहीं बढ सकता कि 'मंदी की खाई' पूरी हो सके. इस कारण सार्वजनिक विनियोजन से ही यह खाई पाटी जा सकती है.

B II सार्वजनिक विनियोजन से Deflationary gap या 'मंदी की खाई' को भरना चाहिए

केन्स ने बताया कि Deflationary gap को न तो उपभोग बढाकर भरा जा सकता है और न ही निजी विनियोजन बढाकर, क्योंकि ये दोनों अपेक्षित मात्रा में बढ ही नहीं पाते अब इस मंदी-खाई को पाटने के लिए सार्वजनिक विनियोजन बढा देना चाहिए

सार्वजनिक विनियोजन हीनार्थ प्रवन्धन करके बढ़ाया जा सकता है यह सार्वजनिक विनियोजन वृद्धि साम-हानि के हिसाब वित्ताव पर आधारित नहीं होती वरन् पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ या देश के नेताओं के हाथ में होती है। केन्स के मॉडल में राज्य का विशिष्ट स्थान है केन्स के अनुसार, राज्य के प्रत्यक्ष कार्य के बिना न तो देश में प्रभावशील भाग बढ़ सकती है और न निजी विनियोजन ही बढ़ सकता है।

राज्य के सार्वजनिक विनियोजन से शुष्क प्रभाव होते हैं राज्य जब व्यय करता है तो निजी क्षेत्र वालों को भी "आर्डर" मिलने है राज्य के विनियोजनों से निजी विनियोजनकर्ताओं को वस्तुओं की माँग प्रत्यक्ष रूप में बढ़ने लगती है। इसके अप्रत्यक्ष लाभ भी थोड़े समय बाद सामने आने लगते हैं। जब राज्य के सार्वजनिक कार्यों में मजदूरों की मजदूरी मिलती है तो उससे देश में प्रभावशाली माँग बढ़ती है। इससे निजी क्षेत्र वालों की वस्तुओं की भी माँग बढ़ती है।

फिर जिस प्रकार से तालाब में पत्थर फेंकने से एक के बाद दूसरी लहरें उठती हैं उसी प्रकार एक विनियोजन में दूसरे विनियोजन बढ़ने लगते हैं

इस प्रकार जब पुन व्यय करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है तो वे व्यक्ति भी, जिन्हें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ है, आशावादी वातावरण में अपना निराशावाद छोड़ देते हैं और व्यय करने लगते हैं

केन्स ने बतलाया कि सार्वजनिक व्यय को चक्रविरोधी रूप से किया जा सकता है जैसे जैसे मंदी कम होती जाय सार्वजनिक व्यय को कम किया जा सकता है और उसका स्थान निजी विनियोजन ले सकता है। इसमें चक्रीय बेरोजगारी दूर की जा सकती है, परन्तु Chronic Unemployment या पुरानी बेरोजगारी आशिक रूप से दूर की जा सकती है। इसके लिए उपभोग भी बढ़ना चाहिए

Keynes on rewards to factors of production.

केन्स के 'उत्पादन के अंगों को पुरस्कार' के सबब में विचार .

Wages मजदूरी • Wages not to be reduced.

केन्स से पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह मत व्यक्त किया था कि अगर देश में विकास प्रक्रिया को कायम रखना हो तो मजदूरी की दरों को लचीला रखना होगा, यर्थात् आदयकतानुसार उन्हें घटा सकने की सुविधा होना चाहिए। इस सुविधा के प्राप्त होने पर ही देश में पूर्ण रोजगार बना रह सकेगा और इसी के होने से देश के निर्यात बढ़ सकेंगे संक्षेप में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री निम्नलिखित कारणों से मजदूरी दर कम रखना चाहते थे

- (i) मजदूरी कम रखने या कम कर देने से लागत घटेगी. इससे वस्तुओं की माग, विक्री व उत्पादन बढ़ेगा और तदनुसार लाभ बढ़ जाएगा.
- (ii) इससे विनियोजन व रोजगार बढ़ेगा.
- (iii) विदेशी व्यापार में निर्यात वर्धन से भुगतान संतुलन पक्ष में आयेगा और देश में विकास होगा
- (iv) मजदूरी कम रखने से उत्पादनकर्ताओं को कम चल पूँजी की आवश्यकता होगी और इससे व्याज की दर भी गिरेगी
- (v) मजदूरी कम होने से थम गहन तकनीक अपनाई जा सकेगी
- (iv) मजदूरी घटने में मजदूरों की आय नहीं घटेगी उन्हें जो अतिरिक्त रोजगार मिलेगा. उससे मजदूरों की कुल आय (Wages bill) कम नहीं होगा

केन्स ने इस विचारधारा का इतना बड़ा विरोध किया कि उन्हें समाजवादी तक माना गया केन्स ने बताया कि हम नीति में बहुत दोष है. इस नीति को अपनाने से न तो पूर्ण रोजगार को स्थापित करने में मदद मिलेगी और न ही इससे विकास में सहायता मिलेगी उन्होंने इसको निम्नलिखित कारणों से गलत बताया

- (i) मजदूरी केवल लागत ही नहीं है वह किसी की आयमदनी भी है अगर देश के सबसे बड़े वर्ग की आय घटा दी गई तो इससे प्रभावशील माँग गिरेगी, इसने देश में उत्पादन विनियोजन व रोजगार गिर जाएगा
- (ii) मजदूरी गिराकर व्याज की दर कम करने के केन्स विल्कुल पक्ष में नहीं थे उनके अनुसार एक तो मजदूरी की दर घटाने में व्याज की दर घटाना 'मूर्खता का कार्य' होगा, क्योंकि इससे आसानी रीति तो मुद्रा की पूँति बढ़ाना हो सकती है और दूसरे व्याज की दर गिराने में विनियोजन व रोजगार बढ़ता नहीं है. जैसा कि हम देख चुके हैं व्याज की दर गिराकर विकास नहीं किया जा सकता.
- (iii) केन्स ने इसके अन्तर्धान यह बताया कि आज के युग में मजदूरी कम करना सम्भव नहीं होगा. मजदूर लोगों को चाहे मार-मार कर बिछा क्यों न दिया जाए वे मजदूरी की दरों में कमी कभी मजूर नहीं करेंगे.

(i) See Part II of the book for "Wage policy for growth."

(ii) Cf Keynes : op. cit. 267-9.

(iii) See also ch. VI of "Economics of wages, productivity and Employment" by O. S. SHRIVASTAVA, Kailash pustak sadan, Gwalior.

(IV) केन्स ने इसकी अन्य हानियाँ यह बतलाई कि मजदूरी घटाने से उत्पादकता घटेगी, हड़तालों के कारण उत्पादन घटेगा और राष्ट्रीय आय घटेगी.

(V) मजदूरी के घटाने से थमिकों की जो माँग घटेगी उससे M. E. C. कम होगी

संक्षेप में केन्स का मजदूरी के सम्बन्ध में यह मत था कि पूर्ण रोजगार युक्त विकास प्राप्त करने हेतु मजदूरी घटाना अनुचित होगा इससे रोजगार बढ़ेगा नहीं बल्कि उसका कम हो जाना सुनिश्चित है. केन्स मजदूरी घटाने के कट्टर विरोधी थे. उनका मत था कि मजदूरी के स्तर ऊँचे रखना ठीक है, परन्तु वे मजदूरी को बढ़ाकर पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की सिफारिश नहीं करते थे.

Interest to be low for economic growth

केन्स ने व्याज की दर को कम रखने की सलाह दी. किसी भी कम विकसित देशों में व्याज की दर के दो कार्य होते हैं. एक तो उसकी दर इतनी कम नहीं होना चाहिए कि बचतें हतोत्साहित हो जाएँ और दूसरे इतनी अधिक नहीं होना चाहिए कि विनियोजन ही हतोत्साहित हो जाये.

केन्स ने अपनी "General Theory" विकसित देशों को ध्यान में रख कर लिखी. उनके मॉडल में बचतें, व्याज की दर निर्भर नहीं करती. (Saving is not a function of rate of interest but of high income) बचतें तो आय बढ़ने के साथ-साथ M. P. S के अधिक होने या M. P. C. के कम होने के कारण हो जाती हैं. इसलिए पूँजीनिर्माण के लिए बचतों व साधनों की कमी तो है ही नहीं. इसलिए केन्स व्याज की दर को कम चाहते थे. व्याज की दर को कम रखने में केन्स के अनुसार विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित मदद मिलेगी

- (i) विनियोजन प्रोत्साहित होगा, (हालाँकि वे इसे M. E. C. की वृद्धि से कम महत्वपूर्ण मानते थे):
- (ii) बचतें कम रहेंगी व उपभोग बढ़ेगा तथा
- (iii) गैर कमाई आय कम होगी और धन की असमानताएँ कम होंगी और देश की M. E. C. बढ़ेगी.

संक्षेप में, केन्स के अनुसार, विकसित देश में, नीची व्याज की दर, उँची व्याज की दर के मुकाबले में विकास प्रक्रिया में अधिक सहायक होती है.

Rent : Euthenasia of the rentier will be helpful

लगान and necessary लगान प्राप्नकर्ताओं को समाप्त होना चाहिए.

केन्स ने लगान आय पर प्रहार किया. उनके अनुसार इससे देश में गैरकमाई आय बढ़ती है और धन की अममानताओं के बढ़ने के कारण देशों की प्रभावशाली माँग कम रहती है परन्तु, केन्स लगान को "क्रान्तिकारी कारणा" से समाप्त नहीं करना चाहते थे वे चाहते थे कि चीन-जैसे यह प्रणाली समाप्त हो जाएगी.

Profits Profits to be high लाभ अधिक होना चाहिए

केस जहाँ लगान व व्याज को कम रखना चाहते थे वहाँ वे लाभ को अधिक हो चाहते थे न केवल लाभ अधिक होना चाहिए वरन् लाभ की आशा भी अधिक होना चाहिए इसमें M E C. अधिक रहती है तथा विनियोजन अधिक रहेगा और पूर्ण रोजगार युक्त विकास संभव होगा

3 Role of International Trade and Investment

केन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन व व्यापार के सम्बन्ध में बहुत ही व्यापक विचार रखे वे Multilateral trading या अधिकाधिक देशों के बीच अधिकाधिक व्यापार के पक्ष में थे इसी कारण उन्होंने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की स्थापना कराने में पहल की

केन्स चाहते थे कि अगर विकसित देश अपने निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें विकासशील देशों की आयात करने की क्षमता बढ़ानी होगी वे कम विकसित देशों के लिए सरक्षण नीति की भी सिफारिश करते थे. वे कम विकसित देशों पर ऋण भार कम रखने या करने की सिफारिश करते थे

केन्स ने बताया कि अगर विकसित देश कम विकसित देशों को सहायता या पूँजी सहाय देते हैं तो इसमें कम विकसित देश इन देशों से खरीदेंगे और प्रभावशील माँग की कमी पूरी हो जाएगी कम विकसित देशों में भी विकास होगा

केन्स का कथन था कि अगर एक अधिक वृद्धि वाला देश मन्दी की बेरोजगारी से पीड़ित हो तो यह देश अगर ऋण, अनुदान व पूँजी तथा तकनीकी ज्ञान कम-विकसित देशों को दे तो इससे इन देशों में भी बेरोजगारी दूर होगी क्योंकि कम-विकसित देशों में माँग उत्पन्न होगी.

केन्स ने विकसित देशों से कम विकसित देशों को सहायता देने में विकसित देशों के भले के लिए बताया

4 Suitable monetary and Fiscal policies.

- (1) केन्स ने ऐसी मौद्रिक नीति की सिफारिश की जिससे मन्दी के दिनों में मुद्रा चलन की पूर्ति बढ़े वे चाहते थे मन्दी के दिनों में व्याज की दर कम कर दी जाए ताकि विनियोजकों को उधार लेना सरल हो.
- (2) केन्स सार्वजनिक विनियोजन की अधिकतम मात्रा पर बल देते थे और वे चाहते थे कि यह विनियोजन 'हीनार्थ प्रवन्धन' से अर्थात् नए नोट छाप कर, किया जाए
- (3) केन्स चाहते थे कि मन्दी काल में राज्य जो अतिरिक्त व्यय करे वह ऋण लेकर करे, अधिक बर सगाकर नहीं करे. ऋण लेकर खर्च करने से वचत्तें व्यय का रूप धारण कर लेती हैं और देश में प्रभाव शील माँग बढ़ती है केन्स 'हीनार्थ प्रवन्धन' को *Income creating finance* कहते थे
- (4) केन्स के मॉडल के प्रकाश में आने से पहले, मन्दी दूर करने के लिए मौद्रिक नीति को ही अधिक महत्व दिया जाता था केन्स ने राज-कोपीय नीति को *Anti cyclical* चक्र विरोधी नीति के रूप में प्रयोग करने की सफल सलाह दी.
- (5) केन्स चाहते थे कि मन्दी के दिनों में आवश्यकतानुसार कुछ अप्रत्यक्ष करों को कम किया जाए ताकि उपभोग बढ़ सके
- (6) उपरोक्त विद्वेषण का अर्थ यह नहीं है कि केन्स मुद्रा स्फीति चाहते थे. वे मुद्रा स्फीति को भी नियन्त्रित रखना चाहते थे उनका कथन था कि मुद्रास्फीति को मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग के स्थान पर, मौद्रिक व राजकोपीय नीति से नियन्त्रित करना चाहिए समृद्धि के दिनों में समस्त राजस्व क्रियाये बरों से चलाना चाहिए इन दिनों में अनिवार्य रूप से वचत्तें भी करार्द्र जा सकती हैं केन्स सही मायनों में मुद्रा स्फीति और मन्दी दोनों पर मौद्रिक, राजकोपीय व विनियोजन नीति से "सामाजिक नियन्त्रण" चाहते थे

मिलार्ड ने इसीलिए लिखा है

'The versatility of Keynes general system of theory was demonstrated by the fact that the same frame-work could be used to analyse inflation and unemployment'

अन्य शब्दों में केन्स ने policy of pump priming (होनार्थ प्रवन्धन) तथा मौद्रिक नीति (Credit regulation and control of rate of interest) के द्वारा व्यापार चक्रों की तीव्रता को समाप्त कर, पूर्ण-रोजगार सहित विकास करने की नीति सुझाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया

Keynesian Model Socialistic or Capitalistic ?

केन्स ने अपनी General Theory में जो कुछ लिखा उससे हम उनका विकास मॉडल निरूपण सकते हैं परन्तु इस सम्प्रन्ध में मनभेद हो सकता है कि वे अधिक समाजवादी थे या अधिक पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे

A उन्होंने भ्रष्टाचारी न घटाने तथा गृह्य व लगान के कम रखने के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा उससे उनके समाजवादी होने का दावा किया जा सकता है केन्स ने धन व आय में समानता के पक्ष में बहुत कुछ लिखा क्योंकि अधिकाधिक समानता से देश में प्रभावशील माँग बढ़ती है जिससे कि पूर्ण रोजगारयुक्त विकास सम्भव होता है उन्होंने अपनी सार्वजनिक नीति में भी (1) ग्रामीरों पर अधिक कर लगाकर गरीबों की सहायता पहुँचाने (11) मूल्य नियन्त्रण रखने, तथा (111) सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी सिफारिश की उनके यह तर्क प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के तर्कों से एकदम भिन्न थे. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री धन की असमानताओं को उत्पन्न करने पर जोर देते थे क्योंकि केवल धनी लोग ही बचत करके वित्तियोजन कर सकते थे. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता पूर्ण रोजगार-रहित विकास की स्थिति में ठीक हो सकती है परन्तु केन्स ने तो अपूर्ण-रोजगार को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता माना.

जैसा कि हमने देखा, केन्स "ग्रामीरों को ही गरीबी का कारण" मानते थे (जैसे बहुत मोटापा शरीर को लाभ न पहुँचाकर हानि ही पहुँचाता है) । उन्होंने कहा था कि जो देश जितना अधिक समृद्ध होगा उतना ही उस देश में वित्तियोजन वृद्धि प्रभावशील माँग की इकाई से कम होने के कारण, कटित होगी.

उनका यह विश्लेषण मार्क्स के विश्लेषण की भाँति था. उन्होंने निर्वाधवादी नीति को विकास में सामाजिक उत्पन्न वृद्धि के लिए अनुपयुक्त बताया उन्होंने यह लिखा कि :

"The classical theory (of development) is a special case which is misleading and disastrous if we attempt to apply it to the facts of experience"

B. परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि केन्स मार्क्स की तरह यह चाहते कि समाजवाद आए. मार्क्स के अनुसार स्थायी विकास की सम्भावना तब ही उत्पन्न हो सकती है जब कि देश में निजी सम्पत्ति पद्धति पूर्ण रूप से समाप्त होकर समाजवाद की स्थापना हो जाए. वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र को "धुंलिन अर्थशास्त्र" कहते थे.

केन्स ने पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को कायम रखकर भी पूर्ण-रोजगारयुक्त विकास की सम्भावनाएँ देखी. ये तो पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को केवल Mend (सुधार) करना चाहते थे, वे उसे end (समाप्त) नहीं करना चाहते थे. वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की समस्त विचारधारा को त्रुटिपूर्ण नहीं मानते थे. उनकी मृत्यु के बाद एक लेख ("The Balance of Payment of United states." in Economic Journal, June 1946) में उन्होंने लिखा.

‘ I find myself moved not for the first time to remind contemporary economists that the classical teachings embodied some permanent truths of great significance ”

केन्स की स्थिति और उनके विकास सम्बन्धी विचारों की निम्नलिखित समीक्षा, जो कि हुडले डिलार्ड ने की है, अत्यन्त उपयुक्त है

“केन्स “औद्योगिक पूँजीवाद” (Industrial capitalism) के समर्थक थे, परन्तु वे “वित्तीय पूँजीवाद” (financial capitalism) के विरोधी थे. वे व्यक्ति की आर्थिक स्वतन्त्रता व निजी उद्योग के समर्थक थे पर वे “निर्वाध-वादी नीति” के विरोधी थे ”¹

उनका स्पष्ट मत था कि अगर पूँजीवाद के वित्त सम्बन्धी दोषों व वितरण सम्बन्धी दोषों को दूर कर दिया जाए तो इसमें अच्छी विकास की सम्भावनाएँ बड़ी और नहीं होंगी.

Evaluation of Keynesian Model with particular reference to The Relevance of Keynesian Model in under-developed Countries.

See - “Economic Thinking of Lord Keynes, Socialist or Capitalist ? by Prof. Dudley Dillard. Forum of Free Enterprise.”

केन्स मॉडल की समीक्षा.

कम विकसित देशों में केन्स के मॉडल का महत्व

केन्स के मॉडल का कम-विकसित देशों में क्या महत्व है इस सम्बन्ध में अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने जो तर्क दिए हैं वे इस प्रकार हैं

(1) केन्स के मॉडल में अर्नैचिक तथा मन्दी की बेरोजगारी दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं परन्तु कम-विकसित देशों में तो संरचना-मन्दन्धी (Structural unemployment) बेरोजगारी तथा Chronic under-employment या पुरानी अथ बेरोजगारी की समस्या होती है. केन्स का मॉडल इस प्रकार की बेरोजगारी को दूर कर विकास पथ नहीं बताता. दास गुप्त के अनुसार कम-विकसित देशों में भुविज से 0.5 प्रतिशत व्यक्ति ही अर्नैचिक बेरोजगारी के शिकार पाए जाएंगे.

(2) केन्स का मॉडल पूर्ण रूप से मुद्रा-चलित अर्थ-व्यवस्था (fully monetized economy) में लागू होगा है कम-विकसित देशों में मुद्रा बाजार इतना अधिक विकसित नहीं होता यहाँ तो बहुत सी मौद्रिक नीति सम्बन्धी काम अपना असर अपेक्षित रूप से नहीं दिखाते. देश के कुछ भागों में 'बदला-बदली' (barter) प्रणाली मौजूद रहती है

(3) विकसित देशों में मन्दी लाने वाली मुख्य चीज M. E. C. का गिरना होता है. कम-विकसित देशों में Liquidity preference तरलता पसन्दगी की अधिकता होता है यहाँ के अधिकांश लोगों की आय कम होती है जिसके कारण वे व्यक्ति अपनी आय को तरल रूप में (या नगद रूप में) 'आड़े दिने' के लिए रखते हैं इससे देश में विनियोजन व पूँजी-निर्माण कम होता है.

स्वयं केन्स ने लिखा

‘भारत के इतिहास ने हमेशा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार एक देश तरलता पसन्दगी के कारण ग़रीब बना रहता है. यहाँ तरलता पसन्दगी एक प्रेम है (Passion) जिसके कारण इस देश में इतना अधिक सोना चाँदी आने पर भी व्याप को दर, देश में वास्तविक धन की मात्रा के माफिक, कम नहीं होती

1. See . A K Das Gupta's Keynesian Economics and Under-developed Countries ch. 2 Planning and Economic Growth. George Allen & Unwin

2 Keynes . op cit ch 23, p. 337.

2 H. W. Singer हॉन्स डब्ल्यू सिंगर :

केन्स के मॉडल में वचतों की कमी की समस्या नहीं है उनका मॉडल विकसित देशों के लिए है जहाँ वचतें स्वयं आय के साथ बढ़ जाती हैं। केन्स के मॉडल में वचतों की अधिकता ही विनियोजन के धक्के पर कम बरती है क्योंकि वचतों की अधिकता ही उपभोग क्षमता की कमी का चेतक है।

परन्तु कम विकसित देशों में यह समस्या नहीं होती यहाँ तो एक तो राष्ट्रीय आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, यहाँ तो वचतों को बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ अधिक वचतें समस्या पैदा नहीं करती बल्कि उनसे जो पूँजी निर्माण होता है, वह विनियोजन को बढ़ाता है और विकास होता है।

The fact of Keynesian thinking, that an excessive propensity to save may kill off the inducement to invest as incomes rise, obviously is not applicable in underdeveloped countries where the increase in savings is conceived as itself the result of the emergence of new investment opportunities

Keynes as stagnationist • विकास पर जिन लेखकों ने लिखा उन्हें किसी न किसी कारण से “स्थगिक अवस्था” का भय सताता रहा। जहाँ रिकार्डों को यह भय उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण सताता था, माल्थस को जनसंख्या की वृद्धि के कारण इस अवस्था के आने का डर था मार्क्स को पूँजीवाद की समाप्ति का डर (या आशा कहे ?) था तो शम्पीटर को यह डर था कि साहसियों के बच्चे “कवि बन कर रह जाएंगे” केन्स को M E C के गिरने के कारण स्थगिक अवस्था के पहुँच जाने का भय था।

केन्स की मुख्यतया दो बातों का भय था एक तो उनकी इस बात का भय था कि गिरती हुई उपभोग क्षमता से विनियोजन, रोजगार व राष्ट्रीय आय गिरते चले जाएंगे और दूसरा उन्हें यह भय था कि अगर गिरते हुए उपभोग क्षमता के दुष्प्रभावों को विनियोजन व गुणक प्रभावों से दूर भी किया जा सके तो M E C के प्रभाव दिखाई देंगे।

See : H. W. Singer • “International Development Growth and Change.” Mc Graw Hill series 1964, p. 4-5, 6, 7 and 27-28

3. Dr. V. K. R. V. Rao : डा० वी० के० आर० वी० राव०

डा० वी० के० आर० वी० राव ने केन्स के मॉडल के कम विकसित देशों में लागू होने के सम्बन्ध में बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। उन्होंने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि इन देशों में केन्स की नीतियाँ लागू नहीं की जा सकती क्योंकि केन्स का गुणक इन देशों में लागू नहीं होता।

इस अवधि में वे यह कहते हैं कि स्वयं केन्स ने यह मॉडल विकसित देशों के लिए नहीं बनाया वरन् यह तो अन्य लोगों ने गलत कार्य किया कि उन्होंने केन्स की नीतियों को कम विकसित देशों में लागू किया।

कम विकसित देशों में केन्स के मॉडल में बताए "गुणक प्रभावों" के लागू न होने के डा० राव ने निम्नलिखित कारण बताए

1. किसी भी देश में "गुणक प्रभावों" के अधिक होने के लिए निम्नलिखित चार बातें आवश्यक होती हैं

(a) M P C. उपभोग क्षमता अधिक होना चाहिए,

(b) देश में अर्धव्यवस्था बेरोजगारी मौजूद होना चाहिए,

(c) देश में Excess capacity मौजूद होना चाहिए अर्थात् कल-कारखानों में उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन होने की स्थिति होना चाहिए तथा

(d) पूँजी की मूल्य वृद्धि की अवस्था में बढ़ना चाहिए,

2. डा० राव का कथन है कि निश्चित ही कम विकसित देशों में 'सीमान्त उपभोग क्षमता' अधिक होती है परन्तु इन देशों में (b), (c), (d) स्थितियाँ मौजूद नहीं होतीं।

डा० राव ने बताया कि कम विकसित देशों में Involuntary unemployment या अर्धव्यवस्था बेरोजगारी नहीं होती वरन् मुख्यतया अर्ध बेरोजगारी होती है विकसित देशों में जब विनियोजन बढ़ाया जाता है तो उत्पादन बढ़ता है और बेरोजगारी दूर हो जाती है परन्तु कम विकसित देशों में विनियोजन के बढ़ाने से अर्ध-बेरोजगारी उतनी शीघ्र दूर नहीं हो पाती इसके दो मुख्य कारण हैं

(1) एक तो बहुत से अर्ध बेरोजगार व्यक्ति इतने अधिक गतिहीन होते हैं कि वे काम के अवसर प्राप्त नहीं कर पाते तथा

Cf : Dr. V. K. R. V. Rao : Investment, Income and the Multiplier in Under-developed Economy, as ch II, p. p. 35-49 in "Essays in Economic Development".

(11) दूसरे वे उत्पादन उस मात्रा में नहीं बढ़ा पाते।

3 विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का अधिक प्रतिशत विनियोजित किया जाता है, जिसके कारण, कम M. P. C होने हुए भी गुणक अधिक होता है।

कम-विकसित देशों में M. P. C तो अधिक होती है परन्तु विनियोजन की मात्रा कुल राष्ट्रीय आय की मात्रा का बहुत कम प्रतिशत होती है, इस कारण गुणक प्रभाव कम रहते हैं

इस प्रकार से कम विकसित देशों में प्राथमिक विनियोजन से जो रोजगार वृद्धि होती है उतनी ही Secondary (उद्योग आदि) तथा Tertiary (आर्थिक-सामाजिक सिरोपरी क्षेत्र जैसे यातायात, बैंकिंग आदि) में रोजगार वृद्धि नहीं हो पाती।

4 डा० राव ने एक और कारण जिसमें केम्स का गुणक कम-विकसित देशों में लागू नहीं होना यह बताया कि इन देशों में पूर्ति लोचदार नहीं होती। इसका कारण यह है कि जब इन देशों में प्राथमिक विनियोजन बढ़ने से उपभोग्य वस्तुओं की माँग बढ़ती है जिन में पूर्ति आसानी से बढ़ाई नहीं जा पाती और इस कारण इनमें रोजगार वृद्धि केम्स के गुणक के अनुरूप नहीं हो पाती। कम विकसित देशों में आय बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की माँग अधिक बढ़ती है या फिर मोटे अनाज के स्थान पर उत्तम अनाज की माँग होने लगती है।

डा० राव का कथन है कि इन देशों में मूल्य परिवर्तन से उपज की किस्मों में परिवर्तन हो जाता है परन्तु कुल पूर्ति में विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता इसका मुख्य कारण, जैसा कि सर्वविदित है कृषि का पिछड़ापन होना तथा उन्नत तरीकों की सुविधाओं की कमी होना है इस कारण डा० राव कहते हैं

“The income multiplier is much higher in money terms than in real terms and to that extent prices rise much faster than an increase in aggregate real income.”

(अर्थात् इन सब कारणों से वास्तविक आय वृद्धि में मौद्रिक आय वृद्धि अधिक रहती है.)

5 डा० राव आगे कहते हैं कि न केवल कृषि क्षेत्र में प्राथमिक विनियोजन के गुणक प्रभाव नगण्य होते हैं वरन् Secondary तथा Tertiary क्षेत्र में

भी यह प्रभाव विकसित देशों की भाँति नहीं होते इन क्षेत्रों में Excess capacity या इस्तेमाल में न आने वाली उत्पादन क्षमता नहीं रहती, जैसा कि विकसित देशों में होता है. डा० राव का अर्थ है जहाँ विकसित देशों में काम में न आने वाली मशीनों को काम में लेकर तुरन्त उत्पादन बढ़ाया जा सकता है वहाँ कम विकसित देशों में ऐसा नहीं हो पाता. यहाँ पर इसी प्रकार से कुशल श्रमिकों की भी कमी रहती है और भिन्न भिन्न प्रकार की रूकवटों से उत्पादन, रोजगार व आय वृद्धि विकसित देशों की भाँति नहीं हो पाती अर्थात् मुख्यतः प्रभाव कम रहते हैं

6 डा० राव का कथन है कि विनियोजन वृद्धि से इन देशों में जिस मात्रा में आय (मौद्रिक आय) बढ़ती है उस मात्रा में उत्पादन व रोजगार नहीं बढ़ता

डा० राव द्वारा केन्स मॉडल की अन्य आलोचनाएँ :

7 केन्स ने विकसित देशों में पूर्ण रोजगार तक पहुँचने की बात कही है, इसके बाद इसे कैसे वायम रखें इसको नहीं बताया यह कार्य बाद में हरोड व डॉनर ने Acceleration principle की सहायता से किया

8 केन्स ने बचतों की अधिकता को सारी कठिनाईयों की जड़ बताया, परन्तु कम विकसित देशों में बचत करके ही विकास प्राप्त किया जा सकता है. यहाँ तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा कथित महत्व को मानना पड़ेगा

9. इन देशों में हम केन्स द्वारा बताई "हीनार्थ प्रबन्धन" की नीति को अधिक अपनाएँ तो बचतें बढ़ने के स्थान पर, मुद्रा स्फीति के कारण, घट सकती है यहाँ तो "अधिक काम करके अधिक बचत करो" का सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण है इन देशों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा बताई हुई नीतियाँ ही अधिक महत्वपूर्ण हैं

Meier and Baldwin's analysis.

मियर तथा बाल्डविन के अनुसार :

1. यद्यपि केन्स की पुस्तक (General Theory) में 'व्यापारिक उन्नावृत्तियों के विश्लेषण में नवक्रान्ति लाई, फिर उनका विश्लेषण अल्पकालिक समस्याओं का था उन्होंने अपने विश्लेषण में, (i) श्रमकी मात्रा व कार्य कुशलता, (ii) पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा व किस्म (iii) वर्तमान तक-

1, Meier and Baldwin : op cit . p. 102-3. & pp. 1, 13, 90, 97, 545 and 546.

नीक, (IV) प्रतियोगिता की मात्रा व (V) उपभोगवर्तियों की आदतों व रुचि को स्थिर माना

2. केन्स का मॉडल "स्थगिक मॉडल" रहा और उसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रिया, मार्क्स व शम्पोटर की भाँति दीर्घकालीन विकास समस्याओं का विश्लेषण नहीं किया गया था

3. यद्यपि केन्स के मॉडल में वचत-विनियोग की समस्या तथा प्रभावशील माँग की समस्या पर पहले के अर्थशास्त्रियों के मुकाबले में अधिक ध्यान दिया, परन्तु उन्होंने Capacity अर्थात् उत्पादन क्षमता की समस्या को ध्यान नहीं दिया. (इस पर हरोड व डोमर ने लिखा)

मीयर तथा बाल्डविन केन्स के (1) प्रभावशील माँग बढ़ाने, (II) व्याज की दर को विकास क्रिया में कम महत्वपूर्ण बनाने, (III) मजदूरी पर प्रहार न करने की सलाह देने, (IV) जनसंख्या वृद्धि को बुरा न समझने (वे उससे प्रभावशील माँग बढ़ने की गुंजाइश देखते थे) तथा (V) guided or planned capitalism अर्थात् आयोजित पूँजीवाद अपनाने की सलाहों की सराहना करते हैं

Joseph Schumpeter

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री शम्पोटर का कथन है कि मार्क्स का मॉडल केवल इंग्लैंड में लागू हो सकता है अन्य देशों में नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा

"प्रायोगिक केन्सवाद एक ऐसा पौधा है जो विदेशी भूमि में नहीं रोपा जा सकता. यह पौधा दूसरे देश में मर जाता है, और मरने से पहले जहरीला हो जाता है परन्तु इंग्लिश भूमि में यह पौधा पनपता है, तथा फल व साया देता है"

केन्स मॉडल की अन्य संक्षिप्त सामान्य समीक्षाएँ :

गुण ।

1 केन्स ने बताया कि वचते व्याज की दर पर निर्भर नहीं रहती वरन् आय के ऊपर निर्भर रहती है विकसित देश में वचतों की अधिकता लाभदायक नहीं वरन् हानिकारक होती है. जहाँ बेरोजगारी व्यापक हो वहाँ अधिक खर्च लाभदायक होता है वचतें नहीं

2. Schumpeter . Ten Great Economists ■ 275.

2. केन्स ने निर्वाचवादी नीति को तिरस्कार किया और "पूर्ण उत्पादन" के स्थान पर "पूर्ण-रोजगार" को अधिक महत्व दिया उन्होंने विकास के लक्ष्यों का "मानवीय" करण किया।
3. केन्स का मॉडल भी विकास के घटको में सह-संबंध अध्ययन करना है, परन्तु केन्स ने राज्य की क्रियाओं को बहुत अधिक महत्व दिया राज्य की राजस्व व मौद्रिक नीतियों को उन्होंने इस प्रकार से संचालित करने को कहा कि उससे विकास में सहायता मिले वे तटस्थ मौद्रिक व राजकोपीय नीतियाँ नहीं चाहते थे
4. उन्होंने पूँजी अर्थव्यवस्था के दोष बताए कि इस व्यवस्था में "पूर्ण-रोजगार युक्त विकास केवल युद्ध काल में या युद्ध की तैयारी में ही प्राप्त हो सकता है" उन्होंने बताया कि अगर इन देशों में पूर्ण रोजगार युक्त विकास लाना है और स्वयं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है तो थोड़ा समाजवाद जैसे (1) मूल्य नियंत्रण (II) एकाधिकार नियंत्रण (III) व्याज प्राप्ति कर्ताओं तथा लगान प्राप्तकर्ताओं की आय कम करना (IV) धन के असमान वितरण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से दूर करना आदि को अपनाता पड़ेगा।
5. उन्होंने "उत्पादन के अगो का राष्ट्रीयकरण" के स्थान पर विनियोजन व कुल उपभोग का समाजीकरण का सुझाव दिया उन्होंने हमेशा याद रखे जाने वाले शब्दों में कहा "मुद्रा स्थिति अन्याय पूर्ण है तथा मुद्रा विस्फीति अनुपयुक्त है, तथा दोनों में मुद्रा विस्फीति अधिक बुरी है।
6. केन्स ने विकसित देशों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में सहायता व व्यापार सम्बन्धी संकीर्णता को दूर किया और विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में कम विकसित देशों व विकसित देशों दोनों का भला बताया
7. उन्होंने पीगू तथा अन्य अर्थशास्त्रियों की Anti-labour मनोवृत्ति को (जिसमें वे मजदूरी दर को नीचा करके रोजगार बढ़ाने की बात कहते थे) गलत सिद्ध कर दिया

दोष :

केन्स के मॉडल व विचारों की कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई आलोचनाएं इस प्रकार हैं :

1. उन्होंने "पूर्ण रोजगार" को पूर्ण उत्पादन के मुकाबले में अनावश्यक रूप से बल दिया. (Hancy, Mantoux, and Hazlitt)

2. उनका मॉडल स्थैतिक है, प्रवैगिक नहीं है (Harrod, D. H. Robertson).
3. यह मॉडल "सामान्य नहीं है" (केन्स ने उसका नामकरण "सामान्य सिद्धान्त" किया था) बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ ही देशों में लागू होता है (Rueff, Knight and Hoover)
4. इसमें 'समय' का ध्यान नहीं रखा गया. केन्स मॉडल में Timelags को उचित स्थान नहीं दिया. (Haberler) उनका गुणक बहुत हद तक काल्पनिक है (Haberler).
5. केन्स ने तो मजदूरी और रोजगार में कोई छवध होना ही झुठला दिया. केन्स ने कंट्रोल व प्रगतिशील करो पर आवश्यकता से अधिक बल दिया (Von Mering O.).
6. केन्स की नीतियों में से बहुत सी नीतियाँ सफल नहीं रही कभी-कभी सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोजन वृद्धि से निजी क्षेत्रों को प्रेरणा मिलने के स्थान पर भय उत्पन्न हो जाता है (Haney).

सबसे अधिक आलोचना तो केन्स की हेजलिट (Henry Hazlitt) ने की है. वे तो avowed anti-Keynesian या उन्होंने तो केन्स का विरोध करने की शपथ ले रखी है उन्होंने एक पूरी पुस्तक "The Failure of New Economics" में केन्स के विचारों की प्रत्येक साइन व प्रत्येक विचार व अध्याय की आलोचना की. उनका यह कथन तो बहुत ही गम्भीर है

"केन्स ने जो कुछ भी मौलिक रूप में प्रस्तुत किया वह सही नहीं था और जो कुछ भी सही कहा वह मौलिक नहीं था."

परन्तु, इस कथन में हेजलिट ने अतिशयोक्ति से काम लिया. केन्स का स्थान अर्थशास्त्र में हमेशा बना रहेगा.

अध्याय : 15

एवसी डोमर का विकास मॉडल

Evsey Domar's Growth Model

I. प्रस्तावना

II. मॉडल की मान्यताये व आधारभूत विवेचनाये.

III. विकास मॉडल.

(a) उत्पादन क्षमता व आय

(b) कुछ आधारभूत समीकरण.

(c) ग्रीर अविक व विस्तृत विश्लेषण,

IV. निर्णायक वाक्य.

अध्याय : 15

एवसी डोमर का विकास मॉडल

Evsey Domar's Growth Model

I. प्रस्तावना :

एवसी डोमर अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। इनका नाम बहुधा हरोड के नाम के साथ जुड़ा रहता है। हरोड इंगलिश अर्थशास्त्री हैं। दोनों के मॉडल अलग-अलग बनाये गए, परन्तु उनमें इतनी अधिक समानताएँ रही कि हम “हरोड-डोमर मॉडल” को एक ही नाम से बोलने लगे। डोमर ने 1947 में *American Economic Review*, मार्च 1947 में इस मॉडल का विकास किया। परन्तु उनका कथन है कि उन्होंने हरोड के मॉडल को अपना मॉडल बनाने के बाद ही देखा, इसलिए उनके विचार हरोड के विचारों से प्रभावित नहीं हैं (2)

II. मॉडल की मान्यताएँ व आधारभूत विशेषताएँ

1. डोमर का मॉडल, केन्स की विचारधारा पर आधारित है, परन्तु डोमर केन्स के मॉडल में कई कमियाँ बताते हैं जहाँ केन्स का कथन था कि बेरोजगारी उदय होने का मुख्य कारण ‘जमाखोरी’ (hoarding) है, वहाँ डोमर का कथन है कि केवल ‘जमाखोरी’ समाप्त करने (अर्थात् विनियोजन करने) से पूर्ण रोजगार उत्पन्न नहीं हो जाएगा।
2. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विनियोजन वृद्धि पर जोर दिया तथा उनका विश्वास था कि माँग तो कभी कम होगी ही नहीं। केन्स ने माँग वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया पर विनियोजन की मात्रा व दर क्या होना चाहिए इस पर ध्यान नहीं दिया। डोमर ने विनियोजन के दोनों पक्षों, माँग उत्पन्न करने का पक्ष या आय बढ़ाने का पक्ष व पूर्ति बढ़ाने का पक्ष या उत्पादन क्षमता बढ़ाने के पक्षों पर समुचित ध्यान दिया।

See • 1. Evsey Domar : *Essay in the Theory of Economic Growth*, Oxford 1957.

2. Evsey Domar : “Expansion and Employment”, Okun Richardson op. cit.

3. डोमर की मुख्य मान्यताएँ (assumptions) यह हैं

- (a) देश में पूर्ण रोजगार आय के स्तर मौजूद है अर्थात् इस मॉडल में मुख्य रूप से उस अर्थ व्यवस्था का अध्ययन है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँच गई है मॉडल में यह बताया गया है कि यह स्थिति कैसे कायम रखी जा सकती है
- (b) राज्य का अर्थ-व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं है
- (c) देश का विदेशों से व्यापार नहीं होता है (अर्थात् closed economy है)
- (d) आर्थिक समायोजन का कार्य तत्काल हो जाता है ('There are no lags in adjustments').
- (e) बचत करने की औसत व सीमांत क्षमताएँ बराबर हैं
- (f) बचत की क्षमता व पूँजी—कोएफ़िशिएंट' (Capital co-efficient mean ratio of capital-stock to output) समान रहने हैं.
- (g) हर घटक को शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे शुद्ध बचत, शुद्ध विनियोजन

III विनाम मॉडल

III. A उत्पादन क्षमता व आय

1. डोमर ने इस बात का अध्ययन किया कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है और फिर कैसे कायम रहती है इसका समाधान उन्होंने राष्ट्रीय आय की दृष्टि में पाया डोमर ने बताया कि जब हम देश में विनियोजन करते हैं तो देश में 'उत्पादन क्षमता' (productive capacity) में वृद्धि होती है, अगर देश में निरन्तर पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है तो हम 'उत्पादन क्षमता' के बराबर वास्तविक आय का मूजन होना चाहिए वास्तविक आय व.ने से विकास बढ़ता है.
2. वास्तविक आय दो रूप से बढ़ सकती है (1) या तो मूल्य घटे या (2) स्थिर मूल्यों पर मौद्रिक आय बढ़ जाए. डोमर मूल्यों को गिराकर वास्तविक

3 Evsey Domar . Capital Extension, Rate of Growth and Employment Economica Vol. XIV p. 142-145 April, 1946

आय को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे सार्वजनिक ऋण का भार बढ़ जाते हैं और पूर्ण रोजगार की सम्पूर्ण योजना असफल हो जाएगी।

3. डोमर का कथन है कि अगर पूर्ण रोजगार को कायम रखना है तो (1) वास्तविक व मौद्रिक आय एक ही दर से बढ़ना चाहिए तथा (11) वास्तविक आय व रचनात्मक क्षमता भी एक साथ बढ़ना चाहिए।

III. B. कुछ आधारभूत समीकरण Some fundamental equations.

1. डोमर चाहते हैं कि विनियोजन में जितना पूँति का सृजन हो (productive capacity) उतनी ही मात्रा में माँग का सृजन हो (real income) (Productive capacity should generate equal amount of real income).
2. किसी भी देश में धतिरिक्त उत्पादन क्षमता, विनियोजन की मात्रा (Investment or I) \times सभावित उत्पादकता (potential productive average productivity of investment or δ) के बराबर होती है अर्थात् Productive capacity is equal to the amount of investment (I) multiplied (\times) productivity (δ or sigma) = $I\delta$
3. देश में यह उत्पादन क्षमता जो भी आय का सृजन करती है वह माँग उत्पादन करती है माँग आय में परिवर्तनों के प्रभावस्वरूप उत्पन्न होती है और स्वयं आय में परिवर्तन विनियोजन की दर में परिवर्तन तथा उसके गुणक (Multiplier) पर निर्भर करते हैं और यह परिवर्तन उपभोग व बचत की क्षमताओं पर निर्भर करते हैं
4. हम ग्रहशास्त्र में राष्ट्रीय आय को Y से दर्शाते हैं तथा उममें होने वाले परिवर्तनों को Δ (डेल्टा) से दर्शाते हैं, यहाँ हम बचत क्षमता (Propensity to save) को α (अल्फा) से दर्शाते हैं तथा विनियोजन में होने वाले परिवर्तनों को ΔI से दर्शाते हैं।
5. अब हम विनियोजन व तदनुसार आय में परिवर्तनों को इस प्रकार डोमर के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं

$$\Delta Y = (\Delta I) 1/\alpha$$
 अर्थात् अगर हम विनियोजन में होने वाले परिवर्तन को 'गुणक' से गुणा कर दें तो आय में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के बराबर होगा।

6. पूर्ण रोजगार जब कायम रहेगा तब पूंति (S) व माँग (d) बराबर हो पूंति का अर्थ उत्पादन क्षमता या $I\delta$ से है और माँग का अर्थ आय में वृद्धि से अर्थात् (ΔI) $1/\alpha$ से है

इस प्रकार से स्थायी विकास के लिए

$$(\Delta I) 1/\alpha = I\delta$$

की स्थिति मौजूद रहना चाहिए.

- 7 इस समीकरण को हम सरल रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं हम दोनों तरफों को I से भाग दे सकते हैं और α से गुणा कर सकते हैं अब यह समीकरण यह हो जाएगा

$$\Delta I/I = \alpha\delta$$

सारार के रूप में डोमर का कथन है .

“The maintenance of a continuous state of full employment requires that investment and income grow at a constant annual percentage (or compound interest) rate equal to the product of the marginal propensity to save and the average productivity of investment”
(अर्थात् अगर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम रहना है तो यह आवश्यक है कि विनियोजन और आय को चक्रवृत्ति व्याज की दर की भाँति बढ़ना चाहिए अर्थात् उस दर से बढ़ना चाहिए जो दर वचत की सीमान्त क्षमता और विनियोजन की औसत उत्पादकता दर के गुणो के बराबर हों

8. डोमर ने इसे और अच्छी तरह में समझाया : अगर उत्पादक क्षमता (δ) को 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष माने, वचत क्षमता (α) को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष मानें और राष्ट्रीय आय को (Y) 150 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष मानें, तो 18 बिलियन प्रतिवर्ष का विनियोजन आवश्यक होगा (वचत के बराबर विनियोजन हो तो $150 \times \frac{25}{100} = 18$)

अब इस विनियोजन से 4.5 बिलियन की उत्पादक क्षमता वृद्धि होगी ($I \times \delta = 18 \times \frac{25}{100} = 4.5$). अब माँग या आय को भी इतनी ही मात्रा में बढ़ाना चाहिए. इस प्रकार से माँग व पूंति में समन्वय आ जाएगा.

यहाँ माँग (आय में वृद्धि) 3 प्रतिशत है ($\frac{4.50}{1.50} = 3\%$) और $\alpha\delta$ भी तीन प्रतिशत है ($\frac{1.20}{1.00} \times \frac{2.50}{1.00}$) तब पूर्ण रोजगार कायम रहेगा.

III C : और अधिक व विस्तृत विदलेपण Further explanation

1 डोमर का इस प्रकार से केन्स में भिन्न मॉडल है केन्स के अनुसार "पूर्ण रोजगार राष्ट्रीय आय पर आधारित है" डोमर कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है कि राष्ट्रीय आय का स्तर समान रखा जाए अर्थात् उसे गिरने न दिया जाए उनके शब्दों में "माज 1941 की राष्ट्रीय आय पूर्ण रोजगार प्रदान नहीं कर सकती किसी भी देश में श्रम के रोजगार की मात्रा राष्ट्रीय आय व उत्पादन क्षमता से अनुपात पर निर्भर है"

2 डोमर देश में न तो excess capacity चाहते हैं और न excess income चाहते हैं. उनके अनुसार अगर पूँजी निर्माण व विनियोजन से केवल "उत्पादन क्षमता" में वृद्धि होती है और आय में नहीं होती तो इसके यह परिणाम होंगे कि पूँजी व श्रम को पूर्ण रोजगार नहीं मिलेगा उदाहरणतः अगर मकानों में विनियोजन से केवल "क्षमता" का सृजन होता है और आय का नहीं होता तो

(1) नये मकान पूरी तरह से या आंशिक रूप से खाली रहेंगे,

या (11) नये मकानों में लोग पुराने मकानों को छोड़कर आपस पर किराया वही रहेगा,

या (III) या अगर नये मकानों को अधिक किराया मिलता है तो किसी अन्य कार्य पर (जैसे कपड़ों पर, खर्च पर) कम धन व्यय किया जायेगा, जिससे कपड़ों के व्यापार में बेरोजगारी फैलेगी

डोमर के अनुसार जहाँ कहीं भी excess capacity रहेगी वहाँ या तो पूँजी को श्रम के स्थान पर प्रतिस्थापन के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप या फिर अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (जैसे कपड़ों के व्यापार के उपरोक्त उदाहरण में) श्रम बेरोजगारी फैलेगी.

3. परन्तु डोमर हर प्रकार की excess capacity या उत्पादक क्षमता को बुरा नहीं मानते. वे बतलाते हैं कि प्रवैगिक अर्थ व्यवस्था में किसी न किसी क्षेत्र में अधिक उत्पादन क्षमता हो जाएगी. जैसे, अगर प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग बढ़ जाए तो चमड़े के बर्तनों के उद्योग में अधिक क्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. यह तो विकास की निशानी है

डोमर तो यह चाहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए जिसमें कि एक ओर तो खाली मकान रहे और दूसरी ओर बेरोजगारी के कारण मकान को किराये पर लेने के इच्छुक व्यक्ति उन मकानों को किराये पर न ले सकें

4. डोमर के अनुसार बेरोजगारी के फैलने का मुख्य कारण आय व विनियोजन का तीव्र गति में न बढ़ना होता है। डोमर के अनुसार "आय का विनियोजन कल की दृष्टि से अधिक होना चाहिए" (Investment must grow at an increasing absolute rate (or constant compound interest rate) equal to the propensity to save (α) times the inverse of the capital coefficient (δ) (या देखिए III B का 7 वाँ पैराग्राफ)।

5. डोमर के अनुसार अगर देश में α या वृद्धि क्षमता घट रही हो तो विनियोजन स्थिर रहे तो भी आय व रोजगार बढ़ सकता है (केन्स ने इस रूप में कहा था कि देश में बढ़ते हुए उपयोग से स्थिर विनियोजन पर भी रोजगार बढ़ सकता है— दोनों बातें एक ही हैं)

परन्तु अगर α बढ़ रहे हो तो इसके सम्भीर परिणाम होने हैं क्योंकि इससे पूर्ण रोजगार बनाए रखना इसलिए कठिन हो जाएगा कि देश में पर्याप्त मात्रा में विनियोजन नहीं होगा

6. डोमर का कथन है कि पूँजीवादी समाज में जहाँ α को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वहाँ आय व रोजगार के उच्चस्तर केवल अधिक विनियोजन में ही प्राप्त किए जा सकते हैं परन्तु विनियोजन अपने δ प्रभावों के कारण एक 'मिश्रित वरदान' है (अर्थात् कभी-कभी अभिशाप बन सकता है) बगैर पर्याप्त विनियोजन के बेरोजगारी फैलेगी और आय जो विनियोजन पर्याप्त है वह उपर्याप्त हो जाएगा।

डोमर का कथन है कि विनियोजन के दोहरे प्रभाव होते हैं : उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और आय में भी वृद्धि होती है जहाँ तक दोनों बराबर रहते हैं ठीक है कभी-कभी आय भी उत्पादन क्षमता से अधिक बढ़ सकती है परन्तु आय में वृद्धि अस्थायी होती है जब कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि स्थायी रहती है इसलिए विनियोजन बीमारी (बेरोजगारी) का इलाज भी है और उसे और बढ़ा भी देता है। (So that as far as unemployment is concerned, investment is at the same time a cure for the disease and the cause of even greater ills in the future).

- 7 डोमर बतलाते हैं कि आजकल विकासशील समाजवादी देशों में विनियोजन δ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए (उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए) किया जाता है जब कि U. S. A. जैसे पूँजीवादी देश में विनियोजन "गुणक प्रभावों" multiplier effects को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है अर्थात् आय व रोजगार बढ़ाने के लिए किया जाता है

रोजगार वृद्धि व निरन्तर विकास के लिए 'हम δ को शून्य पर लाकर निर्वाण की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते' (It would be a defeatist solution to reduce δ to zero and also abolish technical progress, thus escaping from unemployment into the nirvana of a stationary state) सही इलाज तो α को कम करना होगा. उन्नत तकनीक व वस्तुें स्वयं विकास कारक नहीं होती, वे तो विकास करने की शक्ति को हमारे हाथ में देती हैं. सही मायनों में विकास तो आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है

"It must be remembered that neither technology, nor of course saving guarantee a rise in income what they do is to place in our hands the power and the ability of achieving a growing income. And just as, depending on the use made of it, any power can become a blessing or a curse, so can saving and technological progress, depending on our economic policies, result in frustration and unemployment or in an everexpanding economy"

IV Concluding Remark.

डोमर ने निराशावादी युग में लिखा वे स्थैतिक स्थिति के आने के भय से पीड़ित नहीं थे, परन्तु उनके अनुसार "आर्थिक निर्वाण न तो असम्भव है और न ही वह सुनिश्चित है" उन्हें इस बात पर बहुत अधिक आश्चर्य था कि इतने अधिक व महान पर्यवसायियों को स्थैतिक स्थिति का भय था ही क्यों

उन्होंने लिखा

"Economic salvation is not impossible, neither is it assured '' why in spite of remarkable

rapid growth the vision of the stationary state hang so heavily over the thinking of the great Masters of the last century and still preoccupies many of our contemporaries, is more than I can explain. Even my more broadminded colleagues who love growth, are willing to grant her only a reprieve, but not a pardon¹



1. Quoted from H. W. Singer's "International Growth and change" p. 8. Mc Graw Hill.

हरोड का विकास मॉडल

Harod's Growth Model

I सारांश : विकास का अर्थ

II बचतों की पूर्ति

- (a) व्याज क्यों दिया जाता है.
- (b) बचतें तीन उद्देश्यों के कारण होती हैं
- (c) स्थैतिक समाज में बचतें.
- (d) प्रवैगिक अर्थ व्यवस्था में बचतें.

III प्रमुख मान्यताएँ.

III का सारांश हरोड की तीन विकास दरों के समीकरण.

- (1) वास्तविक विकास की दर
- (II) विकास की वाछनीय दर.
- (III) विकास की प्राकृतिक दर.

इन दरों में भिन्नता तथा असंतुलन और विकास

IV. का सारांश

विदेशी व्यापार व विकास के समीकरण या खुली अर्थव्यवस्था में विकास समीकरण

हरोड मॉडल सरल भाषा में

हरोड, डोमर मॉडल की समीक्षा क्या हरोड डोमर मॉडल कम विकसित देशों में लागू हो सकता है.

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. बेन्जामिन हिगिन्स. | 5 एस० बी० मेहता. |
| 2. मीयर तथा बाल्डविन. | 6. प्रो० केनेथ के० कुरिहारा. |
| 3. सी० पी० किन्डल चरनर. | 7. इएगर. |
| 4. एच० डब्ल्यू० सिगर. | 8. ऐरिक सुडबर्ग. |

अन्य आलोचनाएँ

प्रो० जे० के० मेहता की प्रशंसात्मक समीक्षा.

हरोड का विकास मॉडल

Harod's Growth Model

“हरोड का मॉडल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों व मार्क्स के मॉडलों को भागे बताता है हरोड ने अपने मॉडल में शर्प्पाटर की बहुत सी बातों को शामिल किया उनके मॉडल में उन तत्वों का वर्णन है जो विकास कारक व विकास में बाधक हैं उन्होंने यह धारणा किया कि विकास कैसे अनियमित होता है और फिर नियमित हो जाता है”

—बेन्जामिन हिगिन्स (प्र० 144)

हरोड का विकास मॉडल उनकी पुस्तक Towards Dynamic Economics में पूर्णरूप से वर्णित है इस पुस्तक के पृष्ठ 20 पर उन्होंने साफ लिख दिया कि “मैं संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप व अन्य विकसित देशों में दिलचस्पी रखता हूँ”

I सारांश विकास का अर्थ

विकास के संबंध में उनका स्पष्ट मत है कि प्रवैगिक साम्य का उत्पन्न करना ही विकास उत्पन्न करता है वे चाहते हैं कि केन्स के “सामान्य सिद्धान्त” को प्रवैगिक अर्थशास्त्र के उपयुक्त बनाकर ही उसे विकास का सिद्धान्त बनाया जा सकता है

हरोड के विकास मॉडल में तीन प्रमुख तत्व हैं, जो इस प्रकार हैं

- (I) देश की जनशक्ति,
- (II) प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा,
- (III) उपलब्ध पूँजी की मात्रा

हरोड के अनुसार किसी भी देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन देश के (I) प्राकृतिक साधनों, (II) तकनीक व (III) अविष्कारों (जिससे उनका आशय नव प्रवर्तनों से है) पर निर्भर रहता है

हरोड के अनुसार अविष्कार तीन प्रकार के हो सकते हैं

- (1) तटस्थ अविष्कार यह वे अविष्कार होते हैं जिनमें पूँजी गुणक (Capital Co-efficient) वही रहता है अर्थात् पूँजी का उत्पादन से अनुपात वही रहता है

(11) पूंजी-वचाने वाले अविष्कार होते हैं जिनसे पूंजी-गुणक Capital Co-efficient कम होता है.

(111) श्रम वचाने वाले अविष्कार हो सकते हैं (जो वे देश प्रपनाते हैं जहाँ श्रम कम होते हैं) और इनसे Capital Co efficient बढ़ता है

II. वचतो की पूर्ति :

A. ब्याज क्यों दिया जाता है ?

हरोड कहते हैं कि बहुत पुराने दिनों में वचतो को प्रोत्साहन देने वाले ब्याज को बुरा माना जाता था बाद में ब्याज के उत्पन्न होने का मुख्य कारण 'समय पसन्दगी' बताया गया ('Time preference was put forward as explanation for emergence of interest). हरोड इस विचार को गलत मानते हैं कि 'समय पसन्दगी' ब्याज की दर निर्धारित करती है वे प्रो० पीगू के इस कथन से सहमत हैं कि यह विचार धारा 'दृष्टि दोष' के कारण उत्पन्न हुई है (It was explained as occurring due to defective telescopic faculty) वर्तमान समय पसन्दगी के तीन कारण बताये जाते थे

(1) भविष्य अनिश्चित होता है,

(11) वर्तमान की भौतिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की इच्छा बलवती होती है, तथा

(111) लालच भी 'समय पसन्दगी' उत्पन्न करता है ¹

हरोड 'समय पसन्दगी' को ब्याज निर्धारण करने वाला तत्व नहीं मानते उनका कथन है कि ब्याज तो तब ही उत्पन्न होगा जबकि कोई भी व्यक्ति भविष्य को Discount न करता हो ² हरोड का कथन है कि

"समय पसन्दगी मानव कमजोरी है. यह प्राथमिक अवस्थाओं में रहने वाले व्यक्तियों में अधिक होती है और पिछड़ी हुई सम्प्रदाय का द्योतक है " ('Time preference in this sense is a human infirmity, probably stronger in primitive than in civilized man ³ A strong time preference is indicative of a low degree of civilization)⁴

हरोड के अनुसार ब्याज को उत्पन्न करने का मुख्य तत्व उत्पत्ति हास नियम है लोग अपने धन का उपयोग तब करेंगे जबकि भविष्य में उन्हें द्रव्य की उपयोगिता अधिक नज़र आए ⁵

1. Pigon quoted from Economics of welfare p. 25.

2. See : Harrod : 'Towards Dynamic Economics' p. (i) p. 37
(ii) p. 39 (iii) p. 37 (iv) p. 53 (v) p. 40.

B : बचतें तीन उद्देश्यों के कारण उत्पन्न होती हैं.

- (1) Hump savings ये बचतें होती हैं जो कोई व्यक्ति अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए रखता है, अर्थात् बुढ़ावस्था के लिए पेंशन जैसी व्यवस्था करता है
- (ii) Inheritance saving निरामन में देने के लिए बचतें : कुछ बचतें हर व्यक्ति अपनी सतान या उत्तराधिकारियों को देने के लिए करता है
- (iii) Corporate savings औद्योगिक संस्थानों की बचतें : व्यापारिक व औद्योगिक संस्थानों द्वारा भी बचतें की जाती हैं जो कि वे अपने संस्थानों के विकास के लिए करते हैं

C : Savings in static society स्थैतिक समाज में बचतें ।

स्थैतिक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें माधनो, जनसंख्या, तकनीक, व रुचियों और आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होता

ऐसी स्थिति में Hump savings शून्य रहेगी जो व्यक्ति आज जवान है वे बुढ़ापे के लिए बचावें परन्तु बूढ़े आदमी अपनी बचतों को खर्च करेंगे और दोनों की मात्रा बराबर रहेगी ¹

Corporate या औद्योगिक संस्थानों की बचतें भी शून्य रहेगी. कुछ फर्म तो बन्द कर रही होंगी, परन्तु इनकी मात्रा उतनी ही होगी जितनी कि अन्य फर्म हानि उठा रही होंगी ²

केवल कुछ Inheritance savings उत्तराधिकार के लिए बचतें होंगी क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चों के शैशव काल की सुरक्षा चाहेगा और यह चाहेगा कि उसके बच्चे कम से कम वर्तमान जीवन स्तर तो कायम रख सकें ³

ऐसी स्थिति में स्थिर व्याज की दर पर बचतों की मांग ही नहीं होगी जो भी बचतें होंगी उनके प्रयोग में लेने के लिए निरन्तर गिरती हुई व्याज की दर की आवश्यकता ⁴ तो रहेगी गिरती हुई व्याज की दर से उत्पादनकर्ता और जटिल उत्पादन प्रणाली अपनाएंगे (more and more round-about methods of production) क्योंकि पच्ची उधार लेना सस्ता हो जाएगा इससे Corporate बचतें बढ़ेंगी और व्याज की दर और अधिक गिर जाएगी

हरोड का कथन है कि अगर व्याज की दर बढ़ा दी जाए तो बचतें कम हो सकती हैं :

इसका कारण यह है कि अगर व्याज की दर बढ़ जाए तो एक निश्चित व्याज की आय प्राप्त करने के लिए अब उपभोग में कम कटौती करनी पड़ेगी (हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं माना कि एक व्यक्ति को पाँच साल बाद 1000 रु० की आवश्यकता है और 4 प्रतिशत व्याज प्राप्त होता है तो लगभग 825 रु० जमा करके वह पाँच साल बाद 1000 रु० प्राप्त कर लेगा अब अगर व्याज की दर 6 प्रतिशत हो जाए तो लगभग 750 रु० जमा करके ही वह पाँच साल बाद 1000 रु० प्राप्त कर लेगा)

परन्तु यह प्रभाव, हरोड के अनुसार जीवन के शुरू के काल में होता है भ्रत में तो अधिक व्याज की दर पर ही अधिक बचत करने की प्रेरणा होती है भ्रत काल में ही व्याज की दर बढ़ने से बचतें कम हो सकती हैं

D : Savings In Dynamic Societies • प्रवैगिक अर्थ व्यवस्था में बचतें :

अगर अर्थव्यवस्था प्रवैगिक है जहाँ जनसंख्या बढ़ रही हो (परन्तु तकनीक स्थिर हो) तो तीनों प्रकार की बचतें बढ़ेंगी. ऐसी व्यवस्था में पूँजी की आवश्यकता बढ़ेगी, और उसीके कारण 'औद्योगिक संस्थानों' की बचतें बढ़ेंगी. जनसंख्या बढ़ने से hump savings भी अनुपातिक रूप से बढ़ेगी और अधिक वक्चों के लिए विरासत में देने के लिए भी बचतों को बढ़ाना होगा (हरोड यह सब धनी देशों के संदर्भ में कहते हैं)

ऐसी अवस्था में बचतें पूँजी की आवश्यकता से बढ़ जायेंगी और व्याज की दर गिर जायेगी परन्तु यह इतनी नहीं गिरेगी जितनी कि स्वैगिक अर्थव्यवस्था में गिर सकती है

जिस प्रवैगिक अर्थव्यवस्था में जनसंख्या व तकनीक दोनों बढ़ती हैं वहाँ भी तीनों प्रकार की बचतें बढ़ेंगी

III. The Fundamental Equations.

1 प्रमुख मान्यताएँ :

हरोड ने जो अपने समीकरण प्रस्तुत किए वे कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं, जो इस प्रकार हैं

इस प्रश्न का जर्जन हरोड की पुस्तक के पृष्ठ 49-54 पर आधारित है.

(i) हरोड यह मानते हैं कि लोग जितनी मात्रा में बचत करने का सोचते हैं उतनी ही कर लेते हैं, जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार फल प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्

(a) *Intended savings (ex-ante savings)* अपेक्षित बचत = *Actual savings (ex-post savings)*
या वास्तविक बचत

(b) *Intended investment* या अपेक्षित विनियोजन = *Actual investment* वास्तविक विनियोजन

(c) बचत और विनियोजन बराबर रहेंगे

(ii) हर उत्पादनकर्ता (पूर्तिकर्ता) या उपभोक्तार्ता (माँगकर्ता) साम्य की स्थिति का प्राप्त करना चाहता है

(iii) उन्होंने अपने माँडल को सात होने के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति के मौजूद होने की मान्यता की है

(iv) उन्होंने यह माना कि राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता

(v) उन्होंने मूल्य स्तर, व्याज की दर व पूँजी-धन अनुपात तथा पूँजी-उत्पादन अनुपात को स्थिर माना

(vi) उन्होंने विदेशी व्यापार न होने की कल्पना की अर्थात् पहले उन्होंने अपने समीकरणों को बगैर विदेशी व्यापार के परिखामों को ध्यान में रखकर लिखा, परन्तु बाद में उसका समावेश किया है

(vii) प्रगत व विनियोजनों को उसी वर्ष की आय में से होता हुआ माना तथा इनको शुद्ध रूप में (In Net terms) माना

III का सारांश

हरोड की तीन विकास दरों के समीकरण :

वास्तविक विकास की दर *Actual growth rate*.

को हरोड ने निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया है यह वह विकास की दर है जिस दर पर देश विकसित कर रहा है.

$$GC = S \quad \checkmark$$

G = यह आय में वृद्धि की दर है जो किसी निश्चित काल में उत्पन्न होती है (हम इसको $\Delta Y/Y$ से भी समझ सकते हैं (Δ का परिवर्तन होता है Y आय के लिए प्रयोग किया जाता है).

$C = C$ उस दर को बतलाती जो पूँजी-उत्पादन का सवध बतलाती है
 C is incremental capital output ratio (या $I/\Delta Y$
 या बढ़ी हुई आय (ΔY) में से विनियोजित भाग I)

$S =$ यह बचत को दर्शाता है अर्थात् आय Y में से बचाया हुआ भाग S/Y
 वास्तव में इसका अर्थ यह है कि वास्तविक बचतें और वास्तविक विनियोजन
 बराबर होंगे (Ex post savings are equal to ex post invest-
 ment)

उपरोक्त सवध आय के परिवर्तनों व आय पर निर्भर करता है बचत (S) आय
 (Y) पर निर्भर रहती है, विनियोजन (I) आय Y में वृद्धि पर निर्भर रहता है
 (on ΔY) और यहाँ acceleration principle है

2 विकास की वाछनीय दर The warranted rate of growth

हरोड ने अपना दूसरा समीकरण, जो निरन्तर विकास को उत्पन्न करने वाला है
 इस प्रकार से दिया

$$Gw Cr = S$$

‘ यह वह विकास की दर है जो कि अगर प्राप्त करली जाय तो
 साहसियों की मनोवृत्ति इस प्रकार बना देगी कि वे इसी प्रकार से
 विकास करते रहने के लिए प्रेरित होंगे ’

यह विकास की वह दर है जो कि साहसियों के लिए परम उपयुक्त है, वे इस
 विकास दर से परम सन्तुष्ट रहते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इस विकास
 दर को प्राप्त करने के पश्चात् समस्त ‘ अतृप्ति के बेरोजगारी ’ समाप्त हो जाए
 अन्य शब्दों में इस विकास की दर प्राप्त हो जाने पर भी यह बेरोजगारी बनी
 रहती है

$$Gw Cr = S$$

$Gw =$ Warranted rate of growth, विकास की वाछनीय दर
 जिसमें पूँजी का पूर्ण उपयोग हो जाता है

$Cr =$ (i) The requirement of capital for warranted
 growth or (ii) required capital-output ratio
 or (iii) The value of capital required to
 produce a unit of increment of output
 अर्थात् Gw को प्राप्त करने के लिए पूँजी की आवश्यक मात्रा

(ii) आवश्यक पूँजी-उत्पादन दर या (iii) अतिरिक्त उत्पादन को पैदा करने की आवश्यक पूँजी या Value of $I/\Delta Y$.

$S =$ आवश्यक वचत की क्षमता की मात्रा या S/Y

इस समीकरण का अर्थ है कि अगर अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास की दर से बढ़ना हो (Gw) अर्थात् उस दर से बढ़ना हो जिस दर से उत्पादन क्षमता का पूर्ण विकास हो, तो आय को S/Cr प्रति वर्ष की दर से बढ़ना चाहिए या अन्य शब्दों में $Gw = S/Cr$

पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए,

$$G = Gw \text{ और}$$

$$C = Cr$$

3. विकास की 'प्राकृतिक दर' The natural rate of growth

यह दर इस समीकरण द्वारा दर्शायी जा सकती है या इस समीकरण के प्राप्त होने पर प्राप्त होती है

$$Gn Cr = S \quad \checkmark$$

यह विकास की वह दर है जो किसी देश के लिए अधिकतम है। इसकी सीमा देश के प्राकृतिक साधनों, धर्म की उपस्थिति तथा तकनीकी उन्नति पर निर्भर रहती है

इस विकास दर को प्राप्त हो जाने पर देश में पूर्ण रोजगार कायम हो जाता है, मुद्रा स्थिति नहीं रहती तथा विकास की दर स्थिर व निरन्तर प्राप्त होती रहने वाली होती है।

~~इन~~ दरों में भिन्नता तथा असंतुलन और विकास :

- जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं हारोड का कथन है कि निरन्तर विकास के लिए $G = Gw$ और $C = Cr$ की दशाएँ सतुष्ट होना चाहिए अगर ऐसा रहेगा तो जितनी मात्रा में साहसियों की पूँजी की आवश्यकता होगी उतनी ही मात्रा में वचतें प्राप्त हो सकेंगी और इससे "प्रवेगिक साम्य की स्थिति" उत्पन्न होगी और यही निरन्तर व स्थायी विकास होगा
- अगर असंतुलन के कारण विकास बहुत तेज होता है तो वह होता चला जायेगा, और अगर मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है तो मंदी आती चली जाएगी
 - (1) अगर 'वास्तविक विकास दर,' 'वाछनीय विकास दर' से अधिक हो (If G is more than Gw) तो वास्तविक पूँजी वाछनीय

पूँजी दर से कम पड़ जाएगी, इसलिए और अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी जब और पूँजी के आर्डर दिए जाएँगे अर्थात् और मशीनों के आर्डर दिए जाएँगे तो इससे और विकास होगा अर्थात् G, Gw में और अधिक हो जाएगी जब G, Gw से अधिक हो, मुद्रा स्फीति होगी.

$$G > Gw$$

(ii) प्रमत्त G, Gw से कम हो या विकास की वास्तविक दर, वाछनीय दर से कम हो तो वास्तविक पूँजी (C) वाछनीय पूँजी (Cr) से अधिक होंगे इस कारण पूँजीगत मशीनों के आर्डर कम किये जाएँगे और इससे G की दर और गिर जायेगी तथा G, Gw से लगातार कम होती जायेगी, जब G, Gw में कम हो मशी फैलेगी

इस प्रकार से विकास साम्य पथ से एक बार हटा, अर्थात् अधिक या कम हुआ तो ऐसा होता चला जाएगा.

'Thus around the line of advance which, if adhered to, would alone give satisfaction, centrifugal forces are at work, causing the system to depart further and further from the required line of advance''

3. Gn का विचार प्रस्तुत कर के, हरोड ने विनसित अर्थ-व्यवस्था में उन्नावचन, बेरोजगारी व मुद्रा स्फीति की स्थितियों को समझाया. $Gw > Gn$

उन्होंने बताया कि अगर Gw (वाछनीय विकास दर) Gn से (विकास की प्राकृतिक दर) अधिक होती है तो मदी आएगी (इसी प्रकार में जब G, Gw से कम हो). ऐसा तब होता है जब कि जनसंख्या में वृद्धि बन्द हो जाए, तकनीकी उन्नति न हो या नये साधनों की खोज न हो

इसके विपरीत जहाँ Gw, Gn से कम हो (या दूसरे शब्दों में Gn, Gw से अधिक हो) या जहाँ G, Gn में अधिक हो तो ऐसी विकास अवस्था में तेजी आएगी.

$$Gn > Gw$$

4. परन्तु विकास के उत्तरोत्तर बढ़ने या मदी के उत्तरोत्तर बढ़ने की सीमाएँ होती हैं. हरोड के अनुसार

(i) G, Gn से ऊपर, बहुत अधिक मदी के काल को छोड़, नहीं जा सकती.

- (11) जब G , G_n तक पहुँच जाती है तो ऐसे समय में G_w भी बढ़ जाती है.
- (111) इसी प्रकार से एक न्यूनतम सीमा से नीचे अर्थव्यवस्था नीचे नहीं जा सकती विकास शून्य की सीमा तक कभी नहीं पहुँच सकता क्योंकि पूँजी निर्माण कभी शून्य नहीं हो सकता जब G या वास्तविक विकास दर बहुत नीचे आ जाती है तो साहसियों का प्राकृतिक साधनों सबधी ज्ञान उन्हें बचाने करा देता है कि यह व्यवस्था अब और नीचे नहीं गिर सकती विकास सम्बन्धी अनुमाना में फिर उनमें आशावाद आने लगता है और फिर विकास स्तर ऊपर उठने लगता है.

हरोड के अनुसार पूर्ण रोजगार साम्य की अपेक्षित स्थिति $G_n = G_w = G$ होना चाहिए हरोड के मॉडल का सारांश यह है कि मुद्रा स्फीति के दिनों में S घटाना चाहिए (बचत अच्छी चीज है) तथा मंदी के दिनों में बचत बढ़ाना या 'S' घटाना चाहिए

IV का सारांश

— विदेशी व्यापार व विकास के समीकरण या खुली अर्थ-व्यवस्था में विकास समीकरण *Foreign trade and fundamental equations or fundamental equations for an open economy.*

रोड ने "विदेशी व्यापार न होने" की मान्यता को बाद में हटाया. तत्पश्चात् उन्होंने समीकरणों को यह रूप दिया

$$(I) \quad G_c = S - b$$

$$(II) \quad G_w Cr = S - b$$

$$(III) \quad G_n Cr = S - b.$$

'b' से यहाँ पर विदेशी व्यापार के भुगतान सन्तुलन का अर्थ लिया जाता है. एक ऐसे देश में जहाँ G_w , G_n से अधिक रहता है वहाँ मंदी व्यापक हो जाती है ऐसे समय 'b' अगर घनात्मक हो अर्थात् भुगतान सन्तुलन पक्ष में हो तो इस मंदी को दूर करने में मदद मिलती है. इससे G_n बढ़ती है या G_w कम होती है और सन्तुलन व स्थिर व निरन्तर विकास संभव होता है.

जिन देशों में मुद्रा स्फीति है व 'b' वे ऋणात्मक होने से अतिरिक्त क्रय शक्ति विदेशों में चली जाएगी या वस्तुएँ वहाँ से आ जाएगी.

हरोड का कथन है कि "मेरी प्रणाली में निर्यात का प्रभाव रोजगार पर लाभ-दायक पाया जाएगा."

निर्यात का विकास किन तत्वों पर निर्भर है :

1. अगर देश के निर्यात अधिक होने हैं तो विकास अधिक हो सकता है एक देश की निर्यात करने की क्षमता वास्तव में दूसरे देशों की आयात करने की क्षमता पर निर्भर है. हरोड बतलाते हैं कि वहुधा जो अमेरिका के निर्यात कम हो जाते हैं उसका कारण यह है कि आयात करने वाले देशों के पास धन कम हो जाता है.
2. अगर किसी देश में उन वस्तुओं के उत्पादन वृद्धि की मात्रा, जिनके उत्पादन में देश को लागत में तुलनात्मक लाभ है, देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की मात्रा से, अधिक होगी तो निर्यात वृद्धि की मात्रा राष्ट्रीय आय की वृद्धि से अधिक होगी.
3. निर्यात वर्धन के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के अग्रे को पुरस्कार दिए जाएँ (लाभ को छोड़कर) वे आय में जो वृद्धि हो उससे इनके बढ़ने की दर कम हो. इससे लागतें नहीं बढ़ेंगी और भुगतान सन्तुलन बढ़ेगा
4. हरोड के अनुसार, अगर राष्ट्रीय आय के गैर-लाभ भाग (Non-profit rewards) (अर्थात् लगान, व्याज व मजदूरी) बहुत अधिक होंगे तो आयातीत वस्तुएँ घर में बनी वस्तुओं से सस्ती होगी और गृह-उत्पादन की बहुत सी कार्यों विदेशी उत्पादनकर्ताओं के पक्ष में वन्द हो जाएगी तथा देश के बहुत से विदेशी बाजार समाप्त हो जाएंगे
5. हरोड का कथन है कि विश्व में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ वचते लगभग नहीं के बराबर हैं जबकि बहुत से धनी देशों में यह वचते आवश्यकता से अधिक हैं "इन परिस्थितियों में पूँजी की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता से G_n (विकास की प्राकृतिक दर) बढ़ जाएगी यह आशा की जा सकती है कि जन पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिशील होनी तो "तकनीकी ज्ञान व जानकारी" भी इन धनी देशों से निर्यात की जाएगी."
6. हरोड ने कम-विकसित देशों को सहायता देने में न केवल इन कम-विकसित

See : 1. Benjamin Higgins op cit p 157-158

2 Harrod op cit p 103, 108 & 109

as also all pages between 103-116

देशों की भलाई देखी वरन् इसमें विकसित देशों को भी लाभ है परन्तु इन सब के होने हुए भी उन्होंने कुछ हानियाँ भी बतलाई हैं, जो इस प्रकार हैं :

(1) बहुत अधिक जनसंख्या वाले देशों में विदेशी सहायता मिलने से जन-संख्या और बढ़ सकती है

(II) कुछ कम-विकासित देशों में राजनैतिक अस्थिरता के कारण पूँजी डूब सकती है क्योंकि यह देश पूँजी वापिस करने में धोखा कर सकते हैं

निष्कर्ष में हरोड भूतान सन्तुलन के पक्ष में होने को विक्राम में बहुत सहायक मानते हैं, और व्यापार चक्रों को ठीक करने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं.

हरोड मॉडल "सरल भाषा" में (Harrodian Model in Common language

1. हरोड के अनुसार "प्रवैशिक साम्य" की स्थितियों को उत्पन्न करना ही विकास को उत्पन्न करना व बढ़ावा देना है
2. हरोड के मॉडल में विकास चारक घटकों के रूप में वचत, पूँजी, विनियोजन, उत्पादकता व आय का मुख्य स्थान है. वे अपने मॉडल में इन घटकों के सह-संबंध पर प्रकाश डालते हैं. वे अपने मॉडल में यह बताना चाहते हैं कि एक बार पूर्ण रोजगार में आयी अर्थ व्यवस्था में स्थायी विकास कैसे लायक रह सकता है और किस प्रकार से देश की वचतों व उत्पादन क्षमता को पूर्ण रूप में प्रयोग में रखा जा सकता है
3. हरोड ने बताया कि जब वचतें बढ़ती हैं तो विनियोजन बढ़ता है, अधिक विनियोजन से आय बढ़ती है (उत्पादकता दबने से या Through incremental capital-output ratio) इससे और वचतें बढ़ती हैं और फिर यह क्रम चलता रहता है इस प्रकार से विकास चक्रवृद्धि व्याज की भाँति बढ़ता रहता है
4. हरोड के अनुसार विकास की दर = वचत दर \times पूँजी - उत्पादन दर अन्य शर्तों में विकास दखाना हो तो या तो वचत दर बढ़ाया जाना चाहिए या पूँजी-उत्पादन दर घटाया जाना चाहिए (इसका अर्थ होता है अधिक उत्पादन के लिए कम पूँजी की आवश्यकता) यह दोनों दरें ही विकास पथ निर्धारित करती हैं.
5. हरोड के विश्लेषण के अनुसार अगर किसी देश में प्रति वर्ष वचतों की मात्रा 12% हो, पूँजी-उत्पादन दर 3% हो, जनसंख्या वृद्धि 2% हो, तो अर्थ व्यवस्था 2% प्रति वर्ष की दर से विकास कर सकती है

6 हरोड के अनुसार माँग की अधिकता या नमी से विकास पथ से अर्थ व्यवस्था हट जाती है एक बार जब अर्थ व्यवस्था साम्य की स्थिति से हट जाती है तो पुन उसी साम्य की स्थिति में नहीं आती, बरन् एक नए साम्य की स्थिति पर पहुँच जाती है. हर नया (पर ऊँचा) साम्य विकास पथ पर ले जाता है. हरोड ने मदी व तेजी के व्यापार चक्रों को विकास कारक बताया

7 उच्चा-वचनो की अधिकतम व न्यूनतम सीमाएँ होती हैं (a) अगर देश में आय तेजी से बढ़ने लगती है तो तेजी शुरू हो जाती है फिर और अधिक विनियोजन होता है और आय बढ़ती है और यह क्रम वहाँ तक चलता जाता है जहाँ तक कि उसकी सीमा नहीं आ जाती है या स्वयं यह सीमा और ऊपर नहीं उठ जाती यह सीमा देश में अर्थ व प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है. (b) अगर आय धीमे बढ़ना शुरू होती है तो बगैर बिक्री चीजें रहने लगती हैं जिनके कारण विनियोजन और कम हो जाता है और फिर विकास पथ मदी की ओर बढ़ जाता है, जब तक कि वह न्यूनतम सीमा पर पहुँच कर फिर ऊपर नहीं आता. न्यूनतम सीमा पूँजी निर्माण की न्यूनतम मात्रा पर निर्भर है, और पूँजी निर्माण की मात्रा शून्य नहीं हो सकती.

हरोड डोमर मॉडल की समीक्षा क्या हरोड डोमर मॉडल कम-विकसित देशों में लागू हो सकता है ?

हरोड मॉडल की अलग अलग अर्थ शास्त्रियों ने अलग-अलग समीक्षा की है. कुछ ने तो इसे सराहा है और कुछ ने इसे जटिल व गलत बताया है. हम अलग-अलग अर्थ शास्त्रियों के दृष्टिकोणों को अध्ययन करेंगे

बेन्जामिन हिगिन्स :

हरोड का मॉडल चक्र विरोधी नीति के मवर्ष में महत्वपूर्ण विवेचना करता है और सामाजिक आर्थिक नीतियों पर महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत करता है

(परन्तु) इस मॉडल के बीच के अध्याय "ढरावने रूप से कठिन है" ... हरोड की एक सादर समझाने के लिए कभी कभी पूरा लिखना पड़ता है परन्तु अगली लाइन समझाना फिर आसान कार्य नहीं होता.¹

बेन्जामिन हिगिन्स का कथन है कि हरोड का विश्लेषण बहुत ही सामान्य (General) है. इस कारण यह हर जगह लागू किया जा सकता है और कहीं भी उपयुक्त नहीं होता

हरोड का मॉडल हमें बहुत से तथ्य नहीं देता यह मॉडल तो पूर्ण रूप से विकास के सब घटकों में सह-संबंध भी नहीं समझाता. इनके मॉडल में राज्य की क्रियाओं का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, अध्ययन ही नहीं किया जाता ¹

मीयर तथा वाल्डविन :

मीयर और वाल्डविन के अनुसार हरोड मॉडल में कुछ अवास्तविक मान्यताएँ हैं, उदाहरणतः पूँजी-उत्पादन अनुपात तथा वचत अनुपात को हमेशा निश्चित मानना और उसमें वृद्धि व कमी की अपेक्षा न करना अवास्तविक है.

दूसरी नुति पूर्ण बात यह है कि इसमें “विकास पर मृत्यो के परिवर्तनों को” ध्यान में नहीं रखा गया हरोड ने अपने मॉडल में यह मान लिया कि एक बार मूल्यों में परिवर्तन आता है तो या तो मूल्य बढ़ते ही जाते हैं या घटते ही जाते हैं परन्तु वास्तव में “मूल्य परिवर्तन स्वयं ही स्थिरता ले आते हैं” (जैसे मूल्य बढ़ने से पूँति घटेगी या माँग कम होगी और मूल्य स्वयं कम हो सकते हैं) ²

सी. पी. किन्डलर वरजर :

किन्डलर वरजर के अनुसार हरोड डोमर का मॉडल तकनीक में परिवर्तन होने में विकास में जो परिवर्तन होते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखना इनका विश्वास है कि यह मॉडल व्यावहारिक रूप में सही नहीं पाया गया है. इस मॉडल में यह बताया गया है कि अगर पूँजी-उत्पादन दर स्थिर रहे और उसके बाद पूँजी की विनियोजन दर बढ़ा दी जाए तो विकास हो सकता है, परन्तु कभी कभी पूँजी के स्थिर रहने पर विकास हो जाता है. केवल पूँजी ही विकास कारक नहीं है.

“Growth as observed in concrete situation proceeds faster than can be accounted for by the rate of inputs of capital with a constant capital-output ratio, The theory can be saved by allowing the capital-output ratio to change, but then it ceases to be a theory and becomes a mere tautology.” ³

किन्डलर वरजर ने बताया कि हरोड-डोमर का मॉडल Moses Abramovitz और Robert Solow के अनुसार ऐतिहासिक रूप से सत्य साबित नहीं हुआ

1. p 165-66.

2. Meier & Baldwin - op cit - p 114

3. C. P. Kindleberger - op cit: p 4, 49-53.

हैं उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी विकास हुआ है वह केवल पूँजी की अधिकता या पूँजी-उत्पादन की कमी है वरन् अन्य महत्वपूर्ण घटक शिक्षा, तकनीकी उन्नति, साहसियों की कुशलता व पर्याप्तता व राज्य की उचित नीति रहे हैं।

एच. डब्ल्यू. सिंगर.¹

सिंगर का कथन है कि हरोड-डोमर मॉडल विकसित देशों के लिए "भाशा-बादी मॉडल है, परन्तु कम-विकसित देशों के लिए इस मॉडल से निराशावादी विचार सामने आते हैं। इन देशों में जो अधिक जन संख्या वृद्धि हो रही है उसके कारण हरोड-डोमर के parameters (गणित की स्थिर राशियाँ) से हम दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार से इन देशों में cumulative self-sustaining stagnation या निरन्तर बनी रहने वाली स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर इन देशों में शुद्ध विनियोजन 6% से बढ़ रहा हो, पूँजी-उत्पादन अनुपात 3 : 1 हो और जनसंख्या वृद्धि 2% प्रति वर्ष हो, तो हरोड-डोमर समीकरण हमको बताएंगे कि, जब तक कुछ अनुकूल घटक उत्पन्न नहीं होते, तब तक अर्थ व्यवस्था बुरी तरह से स्थिरता की अवस्था में रहेगी। यह अनुकूल परिवर्तन या तो जनसंख्या के बढ़ने की दर में कमी या पूँजी-उत्पादन दर में कमी हो सकती है।

एस. बी. मेहता :

श्री मेहता के अनुसार, हरोड-डोमर की जो मान्यताएँ हैं उनके अध्ययन से ही साफ जाहिर है कि ये मॉडल कम-विकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं है ये मॉडल तो यह बताते हैं कि विकसित देशों में जब पूर्ण रोजगार की अर्थ-व्यवस्था कायम हो जाय तो यह स्थिति कैसे कायम रह सकती है कम-विकसित देशों में मुख्य समस्या तो पहले पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँचना ही है। इन देशों में "वाछनीय विकास दर" (Warranted rate of growth) को प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण तो (Forced rate of growth) या "यत्न-पूर्वक कार्यों द्वारा विकास की दर" होती है

श्री मेहता के अनुसार "वाछनीय विकास दर" को प्राप्त करना तो तब महत्वपूर्ण होगा जबकि कम-विकसित अर्थ-व्यवस्था, विकसित अर्थ-व्यवस्था बन जाए²

1. H. W. Singer : op. cit : p 8.

2. S. B. Mehta : I. E. A's Annual no-on Growth, op cit.

प्रो० बेनेथ के कुरिहारा :

प्रो० कुरिहारा का कथन है कि हरोड-डोमर का मॉडल "अनैच्छिक या मंदी की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपयुक्त हो सकता है परन्तु कम विकसित देशों की मरचना सखी बेरोजगारी" को दूर करने के लिए यह मॉडल उपयुक्त नहीं है।

हरोड-डोमर मॉडल में वृद्धि की कमी की कल्पना नहीं की गई है परन्तु इन देशों में पूँजी निर्माण की कमी ही इस मॉडल की अनुपयुक्तता सिद्ध कर देती है।

प्रो० कुरिहारा का कथन है कि यह मॉडल तो उन्हीं कम-विकसित देशों में कुछ उपयुक्त हो सकता है जहाँ "संतुलित विकास" व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजी-उत्पादन अनुपात तथा वृद्धि-आय अनुपात एक योजना काल में स्थिर रहते हो, अन्यथा नहीं।¹

इएगर : L. B. Yeager

इएगर का कथन है कि हरोड के मॉडल की "वाछनीय विकास दर" क्या होगी इसका पता लगाना असंभव है वे हरोड के इस मत से भी सहमत नहीं हैं कि विकास की अधिकतम सीमा श्रमकी मात्रा व प्राकृतिक साधनों पर निर्धारित है। विकास की सीमा इन स्थंगिता तत्वों पर निर्भर नहीं रहती बल्कि उद्घाटन की प्रवृत्ति, तकनीक तथा संगठन विकास की सीमा निर्धारित करते हैं।

एरिक लुडवर्ग : Eric Lundberg

एरिक लुडवर्ग के अनुसार हरोड मॉडल में पूँजी को ही विकास का एजेंट बताया गया है। परन्तु उन्होंने नाथे व थू० एस० ए० के विकास का अध्ययन करके यह बताया कि तकनीकी अनुमान प्रशासन व शिक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हरोड मॉडल में इन तत्वों तथा मूल्यों के परिवर्तनों, व्याज की दरें, मुद्रा धातु की स्थितियों, तथा साहसियों के कार्यों को शामिल नहीं किया।

अग्र्य आलोचनाएँ :

हरोड मॉडल की अन्य मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :

1. हरोड ने यह मान्यता की है कि राज्य विकास में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और न पहल करेगा। कम-विकसित देशों के लिए यह बात ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ तो राज्य ही विकास शुरू करने में पहल करता है और बाँकर राज्य की सहायता के विकास संभव ही नहीं हो सकता।

2. हरोड मॉडल में जो यह माना है कि एक बार देश (Steady growth path) सतत व नियमित राह से हटता है तो हटता ही जाएगा, यह बात हमेशा सत्य नहीं हो सकती।
3. कम-विकसित देशों में पूँजी-उत्पादन व वचन-आय दरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं जबकि इस मॉडल में उन्हें स्थिर माना है।
4. यह मॉडल चर्मीय बेरोज़गारी को दूर करने में महत्वपूर्ण मार्ग-दर्शन कर सकता है, परन्तु घटती विकसित देशों की संरचना संबंधी, दीर्घ स्थायी व स्वाभाविक बेरोज़गारी को दूर नहीं किया जा सकता।

प्रोफेसर जे० के० मेहता की प्रशंसात्मक समीक्षा : ✓ +

प्रोफेसर जे० के० मेहता हरोड के मॉडल की मान्यताओं को मोटे मोटे रूप से वास्तविक मानते हैं। उनके अनुसार यह मान्यताएँ भले ही पूर्ण रूप में सही न हो परन्तु वे विवेक शून्य नहीं हैं। वे हरोड को विकास मॉडलों की बनाने का प्रवर्तक मानते हैं प्रो० जे० के० मेहता, हरोड के मॉडल को, कुछ अपवादों को छोड़, व्यवहार में लागू किया जा सकता है, कहते हैं।

प्रो० मेहता का कथन है कि हरोड का मॉडल “विकास मॉडल” तथा “चक्र-विरोधी” मॉडल दोनों है उनका मॉडल यह बताता है कि आय वयो बढ़ती है या घटती है, यह ‘विकास मॉडल’ है यह मॉडल यह भी बताता है कि ‘असाम्य’ की स्थिति वयो होती है और कैसे यह असाम्य और खराब हो जाता है।

किसी भी देश में अवनति, उन्नति व उच्चा-वचन विकास प्रक्रिया के ही अंग होते हैं। “Fluctuations are disappointed growth or decline tendencies” अर्थात् उच्चावचन विकास या गिरावट की विफल प्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रो० मेहता के अनुसार हरोड ने अपने मॉडल में खूब अच्छी तरह समझाया है।

अध्याय : 17

नक्स का विकास मॉडल

Nurk's Economic Growth

1. प्रस्तावना :
2. दुश्चक्र को तोड़ने के लिये सन्तुलित विकास आवश्यक है.
3. सन्तुलित विकास के लिये अतिरेक जनशक्ति का पूँजी निर्माण के लिये उपयोग.

अध्याय : 18

ल्युस मॉडल : असीमित श्रमशक्ति के प्रयोग से विकास का मॉडल

**Lewis Model . Growth With Unlimited
Supply of Labour**

- 1 प्रस्तावना
 - (1) ल्युस के अनुसार कम-विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएँ
2. विकास के लिये क्या कर ?
 - (1) श्रमशक्ति को इकट्ठा करना
 - (II) इन्हें काम देने के लिये "जीवन निर्वाह योग्य" मजदूरी देकर काम देना चाहिये
 - (III) अब पूंजी निर्माण करना चाहिये
 - (IV) पूंजी निर्माण बढ़ाने के लिये देश में मुद्रा स्फीति फैलाना चाहिये
- 3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली अर्थ व्यवस्था व उनका मॉडल
- 4 उपसंहार
 - (1) ल्युस मॉडल की समालोचना

ल्युस मॉडल : असीमित श्रमशक्ति के प्रयोग से विकास का मॉडल

Lewis Model Growth With Unlimited
Supply of Labour

1. प्रस्तावना

प्रो० आर्थर ल्युस ने अपने एक लेख 'Economic development with unlimited supply of labour' में विकास की रीति पर अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने इस मॉडल में कम विकसित देशों की समस्याएँ, विशेषताएँ तथा विकास की ध्युह रचना की व्याख्या की. उनके अनुसार उनका मॉडल Modified classical model या परिवर्तित प्रतिष्ठित मर्थशास्त्रियों का मॉडल है

ल्युस के अनुसार कम विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएँ :

ल्युस ने बतलाया कि उन कम विकसित देशों में जहाँ बहुधा जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है वहाँ कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी से पीड़ित रहते हैं और कई व्यक्तियों की सीमान्त उत्पादकता शून्य रहती है ऐसे देशों में श्रमिकों की माँग से उनकी पूर्ति अधिक रहती है और हम इसको "असीमित श्रमशक्ति" कह सकते हैं

ऐसे कम विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में 'दुहरापन' पाया जाता है. इन देशों में एक तो Capitalist sector पूँजीवादी क्षेत्र होता है और दूसरा Subsistence sector या 'पिछड़ा प्राथमिक क्षेत्र' होता है प्रथम में पूँजी, उत्पाद-

"Economic Development with Unlimited Supply of Labour."

W. A. Lewis.

— Reproduced in A. N. Agarwal & Singh - op. cit. p 400-50.

— " " Bernard okun and richard W. richard son's
"Studies in economic development" Holt,
rinehat & winston. 1965 p 292 onwards.

कता व आय अधिक रहती है और दूसरी में कम रहती है. इन देशों में "There are islands of development in the sea of stagnation" अर्थात् पिछड़ेपन के समुद्र में विकास के कुछ द्वीप मौजूद रहते हैं अर्थात् इन देशों में छोटे छोटे खेतों पर पिछड़े किस्म की खेती के साथ साथ उन्नत व बड़े बड़े कृषि फार्म भी मौजूद होते हैं उसी प्रकार छोटे छोटे उद्योगों के बीच उन्नत व आधुनिकतम उद्योग भी मौजूद रहते हैं इन देशों में भी कुछ सूभ्रूभ वाले तथा साधनयुक्त साहसी मौजूद रहते हैं जो कुछ ही उद्योगों में ही पूँजी लगाए रहते हैं इन देशों में अशिक्षित, अश्विश्वासी तथा पिछड़े व अकुशल व्यक्तियों के बीच बहुत मुशिक्षित, आधुनिक व कुशल व्यक्ति मौजूद रहते हैं विकसित क्षेत्र में आधुनिकरण की चाह रहती है पिछड़े क्षेत्र में नहीं रहती

2. विकास के लिए क्या करें ?

त्युस के अनुसार अगर इन देशों में विकास करना है तो यह देश अपनी "असीमित श्रम शक्ति" का पूर्ण प्रयोग कर के ही विकास कर सकते हैं. इसके लिए त्युस निम्नलिखित उपाय सुभाते हैं.

(1) श्रमशक्ति को इकट्ठा करना

1. सर्वप्रथम कम विकसित देशों में स्त्रियों की शक्ति को प्रयोग में लाना होगा. इनमें से बहुत सी तो गृह कार्यों में लगी रहती हैं परन्तु उनकी क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं होता.
2. दूसरे हमको उन व्यक्तियों को भी काम पर लेना होगा जो आज बेरोजगार हैं, या जो अर्ध-बेरोजगारी तथा छद्मवपी बेरोजगारी से पीड़ित हैं तथा जो छोटे भिमान या दुयानदार के रूप में (बगैर आर्थिक लाभ के) कार्य कर रहे हैं.
3. इसी श्रम शक्ति के reserve या योग में बढ़ती हुई जनसंख्या के लोगों को शामिल किया जा सकता है.

हमको इनका अनुमान लगाकर इन्हें अब काम देना होगा.

(11) इन्हें काम देने के लिए "जीवन निर्वाह योग्य" मजदूरी देकर काम देना चाहिए.

त्युस ने अपने विकास योजना के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की योजना को अपनाया है. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की योजना थी कि "असीमित श्रम शक्ति" के

Lewis का यह मॉडल Nurkse के मॉडल से मिलता हुआ पाया जाएगा.

प्रयोग के लिये देश में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी देकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है। बाद में नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस मॉडल को छोड़ दिया था क्योंकि योरोप में "जीवन निर्वाह" बराबर मजदूरी मान्य नहीं थी। केन्स ने "Current rate of wages" पर (या वर्तमान मजदूरी पर) कार्य देने को कहा था ल्युस का कथन है कि कम-विकसित देशों में बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारी की मौजूदगी के कारण जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी ही देना ठीक होगा परन्तु इस विचार में वे सशोभन भी करते हैं वे कहते हैं कि शहरो में जीवन निर्वाह व्यय चूँकि अधिक होता है इसलिए भावास, यातायात व अन्य व्ययों को पूरा करने के कारण पूँजी क्षेत्र में मजदूरी 30 प्रतिशत तक अधिक हो सकती है।

(III) अब पूँजी निर्माण किया जाना चाहिए.

ल्युस के अनुसार अब देश में पूँजी निर्माण की आवश्यकता होगी ल्युस का कथन है कि मुख्य समस्या यह है कि किस प्रकार से यह 4 या 5 प्रतिशत बचत करने वाले देश अपनी राष्ट्रीय आय का 12 से 15 प्रतिशत बचत करने लगे ल्युस कहते हैं कि कम विकसित देशों में लगभग 90 प्रतिशत व्यक्ति तो बचत कर ही नहीं पाते, बचत तो इन देशों के वे धनी व्यक्ति (लगभग 90 प्रतिशत) करते हैं जो देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत भाग प्राप्त करते हैं।

पूँजी निर्माण बढ़ाने के लिए इन्हीं धनी व्यक्तियों की आय बढ़ायी जाना चाहिए

(IV) पूँजी निर्माण बढ़ाने के लिए देश में मुद्रा स्फीति फैलाना चाहिए.

ल्युस का कथन है कि कम-विकसित देशों में पूँजी निर्माण देश में मुद्रा स्फीति फैला कर किया जा सकता है। राज्य को चाहिए कि वह देश में नई मुद्रा छाप कर देश में मूल्य वृद्धि होने दे। ऐसे समय में मजदूरी के स्तर बढ़ने नहीं देना चाहिए और जो मूल्य वृद्धि से धनी व्यक्तियों को, विशेष रूप से उत्पादन कर्ता वर्ग को लाभ हो उन्हें उन व्यक्तियों को प्राप्त करने दिया जाना चाहिए।

ल्युस का कथन है कि इस प्रकार की मुद्रा स्फीति से देश को दीर्घकाल में कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार की मुद्रा स्फीति Self Liquidating या स्वयं समाप्त हो जाने वाली होगी ल्युस का कथन है युद्ध के काल में हीनार्थ प्रवर्तन

Lewis के अनुसार पूँजी निर्माण No. of workers to be provided with work X Amount equal to subsistence wages पूँजी निर्माण की मात्रा होगी.

से जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है वह स्वयं समाप्त नहीं होती परन्तु विकास के लिए की जाने वाली यह मुद्रा स्फीति स्वयं समाप्त हो जाएगी. उसके उन्होंने निम्नलिखित कारण बतलाए.

- (i) सर्व प्रथम तो उत्पादनवर्ता बढ़े हुए मूल्य पर अधिक कमा कर अधिक विनियोजन करेंगे और इसमें उत्पादन बढ़ेगा और मूल्य कालान्तर में गिर जाएंगे. और
- (ii) दूसरे राज्य की वस्तु से भाव बढ़ जाएगी और राज्य को बाह्य में हीनार्थ प्रबन्धन नहीं करना पड़ेगा.

ल्युस इस प्रकार की योजना का एक उदाहरण देने हैं

“माना कि £ 100 के विनियोजन करने से एक वर्ष में £ 20 का लाभ होता है, जिसमें से माना कि £ 10 प्रति वर्ष बचा लिया जाता है. अब अगर हम विनियोजन को पुँजीपति साख निर्माण से करते हैं तो ग्यारहवें (11 वें) साल के शुरू होने पर कुल लाभ £ 200 प्रति वर्ष से बढ़ जाएँगे और हर वर्ष £ 100 अधिक बचते हुआ करेगी, और देश की मुद्रा पर कोई दबाव नहीं रहेगा. हम घटना का अतः केवल इतना रहेगा कि देश में £ 1000 की अधिक पुँजी हो जाएगी अगर भास निर्माण नहीं किया गया होता तो देश में यह सब नहीं होता ”

ल्युस यह मानते हैं कि इस नीति से गरीबों के सामने कठिनाइयाँ आएँगी, परन्तु इससे उन्हें रोजगार मिलेगा और कालान्तर में उनकी वे कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी

3. His Model in Open Economy : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली अर्थ व्यवस्था व उनका मॉडल .

ल्युस ने कहा कि कम विकसित देशों को यह मॉडल अपनाने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भुगतान समस्या सामने आएगी. पहले ही यह देश प्रतिकूल भुगतान संतुलन के शिकार रहते हैं. यह समस्या इस नीति से और बढ़ सकती है जैसे (i) मुद्रा-स्फीति से देश में जो मूल्य वृद्धि होगी उसमें विदेशी विनिमय दर गिरेगी. अथवा (ii) उससे निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित होंगे. (iii) अगर राज्य में राजनैतिक हिंसा न हो तो वह पर्याप्त मात्रा में कर न लगा सकने की स्थिति में देश में धन की प्रमत्तताओं में वृद्धि कर देगी.

इसलिए ल्युस का कथन है राज्य को विदेशी विनिमय पर बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और विदेशों से आर्थिक सहायता या ऋण प्राप्त करना चाहिए.

4. उपसंहार

त्युस का दावा है कि अगर इस मॉडल को अपनाया गया तो देश में पूँजी निर्माण के लिए उपभोग घटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी (जैसी कि नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल में की गई थी) इस प्रकार से पूँजी निर्माण किया जाएगा तो उपभोग वस्तु उद्योग व भारी उद्योग एक साथ फलप सकते हैं।
त्युस ने यह भी बताया कि

“विक्रम की यह प्रक्रिया उस समय समाप्त हो जाएगी और यह नीति उस समय कारगर नहीं रहेगी जबकि पूँजी निर्माण की वृद्धि मात्रा व दर जनसंख्या की वृद्धि दर के बराबर हो जाएगी। अगर मजदूरी बढ़ने दी गई तो यह नीति और पहले ही कारगर नहीं रहेगी।”

* Critique of lewis model त्युस मॉडल की समालोचना :

त्युस मॉडल की अगर हम समालोचना करें तो हम इस मॉडल में बहुत सी कमियाँ पाएंगे इन कमियों में मुख्य निम्नलिखित हैं

- 1 Shult तथा Leibenstein यह नहीं मानते कि कम विकसित देशों में धर्म की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है, उनका कथन है कि अगर ऐसा होता तो मजदूरी दरे भी लगभग शून्य पर आजाती। इस कारण यह पता लगाना कठिन है कि कितने लाग Surplus या आवश्यकता से अधिक है।
2. दूसरी कठिनाई जो इस मॉडल की कार्यान्वित करने में आएगी वह यह है कि “अतिरेक (Surplus) जनसंख्या” की शहरो में ले जाना आसान नहीं होगा। कम विकसित देशों में जनना इतनी गतिशील नहीं होती जाती व धर्म के बन्धन के कारण व्यवसायिक गतिशीलता कम रहती है। भाषा, जन का अभाव, आवास की समस्या, जल्माह की कमी, स्थान व वातावरण से प्रेम आदि के कारण भौगोलिक गतिशीलता कम रहती है। बुशालता के अभाव, प्रशिक्षण की कमी, व अवसर की समानता न होने से horizontal (चैतिज) व Vertical (खड़ी) गतिशीलता कम रहती है। इस मॉडल को कार्यान्वित करने में पहले बृहत् मात्रा में ट्रेनिंग सुविधाओं को बढ़ाना होगा।
3. तीसरे आज कम विकसित देशों में “जीवन निर्वाह” के बराबर मजदूरी देते रहना संभव नहीं है। आज के युग में सम्पूर्ण विकास क्रिया काल में

* Based on Dr. A C Minocha's Paper : "Capital formation in under developed countries—Validity of lewis model" Later published in I E J Vikram university Economists Seminar at Bhopal in 1966

श्रम जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी पर कार्य नहीं करेगा। वह भी बढ़ती हुई महंगाई का मुआवजा मांगेगा और वह भी लाभ में अपने हिस्से की मांग करेगा। आज श्रम आंदोलन, श्रम सघों की मौजूदगी व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ की मौजूदगी के कारण “न्यूनतम मजदूरी” से लेकर श्रम कृत्याण के बहुत से महत्वपूर्ण नियम मौजूद रहते हैं। ये आजकी सामाजिक व राजनैतिक दशा में हटाए नहीं जा सकते। इस कारण त्युस का ‘जीवन निर्वाह’ के बराबर मजदूरी देते रहकर पूंजी निर्माण करके विकास करना संभव नहीं होगा।

4. चौथी आलोचना यह की जा सकती है कि कम-विकसित देशों के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की माँग इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, जितनी तेजी से कि कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रमिकों को काम देना पड़ेगा। हमको चाहिए कि हम कृषि क्षेत्र को भी सम्पूर्ण रूप से विकसित करें।
5. पाँचवी : कम-विकसित देशों में कृषि क्षेत्र कृषि में रत व्यक्तियों को वह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जो औद्योगिक क्षेत्र प्रदान नहीं करता। इस कारण कृषि क्षेत्र से श्रमिकों के निकलने की प्रवृत्ति लोचदार नहीं होती, अर्थात् मूल्य या मजदूरी वृद्धि के अनुरूप नहीं होती।
6. छठी : कुज़नेट्स ने बताया है कि कम-विकसित देशों में धन की असमानताएँ पहले से ही अधिक होती हैं और त्युस मॉडल को अपनाने से ये और बढ़ जाएँगी। प्रो० मीयर और बाल्डविन के अनुसार “धन की असमानताएँ बढ़ने से ही उत्पादक विनियोजन में वृद्धि नहीं हो जाती, क्योंकि कम-विकसित देशों में वचत करने वाले बहुधा ज़मींदार और अन्य पूँजीपति होते हैं। ये व्यक्ति अपने धन को भूमि के सट्टे, अन्य सट्टे तथा सामान व सोना-चाँदी के संचय में लगा देते हैं।
7. सातवी : श्री एस० जे० पटेल तथा यू० एन० श्रो० के विश्व सम्मेलन 1960 के अनुसार, त्युस की यह धारणा गलत है कि कम-विकसित देशों में केवल धनी व्यक्ति ही वचत करते हैं जापान, बर्मा, बांगो आदि देशों में कम आय वाले भी वचत करते पाए गए हैं जब कि अन्य कम-विकसित देशों में जैसे चिली, प्यूरटो रिको में अधिक आय वाले भी कम वचत करते पाए गए।
8. आठवी : कम-विकसित देशों में कुशल साहसियों का सर्वथा अभाव होता है जब ये साहसी नहीं होंगे तो अतिरिक्त जनशक्ति को प्रयोग में लाकर विकास करना सम्भव नहीं होगा।
9. नवी : त्युस ने अपने मॉडल में ऐसे Corporate sector की कल्पना की

है जो अधिक लाभ कमा कर उसे पुन विनियोजित कर देता है परन्तु कम विकसित देशों में यह क्षेत्र बहुत सीमित होता है भारत में 1958-59 में इस क्षेत्र ने देश की राष्ट्रीय आय का केवल 2.8% भाग उत्पन्न किया अधिकतर वचतें 'घरेलू क्षेत्र' से आईं. स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र व बड़े औद्योगिक क्षेत्र ही इन 'घरेलू क्षेत्र' की वचतों का प्रयोग करते हैं

10 इसकी तुलना के इस दावे को कि कम-विकसित देशों में मुद्रा स्फीति स्वयं नष्ट हो जाएगी, Julio H G Oliveros ने अमान्य किया है इन देशों में विभिन्न संरचना सम्बन्धी जटिलताओं से उत्पादन उतनी ग्रासनी से नहीं बढ़ता जितनी शीघ्रता से इन देशों में मुद्रा स्फीति फैल सकती है. कृषि उपर इन देशों में बेरोचदार रहती है.

11 ग्यारह इसी प्रकार से इन देशों में राज्य की कर व्यवस्था इतनी परिपक्व नहीं होती कि बड़ी हुई आय को समुचित रूप से करों द्वारा किया जा सके. इस प्रकार से इन देशों में मुद्रा स्फीति में Built-in brakes की निताव कमी रहती है

मुद्रा स्फीति में देश में, Dr-Roberto Campos, आर्थिक व सामाजिक सिरो-परी नदों में विनियोजन रूक जाएगा.



Select references

- (i) See . Meier & Baldwin . op cit. p. 307-8.
- (ii) Kuznets Quantitative aspects of Economic Growth of Nation . Distribution of income by size—Eco. Dev & Cultural change Dec. 1964 p 80
- (iii) Yasusuke Maki and Makiko Kubo, Migration of Agrarian Labour force and the theory of disguised equilibrium I. E. J Oct. & Dec. 1964.
- (iv) S. J Patel - The Distribution of Income in India, I. Eco. Review Feb. 1956.
- (v) Vakil & Bramhanand : Capital Supply & Growth-Sources of Savings : International Eco. Association.
- (vi) Julio H. G Oliveros : On structural inflation ■ latin American Structuralism : Oxford Eco Papers. Nov. 1964
- (vii) Robert D. Oliveria Campos , inflation & Balanced Growth all from Dr. A. C. Minocha's op cit.

अध्याय : 19

विकास की अवस्था का सिद्धान्त

Stage Theories of Growth

I. List

II. Hilder brand

III. Bunker

IV. Gras

V. Marx

VI. W. W. Rostow

1. पूर्व औद्योगिक अवस्था या प्राथमिक अवस्था की अवस्था
2. आत्म स्फूर्ति-विक्रम के पूर्व की स्थिति की स्थापना की अवस्था
3. आत्म स्फूर्ति की अवस्था
4. उत्तरोत्तर विकास की अवस्था या परिपक्वता की अवस्था : पुरोगामी क्षेत्र का महत्व
5. अत्यधिक उपभोग की अवस्था

B

रोस्टोव की विकास की अवस्थाओं की समीक्षा

1. Gerald M. Meier
2. Simon Kuznet
3. A. K. Cairncross
4. Alexander Gerschenkron
5. H. J. Habakkuk
6. Benjamin Higgins

विकास की अवस्था का सिद्धान्त

Stage Theories of Growth

(With particular reference to Rostow's Stages)

विकास पर लिखने वाले बहुत से अर्थशास्त्रियों ने विकास को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से गुजरने की कल्पना की या ऐतिहासिक विवेचना की इनमें लिस्ट, हिडलब्रान्ड, व्यूकेर, ऐशले, ग्राम, तथा मार्क्स ने विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया

I List :

लिस्ट ने पाँच अवस्थाओं का वर्णन किया

- (I) दहशीपन की अवस्था जब कि व्यक्ति जो कुछ पाता वह खाता है न कि जो कुछ वह उगाता है
- (II) शरागाह अवस्था, जबकि प्राथमिक कृषि उन्नत होती है व जनता खानाबदोशों जैसी रहती है तथा जानवरों की भाँति शरागाह युग में रहती है.
- (III) कृषि अवस्था जबकि देश में कृषि ही मुख्य व्यवसाय व कृषि ही ग्राम का मुख्य स्त्रोत होती है
- (IV) इसके पश्चात कृषि उद्योग की अवस्था आती है औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता है व श्राय का मुख्य साधन हो जाता है. और सबसे अन्त में
- (V) कृषि-उद्योग व व्यापार सब उन्नत हो जाते हैं

लिस्ट के अनुसार पाँचवी अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जनसंख्या भार नहीं रहती और सबको उच्च स्तर पाना सम्भव होता है, तथा जब कि विदेशी व्यापार तथा राष्ट्रीय आय उच्चस्तर पर होते हैं हर देश इस अवस्था को पहुँचने का प्रयत्न करता है

इस अवस्था पर पहुँचना बहुत कुछ प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है उन्होंने इस सम्बन्ध में यह सलाह दी

See : Standard works on history of Economic Thought cited above.

प्रथम तो एक देश को कृषि उन्नत करना चाहिए, फिर औद्योगिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकतानुसार उद्योगों को 'सरक्षण' प्रदान किया जाना चाहिए, और जब देश में अन्तिम अवस्था आजाए तो पुनः देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतन्त्र होना चाहिए।

II Hitlerbrand

हिटलरब्रांड ये भी जर्मन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने विकास की तीन अवस्थाएँ बताईं।

- (1) ग्रामला बदनी की अवस्था
- (II) मुद्रा के माध्यम से विनिमय की अवस्था तथा
- (III) साख के प्रयोग से विकास की अवस्था

यह विश्लेषण अत्यन्त सरल था और आज के युग में जो विकास की जटिल समस्याएँ हैं उन्हें समझाने व सुलझाने का कोई महत्व नहीं है।

III Buker

बुकर के अनुसार विकास की ये अवस्थाएँ होती हैं

- (1) घरेलू अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन व उपभोग स्वतन्त्र रूप से छोटे पैमाने पर होता है।
- (II) नगरीय अर्थ व्यवस्था, जिसमें छोटे या थोड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, पर सम्पूर्ण देश में नाके-चुगी पद्धति रहती है तथा
- (III) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें सम्पूर्ण देश में उत्पादन व वितरण व्यवस्था का एकीकरण रहता है।

IV Gras

ग्रेस ने उपरोक्त अवस्थाओं में चौथी अवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था जोड़ दी, जिसमें देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य स्थान हो जाता है। इन अवस्थाओं में सरलता ही उनका दोष है और हमारी आलोचनाएँ वे ही हैं जो हिटलरब्रांड के सम्बन्ध में हमने की थी।

V Marx :

मार्क्स के सवर्ण में हम पढ़ ही चुके हैं कि उन्होंने समस्त देशों के विकास को इन अवस्थाओं से गुजरने की कल्पना की।

- (1) सामन्तवाद. (II) पूँजीवाद. (III) समाजवाद तथा (V) साम्यवाद.

हम देख चुके हैं कि मार्क्स पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास बन्ना सकने की सम्भावनाओं को मानते हैं, पर वे उसकी सामाजिक विकास न कर सकने को सम्भावनाओं के कारण उस पद्धति को उखाड़ फेंकने की सिफारिश करते हैं और मानते हैं कि यह व्यवस्था कायम ही नहीं रह सकती वे साम्यवाद को विकास की अन्तिम अवस्था मानते थे.

• VI W W. Rostow :

विकास की अवस्थाओं के अध्ययन में रोस्टोव का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है. थी सीयर के अनुसार "His efforts were more substantial than of others His approach more analytical and related to a wider range of issues than any of the approaches of his predecessors "

- 1 Pre-industrial phase or the stage of traditional society. पूर्व-औद्योगिक अवस्था या प्राथमिक अर्थव्यवस्था की अवस्था

ऐसी अवस्था, रोस्टोव के अनुसार, वह थी या होती है जिसमें कि न्यूटन के पूर्व की तकनीक व विज्ञान मौजूद हों. योरोप में 'औद्योगिक क्रान्ति' के पूर्व का काल यही काल था. इस प्रकार की अवस्था में जन्म व मृत्यु दरें अधिक रहती हैं. जन-संख्या में वृद्धि नहीं होती क्योंकि यहाँ 'मान्यस के अवरोध' कार्यान्वित होते हैं उत्पादन व उत्पादकता दोनों कम स्तर पर रहते हैं देश में कृषि ही मुख्य व्यवसाय व कृषि ही राष्ट्रीय आय का मुख्य जरिया होती है. एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने में गतिशीलता कम रहती है. ऐसी अवस्था में देश में यातायात, संचार, व्यापार, राज्य के कार्य, राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय सब कम होते हैं.

2. Pre-conditioning phase : आत्म-स्फूर्ति-विकास के पूर्व की स्थिति की स्थापना की अवस्था :

1. इस अवस्था में विकास की राह में आनेवाले समस्त राजनैतिक कारणों को दूर कर दिया जाता है. देश का राजनैतिक एकीकरण हो जाता है जिससे संगठित अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाती है.
2. इस अवस्था में मुख्यतः Social overheads (शिक्षा, ट्रेनिंग व स्वास्थ्य

सुविधाएँ) का विस्तार होता है। Economic overheads का भी (सड़के, रेलें, संचार साधन, बिजली, बैंक आदि) विस्तार हो जाता है।

3. इस अवस्था में भी विकास संभव है पर उसकी गति धीमी होती है।
4. व्यावसायिक, भौगोलिक व सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है। यातायात के साधन सुलभ व सस्ते हो जाते हैं।
5. कृषि के उत्पादन में आधुनिकता आ जाती है।
6. उद्योगों की भी स्थापना हो जाती है पर विकास की रफ्तार धीमी रहती है।
7. रोस्टोव के अनुसार कोई भी देश इस अवस्था में 100 वर्ष (एक सदी) तक रह सकता है।
8. इस अवस्था में उत्पादन के अंगों का अनुकूलतम रूप में एकत्रित हो जाते हैं। तकनीक भी उन्नत होने लगती है, तथा साहसियों का कार्य व प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है।
9. देश में शिक्षा के विवास व अन्य प्रभावों से देश की जनता में विकास के प्रति रुचि व जागरूकता हो जाती है।
10. इस काल में कृषि का सापेक्षिक महत्व कम होता, व उद्योग, यातायात, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ जाता है। कृषि अर्थिकों की मांग बढ़ने लगती है देश में विनियोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है।

3 The take-off आत्म-स्फूर्ति की अवस्था

1. यह अवस्था महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल होती है। यह अवस्था किसी देश में 20 से 30 वर्षों तक रहती है। इस काल में पहले तो पिछले काल में जो कार्य बाकी बचे जाते हैं, उन्हें पूरे किए जाते हैं।
2. यह शब्द Aeronautical शब्दावली का है। जैसे एक हवाईजहाज एक बार अपने Runway पर दौड़कर ऊपर उठ जाता है और फिर एक निश्चित ऊँचाई पर पहुँच कर उड़ता जाता है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था एक बार आत्म-स्फूर्ति की अवस्था में पहुँचती है तो फिर वह विकास पथ पर बढ़ती ही जाती है।
3. इस अवस्था में औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना हो चुकती है। इससे पूर्व अवस्था कृषि में 75 प्रतिशत लोग लगे

रहते थे इस काल में उनकी सख्या केवल 40 प्रतिशत या इससे कम हो जाती है।

4. इस अवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर, जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक हो जाती है। राष्ट्रीय आय बढ़ने में देश में विनियोजन की मात्रा भी बढ़ने लगती है देश की समस्त राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत या इससे अधिक विनियोजित होता ही रहता है
5. इस काल में परिवर्तन बहुत तेजों से होता है तथा वह अविरल रूप में होता है। यह काल एक प्रकार से “भौतिकीय क्रांति” का युग होता है। अल्प काल में ही उत्पादन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगने हैं।
6. आत्म-स्फूर्ति की अवस्था में पहुँचने के लिए विदेशी पूँजी का होना या न होना बहुत अधिक निर्णायक नहीं होता है जहाँ कि अमेरिका, कनाडा व रूस में आत्म-स्फूर्ति की अवस्था विदेशी पूँजी की सहायता से प्राप्त की गई वहीं ब्रिटेन व जापान ने वगैरह इस सहायता को प्राप्त किए आत्म-स्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त किया
7. रोस्टोव के अनुसार ‘Nationalism becomes an engine of modernisation’ अर्थात् राष्ट्रीयता की भावना ही विकास को आत्म-स्फूर्ति की ओर ले जानेवाली मुख्य घटक बन जाती है।
8. इस काल में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी क्रांति आ जाती है इस काल में नव-प्रवर्तनों की बहुतायत होने लगती है नए बाजार उत्पन्न होते हैं सभी आर्थिक संस्थान लाभ कमाते हैं, और कुछ क्षेत्रों का विकास बहु क्षेत्रीय विकास में परिणित हो जाता है
9. इस काल में वचनो की मात्रा बढ़ जाती है। ‘साख’ देश की मुद्रा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग बनकर पूँजी निर्माण में सहायक होती है
10. इस काल में देश के प्राकृतिक साधनों का और अधिक प्रचला प्रयोग होने लगता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है और निर्यात बढ़ने लगते हैं
11. इस काल में ऐसे व्यक्तियों की आय बढ़ने लगती है जो वचन करके पूँजी निर्माण करते हैं और अधिकाधिक विनियोजन बढ़ाते हैं इस काल में बाह्य मितव्ययनामों की उपलब्धि समस्त अर्थ व्यवस्था में बढ़ जाती है और इनके देश में कुछ Leading Sectors पुरोगामी क्षेत्र की स्थापना हो जाती है जो स्वार्थ विकास की ओर ले जाते हैं :

12 रोस्टोव ने भिन्न-भिन्न देशों की आत्म स्फूर्ति के काल इस प्रकार से दिए :

ब्रिटेन	1783-1802	जापान	1878-1900
फ्रान्स	1830-1860	रूस	1890-1914
बेल्जियम	1833-1860	कनाडा	1896-1914
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	1843-1860	चीन	1952-
जर्मनी	1850-1873	भारत	1952-
स्वीडेन	1868-1890		

कम विकसित देशों को अगर आत्म स्फूर्ति अवस्था को पहुंचना है, तो रोस्टोव उन्हें यह सलाह देते हैं

‘कम विकसित देशों को उपभोग स्तर से ऊपर की आय को पूँजी निर्माण के लिए प्रयोग करना चाहिए उन्हें उद्यमी व्यक्तियों को व्यापार व उधार देने के व्यापार से हटाकर उद्योगों में लगाना चाहिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकीय मौद्रिक व अन्य नीतियों (शिष्टा नीति भी) का प्रयोग करना चाहिए”

C P. Kindleberger ने रोस्टोव की आत्म-स्फूर्ति अवस्था की सुन्दर व्याख्या की है

“Take off is the great watershed resistances and blocks to development are overcome, particularly in one or more leading sectors where technical change is strongly felt”

4 The stage of self-sustained growth or derive to maturity The role of leading sectors उत्तरोत्तर विकास की अवस्था या परिपक्वता की अवस्था . पुरोगामी क्षेत्र का महत्व :

आत्म-स्फूर्ति की अवस्था के पश्चात परिपक्वता की अवस्था आती है जिसमें उत्तरोत्तर विकास होता जाता है इस काल में उन्नत तकनीकी तरीके व उन्नत उत्पादन व्यवस्था सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में फैल जाती है अर्थ व्यवस्था में “विकास करने की आदत हो पड़ जाती है”

इस काल में जनसंख्या वृद्धि में राष्ट्रीय आय कहीं अधिक बढ़ती है हर क्षेत्र में विकास होने लगता है इस काल में सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का स्वभाव ही बदल जाता है. देश का उन्नत राष्ट्रीय में नाम आ जाता है

इस काल में कृषि में रत व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत हो रह जाती है देश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट जाता है शहरों का विकास होता है कुशल व अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है

देश में विनियोजन की मात्रा राष्ट्रीय आय की 10 से बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुँच जाती है आयात घट जाते हैं व निर्यात अधिक हो जाते हैं रोस्टोव के अनुसार इस अवस्था को पहुँचने में 60 वर्ष लग सकते हैं

Leading sectors . They are his analytical bone structure of his stages of growth.

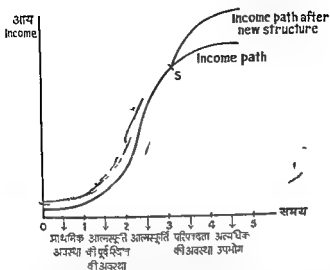
रोस्टोव के अनुसार देश का आर्थिक विकास कुछ परोक्षशी क्षेत्रों में विकास के कारण होता है यह वे क्षेत्र होते हैं जिनमें उत्पादकता अधिक होती है इन क्षेत्रों के विकास से अन्य क्षेत्रों का विकास होता है.

रोस्टोव बताते हैं कि विकास प्रक्रिया में देश में कुछ क्षेत्र व उद्योग पिछड़ने लगते हैं (decelerate) पर वह तो इन क्षेत्रों के विकास का ही परिणाम है कि समूची अर्थ व्यवस्था आगे ही बढ़ती रहती है

विकास प्रक्रिया में (In growth metabolism) ह्रास (Katabolism) विकास (Anabolism) साथ-साथ चलता रहता है. इन क्षेत्रों के कारण anabolism, katabolism में अधिक होता है यह परोक्षशी क्षेत्र ऐसे होते हैं कि समस्त अर्थ व्यवस्था को ही बदल देने हैं (भविष्य में अणु शक्ति का क्षेत्र ऐसा हो सकता है)

5 The stage of mass consumption : अत्यधिक उपभोग की अवस्था

जब देश इस अवस्था में पहुँच जाता है तो न केवल पूँजीगत वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन व उपभोग होता है बल्कि उपभोग उद्योग भी अधिकाधिक उत्पादन करते हैं टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग बढ़ता जाता है सबकी व सब किस्म की मांगें अधिकाधिक पूरी होती हैं देश में अधिकतम आर्थिक कल्याण स्तर पर जनता होती है और हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाती है



रोस्टोव की इन पाँच अवस्थाओं को किन्डलरजर ने इस चित्र में दिखाया है। विकास की अवस्थाएँ Gompertz या 'S' curve से दिखाई गई हैं। (1) विकास धीरे-धीरे शुरू होता है, फिर स्तर ऊपर उठता है, फिर तेजी से ऊपर जाता है, और फिर स्थिर हो जाता है पर उच्च स्तर पर (Curve becomes asymptotic).

B. रोस्टोव की विकास की अवस्थाओं की समीक्षा.

1. Gerald M. Meier.

(A) रोस्टोव ने विकास की इन अवस्थाओं को इसलिए दिया कि वे यह बता सकें कि मार्क्स की बताई हुई अवस्थाएँ (सामन्तवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व साम्यवाद) ठीक नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी अवस्थाओं को Non-Communist Manifesto) कहा (मार्क्स ने Communist Manifesto लिखा था.) रोस्टोव की इन अवस्थाओं में शोषण, या वर्ग संघर्ष की बात नहीं कही गई। जहाँ मार्क्स का कथन था कि विकास पूँजीपति के लाने के लिए ही होता है और विकास को आगे से जाने में पूँजीपति केवल अपना लाभ देखते हैं रोस्टोव का कथन है कि विकास के पीछे निजी स्वार्थ की सकीर्ण भावना ही नहीं होती है। सामाजिक व राष्ट्रीयता की भावना भी होती है। रोस्टोव का कथन ठीक था कि मार्क्स की "अवस्थाएँ" केवल ब्रिटेन के उदाहरण के आधार पर ही लिखी गई थी, जबकि रोस्टोव ने बहुत से विकासशील देशों को ध्यान में रखकर यह सब लिखा।

(B) पर प्रा० मीयरन रास्टोव की इन अवस्थाओं की आलोचना भा की उनके अनुसार रास्टोव की यह बात सही नहीं है कि सब देश इही अवस्थाओं से गुजरते हैं

✍

“Stage making” approaches are misleading when they succumb to a linear conception of history and imply that all economics tend to pass through the same series of stages every country cannot have the same past and same future”

प्रो० मायर का कथन है कि हा सकता है कि विकास में कोई देश एक अवस्था की पूरी तरह राह कर अगनी में पहुँच जाय और फिर हर देश का पाँचवी अवस्था में पहुँचना जरूरी नहीं है प्रो० रास्टोव की अवस्थाओं को हम Water tight compartment में नहीं बाँट सकते एक अवस्था की विशेषताएँ अन्य अवस्थाओं में भी रहती हैं

2 Simon Kuznet

कुजनेट् न रास्टोव की आलोचना रास्टोव के निम्नलिखित वक्तव्य पर की रास्टोव ने कहा था

‘Both the Existence and the quick-emergence of the political social and institutional frame work favourable to exploiting the impulses to expansion in modern sector are helpful for development in take-off’

कुजनेट का कथन है कि रास्टोव की यह मान्यता गलत है कि यह तब आत्म स्फूर्ति की अवस्था में उत्पन्न होता है तो फिर उनके पहलू से मौजूद होने की बात गलत है रास्टोव की अवस्थाएँ एक दूसरे की overlap करती हैं

1 Cf Leading Issues in Development Economics G M Meier Stanford university 1968 N York Oxford university press pp 24 35

2 Cf Simon kuznets Notes in Take-off I E A Septt 1960 from G M Meier op cit 26 33

दूसरी प्रमुख आलोचना यह है कि रोस्टोव ने केवल 'उद्योगों' को ही परोगामी क्षेत्र माना है। क्या कृषि, यातायात या अन्य कोई क्षेत्र परोगामी क्षेत्र नहीं हो सकता ? रोस्टोव ने अधिक उत्पादकता वाले उद्योग को परोगामी उद्योग माना है, पर हर अधिक उत्पादकतावाला उद्योग दूसरे उद्योगों के विकास को नहीं बढ़ाता "अगर एक दशक में हुलाहूप का उत्पादन एक हजार गुना बढ़ जाएँ तो यह परोगामी क्षेत्र नहीं बन जाता है।" (हुलाहूप एक प्लास्टिक का बड़ा छल्ला होता है जो लड़कियाँ अपनी कमर पतली रखने के लिए कमर के चारों तरफ घुमाती है)। तीसरी आलोचना यह है कि आत्मस्फूर्ति काल में, जिन देशों के आँकड़े प्राप्त हैं उनमें दुगुने विनियोजन से राष्ट्रीय आय की उत्पत्ति दुगुनी नहीं होती, जैसा कि रोस्टोव ने माना है।

अन्त में कुजनेट कहते हैं कि स्वयं उत्तरोत्तर विवास करने वाली अवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती।

"The concept of self-sustained growth is misleading. No growth is purely self-sustaining or purely self-financing"

परन्तु कुजनेट यह नहीं कहते कि रोस्टोव की अवस्थाओं के अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। कई देशों ने रोस्टोव की आत्म-स्फूर्ति अवस्था देखी है

3. A. K. Cairncross.

इनकी दो आलोचनाएँ कुजनेट की आलोचनाओं की भाँति हैं (I) वे भी कहते हैं कि परोगामी क्षेत्र रेल यातायात, या फुटकर व्यापार भी हो सकता है, केवल औद्योगिक क्षेत्र का परोगामी क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है (II) हमारे वे यह भी नहीं मानते कि इन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों का विकास होता है उदाहरणतया इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र उद्योग और आज मोटर उद्योग परोगामी बन रहे, पर इनमें सम्पूर्ण देश के विकास में कोई सहायना नहीं मिली।

उन्होंने भी यह आलोचना की कि रोस्टोव की अवस्थाएँ overlap करती हैं और उन्होंने कहा :

"रोस्टोव का यह मत सर्वथा गलत है कि एक बार परिपक्वता की अवस्था में देश आजाए तो विकास अपने आप होता है"

परन्तु बेर्नक्रास का कथन है कि इन कमियों के होने हुए रोस्टोव की अवस्थाओं का अध्ययन विकास प्रक्रिया समझने में महत्वपूर्ण है।

"A great deal of what Rostow says is helpful in spite of rather than because of "stage approach"

4 Alexander Gerschenkron ऐलेक्जेंडर गरशेनक्रोन :

गरशेनक्रोन यह मानते हैं कि एक देश भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओं से गुजरता है परन्तु हर देश इन अवस्थाओं से रोस्टोव की योजनानुसार नहीं गुजरता

5 H J Habakkuk

श्री हवाकुक के अनुसार रोस्टोव की अवस्थाएँ आसानी से पहचानी नहीं जा पाती प्राथमिक अवस्था की स्थिति तथा अत्यधिक उपभोग की स्थिति को तो आसानी से पहचाना जा सकता है परन्तु बीच की तीन अवस्थाओं की सीमा रेखा धुंधली है कनाडा व आस्ट्रेलिया तो पाचवी अवस्था की चौथी अवस्था को पहुँचने से पहले ही पहुँच गए हवाकुक का कथन है कि रोस्टोव ने विकास अवस्थाओं में वायुयान की उड़ान की सजाँ ली उमम व हवाई जहाज की उड़ान में टकराने व गिर पड़ने की अवस्थाओं को तो भूल ही गए

"In his aeronautical concept of growth, he ignored 'the bump downs and crash landings'"

6 Benjamin Higgins बेंजामिन हिगिंस

बेंजामिन हिगिंस, रोस्टोव के विश्लेषण को सैद्धांतिक व ऐतिहासिक रूप से सही मानते हैं



4 Alexander Gerschenkron Economic Backwardness in Historical perspective p 353-9

5 H J Habakkuk Stages of Economic Growth Economic Journal, sept—1961 p 601 4

6 See also G M Baldwin—op cit p 24-44

P D Shrivastava, I J Economics June 1964, Vol. XI. No 4

विकास की व्यूह रचनाएँ

Strategies of Economic Growth

संतुलित व असंतुलित विकास

Balanced Vs Un-balanced Growth

I. A. संतुलित विकास : विशेषताओं का विश्लेषण

प्रो० जे० आर० हिक्स का विश्लेषण.

मोपर तथा बाल्डविन का विश्लेषण.

I. B. संतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक

1. रैगनर नक्षत्र.

2. रोसेन्तीन-रोदान

3. डब्ल्यु० ए० ह्युस.

II. असंतुलित विकास का विश्लेषण

असंतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक

1. रोस्टोव.

2. ए० ओ० हिरशमैन.

3. हेन्स डब्ल्यू० सिगर.

4. सी० पी० किन्डलबर्जर.

5. मारकस फ्लोमिंग.

6. बापर तथा यामे.

7. प्रो० रुजीना.

8. जे० शोहान.

विकास का ऐतिहासिक अध्ययन बताता है कि विकास की मुख्य प्रणाली "असंतुलित विकास पद्धति" रही है.

III. "संतुलित विकास पद्धति" व "असंतुलित विकास पद्धति" के सम्बन्ध में संतुलित मत

पाँच स्ट्रीटन के विचार.

विकास की व्यूह रचनाएँ

Strategies of Economic Growth

संतुलित व असंतुलित विकास

Balanced vrs Unbalanced Growth

I A संतुलित विकास संतुलित विकास की विशेषताओं का विश्लेषण .

संतुलित विकास पद्धति में समस्त क्षेत्रों का संतुलित रूप में, एक साथ व पूर्ण समन्वय से, विकास किया जाता है. (Balanced growth requires that investment take place in clusters) संतुलित विकास व्यवस्था में भ्रगर इस्पात का कारखाना खोला जाना है तो साथ ही साथ लोहे की खान का विकास, कोयले की खानों का विकास, यानायात का प्रबन्ध तथा बाजार के निस्तार का आयोजन एक साथ कर लिया जाता है.

इस पद्धति में इस प्रकार से विकास कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं कि न तो किसी क्षेत्र में अतिविका सामान रहे और न किसी क्षेत्र में उत्पादन की कमी रहे

संतुलित विकास पद्धति के प्रवर्तक इस बात पर जोर देते हैं कि "प्रथम विकास के साम्य को एक स्थान पर नहीं बरन हर स्थान पर तोड़ना पड़ता है" Proponents of balanced growth emphasise that under-development equilibrium cannot be broken at one point.¹

प्रो० पैरू के अनुसार 'संतुलित विकास का सिद्धान्त वास्तव में "चक्र विरोधी नीति" का उत्तराधिकारी सिद्धान्त है. चक्र विरोधी नीति के अन्तर्गत हम मशी काल में व्याज की दर घटा कर, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदकर, मुद्रा प्रसार करके, करो में छूट देकर और व्यय बढ़ाकर तथा अन्य उपायों से विकास में अवरोधों को दूर करते हैं, तो संतुलित विकास नीति के अन्तर्गत हम अन्य व दीर्घकालीन विनियोजन में समन्वय करके विकास को आगे बढ़ाते हैं.

सन्तुलित विकास पद्धति का लक्ष्य देश में अनुकूलतम और उचिततम आर्थिक सामाजिक संरचना को स्थापित करके अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना होता है.¹

प्रो० पेरू के विश्लेषण के अनुसार सन्तुलित विकास में तीन बातें निहित हैं

(i) देश के कुल उत्पादन और कुल रोजगार में वृद्धि हो और इनके स्तर में न्यूनतम उच्चावचन हो, तथा देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो

✓ (ii) अर्थशास्त्र के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम विषमता हो, तथा

✓ (iii) समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में सर्घर्ष न्यूनतम हो.

प्रो० पेरू के अनुसार सन्तुलित विकास पद्धति एक देश में तो अपनाई जा सकती है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनाया जाना अत्यन्त कठिन है

प्रो० जे० आर० हिक्स का विश्लेषण :

प्रो० हिक्स के अनुसार सन्तुलित विकास पद्धति में अर्थव्यवस्था के 'सक्रिय क्षेत्रों' को आगे बढ़ने से रोक लिया जाता है और निष्क्रिय या कम सक्रिय क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाता है. सक्रिय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें विनियोजन, बढ़ते हुए मूल्यों के प्रभाव से, अथवा राज्य के आयोजन के कारण, या इन क्षेत्रों में किसी नव-प्रवर्तन के कारण, पर्याप्त मात्रा में होता रहता है इसके विपरीत कम सक्रिय या निष्क्रिय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विनियोजन नहीं होता. ये क्षेत्र पूँजी की कमी या पिछड़ी तकनीक किन्हीं अन्य राजनैतिक कारणों से पीछे रह जाते हैं.

सन्तुलित विकास पद्धति में इन पिछड़े क्षेत्रों को ही विकास में सक्रिय क्षेत्रों के बराबर लाया जाता है

मीयर तथा बाल्डविन का विश्लेषण :

सन्तुलित विकास व्यवस्था में विनियोजन निजीलाभ की सम्भावित मात्रा को ध्यान

1. "The policy of balanced growth is complete anti-thesis of the haphazard piling up and incoherent juxtaposition of measures of intervention." its aim is to act simultaneously upon the real factors in order to secure ..the maximum productivity of a socially optimum Structure."

Prof P Perroux : See International Economic association "Stability and Progress in the world Economy." Edited D. C. Hague. p 113-129.

2. J R. Hicks See I E A. op. cit. Ed D C. Hague p. 113-129

3. Meier & Baldwin : op. cit : p. 353-367

में रखकर नहीं किया जाता बरन् सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है विनियोजन केवल उन्नत चेत्रों में ही (On growing points) नहीं किया जाता बरन् समस्त चेत्रों को एक साथ बढ़ाया जाता है. भिन्न-भिन्न चेत्रों में विनियोजना को एक दूसरे का प्रतियोगी नहीं बनाया जाता बल्कि उनको पूरक के रूप में किया जाता है. संतुलित विकास में एक क्षेत्र की पूर्ति दूसरे क्षेत्र में माँग बन जाती है और इस प्रकार से न बेच सकने का डर नहीं रहता. संतुलित विकास पद्धति में बाह्य मितव्ययताओं का सृजन होता है.

I : B संतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक

1. Ragnar Nurkse : रैगनर नर्क्स

1. जैसा कि हम देख चुके हैं. नर्क्स का कथन है कि विकासशील देशों के विकास पथ में बहुत से "आर्थिक दुश्चक्र" हैं उनका कथन है कि इन आर्थिक दुश्चक्रों को तोड़ने के लिए "संतुलित विकास" की आवश्यकता है. नर्क्स का कथन है कि "जिस प्रकार से शरीर के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से देश के आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास आवश्यक होता है
2. नर्क्स के अनुसार संतुलित विकास पद्धति से हम माँग और पति दोनों पक्ष से आर्थिक दुश्चक्र को भेद कर समाप्त कर सकते हैं उनका कथन है कि अगर हम भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों में एक साथ समन्वयपूर्ण विनियोजन करें

See : (1) Nurkse : Capital Formation in Under-developed Countries. Oxford University Press 1964. ch 1.

(2) Nurkse : "Some International Aspects of the Problem of Economic Development" in Economics of Under-developed countries, (Ed), by A. N. Agarwal and S. P. Singh.

(3) Nurkse : "The Conflict between Balanced Growth and International specialisation", lectures on Economic development, Faculty of Economics (Istanbul University) and Faculty of pol. sc. (Uni. of Ankara) 1958 of. G. Meier leading Issues in Econ. Development. Oxford.

- तो यह सतुलित विकास पद्धति हुई. इस प्रकार के विनियोजन से बाजार विस्तृत होता है इन उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति ही एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक बन जाते हैं यह माँग पक्ष से दुश्चक्र तोड़ देगा
- 3 पूर्ति पक्ष की ओर से दुश्चक्र को तोड़ने के लिए अगर असतुलित विकास पद्धति अपनाई गई (जिसमें बड़े उद्योगों में पहले विनियोजन हो) तो नक्स के अनुसार, बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ जाएगी. नक्स कहते हैं कि विकास पथ पर बहुत से देश बहुत देर में आये हैं ये देश विकसित देशों के उपभोग व उत्पादन के तरीकों की नकल करने लगते हैं, अर्थात् उच्च विलासिताओं की वस्तुओं का उपभोग करते हैं और जटिल उत्पादन पद्धतियाँ अपनाना चाहते हैं. परन्तु इन देशों में बचत व पूँजी निर्माण तो विकसित देशों के मुकाबले में कम होता है इससे ये देश भुगतान सतुलित नहीं रख पाते. अगर ये देश सन्तुलित विकास पद्धति अपनाएँ तो इस प्रकार की कठनाई से बच सकते हैं
4. सन्तुलित विकास का यह भी अर्थ होता है कि कृषि व उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाये जब ऐसा किया जाएगा तो कृषि क्षेत्र की अनिवार्य जनसंख्या को औद्योगिक क्षेत्र में कार्य मिल सकेगा.
- 5 इसके अतिरिक्त, नक्स कहते हैं, सतुलित विकास पद्धति से विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा सतुलित विकास पद्धति में हम कृषि व औद्योगिक विकास साथ-साथ करते हैं, भिन्न भिन्न उद्योगों को एक साथ उन्नत करते हैं तथा
- Social overheads (शिक्षा व स्वास्थ्य) व economic overheads (बाह्य आर्थिक मितव्ययिताये अर्थात् बैंक व यातायात विकास) का विकास भी एक साथ करते हैं इन सब सुविधाओं की मौजूदगी से विदेशी विनियोजक इन देशों में विनियोजन करने को प्रोत्साहित होते हैं नक्स के अनुसार सतुलित विकास पद्धति विदेशी व्यापार के तुलनात्मक लागत के मिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है उन्होंने कहा
- “वेनेज्वेला के 90 प्रतिशत निर्यात पेट्रोल के होते हैं फिर भी इस इस उद्योग में देश की केवल 2 प्रतिशत श्रम शक्ति कार्य पाती है अगर इस देश में सतुलित विकास होता तो देश के अन्य लोग भी निम्न स्तर के जीवन व्यतीत करने के स्थान पर उच्च स्तर का जीवन यापन कर सकते थे.”

नक्स का कथन है -

“Balanced growth is a good foundation for

International trade the case for balanced growth is not a case for autarky."

6. इस प्रकार से नवर्म के अनुसार केवल सतुलित विकास में ही आर्थिक दुष्पन्न टूट सकता है। इससे एक क्षेत्र की पूर्ति की दूसरे क्षेत्र में मांग होगी, दूसरे क्षेत्र की पूर्ति की मांग तीसरे या पहले क्षेत्र में होगी और यही क्रम चलता रहेगा। इस प्रकार से मजदूरी का साथ-साथ विकास होगा और कोई भी क्षेत्र पिछड़ा या मंदी की अवस्था में नहीं रहेगा। Evsey Domar ने इसीलिए कहा है

"His theory of balanced growth has been inspired by a variant of the Keynesian analysis of the slump" अर्थात् नवर्म के सतुलित विकास सम्बन्धी विचार केन्स के मंदी सम्बन्धी विश्लेषण से प्रभावित है।

2. Rosenstein-Rodan रोसेन्तीन-रोदान

1. नवर्म की भाँति रोदान भी सतुलित विकास के पक्ष में है। रोदान का कथन है कि अगर कम विकसित देश उस की भाँति असतुलित विकास पद्धति अपनाएँगे तो बड़े-बड़े उद्योगों के विकास के लिए जितनी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी उतनी पूँजी को इकट्ठा करने के लिए देशवासियों को बहुत अधिक मात्रा में उपभोग का त्याग करना पड़ेगा। दूसरी बुराई इसमें यह पैदा होगी कि इन बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना से अतिरिक्त व अनावश्यक उत्पादन क्षमता निर्मित हो जाएगी। सतुलित विकास पद्धति में ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। तीसरी बुराई यह होगी कि असतुलित विकास से पूर्ण विकास होने में काफी समय लगेगा।

2. रोदान सतुलित विकास पद्धति के लिए 'श्रम-महान तकनीक' Labour-intensive techniques अपनाने के पक्ष में है। उनका कथन है कि

1. Nurkse cf G Meier op. cit p 250-254 & A N Agrawal & S. P. Agarwal. p. 256-71

2. Evsey Domar quoted from Alak Ghosh's New horizons of planning p 63.

Rosenstein Rodan : Problems of Industrialisation of Eastern and south, Eastern Europe Eco-Journal June-sept. 1943.

Rio. Round table conference of international Economics Association 1957. See : Okun & Richardson . op cit : p. 124-132.

असंतुलित विवास में हम बड़े उद्योगों की स्थापना करते हैं और पूँजी-गहन तकनीक से उत्पादकता वृद्धि करते हैं और इसी प्रकार से बाजार का विस्तार होता है (मूल्य कम होने से)। परन्तु अगर हम संतुलित विकास पद्धति अपनाएँगे तो असह्य अर्धवैरोजगारों को, श्रम-गहन तकनीक अपनाने के कारण, रोजगार भी मिलेगा और जन साधारण की क्रयशक्ति भी बढ़ेगी इस प्रकार से सामान न बेच सकने का जोखिम भी नहीं रहेगा "जोखिम" भी एक प्रकार की लागत होती है और इसके कम होने में वास्तु मितव्ययिता का सृजन होता है।

3. रोदान के अनुसार संतुलित विकास से व्यक्तिगत लाभ व सामाजिक लाभ में अन्तर कम होते हैं एक साथ कई क्षेत्रों में विनियोजन से निजी क्षेत्र के लाभ के स्तर नीचे हो सकते हैं परन्तु सामाजिक लाभ तो बढ़ ही जाएँगे (Balanced growth will reduce the divergence between the private and social marginal returns... ..Balanced growth will generate external economics and the external economics should be included in the calculus of profitability)

3. W. A. Lewis आर्थर ल्युस¹ :

1. ल्युस भी संतुलित विकास के पक्ष में पूर्ण समर्थन देने में विल्कुल नहीं हिचकते किसी भी विकास कार्यक्रम के सफल होने के लिए यह सबथा आवश्यक है कि कृषि व उद्योग के बीच संतुलित विकास हो, देश में उपभोग किए जाने वाले उत्पादन व निर्यात किये जाने वाले उत्पादन में संतुलन हो। इसी प्रकार से आयात व निर्यात में संतुलन होना चाहिए
2. संतुलित विकास का अर्थ यह नहीं होता कि समस्त क्षेत्रों की विकास दर समान हो इसका तो केवल यह अर्थ होता है कि समस्त क्षेत्रों में बाध्यनीय दर से विकास हो ३

1. W A Lewis : Theory of Economic Growth p 274-83.

2 Lipton इस सम्बन्ध में कहते हैं कि संतुलित विकास में सब क्षेत्रों में एक ही दर से विकास होना चाहिए। परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री इस मत के नहीं हैं। W. Birmingham व A. G. Ford भी ल्युस के मत के समर्थक हैं उनका कथन है .

"संतुलित विवास का यह अर्थ नहीं है कि अगर किसी क्षेत्र में

ल्युस सतुलित विकास पद्धति को निम्नलिखित दो लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चाहते हैं

(I) सतुलित विकास से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य स्तर ऐसे रहेंगे जिससे किसी भी क्षेत्र में मूल्य न तो अधिक गिरें और न ही अधिक बढ़ें, इससे ऐसा नहीं होगा कि एक क्षेत्र की 'व्यापार की शर्तें' इस प्रकार में सुधरे कि दूसरे क्षेत्र की व्यापार की शर्तें बिगड़ जाएँ

(II) सतुलित विकास से भिन्न-भिन्न प्रकार के अवरोध (bottlenecks) जो विकास के मार्ग में आते हैं, वे दूर हो जाते हैं भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विकास उनकी आय की सोच के अनुसार होता है.

II. असतुलित विकास का विश्लेषण

अर्थशास्त्र के विचारों की अधिक जानकारी न रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि "असतुलित" विकास तो अवश्य ही त्रुटिपूर्ण पद्धति है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता न केवल "असतुलित" विकास को बुरा नहीं समझा जाता बल्कि बहुत से अर्थशास्त्री तो "असतुलित" विकास पद्धति के प्रबल प्रवर्तक भी हैं।

असतुलित विकास पद्धति में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पूँजी-गत विनियोजन अलग-अलग से बढ़ाया जाता है जो अर्थशास्त्री असतुलित विकास चाहते हैं उनका कथन कि सतुलित विकास के लिए इतने अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी कि किसी भी कम-विकसित देश को एक साथ समस्त क्षेत्रों में विनियोजन करना सम्भव नहीं होगा इन देशों के लिए यही भ्रष्टा होगा कि वे कुछ प्रमुख व विकासशील

5 प्रतिशत की दर से प्रगति हो रही हो तो सब क्षेत्रों में इसी दर से प्रगति हो कुछ क्षेत्र तो कम दर से व कुछ क्षेत्र अधिक दर से प्रगति करेंगे ही, हम समान दर में प्रगति नहीं चाहते बल्कि समन्वित रूप से प्रगति चाहते हैं देश में Capital-output ratio (पूँजी-उत्पादन अनुपात) के अध्ययन से हम अलग-अलग क्षेत्रों के सापेक्षिक समन्वय को निर्धारित कर सकते हैं¹

Lipton quoted from

See : K. N. Prasad . Balanced vs Unbalanced Growth : Indian Economic Journal Oct-Dec. 1966.

Birmingham ■ Ford Planning and Growth in Rich and Poor Countries. p 35

उद्योगों में ही विनियोजन बढ़ाएँ और जान-बूझकर असंतुलित उत्पन्न करें। संतुलित विकास में विकास की दर धीमी रहेगी जब असंतुलित विकास में विकास की दर अधिक रहेगी। असंतुलित विकास में विनियोजन इस प्रकार से होगा कि उसमें जाने वाली अवस्थाओं में स्वयं ही उत्पादन बढ़े तथा वर्तमान उत्पादन की पिछली प्रक्रिया में (जैसे कपड़ा मिल की पिछली प्रक्रिया रुई उगाना) भी विनियोजन बढ़ जाए।

"Investment should be concentrated in industries with greatest amount of forward linkage (encouraging investment in subsequent stages of production) and backward linkage" (inducing investment in earlier stages of production)

असंतुलित विकास पद्धति में बढ़ते हुए उद्योगों को ही आगे बढ़ाया जाता है, इससे अधिक लाभ कमाये जाते हैं और फिर इन्हीं लाभों को विनियोजन कर के अन्त में संतुलित विकास लाया जा सकता है।

असंतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक .

1. W. W Rostow : रोस्टोव :

रोस्टोव का कथन है :

"किसी भी देश में आर्थिक विकास कुछ अग्रगामी क्षेत्रों के विकास के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावों पर निर्भर करता है। इन क्षेत्रों में, जो अधिकाधिक उत्पादकता वृद्धि होती है वही सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा देती है."

रोस्टोव असंतुलित विकास पद्धति को ही सर्वोपरि मानते हैं। अग्रगामी क्षेत्रों से उनका आशय उन क्षेत्रों से है जो अपनी नवीन उत्पादन पद्धति से उत्पादकता में आगे हैं इस कारण इनमें लाभ अधिक होता है और इन लाभों को पुन अधिक उत्पादक कार्यों में विनियोजित कर दिया जाता है। इस पद्धति से सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया स्वयंचालित हो जाएगी।

2. A. O. Hirschman : ए० ओ० हिरशमैन

हिरशमैन संतुलित विकास पद्धति को उचित नहीं मानते। उनका कथन है कि

Cf : Mc Graw Hill Dictionary of Modern Economics p. 32-33.

1. Rostow : op. cit.

2. A O. Hirschman : 'The Strategy of Economic Development.', Yale University Press, New Haven, 1958 p. 36 and 66

See also Gerald M. Meier "Leading Issues" p. 254-9

कम विकसित देशों कुशल व तकनीकी विशेषज्ञों की पहले ही कमी रहती है। सतुलित विकास पद्धति में एक साथ भिन्न-भिन्न उद्योगों को प्रारम्भ करना इन व्यक्तियों की कमी के कारण सम्भव ही नहीं होगा।

हिरशमैन का कथन है कि सतुलित विकास का सिद्धान्त केवल विकसित देश ही अपना सकते हैं कम-विकसित देशों के लिए असतुलित विकास का सिद्धान्त "Is children's parallel play" हिरशमैन तो See-saw advance of growth (अर्थात् बच्चों का वह खेल जिसमें एक बच्चा जब ऊपर जाता है तो दूसरे सिरे का बच्चा नीचे चला जाता है और जब दूसरा बच्चा ऊपर जाता है तो पहला नीचे चला जाता है) अर्थात् विकास तो तब होगा जबकि अर्थ-व्यवस्था कभी आगे व कभी पीछे हो जाए सतुलित विकास, हिरशमैन के शब्दों में Escapist solution है अर्थात् वास्तविकता में बचकर निकल भागने की योजना है।

हिरशमैन का कथन है कि अगर कम-विकसित देश असतुलित विकास पद्धति अपनाने लें तो ही वे इन देशों में इतने साहसियों की कमी की स्थिति से मुक्ति पा सकते हैं इन देशों में इतने साहसी नहीं होते कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास का कार्य हाथ में ले सकें।

हिरशमैन का कथन है कि असतुलित विकास पद्धति व्यावहारिक नहीं है उनके अनुसार हम इस पद्धति को न केवल अपना नहीं सकते बल्कि इस पद्धति को अपनाना अनुचित भी होगा हिरशमैन का कथन है कि हमारा यह सोचना गलत है कि अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थिति वाछनीय व असाम्य की स्थिति अवाछनीय होती है। वास्तव में हमारी अर्थ-व्यवस्था हमेशा असाम्य की स्थिति से साम्य की ओर जाती है और इसी से विकास होता है हिरशमैन, टाइबर साइटोव्स्की (Tibor scitovsky) के उस कथन से पूर्णतया सहमत है जिसमें उन्होंने कहा था कि "लाभ असाम्य की परिस्थिति में ही उत्पन्न होते हैं।" इसलिए हिरशमैन असतुलित विकास के पक्ष में है।

हिरशमैन का कथन है

"In general, development policy must keep alive rather than eliminate the disequilibria of which profits and losses are symptoms in a

Tibor Scitovsky quoted from : "Two concepts of external Economics," Journal of Political Economy April 1954 p. 148.

competitive economy If the economy is to be kept moving ahead the task of development policy is to maintain tensions, disproportions disequilibria The nightmare of equilibrium economics, the endless spinning cobweb is the kind of mechanism we must assiduously look for as an invaluable help in development process”¹

(अर्थात् किसी भी विकास नीति का लक्ष्य असंतुलन व असाम्य की स्थिति को समाप्त करना नहीं होना चाहिए वरन इनको कायम रखना चाहिए)

3 Hans W Singer हेस डब्लू सिंगर

सिंगर भी असंतुलित विकास के पक्ष में हैं व संतुलित विकास पद्धति की प्रशंसा से भी अवगत हैं परन्तु उससे अधिक व असंतुलित विकास को अच्छा मानते हैं सिंगर का कथन ■ कि संतुलित विकास पद्धति निश्चय ही कम विकसित देशों में बाजार सबधी कठिनाइयों को दूर कर सकती है परन्तु साधनों की कमी के कारण इस नीति को अपनाना संभव नहीं होगा सिंगर संतुलित विकास पद्धति के निम्न लिखित गुण बताते हैं

- (1) संतुलित विकास पद्धति अपनाते पर बाजार सबधी कठिनाईया दूर होगी
- (ii) इससे White elephant projects या बड़ व कम लाभदायक उद्योगों या कार्यों की स्थापना नहीं होगी
- (iii) इस पद्धति को अपनाते पर और अधिक विनियोजन करने की प्रेरणा रहेगी

सिंगर का कथन है

जिन देशों में विकास के निम्नस्तर का कारण साधनों की कमी नहीं बल्कि अत्यधिक निराशात्मक वातावरण है वहाँ संतुलित विकास पद्धति सैद्धान्तिक व व्यवहारिक दोनों रूप से उचित होगी

इन सब प्रशंसाओं के होते हुए भी सिंगर के अनुसार संतुलित विकास पद्धति कम देशों के लिए कई कारणों से अनुपयुक्त है उनका कथन है

“संतुलित विकास पद्धति के प्रवर्तक यह मानते हैं कि इस पद्धति में पूर्ति अपनी माँग स्वयं उत्पन्न कर लेगी और साधन भी प्राप्त हो जाएंगे परन्तु यह संभव नहीं है कि यह दोनों लाभ एक साथ प्राप्त हो जाएँ इन देशों को हम “उच्च विचार” रखने की सलाह तो दे सकते हैं परन्तु ‘बड़े बड़े कार्य करो’ की सलाह देना अत्यन्त गलत होगा. . . विकास की सर्वोत्तम नीति तो यह ही होगी कि हम साधनों को उन क्षेत्रों में लगाएँ जो पहले से ही विकसित हों. जिनमें शीघ्रातिशीघ्र और अधिक विकसित होने की तथा देश की अर्थ व्यवस्था को लचीला बनाने की सम्भावनाएँ हों.”

“ ‘Think big’ is a sound advice to these countries but ‘Act Big’ is unwise counsel if it spurs them to efforts to do more than their resources permit. Therefore to recommend the balanced investment package as a device simultaneously to solve the marketing deadlock and to solve the deadlock of insufficient resources is to be become victim of double counting trick ”

सिंगर का कथन है कि संतुलित विकास पद्धति विकास की शुरु की अवस्था के लिए सर्वथा अनुपयुक्त व हानिकारक होगी (It will be incomplete, implausible and even potentially dangerous). सिंगर संतुलित विकास पद्धति को गलत नहीं मानते बल्कि उसे कम-विकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं मानते The doctrine is premature rather than wrong.
4. C. P. Kindleberger · सी० पी० किण्डलबरजर :

किण्डलबरजर भी असंतुलित विकास पद्धति को ही उचित मानते हैं, किण्डलबरजर का कथन है कि संतुलित विकास पद्धति को अपनाने का अर्थ यह होता है

See : International Development-Growth & Change, Mc Graw Hill 1964, “Balanced Growth-Theory & Practise p. 47-55
—also “The concept of Balanced Growth and Economic Development “Theory & Facts.”

(1) C. P. Kindleberger ; op. cit : p. 223-225.

कि "कही भी काम शुरू करने से पहले हर स्थान पर काम शुरू करो." उनका कथन है कि सतुलित विकास पद्धति को अगर कम-विवसित अपनाएँगे तो साधनों की कमी आएगी, मशीनों की कमी आएगी और हर क्षेत्र में रुटियाँ होगी.

किन्डलबरजर का कथन है कि सतुलित विकास की बात बरना 'केवल नारेबाजी है' हर स्थान पर बाजार सवधी सतुलन स्थापित करने के स्थान पर हमको चाहिए कि हम असतुलित विकास पद्धति को अपनाएँ और बाजार में स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली को प्रभावशाली होने दें किन्डलबरजर का कथन है

"But if the slogan of balanced growth helps make the authorities examine sectoral inter-relations and judge their nature, it will serve a useful purpose. Balanced growth is rather an empty slogan unless it means only that agriculture merits alteration as well as industry."

5 Marcus Fleming भारक्स फ्लेमिंग

मारकस फ्लेमिंग ने भी असतुलित विकास पद्धति के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका कथन है कि सतुलित विकास पद्धति के प्रवर्तक उन उद्योगों को जिनमें एक साथ विनियोजन किया जाता है परस्पर एक दूसरे का पूरक मानते हैं परन्तु साधनों की कमी के कारण वे एक दूसरे के प्रतियोगी ही रहते हैं

अगर हम सतुलित विकास पद्धति को अपनाते हैं तो हम उत्पादन वस्तु उद्योगों व उपभोग वस्तु उद्योगों का एक साथ विकास करेंगे इससे उत्पादन वस्तु उद्योगों को साधनों की कमी पड़ जाएगी और इससे अर्थ व्यवस्था में मितव्ययिताओं के सृजन के स्थान 'अमितव्ययिताओं' या हानियों का सृजन होगा

फ्लेमिंग के अनुसार अगर कम विकसित देशों में असतुलित विकास पद्धति के अन्तर्गत केवल उन उद्योगों में विनियोजन किया जाए जिनमें उत्पादन का वृद्धि नियम लागू होता है तो इन देशों में विकास की सम्भावनाएँ बढ़ जाएगी.

Marcus Fleming External Economics and the Doctrine of Balanced Growth The Economic Journal June 1955
See also in A N Agrawal and P. Singh op cit. as also in Okun & Richardson op cit.

मारक्स फ्लेमिंग के अनुसार सन्तुलित विकास पद्धति केवल उन्ही देशों में अपनाई जा सकती है जहाँ (1) पर्याप्त मजदूरी में पजी, कम व्याज की दर पर प्राप्त हो सकती है, (11) जहाँ श्रम सघो को श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी न बढ़ाने दी जाती हो, और (111) जहाँ कृषि क्षेत्र में बहुत से अर्ध-बेरोजगारी से पीड़ित लोग वर्तमान वास्तविक मजदूरी पर ही रोजगार प्राप्त करने को तैयार हों।

अगर उपर्युक्त स्थितियाँ किसी कम विकसित देशों में मौजूद न हों तो वहाँ संतुलित विकास के स्थान पर असन्तुलित विकास पद्धति ही अपनायाना चाहिए।

6. Bayer and Yamey बायर तथा यामे

ये अर्थशास्त्री भी सन्तुलित विकास पद्धति से असन्तुलित विकास पद्धति को उत्तम मानते हैं। ये अर्थशास्त्री सन्तुलित विकास पद्धति की दो कारखों से आलोचना करते हैं।

- (1) सन्तुलित विकास पद्धति को अपनाने से विकास की मौद्रिक व वास्तविक लागत बढ़ जाएगी और इसमें समस्त योजना की सफलता की सम्भावना घट जाएगी।
- (11) सन्तुलित विकास पद्धति देश के आन्तरिक व्यापार में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन में अपनायी जा सकती है, परन्तु अगर देश की वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान प्राप्त करना हो तो इसके लिए केवल उन उद्योगों को स्थापित करना चाहिए जिन उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन में उस देश को विशिष्टता प्राप्त हो। और इसी कारण असन्तुलित विकास की पद्धति उचित रहेगी।

7. Prof Rugina . प्रो रुजीना .

प्रो. रुजीना भी असन्तुलित विकास पद्धति के पक्ष में हैं और वे सन्तुलित विकास पद्धति को मुख्यतः राजनैतिक कारणों से ठुकराने हैं। उनका कथन है कि सन्तुलित विकास पद्धति राज्य के निर्देशन के बगैर नहीं अपनायी जा सकती। इस प्रणाली को अपनाने पर राज्य का हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाएगा और "इससे समाजवाद की को हम पिछले दरवाजे से आने की अनुमति दे देंगे" उनका विचार है कि यह विकास पद्धति भी चक्र विरोधी नीति की भाँति असफल रहेगी। उनका कथन है -

"सन्तुलित विकास की नीति असफल होगी, परन्तु राजनीतिज्ञ इसकी असफलता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे वे इसके स्थान पर और

Bayer & Yamey . The Economics of Under developed Countries
p 247-50.

7. Cf : I. E. A. "Economic stability... .." op cit. p 143-4.

अधिक कायदे कानून व नियंत्रण नियम बनाएंगे, वे हमेशा इसके असफल होने का दोष जनता को 'गलत' आचरण पर मढ़ दगे वे अपने तथा कथित 'विशेषज्ञों' के त्रुटि-पूर्ण सिद्धान्तों की नहीं मानेंगे, वरन् वे सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को आयोजित करके समाजवाद की स्थापना कर देंगे "

प्रो रुजीना का विश्वास है कि संतुलित विकास प्रणाली से न तो व्यापार चक्र समाप्त होंगे और ना ही राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी.

8. J. Sheahan : जे. शीहान .

जे शीहान संतुलित विकास-पद्धति को गलत राह पर ले जाने वाली (misleading) पद्धति मानते हैं उनका कथन है कि अगर हम संतुलित विकास पद्धति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सकें तो यह उचित होगा परन्तु यह संभव नहीं है. इसलिए किसी भी राष्ट्र को अकेले ही संतुलित विकास की नीति नहीं अपनाना चाहिए.

विकास का ऐतिहासिक अध्ययन बताता है कि विकास की मुख्य प्रणाली "असंतुलित विकास पद्धति" रही है .

आज जो पश्चिमी राष्ट्र उन्नत हैं उन सब में असंतुलित विकास की ही पद्धति अपनाई थी. औद्योगिक क्रांति से आज तक किसी भी उन्नत देश में संतुलित विकास पद्धति नहीं अपनाई हर देश में कुछ अग्रगामी क्षेत्र रहे हैं जिनमें तकनीकी उन्नति व उत्पादन के स्तर सर्वथा ऊँचे रहे हैं. अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा व आस्ट्रेलिया ने असंतुलित विकास पद्धति अपनाई. फ्रांस के हर आयोजन में अलग-अलग उद्योगों पर कम या अधिक महत्व दिया गया, पर इससे फ्रांस के आयोजन ने प्रवैगिक अर्थ-व्यवस्था को जन्म दिया.

बलबीर साहनी का कथन है .

"हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के

8 J. Sheahan : International Specialisation and the concept of Balanced Growth, Quarterly Journal of Economics, Feb. 1958

See : Balbir S. Sahni . Transformation through planned development, Eastern Economist, April 19, 1968

Alak Ghosh : New Horizons in planning : 1960, p. 50, 51, 61 and 71.

विक्रम सम्बन्धी लक्ष्य, किसी भी विकास की अवस्था में तब प्राप्त हो सकते हैं जब आयोजन की विभिन्न योजनाएँ 'असंतुलित विकास पद्धति' पर आधारित हों।"

भारतीय व रूसी आयोजन भी असंतुलित विकास पद्धतियाँ पर आधारित हैं पश्चिमी राष्ट्रों में असंतुलित विकास की पद्धति "अनियोजित" रूप से अपनाई गई, अर्थात् मूल्यों की व्यवस्थानुसार विकास हुआ (अन्य शब्दों में जिन उद्योगों में अधिक लाभ होता था वे ही विकसित किये गए) परन्तु रूस में असंतुलित विकास-पद्धति को 'आयोजनानुसार' अपनाया गया

रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना में 86 प्रतिशत पूँजी का विनियोजन पूँजी-गत वस्तुओं के उद्योग में किया गया और उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में केवल 14 प्रतिशत पूँजी लगाई गई। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी जो श्री महलानोबिस के प्रारूप पर आधारित थी, भारी उद्योगों पर अधिक बल दिया गया था योजना में भारी उद्योगों की स्थापना (इस्पात, इन्जीनीयरिंग, शक्ति, कोयला आदि) पर अधिक बल इस विश्वास पर दिया गया कि इन उद्योगों के विकास से जो मशीनें बनेंगी उनसे अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। बाद में जब पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक उन्नति की आधार शिला जम जाएगी, तो बाद में उपभोग वस्तुओं के निर्माण के उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार की विकास पद्धति में पहले बाह्य मितव्ययिताओं का horizontal transmission और फिर Vertical transmission होता है

थोड़े समय बाद उपभोक्ता-वस्तु उद्योग भी तेजी से भारी उद्योगों की बराबरी में आ जाते हैं। (The rate of growth of the consumer goods industries would asymptotically reach the rate of capital goods sector) और इसके पश्चात् फिर स्थायी व संतुलित विकास का युग शुरू हो जाता है

"असंतुलित विकास पद्धति में आय बढ़ने की दर से विनियोजन बढ़ने की दर अधिक होती है, आय स्वयं उपभोग वृद्धि की दर से अधिक बढ़ती है। इसके कारण वचत-आय अनुपात व पूँजी-उत्पादन अनुपात में लाभदायक परिवर्तन होते हैं। अतः में जाकर समस्त क्षेत्रों में विकास संतुलित हो जाता है, और विकास दर भी संतुलित विकास से अधिक रहती है।"

Li Fu Chun .

जो साम्यवादी चीन के आयोजन कमिशन के अध्यक्ष थे, 1960 में बजट भाषण के दौरान कहा था .

“विकास एक असंतुलन की अवस्था में दूसरी असंतुलन की अवस्था में पहुँचने से होता है. अर्थ-व्यवस्था असंतुलन से संतुलन की ओर फिर पुन. असंतुलन की ओर जाती है इस प्रक्रिया में हर बार उत्पादन व आय के स्तर ऊपर बढ़ जाते हैं विकास की इन्हीं तरंगों की परिवर्तनों से अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ती है.”

III : “संतुलित विकास पद्धति” व “असंतुलित विकास पद्धति” के संवध में संतुलित मत :

-Balanced view regarding the strategies of
- ‘Balanced’ or ‘Unbalanced growth’.

Paul Streeten : पाल स्ट्रीटन के विचार :

संतुलित विकास पद्धति व असंतुलित विकास पद्धति में से कौन सी पद्धति उत्तम है इस संवध में एक निर्णय देना ठीक नहीं होगा पाल स्ट्रीटन ने इस संवध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे बहुत ही संतुलित हैं और हम उन्हें यहाँ प्रस्तुत करते हैं

उनका कथन है कि :

“संतुलित व असंतुलित विकास की पद्धतियों के सम्बन्ध में वाद-विवाद निरर्थक है दोनों पद्धतियों के अपने-अपने दोष हैं. वस्तु स्थिति तो यह है कि कोई भी कम विकसित देश जब विकास के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहता है तो उसे देश के राजनीतिज्ञों को सिवाय असंतुलित विकास पद्धति अपनाने के और कोई रास्ता ही नहीं होता है कम विकसित देशों की इस नीति की अर्थशास्त्र के सिद्धान्त

Li Fu Chun : Quoted from ch. VIII of Gautam Mathur's book on Planning—“Balanced vs. Unbalanced Growth.” p. 113.

Paul Streeten : Balanced vs Unbalanced Growth . The Economic weekly April 28, 1963 p 669-71. G Meier : op. cit . p 259-63.

विशेषज्ञ को आलोचना नहीं करना चाहिए कम विकसित देश में अर्थव्यवस्था इतनी लचीली नहीं होती कि संतुलित विकास की पद्धति को अपनाया जा सके ।

“All investment creates unbalances because of rigidities, indivisibilities, sluggishness of response both of supply and of demand in these low elasticity economics and because of miscalculations ”

स्ट्रीटन कहते हैं कि असंतुलित विकास पद्धति से निश्चित ही विकास की दर अधिक रहती है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि समन्वय व पूरक विनियोजन” पद्धति की बिल्कुल अवहेलना कर दें दोनों प्रकार की विकास पद्धतियों में राज्य के आयोजन की आवश्यकता हो जाती है और दोनों प्रकार की पद्धतियों के अपनाने पर बाह्य मितव्ययिता का मूलन होता है

“It is not surprising that both balanced growth and unbalanced growth should be more effective presuppose each (a different kind of) planning for they are both concerned with lumpy investments and complementarities ”

स्ट्रीटन का ध्यान है कि जब कभी भी हम असंतुलित विकास पद्धति अपनाने तो हमको निम्नलिखित प्रश्नों पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए

- (I) क्या असंतुलन उत्पन्न करना आवश्यक है और इससे कोई हानि तो नहीं होगी ?
- (II) किन क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न करना चाहिए
- (III) कितना असंतुलन उत्पन्न करना चाहिए
- (IV) असंतुलन की अधिकतम व अनुकूलतम सीमा क्या होगी

बलवीर साहनी ने भी इसी प्रकार लिखा :

“आर्थिक विकास के आयोजन के लिए कोई एक पद्धति ही पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है विकास अर्थशास्त्र का स्वभाव ही ऐसा है कि कोई भी एक पद्धति, स्थगित आय सिद्धान्त के विपरीत, लागू नहीं होती ”

अध्याय : 21

रोसेन्स्तीन रोदान तथा उनका
“बड़ा धक्का” का सिद्धान्त

Rosenstein—Rodan and His “Big
Push Theory”

आलोचनात्मक विश्लेषण :

1. Jacob Viner.
2. H. E. Ellis.
3. J. H. Adler.
4. वर्तमान लेखक की नजर में.

रोसेन्स्तीन रोदान तथा उनका “बड़ा धक्का” का सिद्धान्त

Rosenstein—Rodan and His “Big Push
Theory”

आलोचनात्मक विश्लेषण

रोसेन्स्तीन रोदान सन्तुलित विकास के पक्ष में है परन्तु वे चाहते हैं कि यह सन्तुलित विकास पद्धति “बड़े धक्के” के रूप में अपनाया जाना चाहिए प्रो० रोदान ने अपने तर्क इस प्रकार से दिए हैं

प्रो० रोदान का कथन है कि कम-विकसित देशों में आर्थिक व सामाजिक सिरोपरी सुविधाओं (Social and economic overheads) की नीतान्त कमी है. निजी साहसियों के पास इन्हें प्रदान करने की न तो क्षमता होती है और न ही इच्छा होती है इस कारण राज्य को (जिसमें साधनों के लिए अन्य जरूरतों से भाग प्राप्त की जा सकती है) इन सिरोपरी सुविधाओं में (यातायात, संचार, शक्ति, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग आदि) अधिक मात्रा में एकदम धन लगाना चाहिए इस प्रकार के व्यय से निजी विनियोजकों तथा औद्योगीकरण के इच्छुक देशी व विदेशी व्यक्तियों को उद्योग खोलने की प्रेरणा व सुविधा मिलेगी

प्रो० रोदान का कथन है कि कम-विकसित देशों में धीरे-धीरे विकास करना सम्भव नहीं होगा यह तो केवल Big Push या “बड़े धक्के” से ही सम्भव हो

See : Rosenstein Rodan : “Problems of Industrialization of Eastern and S E Europe” Economic Journal June Sept 1943. pp. 204-7 “Notes on the Theory of Big Push” in Howard S. Ellis (ed) Economic Development for Latin America, St Martins Press N. York 1966 p 57-66 See : G Meier, leading issues in Economic Development p 431-440

व्ययिताएँ तो विदेशी व्यापार से भी प्राप्त हो सकती हैं और इतनी अधिक मात्रा में विनियोजन आवश्यक नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त Viner का कथन है कि बाह्य मितव्ययिताएँ "लागत अधिक घटाती हैं, उत्पादन उतना नहीं बढ़ाती" कम विकसित देशों में इसलिए यह नीति उपयुक्त नहीं होगी

H E Ellis : भी रोदान की उपयुक्त नीति को अपनाने की कठिनाइयाँ बतलाते हैं। वे इस नीति की निम्नकारणों से आलोचना करते हैं

(1) कम-विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादनकर्ता होते हैं। इन देशों में बाह्य मितव्ययिताएँ बढ़ने से इन वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

(11) दूसरे यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि विकास औद्योगीकरण से ही हो सकता है कृषि की उन्नति से नहीं हो सकता। कम-विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय या विदेशी व्यापार आय में से दो-तिहाई भाग कृषि से प्राप्त करते हैं इसलिए कृषि के विकास से कुल अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव है

(111) अगर हम विकसित देशों का इतिहास देखें तो हम पाएँगे कि उन देशों का विकास किसी "बड़े धक्के" के कारण नहीं हुआ था। तथा

(iv) रोदान ने कम विकसित देशों में वृद्धि की समस्या को ध्यान में नहीं रखा।

J. H. Adler भी यह सोचते हैं कि थोड़ी मात्रा में व धीरे-धीरे विनियोजन से अधिक लाभदायक परिणाम निकलेगे

वर्तमान लेखक की नजर में प्रो० रोदान का विचार ठीक है। आज हम इसी विचार को कृषि में (Package programme या Crash programme) लागू करते हैं जबकि एक साथ हम सिंचाई, बीज, खाद, उपकरण व साख आदि का एक सघन क्षेत्र में प्रवन्ध करते हैं "बड़े धक्के" से ही निर्यात क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और अन्ततः औद्योगीकरण से ही विकास हो सकता है। सोने हुए व्यक्ति या अर्थव्यवस्था को एकदम झकझोर कर ही उठाना पड़ता है अतः हम इस नीति को उचित ही मानेंगे।

अध्याय : 22

लीबिन्स्टीन का मॉडल

Harvey Leibenstein's Thesis of Critical
Minimum Effort

हार्वे लीबिन्स्टीन तथा उनका "अत्यावश्यक न्यूनतम
प्रयास" का विचार

1. प्रस्तावना
2. कम विकसित देशों की समस्याएँ
3. विकास के लिए Critical Minimum Effort अर्थात् "अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास" करना अनिवार्य है.
4. विकास के लिए उचित मनोवृत्ति तथा प्रेरणाओं का सृजन आवश्यक : Transformation of attitudes, motivation and "zero-sum" incentives necessary
5. Growth agents and entrepreneurs विकास के अंगों का महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक.
6. जनसंख्या : आर्थिक विकास तथा C. M. E
7. विकास के लिए उचित 'विनियोजन मानदण्ड'
8. विकास के साथ ICOR (Incremental capital output ratio) पूँजी-उत्पादन अनुपात गिरता है और इसीलिए C. M. E. करना आवश्यक है.
9. थम-उत्पादकता : विकास की एक कुंजी.
10. समीक्षा.

लीबिन्स्टीन का मॉडल

Harvey Leibenstein's Thesis of Critical Minimum Effort

1. प्रस्तावना :

हार्वे लीबिन्स्टीन ने अपनी पुस्तक *Economic Backwardness and Economic Growth* में कम विकसित देशों के संबंध में एक वाद 'Thesis' को जन्म दिया. यह विचार *Critical Minimum Effort* या "एक अव्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" से कम प्रयास न हो वरन् प्रयास की इस मात्रा को अवश्य कार्यान्वित किया जाए यह विचार *Rosenstein Rodan* के 'Big push' सिद्धान्त की भाँति है परन्तु विश्लेषण व सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह बड़ी उत्तम है.

लीबिन्स्टीन ने अपने इस शोध ग्रन्थ में उन कम विकसित देशों की समस्याएँ अध्ययन की हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है, अर्थात् भारत, चीन, इंडो-नेशिया जैसे देश उन्होंने अपनी इस पुस्तक की प्रस्तावना में जो लिखा है उनमें तीन बातें मुख्य हैं

- (1) एक तो उनकी पुस्तक का लक्ष्य कम-विकसित देशों की समस्याओं को समझना है न कि कम विकसित देशों की समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाना है (परन्तु उन्होंने महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं).
- (II) दूसरे उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पिछड़ेपन से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है, तथा
- (III) तीसरे उन्होंने अपनी पुस्तक में विकास के समस्त घटकों व नीतियों को अध्ययन नहीं किया है उनका मुख्य लक्ष्य तो उनके *Critical Minimum Effort* के 'Thesis' को समझना है.

"*Economic Backwardness and Economic Growth*" by Harvey Leibenstein.

Science Edition John Wiley & Sons Inc N. Y. 1957.

पुस्तक में Critical Minimum Effort को अथ C M E लिखा जाएगा.

ले विन्स्टीन ने बताया कि कुछ देश Stationary Equilibrium या "स्थैतिक साम्य" की अवस्था में रहते हैं. ये वे देश हैं जो हृदय के पिछड़े हुए हैं. उन्होंने अपने मॉडल में इन देशों को पृष्ठ भूमि में नहीं रखा है. लीविन्स्टीन के अनुसार विकसित देश Non-Equilibrium State या अमान्य की स्थिति में रहते हैं. उनकी यह प्रवैगिक साम्य की अवस्था उन्हें हमेशा दीर्घकालीन विकास की ओर ले जाती है. इन देशों में पूँजी स्टॉक, जनसंख्या, श्रम शक्ति, तकनीक व प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर परिवर्तन होने रहते हैं.

लीविन्स्टीन अपने आपको quasi-stable equilibrium या quasi-equilibrium (अर्ध-स्थैतिक साम्य या अर्ध-प्रवैगिक साम्य) की अर्ध-व्यवस्था से संबंधित बताते हैं. इस स्थिति में पूँजी स्टॉक, श्रम शक्ति, तकनीक आदि में परिवर्तन तो होते हैं परन्तु प्रति व्यक्ति आय में बहुत कम परिवर्तन होते हैं. प्रति व्यक्ति आय स्तर 'अर्ध-स्थैतिक' अवस्था में बनी रहती है. इन देशों में अर्ध-व्यवस्था अपने आप प्रगति नहीं कर सकती ('There is no built in mechanism of indigenous influences') बाह्य प्रयत्न ही (या Exogenous influences) से ही विकास हो सकता है.

लीविन्स्टीन के अनुसार कम-विकसित देशों की मुख्य समस्या Subsistence or near- subsistence equilibrium state या जीवन निर्वाह साम्य की स्थिति को तोटना है.

लीविन्स्टीन ने अपने मॉडल में मौद्रिक नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे महत्वपूर्ण घटकों को छोड़ दिया.

उनके अनुसार :

"No attempt has been made to consider every aspect of equilibrium (but to) shed some light on central aspects of the development problems." (p 185).

2. लीविन्स्टीन के अनुसार कम-विकसित देशों की समस्याएँ :

लीविन्स्टीन ने कम-विकसित देशों की विशेषताओं व समस्याओं का विश्लेषण

(पृष्ठ 40-41 देखिए) किया है, बेन्जामिन हिगिन्स के शब्दों में, उससे अच्छा विश्लेषण करना संभव नहीं है. इन विशेषताओं को उन्होंने इस प्रकार बताया है.

1 प्राथिक विशेषतायें व समस्याएँ :

A. सामान्य :

1. देश की अधिकांश, सामान्यतः 70 से 90 प्रतिशत, जनता कृषि पर निर्भर रहती है.
2. कृषि में "जनसंख्या अधिव्यय" मौजूद रहती है. अर्थात् कुछ कृषि में रत व्यक्तियों को कृषि कार्यों से हटा भी लिया जाए तो भी कृषि की उपज घटेगी नहीं.
3. कृषि क्षेत्र की जनसंख्या तो छपबेपी बेरोजगारी से पीड़ित रहती है और इस क्षेत्र से बाहर रोजगार के अवसर बहुत कम रहते हैं
4. प्रतिव्यक्ति पूँजी की उपलब्धि बहुत कम होती है.
5. प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण निम्नजीवन स्तर होता है.
6. अधिकांश जनता की वचतो की मात्रा शून्य होती है.
7. जो व्यक्ति वचत करते हैं वे उत्पादन कार्यों में नहीं लगाते
8. कृषि, वन व खानों में जो रोजगार प्राप्त होता है, वह स्थानीय प्रकृति का होता है.
9. कृषि उपज मुख्यतया खाद्यान्नों की होती है. देश में प्रोटीन पदार्थों की उपज कम रहती है.
10. जनता का अधिकांश व्यय खाद्य पदार्थ तथा आवश्यक आवश्यकताओं पर होता है
11. निर्याती वस्तुएँ, बहुधा प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएँ होती हैं
12. निर्यात की प्रति व्यक्ति मात्रा बहुत कम होती है
13. देश में साख व विपणन सुविधाएँ अत्यन्त कम होती हैं
14. देश में आवास की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रहती है

B. कृषि की मुख्य बातें :

1. कृषि में लगी पूँजी की मात्रा न केवल कम होती है वरन् जो भी पूँजी लगी

रहती है उसका ही दग से प्रयोग नहीं हो पाता, जिसका मुख्य कारण भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटा होना होता है

2. कृषि अत्यन्त पिछड़े औजारों और तकनीकी आधार पर की जाती है.
3. यातायात के साधनों तथा माँग की कमी के कारण बाजार सकीर्ण रहते हैं. केवल थोड़ी सी कृषि ही आधुनिक रीतियों के आधार पर होती है.
4. छोटे-छोटे किसान अल्पकालिक विपत्ति का भी सामना नहीं कर पाते कृषि इस प्रकार से की जाती है कि भू चरण बहुत होता है.
5. कृषकों की ऋण प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है
6. कृषि उपज का बहुत थोड़ा भाग विपणन के लिए बचता है.
7. भू-स्वामित्व प्रणाली इस प्रकार से होती है कि अधिकांश जनता जमीन की भूखी होती है कुछ व्यक्ति अधिक जमीन के मालिक बने रहते हैं.

2 जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ :

1. इन देशों में जन्म दर बहुधा 40 प्रति हजार से अधिक होती है
2. इन देशों में मृत्यु दर भी अधिक होती है, अर्थात् औसत आयु कम होती है
3. योगों के आहार असंतुलित होने हैं
4. देश की अधिकांश जनता का रहन-सहन निम्नकोटि का होता है
5. साफ-सफाई के तरीके पिछड़े हुए होते हैं व स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएँ भी कम होती हैं.
6. मकानों में Over crowding होती है या प्रति व्यक्ति कम स्थान प्राप्त होता है.

3. सांस्कृतिक व राजनैतिक :

1. देश में शिक्षा का स्तर निम्न रहता है तथा शिक्षित व साक्षर व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशान कम होता है.
2. देश के कई बच्चों को भी विद्या अध्ययन के स्थान पर कार्य करना पड़ता है
3. देश में मध्यम वर्ग कम व कमजोर होता है.
4. देश में स्त्रियों का स्थान निम्नस्तर का रहता है.
5. अधिकांश जनता परम्परागत रीति-रिवाजों की गुलाम रहती है.

4. तकनीकी व अन्य विशेषताएँ :

1. देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता कम रहती है.

II : लीविन्स्टीन मानते हैं कि हर बात में Critical Minimum Effort नहीं किया जा सकता. हर बात एकदम नहीं की जा सकती कभी कभी यह अधिक अच्छा होता है कि किसी विनियोजन को 10 वर्षों में फैला दिया जाय न कि सारा का सारा एक ही वर्ष में कर दिया जाय हर विनियोजन को न्यूनतम माना का अनुकूलतम स्तर होता है.

"This implies that the critical minimum effort viewed as a minimum minimumum of all possible efforts that would lead to sustained real income growth involves an optimum time pattern of expenditure or effort" (P 105)

C : C M. E. की आवश्यकता क्यों होती है ?

लीविन्स्टीन अपने C M E की आवश्यकता तथा वांछनीयता के पक्ष में कई तर्क देते हैं, जिनमें से मुख्य यह है :

1. उत्पादन में बहुत सा विनियोजन इस प्रकार का होता है कि जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता अगर ऐसा किया तो बाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त नहीं हो सकती (To overcome internal diseconomies of scale due to indivisibilities the factors of production)
2. देश में सतृलित विकास के लिए C.M E. आवश्यक होगा. (Balanced growth requires lumpy investment and because of the indivisibilities C M E will be necessary)
3. कभी-कभी विकास के परिणामस्वरूप ही विकास बाधक तत्व सामने आते हैं. जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर कम होती है और जनसंख्या बढ़ती है इसके लिए यह आवश्यक होगा कि C M E. द्वारा इतना व्यय कर दिया जाए कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ जन्म दर भी कम हो जाए
4. विकास पुरानी मान्यताओं, आस्थाओं, विचारों व रीति रिवाजों को भेदने से होता है C M E. से कम विनियोजन से यह नहीं टूटते. ये तो केवल C M. E. से ही टूटेंगे परिवर्तन से ही परिवर्तन उत्पन्न होते हैं. इसके लिए C. M. E. ही जरूरी है

इसी अध्याय में जनसंख्या संबंधी Point देखिए

“Hence a sufficiently large minimum effort is necessary at the outset if the necessary minimum momentum is to be achieved”

4 Transformation of attitudes, motivation and “zero sum incentives necessary” विकास के लिए मनोवृत्ति तथा प्रेरणाओं में परिवर्तन

लीविन्स्टीन का कथन है कि आर्थिक विकास तब हा हो सकता है जबकि देश की अधिकांश जनता को पुरानी मनोवृत्तियाँ बदल न दी जाएँ देश की अधिकांश जनता की उद्यमीन मनोवृत्ति को बदल कर उन्हें आय बढ़ान की इच्छुक तथा जोखिम उठान की शौकीन बनाना होगा लीविन्स्टीन का कथन है कि कम विकसित देशों में दो प्रकार के Incentives या प्रेरणाएँ होती हैं

(1) Zero Sum Incentives लीविन्स्टीन का कथन है कि कम विकसित देशों में उत्पादन में रत व्यक्तियों के अनुपात में अधिक श्रम वितरणीय कार्यों में नग रहते हैं इस प्रकार के उद्योगों में नग रहने में देश की वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती बरन केवल भाग्यहीन साहसियों में धन भाग्यशाली साहसियों को हस्तांतरण होता है इस प्रकार का कार्य केवल व्यापारिक जोखिम होता है Zero Sum Incentives में व्याक्तगत लाभ कम व अधिक हो सकता है परन्तु सामाजिक लाभ नहीं है इस प्रकार के कार्यों में एक व्यक्ति के पास में दूसर व्यक्ति के पास तरलता का हस्तांतरण होता है

(ii) Positive Sum Incentives इस प्रकार के कार्यों से लीविन्स्टीन का आशय उत्पादन कार्यों से है इनमें न केवल व्यापारिक जोखिम है बल्कि स्वयं उत्पादन सबंधी जोखिम भी होते हैं जब देश में positive sum enterprises का विकास होता है तबही विकास होता है

लीविन्स्टीन का कथन है कि कम विकसित देशों में आवश्यकता इस बात की है कि (i) देश में zero sum incentives व enterprises कम हो तथा (ii) positive sum incentives व enterprises बढ़ देश में posi

tive sum enterprises को कायम रहना चाहिए, उनका विकास अल्प-कालिक नहीं होना चाहिए

कभी-कभी positive-sum incentives स्वयं ही zero-sum incentives को बढ़ावा देते हैं जिसको रोकना चाहिए उदाहरणतया अगर देश में positive-sum enterprises में मुद्रा स्फीति फैलती है तो सट्टे के zero-sum enterprises उत्पन्न होने हैं इसी प्रकार से एकाधिकारी प्रवृत्तियों से zero-sum incentives को बढ़ावा मिलता है, आवश्यकता इस बात की है कि देश में zero-sum incentives से positive-sum incentives अधिक हो, उन्होंने कहा

“To overcome these influences which keep the economy in a state of economic backwardness a sufficiently critical minimum effort is required to sustain a rapid rate of economic growth which should stimulate a positive-sum incentive and create forces for counteracting zero-sum incentives.” (अर्थात् अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उन दुःप्रभावों को जो कि एक देश को गरीब रखते हैं, दूर करने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम माना में ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे positive-sum incentives बढ़ें तथा zero-sum incentives के दुःप्रभाव दूर हो)

5 Growth Agents and Entrepreneurs : विकास के अग्रे तथा साहसी

लीविन्स्टीन का कथन है कि ‘विकास, विकास के अग्रे का कार्य है विकास अग्रे का अर्थ “जनमस्या में निहित उन क्षमताओं से है जो विकास करती हैं, जब देश में इन क्षमताओं का सख्यात्मक व गुणात्मक विकास होता है तो देश के इन विकास अग्रे का विकास होता है-

लीविन्स्टीन का मत है कि growth agents के विकास से आर्थिक विकास होता है और जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे-वैसे “उत्पादन अग्रे” का विकास होता है और growth agents ही positive-sum incentives को जन्म देते हैं व उनके कारण जन्म लेते हैं.

लीविन्स्टोन "साहसियों की क्षमता" को एक विशिष्ट प्रकार का गुण मानने हैं साहसी का मुख्य कार्य विनियोजन की मुख्य मंशों को चुनना होता है, वे उत्पादन के साधनों को जुटाते हैं, वे नये उद्योग शुरू करते हैं और हर चीज को बड़े पैमाने पर करते हैं। कम-विकसित देशों में साहसियों की पूर्ति कुछ ही जातियों या वर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जब पिछड़ी जातियों या वर्गों से भी साहसी उत्पन्न होने लगे तो विकास सुनिश्चित होता है।

साहसियों का मुख्य कार्य विनियोजन के उचित अवसर खोजना होता है। उनके कार्यों की सफलता उचित भौतिक व राजकोपीय नीतियों, उत्पादन के ऋणों के मूल्यों, साधनों की खोज आविष्कारों, बाजार की स्थिति आदि पर निर्भर करता है।

साहसियों के कार्यों में वृद्धि से प्रति-व्यक्ति आय बढ़ती है और प्रति-व्यक्ति आय बढ़ने से ही साहसियों के कार्यों बढ़ते हैं। कम-विकसित देशों में सबसे बुरी बात है कि इन देशों में साहसी के कार्यों को उचित महत्व नहीं दिया जाता है।

। में जब साहसियों की positive-sum activities बढ़ जाती हैं तो देश वास्तविक आय में वृद्धि हानी है और यह पुनः उनको positive-sum activities में लगने को प्रोत्साहित करती है।

विकास की बहुत सी दूरी हो सकती है। हर क्षेत्र में एक दर से विकास नहीं हो सकता किन्हीं क्षेत्रों के प्रति 'विकास अग्र' उदासीन रहते हैं या सुस्त रहते हैं। zero-sum activities हमेशा विकास की दर को कम रखती हैं। बहुत अधिक विकास की दर भी थोड़े समय बाद bottlenecks (या भिन्न-भिन्न प्रकार के अवरोधों के कारण) कायम नहीं रह पाती विकास के मध्यम दर अच्छी होती है परन्तु शुरू में हमको "आवश्यक न्यूनतम" प्रयास आवश्यक करना चाहिए।

"The rate of growth will depend on the interaction between the plans for expansion of the various growth agents, their simultaneous attempts to carryout these plans based on anticipations about the economic environment in the future and the actual rate of growth that results from these simultaneous activities which in turn, determine the plans and activities of succeeding period."

(p. 144) p 121-150] op. cit.

6. Population : Economic Growth and C. M. E.

जनसंख्या : आर्थिक विकास : तथा C. M. E.

जितनी जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी उतनी ही मात्रा में उस कम-विकसित देश को निम्न जीवन स्तर के फन्दे से निकलने के लिए अधिक मात्रा में 'अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास' करने होंगे. (अध्याय 10)

जनसंख्या और विकास के सम्बन्ध में लीविन्स्टीन ने कई मुद्दों पर विचार किया, जिनमें निम्नलिखित मुद्दे मुख्य हैं.

जनसंख्या का घनत्व व विकास :

लीविन्स्टीन अधिक घनत्व को विकास में बाधक अथवा कम घनत्व को विकास कारक नहीं मानते. विकास तो देश के प्राकृतिक साधनों की किस्म व मात्रा, पूँजी की उपलब्धि, तकनीकी स्तर व उत्पत्ति के नियमों पर निर्भर रहता है. उन्होंने बताया कि अमेरिका के "रेड-इन्डियन्स" का घनत्व तो बहुत कम था फिर भी पिछड़ी तकनीक के कारण वे विकास नहीं कर पाए.

जन्म दर व आर्थिक विकास :

लीविन्स्टीन यह भी नहीं मानते कि जब तक कि जन्म दर गिरे नहीं तब तक विकास नहीं हो सकता. उन्होंने कहा "हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि जन्म दर में कमी भी विकास का परिणाम होता है. आर्थिक विकास बगैर कोई भी प्रत्यक्ष तरीके, जन्म दर नियंत्रण में सफल नहीं हो सकते. वास्तव में पहले तो आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू करना होगा".

जनसंख्या की अवस्थाएँ तथा अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास :

लीविन्स्टीन ने कम-विकसित देशों में जनसंख्या सम्बन्धी अवस्थाओं का अध्ययन किया. उन्होंने C. P. Black, W. S. Thompson तथा F. W. Notestein द्वारा बताई गई अवस्थाओं का अध्ययन किया* इन अर्थशास्त्रियों का, मोटे मोटे रूप से, यह विचार है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी उन्नति के साथ जन्म दर भी घटती जाती है. सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, स्त्रियों के समाज में स्तर की उन्नति, नगरीयकरण आदि से जन्म दर में कमी होती है.

* p. 151-152.

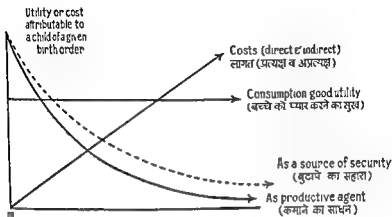
लीविन्स्टोन ने जनसंख्या की अवस्थाओं तथा जनसंख्या व विकास के सह-संबंध में स्वयं के विचार प्रस्तुत किए। लीविन्स्टोन का कथन है कि कम-विकसित देशों के लोग विवेकशील नहीं होते वे यह नहीं जानते कि गर्भधारण को कैसे रोका जा सकता है वे सहवास क्रिया व प्रजनन क्रिया को अलग नहीं कर पाते। उनके पास जनसंख्या निरोध के साधन नहीं होते हैं और वे बहुधा इस पर अधिक ध्यान भी नहीं देते

कम-विकसित देशों में मृत्युदर की अधिकता के कारण अधिक बच्चे पैदा करने पड़ते हैं अन्यथा बुढ़ापे में कोई व्यक्ति झोलाधारी रह सकता है। इन देशों में बच्चों पालने का खर्च अधिक नहीं होता गरीब के बच्चों को खर्च केवल जीवन निर्वाह के बराबर देना पड़ता है जब कि अमीर के बच्चों को उच्च शिक्षा व रहन-सहन के कारण अधिक खर्च करना पड़ता है इसलिए कम-विकसित देशों में बच्चों के उत्पन्न होने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसकी लागत से अधिक रहती है।

लीविन्स्टोन का कथन है कि एक नवजात बच्चा तीन प्रकार की उपयोगिता देता है :

- (1) वह एक Consumption goods है या वह एक उपभोग वस्तु है, अर्थात् वह माँ-बाप को उसे खिलाने (प्यार करने) का सुख देता है।
- (ii) वह एक Productive agent भी है, अर्थात् वह स्वयं काम कर खिला सकता है और कम-विकसित देशों में वह यह काम कम आय में ही कर सकता है।
- (iii) वह Source of security या बुढ़ापे का सहारा है।

लीविन्स्टोन का कथन है कि कम विकसित देशों में बच्चे पैदा होने की मात्रा को हम माँग व पूर्ति के आधार पर दर्शा सकते हैं। अर्थात् यहाँ भी बच्चे पैदा होता (माँग) लाभ व (पूर्ति) लागत के आधार पर निर्धारित होता है इसे वे इस प्रकार से दर्शाते हैं :



उपरोक्त चित्र में :

- (i) Cost रेखा बच्चों के जन्म से बढ़ती है. प्रत्यक्ष लागत का अर्थ बच्चे को खिलाने व पहनाने का खर्च होता है, तथा अप्रत्यक्ष लागत से यहाँ उनका अर्थ "अवसर लागत" से है. बच्चे पैदा होने के समय या बाद में बहुधा माँ-बाप को काम से छुट्टी लेनी पड़ती है या उनकी आय व गतिशीलता कम हो जाती है इसलिए 'लागत' बढ़ती जाती है.
- (ii) बच्चे से प्राप्त होने वाली "उपभोग उपयोगिता" समान माना है. यह मानते हैं कि हर बच्चा समान आनन्द देता है और आय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है.
- (iii) जहाँ तक बच्चे से प्राप्त होने वाली Productive agent utility व security utility मिलती है, यह माना गया है कि आय के बढ़ने से हर आने वाले बच्चे का इस सम्बन्ध में महत्व घटता जाता है.

इन मान्यताओं के आधार पर लोबिन्स्टोन का कथन है कि कम-विकसित देशों में केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर ही जन्म दर घटेगी, अर्थात् उनका कथन है कि

पहले जन्म दर को घटा कर विकास नहीं होता वरन् पहले विकास होना चाहिए और फिर जन्म दर घटेगी। पहले विकास के लिए Critical Minimum Effort या 'अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास' जरूरी होगा।

A. कम आय

जब अधिकांश व्यक्तियों की प्रति-व्यक्ति आय कम होती है तब मृत्यु दर अधिक होती है और इसलिए बच्चों की एक न्यूनतम मात्रा के लिए अधिक बच्चे पैदा करने पड़ते हैं क्योंकि कुछ तो मर जाते हैं, फिर पालने का खर्च भी तो कम होता है बच्चों के तीनों प्रकार की उपयोगिताएँ अधिक होती हैं। ऐसी अवस्था में अधिक जन्म दर होने हुए भी इतने बच्चे बचते हैं कि वे अपने माँ-बाप का प्रति-स्थापन ही कर पाते हैं, अर्थात् जन-संख्या वृद्धि नहीं होती।

B. अधिक आय

जब देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तब मृत्यु दर घट जाती है, परन्तु जन्म दर तत्काल नहीं घटती, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों को मृत्युदर के घटने का आभास देर से होता है। बच्चों की अनुत्पादक आय से उनकी उत्पादक आय बढ़ जाती है। इस समय में बच्चों की "उत्पादन उपयोगिता" व "सुरक्षा उपयोगिता" एकदम बढ़ती है इस कारण जन्म दर घटाने की कोई प्रेरणा नहीं रहती।

C. और अधिक आय वृद्धि :

और आय बढ़ने पर तथा अधिक बच्चों के जिन्दा रहने पर बच्चों की "उपभोग उपयोगिता" घट जाती है। फिर अधिक धनी व्यक्ति के बच्चे जल्दी नहीं ब्रमाते तो इससे उनकी 'उत्पादन उपयोगिता' घट जाती है, और "सुरक्षा उपयोगिता" की भी इतनी जरूरत नहीं रहती।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ों व अन्य खर्चों के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें भी बढ़ जाती हैं।

ऐसी अवस्था में लागतें जब लाभ से बढ़ जाती हैं तो फिर जन्म दर को कम रखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इस प्रकार से जनसंख्या की चार मुख्य अवस्थाएँ हो सकती हैं।

अगर किसी क्रम-विकसित देश के वर्तमान आय स्तर डम "अत्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" से कम हो तो विकास केवल तब हो सकता है जब अर्थव्यवस्था के बाहर से (जैसे विदेशी सहायता से) एक बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में विनियोजन का "इन्जेक्शन" दिया जाए

जैसा कि हम देख चुके हैं कि सीबिन्स्टीन यह नहीं चाहते कि यह समस्त विनियोजन एक बार में एकमुश्त कर दिया जाए. समयानुसार यह छोटी छोटी मात्रा में भी किया जा सकता है. उनको योजना यह है कि विनियोजन के कई "इन्जेक्शन" इस प्रकार से दिए जाएँ कि वे एक निश्चित काल में देश की प्रति-व्यक्ति आय को "आवश्यक न्यूनतम स्तर" पर पहुँचा दे. हर "इन्जेक्शन" को इस प्रकार से लगाया जाय कि इससे पहले कि प्रथम "इन्जेक्शन का प्रभाव समाप्त हो, दूसरा "इन्जेक्शन" लगा दिया जाए. वे इस बात को मानते हैं कि एक बड़े "इन्जेक्शन" के स्थान पर विनियोजन के कई छोटे छोटे इन्जेक्शन, अगर उन्हें उचित समय के अन्तर से लगाया जाये (if they are optionally spaced) तो वे अधिक प्रभावशील होंगे.

परन्तु यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि बहुत छोटे छोटे विनियोजन भी प्रभावशील नहीं होते. हर विनियोजन के इन्जेक्शन की भी "आवश्यक न्यूनतम मात्रा" होती है जिससे कम विनियोजन नहीं हो सकता

सीबिन्स्टीन का कथन है कि Indivisibilities of capital goods (जैसे कोई पूंजीगत मशीन स्वयं में ही बड़ी होती है और उसे टुकड़ों में तो लगा नहीं सकते वरन् पूरी ही लगानी पड़ेगी) तथा Complementarities (अर्थात् आवश्यक पूरक विनियोजन के कारण) हमेशा विनियोजन की 'आवश्यक न्यूनतम मात्रा' होती है और उससे कम खर्च नहीं किया जा सकता

इस प्रकार से विकास-कारक विनियोजन की 'न्यूनतम' व 'अधिकतम' मात्राएँ निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक होता है

Investment Criteria विनियोजन नीति

जहाँ तक उचित विनियोजन नीति का प्रश्न है, सीबिन्स्टीन Kahn के The Marginal or Social Marginal Productivity Criteria (सीमान्त उत्पादकता या सामाजिक सीमान्त उत्पादकता मान दण्ड) तथा

Nurkse के The Employment Absorption Criteria (रोजगार मान दण्ड) तथा Kahn and Viner के Investment in Agriculture कृषि विनियोजन मान दण्ड को अस्वीकार करते हैं

A उनका कथन है कि Kahn की Marginal or Social Marginal Productivity Criteria के अनुसार विनियोजन करने से राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि नहीं हो सकती, और न ही इसमें प्रति-व्यक्ति आय अधिकतम होती है इसके अतिरिक्त विनियोजन की 'सीमांत सामाजिक उत्पादकता' पता नहीं लग सकता

B. इसी प्रकार से लीविन्स्टोन Nurkse के "रोजगार वृद्धि" मानदण्ड को भी अस्वीकार करते हैं. Nurkse का कथन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, यह है कि कम-विकसित देशों में विनियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि अधिकतम लोगो को रोजगार मिल सके, और देश में श्रम गहन तकनीक अपनाई जाए. लीविन्स्टोन का कथन है कि अगर पूंजीमहन विनियोजन को कम रखा गया तो देश में उत्पादन विकास का निर्माण नहीं होगा, और इससे विकास की आगदानी घीमी रहेगी उनका कथन है

"The full employment of those believed to be disguisedly unemployed seems pointless of other investment policies yield higher growth rates, unless it be done for its own sake" (p. 251)

C लीविन्स्टोन Kahn तथा Viner के इस विचार से भी सहमत नहीं हैं कि कम-विकसित देशों को अधिकाधिक विनियोजन सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र में करना चाहिए कृषि उन्नति में ही औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार में उन्नति तथा हर क्षेत्र का विकास होगा

लीविन्स्टोन का कथन है कि इस नीति से अल्पकाल में अवश्य लाभ होगा, परन्तु कृषि क्षेत्र में विकास से 'विकास का दातावरण' निर्मित नहीं होता गाँव के विकास से देश में 'श्रमिक कुशलता, तकनीक, आविष्कार, ज्ञान तथा साहसियों की गतिविधियों में उन्नति व प्रगति नहीं होती "

इसके अतिरिक्त कृषि में अधिकाधिक विनियोजन से बहुधा जमींदार व बड़े किसान लाभान्वित होते हैं. ये अपने लाभ को सोना-चाँदी, भूमि तथा सट्टों में लगा देते हैं.

D. Investment in both physical and human capital, should be on critical minimum basis

लीविन्स्टोन के अनुसार विनियोजन भौतिक व मानवीय दोनों प्रकार की पूँजी वृद्धि में होना चाहिए और यह "न्यूनतम आवश्यक मात्रा" में होना चाहिए जहाँ कल व कारखानों, मशीनों व खेतों में अधिकाधिक विनियोजन हो वहाँ देश में शिक्षा ज्ञान, तकनीक तथा कार्य कुशलता में वृद्धि होना चाहिए, देश में विनियोजन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि देश में साहसियों को बढ़ावा मिले तथा जिससे श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हो विनियोजन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे देश में वचते भी प्रोत्साहित हो तथा जिससे जनसंख्या वृद्धि भी कम हो

विनियोजन नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें और विनियोजन हा दीर्घकाल में विनियोजन का लक्ष्य उपयोग और विलासिताओं का उपयोग बढ़ाना होगा परन्तु मल्पकाल में मर्वागीख उत्पादन क्षमता में विकास करना ही सर्वोपरि होता है

"In the long run, endless growth for its own sake does not make too much sense At some point the populace may become more concerned with enjoying the fruits of its development than maintaining the maximum rate of development...Then the problem of maximising current consumption and luxuries will be more important...But it is not our immediate problem." (p 267 8)

8 Capital-output Ratios and Critical Minimum Efforts पूँजी-उत्पादन अनुपात व "आवश्यक न्यूनतम प्रयास" .

"The diminishing capital-out put ratios, as growth increases, reinforce the critical minimum effort thesis for once the initial high capital-output ratio is overcome, the obstacle to economic growth is reduced, since

"a smaller rate of saving is necessary in order to induce further growth." (p 184)

लीविन्स्टीन का कथन है कि विकास के साथ-साथ पूँजी-उत्पादन अनुपात घटता जाता है। इसलिए घटते हुए पूँजी-उत्पादन अनुपात की स्थिति को पहुँचने के लिए "न्यूनतम आवश्यक प्रयास" करने ही होंगे, इससे कम मोटे मोटे रूप से जब भी हम Capital-output ratio शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा आशय Incremental capital-output ratio से होता है। Incremental capital-output ratio (ICOR) से हमारा अर्थ "उस दर से होता है जिस दर से विनियोजन के परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में किसी वर्ष में शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है" उदाहरणन अगर राष्ट्रीय आय का 15% भाग विनियोजित किया जाता है, और अगर यह विनियोजन राष्ट्रीय आय में 5 : 1 के अनुपात से परिवर्तन लाता है तो ICOR 3% हुआ।

लीविन्स्टीन का कथन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की घटती हुई ICOR दर महत्वपूर्ण कारण है उनका विश्वास है कि "अगर विनियोजन "आवश्यक न्यूनतम मात्रा" में कर दिया जाए तो ICOR घटेगा और विकास होगा"

लीविन्स्टीन ने श्री धी डी भट्ट के इस विचार से असहमति प्रकट की कि विकास के साथ ICOR बढ़ जाता है श्री भट्ट का तर्क यह था कि कम-विकसित देशों में उत्पादन में मशीनीकरण होगा और मजदूरी दर बढ़ने से जब मजदूरों के स्थान पर मशीनें प्रतिस्थापित की जाएगी तो ICOR बढ़ जाएगा एक और अन्य कारण जो श्री भट्ट ने बताया वह यह है कि विकास के साथ जब प्राकृतिक साधनों की कमी आएगी (जैसे लोहे आदि की कमी) तो मशीनों की लागत बढ़ जाएगी और ICOR बढ़ जाएगा

परन्तु लीविन्स्टीन इस मत में पूर्णतः असहमत होते हुए निम्नलिखित तर्क देते हैं जिनके आधार पर वे यह साबित करना चाहते हैं कि विकास के साथ ICOR घटता है और ICOR के घटने से विकास होता है

- (1) विकास के विनियोजन के कारण श्रम की कार्यक्षमता, उत्पादकता बढ़ जाएगी जिससे ICOR घट जाएगा

- (ii) विकास के साथ-साथ जो राष्ट्रीय आय बढ़ती है और जो श्रम विभाजन में विस्तार होता है उससे भी ICOR घटेगा
- (iii) शिक्षा व ट्रेनिंग के ऊपर होने वाले व्यय से श्रम की विस्म में सुधार होता है, जिससे मशीनीकरण के समान स्तर पर ही श्रम के प्रयत्न के कारण उत्पादकता बढ़ जाती है और ICOR घट जाती है।
- (iv) विकास के साथ-साथ आर्थिक क्रियाओं का केन्द्रीयकरण कृषि के प्राथमिक क्षेत्र से हटकर Tertiary (तृतीयक क्षेत्र-यातायात संचार व व्यापार) में लग जाता है इससे भी ICOR घटता है
- (v) फिर जैसे जैसे विकास हो जाता है भारी मशीनों की आवश्यकता घट जाती है और ICOR घट जाता है

9. Labour Productivity Also A Key Factor in Promoting Growth : श्रम उत्पादकता-विकास की एक कुंजी .

अन्य समस्त अर्थशास्त्रियों की भांति लीविन्स्टोन भी स्वाभाविक रूप से श्रम की उत्पादकता वृद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास है कि अगर कम विकसित देशों में श्रमिक को पर्याप्त मजदूरी दी जाय तो उनके स्वास्थ्य सुधार से उनके गैरहाज़िर रहने की प्रवृत्ति कम होगी, उनके उपभोग वृद्धि से स्वास्थ्य सुधरेगा और उनके कार्य करने की शक्ति व इच्छा में वृद्धि होगी।

लीविन्स्टोन का कथन है कि केवल मजदूरी बढ़ा देने से ही श्रम की कार्यशक्ति नहीं बढ़ती अगर श्रमिक की मनोवृत्ति भी विकास के प्रति बढ़ती है तो श्रमिक के वेतन बढ़ने से वह अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा अन्यथा वह अधिक मजदूरी प्राप्त होने पर अधिक आराम करना पसंद करेगा देश में कुशलता वृद्धि (Skill development) के लिए पर्याप्त धन व्यय किया जाना चाहिए शिक्षा के विकास से ही कुशलता वृद्धि होती है। देश में पूँजी को गहन रूप से लगाने में अधिक 'कुशलता' की आवश्यकता होती है और विस्तृत रूप में लगाने में कम आवश्यकता होती है। (capital deepening activities require more skill than capital widening). श्रम की गतिशीलता से भी श्रम उत्पादकता बढ़ती है जो कि विकास के लिए परम आवश्यक है।

(i) See also : Colin Clark : Conditions of Economic Progress 2nd Edition, London, Macmillan & Co. Ltd 1951 Ch-XI, Csp p. 500-4.

(ii) श्रम उत्पादकता अध्याय ६ लीविन्स्टोन तथा पृष्ठ 141.

An Appraisal of Leibenstein Model of Growth लीविन्स्टोन मॉडल की समीक्षा •

जैसा कि हम देख चुके हैं, लीविन्स्टोन मॉडल की विचारधारा Rosenstein Rodan की Big push theory से मिलती है. उनका Critical Minimum Effort का विचार रोदान के “बड़े धक्के” के विचार से अधिक व्यावहारिक है। उसमें जितनी पूँजी की आवश्यकता पड़ जाएगी उससे इस नीति को अपनाने में कम पूँजी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लीविन्स्टोन तो CME, विनियोजन को कई भागों में बांटने को भी संभव मानते हैं।

फिर भी, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उन्होंने राजकोपीय, राज्य-नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार व सहायता आदि नीतियों के विकास पर प्रभाव को अध्ययन न करके अपने मॉडल की व्यापकता कम कर दी।

विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन

खण्ड : 2

आर्थिक विकास नीतियाँ

देश के प्राकृतिक साधन व आर्थिक विकास

Natural Resources and Economic Growth

विकास के लिए प्राकृतिक साधनों के प्रयोग की नीति

Resource Utilisation Policy for Growth

1. "प्राकृतिक साधनों" का अर्थ
2. विकास में प्राकृतिक साधनों का महत्व
प्रथम मत : (A) प्राकृतिक साधनों का महत्व नहीं है.
दूसरा मत : (A) विकास में प्राकृतिक साधन महत्वपूर्ण.
(B) सतुलित मत.
3. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग को निर्धारित करने वाले तत्व.
1. पूँजी, 2. साहस व संगठन, 3. तकनीक, 4. बाज़ार, 5. श्रमशक्ति
6. सामाजिक तत्व, 7. राज्य.
4. प्राकृतिक साधनों की प्रयोग नीति
 1. सर्वेक्षण करें तथा लिस्ट बनायें
 2. पूँजी का संघय पर्याप्त मात्रा में किया जाय
 3. देश की अर्थ व्यवस्था के प्रमुख तकनीक अपनायी जाय.
 4. स्थानीय साधनों का प्रयोग हो
 5. साधनों का वर्तमान प्रयोग और भविष्य में प्रयोग सतुलित रखा जाय.
 6. साधनों का बहुउद्देशीय प्रयोग होना चाहिए
 7. श्रम बाज़ार उन्नत करें.
 8. बाज़ार स्थिति के पर्याप्त व व्यापक सर्वेक्षण हों.
 9. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में धरवासी कम से कम होना चाहिए तथा साधनों के परीक्षण को भी ध्यान में रखना चाहिए.
 10. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में अवरोधों व रुकावट डालने वालों को दूर किया जाये.
 11. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के लाभ अधिकाधिक व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए.
 12. अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए.
 13. प्राकृतिक साधनों का प्रयोग तथा राज्य

देश के प्राकृतिक साधन व आर्थिक विकास

Natural Resources and Economic Growth
विकास के लिए प्राकृतिक साधनों के प्रयोग की नीति
Resource Utilisation Policy for Growth

1. "प्राकृतिक साधनों" का अर्थ .

1. जैसा कि सर्वविदित है कि आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक विकास के लिए तीन प्रकार के साधनों की आवश्यकता मुख्य है. ये साधन हैं

(i) प्राकृतिक भौतिक साधन, (ii) मानवीय साधन तथा

(iii) मनुष्य द्वारा उत्पादित भौतिक साधन (या पूँजी) Eric Zimmermann ने प्राकृतिक साधनों की परिभाषा इस प्रकार दी है .

"प्राकृतिक साधन भौतिक वातावरण के वे भाग होते हैं जिनसे मानव अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन प्राप्त करता है."

2. प्राकृतिक साधनों के अन्तर्गत हम समस्त भूमि (जो चाहे कृषि के प्रयोग में लाई जा रही हो अथवा नहीं), जंगल, पानी, धातुएँ आदि शामिल करते हैं जब कि पानी व जंगल Renewable resources हैं या पुनः उत्पादन योग्य साधन हैं, धातुओं को हम Exhaustible resources या समाप्त होने वाले साधन कहेंगे.

3. प्राकृतिक साधनों का हमने Dynamic या प्रवैगिक अर्थ लेना चाहिए. साधनों की मात्रा भौतिक मात्रा के रूप में ही नहीं माँकी जाती है. तकनीक

See : (i) Joseph. L. Fisher : Role of Natural Resources in Growth : in Williamson & Buttrick : Economic Development, Principles & Pattern, Prentice-Hall Inc. 1962, p. 26

(ii) Economic Development, Ed. Adamantios Papalasis, Leon Mears, Irma Adelman: Ch. II. Natural Resources.

में उन्नति, जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन, यातायात, संचार, पूंजी की मात्रा में वृद्धि, एवं परिवर्तन आदि से इनके प्रयोग में वृद्धि हो जाती है और इस रूप में हम प्राकृतिक साधनों को बढ़ता हुआ मान सकते हैं।

4. हर प्राकृतिक साधन में कुछ भाग प्राकृतिक और कुछ मानवीय रहता है, जैसे एक बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के बाद वह आंशिक रूप से 'भूमि' व आंशिक रूप से पूंजी है।

2. विकास में प्राकृतिक साधनों का महत्व :

(A) प्रथम मत प्राकृतिक साधनों का कोई महत्व नहीं है ।

1. कुछ अर्थशास्त्रियों का कथन है कि प्राकृतिक साधनों के अधिक होने से विकास सुनिश्चित नहीं होता। अफ्रीका में प्राकृतिक साधन भरे पड़े हैं परन्तु वह बहुत पिछड़ा हुआ देश है। स्वीटजरलैंड व जापान प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से पिछड़े देश हैं परन्तु वे आज आय की दृष्टि से उन्नत देशों में हैं। इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि प्राकृतिक साधनों की मात्रा तो स्थिर है, इस कारण वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

Simon Kuznets साइमन कुजनेट्स के अनुसार :

"Any land base is sufficient to get growth started." अर्थात् विकास के लिए हर भूमि या कोई भी भूमि पर्याप्त है।

- 2 प्राकृतिक साधन निष्क्रिय होते हैं और इसी कारण उनका विकास प्रक्रिया पर प्रभाव भी निष्क्रिय होता है। उनमें गतिशीलता तब आती है जबकि देश में तकनीकी उन्नति व पूंजी वृद्धि के कारण उनका प्रयोग बढ जाता है।

Theodore Schultz थ्योडोर शुल्ज का कथन है कि :

"जैसे-जैसे कोई देश विकसित होता जाता है वैसे-वैसे प्राकृतिक साधनों का महत्व घट जाता है क्योंकि विकसित देश के राष्ट्रीय

See : (i) Kuznets : Towards a Theory of Economic Growth in National Policy in Economic Welfare at Home and Abroad. (Ed) R. Lekachman 1955 p 76

(ii) Ch. iv : Kindleberger : op cit.

(iii) Schultz Quoted from : Pepalasis . op cit p.19

(iv) W N. Parker : J. J. Spenser (Ed). Natural Resources and Economic Growth, Washington 1961

(v) Mather quoted from Meier & Baldwin op cit p 527

आय में कृषि का योगदान घट जाता है. प्राकृतिक साधनों का राष्ट्रीय आय में योगदान "कृषि अवस्था" में वह केवल 25% रहता है परन्तु "औद्योगिक अवस्था" में वह केवल 50% तक रह जाता है."

3 Mather माथेर का कथन है कि . विश्व के आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों की कमी कभी नहीं आयेगी. यहाँ प्रकृति के भंडार हमारी आशा से अधिक भरे पड़े हैं

कभी-कभी तो प्राकृतिक साधनों की अधिकता से अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी कमी से, कृत्रिम साधनों की खोज होती है और नवप्रवर्तन की मनोवृत्ति को बल मिलता है, जैसा कि जापान व इजराइल में हुआ है.

(A) दूसरा मत : विकास में प्राकृतिक साधन महत्वपूर्ण :

बहुत से अर्थशास्त्री, रिवाइडों के समय से ही, विकास में प्राकृतिक साधन को महत्वपूर्ण मानते हैं. इनका विचार है कि प्राकृतिक साधनों के होने से विकास होता है और कम होने या समाप्त होने से विकास कम होगा या रुक जायेगा. किसी भी देश का विकास प्राकृतिक साधनों की अधिकता या कमी पर निर्भर करता है

Osborn का विचार है कि हमारा विकास कभी न कभी प्राकृतिक साधनों की कमी से रुक जायेगा. उनका विचार है कि यह हमारे भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से डाल देगी. उनका कथन है कि "यह दूसरा खामोश विश्व युद्ध है."

(B) संतुलित मत :

वास्तव में प्राकृतिक साधनों की कमी से विकास का रुकना या बहुतायत से विकास का सुनिश्चित होना आवश्यक नहीं है. आज विश्व में 1 लाख से अधिक

(i) P. Osborn, our Plunderd Planet, Grosset and Dunlop, New York, 1948 (x)

(ii) See also : Substitute Materials In War & Peace, Cecil H. Desch

(iii) Ch. iv of Bauer & Baldwin, "Natural Resources" The Economics of Under-Developed Countries." Nisbet & Combri-
dge, 1965, (Ed).

(iv) Dr. Miss I. Z. Hussain, Economic Factors In Economic Development P. 100-101.

कच्चे माल प्रयोग में लाये जाते हैं। कोई भी देश इन सबको स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता। वास्तव में जैसा, कि Bauer and Yamey ने कहा है, "प्राकृतिक साधनों से अधिक उत्पाति के अन्य सहायक साधन विकास में महत्वपूर्ण हैं" वे कहते हैं कि U. S. A. में रेड इण्डियन के युगों में भी तो प्राकृतिक साधन वही थे, परन्तु प्रवासी नागरिकों ने ही U S A का विकास किया।

डा० (कुमारी) इशरत जेड हुसैन के अनुसार प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त मात्रा में होना विकास में सहायक अवश्य होता है परन्तु यह स्वयं किसी देश को विकास पथ पर अग्रसर नहीं कर देता है। इनके होने से देश में खानदान, शक्ति व धातुओं की आवश्यकता पूरी हो जाती है, विकास की उन्नत अवस्थाओं में पूँजी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। समस्त विकास क्रिया में तकनीक शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है।

3. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग को निर्धारित करने वाले तत्व :

किसी भी देश में प्राकृतिक साधनों का कम या अधिक प्रयोग कई बातों पर निर्भर करता है, जिनमें यह प्रमुख है

1 पूँजी :

पूँजी ही वास्तव में प्राकृतिक साधनों का आकार या उपयोग परिवर्तन करती है तथा पूँजी ही उनको साने ले जाने में सहायता करती है उन्नत तकनीक से ही प्राकृतिक साधनों का प्रयोग बढ़ता है और उन्नत तकनीक का अपनाया जाना स्वयं अधिक पूँजी पर निर्भर करता है।

2. साहस ■ संगठन :

प्राकृतिक साधनों का महत्व तो साहसी ही आर्क्ते है इसके लिए देश में पर्याप्त मात्रा में आर्थिक स्वतंत्रता होना चाहिए परन्तु अगर देश में एकाधिकारी व्यवस्था है तो न तो प्राकृतिक साधनों का और न ही मानव साधन का पूर्ण प्रयोग होगा क्योंकि एकाधिकारी कृत्रिम न्यूनता बनाए रखकर ही लाभ कमाने का लक्ष्य रखता है। प्रतियोगितात्मक साहसी व्यवस्था, जो विदेशी तकनीक व पूँजी को भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर सकते हैं

3. तकनीक :

तकनीक ही प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। योरोप के मुकाबले में समुद्र राष्ट्र अमेरिका के अधिक विकसित होने का कारण उसकी

उन्नत तकनीक ही है उन्नत तकनीक का अर्थ पूँजी-गहन तकनीक ही नहीं होता, जापान ने तो थम गहन तकनीक से ही बहुत कुछ कर दिखाया है

4 बाजार :

प्राकृतिक साधनों का प्रयोग बाजार के विस्तृत होने और उसमें स्थायी व अधिक माँग पर भी निर्भर करता है. बाजार के मूल्य परिवर्तन साधनों के प्रयोग की मात्रा व प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला देते हैं बाजार की स्थितियों में परिवर्तन होने से ही कृत्रिम साधनों की खोज होती है.

5 अम शक्ति :

देश में अगर पर्याप्त मात्रा में तथा प्रशिक्षित श्रमिक हैं जो खानों, जंगलों, कृषि मछली पालन व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक साधनों का प्रयोग बढ़ेगा अम शक्ति ही उत्पादकता निर्धारित करती है. अगर देश में उत्पादकता अधिक होगी तो अधिक से अधिक वस्तुएँ कम से कम लागत में बनती हैं और इससे देश के अन्दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है.

6 सामाजिक तन्त्र :

देश की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति भी प्राकृतिक साधनों के प्रयोग को निर्धारित करती है जिस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती है वहाँ प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता शिक्षित व्यक्तियों के सम्य समाज में विज्ञान व तकनीक की उन्नति से साधनों के प्रयोग का क्षेत्र बढ जाता है. वभी कभी जाति प्रथा, धर्म या रूढ़िवाद के कारण प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पाता.

7 राज्य :

बहुधा राज्य ही प्राकृतिक साधनों के उचित प्रयोग के लिए मार्ग दर्शन करता है और उसके लिए उचित कानूनी व आर्थिक व्यवस्था करता है. उसकी प्रशासन, राजकोषीय व अन्य नीतियाँ ही देश में साहसियों के कार्य प्रणाली व क्षेत्र निर्धारण करती हैं.

4. प्राकृतिक साधनों की प्रयोग नीति :

1 सर्वेक्षण करें तथा Inventories (लिष्ट) बनाएँ :

बहुत से कम विकसित देश तो यह भी नहीं जानते कि उनके प्राकृतिक साधन क्या हैं और कितने हैं इसके लिए सर्वप्रथम, विकसित देशों या अन्तर्राष्ट्रीय

संस्थाओं की सहायता से व्यापक भूमि सर्वेक्षण करना पड़ेगा, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से ही प्राकृतिक साधनों के प्रयोग का लाभ-लागत पट्ट पता लग सकेगा इसके लिये पूर्ण वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करना पड़ेगा.

2. पूँजी का संचय पर्याप्त मात्रा में किया जाए .

बहुत से कम विकसित देशों में पूँजी की मात्रा की कमी के कारण ही सर्वेक्षण नहीं हो पाते और इसी कारण उन्नत तकनीक नहीं अपनायी जा पाती. इसके लिए पूँजी निर्माण परम आवश्यक होगा. &

3. देश की अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप तकनीक अपनायी जाए :

हर कम-विकसित देश को "उचित" तकनीक अपनाना चाहिए यह देश में धन की मात्रा, उनकी कुशलता, संगठन कर्ताओं की कुशलता, तथा पूँजी की मात्रा पर निर्भर रहेगी कम-विकसित देशों को उन्नत देशों की जटिल तकनीक नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा कम-विकसित देशों में उनको चराने वाले और ठीक करने वाले की कमी पड़ जाएगी.

4. स्थानीय साधनों का प्रयोग हो :

कम-विकसित देशों को सर्वप्रथम अपने स्थानीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए. उसके पश्चात् ही उन्हें आयातीत कच्चे माल के उद्योग शुरू करना चाहिए

5. साधनों का वर्तमान प्रयोग और भविष्य में प्रयोग समुचित रखा जाए :

देश में प्राकृतिक साधनों के प्रयोग की दर देश के लिए अनुकूलतम (optimum) होना चाहिए. किसी भी मंहगे साधन को प्रयोग में लाने से पूर्व सस्ते साधन का पता लगाना चाहिए. वर्तमान में राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए साधनों को समाप्त नहीं कर देना चाहिए. दोनों कालों के लिए समुचित प्रयोग योजना होना चाहिए

6. साधनों का बहुउद्देश्यीय प्रयोग होना चाहिए .

कम-विकसित देशों में पूँजी साधन कम होते हैं इसलिए प्राकृतिक साधनों का प्रयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जैसे बांध बनाने का कार्य ऐसा है कि इससे पानी का प्रयोग सिंचाई, बिजली उत्पन्न करना, मछली पालना, परिवहन बाढ़ नियंत्रण व अन्य कार्यों के लिए होता है. इसके फिर अत्यन्त और प्रभाव होने हैं.

इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि साधनों के waste products (जैसे शक्कर के रस निकले गन्ने) का भी समुचित प्रयोग हो सहायक व पूरक उद्योगों की साथ-साथ निर्मित किया जाना चाहिए

7. श्रम बाजार उन्नत करें :

कम-विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों की प्रयोग करने के लिए, देश में गतिशील, प्रशिक्षित, ट्रेनिंग प्राप्त किये हुए और कुशल श्रमिकों का होना आवश्यक है ऐसा होने पर ही देश में उन्नत तकनीक को अपनाया जा सकता है. इसके लिए देश में सर्वप्रथम "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" पास करना चाहिए ताकि देश में एक सीमा से कम मजदूरी न दी जा सके इससे श्रमिकों की प्रच्छा कार्य करने की इच्छा व शक्ति बढ़ेगी. देश में Incentive wages system, अर्थात् अधिक कार्य अधिक मजदूरी पद्धति, अपनाया जाना चाहिए कम-विकसित देशों में श्रमिकों को उचित हक मिलना चाहिए वहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि औद्योगिक स्पर्ष एवं हड़तालों और तालाबन्दियों को नहीं होने देना चाहिए

8. बाजार स्थिति के पर्याप्त व व्यापक सर्वेक्षण हों

साधनों के प्रयोग के लिए सहासी पूँजी लगाने से पहले यह जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग कितनी हो सकती है, वह क्या मूल्य रख सकते हैं वस्तु की किस्म क्या होना चाहिए उनको बाजार में कितनी, किस से व कैसी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा. इसी प्रकार से वे यह जानना चाहेंगे कि उत्पादन के अगो को प्राप्त करने के लिए (मजदूर, पूँजी व संगठन कर्ताओं को कितने मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं) उन्हें किस प्रकार की बाजार स्थिति का सामना करना पड़ेगा

इन समस्त चीजों के लिए व्यापक व पर्याप्त सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ेगी.

9. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में बर्बादी कम से कम होना चाहिए तथा साधनों के Conservation (या परिरक्षण) की भी ध्यान में रखना चाहिए.

अगर प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में बर्बादी कम से कम रखी जाती है तो इससे प्रति वस्तु लागत कम रहेगी. इससे मूल्य कम व काम अधिक हाँगे, निर्वात प्रोत्साहित होंगे तथा देश में और पूँजी निर्माण हो सकेगा पानी, भूमि व वन के साधनों के प्रयोग में मविष्य के प्रयोग के लिए भी इन साधनों को बनाए रखना चाहिए.

खनिज सम्पत्ति को हम re-new नहीं कर सकते या समाप्त होने के बाद पुन नहीं ला सकते, इस कारण यह आवश्यक होगा कि देश में इस सम्पत्ति का

विवेकपूर्ण प्रयोग हो और नये प्रतिस्थापन साधनों का पता लगाया जाए. इन साधनों के re-use पुनः प्रयोग सम्बन्धी अन्वेषण होना चाहिए

खनिज सम्पत्ति को हम Re-new नहीं कर सकते या समाप्त होने के बाद पुनः नहीं ला सकते. इस कारण यह आवश्यक होगा कि देश में इस सम्पत्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग हो और नये प्रतिस्थापन साधनों का पता लगाया जाए. इस साधनों के re-use पुनः प्रयोग संबंधी अन्वेषण होना चाहिए.

10. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में अवरोधों व रुकावट डालने वालों को दूर किया जाए :

प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के लिए कभी कभी कोई Key resource या मुख्य साधन होते हैं, जैसे हजराहत में कृषि करने के लिए 30% व्यय तो पानी पर ही होता है या पहाड़ी क्षेत्र में साधनों के प्रयोग के लिए सड़के व यातायात मुख्य होते हैं. राज्य को चाहिए कि वह इन साधनों के जुटाने में सहायक हो.

किसी भी देश में साधनों का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित चार में से एक अधिक कारणों से एक सकता है :

(i) देश में सहयोगी साधनों की कमी हो.

(ii) देश में मूल्य स्तर ऐसा हो, जिससे लाभ प्राप्त न हो रहे हो.

(iii) देश के प्राकृतिक साधनों को अविष्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित रख दिया हो, और

(iv) देश में एकाधिकारी इनका प्रयोग न होने दे रहे हो.

प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में Vested Interest, भी बाधक हो जाती है, जैसे कृषि को उत्तम रीति से करने के लिए जो भू-सुधार हो उनमें जमींदार लोग बाधा डाल सकते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आधार पर साख का इन्तजाम जो सहकारी संस्थाएँ करे उनमें पेशेवर साहूकार बाधा डाल सकते हैं. इस प्रकार के रुकावट डालने वालों को हटा देना चाहिए.

11 प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के लाभ अधिकाधिक व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए :

प्राकृतिक साधन समूचे देश की सम्पत्ति होने हैं इस कारण इनके प्रयोग में अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक लाभ हो. विकसित देशों में साधनों के प्रयोग को चक्रविरोधी नीति के रूप में कार्य में लाया जा सकता है अर्थात् मंदी के बाल साधनों के प्रयोग के कार्य को सार्वजनिक कार्य द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है

विकासशील देश प्राकृतिक साधनों के प्रयोग पर तो ध्यान देते हैं परन्तु मानव साधनों के प्रयोग पर अधिक ध्यान नहीं देते. पूर्ण रोज़गार की व्यवस्था भी साधनों के पूर्ण प्रयोग का अंग होना चाहिए.

12. अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए

जब तक देश में बैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता तब तक देश में प्राकृतिक साधन सबधी जानकारी कम रहेगी, उसी प्रकार से उपयुक्त तकनीक भी नहीं अपनायी जा सकेगी और न ही देश में साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का पता लग सकेगा या उचित प्रतिस्थापन साधनों का पता लगाया जा सकेगा. इस कार्य के लिए राज्य को निजी क्षेत्र वालों को अनुसंधान करने में कर संवधी छूट देना चाहिए और विदेशी विनिमय सबधी सहायता का प्रबंध करना चाहिए. राज्य को स्वयं भी इस कार्य में धन लगाना चाहिए. राज्य को चाहिए कि वह यह देखे कि अनुसंधान कार्य में Duplication अर्थात् बेकार दुहरा खर्च या दुहरे प्रयत्न तो नहीं हो रहे हैं.

13. प्राकृतिक साधनों का प्रयोग तथा राज्य :

इस सबध में हम राज्य के उत्तरदायित्व को सीमित नहीं मान सकते. देश में स्वार्थी कुशल, भ्रष्टाचार स परे सरकार ही देश में विकास करा सकते हैं. उसकी उचित मौद्रिक, राजकोपीय व मूल्य नीति पर ही साधनों का विकास निर्भर रहता है.

अध्याय : 2

विकास व कृषि

Development and Agriculture

1. कम-विकसित देशों में कृषि की स्थिति व विशेषताएँ :

1. कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है.
2. कृषि प्राकृतिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर रहती है.
3. देश के अधिकांश व्यक्तियों का रोज़गार साधन है.
4. विदेशी व्यापार का मुख्य स्रोत है.
5. अधिकांश ग्रामीण अर्थ व्यवस्था अमौद्रिक भी होती है.
6. कृषि में रत व्यक्तियों की, कृषि में प्रयोग में आनेवाली भूमि की प्रति-एकड़ उत्पादकता भौतिक रूप तथा मौद्रिक रूप दोनों में कम होती है.
7. कृषि से बहुत कम "विपणन योग्य आधिक्य" मिलता है.

2. कम-विकसित देशों में कृषि के पिछड़ेपन के कारण -

1. अप्रतिशोत भू-मालिकियत प्रणाली व भू-सुधारों की प्रभावहीनता.
2. भूमिका अपवर्णन तथा बिखरापन तथा अनाधिक जोतें
3. सिंचाई सुविधाओं की कमी.
4. कृषि के लिये सस्ती व सुगम साख की कमी तथा कृषकों की ऋण प्रवृत्ति.
5. भू-क्षरण तथा अन्य हानिकारक प्रयोग.
6. कृषि में बिजली तकनीक.
7. खाद की कमी.
8. विनष्टन की समुचित व्यवस्था की कमी.
9. प्रकुशल श्रमिक, साहसियों की कमी
10. राज्य की उदासीनता.

3. अ-कृषि का सतुलित विकास में स्थान -

- (1) पहला मत : कृषि का विकास में महत्व अधिक नहीं है.
दूसरा मत . कृषि के बिना सतुलित विकास असंभव है निष्कर्ष.

(ii) विकास के साथ-साथ कृषि का महत्व घटता जाता है.

4. कम-विकसित देशों में कृषि के आत्म-स्फूर्ति की अवस्था को पहुँचने व स्थायी विकास के लिये आवश्यक तत्व : विकास की अवस्थाएँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय

1. भूमि सुधार तथा कृषि में उन्नति.
2. भूमि की तकनीकी, भू-क्षरण को रोकना तथा पड़ती भूमि को पाटना
3. कृषि विकास के लिये पूँजी निर्माण व साख व्यवस्था.
4. उत्तम सिंचाई, बीज, खाद और यन्त्रायात का प्रबन्ध
5. कृषि का विपणन तथा बाजार व्यवस्था उन्नत करना
6. कृषि विकास व कृषि अनुसंधान
7. शिवा का विकास व कृषि.
8. कृषि विकास तथा मूल्य नीति
9. कृषि विकास के लिये उचित नेतृत्व व सेवाओं का प्रावधान.

अध्याय : 2

विकास व कृषि

Development and Agriculture

I. कम-विकसित देशों में कृषि की स्थिति व विशेषताएँ Characteristics of Agriculture in Under-Deve- loped Countries

कम-विकसित देशों में कृषि की क्या स्थिति है इस सम्बन्ध में कम विकसित देशों के निवासी भलीभाँति परिचित हैं संक्षेप में इनको निम्नलिखित ढंग से वर्णित किया गया है.

1. कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है
2. कृषि प्राकृतिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर रहती है तथा 'Prince to pauper cycles' से पीड़ित रहती है
3. देश के अधिकांश व्यक्तियों का रोजगार साधन है
4. विदेशी व्यापार का मुख्य स्रोत है.
5. अधिकांश ग्रामीण अर्थव्यवस्था अमौद्रिक भी होती है Non-monetized transactions persist in agricultural sector.
6. कृषि में रत व्यक्तियों की, कृषि प्रयोग में आने वाली भूमि की प्रति-एकड़ उत्पादकता भौतिक रूप तथा मौद्रिक रूप दोनों में कम होती है.
7. कृषि से बहुत कम 'विपणन योग्य आधिक्य' मिलता है

बहुत हद तक कम विकसित देशों की गरीबी की समस्या, कृषकों की गरीबी की समस्या होती है. विश्व की समस्त जन-संख्या का 60% या 1500 मिलियन व्यक्ति कृषि पर निर्भर रहती है. इनमें से 1200 मिलियन व्यक्ति कृषि एशिया, अफ्रीका तथा मध्य व दक्षिणी अमेरिका में हैं और शेष योरोप व उत्तरी अमेरिका में हैं. जहाँ योरोप में हर तीन में से एक, उत्तरी अमेरिका में हर पाँच में से एक व्यक्ति कृषि में लगा है, वहाँ एशिया व अफ्रीका में हर चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति कृषि में लगे रहते हैं

कम विकसित देशों में कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन होती है लगभग 50% राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है.

Benjamin Higgins के शब्दों में

“With a large proportion of the population engaged in agriculture on very small holding, the rural sector acts as an anchor sunk deep in the sands of time, so that the ship of state can never move far from its present becalmed position with low levels of productivity and income”¹

कम विकसित देशों में कृषि सदियों से पिछड़ी व स्थगित अवस्था में पड़ी हुई है.² संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1800-1940 के बीच 100 कुशल बंदू पैदा करने के लिए Man-hours श्रम घटा का मात्रा 373 से घटकर 47 रह गई. वहाँ 1820 में 2 व्यक्ति मिल कर तीसरे व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध करा देते थे 1946 में एक ही व्यक्ति 15 अन्य व्यक्तियों के लिए उत्पादन कर सकता था भारत में 4 व्यक्ति मिल कर आज भी 5वें के लिए उत्पादन नहीं कर पाते.

कम विकसित देशों में, Umbreit, Kunt तथा Kinter के शब्दों में कृषि ‘Prince to pauper cycles’ तथा ‘Pauper to prince cycles’ से पीड़ित है. (अर्थात् आज के धनी कल गरीब, या आज के गरीब कल धनी बन जाते हैं)³

कम विकसित देशों की कृषि हर प्रकार की बेरोजगारी अवस्था का शिकार होती है. यहाँ पर भूमि की मात्रा, भूमि से कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन का उपभोग तथा कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की पूर्ति सब ही बेरोजगारी रहती है

जहाँ तक उत्पादकता का प्रश्न है, यह भी सर्वोन्निहित है कि कम विकसित देशों में प्रतिव्यक्ति व प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है कम विकसित देशों के मुकाबले 1/4 से लेकर केवल 1/10 भाग उत्पादन कर पाते हैं. भारत में कृषि उत्पादकता लका, जावा, मित्र की ही आधी तथा ब्राजील की 1/7 भाग है.

1. B. Higgins - op. cit p 454-5

2 D B Singh - op cit : p 471

3 Umbreit, Hunt, Kinter Ch 25 Econ by G L Bach.

U N O के अनुमानों के अनुसार जहाँ उत्तरी अमेरिका में कृषि में रत प्रति व्यक्ति का वार्षिक उत्पादन $3\frac{1}{2}$ टन है वहाँ कम विकसित देशों में, जैसे एशिया में यह केवल $1\frac{1}{4}$ टन है और अफ्रीका में $1\frac{1}{8}$ टन है।

कम विकसित देशों में कृषि ही मुख्य धनवा, मुख्य आय का साधन तथा मुख्य निर्यात का साधन है और जब वह ही स्थैतिक व पिछड़ा उद्योग है तो समस्त अर्थव्यवस्था ही पिछड़ी रहती है कम विकसित देशों में कृषि में रत व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका कारण यह नहीं है कि यह उद्योग अधिक आय या अधिक सुरक्षा या अधिक उच्च-सामाजिक स्तर प्रदान करता है वरन् यह इसलिए है कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ही नहीं बढ़ने हैं, और कृषि में रत व्यक्तियों की गतिशीलता कम होती है।

कम विकसित देशों के लगभग 50% निर्यात तो कृषि वस्तुओं के होते हैं और अन्य 25% कृषि वस्तुओं पर ही आधारित होते हैं इसी प्रकार राज्य की आय भी कृषि क्षेत्र से आती है मालगुजारी प्रणाली बेरोजगार प्रणाली होती है और इस कारण राज्य की आय भी नहीं बढ़ती है कृषि में प्रकृति के कोप या महर्घानों के अनुसार राज्य की आय भी घट बढ़ जाती है जो बड़ी ही अनिश्चित परिस्थिति होती है।

कृषि ही देश के औद्योगिक विकास का आधार होती है और अन्य क्षेत्र जैसे तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) कृषि विकास पर बढ़ता है।

परन्तु आज भी कम विकसित देशों में कृषि से दिपलून योग्य आविषय कम निकलता है और आज भी कृषि क्षेत्र में अमौद्रिक सौदे होते हैं और यह क्षेत्र अन्ध-विश्वास, हडिवादता, भाग्यवादता, अशिष्टता, अज्ञान व सुरती का क्षेत्र बना है।

II. कम विकसित देशों में कृषि के पिछड़ेपन के कारण .

कम विकसित देशों में कृषि पिछड़ी है और पिछड़ेपन के कारण भी सर्वविदित है। फिर भी संक्षेप में उन्हें प्रस्तुत करना, समस्या के समझने व निराकरण के लिए आवश्यक है इन कारणों में मुख्य यह हैं

1. अप्रगतिशील भू मालिकीयत प्रणाली व भू-सुधारों की प्रभावहीनता
2. भूमि का अपखंडन तथा विखरापन, तथा अनाधिक जोतें।
3. सिंचाई सुविधाओं की कमी।

4. कृषि के लिए सस्ती व सुगम सास की कमी तथा कृषकों को ऋणग्रस्तता
5. भू-क्षरण तथा अन्य हानिकारक प्रयोग.
- 6 कृषि में पिछड़ी तकनीक
- 7 खाद की कमी.
- 8 विपणन की समुचित व्यवस्था की कमी.
9. अकुशल श्रमिक, माहसियों की कमी.
10. राज्य की उदासीनता

1 अप्रगतिशील भू-माल्कियत प्रणाली व भू-सुधारों की प्रभावहीनता :

कम विकसित देशों में भूमि की माल्कियत कुछ व्यक्तियों के हाथ रहती है जैसे इन देशों में प्रायः व सम्पत्ति कुछ हाथों में केन्द्रित रहती है जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की माल्कियत कुछ के ही हाथों में केन्द्रित रहती है. मिस्र (Egypt) में 1952 में देश के 72% कृषकों के पास 1 या इससे भी कम एकड़ के रेत में और उनके पास केवल 13% भूमि ही थी, जबकि देश के केवल 1/2 (आधा) प्रतिशत किसान (या सही मायनों में जमींदार) 50 एकड़ या इससे अधिक के मालिक थे व उनके पास समस्त भूमि का 34% भाग था.

इराक में हाल के वर्षों तक वहाँ के शैल बड़ी बड़ी भूमि के टुकड़ों के मालिक हैं. सिंचाई वाले क्षेत्र तो लगभग सब उनके पास हैं वहाँ पर *Fellahin* (फैलाहिन या *Serf*) 'गुलाम' कारतकार अपनी उपज का 1/2 भाग इन शैलों को दे देते हैं. अगर शैल बीज दना तो 2/3 और पानी देना था तो 1/2 भाग तक देना पड़ता था. तब 1952 व 1958 में भू-सुधार किए गए.

स्वयं भारत में राष्ट्रीय सम्पल सर्वे के अनुसार जमींदारी उन्मूलन से पहले देश में 25 एकड़ से अधिक माल्कियत वाले 4% परिवारों के पास कुल स्वाम्य-भूमि का 34% था और 50 एकड़ से अधिक स्वाम्यधारी 1% परिवारों के पास कुल स्वाम्य-भूमि (कुल माल्कियत भूमि) का 16% था.

इसके विपरीत 5 एकड़ से कम के स्वाम्यधारी 53% परिवारों के पास लगभग 17% भूमि थी. 5 और 25 एकड़ के भीतर स्वाम्यधारी 22% परिवारों के पास कुल स्वाम्य-भूमि का 49% था 22% परिवारों के पास कोई भूमि न थी.

इन देशों में हाल के वर्षों में बहुत से भू-सुधार हुए हैं परन्तु आज भी स्थिति ठीक नहीं है. भू-सुधार न होने से कृषि पर बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं जैसे

- (1) कृषि में प्रति एकड़ व प्रति व्यक्ति उपज कम होती है

- (ii) कृषि में उन्नत साधनों, व सिंचाई अच्छे बीज आदि का प्रयोग नहीं हो पाता.
- (iii) कृषकों को अधिक उपज की प्रेरणा नहीं रहती.
- (iv) कृषकों का जीवन स्तर गिरता है
- (v) कृषकों द्वारा बचतें व पंजी-निर्माण की कमी रहती है U.N. की एक रिपोर्ट के अनुसार :

“भू-सुधार न होने से भूमि का उचित व अच्छा प्रयोग नहीं हो पाता और जिन भूमिपतियों के पास कम भूमि होती है वे भूमि को अधिकाधिक जातकर उसके चरण को उत्पन्न करते हैं.”

भारत के सम्बन्ध में Prof. M.L. Dantwala ने जो बातें कही हैं वे अन्य देशों पर भी लागू होती हैं उन्होंने कहा है .

“अगर कोई मुझसे यह पूछे कि भारत के भू-सुधार नियमों की विशेष बात क्या है तो मैं यह कहूँगा कि वह उनको कार्यान्वित न करना है.”

नियम बनाना आसान है पर उन्हें कार्यान्वित करना कठिन है. इन देशों में नियम बनाने में ढील डाल रहती है एवं उन्हें कार्यान्वित करने में भी ढील रहती है नियम बनाने व कार्यान्वित करने से पहले जो जोर-शोर के एलान होते हैं उनसे जमींदार व भूमिपतियों को पता चल जाता है और वे उसके अनुसार कानूनी Loophole या छिद्र निकाल लेते हैं और बच निकलते हैं. राज्य का प्रशासन भी इन सुधारों को कार्यान्वित करने में सर्वथा अयोग्य व अनिच्छुक पाया गया है.

भारत में “बुद्धकाशत” कहकर बहुत से जमींदार भूमि दवायें रहे और भू-वितरण नहीं होने दिया. भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में नियम अलग-अलग रहे परन्तु उन सब में एक ही समानता रही की उनके कार्यान्वित करने में सुस्ती से काम लिया गया. जमींदारों ने किसानों से “ऐच्छिक” रूप से बहुत सी भूमि छुड़वा ली.

See also : (i) “Land Reform” U.N. Defects in Agrarian Structure as obstacles to Economic Development p. 65.

(ii) “Land Reforms in India” Tokyo Conference Papers on Economic Growth M L. Dantwala.

(iii) Ford Foundation Report on Land Reforms in India.

राज्यो ने भू-सुधार की घोषणा की तो कार्यान्वित होने से पहले ही किसानों को वेदखल कर दिया गया।

भूमि की जोत की मात्रा निर्धारण से बचने के लिए परिवार के सदस्यों में ही भूमि के वितरण की कामजी कार्यवाही कर ली गई। आय का एक चौथाई भाग लगान में चले जाने से वचत बहुत कम रहती है।

2. भूमि का अपखंडन तथा विखरापन तथा अनाधिक जोतें :

कम विकसित देशों में कृषि भूमि की जोतें बहुत छोटी हैं। जहाँ अमेरिका में 75 एकड़ का खेत छोटा माना जाता है वहीं भारत जैसे कम विकसित देश में 5 एकड़ का खेत ही बड़ा माना जाता है। जनसंख्या की अधिकता, कृषि योग्य भूमि की कमी (Leibenstein के अनुसार विश्व का $\frac{1}{3}$ भाग जो रेगिस्तान तथा और $\frac{1}{3}$ भाग कृषि योग्य नहीं है) जनसंख्या की वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी तथा उत्तराधिकार के नियमों के कारण भूमि का अपखंडन होता ही चला जाता है। जापान, चीन, इन्डोनेशिया, भारत, कम्बोडिया, वियतनाम व लका में जन-संख्या का भार इतना अधिक है कि प्रति व्यक्ति $\frac{1}{2}$ एकड़ से भी कम भूमि हिस्से में आती है। भूमि के अपखंडन के साथ-साथ उनका विखरापन भी एक गम्भीर समस्या है। कृषकों की पूरी भूमि कई टुकड़ों में बँटी रहती है (कही कही तो 25 टुकड़ों तक में) जो पास-पास नहीं होते।

भूमि-उप-विभाजन एवं अपखंडन के दोष जाहिर हैं। कम-विकसित देश अनाधिक जोतों के देश बन गए हैं। इतने छोटे खेतों के कारण आधुनिक रूप से कृषि नहीं हो पाती। सिंचाई की सुविधाओं का प्रयोग नहीं हो पाता, उत्पादकता कम रहती है तथा आय कम रहती है। इस व्यवस्था से बहुत सी कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। कृषकों की गृहस्थता बढ़ती है और कृषि की पिछड़ी व्यवस्था बनी रहती है।

3. सिंचाई सुविधाओं की कमी :

कम-विकसित देशों की कृषि मौसमी बरसात पर ही अधिक निर्भर रहती है। पूँजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन तथा कृषकों की अनिच्छा से सिंचाई से कृषि का अनुपात अभी भी कम है। भारत में 20% से भी कम कृषि सिंचाई पर आधारित है। कम-विकसित देश अपने पानी का 5-10 प्रतिशत भाग ही काम में ले पाते हैं। W. S. Woytinsky तथा E. S. Woytinsky के अनुसार अगर सिंचाई

सुविधाएँ उपलब्ध कर दी जाएँ तो वर्नी में 1.9 करोड़ एकड़ भूमि प्रौर कृषि योग्य बनाई जा सकती है. इराक में यह भूमि 60 लाख एकड़ से बढ़ कर 200 लाख एकड़ हो जाएगी, सीरिया में 40 लाख एकड़ से 100 लाख एकड़ हो जाएगी तथा टर्की में यह मात्रा 250 लाख एकड़ से 400 लाख एकड़ हो जाएगी

कम-विकसित देशों में कृषक लोग समय पर पानी देना, मही मात्रा में पानी देने के बारे में पूर्णरूप से जानकारी नहीं रखते. सिंचाई की सुविधाओं की कमी के कारण एक से अधिक उपज नहीं ले पाते, प्रति एकड़ व व्यक्ति उपज कम रहती है

कृषकों में बेरोजगारी तथा छद्मबेरोजगारी बढ़ती है उत्पादन लागत अधिक तथा कम व खराब उपज व बच्चा भात पैदा होता है. कम-विकसित देशों में बाढ़ों की अधिकता या सूखे का कृषि शिकार होती रहती है या पानी से निकलने वाली मग से हानि उठा जाते हैं.

4. कृषि कार्यों के लिए सस्ती व सुगम साध, विशेष रूप से दीर्घकालीन विनियोजन के लिए, की कमी तथा कृषकों की ऋणग्रस्तता.

जैसा कि सर्वविदित है, कम-विकसित देशों के अर्रिकारा कृषक अपनी पिछड़ी व छोटे पैमाने की खेती के कारण उनके पास "विपणन योग्य आधिकार" कम रहता है इस कारण उनकी आय, बचत व पूँजी कम रहती है और वे पिछड़े ढंग से खेती करते रहते हैं और वे कम आय व ऋणग्रस्तता के दुश्चक्र में फँसे रहते हैं उनकी अधिक जन्म, कम आयु दर तथा कुछ सामाजिक-धार्मिक रीति रिवाज भी उन्हें इस स्थिति में बनाए रखते हैं और जैसा कि आमतौर से कहा जाता है

"कृषक पालने से कत्र तक ऋण में रहते हैं "

इस कारण जब कभी भी कृषक को कृषि के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है तो उसे दूसरों से ही उधार लेना पड़ता है. कम-विकसित देशों में मुद्रा बाजार इतना विस्तृत नहीं होता कि वह ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी कर सके इसलिए पेशेवर व्यापारी यह उधार देने का कार्य करते हैं और कृषकों को चूसते रहते हैं. भारत के बारे में जो All India Rural Credit Survey Committee ने लिखा था वह समस्त कम-विकसित देशों के लिए अनुपयुक्त नहीं है. कमेटी ने लिखा था

"To day the agricultural credit that is supplied falls short of the right quality, is not of the right type, does not serve the right purpose,

and by the criterion of need often fails to go to the right people ”

कृषकों की Credit worthiness या उधार लेने की साख कम होती है जिससे वे ब्याज अधिक देते हैं साहूकार उन्हें अल्पकालिक ऋण ही देते हैं जिससे दीर्घकालीन विकास कार्य नहीं होता भारत में 70% किसान ऋणग्रस्त हैं और भारत में आज भी इन्हे राज्य व सगठित संस्थाओं से केवल 10% के लगभग ऋण मिलता है। कृषि में दीर्घकालीन विनियोजन की कमी के कारण कृषि पिछड़ी रहती है।

5. भू-क्षरण तथा भूमि के अन्य अनार्थिक प्रयोग :

कम-विकसित देशों ने अपनी मिट्टी की उर्वरता को बराबर कायम नहीं रखा। हजारों वर्षों से भूमि का जिस मात्रा में प्रयोग हो रहा है उस मात्रा में उनकी उर्वरता को बनाए रखने के प्रयत्न नहीं किए गए हैं युगो युगो से वर्षा और हवाओं ने भूमि का बटाव जारी रखा है। Wind erosion जिसमें आधी अच्छी मिट्टी को ले जाकर दूसरे स्थान पर पटक देती है और भूमि को नगा छोड़ जाती है, Gully erosion जो वर्षा के पानी की नालियों के रूप में हजारों एकड़ भूमि कृषि के अयोग्य हो गई है बहुत अधिक मात्रा में हुई है। इससे भी अधिक इन देशों में पशुओं की चराई, जंगलों की कटाई व वर्षा आदि के कारण उपजाऊ मिट्टी बहकर ऊपर हजारों एकड़ भूमि की उर्वरता नष्ट हो गई है और कम-विकसित देशों में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इन कटाव के कारण इन देशों में बाढ़ों का वेग बढ़ा है। भूमि की पानी सोखने की शक्ति कम होती है जिससे सिंचाई के लिए Sub soil या भूमि के अन्दर कुओं का पानी कम होता है कृषि योग्य भूमि कम होती है जबकि इन देशों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके कारण हो कम-विकसित देशों में कृषि Creeping death (धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर) की ओर जा रही है

6. कृषि में पिछड़ी तकनीक :

कम-विकसित देशों में कृषि के पिछड़े पन का सबसे प्रमुख कारण पिछड़ी तकनीक ही है। जापान ने उन्नत तकनीक को अपनाकर ही छोटे छोटे खेतों पर भी अधिक

पाकिस्तान में विश्व बैंक ने “सेम व थोर के मसले” (अर्थात् भूमि में पानी भर जाने व नमक आजाने की समस्या) को सबसे गम्भीर माना और उसके दूर करने में सहायता की

उपज उत्पन्न करके दिसला दिया है। श्री नेहरू ने इसी कारण एक बार कहा था "While the world is now in atomic age, we are living in cow-dung age." विकसित देशों में कृषि के शुरु से आखिर तक के कार्य मशीनों से होते हैं जो अधिक उपज देते हैं और बड़ा आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए भी इन्तजाम हो जाता है। कम-विकसित देशों में श्रम की कमी नहीं है इसलिए पूर्ण मशीनीकरण न तो संभव होगा और न वांछनीय होगा। परन्तु फिर भी ट्रैक्टर तथा अन्य आधुनिक उपकरण व तकनीक तो अपनाई जा सकती हैं। 1960 में जहाँ स्वीटजरलैंड में प्रति 1000 हेक्टर में 83 ट्रैक्टर थे, पश्चिमी जर्मनी में 81 थे, नीदरलैंड में 44, इंग्लैंड में 59 थे वहाँ टर्की में केवल 107 ही थे।

W. S. Woytinsky तथा E. S. Woytinsky के अनुसार 1955 में आज विश्व के समस्त ट्रैक्टरों में से 68 प्रतिशत तो उत्तरी अमेरिका में, 23% योरोप में, 3 प्रतिशत दक्षिणी अमेरिका में थे, सुदूर तथा पास पूर्व में 1 प्रतिशत थे और अफ्रीका में 2 प्रतिशत थे। 1951 में U S A. में प्रत्येक 119 एकड़ के पीछे एक ट्रैक्टर था, कनाडा में 247 एकड़ के पीछे एक ट्रैक्टर था, भारत में 21000 एकड़ के पीछे एक ट्रैक्टर था और इन्डोनेशिया में 2, 71, 810 एकड़ के पीछे एक ट्रैक्टर था।

कम-विकसित देशों में कृषि करने, खाद व पानी देने या भू-चरण रोकने आदि के सबंध में अधिकांश जनता आधुनिक तकनीक से अनभिज्ञ है।

7. खाद तथा अन्य आवश्यक सामग्री की कमी :

कम-विकसित देशों में यूर तो खाद दिया जाता है परन्तु आवश्यक मात्रा में आवश्यक खाद नहीं दिया जाता। कृषि के लिए नाइट्रोजन, पोटास तथा फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है।

F. A. O. की Year-book of Food and Agricultural Statistics, Rome, 1956, (p 213) के अनुसार, 1954-55 में

"1954-55 में विश्व में जितना नाइट्रोजन रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ उसका 45% तो योरोप में प्रयोग में लाया गया, 32 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका में प्रयोग में लाया गया, 4% दक्षिणी अमेरिका में प्रयोग में लाया गया, निकट पूर्व में 3% कार्य में लाया

गया, सुदूरपूर्व में 16% प्रयोग में आया और सम्पूर्ण अफ्रीका में केवल 1% नाइट्रोजन की खपत हुई थी."

इसी प्रकार से Eastern Economist, Annual No. 1962 के अनुसार

"नीदरलैंड में प्रति हेक्टर 461 किलोग्राम का प्रयोग हुआ, पश्चिमी जर्मनी में 278 कि० ग्रा० हुआ, स्वीट्जरलैंड में 207 कि० ग्रा० U K. में 180 कि० ग्रा०, ग्रीस में 31, स्पेन में 29 कि० ग्रा० भारत में 3 कि० ग्रा०, बं टर्कों में 1 किलोग्राम रहा"

जो कुछ भी रासायनिक खाद का प्रयोग होता है वह विशेष रूप से बड़े वागान व फार्मों में प्रयोग होता है कम विकसित देशों में इस संबंध में कुछ कठिनाईयाँ हैं :

(1) पहले तो इन देशों में कृत्रिम खादों का उत्पादन ही कम है भारत में ही यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि अतिरिक्त खाद उत्पादन करने के लिए विदेशी कम्पनी को इजाजत दी जाए या भारत के निजी क्षेत्र को दिया जाए, अथवा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र से उत्पादन बढ़े. इस प्रकार की अनिश्चितता की बहुत आलोचना की जाती है

(11) दूसरे मिचाली सुविधाओं की कमी के कारण इनका उतना अधिक प्रयोग संभव नहीं है और भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि को कौन सी खाद अच्छी रहेगी इसके भी अच्छे सर्वेक्षण नहीं हैं

कम-विकसित देशों में High yielding Varieties अधिक उपज देने वाले बीजों का भी आवश्यक मात्रा में प्रयोग नहीं हो पाता है

इसी तरह फसलों की रखवाली के लिए Barbed wire या कीटों से रक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी नहीं हो पाता है या बहुत कम होता है.

8. विपणन की समुचित व्यवस्था की कमी :

जैसा कि हम जानते हैं कि कम-विकसित देशों में एक तो "विपणन योग्य आधिक्य" ही कम होता है और दूसरे उसके विपणन में बहुत सी कमियाँ व बुराईयाँ रहती हैं. कम-विकसित देशों में फसलों का एकत्रीकरण, श्रेणी विभाजन, विभाजन (processing) संग्रहण, यातायात तथा अर्थ प्रवर्धन ठीक से नहीं होता. इन देशों में विपणन का कार्य अधिकतर "मध्यस्थ" लोग करते हैं और वे वास्तव में सूट्टे के रूप में व्यापार करते हैं कृषकों को उनका उचित मूल्य नहीं मिलता वरन् मध्यस्थ लोग ही (विशेष रूप से अर्थ-प्रदधक पेशेवर लोग) उनकी मेहनत का

बड़ा भाग ले लेते हैं। कृषकों की फसल को रोक कर बेचने की शक्ति कम होती है इससे वे ऐसा करते हैं।

कम विकसित देशों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन में भी ऐसे ही दोष पाए जाते हैं इन देशों की मंडियों में बेईमानी, धोखेबाजी तथा शोषण सब प्रचलित रहते हैं।

9. अकुशल श्रमिक, साहसियों की कमी कम-विकसित देशों के कृषक अशिक्षित होते हैं। जिसके कारण उनके रहने, कृषि करने, व सोचने विचारने के तरीके पिछड़े हुए हैं। इसी कारण इनके यहाँ जन्म-दर अधिक रहती है। ये कृषि के उन्नत तरीकों की आवश्यकता के प्रति अनभिज्ञ होते हैं या उदासीन रहते हैं। अशिक्षा के कारण वे भाग्यवादी होते हैं और फिर वे सतोषी जीवन-यापन करते हैं और भौतिक उन्नति के प्रति उदासीन हो जाते हैं अधिक भ्रातृ प्राप्त होने पर श्रम की मात्रा कम करके आराम करने लगते हैं या कृषि की मात्रा कम कर देते हैं इसी कारण वे अप्रत्यक्ष कर देते हैं और पूँजी निर्माण कर कृषि में अच्छा विनियोजन नहीं करते।

उनके अशिक्षित रहने के कारण ही वे महाजनो, व्यापारियों के जगल में फँस जाते हैं और भू सुधार नियमों के लाभ नहीं उठा पाते। जमींदार लोग उन्हें धोखा दे देते हैं। कृषकों की अशिक्षा व पिछड़ेपन के कारण ही उनकी व्यावसायिक व भौतिक गतिशीलता कम होती है और कृषि में छद्मवेपी बेरोजगारी बनी रहती है।

Boulding के शब्दों में

“कृषि में अन्य उद्योगों की भाँति साहसियों को कार्य करने के अवसर नहीं हैं”

10. अन्य कारण : राज्य की उपेक्षा : साम्राज्यवादियों द्वारा शोषण :

कम-विकसित देशों का विकसित देशों से खूब शोषण किया। उन देशों से कच्चा माल कम मूल्य पर लेते रहे और कृषि को उन्नत करने का प्रयत्न नहीं किया गया। अधिकांश कम-विकसित देश पिछले 25 वर्षों में ही स्वतन्त्रता पाए हैं और साम्राज्यवादी देशों की सरकारें कृषि की उन्नति के प्रति उदासीन ही रही। इन देशों की सरकारें सिंचाई सुविधाएँ बँटाने, किसानों को भूमि-सुधार से लाभान्वित करने, उन्हें अच्छी तकनीक सिखाने, उन्हें आवश्यक उपकरण व Inputs या लागतें प्रदान करने, उन्हें आर्थिक सहायता देने व उनके लिए विपणन सुविधाएँ देने के प्रति उदासीन रही हैं। अनुसंधान के प्रति भी ध्यान नहीं दिया।

कृषि को की प्रकृति से लड़ने या प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने का कोई कार्य नहीं किया गया मूल्यों के उच्चावचन से भी उन्हें सुरक्षित नहीं रखा गया

III. A The Place of Agriculture in Balanced Growth कृषि का सतुलित विकास में स्थान :

पहला मत : कृषि का विकास में महत्व अधिक नहीं है.

बहुत से अर्थशास्त्रियों का मत है कि कृषि के विकास के साथ-साथ महत्व घट जाता है तथा कृषि का विकास करने में महत्व अधिक नहीं होता. उनमें से एक मत इस प्रकार है.

K. K. Kurihara : के० के० कुरिहारा :

कुरिहारा का मत है कि कृषि में उत्पादकता इतनी कम होती है कि कम-विकसित देशों की अल्प-पूंजी को इतनी कम उत्पादकता के क्षेत्र में लगाना घातक होगा. इसके विपरीत उद्योगों में उत्पादकता अधिक होती है और इसलिए इसी क्षेत्र में पूंजी लगाना चाहिए.

इसके प्रतिरिक्त कृषि क्षेत्र में व्यक्तियों की "सीमान्त उपभोग क्षमता" अधिक होती है अर्थात् उनकी वचन क्षमता कम होती है. इस कारण कृषि की समस्त उन्नति अधिक उपभोग में निकल जाती है और इस कारण विनियोजन से पूंजी निर्माण नहीं होती.

तीसरा कारण यह है कि उन्नति के साथ कृषि क्षेत्र की "व्यापार की शर्तें" (Terms of trade) औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार की शर्तों के मुकाबले में गिरती जाती है इस कारण यह उपयुक्त होगा कि औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत किया जाये और कृषि क्षेत्र को परिणामस्वरूप उन्नति होने दिया जाए

इसके प्रतिरिक्त कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का अपना अधिक कठिन होता है. कृषि क्षेत्र बृहद् क्षेत्र होता है जिसमें एक साथ उन्नति कठिन हो जाती है. इस क्षेत्र में सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाएँ भी आती हैं यह क्षेत्र तो विकास के प्रति उदासीन होता है, इस कारण इस क्षेत्र का विकास इतना आसान नहीं है.

दूसरा मत : कृषि विकास के बिना सतुलित विकास असंभव है :

अधिकांश अर्थशास्त्री, स्वाभाविक रूप से इस मत के हैं कि अगर कम-विकसित

K. K. Kurihara : Theoretical objections to Agriculture Based on Economic Development. Indian Journal of Economics, Oct. 1958. p 163-9

देशों में विकास करना हो तो सर्वप्रथम कृषि को विकसित होना चाहिए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मत दिये जाते हैं

1. Giuseppe Ugo Papi . जिसे व यूगो पापी :

श्री पापी का मत है कि इससे पहले कि किसी अन्य क्षेत्र में विकास शुरू किया जाए, सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र को सुधारना होगा। इसी की उन्नति से देशवासियों को अधिक व अच्छा भोजन मिल सकेगा, उद्योगों को अधिक अच्छा व सस्ता कच्चा माल मिल सकेगा तथा देश में अच्छा रहन सहन का स्तर होगा। देश में कृषि क्षेत्र के मूल्य जब तक सस्ते न हों तब तक देश में मूल्य वृद्धि को रोकना नहीं जा सकेगा। फिर देश में मजदूरी बढ़ेगी और मुद्रा स्फीति फैलेगी। इसलिए विकास के लिए यह आवश्यक है कि खाद्यान्न, कच्चे माल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रति व्यक्ति व प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जाए।

कृषि उत्पादन में उन्नति से कपड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग, तेल उद्योग तथा बहुत से अन्य उद्योग तो प्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित होते हैं। अन्य उद्योग भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। जब वे उद्योग जो कृषि उन्नति से उन्नत होते हैं बढ़ते हैं तो उनसे देश के मरान बनाने के उद्योगों तथा अन्य सहायक व पूरक उद्योगों को बड़ावा मिलता है।

कृषि के उन्नत होने में कृषि क्षेत्र से जो व्यक्ति हटते हैं वे औद्योगिक क्षेत्र को मूल्य श्रम के रूप में उपलब्ध होते हैं।

कृषि की उन्नति से ही औद्योगिक क्षेत्र और फिर तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) जैसे यातायात व संचार क्षेत्र, या बैंक व साख क्षेत्र का विकास होता है। सम्पूर्ण निजी क्षेत्र का विकास होने लगता है। श्री पापी का कथन है .

“The key to development is the growth of agricultural income, and if a country fails to achieve this before all else, the whole development process may be held back ” (P. 76).

2 Theodore W. Schultz :

श्री शुल्ज भी इसी मत के हैं कि अगर किसी काम को पूरा करना हो तो उसे कायदे से शुरू से करना पड़ेगा। कृषि के विकास न करने पर खाद्यान्न विदेशों

से मंगाना पड़ेगा और देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में ही चली जाया करेगी।

3-4-5 : C. P. Kindleberger, B F Johnston तथा J. W. Mellor.

ये अर्थशास्त्री भी कृषि के विकास को सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया का पहला चरण मानते हैं। इनका कथन है कि कृषि विकास से उद्योगों का विकास होगा, बहु-मूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं और खाद्यान्न के आयात का खर्च बच सकता है। कम विकसित देश जितनी आसानी से कृषि उपज को निर्यात कर सकते हैं उतनी आसानी से औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुएँ निर्यात नहीं कर पाते।

इसके अतिरिक्त जब तक कृषि क्षेत्र विकसित नहीं होगा, औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं की मांग वहाँ से उत्पन्न होगी। कृषि का विकास करके, तथा उसकी बढ़ी हुई आय को उचित राजस्व नीतियों द्वारा कर के रूप में लेकर पूँजी निर्माण भी कर सकते हैं। कृषि विकास से ही उपभोग व उत्पादन क्षेत्र में साथ-साथ विकास हो सकता है।

Dr Bright Singh

डा० ब्राइट सिंह भी कृषि विकास को प्राथमिकता देने के पक्ष में हैं। उनका कथन है कि कम-विकसित देशों में विशेषकर एशिया में न्यूनतम आवश्यक जीवन निर्वाह उपभोग स्तर से भी 5% लेकर 20% तक है। इन देशों में उपभोग का अधिकांश भाग खाद्यान्न पर व्यय होता है और जब आय बढ़ती है तो सर्वप्रथम कृषि पदार्थों की ही माँग बढ़ती है (Income elasticity of food is high.....coefficients range between 0.6 to 0.7). अर्थात् अगर किसी व्यक्ति की आय 1 रुपए से बढ़ती है तो खाद्यान्न की आय 60 से 70 पैसे तक बढ़ जाती है।

1. Theodore W. Schultz The Economic Organisation of Agriculture : Mc Graw Hill, New York 1953 P. 273
2. C. P. Kindleberger op cit P 218-19.
3. B. F. Johnston & J W. Mellor, "The role of Agriculture in Economic Development, American Economic Review, Sept., 1961. P. 566-593

Dr. Bright Singh (Prof. of Economics, Madras University) : op-cit. ch. XIV : p 500.

कम विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि 2 से 2.5% प्रतिवर्ष हो रही है। इस प्रकार से इन देशों में भुखमरी रोकने के लिए ही कृषि की उन्नति आवश्यक होगी। विकास के साथ-साथ कृषि उपज की विस्मों की मांग भी बढ़ती है फिर अन्धे अनाज, फल, सब्जी, धो, दूध तथा गोरत व अडो की मांग बढ़ती है। अगर कृषि का विकास नहीं करेंगे तो कच्चे माल महंगे होंगे और फिर देश में महंगाई से निर्यात भी हतोत्साहित होंगे।

परन्तु डॉ० सिंह यह भी कहते हैं कि कृषि की उन्नति इस प्रकार से नहीं की जानी चाहिए कि कृषि पदार्थों की बहुतायत से मूल्य गिर जाएँ और कृषकों को हानि होने लगे कृषि की उन्नति मांग के अनुरूप हो होना चाहिए।

कृषि की उन्नति से ही देश में सड़कों, आवास व शहरीकरण का विकास होगा। कृषि की उन्नति से ही देश में श्रम की सीमान्त उत्पादकता बराबर होती है अन्यथा कृषि क्षेत्र में सीमान्त उत्पादकता कम रहती है। कृषि विकास ही कृषि की बेरोजगारी समस्या का निराकरण है।

निष्कर्ष :

जैसा कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है, कृषि का विकास, विकास प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है तथा आवश्यक कार्य है निष्कर्ष में हम Meier and Baldwin का मत उद्धृत कर सकते हैं :

“कृषि व उद्योग का विकास एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है बरन् एक दूसरे के पूरक है बहुधा उद्योग क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र के विकास पर आधारित है। कृषि क्षेत्र के विकास बिना केवल औद्योगिक क्षेत्र के विकास से मुद्रा स्थिति फैलेगी कृषकों की आय में वृद्धि किए बगैर उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए उन्नत कृषि की मजबूत नींव चाहिए। बहुधा यह कहा जाता है कि कृषि की उत्पादकता कम है परन्तु कृषि में जो ऊँची सीमान्त सामाजिक उत्पादकता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता कृषि कम प्रति व्यक्ति आय के लिए उत्तरदायी नहीं है बरन् पिछड़ी कृषि इसके लिए उत्तरदायी है और अगर कृषि को उन्नत किया जाए तो फिर देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जो विकास का मापदण्ड है।”

वास्तव में बहुत से अर्थशास्त्री कृषि को ही प्राथमिकता देना चाहते हैं। उनका कथन है "you have to start somewhere before starting everywhere, and it is better to start from the beginning and from agriculture" यह मत U N reports में हमें देखने को मिलता है।

संतुलित विकास के समर्थक तो कृषि के पक्ष में लिखते ही हैं, कुछ असंतुलित विकास के पक्ष में लिखने वाले अर्थशास्त्री भी कृषि में विनियोजन को महत्व देने हैं।

भारत ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ण सफलता न होने पर इस तथ्य को समझा है और कृषि की तरफ पूर्ण ध्यान देने पर आज कृषि उपज की पर्याप्तता के कारण जो मूल्य गिरे हैं उसमें अर्थव्यवस्था पर strain या भार कम हुआ है। Benjamin Higgins ने भी इसी प्रकार कहा है

"So far as industry vis agriculture is concerned it is not a question of balanced growth or unbalanced growth but one of balanced growth or no growth at all."

III B Declining Importance Of Agriculture In Growth Process विकास के साथ-साथ कृषि का महत्व घटता जाता है।

विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण अवश्य है परन्तु जैसे-जैसे विकास होता जाता है वैसे-वैसे कृषि का महत्व घटता जाता है K.E Boulding के अनुसार "कृषि में तकनीकी सफलता से ही उसका महत्व घट जाता है।" इसका मुख्य कारण कृषि-उपज की Low-income elasticity है, अर्थात् आय बढ़ने के साथ-साथ एक सीमा के बाद कृषि पदार्थों की माँग घटने लगती है फिर राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान और कम होता जाता है। श्री मार्टिन एन (Martin Anne) ने कृषि पदार्थों की आय-जोड़ इस प्रकार आँकी है

1. K.E Boulding . "Principles of Economic Policy" Agriculture Policy. ch. 13. p 314 ff
- 2 Martin Anne : "Economics & Agriculture, Routledge and Kagan Paul, London 1958 P. 21.

विकास व कृषि

लका	.79	स्वीडेन	.32
जर्मनी	.36	यू.एस.ए.	.27
यू०के०	.33		

डॉ० एगबर्ट दी व्रोज (Dr. Egbert de Vries) के अनुसार अगर देश में 10 प्रतिशत प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि होती है तो कृषि का योगदान $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत गिर जायेगा. भारतवर्ष में 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हैं जो राष्ट्रीय आय के 50 प्रतिशत भाग को उत्पन्न करते हैं. इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में व्यक्तियों का योगदान अकृषि क्षेत्र के मुकाबले में केवल $\frac{1}{3}$ ही है. जैसे-जैसे विकास आगे बढ़ता है कृषि का कार्य राष्ट्रीय आय में योगदान कम हो जाता है. U.S.A. में जहाँ 18 वीं सदी में 90 प्रतिशत साधनों को लगाया गया वहाँ 1870 तक यह प्रतिशत केवल 50 था और 1960 में यह 15% रह गया. कालान्तर में यह प्रतिशत 5 तक रह जाएगा.

कृषि क्षेत्र में अकृषि क्षेत्र में अधिक आय कमाई जाती है. इसलिए विकास के साथ-साथ लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाने लगते हैं, कृषि में जो तकनीकी उन्नति होती है उससे भी बहुत से व्यक्ति कृषि कार्यों के लिए फालतू हो जाते हैं इसी प्रकार से भूमि की पूर्ति के बेलोच हाने के कारण (जनमर्यादा वृद्धि के साथ भूमि की मात्रा नहीं बढ़ती है) भी लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है.

इसके अतिरिक्त जब कृषि के विकास के परिणामस्वरूप कृषि में अधिक उत्पादन होता है तो कृषि के मूल्य गिर जाते हैं जबकि उद्योग में बनी वस्तुओं के मूल्य नहीं गिरते. इससे कृषि की भुगतान की शर्तें (Terms of Trade) विपक्ष में जाती हैं. कृषि क्षेत्र के अनुपात में उद्योग क्षेत्र में अधिक लाभ होने लगते हैं कृषि के अनिश्चित वातावरण से जहाँ मौसम की अनिश्चितता बनी रहती है तथा जहाँ मौसमी व्यापार चक्रों का प्रभाव पड़ता है, वहाँ से लोग निकलकर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ लाभ अधिक होते हैं. कृषि का आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति-कर्ता के रूप में भी महत्व घट जाता है क्योंकि आधुनिक युग में कृत्रिम कच्चे माल (Synthetic Products) के कारण भी पैदा होने लगे हैं :

कृषि का विकास शुरू करने में महत्व है, विकास के बाद महत्व घट जाता है :

“Though salvation of a country lies in industrialization raising of agricultural production will be sine qua non of any programme for growth.”¹

IV. Conditions for Agricultural Take-off and Sustained Growth in Under-Developed Countries : कम-विकसित देशों में कृषि के आत्म-स्फूर्ति की अवस्था को पहुँचाने व स्थायी विकास के लिए आवश्यक तत्व •

कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम नीति है “Remove the cause remove the evil” अर्थात् अगर हम बाँप दूर कर दें तो विकास स्वयं होगा.

Johnston and Mellor ने कृषि के विकास को तीन अवस्थाओं में बाँटा है प्रथम Pre-condition का हमारी अवस्था में कृषि में धम-गहन व पूँजी बचत करने की नीतियाँ अपनाना चाहिये, और तीसरी अवस्था में पूँजी-गहन व धम बचत करने वाली तदनीक अपनाना चाहिए

प्रथम अवस्था में •

हमको (I) भूमि-सुधार करना चाहिए, भूमि का अनुकूलतम वितरण करना चाहिए, लगान की स्थिति ठीक करना चाहिए.

(II) कृषकों को शिक्षित करना चाहिए तथा उनकी पिछड़ी मनोवृत्ति को दूर करना चाहिए.

(III) विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए

(IV) भूमि की चकबन्दी का कार्य करना चाहिए, परती भूमि को कृषि योग्य करना तथा भू-क्षरण को समाप्त करना चाहिए.

द्वितीय अवस्था में :

हमको (I) कृषि की तकनीक में उन्नति करना चाहिए

(II) अच्छे बीज, अच्छी सिंचाई व खाद की सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए.

(III) कृषि साख व सहकारिता की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए.

(IV) यातायात में सुधार होना चाहिए.

(v) कृषि में अनुसन्धान.

(vi) सरकारी सहायता व व्यवस्था परिपक्व हो जाना चाहिए
तृतीय अवस्था में .

हमको कृषि का यंत्रीकरण करना चाहिए.

Johnston and Mellor की इन अवस्थाओं के अनुसार ही कृषि के लिए आवश्यक नीतियों का अध्ययन करेंगे इनमें थोड़ा-सा सुधार कर दिया गया है परन्तु तर्कों में अन्य शर्तशालिनियों के मत का समावेश किया गया है.

IV -I. Land Reforms and Agricultural development भूमि-सुधार तथा कृषि में उन्नति :

कृषि विकास के लिए शायद सर्वप्रथम भूमि-सुधार आवश्यक होगा. जो बड़े-बड़े जमींदार, बड़ी-बड़ी जमीने रखे रहते हैं उन्हें लेकर कृषिहीन किसानों को उनका मालिक बनाना चाहिए बड़े जमींदारों को कमी भी ऐसी जमीन को रखने की इजाजत नहीं देना चाहिए जिस पर वे स्वयं कृषि न कर सकें. इससे कृषक-मजदूरों की रोजगार स्थिति में चाहे परिवर्तन न हो परन्तु इससे उनकी आय बढ़ेगी तथा उनका सामाजिक स्तर तथा उनकी सुरक्षा में वृद्धि होती है.

भूमि-सुधारों का लक्ष्य देश की भूमि का ऐसा वितरण होना चाहिए जिससे कि भूमि के टुकड़े अनुकूलतम आकार के हो जाएँ. भूमि-सुधार का कार्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि साथ ही साथ छोटे किसानों को अलग-अलग सहकारी संगठन में बाँधकर वित्तीय सहायता भी नहीं प्रदान किया जाता पूर्ण की आवश्यक पूर्ति के साथ विपणन, संग्रह आदि की सुविधाएँ भी प्रदान करना चाहिए. भू-सुधार का कार्य भूमि की मालिकियत में परिवर्तन ही नहीं हो जाता है. भू-सुधार तो एक निरन्तर चलती रहने वाली क्रिया है. नये मालिकों को शिक्षित करना भी अत्यन्त आवश्यक है.

G. U. Papi के अनुसार

“The history of land reforms is full of examples of sorry failure, which go to show that the

problems of agriculture do not respond to isolated measures”

भूमि-मुधार से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषकों में अपने निजी लाभ बढ़ाने का प्रोत्साहन होता है, और धीरे-धीरे उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके उपयोग स्तर में वृद्धि हो जाती है।

प्रो० दान्तवाला तथा के० ई० बोल्टिङ्ग ने यह भी बताया है कि भूमि-मुधार की कृषि में क्रांति लाने का निश्चित कदम नहीं मान लेना चाहिए। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भूमि-मुधार निश्चित ही आवश्यक है, परन्तु अगर कृषि के बड़े भालिकों से जमीन लेकर गरीब कृषकों को देने से तकनीकी स्तर तथा विनियोजन की मांग गिर जाती है तो भूमि के अनाधिक दुकड़ों में बंट जाने से कृषि उपज गिर सकती है। इसलिए कृषि उन्नति के लिए पूंजी व्यवस्था तथा सहकारी कृषि आवश्यक हो जाती है।

लगान में कमी¹

कम-विकसित देशों में 70% आय खाने पर खर्च की जाती है और खाने की लागत में अनुमानतः 33-34 प्रतिशत भाग लगान का होता है। इस प्रकार से आय का 1/4 भाग लगान में चला जाता है। इसके विपरीत उन्नत देशों में केवल 12% आय खाने पर खर्च होती है जिसका 20% भाग ही लगान के रूप में जाता है। इस प्रकार से लगान का भाग राष्ट्रीय आय का केवल 2.5% होता है। लगान की अधिकता को कायम रखने के लिए Vested interest (मत-बंदी दत्त) का उद्देश्य होता है और वे भूमि मुरादा नहीं करने देते।

क्या लगान को कम करना चाहिए? इसका उत्तर आसान नहीं है। लगान कम करने से राजस्व की आय कम होती है तथा उसमें कृषि उन्नति कार्य करने की क्षमता घटती है या इसी प्रकार से जमींदारों की पूंजी घटती है। जापान में तो लगान वृद्धि के कारण ही वृद्धि के किमान अविव पैदा करने थे ताकि वे लगान चुकाकर अपने लिए बचा सकें।

इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि लगान पद्धति को प्रगतिशील बनाकर लगान ले सकते हैं, जो किसान अधिक या अविव मूल्य की फसलें उगाते हैं उनमें

1. See also : Bayer and Yamey . op cit. ch. xiv.

See D B Singh : op cit. p 475.

Schultz Economic Organization of Agriculture . Mc Graw Hill N York 1953 p 125-7.

अधिक लगान लिया जा सकता है और कम आय पाने वाले किसानों से कम या शून्य लगान लिया जा सकता है।

IV. II भूमि की चकबन्दी, भू-क्षरण को रोकना तथा पड़ती भूमि को पाटना

कम-विकसित देशों में भूमि-सुधार के बाद सर्वप्रथम भूमि के बिखरे टुकड़ों को चकबन्दी करके आर्थिक जोतों में परिवर्तित करना चाहिए भू-सुधार का लक्ष्य भूमि के बड़े टुकड़ों को तोड़ना ही नहीं होता है वरन् उनको अनुकूलतम जोता में परिवर्तन करना चाहिए, बड़े पैमाने की कृषि के लाभों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करना है इसलिए भूमि की चकबन्दी के बाद सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने पर कृषि हो सकती है प्रत्येक कम-विकसित देश में आर्थिक जोतों का निर्माण होना चाहिए जो एक कृषक परिवार को एक निश्चित आय प्रदान कर सके आर्थिक जोत की माना किसी देश में न्यूनतम अपेक्षित आय' भूमि की उर्वरता, सिंचाई सुविधाएँ, कृषि करने का तरीका, फसलों का स्वरूप, मूल्य स्तर आदि पर निर्भर करेगा।

भूमि की चकबन्दी करने के पश्चात् यह भी आवश्यक है कि आगे पुनः भूमि का अपक्षजन न हो इसके लिए आवश्यक नियम बनने चाहिए, जहाँ तक हो सके चकबन्दी को ऐच्छिक रूप से कराना चाहिए अन्यथा अनिवार्य रूप में भी चकबन्दी की जा सकती है।

चकबन्दी के साथ-साथ कृषि भूमि की उच्चतम सीमा भी निर्धारित करना चाहिए, भारत में ही, उदाहरणतया, कृषि क्षेत्र के 34.4% भाग पर 4.5% व्यक्ति कृषि करते हैं, जबकि 15.5% भाग पर 66.9% व्यक्ति कृषि करते हैं और लगभग 19% कृषि में रत व्यक्ति भूमि विहीन हैं, 45% व्यक्तियों के पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है, इसलिए भूमि की सीमा बाँध कर भूमि-विहीन श्रमिकों में भूमि बाँट देना चाहिए, बड़े-बड़े वागालों या बन्वा माल उगाने वाली इकाईयों को नहीं तोड़ना चाहिए, सीमा निर्धारण से घन की असमानताएँ दूर होती हैं, रोजगार में वृद्धि होती है तथा कृषि में उत्पादन भी बढ़ जाता है, बहुधा बड़े जमींदार भूमि को सट्टे के लिए काम में लाते हैं।

पड़ती भूमि को पाटना चाहिए :

कम-विकसित देशों में आज भी लाखों एकड़ भूमि दल-दल, अनावश्यक जंगलों, समुद्र के किनारे, अर्धरेगिस्तान, कृषि योग्य पहाड़ी भूमि तथा अन्य स्थानों पर

कृषि के प्रयोग में नहीं आ रही है इनको अगर पुन स्थापन कर दें तो वास्तव में भूमि की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है

भारत में मोटे तौर से कृषि के प्रयोग की यह स्थिति है

कुल क्षेत्रफल 32 68 करोड़ हैक्टर

वर्गित क्षेत्रफल 30 56 „ „

इन 30 56 करोड़ हैक्टर में से भूमि का प्रयोग इस प्रकार है

उचित प्रयोग 1	कृषि की जाने वाली भूमि	45 4%
2	जंगल	19.0%
3	शहरी भूमि, सड़के आदि	4 8%
4	चारा भूमि	4 7%
5	फल-कुज, मादि	1 9%
		<hr/> 75 8%

उचित प्रयोग न होने वाली भूमि

1	कृषि योग्य भूमि जिसका प्रयोग नहीं है	5.8%
2	पटती भूमि-बालू व अन्य	7 1%
3	कृषि के अयोग्य भूमि	11 3%
		<hr/> 24 2%

कुल दोनों का जोड़—100 0%

अगर प्रयत्न किए जाएं तो Terrace cultivation (सीढ़ी के रूप में खेती में खेती) पहाड़ी इलाकों में की जा सकती है. जहाँ तक वनों का संबंध है वे आवश्यक अवश्य है पर हम यह कर सकते हैं कि अर्धरगिस्तानी इलाकों में जंगलों का विस्तार करें तथा जहाँ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि निकल सकती है वहाँ जंगल काटे जा सकते हैं कृषि के अयोग्य भूमि को भी बहुत ही अधिक मात्रा में विनियोजन करके तथा उन्नत विज्ञान की तकनीक को अपनाकर कुछ न कुछ उपज लायक बनाया जा सकता है

कम-विकसित देशों में विकसित देशों के अनुपात में कृषि योग्य भूमि या तो कम है या जनसंख्या की अधिकता से प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम है. आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक अर्थात् 3 04 हैक्टर है. इसके बाद कनाडा में 2 26 हैक्टर, रूस में 1 15 हैक्टर व अमेरिका में 1 04 है. भारत में यह मात्रा केवल 0 37 हैक्टर, बर्मा में 0 63 हैक्टर व जापान में मात्र 0 07 है

ऐसी स्थिति में Bayer तथा Yamey का मत है

‘जहाँ भूमि कम तथा जनसंख्या अधिक हो वहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर प्रति एकड़ उपज बढ़ाना चाहिए’
(पृ० 382)

सहकारी कृषि

कम विकसित देशों में जहाँ समझ हो सहकारी कृषि की जानी चाहिए इससे भूमि का राष्ट्रीयकरण किए बिना ही बड़े पैमाने पर कृषि की जा सकती है इस प्रकार की कृषि से व्यक्तिगत कृषि एवं सामूहिक कृषि दोनों के लाभ प्राप्त हो सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं सहकारी कृषि व्यवस्था से उन्नत तकनीक अपनाई जा सकती है सिंचाई की उत्तम व्यवस्था संभव होगी साख व विपणन का उत्तम प्रबंध हो सकेगा यह भी संभव है कि इस प्रकार की कृषि से विपणन योग्य अधिक से अधिक पैदा हो तथा इससे कृषि के आर्थिक विकास के लिए अधिक पूँजी निर्माण संभव होगा इस प्रकार की संस्था को बैंकों से भी विनियोजन के लिए धन मिल जाता है उत्तम उपज कम मूल्य में पैदा होती है तथा मूल्यों के उच्चा-वचन से सामूहिक सुरक्षा हो सकती है

भारत जमीन की मालिकियत अलग रखना है तो जैसा कि फ्रांस, नार्वे, नीदरलैंड इंग्लैंड या मेक्सिको में है यह सहकारिता मशीनों, पानी व साधन-सुविधाओं के लाभ उठाने के लिए अपनायी जा सकती है पूर्वी योरोप के देशों में इस प्रकार की संस्थाएँ सफलता पूर्वक कृषि के विकास में सहयोग देती हैं U N O के अनुसार

‘It is clear that if small farms are to gain the benefit of new development co-operative farms, can fulfil a useful indeed an essential, function’

IV-III Capital formation and credit facilities in Growth कृषि विकास के लिए पूँजी निर्माण व साख व्यवस्था

कृषि विकास के हर कार्य के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है भूमि-मुपार के बाद यह पूँजी जमींदारों से नहीं मिल सकती और कृषकों को पेशेवर उधार देने

वालो के चगल में छुड़ाने के लिए भी यह कार्य राज्य, बैंक तथा सहकारिता के आधार पर ही करना पड़ेगा कम-विकसित देशों में कृषकों की अल्पकालिक, मध्य-कालीन तथा दीर्घकालीन समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। आज की स्थिति में "Money lender cannot be ended, he can be mended only." अर्थात् महाजन को समाप्त नहीं किया जा सकता बल्कि उसकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य को ऐसे अधिनियम बनाने चाहिए ताकि लायसेंस शुदा पेशेवर उधार देने वाले उचित रूप से उधार दे सकें राज्य को सम्बन्धित बाल से चले आ रहे ऋणों को अनिवार्य रूप से कम कर देना चाहिए शिक्षा के विकास के साथ कृषकों का अनुत्पादक ऋण के कम होने की आशा है परन्तु उत्पादक कार्यों के लिए उसकी माँग बढ़ेगी इसके लिए देश में सहकारी साख सर्वोत्तम व सबसे सस्ती होगी। देश के केन्द्रीय बैंक को तथा अन्य बैंकों को इस प्रणाली में मदद देना चाहिए। बैंक तो अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए ही ऋण दे सकते हैं। इन बैंकों को चाहिए कि इन देशों में भूमि वन्धक बैंकों के ऋण पत्रों व विलों में धन लगाकर उनकी साख व्यवस्था मजबूत करें और बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता के लिए बड़े निगमों की स्थापना की जानी चाहिए ये निगम व संस्थाएँ बहुत बड़ी दीर्घकालीन योजनाएँ जैसे सिंचाई योजनाएँ, भू-रक्षण व पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए सहकारी संस्थाओं को ऋण दे सकती हैं।

अल्पकालिक तथा गाँवों व किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहकारी संस्थाएँ ही आवश्यक होंगी इनसे कम व्याज दर पर धन प्राप्त होगा तथा लाभ से भी सदस्यगण ही लाभान्वित होते हैं कम-विकसित देशों में सहकारिता के आन्दोलन को अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाई क्योंकि कृषक अशिक्षित हैं, महाजनो ने इनकी सकलता में रोड़े अटकाए तथा इनमें भ्रष्टाचार का खोलबाला रहा, फिर भी जैसा कि कहा जाता है

"Co operation has failed, co-operation must succeed"

IV-IV. Extension of irrigation facilities, provision of better seeds and fertilizers and transportation.

सिंचाई :

कम-विकसित देशों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार परम आवश्यक होगा। इसके लिए बड़े-बड़े बाँध आवश्यक होंगे जो कुछ समय बाद सस्ता पानी तथा

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सस्ती बिजली प्रदान करेंगे परन्तु हाल की समस्याओं के निराकरण के लिए कम घन की मध्यम व छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में जल निकासी संबंधी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए सिंचाई मुविधाओं के समुचित प्रयोग के लिए खेतों में नालियाँ पृथक्-पृथक् बनाया जाना चाहिए कुओं, तालाबों तथा नलकूप योजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इन्हें बनाने के साथ-साथ अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए. सिंचाई के साथ-साथ भूमि में अधिक खाद देना चाहिए. जलवायु वेदन और नमक फूटने के दोषों के निवारण हेतु पानी की अधिकता वाली भूमि में वे पम्पों द्वारा पानी बाहर निकालना चाहिए. नहरों के तल कच्चीट से बनाना चाहिए, जल निकासी में मार्गों को साफ रखना चाहिए, कुओं से सिंचाई को प्रोत्साहन देना चाहिए, कृषकों पर जल के मित-भयितापूर्ण प्रयोग के लिए जोर देना चाहिए और नहरों से समय के अनुसार पानी मिलना चाहिए

बड़ी सिंचाई योजनाओं से राजगार में वृद्धि होती है, बाढ़ों में सुरक्षा तथा भूमि कटाव का निपटारा होता है, कृषि उपज की मात्रा व किस्म बढ़ती है, एक से अधिक फसलों की प्राप्ति की जा सकती है, यातायात की सुविधाएँ बढ़ती हैं और बिद्युतीकरण से छोटे बड़े सभी उद्योग बढ़ते हैं.

खाद :

खाद की सुविधाएँ भी बढ़ाना जरूरी है. इन्हीं पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि इन देशों में बहुत कम खाद दी जाती है. कम-विकसित देशों में महुँगे खाद के होते हुए भी आजकल विदेशों से खाद नहीं मँगायी जाती और न ही विदेशी कम्पनियों को इसका उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है भारत को अपने एक ही वर्ष के खाद आयात से नया कारखाना लगवा सकता है.

Uex Kuall के अनुसार

“इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा तथा भारत में यू० एस० ए० द्वारा उत्पादित खाद के मूल्य से 2 गुना व 3 गुना मूल्य देशी खाद का होता है और वे खाद का उत्पादन न बढ़ाते हैं और न विदेशी कम्पनियों को कारखाने लगाने देते हैं.”¹

H R. Von Uex Kuall : Obstacles to using Fertilizer for Rice in S. E. Asia, World Crops, March 1964.

See also Free Press Journal, London News letter, May 10, 1969.

1. “It becomes extremely difficult to generate a yield take off,

बीज :

भारत तथा अन्य कम-विकसित देशों में कुछ निम्न के उन्नत बीजों के प्रयोग से उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। इन बीजों के बहुगुणन तथा वितरण की आवश्यकता भी सर्वोपरि है।

पौध संरक्षण व जानवरों से बचाव :

कुछ अनुमानों के अनुसार कम-विकसित देशों में लगभग 1/4 फसल टिड्डियों, चूहों, पक्षियों, कीड़ों व जानवरों द्वारा खा ली जाती है। इनसे सुरक्षा किए बिना सारी Capital inputs (पूँजीगत लागतें) बेकार चली जाएंगी। इनको नष्ट करना मानव जाति के लिए स्वयं जीवन मरण का प्रश्न है।

मशीनीकरण

कालान्तर में कृषि का यंत्रीकरण आवश्यक होगा परन्तु जब तक कि देश में छद्म-बेरोजगारी बनी है तब तक ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा। मनुष्य के सहायता के लिए मशीन ठीक है। अभी उसको हटाने के लिए मशीन नहीं लगाना है।

यातायात :

यातायात के सुगम व सस्ते साधन भी कृषि की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

IV-V. Market orientation and Commercialization : कृषि का व्यापारीकरण करना तथा बाजार व्यवस्था उन्नत करना

कम-विकसित देशों में जो कृषि उपज होती है उसके विपणन को उचित व आधुनिक पद्धति से करना चाहिए और दूसरे इन देशों में विपणन योग्य आधिव्य की मात्रा में वृद्धि होना चाहिए। कम-विकसित देशों में कृषि उपज का केवल 1/4 से 1/2 भाग विपणन को जाता है। जब तक कि विपणन योग्य भाग में वृद्धि नहीं होती तब तक वृद्धि और पूँजी निर्माण कम रहेगा। पूँजी निर्माण ने ही उपज

without an adequate development of non-agricultural supporting cast, modern agriculture cannot develop in a vacuum. Increased application of fertilizers and optimum utilization of water are the two most important requisites for accelerating farm productivity in developing economies."

Dr. D. L. Narayana : op. cit. P. A. 49.

बढ़ाने वाली Capital inputs बढ़ाई जा सकती है जिससे उत्पादकता तथा विपणन योग्य आधिक्य बढ़ता है

कम-विकसित देशों में सर्वप्रथम नियंत्रित मंडियों की स्थापना होना चाहिए जहाँ नियमपूर्वक विपणन हो, जहाँ तेल, भावों व चुकाने की पद्धतियों में एकरूपता हो, जहाँ कृषक अपनी उपज को स्वतन्त्र रूप में बेच सकें तथा जहाँ बीच के बिचौलियों शोषण न कर सकें। इन मंडियों में उचित श्रेणी विभाजन व प्रमाणीकरण पद्धतियाँ होना चाहिए। इस सुविधा से न केवल धान्तरिक व्यापार में वृद्धि होती है बल्कि निर्माता भी प्रोत्साहित होते हैं।

देश में गोदामों की सुविधाएँ भी विकसित करना चाहिए। इससे उपज नष्ट होने से बचती है तथा कृषि मूल्यों में गिरावट बच जाती है। कृषि के विपणन सुधारों में विपणन अनुसंधान एक सर्वोच्च, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, यातायात सुविधाओं का सुधार, तथा मूल्य आदि की तत्काल जानकारी आवश्यक होगी।

इस संबंध में कम-विकसित देशों में सहकारी विपणन की सम्भावनाओं को जाँचना चाहिए। सहकारी कृषि, सहकारी वित्त-व्यवस्था तथा सहकारी विपणन साथ ही तो और सफलता होगी, अन्यथा सहकारी विपणन संस्था का छोटे-छोटे क्षेत्रों से या छोटे-छोटे कृषकों से विपणन योग्य वस्तु खरीदने में अधिक समय व व्यय लगेगा, Monoculture Countries (मुख्य रूप से एक ही फसल उत्पन्न करने वाले देश) इस प्रकार की विपणन पद्धति से मूल्यों के उच्चावचन से भी सुरक्षा कर सकते हैं बिचौलियों के हटने से अधिक मूल्य मिल जाते हैं तथा प्रतिव्यक्ति व प्रति एकड़ उत्पादकता, जैसा कि योरोप के देशों में हुआ, बढ़ जाती है।

IV-VI. Agricultural research, sine qua non, for agricultural development : कृषि विकास व कृषि अनुसंधान :

कृषि की उन्नति के लिए अनुसंधान का महत्व कम नहीं है। कई कम-विकसित देश विकसित देश की तकनीक को आँख मोच कर नकल नहीं कर सकते। Herdt तथा Mellor ने यह सिद्ध किया है कि जहाँ U S A. में प्रति एकड़ 120 पौंड नाइट्रोजन खाद दी जा सकती है वहाँ भारत में 50 पौंड से ऊपर हानि होने लगती है इसलिये परिस्थितियों के अनुसार कार्य होना चाहिए।¹

1. R. W. Herdt and J. W. Mellor "Contrasting Response of Rice to Nitrogen, India and U. S., p. 155. From "Agricultural Take off in Under-developed Countries" Dr. D. L. Narayana, Commerce Annual Nov. 1965.

अनुसंधान तो कृषि विकास की कुंजी है. Dr. Mc. Meekan के अनुसार.¹ कम-विकसित देशों में कृषि अनुसंधान के पूर्ण सफल होने में दो मुख्य बाधाएँ हैं :

- (i) प्रथम तो इन देशों में सैद्धान्तिक समस्याओं पर अधिक कार्य होता है और स्थानीय महत्व के व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता.
- (ii) दूसरे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ स्थानीय समस्याओं को नहीं समझते तथा इन देशों के विशेषज्ञ विदेशों की बातें बगैर उन्हें देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखे सामू करना चाहते हैं. इनका कथन है कि अनुसंधानों के कार्यों को लाभदायक होना चाहिए. इनकी सफलता में राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रशासकों का सहयोग होना चाहिए.

Johnston and Mellor² का विचार है कि यह समस्त अनुसंधान का कार्य राज्य या अन्य किसी बड़ी संस्था को हाथों में लेना होगा "भारत के 6,00,000 गाँव बगैर राज्य के पथ प्रदर्शन के स्वयं सगठित होकर उन्नति नहीं कर सकते." उनका कथन है कि नई उत्पादन पद्धतियाँ, नये बीज व उचित खाद व्यवस्था, नई विपणन, साख व सगठन प्रणालियों के लिए अनुसंधान बाहर से करना होगा.

IV-VII. High level of literacy : शिक्षा का विकास व कृषि : शिक्षा के बगैर कृषि अनुसंधान की जानकारी को कृषकों में नहीं फैलाया जा सकता. अनुसंधानशालाओं के सफल प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही तो फैलाए जा सकते हैं, अभी तक का अनुभव यह साबित कर देता है कि जब तक अशिक्षा बनी रहेगी तब तक उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो सकती. अशिक्षा ही अज्ञान है. सामाजिक पिछड़ेपन से नव प्रवर्तन नहीं होते, निराशा का वातावरण फैलता है और नई माय्यताओं में विश्वास पैदा नहीं होता.³

1. Mc. Meekan : Finance and Development—The Fund and Bank Review vol II No 2, June 1965 p. 78 Washington D. C

2. Johnston & Mellor op cit.

3. उत्तर प्रदेश के माताटीला बाँध का पानी जब सिंचाई के लिये नहरों में छोड़ा गया था तो नहरी क्षेत्र के अशिक्षित कृषकों ने उसे प्रयोग नहीं किया क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि उस पानी में विजली निकाल लेने पर उसमें सिंचाई के सत्व नहीं रहे.

श्री लेस्टर ब्राउन (Lester R. Brown)¹ के अनुसार शिक्षा व उत्पादकता में गहरा सम्बन्ध है, उन्होंने मुख्य चावल, गेहूँ व मक्का उगाने वाले देशों का अध्ययन किया। 1935-1962 के बीच इनमें से 24 देशों में साक्षरता का प्रतिशत 50 से कम था, तो इनमें उत्पादकता वृद्धि दर 0.17 थी, परन्तु जिन 13 देशों में साक्षरता प्रतिशत 50-80 के बीच थी वहाँ उत्पादकता वृद्धि 1.02 प्रतिशत रही अन्य 23 देशों में जहाँ साक्षरता का अनुपात 80 प्रतिशत से ऊपर था वहाँ उत्पादकता वृद्धि 1.43 प्रतिशत थी।

कम-विकसित देशों में तो दुर्भाग्यवश यह साक्षरता अनुपात 25 से भी कम है।

शिक्षा का विस्तार अवश्य एक आवश्यक शर्त है परन्तु इसके प्रसार मात्र से ही कृषि आत्मसufficiency समस्या में नहीं पहुँच जाती शिक्षा के विस्तार से विकास की राह के अवरोध दूर करने में मदद मिलती है

IV-VIII Price-Support and Price Incentives कृषि विकास तथा मूल्य नीति

कृषि विकास के लिए राज्य को मूल्य सम्बन्धी प्रेरणा या सहायता देना चाहिए अथवा नहीं इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद है। अधिकांश अर्थशास्त्री यह चाहते हैं कि राज्य कृषकों को मूल्य सम्बन्धी सहायता दे, वैसे यह माना जाता है कि कृषक अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन के अनुसार उपज की मात्रा व किस्म में परिवर्तन नहीं करते, बहुत से कृषक मूल्य गिरने पर भी कृषि करते रहते हैं और बढ़ती बढ़ने पर भी शीघ्र उपज नहीं बढ़ाते फिर भी यह आवश्यक है कि कृषकों को मूल्य सम्बन्धी प्रेरणा दी जाए कि वे आधुनिक ढंग से कृषि करें और उत्पादकता बढ़ाएँ इसलिए साक्ष उपलब्ध कराने के साथ-साथ कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त होना चाहिए अर्थात् ऐसे मूल्य हों जिनसे उसे प्रेरणा मिले कि वह अपनी कृषि को उद्योग की भाँति संचालित करें, अगर उन्हें उन्नत तकनीक सीखने या अपनाते में रुचि होता है तो राज्य को उन्हें अनुदान आदि देना चाहिए अन्यथा वह नव-प्रवर्तनों को कृषि में नहीं अपनाएगा।

कृषि में बहुधा मूल्य गिरने की प्रवृत्ति सामने आ सकती है कृषि पदार्थों का उत्पादन अगर अधिक हो जाता है तो मूल्य गिर जाते हैं यद्यपि के दिनों में भी कृषि उपज कम नहीं होती जब कि औद्योगिक उत्पादन कम कर दिया जाता

1. World Population and Food supplies 1980, A & A Special Publication, No. 6 PP 12-13.

है कृषि बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है जब कि औद्योगिक वस्तुओं का बाजार एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार होता है। इसलिए कृषि वस्तुओं की "व्यापार की शर्तें" गिर जाती हैं (अर्थात् औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों से कृषि वस्तुओं के मूल्य अधिक गिर जाते हैं) जहाँ औद्योगिक क्षेत्र के अधिक बेरोजगारी से पीड़ित रहते हैं कृषि क्षेत्र के व्यक्ति कम आय से पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए बहुत से अर्थशास्त्री कृषकों को Price support देने की गिफ़ारिश करते हैं

K. E. Boulding तथा A. G. Hart इस नीति के विरुद्ध हैं इनका कथन है कि कृषकों के हित को ध्यान में रखने के लिए जो बाजार मूल्यों से अधिक मूल्य रखे जाते हैं उनसे लाभ के स्थान पर हानि ही सुनिश्चित है : (This method is wasteful and self-defeating) बोल्टिङ्ग का कथन है कि इस नीति में बड़े किसानों को ही लाभ होया क्योंकि छोटे कृषकों के पास विपणन और अधिक व्यय बहुत कम होता है, उनके शब्दों में .

"In case of a completely self-subsistent home-
stead which sells nothing off the farm the
level of income is completely unaffected by
prices, for nothing multiplied by anything is
still nothing

So a policy of raising farm prices through
some artificial means helps the rich farmers
who constitute the backbone of agriculture
organisation and pressure groups much more
that it helps the poor farmers".

A.G. Hart इस नीति को "Charity racket" कहते हैं अर्थात् "दल का राज्य" यह अनुदान व सहायता की रूप में दे सकता है प्रथम जैसे वह मूल्य 1.50 कितना रखना चाहता और बाजार में वह 0.75 रु० में विक्री होती है तो राज्य उसे स्वयं 1 रु० में ले या फिर कृषक को 0.25 रु० सहायता रूप में दे दे

विकसित देश तो इस नीति को और भी नहीं अपना सकते. उनके सामने जब अधिक उत्पादन के कारण मूल्य गिरने की समस्या आती है तो उनके सामने चार विकल्प हो सकते हैं

(1) वे कुछ फसल को नष्ट कर दें, जैसे यू एस ए करता था या ब्राजील काफी को नष्ट कर देता था आज के इस वातावरण में जबकि कम-विकासित देशों में इतनी भूख है यह निन्दनीय कार्य होगा (Patently wicked)

(11) वे कम-विकासित को सहायता या कम मूल्य पर दे सकते हैं.

(111) या वे उत्पादन गिरा सकते हैं

उचित यह होगा कि वे सस्ते दर पर गरीबों को दें वे कृषकों को मूल्य सहायता अनुचित होगा.

समुचित मत यह है कि आवश्यकता पड़ने पर कृषकों को Price Support देना अनुचित नहीं होगा ¹

IV-IX Provision of Agricultural Service and Agricultural Leadership कृषि विकास के लिए यह उचित नेतृत्व व सेवाओं का प्रावधान

कम-विकासित देशों में कृषक कृषि को बड़े उदासीन रूप में करता है (The subsistence farmer is a routine cultivator) इन देशों में ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं व राज्य प्रशासन की आवश्यकता है जो इन अशिक्षित, भाग्यवादी, निरुत्साही, पुराने विचारों वाले किसानों को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जाये कि वे उत्साह के साथ कृषि को प्राधुनिक ढंग से करें. इन देशों में National Extension Service को शुरू करना चाहिए जिससे उन्हें उन्नत खेती के तरीकों को सिखाया जाए Demonstration farms की स्थापना से ही कृषक अच्छी खेती के तरीके सीखेंगे व अपनाएंगे कृषकों को सिखाई करने भ्रष्टाचार रोकने, खाद देने, बीज चुनने आदि के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह मिलना चाहिए Mobile vans (चलती फिरती गाड़ियों) में यह सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है. कृषि विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि स्थानीय, राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर के कार्य-क्रमों में समन्वय हो.



आर्थिक विकास तथा श्रम को योगदान व मजदूरी नीति और विकास

Role of Labour Force and Wage Policy for Economic Development

I. Role of Labour force in Growth.

- A. "Work force" या श्रम शक्ति का अर्थ,
- B. श्रम-शक्ति व विकास.
- C. श्रम-शक्ति को उन्नत करने के लिए आवश्यक कदम.
- D. श्रम संघों का विश्वास में योगदान.

II. Wage policy for economic development.

1. न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित व कार्यान्वित करना चाहिए.
2. मजदूरी का प्रमाणोकरण चाहिए.
3. वास्तविक मजदूरी को गिराकर पूंजी निर्माण संबंधी अनुचित होगा.
4. मजदूरी को मुद्रा स्फीति का 'एजेंट' नहीं बनने देना चाहिए.
5. मजदूरी को उत्पादकता वृद्धि का जरिया होना चाहिए. प्रेरणादायक मजदूरी देना आवश्यक.
6. देश में सामूहिक सौदागिरी प्रथा (collective bargaining) को कार्यशील होने देना चाहिए. विकेंद्रित मजदूरी नीति की आवश्यकता.
7. सामाजिक सुरक्षा का धीरे-धीरे विकास.
8. मजदूरी नीति को रोजगार व उत्पादकता वृद्धि योजनाओं से समन्वित

यह अध्याय लेखक की पुस्तक 'Economics of Wages, Productivity and Employment' के अध्याय 11 व 12 पर आधारित है.

See also :

- (i) Charles D. Stewart : Role of labour force in Growth ch. IV of Williamson & Butchick's op. cit.
- (ii) Tokyo conference on Economic Growth, papers of Dobb & Ashok Mehta.
- (iii) Meier & Baldwin : op. cit.
- (iv) B. Higgins : op. cit.

अध्याय : 3

आर्थिक विकास तथा श्रम की योग- दान व मज़दूरी नीति और विकास

Role of Labour Force and Wage Policy for
Economic Development

I Role of Labour force in Growth.

A. "work force" का अर्थ व्यापक रूप से लिया जा सकता है. इसके अन्तर्गत साहसी, मैनेजर, तकनीकी विशेषज्ञ व वैज्ञानिक भी आ जाते हैं. परन्तु हम "work force" का अर्थ मनुष्यवृत्ति रूप में लेते हैं और हमारा आशय यहाँ श्रमिक से है. वैसे तो कम-विकसित देशों में विकास के प्रमुख घटकों के रूप में पूँजी व साहसियों को ही माना जाता है, फिर भी यम शक्ति ही विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले "हाथ" हैं व साहसी मस्तिष्क हैं. Lewis तथा Nurkse तो केवल श्रम-शक्ति के प्रमुख घटक के आधार पर ही विकास करने की सम्भावनाएँ देखते हैं.

B. श्री चार्ल्स डी० स्टेवर्ट के शब्दों में :

"Economic development is conditioned by the character of the work force and by the response of workers to innovations, large and small, which lead to more efficient production and increase real income."

जहाँ तक श्रम-शक्ति व विकास का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में मुख्य कार्य श्रम-शक्ति को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में लाना तथा उसे प्रशिक्षित करना है. उनकी मनोवृत्ति तथा आचरण में उचित परिवर्तन लाना है. उनमें नई तकनीक अपनाने की इच्छा व क्षमता का विकास करना होगा.

जैसा कि हम "कम-विकसित देशों की विशेषताओं" के अध्याय में पढ़ चुके हैं, इन देशों में जन-शक्ति, गरीब, अशिक्षित, या कमशिक्षित, कमशोर, अप्रशिक्षित,

इस सम्बन्ध में हम Lewis तथा Nurkse मॉडल अध्ययन कर चुके हैं.

कम उत्पादक, रूढ़िवादी, परम्परागत मान्यता वाली है। इससे विकास में बाधा पड़ती है, उसी यह स्थिति स्वयं विकास की कमी से है

Stewart के शब्दों में

"The work force is not something, independent or separate from the society of which it is a part. Deficiency in the work force—illiteracy, lack of training and skill, unfavourable attitudes towards the work of suspicion of change—limit the rate of industrial progress, they are at the same time consequences of the entire social milieu associated with the existing stage of economic development."

कम विकसित देशों में श्रम राज्य की अवज्ञा का शिकार रहा है समाज ने उसे उचित दर्जा नहीं दिया, उसे उसकी मेहनत का उचित पुरस्कार नहीं मिला, पूँजी-पतियो ने उसका शोषण किया है सदियों से श्रम गुलाम रहा है। परन्तु सोवियत क्रान्ति ने श्रम को उसका महत्व सामने ला दिया है जबकि साम्राज्यवादी देशों में उन देशों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक कल्याण की सुविधाएँ प्रदान की जाने लगी थीं। कम-विकसित देशों में इन्हीं देशों ने छोटी से छोटी सुविधा देने से वंचित रखा १

C. कम-विकसित देशों में श्रम शक्ति का विकास में भरपूर योगदान संभव हो इसके लिए निम्नलिखित कदम अत्यन्त आवश्यक होंगे

- (1) श्रमिकों को शिक्षित व प्रशिक्षित करना होगा, इसका व्यय मुख्यतः राज्य को उठाना होगा, किसी देश का सबसे अधिक बहुमूल्य साधन सोना चाँदी नहीं बल्कि वहाँ की जनशक्ति होती है
- (ii) कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी व अल्प बेरोजगारी दूर कर वहाँ की अतिरिक्त जनसंख्या के लिये शहरों में रोजगार व्यवस्था करना चाहिए,
- (iii) श्रमिकों की मनोवृत्ति इस प्रकार करनी होगी कि वे तकनीकी परिवर्तनों के खिलाफ न हों अगर उनके रोजगार के हित सुरक्षित रहे तो इसमें कठिनाई नहीं होगी।

- (iv) उनको उचित मजदूरी तथा अतिरिक्त प्राय मिलना चाहिए अर्थात् उन्हें उत्पादकता वृद्धि से पर्याप्त हिस्सा मिलना चाहिए
(इस पर इसी अध्याय व अगले अध्याय में विस्तार से लिखा है)

Stewart के शब्दों में

“Broader distribution of the fruits of economic progress appears to be a necessary condition for maximum growth of per-capita income in industrialized society, in terms both creating an expanding domestic market and providing incentives to workers to respond favourably to changes in traditional patterns of work. High productivity and low wages favour luxury expenditure on personal servants and foreign imports at the expense of possible growth of domestic “Industries based on mass consumption”

- (v) देश में श्रम सघों का पर्याप्त विकास हो तथा देश में सामूहिक सौदागिरी प्रणाली हो श्रम सघ देश में धर्मिकों को उचित वेतन व लाभ का उचित भाग दिलाने हैं वे श्रम की उत्पादकता वृद्धि में सहायक हो सकते हैं वे उत्पादनकर्ताओं को उत्पादन पद्धति के सुधार में सहायता दे सकते हैं जहाँ आवश्यक हो उनके सहयोग से Wage Restraint तथा Rationalization की नीतियों को कार्यान्वित करा सकते हैं

श्रमिक जब गाँवों से शहरों में आते हैं तो बहुत सी आर्थिक सामाजिक समस्याएँ सामने आती हैं इनके समाधान के बगैर श्रम शक्ति का विकास में अपेक्षित योगदान नहीं हो सकेगा। ये समस्याएँ हैं, गन्दी वस्तियाँ, पारिवारिक विघटन, बेरखा-वृत्ति, बाल-मरण, जुआखोरी, शराबवाजी आदि। श्रमसघ इस समस्याओं के निराकरण में सहायता दे सकते हैं।

श्रम सघ धर्मिकों के हित के लिए आवश्यक नियम बनवा सकते हैं जो धर्मिकों के कार्य, रहने व वेतन संबंधी सुविधाओं को बढ़ाएँ। श्रम सघों को कुछ राजनैतिक कर्तव्य अवश्य निभाने पड़ते हैं परन्तु सरकार बनाना, सरकार का विरोध

करना या राजनैतिक समस्याओं पर प्रचार या आन्दोलन करने से उन्हें खवप नही रखना चाहिए।

D कम-विकसित देशों में धर्मसंघों का संगठन कार्य-प्रणाली अभी ऐसी नहीं है कि वे विकास में सहायक हों। बहुधा वे विकास में बाधा ही उत्पन्न कर देते हैं। इन देशों में धर्म संघों की वित्तीय व्यवस्था शोचनीय होती है। सदस्यों की संख्या कम तथा अस्थिर रहती है, उनके वित्तीय प्रवन्ध असंतोषजनक होता है, उनके नेताओं में अनुभव, लगन व परिपक्वता की कमी होती है उनके नेता धर्मसंघों के माध्यम से अपने राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। ये नेता बाहर के आन्दोलन से प्रभावित रहते हैं। इन देशों में धर्म संघों व नेताओं की आवश्यकता से अधिक सरया होती है। ये सब धर्म-क्रियाएँ के कार्यों में उतनी रूचि नहीं लेते हैं। इन देशों में इन सब बुराइयों की जड़ धर्मिकों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ऋणप्रस्तता तथा जनसंख्या की वृद्धि है। दुर्भाग्य से इन देशों में राज्य का आचरण व व्यवहार भी निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ताओं से अच्छा नहीं होना। राज्य के उद्योगों में भी धर्मिकों का असंतोष बना रहता है। इन उद्योगों के प्रशासक तो धर्म संघों में रुचीनापन और समाप्त कर देने हैं।

Webb का मत है कि धर्म-मनष तीन मान्यताओं से प्रभावित होते हैं

- (i) The doctrine of vested interest (अपने स्वार्थ की भावना) इसके अन्तर्गत वे राज्य का संरक्षण माँगते हैं, नई तकनीक अपनाते में बाधा डालते हैं, भिन्न-भिन्न धर्म-संघों में अन्तर बनाए रखते हैं आदि।
- (ii) The doctrine of supply and demand (माँग व पूर्ति का नियम) इसके अन्तर्गत वे सामूहिक सौदागिरी, मजदूरी संरचना, हड़ताल, तालाबन्दी उत्पादन को जानबूझ कर कम रखना या फिर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होना आदि की ओर अधिक ध्यान देते हैं।
- (iii) The doctrine of improvement. (सुधार के नियम) इसके अन्तर्गत धर्म संघ धर्मिकों की कार्य करते, रहने की अवस्थाओं में सुधार के लिये प्रयत्न करते हैं। मजदूरी को बढ़ावाते हैं तथा धर्मिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि कराने की ओर ध्यान देने हैं।

Webb का कथन है कि श्रम सघो को प्रथम नीति छोड़ देना चाहिए, द्वितीय को संशोधित रूप में अपनाये तथा तृतीय कार्यो को बढ़ावा दे.

श्री वी० के० धार० वी० राव के शब्दों में हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए. "श्रम उत्पादन का साधन ही नहीं है बल्कि साध्य भी है आर्थिक विकासवर्धन के नाव व उतावनेपन ये हम श्रम को साधन के रूप में ही देखने हैं " मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता हमको मनुष्य को मशीन नहीं बनाना है बल्कि विकास का सक्षय श्रम का जीवन स्तर ऊँचा करता है .

'We cannot let our desire for economic growth make a machine of a man, even though we should within the limits set by human and spiritual values, strive to adopt and use the human factor for getting out of the rut of economic stagnation on to the road of economic growth.'

II. मजदूरी नीति व विकास

1. न्यूनतम मजदूरी को निर्धारण व कार्यान्वित करना चाहिए

अर्थ : कम-विकसित देशों में उचित मजदूरी नीति के बिना विकास की कोई सम्भावना नहीं है. इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम इन देशों में 'न्यूनतम' मजदूरी की स्थापना होना चाहिए.

"न्यूनतम" मजदूरी से हमारा आशय मजदूरी की उस कानूनी न्यूनतम सीमा से जिसे कम कोई उत्पादनकर्ता नहीं दे सकता. हर क्षेत्र के लिए तथा हर उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग होती है.

निर्धारित करने वाले तत्व : कम-विकसित देशों में 'न्यूनतम' मजदूरी को निर्धारित करने समय बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिये सर्वप्रथम उद्योग की मजदूरी देने की क्षमता ध्यान में रखना चाहिए बहुत ऊँची मजदूरी निर्धारित करने से कम कुशल उत्पादनकर्ता व्यापार में नहीं रह सकेंगे और बहुत नीचे न्यून-

See also : (1) Ishrat Hussain : op. cit. ch. VI on The Labour Force & Population.

(2) V. K R. V. Rao : op. cit. ch. 7. The Human Factor in Economic Growth.

तम मजदूरी में श्रम का कोई लाभ नहीं होगा। किसी "प्रतिनिधि फर्म" की मजदूरी देने की क्षमता को ध्यान में रख कर यह मजदूरी निर्धारित की जा सकती है। दूसरे, 'न्यूनतम' मजदूरी निर्धारित करते समय अन्य उद्योगों की न्यूनतम का भी निर्धारण करना चाहिए।

तीसरे, 'न्यूनतम' मजदूरी को living wage या अच्छे जीवनयापन के लिए पर्याप्त मजदूरी के बराबर होना चाहिए। यह जीवन स्तर इतना होना चाहिए कि मजदूर इज्जत से जीवन यापन कर सके। यह इतनी मजदूरी है जो श्रमिक को अच्छा खाना, रहने, पहनने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ट्रेनिंग की सामान्य सुविधाएँ प्राप्त करा सके इसका अर्थ बहुत उच्च स्तर से नहीं है।

न्यूनतम मजदूरी व उत्पादकता, रोजगार, भूम्य लाभ व विकास पर प्रभाव : कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि कम विकसित देशों में न्यूनतम मजदूरी सबंधी नियमों को कार्यान्वित करने से उत्पादन-कर्ताओं के लाभ कम होंगे और इससे उत्पादन व रोजगार कम होगा। इसीलिए विकास के लिए मजदूरी दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करना चाहिए।

यह विचारधारा सर्वथा भ्रमात्मक है। न्यूनतम मजदूरी नियमों के अनुसार मजदूरी देने से श्रमिकों की कार्य करने की शक्ति व इच्छा बढ़ती है, उत्पादनकर्ता भी मेहनत से काम कर सकते हैं। अगर न्यूनतम मजदूरी के देने से श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है तो मूल्यों का बढ़ना भी आवश्यक नहीं है। न्यूनतम मजदूरी देने से देश में माँग की वृद्धि होती है और इससे उत्पादनकर्ताओं को और अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है।

न्यूनतम मजदूरी देने में अगर उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती तो उत्पादनकर्ताओं के लाभ घट जाएंगे और अगर उत्पादकता में वृद्धि होती है तो लाभ पूर्ववत् रह सकते हैं और लाभ बढ़ भी सकते हैं। अगर कुछ उत्पादनकर्ताओं को हानि भी होती है तो उनके हटने से कोई बुराई न होगी उनका उत्पादन दूसरे उत्पादनकर्ता अपने हाथ में ले सकते हैं।

वस्तुस्थिति : आज कम विकसित देशों में वस्तुस्थिति यह है कि न्यूनतम मजदूरी नियम तो लगभग सब देशों में बना दिए गए हैं परन्तु उनका पालन बहुत कम होता है। भारत में ही 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का लक्ष्य 1950 तक समस्त उद्योगों के लिए नियम बनाने का था, परन्तु 1961 तक यह कार्य पूरा न हो सका और अन्त में समय सोमा ही हटा दी गई। कम-विकसित देशों में मजदूरी की अशिक्षा व अज्ञानता के कारण मजदूर अपनी बेरोजगारी

की मजदूरी के कारण कम ले लेते हैं। निरीक्षकों का कार्य अत्यन्त घसतीपजनक रहता है।

देश में मजदूर को विकास में योगदान योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम देश में न्यूनतम मजदूरी को स्थापित करना होगा

2. मजदूरी स्तर का Standardization या स्तरोन्मयन का प्रभावीकरण होना चाहिए.

मजदूरी की एक दर नहीं होती बल्कि दरें होती हैं उचित मजदूरी प्रणाली का प्रमुख गुण यह होना चाहिए कि मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरों में जो अन्तर वे प्राथिक व सामाजिक दृष्टिकोण से न्यायोचित हों. कम विकसित देशों में यह अंतर बहुत अधिक है एक ही शहर एक ही उद्योग की इकाइयों में मजदूरी कम व अधिक हो सकती है

इसलिए आवश्यक यह है कि इन दरों को न्यायोचित किया जाए. सारे कार्यों व सारे उद्योगों या उनकी इकाइयों के विभिन्न विभागों की मजदूरी की दरें कम व अधिक अवश्य रहेंगी अन्यथा कुशल व अकुशल में अन्तर नहीं रहेगा. परंतु बहुधा यह अन्तर कुशलता व योग्यता पर आधारित होने के स्थान पर किसी अन्य कारण (जैसे श्रमसंधों के कार्य) से स्थापित हो सकती है. इनको घटा देना चाहिए. समान योग्यता के व्यक्तियों को समान आय व असमान योग्यता के व्यक्ति को असमान आय मिलना चाहिए. पूर्ण समानता सम्भव नहीं होती. इस में भी पूर्ण समानता नहीं है. मजदूरी में समानता ही देश में विकास का सक्षय नहीं होना चाहिए. उससे अधिक तो महत्वपूर्ण रोजगार में वृद्धि व उनकी कुशलता में वृद्धि करना अधिक महत्वपूर्ण होगा आज के युग में centripetal (समानता की

References on Minimum wages :

- (i) I. L. O. "Problems of Wage Policy in Asian Countries" p 92-7.
- (ii) Dr. R. Singh : Movement of Industrial Wages in India, ch. II, III
- (iii) Indian Journal of labour Economics Jan. 1959.
- (iv) G. Anderson, Fixation of Wages p. 187.
- (v) R. A. Lester . Economics of Labour & Industrial and Labour relations.

माँग) तथा centrifugal (असमानता की माँग) दोनों प्रवृत्तियाँ साथ चलती हैं। वही पर श्रमिक समानता चाहते हैं वही असमानताएँ बढ़वाना चाहते हैं।

मजदूरी के स्तरनियमन के लिए कार्य करने से कम-विकसित देशों में प्रयत्न आवश्यक है इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मजदूर एक Standard wage ही कमायेगा, केवल standard rate ही निर्धारित किया जाता है, इस कार्य से कार्य क्षमता बढ़ती है, मजदूरी स्तर में न्याय का समावेश होता है, औद्योगिक शान्ति की स्थापना होती है, उन्नत तकनीक अपनाई जासकती है पहले क्षेत्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण होना चाहिए बाद में देश में इसे करना चाहिए।

3 विकास के नाम पर वास्तविक मजदूरी नहीं गिराना चाहिए : *

बहुधा यह सलाह दी जाती है कि विकास के लिए मूल्यों को बढ़ने देना चाहिए और मजदूरी स्तर को वहीं रहना चाहिए इससे उत्पादनकर्ता लाभ कमाएँगे और, और अधिक पूँजी निर्माण करेंगे।

परन्तु पूँजीनिर्माण के नाम पर तथा मुद्रा स्फीति को नियन्त्रण में रखने के लिए इनको मजदूरों को भुक्तमरी के स्तर पर नहीं बाँध देना चाहिए, अन्यथा यह गरीब लोग अपने खाने पीने की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएँगे

References :

1. J T. Dunlop "The Test of contemporary Wage Theory" in the Theory of Wage Determination Ed by the same author.
2. A. M. Ross "External Wage structure" in New concepts of Wage determination.
3. F. R Fairchild, Furniss, Buck, Economics p. 407-8.
4. Dr. R. Singh op. cit. p. 63.
5. J. R Hicks, Economic Foundations of Wage Policy, Economic Journal, Sept 1955.
6. A. D. Gupta, "Skill differentials and Wage Policy." Indian Journal of Labour Economics.
7. E. R. Livernash. "Internal Wage Structure" in New concept of wage Determination.
8. I. L. O. wages General Report v.
9. Dobb. Wages.
10. Rothschild : Theory of Wages.

* इस सम्बन्ध में पूँजी निर्माण का अध्याय देखिए

तत्सम्बन्धित सन्दर्भ (references) भी वहाँ देखिए

भारत में 1964 तक मजदूरी की वास्तविक मजदूरी 1939 के स्तर पर ही रही कम विकसित देशों में विकास का मूल्य गरीबों को ही क्यों चुकाने को कहा जाए ? आज के युग में सामाजिक व राजनैतिक जागरूकता इतनी अधिक है कि समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इस में ऐसा किया जा सका था परन्तु वहाँ तो राज्य का अकुश था आज के युग में ब्याज व लाभ कमाने वालों को भाय बैसे ही अधिक है और फिर मजदूरी और कम कर दें तो अन्याय के मिश्रण और क्या होगा ? अगर इन गैर-मजदूरी भाय को कम न किया जाएगा तो मजदूरी को कम करना बहुत गलत होगा

कम-विकसित देशों में अधिक मजदूरी से ही मुद्रा स्फीति नहीं फैलती मुद्रा स्फीति के बहुत से कारण हैं जैसे फ्रिजूल सचॉ राजकोपीय नीति, कर सभाने की शर्मीली नीति, कर लगाने व इकट्ठा करने वाला अट प्रशासन, एकाधिकारी उत्पादनकर्ता मूल्य बढ़ा देने हैं. देश में मूल्य वृद्धि के अन्य कारण हैं : अधिक लाभ लेना, साख प्रसार, सट्टों में वृद्धि, काला बाजारी, जमाखोरी, अकुशल उत्पादनकर्ता, प्राकृतिक कारणों से कच्चे माल की कमी मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं

इस प्रकार से मजदूरी का मुद्रा स्फीति में योगदान इतना नहीं होता भारत में ही औद्योगिक श्रम राष्ट्रीय श्रम का केवल 2% ही होता है, फैक्ट्री मजदूरी राष्ट्रीय भाय का 2 से 3% भाग ही होती है तथा मजदूरी कुल लागत का 3% से 20% तक ही भाग होती है

दीर्घकाल में मजदूर सघ इस नीति को स्वीकार नहीं करेंगे. कम-विकसित देशों में बहुत से क्षेत्रों में उत्पादनकर्ता अनधिक लाभ कमाते रहते हैं अगर मजदूरी बढ़ाने के लिए इन लाभों को कम कर दिया जाए तो रोजगार कम भी नहीं होगा. निम्न-लिखित परिस्थितियों में मजदूरी वृद्धि से रोजगार कम नहीं होगा

- (i) अगर मजदूरी वृद्धि मूल्य वृद्धि के बाद हुई है तो इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी
- (ii) अगर पूँजी की गतिशीलता नहीं है अर्थात् दूसरे स्थान को नहीं ले जाई जा सकती, तो मजदूरी बढ़ने से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी
- (iii) अगर देश में भाँग वृद्धि के कारण और उद्योगों का विकास हो रहा हो तो मजदूरी वृद्धि से बेरोजगारी नहीं फैलेगी
- (iv) मजदूरी वृद्धि से अगर मजदूरों की शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग में सुधार होना है तो उनकी उत्पादकता वृद्धि से लागत कम होगी और बेरोजगारी नहीं फैलेगी क्योंकि कम मूल्य के कारण माँग में वृद्धि होगी.

- (v) अगर वस्तु की माँग वेलोचदार है तो मजदूरी बढ़ने से भी माँग में कमी नहीं आएगी और बेरोजगारी नहीं फैलेगी.
- (vi) जब मजदूरी कुल लागत का बहुत कम भाग होती है तो मजदूरी बढ़ने से लागत पर प्रभाव नगण्य होगा और बेरोजगारी नहीं फैलेगी.
- (vii) अगर श्रम आन्दोलन देश व्यापी है तो उत्पादनकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने उत्पादनकार्य को नहीं ले जा सकते हैं और इससे स्थानीय बेरोजगारी नहीं पैदा सकती.

इन सब विश्लेषण का अर्थ यह नहीं है कि मजदूरी को उत्पादकता से अधिक बढ़ने दिया जाए. आवश्यकता इस बात की है कि मजदूरी तो बढ़े परन्तु श्रमिक उत्पादकता बढ़ाएँ.

4 मजदूरी को मुद्रा स्फीति का एंजिन नहीं बनने देना चाहिए.

कम-विकसित देशों में जहाँ मजदूरों को न्याय देना है तथा जहाँ उनका राष्ट्रीय आय में हिस्सा वृद्धि करना है वहाँ यह भी आवश्यक है कि यह हिस्सा बड़ी हुई राष्ट्रीय आय में से ही आना चाहिए. श्रम नेताओं को यह देखना चाहिए कि उनकी "सामूहिक सौदा" नीति Collective bargaining policy विवेकपूर्ण व जिम्मेदार नीति है आज के युग में श्रम व उत्पादनकर्ताओं को एक दूसरे का दृष्टिकोण समझकर कार्य करना चाहिए सामूहिक सौदागिरी करने वालों को यह देखना है कि देश में उत्पादन, उत्पादकता, मालिकों के लाभ को बढ़ते रहना चाहिए. उनका हिस्सा भी इसी अधिक आय में से आएगा, अन्यथा ऐसी मुद्रा स्फीति फैल सकती है जो विकास की राह में रोड़ा बनकर रह जाएगी. आज के युग में सततवन्दी व हड़ताल विलासिता है और इस विलासिता को अपनाता विकास के लिए सबसे अधिक घातक होगा

इस सम्बन्ध में मजदूरी नीति को Anti-inflationary policies मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति का सहायक होना चाहिए, जैसा अगर मुद्रा स्फीति फैलने का डर हो तो मजदूरों को अपनी मजदूरी का कुछ भाग deferred payments या देर से भुगतान (जैसे प्रावीडेन्ट फंड) के रूप में ले लेना चाहिए.

5. प्रेरणादायक मजदूरी प्रणाली अपनाना चाहिए.

कम-विकसित देशों में मजदूरी को प्रेरणादायक रूप में देना चाहिए (Incentive wages should be established) कार्यानुसार मजदूरी पद्धति से श्रमिक की उत्पादकता भी बढ़ती है और उसकी आय भी अधिक हो जाती है. इस प्रकार से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है यह कार्यानुसार मजदूरी भी किसी प्रेरणा-

दायक योजना पर आधारित होना चाहिए, अर्थात् जैसे-जैसे श्रमिक का कार्य व उत्पादकता अधिक हो जैसे-जैसे उन्हें अधिक दर से मजदूरी दी जाए सोवियत युनियन में Stakhanovist स्ताखनोविस्त ग्रान्दोलन ने वहाँ उत्पादकता वृद्धि के नये से नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। भारत में भी श्रमवीर की उपाधि उसीसे मिलनी जुलती नीति है परन्तु उसकी व्यापकता कम है तथा अभी इस ग्रान्दोलन को क्रान्तिकारी ढंग से नहीं लिया जाता है।

साम में से श्रमिकों को हिस्सा देने से भी (Bonus or profit sharing) श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी। श्रमिकों को फिर नैतिक और कानूनी अधिकार भी हैं इन सब न्ययों को हमें मागत के रूप में ही नहीं देखना है बल्कि यह तो 'मानव-साधन' में विनियोजन है, क्योंकि अधिक उत्पादकता ही विकास की कुञ्जी है।

6 देश में सामूहिक सौदेबाजी (Collective bargaining) प्रथा को बढ़ावा देना चाहिए और जहाँ तक हो सके विकेन्द्रित मजदूरी नीति होना चाहिए।

कम-विकसित देशों में सदियों से मजदूरी निर्धारण उत्पादनकर्ताओं के हाथ में रहा है कम-विकसित देशों में इन प्रकार मजदूरी बहुत ही निम्न स्तर पर निर्धारित होती रही, मजदूर केवल दया की भाँज में मालिकों के अल्लाह कुछ नहीं कर सकते थे। कालान्तर में राज्य ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। उधर श्रम ग्रान्दोलन के विकास के साथ-साथ सामूहिक सौदेबाजी भी विकसित होने लगी। कम-विकसित देशों में अगर आर्थिक स्वतन्त्रता कायम रखना है तो सामूहिक सौदेबाजी को विकसित करना आवश्यक है। बहुधा सामूहिक सौदेबाजी असफल हो जाती है तो राज्य मजदूरी निर्धारण Tripartite Boards द्वारा निर्धारित कराता है। भारत के वर्तमान (निबन्ध का समय 17-5-1969) कार्य बाह्य राष्ट्रपति श्री ज़्ही० ज़्ही० मिरी, जो स्वयं प्रसिद्ध श्रमनेता रहे हैं, इस प्रकार की मूल्य निर्धारण पद्धति को उचित नहीं मानते। उनके शब्दों में

“मजदूरी बोर्ड समन्वित उद्योगों में बेकार होते हैं और वे श्रम व मालिकों के अच्छे संबंधों में बाधा ही बनते हैं। इन बोर्डों के निर्णय को पसन्ना कानूनी बाध्यता होती है और इसीलिए ये दोनों पार्टियों को पसन्द नहीं आते इन बोर्डों से श्रम एवम्ता को घटका लगता है, श्रम-मणों में विश्वास घटता है क्योंकि उनके मामलों में तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप होता है”

इसलिए यह आवश्यक है कि कम-विकसित देशों में सामूहिक सौदेबाजी को विकसित किया जाए। कम-विकसित देशों में श्रम-संघों को “कम्प्युनिस्ट एजेंट” ही

नहीं मानना चाहिए। श्रम-मण्डों को राजनीति के बजाय श्रमिकों के हित के मामले में ही ध्यान रखना चाहिए।

सामूहिक सौदेबाजी शक्ति संचय होती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करता है। दोनों पक्ष असहमत होने पर समझौता कर सकते हैं। फिर वे तालाबन्दी व हड़ताल से एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश करते हैं। वे देखते हैं कि दूसरे पक्ष की शर्तें मानना सस्ता है अथवा हड़ताल या तालाबन्दी की स्थिति का सामना करना सस्ता है। सामूहिक सौदेबाजी में धोखा तथा सद्भावना दोनों प्रयोग में आते हैं तथा आर्थिक तत्वों के साथ सामाजिक, राजनैतिक मनो-वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक तत्वों का भी समावेश होना चाहिए।

अगर सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित किया जाता है तो मालिकों व मजदूरों में परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे। मजदूर लोग महंगाई बढ़ने पर, मालिकों के लाभ बढ़ने पर, अन्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा अधिक मजदूरी देने पर, तथा मजदूरों की उत्पादकता बढ़ने पर प्रकाश डालते हैं जबकि मालिक इस बात पर जोर देते हैं कि इससे लागत बढ़ जाएगी। अगर देश में सामूहिक सौदेबाजी

References :

1. Barbara Wootton : Social foundations of wage Policy.
2. A. M. Ross : Trade Union & wage Policy.
3. S. A. Palekar : Problems of wage policy for Economic development.
4. Chamberlin : Labour.
5. J. T. Dunlop : Wage Determination under Trade unions
6. Bowen . wage price issue.
7. Chamberlin : Trade Unions-Economic Analysis of Labour Union-Powers.
8. P. Ford : Economics of collective Bargaining.
9. Giri : Labour Problems in Indian Industries, P. 505.
10. W. H. Hutt : The Theory of Collective Bargaining.
- 11-12. Marshall : Principles of Economics, Book VI, ch. III-V.
Economics of Industry, Book VI, ch. IV.
13. Lindblom : Unions and capitalism. p. 35.
14. S. H. Slichter : The Challenge of Industrial Relations.
15. A. M. Ross : The Trade Unions as wage-Fixing Institutions; The Dynamics of wage Determination under Collective Bargaining; Union Policies and Industrial Management.

की प्रथा को उन्नत किया जाए तो श्रम-सघो के महयोग से उत्पादकता बढ़ सकती है जहाँ जहाँ श्रम-मय सक्रिय रहे हैं वहाँ मानिको को अच्छी मशीनें लगानी पड़ी है, अच्छा कच्चा माल प्रयोग करना पड़ा तथा उत्पादकता बढ़ानी पड़ी. इसीमे विकास होता है.

7. देश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होना चाहिए :

कम-विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के दौर लगने पर मुआवजा, मृत्यु होने पर मुआवजा, बीमारी का इलाज, प्रावीडेंट फंड व पेंशन, मातृत्व के समय छुट्टी व इलाज आदि की आवश्यकता तो विकसित देशों से भी अधिक है. कम-विकसित देशों में बहुत से मजदूरों का जीवन स्तर अत्यन्त हीन होता है और वे थोड़ी सी असुरक्षा सहन नहीं कर सकते परन्तु आज की स्थिति हम कम-विकसित देशों में विकसित देशों की भाँति सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते. 1958 में जर्मनी में प्रति व्यक्ति 191 U. S. डॉलर के बराबर, यू. एन. ए. में 175 डॉलर के बराबर, तथा आस्ट्रेलिया में 131 U. S. डॉलर के बराबर सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान की गईं. इतनी तो बहुत से कम-विकसित देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी नहीं होती

साधनों की कमी से इतनी सुविधाएँ प्रदान न की जा सकें तो भी इन सुविधाओं का शुभारम्भ आवश्यक होगा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, भूमि सुधार, मूल्य नियन्त्रण, अधिक रोजगार, शिक्षा का प्रसार यह सर्वोत्तम सामाजिक सुरक्षा होगी.

Wage guarantees कम-विकसित देशों में थोड़ी बहुत मात्रा में "मजदूरी की जमानतदारी" भी दी जानी चाहिए, अर्थात् अगर मजदूर का कोई दोष हुए वगैर किसी कारण वश उसे हटाना पड़े या कुछ समय के लिए कार्य बन्द करता पड़े तो उत्पादनकर्ताओं को मजदूरी का भाग मिलते रहना चाहिए. इससे श्रमिकों के जीवन स्तर की सुरक्षा रहेगी और उनकी उत्पादकता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा मालिक भी उत्पादन में पड़े अवरोधों को शीघ्रातिशय हटाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार की व्यवस्था से देश में औद्योगिक शान्ति भी रहेगी तथा मजदूरों की आय नहीं गिरेगी व असमानताएँ नहीं बढ़ेंगी इसमें देश में उपभोक्ता माँग भी स्थिर रहती है तथा विनियोजन में भी स्थिरता आती है.

कम-विकसित देशों में धीरे-धीरे उन सुविधाओं के विस्तार से उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि अवश्य होगी और यह बात विकास में सहायक होगी.

कम-विकसित देशों में दो प्रकार की मजदूरी नीति अपनाई जा सकती है. एक **Centralized wage policy** केन्द्रीय नियन्त्रित मजदूरी नीति तथा दूसरी,

decentralized wage policy अर्थात् विकेन्द्रित मजदूरी नीति। कम-विकसित देशों में श्रम आन्दोलन इतना विकसित या संगठित नहीं पाया जाता कि केन्द्रीय नियंत्रित मजदूरी नीति अपनाई जा सकें। इसके अतिरिक्त अगर कम-विकसित देश Capitalist or mixed economy पूँजीवादी या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाता है तो पूर्ण रूप से केन्द्रीय संचालित श्रम नीति स्वतन्त्रता व लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ है। हर देश में क्षेत्रीय अन्तर होते हैं और एक ही नीति सम्भव नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हर उद्योग व उद्योग की इकाइयों की स्थिति भी भिन्न-भिन्न होती है। स्वयं श्रम संघ इस नीति को पसन्द नहीं करते क्योंकि इससे उनकी स्वतन्त्रता का हनन होता है और श्रम आन्दोलन सान्नाशाही के अन्तर्गत आ जाता है।

कम-विकसित देशों में कुछ मौलिक सिद्धान्त बना लेना चाहिए (Some contours of basic principles) और फिर परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। राज्य को तो सिर्फ सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करके मजबूत करना चाहिए और देश में औद्योगिक झगड़ों को निपटाने वाली एक ही व्यवस्था होना चाहिए।

8. मजदूरी नीति को रोजगार व उत्पादकता वृद्धि योजनाओं से समन्वित होना चाहिए :

कोई भी मजदूरी नीति हर देश के लिए उपयुक्त नहीं होती और न एक ही देश के लिए हर समय के लिए उपयुक्त होती है। मजदूरी नीति ऐसी होना चाहिए जो :

- (1) पूँजी निर्माण में बाधक न बनें।
- (II) उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो, तथा
- (III) विनियोजन व रोजगार वृद्धि में सहायक हो।

मजदूरी नीति स्वयं में विकास उत्पन्न नहीं कर सकती इसके लिए मौद्रिक, राजकोपीय, मूल्य तथा अन्य नीतियाँ भी सहायक होना चाहिए। मजदूरी नीति को उनसे समन्वित होना चाहिए।

कालान्तर में हर चीज की सीमा होती है। इसी प्रकार से किसी भी देश में परिस्थितियों के अनुसार optimum wage या अनुकूलतम मजदूरी स्तर होता है। हमको इसे साँपना नहीं चाहिए।

अध्याय 4

उत्पादकता तथा विकास

Productivity and Economic Growth

- I उत्पादकता का अर्थ
- II उत्पादकता माप
- III उत्पादकता वृद्धि का महत्व उत्पादकता व विकास
- IV कम-विकसित देशों में उत्पादकता
- V उत्पादकता वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व

यह अध्याय मुख्यतः लेखक की पुस्तक *Economics of Wages Productivity and Employment* के अध्याय 2, 8, 9 व 10 पर आधारित है अन्य references दिए हुए हैं

अध्याय : 4

उत्पादकता तथा विकास

Productivity and Economic Growth

I उत्पादकता का अर्थ

अधिक उत्पादकता का अर्थ होता है कि उतनी ही मात्रा के साधनों से अधिक या और अच्छा उत्पादन होता है या उतनी ही मात्रा का उत्पादन कम साधनों से उत्पन्न होता है अधिक उत्पादकता का अर्थ होता है कि अधिकाधिक उत्पादन को पैदा करने के लिए पूँजी, कच्चा माल मेहनत या कार्य क बड़े अपेक्षाकृत कम लगते हैं उत्पादकता वृद्धि के वातावरण में साधारण घटनाक्रम तोड़ दिया जाता है (routine is broken), नई उत्पादन मनोवृत्ति का जन्म होता है और अर्थ-व्यवस्था में प्रवैगिक गतिशीलता का संचार हो जाना है उत्पादकता का अर्थ होता है कि उत्पादन में कार्य क्षमता बड़ी है और उत्पादन में मितव्ययिता हुई है उत्पादकता को हम प्रति मशीन की इकाई की भौतिक उत्पादकता प्रति व्यक्ति उत्पादन, या प्रति अश्वशक्ति उत्पादन के रूप में व्यक्त करते हैं

“Productivity can be expressed as the physical output per unit of horse power raised, per unit of Capital equipment operated, per unit of materials consumed, or per unit of labour employed it is expressed as ratio of output to resources expended, as overall effectiveness of a productive unit, as ratio of output to the corresponding input of labour or production per man-hour”

II. उत्पादकता नापने की विधियाँ

उत्पादकता को नापना सरल कार्य नहीं है उत्पादन बहुत सी लागतों (inputs) तथा उत्पादन के व्ययों का सामूहिक परिणाम होता है और किस व्यय या लागत

के कारण कितना उत्पादन हुआ यह बताना सरल नहीं होता। सामान्यतः उत्पादकता श्रम की उत्पादकता के रूप में व्यक्त की जाती है

श्रम के रूप में उत्पादकता नापना :

परम्परानुसार उत्पादकता श्रम की इकाईयों की उत्पादकता के रूप में नापी जाती है। शायद इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य inputs लागतों की प्रपेक्षा श्रम का समय आसानी से नापा जाता है और श्रम घटे तो हर उत्पादित वस्तु में निहित होते हैं कुल उत्पादन को कुल कार्य घंटों से भाग देने पर प्रति श्रम घंटा उत्पादन निकल आता है श्रम की उत्पादकता इस प्रकार से नाप सकते हैं

$$R = \frac{O}{LH}$$

R=Ratio . O=output in volume,

H=No of hours LH=Total available labour Hours

श्रम उत्पादकता को हम "प्रति व्यक्ति उत्पादकता" या "प्रति श्रम घंटा उत्पादकता" के रूप में नापते हैं मुख्यतः हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए "प्रति श्रम घंटा" उत्पादकता ही नापते हैं

यद्यपि उत्पादकता "प्रति श्रम घंटा" ही अधिक नापी जाती है परन्तु यह प्रणाली दोष रहित नहीं है उत्पादकता श्रम के अतिरिक्त पूँजी, संगठनकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञों सभी के सहयोग से बढ़ती है और केवल श्रम-घंटे के रूप में ही हम उसे नहीं नाप सकते। इसी प्रकार से अगर खराब कच्चे माल, अथवा किसी भी तकनीकी अवरोध के कारण उत्पादकता गिरती है तो इसका अर्थ यह तो नहीं होगा कि श्रम की कार्य क्षमता घट गई है

Select references

1. M M Mehta, Measurement of Industrial Productivity.
2. M B Shah, M P. Chronicle, May 30, 1960
3. K. V. Ramana, Indian Journal of Economics July 1953, Vol, XXXIV, No. 132, P. 87.
4. R A Lester, Industrial & Labour Relations p 78
5. P. Mazumdar, Indian Journal of labour Economics, vol III. No. 61, Jan 61.
6. Vohar Sangha . Productivity

इसके अतिरिक्त कई व्यक्ति जैसे कानूनी सलाहकार, बर्नर, तेल देने वाला व्यक्ति आदि की उत्पादकता नापी नहीं जा सकती।

मशीन की उत्पादकता के रूप में उत्पादकता नापना :

जिन उद्योगों या उत्पादन कार्यों में मशीनीकरण अधिक हो उनकी उत्पादकता, स्वभावतः मशीन की इकाई की उत्पादकता के रूप में नापी जाना चाहिए, तब उत्पादकता इस प्रकार से नापी जाएगी।

$$R = \frac{O}{MH}$$

R = ratio, O = output in Volume, MH = Machine hour

यह प्रणाली भी दोषपूर्ण है क्योंकि समस्त उत्पादन वृद्धि या कमी मशीनों के कारण नहीं होती। बहुधा उन्ही मशीनों पर कार्य करते रहने पर उत्पादकता बढ़ती घटती रहती है।

व्यय से उत्पादकता नापना :

Measurement in terms of monetary value of the output or the corrected monetary Value of the output.

उत्पादकता नापने का सर्वोत्तम तरीका उसे राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में नापना चाहिए हम समस्त लागतों के द्राव्यिक मूल्य के आधार पर उत्पादकता नाप सकते हैं इस प्रकार से उत्पादकता को हम 'उत्पादन-लागत अनुपात' के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या तो इसे हम Cost per unit प्रति वस्तु लागत से नाप सकते हैं या लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में नाप सकते हैं।

एक और तरीका Connected monetary Value of output के रूप में उत्पादकता नापने का होता है इसके अनुसार उत्पादकता भौतिक रूप में नहीं नापी जाती बरन् मूल्यों के परिवर्तनों के अनुसार उत्पादकता को मापा जाता है। सही उत्पादकता नाप के लिए हमको एक से अधिक तरीके से नापकर उत्पादकता माप के परिणामों को अध्ययन करना चाहिए।

III. उत्पादकता व विकास : उत्पादकता का महत्व :

उत्पादकता से केवल अर्थशास्त्रियों का ही संबंध नहीं होता है बरन् इससे देश के मजदूर, उत्पादनकर्ता, आयोजनकर्ता तथा राज्य सभी का सम्बन्ध रहता है। हर

ऐसे देश में जहाँ खाना पान की कमी हो, जहाँ साधनों की कमी हो तथा जहाँ विनियोजन व रोजगार में वृद्धि करना हो वहाँ उत्पादकता वृद्धि सर्व प्रथम आवश्यक होती है। जीवन स्तर को उसी स्तर पर कायम रखने तथा वृद्धि करने के लिए उत्पादनता वृद्धि आवश्यक है। उत्पादनता वृद्धि के आकड़ों से ही हमें विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन करने का मार्ग दर्शन मिलता है।

विनियोजन तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्या आयोजन उत्पादनता वृद्धि की मान्यताओं व सम्भावनाओं पर आधारित होती है। उत्पादनता वृद्धि का सर्व सामान्य में कमी होती है। इसलिए इससे आम की मात्रा, मात्र तथा प्रति व्यक्ति मात्र प्रभावित होती है।

उत्पादनता के अनुमान तथा आकड़े अर्थ व्यवस्था के Temporal Changes (दो समयों के बीच के परिवर्तन या व्यापार क्षीय परिवर्तनों), Spatial (अर्थात् दो स्थानों के बीच परिवर्तनों) तथा Cross-Sectional Changes (दो उद्योगों के बीच परिवर्तनों) का मूल्यांकन करने में सहायता देने हैं। उत्पादनता के अनुमान के आधार पर ही भिन्न-भिन्न उद्योगों का चयन, उनके स्थानीय करण करने का प्रश्न, उनके विकास का आयोजन, तथा उनका संचालन का प्रकार निश्चित किया जाता है।

उत्पादनता समूहों का अध्ययन में माँग परिवर्तनों के अध्ययन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इन आँकड़ों को हम उन्नत तकनीक का रोजगार पर परिवर्तन का प्रभाव अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं। और फिर देश के लिए उपयुक्त तकनीक का चयन कर सकते हैं। इन्हीं आँकड़ों के अध्ययन से हम विनियोजन, उत्पादन, रोजगार व राष्ट्रीय धाम पर मौद्रिक व राजकोषीय नीति आदि का प्रभाव अध्ययन कर सकते हैं। उत्पादनता आँकड़ों से हम rationalisation (या तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन का विवेकीकरण करना) के प्रभाव अध्ययन कर सकते हैं।

जैसे क्रिकेट खेल में कहावत है "A run saved is a run made" उसी तरह उत्पादन क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि उत्पादनता वृद्धि से जो साधनों की बचत होती है वह आम बजट के बराबर ही होती है। उदाहरणतया अगर किसी देश ने 15000 करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय है और आयोजन के कारण 5% उत्पादनता बढ़ती है तो 750 करोड़ की अतिरिक्त आय का सृजन होता है। राज्य की योजना कार्यान्वित करने में अगर उत्पादनता वृद्धि होती है तो या तो उसको

कम कर लेने से काम चल जाएगा या फिर वह उतनी मात्रा में अधिक कार्य कर सकता है.

अधिक उत्पादकता के लिए हमको साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना पड़ेगा और इसी से देश में राष्ट्रीय आय व कल्याण बढ़ सकता है अधिक उत्पादकता से अधिक लाभ होता है, अधिक वचन हो सकती है, अधिक मात्रा में विनियोजन योग्य पूंजी का निर्माण होता है और इस प्रकार से अधिक उत्पादकता विकास की कुंजी है.

अधिक उत्पादकता की आवश्यकता कई कारणों से उत्पन्न होती है. औद्योगीकरण की योजना के कारण देश में भारी उद्योगों में अधिक विनियोजन है और इससे उपभोग वस्तुओं की कमी पड़ जाती है इस कारण आय तो बढ़ जाती है परन्तु उसी मात्रा में वस्तुओं के न बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है मूल्यों के बढ़ने से कच्चे माल तथा अन्य लागतों पर खर्च बढ़ने से और मूल्य वृद्धि होती है और हो सकता है कि इससे पूंजी निर्माण हतोत्साहित हो क्योंकि खर्च कम हो जाती है इसलिए सन्तुलित, स्थाई व निरन्तर विकास के लिए उत्पादकता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक होती है. M Bertrand de Fourcnel des Ursin (यह एक ही व्यक्ति है) ने मन व्यक्त किया है कि कम-विकसित देश उत्पादन वृद्धि को अधिक मानें अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए पूंजी गहन तकनीक अपनाई जाती है और इससे बेरोजगारी फैलती है इसलिए पहला महत्व उत्पादन वृद्धि पर होना चाहिए और फिर उत्पादकता वृद्धि पर होना चाहिए.

IV कम-विकसित देश व उत्पादकता :

कम-विकसित देशों में उत्पादकता कम है. इसमें तो कोई संशय नहीं है परन्तु तुलना के लिए विरवास योग्य आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं इन देशों में उत्पादकता बहुत कम है और इन देशों के मजदूर विकसित देशों के मजदूरों की तुलना में बहुत अधिक समय उतनी ही मात्रा में वस्तु पैदा करने के लिए लेते हैं निम्नलिखित तालिका से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं

See also : (1) "Wages and Productivity in Indian Industry."
P. Y. Chinchankar, Commerce Annual Number 1968

(2) "Prosperity through Higher Productivity-certain basic issues and Practical difficulties." Naval H Tata, Commerce Annual Number 1965

देश	हर टन पैदा करने के लिए थम घटे		हर शिफ्ट में उत्पादित टनो में
	शक्कर	सीमेंट	कोयला
फिलीपाइन्स	16 83
हवाई	4 64
लाउइसियाना	7 87
युरट्रिको	5 10
भारत	83 04	10 18	0 51
फ्रान्स	...	1.60	...
जर्मनी	.	2.20	2.00
बेल्जियम		1 51	...
यू० के		1.82	1 84
यू० एम० ए०		1 50	15.00
जापान		1.75	...

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय मजदूर हवाई के मजदूर के मुकाबले में एक टन शक्कर बनाने में 16 गुना अधिक समय लेता है, तथा सीमेंट बनाने में यू० एम० ए० के मजदूर से 10 गुना अधिक समय लेता है, या कोयले के उत्पादन में भारतीय मजदूर की उत्पादकता केवल $\frac{1}{10}$ है यह जल्द है कि उन देशों में उन्नत तकनीक, मशीनों तथा अन्य कारणों से उत्पादकता अधिक है फिर भी मजदूर की भी कम उत्पादकता में बहुत जिम्मेदारी है।

भारत¹ में 1946 से 1952 के बीच समस्त उद्योगों की उत्पादकता निर्देशांक 100 से गिरकर 92 आ गया अर्थात् उत्पादकता 1.56 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से घट गई तथात्वात् उत्पादकता बढ़ी और 1964 में यह निर्देशांक 157 था. अर्थात् 1946-1964 के 19 वर्षों में उत्पादकता 57% बढ़ी यानी प्रतिवर्ष $\frac{3}{5} = 3.00$ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी

Eastern Economist के अनुसार² 1939-1959 साल में संगठित उद्योगों में उत्पादकता केवल 1% प्रतिवर्ष से बढ़ी.

G. F. : Ch 13. J. Pajestka : अध्याय के अन्तिम पृष्ठ पर reference है.

Ref : Nawal H. Tata : op. cit.

1. Cf : P. Y. Chinchankar : op. cit.

2. Eastern Economist Annual Number 1961.

यह उत्पादकता वृद्धि अधिक नहीं थी क्योंकि विकास को शुरू के काल में उत्पादकता वृद्धि की अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं

U S S. R में शुरू के काल में वही अधिक उत्पादकता वृद्धि हुई थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है

वर्ष	उत्पादकता वृद्धि
1900-1913	3.1% प्रतिवर्ष
1928-1955	7.5% ,,
1950-1958	7.2% ,,

कम-विकसित देशों में उत्पादकता कम होने के कारण पता लगाना कठिन नहीं है :

1. सर्वप्रथम इन देशों में मशीनें पुरानी व पिछड़े किस्म की होती हैं बहुधा उन्नत देशों द्वारा हटाई गई पुरानी मशीनें खरीद ली जाती हैं.
2. इन देशों में धमिक शारीरिक रूप से कमजोर तथा अप्रशिक्षित व तकनीक ज्ञान में पिछड़े होते हैं निम्नजीवनस्तर के कारण वे बीमार रहते हैं, जिससे उनकी गैरहाजिरियाँ अधिक रहती हैं. वे जल्दी थक जाते हैं और उनमें अधिक कार्य करने की शक्ति, रुचि व योग्यता का अभाव रहता है.
3. इन देशों में संचालित छोटे बड़े उद्योग अनुबूलतम आकार के नहीं होते. कुछ उद्योग इतने छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं कि उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों को उपलब्ध आन्तरिक व बाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त नहीं होती अथवा कुछ बड़े उद्योग बहुत Unwieldy भारी या स्थूल होते हैं.
4. इन देशों में कुशल व उम्माहो साहसियों की कमी है. बहुत से प्रशासक भी कर्मण्य व दक्ष नहीं होते. ये अपने हर काम पुराने ढंग व ढर्रे से चलाते रहते हैं.
5. पूँजी की कमी से (जो स्वयं कम उत्पादकता, कम राष्ट्रीय आय, कम प्रति व्यक्ति आय व कम बचतों के कारण होती है) देश में पूँजीगत विनियोजन कम होता है जिसके कारण उत्पादन के तौर तरीके पुराने होते हैं और उत्पादकता कम होती है
6. इन देशों में नव प्रवर्तनों की कमी रहती है और विदेशी की तकनीक को नकल करते हैं चाहे वैसी स्थितियाँ इन देशों में उपलब्ध हों या नहीं.
7. इन देशों में बाजार विस्तृत नहीं होते. यातायात साधनों का पिछड़ापन, गरीबी तथा अज्ञानता व पिछड़ेपन के कारण माँग की व्यापकता कम होती है.

इस कारण उत्पादकता भी कम रहती है इन देशों में वगैरह विके सामान तथा अन्तः आवश्यकताओं की विगोचाभासी स्थिति मौजूद रहती है

8. इन देशों में मजदूरी कम होने से श्रमिकों का जीवनस्तर कम रहता है और इस कारण उनकी योग्यता व शक्ति तथा कार्य करने की इच्छा कम रहती है
9. कम-विकसित देशों में श्रममध भी उत्पादकता वृद्धि में सहायक नहीं होते भारत की National Productivity Council के भूतपूर्व अध्यक्ष डा पी० एस० लोहानाथन के अनुसार भारत के प्रमुख श्रम संघ 'Indian National Trade Union Congress' ने 1966 में उत्पादकता वर्ष के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहयोग नहीं दिया
10. उन देशों में जो बेरोजगारी की अधिकता है उससे भी उत्पादकता कम रहती है रोजगार वृद्धि से सामाजिक उत्पादकता बढ़ती है देश की आय बढ़ती है तथा परिवारों की आय बढ़ती है इसके फलस्वरूप ग्राम जनता के शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर ऊँचे उठते हैं और पूर्ति बढ़ाने की क्षमता बड़ जाती है दूसरी ओर सामाजिक आय बढ़ने से देश में प्रभावशील माँग बढ़ती है और उत्पात्ति की मात्रा में वृद्धि से बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त होते हैं जिन देशों में पूर्ण रोजगार व्यवस्था होती है, वहाँ पर श्रमिक मशीनीकरण के विरोधी भी नहीं होते और फिर तकनीकी उन्नति होती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है
- 11 मजदूरी स्तर के नीचे होने, प्रेरणादायक मजदूरी प्रणाली के न होने, लाभ में भागीदारी की उचित व्यवस्था न होने तथा श्रम को सस्ती वस्तु के रूप में प्रमोद करने की प्रवृत्तियाँ इन देशों में उत्पादकता को नीचे स्तर पर ले जाती है
- 12 इन देशों में उत्पादकता कम होने के अन्य कारण इस प्रकार हैं
 - (i) उत्पादकता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आन्दोलनों की सर्वथा कमी है.
 - (ii) इन देशों में उत्पादकता वृद्धि सबंधी अनुसंधानों की सर्वथा कमी है
 - (iii) उत्पादकता वृद्धि के लिए समन्वित योजना, जिसके अन्तर्गत यातायात सबंधी प्राथमिकताएँ तक निर्धारित की जाती हैं, का सर्वथा अभाव रहता है
 - (iv) मृत्यों के सच्चावचन भी उत्पादकता सबंधी दीर्घकालीन आयोजन को सम्भव नहीं बनाने.

V. उत्पादकता वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व :

कम-विकसित देशों में उत्पादकता वृद्धि के लिए मजदूर, उत्पादनकर्ता, संगठनकर्ता, वैज्ञानिक, राज्य तथा अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से ही सम्भव होगा लेखक के दृष्टिकोण से इसके लिए सबसे मुख्य बातें देश में :

- (1) पूँजी निर्माण बढ़ाना.
- (II) मजदूरों की मजदूरी को प्रेरणादायक बनाना.
- (III) देश में पूर्ण रोजगार की नीति अपनायाना चाहिए.
- (IV) तकनीकी उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए.
- (V) उद्योगों का आकार अनुकूलतम रखना चाहिए.
- (VI) संगठन आधुनिक रूप में करना चाहिए, आदि.

हम इनको विस्तृत रूप में अध्ययन करें

1 मजदूरी को प्रेरणादायक बनाया जाए :

आज के युग में कम विकसित देशों में कम मजदूरी, कम उत्पादकता, तथा कम-उत्पादकता और कम मजदूरी का दुष्परिणाम है. प्रश्न यह है कि मजदूरी पहले बढ़ाई जाए अथवा पहले उत्पादकता बढ़े और तदुपरान्त मजदूरी बढ़ाई जाए. लेखक का मत है कि पहले मजदूरी स्तर में उन्नति करना चाहिए. मोरोप व अमेरिका में उत्पादकता वृद्धि का कारण वहाँ श्रमिकों को प्रेरणादायक मजदूरी देना रहा है. एशिया में श्रम सन्तुष्ट है इसलिए यहाँ पर उद्योगीकरण अधिक नहीं हुआ. स्वयं यू.एस.ए. में दक्षिण में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि के कारण वहाँ पर मशीनीकरण कम है और उत्पादकता भी कम है अधिक मजदूरी देने से

- (1) श्रमिकों के खाने पीने के स्तर से उसकी शक्ति बढ़ती है, भावी श्रम पौडिया स्वस्थ होती है
- (II) उचित शिक्षा व ट्रेनिंग पा सकते हैं
- (III) श्रमिकों की फिर रुढ़ीवादिता, भाग्यवादिता, आत्मसम्मान होता है
- (IV) उसकी गतिशीलता बढ़ती है वह दूसरे कार्य कर सकता है.
- (V) शिक्षित श्रमिकों के होने से मजबूत तथा अच्छे श्रम-संघों का विकास होता है.
- (VI) उन्नत तकनीक को अपनाकर कार्य कर सकते हैं तथा बाजार के विस्तार से भी उत्पादकता वृद्धि होती है

इस पर पूरा अध्याय लिखा गया है

परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि मजदूरी का प्रेरणादायक बनाया जाए तथा कार्यानुसार दिया जाए मजदूरी के अन्तर भी तर्कयुक्त होना चाहिए।

J. P. Davison, P. Sargant Florence, Barbara Gray and N. S. Ross के अनुसार

“प्रेरणादायक मजदूरी देने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति वस्तु लागत घटती है, सिरोपरि लागतों का प्रति वस्तु भार कम हो जाता है, कम ओवरहाडम की आवश्यकता रहती है, कार्य सन्तुष्टि बढ़ती है।”

Stansfield ने तो न्यूटन के मॉडल पर Socio-Psychological Motion का नियम बनाया है कि

“Every person continues in his state of rest, or of uniform work in a straight line, unless he is compelled by impressed incentives to change his state.”

इसलिए मजदूरी व्यवस्था के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए।

2. पूर्ण रोजगार की नीति अपनायी जाए :

कम-विकसित देशों में रोजगार के प्रति पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में प्रथम योजना के अन्त में 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार, चतुर्थ योजना के अन्त तक इसकी संख्या बढ़कर 160 लाख से ऊपर हो जाने की सम्भावना है। इस कारण कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि *rationalization* नीतियों के कारण वह नौकरी से निकले। इसलिए श्रमिक उत्पादकता वृद्धि नीतियों के विपक्ष में हो जाते हैं। कम-विकसित देशों में पूर्ण रोजगार प्रदान करने के द्वारे में असमर्थता व्यक्त की जाती है परन्तु राज्य सत्र व्यक्तियों को नौकरी नहीं दे सकता पर रोजगार के अवसर तो प्रदान कर सकता है।

3 तकनीकी उन्नति :

तकनीकी उन्नति का अर्थ यह नहीं है कि कम विकसित देश एकदम उन्नत देशों की तकनीक अपना सकते हैं। इसका अर्थ है कि अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार वे तकनीक अपनाएँ और उसमें ब्योचित परिवर्तन करने रहें।

4. धम संघों को सहायता देना चाहिए

धम संघ औद्योगिक शान्ति बनाये रखने, उत्पादकता बढ़ाने की प्रेरणा देने व जिम्मेदारी सिखाने, तकनीकी व्यवस्था को अपनाने में सहायता देने आदि कार्यों से उत्पादकता वृद्धि में सहायता कर सकते हैं।

5. संगठन :

उत्तम संगठन, उत्पादन इकाई का अनुकूलतम आकार, कार्य करने व रहने की उत्तम व्यवस्था, अच्छे कच्चे मात का प्रयोग, मशीनों को अच्छी तरह से चलाना व रखना, उचित बजट कंट्रोल, better layout उद्योग का उचित स्थापन, उचित खरीद व बेच नीति तथा उत्तम प्रशासन उत्पादकता वृद्धि के लिए परम आवश्यक है।

6. राज्य की अन्य नीतियाँ :

उत्पादकता वृद्धि के लिए सस्ती साख व्यवस्था तथा उचित ऋण व्यवस्था जिसमें विनियोजन की प्रोत्साहन मिले आवश्यक होगी।



Other references —

Angus Maddison .

1. Facts and Observations on labour Productivity in Western Europe, North America & Japan
2. Walter Galenson & John R. Erikson Industrial Labour Productivity in North Western Countries.
3. J. Pajestka . Stages of Industrialization & Labour Productivity.
4. Strigeto Tsuru . Technology and Productivity.
5. W. E. G. Salter Productivity Growth and Accumulation as historical processes.
6. Reynolds . Wages and Productivity.
7. S. Carlson Contribution of management to productivity.
8. H. A. Turner . The Contribution of workers to productivity.
9. John T. Dunlop : Evaluation of factors affecting Productivity
10. Participants . Internation Economic Association
Cf: Problems in Economic Development, Ed. E. A. G. Robinson, Melvin Redder, V. K. & V. Rao, Gyorgy Cukor, E. I. Kapustin, Giovanni Lasorsa, D. J. Delivanis, Edvard Muirz, Elihort Berg Subbiah Kannappan, Gosta Rehn, J. H. Davis, J. P. Carter, John Kendrick, Pierre Gonad, Felix Trappaniers, Carl Knollinger, Kjell Eide, R. Ulavic, Huber Sainmount, G. A. Prudensky, Zofia Morecka, Adolf Sturumthal, K. F. Walker etc.

अध्याय : 5

विकास व मौद्रिक नीति

Growth And Monetary Policy

भाग 1

- I. मौद्रिक नीति का अर्थ .
- II विकसित देशों में स्थिरता व विकास के लिए नीति :
 - (a) आन्तरिक मूल्य में स्थिरता का लक्ष्य.
 - (b) विनिमय दर स्थिरता का लक्ष्य.
 - (c) तटस्थ मुद्रा नीति.
 - (d) विकास के लिए मौद्रिक नीति.
- III. विकसित देशों में मौद्रिक नीति की सीमाएँ .
- IV. मौद्रिक व राजकोषीय नीति.

भाग 2

- I विकास के लिए मौद्रिक नीति के आवश्यक तत्व :
 - (i) मौद्रिक नीति से सस्वागत बचतें बढ़ना चाहिए.
 - (ii) मौद्रिक नीति को पूंजी निर्माण में सहायक होना चाहिए. मुद्रा नीति व पूंजी निर्माण.
 - (iii) देश में साक्ष का सामाजिकरण व प्रजातान्त्रीयकरण होना चाहिए.
 - (iv) केन्द्रीय बैंकिंग की कला का विकास आवश्यक.
 - (v) विदेशी विनिमय पद्धति में स्थायित्व.
 - (vi) दीर्घकालीन विनियोजन को प्रोत्साहन.
 - (vii) मौद्रिक नीति को सन्तुलित होना चाहिए.
- II मौद्रिक नीति की सीमाएँ

अध्याय : 5

विकास व मौद्रिक नीति

Growth And Monetary Policy

भाग 1

I मौद्रिक नीति का अर्थ

मौद्रिक नीति ¹ के अन्तर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जो राज्य या केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा चलन या साख, मुद्रा चलन (Close Money Substitute or Near Monies) प्रभावित करने के लिए करता है मौद्रिक नीति के अन्तर्गत, बैंक दर में परिवर्तन करना खुले बाजार की नीति के अन्तर्गत प्रतिभूतियों को खरीदना व बेचना, व्यापारिक बैंकों की न्यूनतम नगद विधि को बदलना, धनवा सात नियन्त्रण करना आदि सब कार्य आते हैं

मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मुद्रा व साख का नियमन व नियन्त्रण किया जाता है K. E Boulding 'मौद्रिक नीति' के स्थान पर "वित्तीय नीति" कहना पसन्द करते हैं उनका विचार है कि "मौद्रिक नीति" के अन्तर्गत बैंक ऋणों का निम्न हम साख नहीं वह सबत उनका नियन्त्रण आता है जबकि "वित्तीय नीति" के अन्तर्गत बैंकों व बीमा कम्पनियों के नियन्त्रण का कार्य आता है केन्द्रीय बैंक के संचालन का कार्य तथा मुद्रा बाजार का नियन्त्रण भी इसी नीति के अन्तर्गत आते हैं

परन्तु प्राग्ग समस्त अर्थशास्त्री "मौद्रिक नीति" शब्द ही प्रयोग में लाते हैं और उनका आशय इस नीति से वही होता है जो कि बोल्डिंग "वित्तीय नीति" से मानते हैं

पुराने अर्थशास्त्रियों का मौद्रिक नीति की अस्थिरता दूर करने के लिए अपनाए जाने में अत्यधिक विश्वास था वे मानते थे कि जब कभी भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है मौद्रिक नीति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके स्थिति

1. Allen, Buchanan and Colberg - "Prices, Income & Public Policy." p. 221.

पर नियंत्रण किया जा सकता है, परन्तु स्वर्णमान के टूटने और 1930 की महान् मंदी के बाद मुद्रा नीति से राजस्व नीति का महत्व अधिक बढ़ गया लेकिन हाब के वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने मौद्रिक नीति के महत्व को पुन स्वीकार करना शुरू कर दिया है

II मौद्रिक नीति और विकसित देश . स्थायित्व या विकास ?

विकसित देशों के सम्बन्ध में मौद्रिक नीति के चार मुख्य उद्देश्य बताये जाते हैं कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि विकसित देशों में मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य देश में मान्यतापूर्ण मूल्यों में स्थिरता माना है ¹ कुछ अन्य अर्थशास्त्री विदेशी विनिमय स्थायित्व को मौद्रिक नीति का मुख्य भग मानते हैं ² कुछ अन्य अर्थशास्त्री "तटस्थ मौद्रिक नीति" की सिफारिश करते हैं, जबकि बहुत से अन्य अर्थशास्त्री यह चाहते हैं कि विकसित देशों में भी मौद्रिक नीति का लक्ष्य देश में विकास बढ़ाना है. हम इन नीतियों के आँचिस्व को जाँचें

(a) क्या मौद्रिक नीति का लक्ष्य आन्तरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व लाना है ?

1930 के वर्षों की महान् मंदी के बाद केन्स ने मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य नियंत्रण पर बहुत जोर दिया Crowther (क्रउथर) तथा Gustav Cassel (गुस्टव कैसेल) भी इसी मत के थे. इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि जनत देश राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों से पीड़ित रहते हैं "सदी के काल" में उत्पादनकर्ता व व्यापारी हानि उठाने हैं इन दिनों में बेरोजगारी फैलती है, राष्ट्रीय आय गिरती है विनियोजन कम होते हैं, बैंक फेल होते हैं तथा मजदूरी दर गिरती है लेजी के काल में, इसके विपरीत निश्चित आय व मजदूरी पाने वालों को मूल्य वृद्धि के कारण वास्तविक आय में कमी उठानी पड़ती है इन दिनों में विनियोजन महंगा पड़ जाता है ऐसे काल में आर्थिक जगत में जो लेजी, घाटावाद और फोरा माता है वह अत्यन्तविक व दुर्निम होता है मुद्रा स्थिति में स्वयं ही बरखादी के बीज बोने रहते हैं

इसके लिए यह आवश्यक है कि चक्र विरोधी मौद्रिक नीति अपनायी जाए.

1. K. E. Boulding : Principles of Economic Policy, Asia Publishing House 1962 p 210-11
2. A. G. Hart, Monetary Policy for Income Stabilization for a developing democracy. Ed. Max F. Millikan Yale 1953, p. 304.

मंदी के काल में बैंक दर घटा दी जानी चाहिए ताकि बैंक अधिकाधिक साख निर्माण कर सके राज्य को चाहिए (या केन्द्रीय बैंक को चाहिए) कि वह खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदे ताकि जनता या बैंकों के कोष बढ़ सकें और वे और अधिक साख निर्माण कर सकें इन दिनों में प्रवृत्त गुणात्मक साख नियंत्रण (Selective Credit Control) या चयनात्मक साख नियंत्रण या तो ढीला कर देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए

मुद्रा स्फीति काल में इनके विपरीत मौद्रिक नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए अर्थात् इन दिनों में बैंक दर बढ़ा दी जानी चाहिए, चयनात्मक नियंत्रण शुरू करना चाहिए, व्यापारिक बैंकों द्वारा जमा किए जाने वाली राशि परिवर्तनशील न्यूनतम निधि अनुपात बढ़ा दी जानी चाहिए और राज्य को खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचना चाहिए जिससे कि देश से फासतू मुद्रा चलन में से निकाली जा सके

आन्तरिक मूल्य स्तर को स्थिर रखने की इस मौद्रिक नीति का U S A. में प्रेसीडेंट एफ डी रूजवेल्ट की 'न्यू डील नीति' में भी समर्थन मिला था

आलोचना :

इस प्रकार की नीति को बहुत से अन्य अर्थशास्त्रियों से समर्थन प्राप्त नहीं है इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि मूल्य नियंत्रण नीति से साहसियों व उत्पादनकर्ताओं को लाभ नहीं होने जिससे पूँजी निर्माण रुकेगा इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि वास्तव में "वस्तुओं" के मूल्यों को स्थिर करने के स्थान पर 'उत्पादन के अंगों' के मूल्य स्थिर करना चाहिए. आन्तरिक मूल्य स्थिर करने के सम्बन्ध में सबसे मुख्य परेशानी तो यह रहती है कि किन वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखे जाएँ देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं के मूल्य तो स्थिर नहीं किए जा सकते हैं इसके प्रतिरिक्त लागत सम्बन्धी इतनी कठिनाइयाँ रहती हैं कि यह प्रश्न उठता है कि मूल्यों को किस स्तर पर स्थिर किया जाए इस सम्बन्ध में इसीलिए 1932 में Prof. Hayek ने कहा है

“हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले छै या आठ वर्षों से मौद्रिक नीति को हमने समस्त विश्व में स्थिरता लाने के समर्थकों की सलाह पर ढाला है. अब वक्त आ गया है कि हम इनके प्रभाव को, जिससे पर्याप्त हानि हो चुकी है, उतार फेंका जाए ”

(b) क्या मौद्रिक नीति का लक्ष्य विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाना होना चाहिए ?

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य विदेशी विनिमय में स्थिरता लाना होना चाहिए। यह नीति मुख्य रूप से उन देशों को अपनाना चाहिए, जो अपनी राष्ट्रीय आय का मुख्य भाग विदेशी व्यापार से प्राप्त करते हैं। यह नीति उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनमें बहुत सी विदेशी पूंजी लगी हो। इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि विदेशी विनिमय में अस्थिरता से विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा का सट्टा होने लगता है। अगर देश में विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता नहीं रहेगी तो विदेशी पूंजी का आना जाना इस प्रकार से लगा रहेगा कि देश को लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है, विदेशी विनिमय की अस्थिरता के कारण जनता की तरलता पसंदगी बढ जाती है और वे स्वयं संचय करने लगते हैं, जिसे वे बाद में "सुरक्षित मुद्रा" (Safe currency) में बदल लेते हैं।

इस नीति के समर्थक यह चाहते हैं कि जब विदेशों में मूल्यों में परिवर्तन हो तो अपने देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन करने के स्थान पर देश के आन्तरिक मूल्यों में परिवर्तन कर देना चाहिए।

हमने देखा था कि प्रथम नीति के प्रवर्तक (आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता के समर्थक) आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता और तदनुसार विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन चाहते थे, जबकि इस नीति के प्रवर्तक विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता और तदनुसार आन्तरिक मूल्यों में परिवर्तन के समर्थक हैं।

आज इस नीति के अधिकांश अर्थशास्त्री समर्थक नहीं हैं। फिर I.M.F. या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद यह कार्य अब मौद्रिक नीति का मुख्य प्रग नहीं रह गया है।

(c) क्या तटस्थ मौद्रिक नीति उपयुक्त होगी ?

विकस्टीड (Wicksteed) जे. सी. कूपमॉन्स (J. C. Koopmans), हाएक (Hayek) तथा डी. एच. गार्डर्सन चाहते हैं कि विकसित देश तटस्थ मौद्रिक नीति अपनाएं तो सर्वोत्तम होगा। इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि मौद्रिक नीति इस प्रकार की हो कि देश में आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें मुद्रा के माध्यम से विनिमय ऐसा हो, जो वास्तव में "वदला वदली" हो (The aim of the monetary policy should be to establish an economic system in which exchange may essentially be barter with the help of money))

तटस्थ मौद्रिक नीति का मुख्य ध्येय यह कि देश में मौद्रिक नीति का प्रयोग न तो मुद्रा स्फीति को उत्पन्न करना होना चाहिए और न ही मुद्रा विस्फीति उत्पन्न होने देना चाहिए.

यह सिद्धान्त वास्तव में “मुद्रा परिमाण” सिद्धान्त पर आधारित है और उस नीति की भाँति ही नुटिपूर्ण है. इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों का ख्याल है कि अगर मुद्रा की मात्रा निश्चित रखी जाए तो मूल्य स्तर भी उच्चावचन रहित रहेंगे. वास्तव में मूल्य परिवर्तन तो मुद्रा की स्वायी मात्रा पर भी होंगे. दीर्घकाल में तटस्थ मुद्रा नीति आर्थिक मदों का कारण बन जाती है. आज के युग में गतिशील या प्रवैगिक अर्थव्यवस्था में तटस्थ मौद्रिक नीति अनुपयुक्त रहेगी.

(d) विकसित देश और विकास प्रोत्साहित करने वाली मौद्रिक नीति :

Crowther ब्राउथर के अनुसार, मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य पूर्ण रोजगार व्यवस्था पर वचत व विनियोजन में समन्वय व साम्य स्थापित करना पड़ता है.

विकास के लिए तो वास्तव में वर्तमान वचतो से वर्तमान विनियोजन ज्यादा होना चाहिए. यह कार्य या तो साख या बैंकनिवेश या मुद्रा की चलन गति में वृद्धि करके किया जा सकता है. जमा की हुई (Hoarded) मुद्रा को निकालने का भी यही प्रभाव होता है. जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाए तो वचत व विनियोजन बराबर हो जाना चाहिए. इस स्थिति में अगर विनियोजन, वचतो से अधिक रहा तो देश की वास्तविक आय में तो कोई वृद्धि नहीं होगी, केवल मुद्रा स्फीति फैलेगी और अगर विनियोजन कम रहा तो देश में बेरोजगारी और मंदी फैलेगी.

मौद्रिक नीति अगर देश में पूर्ण रोजगार के स्तर पर मूल्य स्थिरता रखने में सफल होती है तो इसके विकास होगा. जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा की मात्रा में आवश्यकतानुसार वृद्धि से देश में मुद्रा-स्फीति भी नहीं होगी और देश में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के आयोजन में कोई अवरोध भी पैदा नहीं होगा.

III. विकसित देशों में विकास के लिए मौद्रिक नीति की सीमाएँ :

(a) मौद्रिक नीति ही विकसित देशों में न तो मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रख पाती है और न ही मुद्रा विस्फीति को दूर कर पाती है :

Alvin H. Hansen एल्विन हन्सन का मत है कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति अपयशहीन रहती है. आज जबकि मुद्रा परिमाण

सिद्धान्त को "ताक पर रख दिया गया है" फिर भी कभी-कभी यह देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि मूल्यों पर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। यह बात अर्ध-सत्य और वास्तविकता का सरलोकरण है।

हन्सन का मत है कि राजकोषीय नीति का प्रयोग इस अवधि में मौद्रिक नीति के प्रयोग से अधिक प्रभावशील और कम खतरनाक है मौद्रिक नीति से प्रभावशील माँग कम करना अत्यन्त कठिन होगा या तब ही हो सकता है जबकि 'ब्रेक' (Brakes) इतनी तेजी से लगाए जाएँ कि अर्थव्यवस्था भटके से स्थिर होकर गिर जाए, इसके लिए व्याज की दर को बहुत बढ़ाना होगा।

हन्सन ने सुन्दर शब्दों में कहा

"वे लोग, जो मौद्रिक नीति से मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने की बड़ा मुँह फैलाकर बात करते हैं यह भूल जाते हैं कि केवल मौद्रिक नीति से काम नहीं बन सकता और अगर वे उसे प्रभावशील बनाने के लिए सभ्य कदम उठाते हैं तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाकर गिर जाएगी (The economy will turn into rail spin)"

वे और कहते हैं

"किसी भी मोटे व्यक्ति का मोटापा दूर करने का सबसे सरल उपाय उसका भना घोटना ही है इतना सख्त कदम उठाने पर अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और इससे कम कदम उठाने पर यह नीति प्रभावहीन रहेगी" (It would be an easy matter to stop a man from becoming excessively corpulent simply by strangling him to death A sufficiently sharp curtailment of money supply could indeed quickly end an inflation. No one denies that. But a programme to stop an inflationary development merely by reducing the quantity of money is a dangerous device Moderately used, it courts the failure of ineffectiveness, pushed to the needed fanatical extremes, it courts disaster."

हन्सन की इस सम्बन्ध में अन्य आपत्तियाँ ये हैं

1. मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए साख नियंत्रण से छोटे विविधियों को हानि

होगी, बड़े विनियोजकों के पास तो अपने स्वयं का धन होता है, इससे सामाजिक अहित होगा।

- 2 देश में बैंक ही तो साख्त नहीं प्रदान करते, बैंकिंग कम्पनियाँ, निजी उधार देने वाली संस्थाएँ, तथा वित्तीय संस्थाएँ भी तो धन देती हैं इस संबंध में Radcliffe Committee का मत है कि मौद्रिक नीति प्रभावशील तभी हो सकती है जबकि इससे सम्पूर्ण देश की तरलता प्रभावित होती हो।
3. हन्सन ने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर उनका कथन है कि मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में मजदूरी नियंत्रण या राज्यकोपीय नीतियाँ अधिक प्रभावशील होती हैं।

(b) मौद्रिक नीति से मदी भी दूर नहीं होता।

Pro. Bach : प्रो. बाख का कथन है कि मौद्रिक नीति मदी दूर करने में प्रभावहीन रहती है। मौद्रिक नीति से अगर जो कुछ भी मुद्रा स्फीति नियंत्रण होता है उससे भी कम उसका प्रभाव मदी को दूर करने में होता है। किसी भी देश में केन्द्रीय बैंक बाजार में मुद्रा की बाढ़ ला सकता है परन्तु उसमें यह शक्ति नहीं होती कि वह बैंकों को उधार देने और विनियोजकों को उधार लेने पर मजबूर कर सके, उनके शब्दों में

“मौद्रिक नीति से मदी दूर करना उसना ही कठिन है जितना कि गैस निकाले फूटने को डोर दीसा करके ऊपर चढ़ाना होता है”

मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मदी दूर करने के लिए ब्याज की दर घटाते हैं, परन्तु (जैसा कि केन्स के मॉडल में देख चुके हैं) ब्याज की दर के घटाने से मदी दूर नहीं होती।

(c) मौद्रिक नीति के प्रभावशील होने में देर लगती है :

Milton Friedman मिल्टन फ्राइडमैन के अनुसार मौद्रिक नीति का प्रभाव देर से प्रकट होता है उन्होंने अनुमान लगाया है कि मौद्रिक परिवर्तन होने के कारण आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने में 16 से 20 महीने तक का समय लग जाता है

(d) मौद्रिक परिवर्तनों का मदी व तेजो के काल में पूरा प्रभाव इसलिए नहीं रहता कि मदी के काल में अगर M का संकुचन रोक भी दिया जाय तो V का

1. George Leland Bach, Economics : ch 14 : Monetary Policy p 256-9

2. Milton Friedman quoted from D II Singh op. cit p 265.

सकुचन नहीं एक पाता और उसी प्रकार से तेजी बाल में M को तो कम किया जा सकता है परन्तु V को कम नहीं किया जा सकता

(e) मौद्रिक नीतियाँ विकासवर्धन के लिए अपर्याप्त है :

प्राज के युग में मौद्रिक नीति की विकासवर्धन क्षमता अधिक नहीं मानी जाती इस सन्दर्भ में निम्नलिखित उद्धरण महत्वपूर्ण है, जो यह सम्मति जाहिर करते हैं कि मौद्रिक नीति विकास में महत्वपूर्ण नहीं है

Haberler : हेबरलर का कथन है

"भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के दीर्घकालीन भविष्य, उन देशों के व्यक्तियों के जीवन स्तर और देश की राष्ट्रीय आय की विकास दरे, मुख्य गैर-मौद्रिक कारणों से प्रभावित होती हैं ये तर्क हैं—धनुकूल भूमि-धन सन्ध, अच्छे प्राकृतिक साधन, देश की जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर, राजनैतिक व सामाजिक स्थिरता वचन की क्षमता, तथा उत्पादकता मौद्रिक नीतियाँ-विकास में बाधक के रूप में अधिक प्रभाव डाल सकती हैं, पर विकासवर्धन क्षमता उनही सीमित हैं उचित मौद्रिक नीति विकास में सहारा दे सकती है पर स्वयं विकास-कारक नहीं हो सकती "

K E Boulding के ई. बील्डिंगका मत भी हेबरलर जैसा है. उनके अनुसार "विकास के महत्वपूर्ण घटक परस्पर तथा दश की संस्कृति व मनो-वृत्ति से इतने अधिक सह-संबंधित हैं कि उनको अलग करना कठिन है इसी कारण हम यह कहने में असमर्थ रहते हैं कि विकास के लिए नियमित बैंकिंग पद्धति उत्तम है या वित्कुल स्वतंत्र पद्धति उप-युक्त है. या देश में आयोजित अर्थ-व्यवस्था उत्तम है या निर्वाचिकी अर्थव्यवस्था उत्तम है

वित्तीय व्यवस्था का कभी कार्य केवल साहसियों को सहायता देना है तो कभी उन्हें स्वयं साहसी बनना पड़ता है इसलिए हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि विकास के लिए निष्क्रिय परम्परागत बैंकिंग पद्धति होना चाहिए या चपल सहस्रपूर्ण पद्धति होना चाहिए

1. Haberler : Monetary factors affecting economic stability, in International American Association's "Stability & progress in the world's economy" Ed. by D. C Hague pp 151-207.
2. Boulding . op cit : p 222

(Whether a conservative banking system is preferable to an active entrepreneurially minded banking system).”

Back वास्तव के शब्दों में

“आर्थिक विकास बहुत सी बातों पर निर्भर होता है और मुख्यतः वह विनियोजन की दर पर निर्भर है. अगर मौद्रिक नीति से विनियोजन प्रोत्साहित होता है तो विकास होगा और अगर विनियोजन हतोत्साहित होता है तो विकास स्केमा कम व्याज की दर से विकास में सहायता मिलती है क्योंकि हमने विनियोजन और रोजगार में वृद्धि होती है अगर किसी देश में रोजगारों के वृद्धि की पवृति हो तो कम व्याज की दर निश्चित ही समृद्धि तथा विकास में सहायक होने है. अगर देश में पहले ही पूर्ण रोजगार है तो व्याज की दर को गिराने में केवल मुद्रा स्फीति फैलती है महंगाई फिर विकास का मूल्य (दंड) बन जाती है और अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति में व्याज की दर अधिक रखी जाए तो विकास रुक जाता है ... There is the danger of too much or too little in monetary policy ”

IV विकास और मौद्रिक व राजकोपीय नीति

दोनों ही मौद्रिक व राजकोपीय नीतियाँ एक दूसरे की पूरक हैं, परन्तु विकास वर्धक नीति के रूप में राजकोपीय नीति का मौद्रिक नीति के मुकाबले में अधिक प्रभाव पड़ता है मुद्रा स्फीति के दिनों में हम या तो कर बढ़ा सकते हैं (जिससे व्यय कम हो) या हम व्याज की दर को बढ़ा सकते हैं व्यवहार में कर बढ़ाने के प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण पाए गए हैं मंदी के काल में भी व्याज की दर के घटाने से सार्वजनिक व्यय बढ़ाने व कर घटाने की नीतियाँ अधिक महत्वपूर्ण पाई गई हैं. फिर भी वास्तव में दोनों नीतियाँ को एक साथ कार्यान्वित करने के अधिक प्रभाव होते हैं.

मीयर तथा बाल्डविन, बेन्जामिन हिगिन्स, एलन, बुखानन, कोलवर्ज, बोरिडग, हेवरनर सब ही यह मानते हैं कि जब तक कि राजकोपीय नीति और मजदूरी नीति का मौद्रिक नीति से समन्वय नहीं होता तब तक मौद्रिक नीति प्रभावशील नहीं हो सकती मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण है परन्तु एलन, बुखानन तथा कोलवर्ज का कथन है :

“सफल मौद्रिक नीति कुछ नियमों पर आधारित है, एक आधुनिक मौद्रिक नीति को बनाने में कठिनाई यह है कि उसके नियमों पर सहमति नहीं है और मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करने में कठिनाई यह है कि लोग तत्सम्बन्धित नियमों का पालन नहीं करते हैं।”

इन सबका अर्थ यह नहीं है कि मौद्रिक नीति त्रिकुल महत्वहीन है

प्रो. बेन्जामिन हिगिन्स के अनुसार

“जहाँ राजनैतिक धारणों से उचित राजस्व नीति नहीं प्रपनाई जा सकती, वहाँ मौद्रिक नीति सफल हो सकती है”

Hansen का भी कथन है :

“In conjunction with fiscal and other policies, monetary policy can play a significant role in helping to bring the economy through more stable conditions”

भाग 2

I. कम-विकसित देशों के विकास के लिए मौद्रिक नीति की विशेषताएँ

कम-विकसित देश व्यापार चक्रों से पीड़ित नहीं होने बरन् वे तो चिक्वाप्पीन पिछड़ेपन से पीड़ित रहते हैं। इसलिए इन देशों में मौद्रिक नीति का लक्ष्य केवल आर्थिक स्थायित्व बनना ही नहीं होता बरन् विकास को प्रोत्साहन देना होता है। इसलिए कम-विकसित देशों में मौद्रिक नीति को निम्नलिखित तथ्यों की पूर्ति करना चाहिए।

1. देश में बचतों को प्रोत्साहन : बचतों को संस्थागत किया जाना चाहिए :

कम-विकसित देशों में बचतें तो कम हैं ही, साथ ही इन बचतों का अधिकांश भाग लोग अपने ही पास रखते हैं या फिर सोने, चाँदी एवं जमीन खरीदने में लगा देते हैं। एक दृष्टिकोण से इस प्रकार से बचत करना व्यक्तिगत हित के लिए ठीक है। इस प्रकार उनकी बचतों का वास्तविक मूल्य मुद्रा स्थिति के काल में भी नहीं गिरता, बल्कि बढ़ता है। पर इस प्रकार की बचतों में समाज को लाभ नहीं होता, इन्हीं बचतों को जब बैंकों, बीमा कंपनियों व राज्य के अणु पत्रों में

सगाया जाए तो देश में इन वस्तुओं की पूर्ण निर्माण के काम में लागे जा सकता है। इसलिए कम-विकसित देशों में इन सस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ व छूट देकर इन वस्तुओं का सस्थापित कराना चाहिए। इसके लिए यह देखना आवश्यक होगा कि जनता का धन सुरक्षित रहता है, केन्द्रीय बैंक को यह देखना चाहिए कि देश की मौद्रिक समस्याएँ फेल हो नहीं होतीं। भारत में जो जमा बीमा योजना (इसके अन्तर्गत बैंक, बीमा निस्त चुकाते हैं और प्रत्येक बैंक 'फेल' हो जाए तो जो जमा करनेवालों को धन बीमा कम्पनी देती है,) है वैसे हर कम-विकसित देश में होना चाहिए।

2. मौद्रिक नीति को पूर्ण निर्माण में सहायक होना चाहिए। क्या इसके लिए मुद्रा स्फीति की नीति आवश्यक है ?

जैसा कि हम सब जानते हैं कि कम-विकसित देशों में जनता राज्य से हर कार्य की अपेक्षा करती है वह अच्छी सड़कें, स्कूल, कलेज, अस्पताल आदि चाहती है परन्तु उतनी मात्रा में साधन राज्य के हाथों में, करो व ऋणा के माध्यम से, नहीं देती। परिणाम यह होता है कि राज्य को केन्द्रीय बैंक से उधार लेकर मुद्रा स्फीति के द्वारा पूर्ण निर्माण करना व कराना पड़ता है।

हुमसेन, कास्टार तथा हेमिस्टन आदि अर्थशास्त्रों इस प्रकार की मौद्रिक नीति चाहते हैं जिससे होनार्वप्रबन्धन करके देश में थोड़ी मुद्रा स्फीति फैलाकर, उत्पादनकर्ताओं को लाभ पहुँचाकर, पूर्ण निर्माण किया जाए, इनका कथन है कि बाद में जब उत्पादन बढ़ने लगेगा तो मूल्य फिर गिर जायेंगे, पर पूर्ण निर्माण से देश उन्नति की राह पर चल निकलेगा वे पूर्ण निर्माण के लिए *Mild inflation* (थोड़ी मुद्रा स्फीति) चाहते हैं और उनका विचार है कि इस प्रकार की स्फीति *Self-Liquidating* (स्वयं समाप्त होने वाली) होगी।

इस प्रकार की नीति की बहुत आलोचना की जाती है मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार हैं।

(i) इससे देश की गरीबी पर बहुत भार पड़ेगा और आर्थिक उन्नति से रुढ़े लाभ के स्थान पर हानि होगी।

(ii) अन्न-मिन्न देशों ने जो यह नीति अपनाई थी, उनके अन्न-मिन्न वारण थे, जैसे इंग्लैंड अपने अधीनस्थ देशों से सस्ता कच्चा माल व

खाद्य-सामग्री प्राप्त कर लेता था। इस में सरकारी अकुश था तथा अमेरिका में उस समय विदेशी पूँजी काफी मात्रा में प्राप्त थी।

- (iii) मुद्रा स्फीति से, एरिक लिन्डहॉल Eric Lindhall के अनुसार, एक ओर तो ऋण लेने वाले अधिक ऋण लेते हैं क्योंकि उन्हें बाद में जब ऋण वापस करना पड़ता है तो उसका वास्तविक मूल्य कम होता है और दूसरी ओर देशवासी अपने धन को सोना चांदी व जमीन के खरीदने में लगाकर और मुद्रा स्फीति बढ़ा देते हैं।
- (iv) इसके अतिरिक्त प्राचाय पी सी. मलहोत्रा के शब्दों में, "Mild inflation is like small pregnancy" अर्थात् थोड़ी मुद्रा स्फीति "थोड़े में गर्भावस्था" की भाँति है—अर्थात् वह तो पूर्ण रूप से निवसित होगी ही।
- (v) मुद्रा स्फीति से निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित होंगे, जिससे भुगतान की स्थिति और बिगड़ेगी।
- (vi) मुद्रा स्फीति में राज्य के भी व्यय बढ़ जाते हैं और राज्य को अधिक कर लगाने पड़ेंगे या और मुद्रा स्फीति बढ़ेगी।

David Felix डेविड फेलिक्स ने भी इसी प्रकार कहा है

"स्वैन में पिछले 200 वर्षों में मूल्य वृद्धि के काल में लाभ वृद्धि बहुत कम रही है। फ्रान्स में लाभ वृद्धि मूल्य वृद्धि के बगैर होती रही। इंग्लैंड में कम लाभ स्फीति के साथ-साथ ही आर्थिक उन्नति हुई है। इस प्रकार से मुद्रा के कारण लाभ स्फीति होना और आर्थिक उन्नति होना आवश्यक नहीं है।"

मोघर तथा माल्टाबिन भी इस नीति के विपक्ष में हैं उनका कथन है

"लाभ वृद्धि पर आधारित मुद्रा स्फीति से बचते या तो बढ़ती ही नहीं है या फिर बहुत कम बढ़ती है और अगर हम मुद्रा स्फीति के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि यह रीति सर्वथा

अन्य आँकड़ों के लिए पूँजी निर्माण सचची अध्याय देखिए।

Principal P. C. Malhotra : A remark in seminar on "Price Mechanism and Development" at Bhopal, in May 1967.

David Felix, Price Inflation & Industrial Growth, the Historic Record & Contemporary Analogies. The Quarterly Journal of Economics, August, 1956, P 444.

गलत व अवाछनीय है. बहुत से देशों के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि केवल साख वृद्धि से ही विनियोजन नहीं बढ़ जाता है. शायद मुद्रा स्फीति के न होने से ज्यादा विनियोजन हो सकता है."

Haberler हेबरलर भी इसी प्रकार से कहते हैं -

"दीर्घकाल में मुद्रा स्फीति से विकास रुक जाती है हमारे युग में मुद्रा स्फीति से पूंजी निर्माण का बहुत ही अधिक दुस्प्रयोग हुआ है और यह दुस्प्रयोग विशेषतया कम-विकसित देशों में अधिक हुआ है."

जी. एम बर्नस्टीन तथा आई. जी. एटेल ने इसीलिए यह विचार व्यक्त किया है कि मुद्रा स्फीति के दुष्परिणाम अधिक होते हैं. उन्होंने कहा है -

"गहन विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि निरन्तर मूल्य वृद्धि का उत्तरदायित्व गलत मौद्रिक नीति पर डाल सकते हैं. मुद्रा स्फीति मौद्रिक घटना है (Phenomenon) और मौद्रिक नियंत्रण से ही दूर की जा सकती है"

उपरोक्त कथन के सबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है. कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि मूल्य वृद्धि के कुछ 'वास्तविक कारण' होते हैं (जैसे वस्तुओं की कमी) (Inflation is a real 'Phenomenon'. Such economists are known as structuralists.) इन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन व पूंति का बेलोचदार होना है. मौद्रिक व राजस्व नीतियाँ तो मूल्य वृद्धि में केवल सहायक हो सकती हैं.

मूल्य वृद्धि का कारण कुछ भी हो, मूल्य वृद्धि व विकास में कोई निश्चित सबंध नहीं होता. जैसे

- (1) भारत व लका में काफी समय से मूल्य स्थिरता रही पर उन दिनों में आर्थिक उन्नति कम हो रही. जबकि,
- (11) जर्मनी में मूल्यों की स्थिरता के साथ आर्थिक उन्नति हुई.
- (111) मेक्सिको, ब्राजील व टर्की में मूल्य वृद्धि के होते हुए भी आर्थिक उन्नति हुई. तथा,

1. Meier & Baldwin : Economic Development. Asia 1962 p 401
2. Haberler : op cit. (as in this chapter).
3. G. M Bernstien & G. M Patel : Inflation in Relation to Economic Development' International monetary fund staff Papers, Vol II No. 3 Nov. 1952 p. 363-98.

(iv) चिली, इन्डोनेशिया, बोलिविया व अर्जेन्टाइना में मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक उन्नति नहीं हुई.

निष्कर्ष :

इस संबंध में हम इतना ही कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि इसके प्रयोग से मुद्रा स्फीति के वगैरह पूर्ण निर्माण होना चाहिए. मुद्रा स्फीति के साथ न तो विकास सुनिश्चित है और न ही असंभव है. केन्द्रीय मौद्रिक संस्थाओं का मुख्य कर्तव्य यह है कि वे देश में व्यक्तियों या संस्थाओं का सम्पर्क स्थापित करें, मियर व बान्डविन का कथन है :

‘देश में मुद्रा पूर्ति उम अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में देश में जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो तथा जिस अनुपात में अमुद्रा क्षेत्र में (From non-monetized sector मुद्रा क्षेत्र में (monetized) साधनों का हस्तान्तरण किया जाता है.”

Kindleberger ने इसीलिए कहा है -

“हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मौद्रिक नीति के माध्यम से हम विकास की शाही सड़क पर पहुँच सकते हैं. विवेक से कार्य करने पर सहायता अथवा मिलती है.”

3. देश में साख का “सामाजीकरण व प्रजातान्त्रीयकरण” करना चाहिए :

इन देशों में यह आवश्यक है कि बैंकों द्वारा साख निर्माण का लाभ छोटे व्यापारी, किसान, उद्योगपति व उपभोक्ताओं को भी पहुँचना चाहिए जैसा कि प्रो. बोर्लिंग का मत है. कम-विकसित देशों में किसान व छोटे व्यापारी “ऋण की गुलामी” (Debt slavery) से पीड़ित हैं और यह अन्यायपूर्ण है. अगर साख का लाभ सबको प्राप्त हो सके तो इससे साख का “सामाजीकरण व प्रजातान्त्रीयकरण” होगा (The Government through democratization of credit can bring about deproletarianization of the masses, through its monetary policy.)

पर इस नीति में एक बुराई भी उत्पन्न हो सकती है. अगर साख का “प्रजातान्त्रीयकरण” बहुत अधिक हो जाए तो ऐसे लोग भी उधार ले सकते हैं जो बाद में ऋण चुकाने योग्य न हों, इसलिए साख निर्माण का कार्य कम धनी व्यक्तियों के लिए सुलभ होने के साथ साथ सुरक्षित भी होना चाहिए

4. केन्द्रीय "बैंकिंग कला" का पूर्ण विकास होना चाहिए :

कम-विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक की स्थापना भी काफी देर में हुई है, पर अभी भी बहुत से देशों में केन्द्रीय बैंक की तकनीक पूर्ण-विकसित नहीं हो पाई है.

Henry wallich के अनुसार

“आज की परिस्थितियों में कम-विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक मुद्रा नियन्त्रण के स्थान पर साख निर्माण व मुद्रा स्फीति का कारण बनकर रह जाते हैं.”

केन्द्रीय बैंक को चाहिए कि देश के औद्योगिक क्षेत्र को समान करें जब मुद्रा का अत्यधिक प्रसार हो तो बैंक दर बढ़ा कर, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचकर, प्रत्यक्ष चयनात्मक साख नियन्त्रण से रोके. अगर देश में मंदी है तो केन्द्रीय बैंक, बैंक दर घटाए, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदे और साख नियन्त्रण के प्रतिबंध हटाएँ.

5. मौद्रिक नीति को विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाने में सहायता देना चाहिए :

हम सबको विदित है कि कम विकसित देशों में निर्यात से आयात अधिक रहने हैं. इन देशों में पूँजी या मशीनों के आयात अत्यन्त आवश्यक होते हैं और इससे विदेशी विनिमय की स्थिति और गम्भीर हो जाती है. विदेशी मुद्रा की माँग की अधिकता में विनिमय दर विपक्ष में जाती है, जिससे देश की हानि होती है, तथा मुद्रा व्यापार में सट्टा होता है.

उचित मौद्रिक नीति का तकाजा यह है कि जब कभी भी निर्यात अधिक हो तो विदेशी मुद्रा को संचित करें. आयात पर कड़ा नियन्त्रण हो यह भी उचित होगा कि राज्य विदेशी विनिमय व्यापार अपने हाथ में ले ले. लेकिन निर्यात बढ़ाने के लिए देश में मुद्रा अल्पस्फीति को नीति नहीं अपनाना चाहिए. इस समय में उचित मुद्रा नीति के साथ-साथ उचित राजस्व नीति भी आवश्यक है.

6. मौद्रिक नीति को दीर्घकालीन विनियोजन में सहायता देना चाहिए :

विकास विनियोजन का ही प्रतिफल होता है साख के बगैर विनियोजन सम्भव नहीं होता. देश में मौद्रिक संस्थाओं की स्थापित होना चाहिए जो अल्प व दीर्घ, कम व अधिक, तथा विभिन्न क्षेत्रों को उचित व्याज दर पर उपहार दे सकें. उनके

Boulding : cp. cit.

Henry wallich : Monetary Problems of an Export Economy
Harvard University Press, Cambridge 1950 p. 284.

लिए केन्द्रीय बैंक से पुनर्भुनाने की सुविधा (Rediscounting facilities) व्यापारिक बैंको को प्रदान करना चाहिए

7. मौद्रिक नीति "सतुलित" होना चाहिए :

कम विकसित देशों में व्याज की दर न तो कम और न बहुत अधिक होना चाहिए थोड़ी ऊँची व्याज की दर बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक होगी, परन्तु बहुत अधिक ऊँची होने से विनियोजन हतोत्साहित होगा उधर कम व्याज दर से राज्य का ऋण भार तो कम रहेगा परन्तु इससे बचते कम रहेंगी.

कम विकसित देशों में सफल आयोजन व आर्थिक उन्नति के लिए देश में संचालित पत्र मुद्रा का मान होना चाहिए और मुद्रा की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि देश में न तो मुद्रा स्फीति रहे और न मुद्रा विस्फीति

कम-विकसित देशों में मौद्रिक नीति क्या होना चाहिए यह तो हर देश विशेष की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है. हम इस सबंध में, निष्कर्ष में, बेन्जामिन हिगिंस को उद्धृत कर सकते हैं

"Under developed Countries may need monetary measures of a sort tailor made for their own institutional framework, but that such measures can be an effective insurance of economic stabilization"

(अर्थात् "कम विकसित देशों को अपनी परिस्थितियों व संस्थाओं के अनुसार नीति बनानी होगी (Tailor made) अर्थात् मिले सिलाए कपड़ों की भाँति "रिडी मेड" नहीं बरन् नाप देकर बनाए हुए कपड़े की भाँति)

II. कम-विकसित देशों में मौद्रिक नीति की सीमाएँ

जब हम यह देख चुके हैं कि मौद्रिक नीति विकसित देशों में भी पूर्ण रूप से प्रभावशील नहीं होती, तो कम-विकसित देशों में उसने पूर्ण रूप से प्रभावशील होने का प्रश्न ही नहीं उठता. कम विकसित देशों में मौद्रिक नीति के पूर्ण रूप से प्रभावशील न होने के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है

1 सर्वप्रथम सीमा तो यह होती है कि इन देशों में मुद्रा बाजार कम-विकसित होते हैं. "भारत में ही अनुमानतया 35% राष्ट्रीय आय मौद्रिक सौदा के

क्षेत्र से बाहर है. मौद्रिक क्षेत्र में भी लगभग 50% उधार पूंजी संगठित मुद्रा बाजार से प्राप्त होती है और शेष 50% गैर बैंकिंग संस्थाओं से प्राप्त होती है "

2. दूसरे इन देशों में साख मुद्रा से अधिक 'चलन' मुद्रा महत्वपूर्ण होती है इस कारण साखी नियंत्रण के उपायों से मुख्य मुद्रा चलन पर प्रभाव नहीं पड़ता.
3. इन देशों में बैंक दर बढ़ाने से भी साख संकुचन नहीं हो पाता, क्योंकि विदेशी बैंक इन देशों के केन्द्रीय बैंकों से उधार लेने के स्थान पर अपने विदेशी मुख्यालय से धन भेगा लेते हैं. इधर देश के व्यापारिक बैंक भी केन्द्रीय बैंक के ऊपर आश्रित नहीं होते क्योंकि व्याज की दर बढ़ने से बैंकों के पास जमा राशि बढ़ जाती है. इस कारण वे अपनी साख का निर्माण का कार्य पूर्ववत् रख सकते हैं
4. इसी प्रकार से खुले बाजार की नीति भी साख निर्माण बढ़ाने या संकुचन करने में अधिक सफल नहीं होती इसका कारण यह होता है कि इन देशों में राज्य की प्रतिभूतियों का बाजार अधिक विकसित नहीं होता. राज्य की प्रतिभूतियाँ पर औसतन 4 या 5 प्रतिशत का व्याज मिलता है जबकि व्यापारिक संस्थानों की प्रतिभूतियों पर व्याज की दर 8 से 12 प्रतिशत तक होती है. इससे व्यापारिक बैंक इन प्रतिभूतियों में व्यापार करते हैं और केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार नीतियों का प्रभाव कम पड़ता है.
5. इसी प्रकार से केन्द्रीय बैंक के द्वारा 'न्यूनतम कोप सीमा' बढ़ाने से भी साख संकुचन नहीं होता. कम-विकसित देशों में बैंकिंग के बहुत से सौदे नगद होते हैं इस कारण बैंक इस न्यूनतम सीमा से कहीं अधिक नगद कोप रखते हैं और अगर केन्द्रीय बैंक यह जमा सीमा बढ़ाता है तो उसके लिए साख संकुचन नहीं करना पड़ता
6. श्री एच० वी० आर० आण्णार H V. R Iengar ने जो भारत के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व डायरेक्टर रहे हैं, कम-विकसित देशों में विकास बढ़ाने में मौद्रिक नीति की सीमाओं का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है. उनके विचारों को नीचे व्यक्त किया जा रहा है .

"इसमें कोई शक नहीं है कि मौद्रिक नीति प्रशासकों का विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, फिर भी उनके महत्व को बड़ा बढ़ाकर

विकास व मौद्रिक नीति

प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की मौद्रिक नीति खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ा सकती। इसी प्रकार से मौद्रिक नीति का उन समाजद्रोही तत्वों, जो कि काला बाजार, व सट्टा व जमाखोरी करते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति को इतना रखें कि न्यून पूर्ति वस्तुओं पर माँग का दबाव कम बना रहे। साख नियंत्रण ऐसे कठोर नहीं होना चाहिए कि इससे उत्पादन में रुकावट हो या बाजार के व्यापक होने में बाधाएँ आएँ।

माँग पर मौद्रिक भार पड़ने से बचने के लिए केन्द्रीय बैंक चयनात्मक व सामान्य साख नियंत्रण पद्धति अपना सकता है। परन्तु मौद्रिक नीति पूर्ति की कमी को दूर नहीं कर सकती परन्तु सटोरियों और जमा-खोरी को साख सुविधा बन्द कराकर केन्द्रीय बैंक उचित कार्य कर सकता है। यहाँ पर कठिनाई यह है कि यह व्यक्ति गैर-बैंकिंग संस्थाओं से उधार लेते हैं यह आवश्यक है कि और गैर-बैंकिंग संस्थाएँ केन्द्रीय बैंकिंग के नियंत्रण में आयें ”

अध्याय : 6

विकास व राजकोषीय नीति

Role of Fiscal Policy for Economic Development

or

Fiscal Policy and Economic Development

I प्रस्तावना

विकसित देशों के लिए राजकोषीय नीति

Functional Finance (क्रियात्मक वित्त) Counter or anti-cyclical finance (चक्रविरोधी नीति) या compensatory finance (क्षति-पूर्ति नीति)

1. मंदीकाल - घाटे का बजट व उसकी तीन रीतियाँ
2. तेजीकाल ॥

चक्रविरोधी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रीतियाँ.

Built-in flexibility, formula flexibility, discretionary action.

II कम विकसित देशों के लिए राजकोषीय नीति

II : A. आय नीति :

II A (a) कर नीति के उद्देश्य अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से .

1. पूँजी निर्माण का उद्देश्य
2. उपभोग कम, बचतें, विनियोजन तथा उत्पादन के लिए प्रेरणा
3. विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, विदेशी विनियोजकों को प्रोत्साहन,
4. मुद्रा स्थिति नियन्त्रण
5. समानता साने का लक्ष्य.
6. देश में, कर व्यवस्था में समन्वय तथा अन्य नीतियों से समन्वय
7. भ्रष्टाचार रोकना व प्रशासनिक सुधार

सीयर तथा बाल्डविन, किन्डलबरजर, आर०एन० भार्गव व आर०एन० त्रिपाठी के विचार ¹

II : A (b) कम-विकसित देशों में भिन्न-भिन्न करों का स्वभाव व सापेक्षिक संरचना कैसी हो

कृषि पर कर, आय कर व कम्पनी कर, सम्पत्ति कर, उत्तराधिकार कर, पूँजी लाभ कर, उपहार कर, उत्पादन कर, बिक्री कर, आयात व निर्यात कर, लाभ पर कर, विदेशी विनियोजकों पर कर आदि को विकास के लिए क्या संरचना हो.

II : A. (c) करों की अधिकता विकास के लिए घातक

II : B कम-विकसित देशों के लिए सार्वजनिक व्यय नीति व विकास

II : C. कम-विकसित देशों में ऋण व्यवस्था संबंधी नीति व विकास

1. अन्य अर्थशास्त्रियों के विचारों की समालोचना नहीं की गई क्योंकि इन्हीं विचारों को दूसरे शब्दों में व्यक्त करना पड़ता.

अध्याय : 6

विकास व राजकोषीय नीति

Role of Fiscal Policy for Economic Development

or

Fiscal Policy and Economic Development

I. प्रस्तावना

राजकोषीय नीति के अन्तर्गत वजट की वे समस्त क्रियाएँ आती हैं, जिनके अन्तर्गत राज्य के द्वारा धन इकट्ठा करना, खर्च करना, ऋण लेना और चुकाना, तथा वित्तीय प्रबंधन करना शामिल है। पहले इस नीति को Public finance policy राजस्व नीति कहते थे परन्तु इसका आधुनिक नाम Fiscal policy राजकोषीय नीति है।

इसी प्रकार से वित्तीय नीति (financial policy) तथा राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में अन्तर होता है। वित्तीय नीति के अन्तर्गत हम राज्य का आय इकट्ठा करने एवं खर्च करना अध्ययन करते हैं। राजकोषीय नीति के अन्तर्गत राज्य का आय संचित करना व व्यय करना भी किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरणतः सड़क निर्माण कार्य इसलिए किया जाता है कि एक सड़क की आवश्यकता है (यह वित्तीय नीति के अन्तर्गत कार्य हुआ) परन्तु जब सड़क का निर्माण इसलिए भी किया जाता है कि इससे देश में रोजगार व आय में भी वृद्धि हो, तो यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य हुआ।¹

विकसित देशों के लिए राजकोषीय नीति :

विकसित देशों में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य मदी को रोकना है। राजकोषीय नीति का प्रयोग तेजी व मदी के चक्रा के दुष्प्रभावों को रोकना है। पुराने अर्थशास्त्री आर्थिक मदी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करने के पक्ष में थे।

1. Allen, Buchanan & Colberg : Prices, Income & Public Policy :
ch. 191.

Hawtrey हाट्ट्रे का तो यहाँ तक विश्वास था कि केवल अल्पकालीन व्याज की दरों में परिवर्तन कर के ही मंदी एवं तंजोंकाल पर नियन्त्रण पाया जा सकता है, परन्तु 1930 की महान मंदी ने मौद्रिक नीति द्वारा मंदी व बेरोजगारी को दूर करने में प्रभावहीनता साबित कर दी. महान मंदी के बाद केन्स (Keynes) हन्सेन (Hansen) तथा लेनर (Lerner) जैसे प्रभावशाल अर्थशास्त्रियों ने राजकोपीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण बताया. तब से आज तक राजकोपीय नीति विकसित देशों में अक्रविरोधी नीति के रूप में प्रयोग होती है.

• Functional finance (क्रियात्मक वित्त) Counter or Anti-cyclical finance (अक्रविरोधी नीति) या Compensatory finance (क्षति-पूर्ति वित्तीय नीति) :

1. संक्षोभकाल :

मंदीकाल में, जैसा कि सर्वविदित है, मूल्य गिरते हैं जिससे उत्पादनकर्ताओं को हानि होती है, उत्पादन कम होता, मजदूरों की छटनी होती है, रोजगार वृद्धि के अवसर कम होते हैं, मजदूरी की दरें गिरती हैं, विनियोजन कम होता है, राज्य की आय गिरती है, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय गिरती है जो व्यक्ति रोजगार में लगे रहते हैं उनकी वास्तविक आय ताँ बढ जाती है परन्तु पारिवारिक आय, बेरोजगारी के कारण, गिर जाती है विकसित देशों में यह मंदी मुख्यतः प्रभावशाल माँग की कमी, अर्थात् उपभोग में सापेक्षिक कमी तथा बचतों में सापेक्षिक वृद्धि हो जाती है मंदी को दूर करने के लिए, स्वाभाविक रूप से, बचतों को घटाना व उपभोग बढ़ाना लक्ष्य रहता है, तथा देश में घाटे का बजट बनाकर देश में अतिरिक्त मुद्रा पहुँचा कर मूल्यों में वृद्धि करना होता है

घाटे का बजट तीन रूप से प्रस्तुत हो सकता है :

पहली रीति है कि खर्च बढ़ा दिए जाएँ एवं आय उतनी ही रखी जाए और अतिरिक्त व्यय को नये नोट छापकर पूरा किया जाए दूसरी रीति है कि खर्च उतना ही रखा जाए परन्तु करों को घटा दिया जाए और यह घाटा भी नये नोट छापकर पूरा कर लिया जाए तीसरी रीति है कि मत्तुलित बजट के मुख्य प्रभाव द्वारा मंदी का सामना किया जाए

पहली रीति :

यह रीति यह है कि राज्य अपने विनियोजन एवं राहत कार्यों पर व्यय बढ़ाए, बेरोजगारी का मुआवजा दे, उपभोक्ताओं को बोनस दे, किसानों को गिरते मूल्यों की क्षति पूर्ति करे या मुआवजा दे. (to give price support) परन्तु

अपनी आय को उसी स्तर पर रखे इस नीति के कई लाभ हैं, जैसे मदी के दिनों में चीजे सस्ता होने के कारण राज्य को विनियोजन करना भी सस्ता पड़ता है (real cost of public expenditure is less), दूसरे जनता को यह विश्वास हो जाता है कि राज्य उत्पादन वृद्धि के कार्य में मागे आकर वास्तव में मदी को दूर करने के लिए कटिबद्ध है परन्तु इस नीति को अगर बहुत अधिक कार्यान्वित किया गया तो निजी क्षेत्र के विनियोजकों को यह भय भी हो सकता है कि राज्य उनसे प्रतियोगिता करने लगा है और इस कारण वे हतोत्साहित हो सकते हैं

दूसरी नीति :

राज्य यह भी कर सकता है कि करों को कम कर दे तथा कर सवधी ऐसी छूटें दे जिससे उत्पादन बढ़े, अगर राज्य ऐसी वस्तुओं के कर में कमी करे जिनकी मांग लोचदार है तो इससे देश में प्रभावशील मांग बढ़ेगी स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में ऐसी नीति को प्रथम नीति से अधिक पसंद किया जाता है दूसरे यह खर्च बढ़ाने के कार्य से अधिक सरल है और शीघ्र किया जा सकता है

इस नीति को प्रमुख दुर्गह यह है कि इससे धन की अनमानताएं बढ़ती हैं,

उचित नीति तो यह होगी कि कुछ मात्रा में तो कर कम किए जाएं तथा कुछ मात्रा में व्यय बढ़ाए जाएं वास्तव में दोनों नीतियों का उचित समिश्रण उचित होगा

तीसरी नीति :

यह एक दिलचस्प विचार है कुछ अर्थशास्त्रियों का कथन है कि सतुलित वज्रट से भी गुणक प्रभावों द्वारा मदी दूर होने में सहायता मिलती है इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं

माना कि एक देशवासी औसतन अपनी आय का $4/5$ भाग उपभोग करते हैं अर्थात् $1/5$ बचत करते हैं अब इस देश में गुणक 5 होगा, (Multiplier will be 5) अर्थात् राज्य जो 100 रुपये खर्च करेगा उसके बाद 400 रुपये और खर्च होकर कुल 500 खर्च होगा राज्य के 100 रु० खर्च करने से कुल 500 रु० के बराबर प्रभावशील मांग बढ़ती है

राज्य 100 रु० व्यय करने के लिए 100 रु० के कर लगाएगा कर लगाने से लोग 80 रु० तो उपभोग कम करके देंगे (उपभोगचमता $4/5$ है) और 20 रु० बचतों में से देंगे, कुल उपभोग $80 \times 5 = 400$ रु० का कम होगा इस प्रकार से समाज में फिर भी समाज को 100 रु० की मुद्रा के बराबर प्रभावशील मांग बढ़ जाएगी

देश में उपभोग क्षमता अधिक होने से **Balanced budget multiplier** अधिक होगा

इस नीति या विचार में यह कमी है कि 100 रु० की आय खर्च करने को 100 रु० से अधिक के कर लगते हैं करो के इकट्ठा खर्च व सार्वजनिक व्यय करने में भी तो व्यय होगा

घाटा किस प्रकार से पूरा किया जाए ?

राज्य घाटे को या तो नए नोट छाप कर पूरा कर सकता है, या व्यापारिक बैंको से उधार लेकर पूरा कर सकता है या फिर जनता से उधार लेकर पूरा कर सकता है

- ✓ (1) राज्य अगर नए नोट छाप कर घाटे को पूरा करता है (अर्थात् केन्द्रीय बजट में उधार लेकर) तो इससे देश में मुद्रा प्रसार बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ने से व्याज की दर घटेगी और निजी विनियोजन प्रोत्साहित होगा
- (ii) अगर यह घाटा साधारण बैंको से उधार लेकर पूरा किया जाएगा तो राज्य द्वारा उधारी की माँग से व्याज की दर बढ़ेगी और निजी विनियोजन प्रोत्साहित नहीं होगा
- (iii) जनता से उधार लेकर घाटा पूरा करना इसी प्रकार से उचित नहीं होगा क्योंकि जनता राज्य को ऋण देने के लिए बैंको से ऋण लेगी और इससे बैंको के कोष कम होंगे और साख निर्माण कम होगा यह नीति आजकल प्रचलित रीतियों की मान्यताओं से भिन्न है आजकल राज्य मन्दी के दिनों में ऋण लौटाती है, लेती नहीं है.

2. लेनी बूर करने को

मुद्रास्फीतिकाल में मदीकाल का उटना होना चाहिए, अर्थात् इसमें अधिक का बजट बनता है (**Surplus budget**) अधिक का व्यय या तो करो की मात्रा व्यय से अधिक करके या करो के वर्तमान स्तर से उससे व्यय की मात्रा घटाकर बनाया जा सकता है राज्य को ऐसे करो को बढ़ाना चाहिए जिनसे उपभोग कम हो, अर्थात् लोचदार माँग वाली विलासिताओं पर कर लगाना चाहिए.

See :

1. Boulding . Principles of Economic Policy. p. 147 Fg
 2. Taylor : Public finance chs. 4, 5, 6.
 3. Ganguly : Public finance p 80-90.
- and other standard works on Public Finance.

तेजीकाल में राज्य को मृग्य लेना चाहिए. इस काल में अनिवार्य वचन योजनाएं चलाई जा सकती हैं. प्रायः कमाने के बाद तात्कालिक कर काटा जा सकता है. Tax deduction at source

चक्रविरोधी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रीतियाँ :

चक्रविरोधी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की तीन रीतियाँ हैं. ये तीन रीतियाँ हैं.

(i) Built-in Flexibility स्वयं उत्पन्न होती रहने वाली लोचकता :

यह वह व्यवस्था है जिसमें बगैर कर की या व्यय की दरों में परिवर्तन किए या बगैर कोई संवैधानिक कदम उठाये स्वयं ही स्वयं चक्र विरोधी वित्तीय व्यवस्था हो जाती है अर्थात् जब देश में मुद्रा पतनती है तो करो से प्रायः स्वयं बढ़ जाती है, और व्यय स्वयं कम हो जाने है, यह उस समय होता है जबकि देश की कर व्यवस्था अत्यन्त प्रगतिशील हो जब मूल्य वृद्ध होती है तो लोग स्वयं ही ऊँचे आय स्तर पर पहुँच जाते हैं, अधिक बिलासिताप्रा का प्रयोग करते हैं तथा स्वयं ही अधिक कर चुकाने हैं उधर किसानों को Price support subsidies (मूल्य गिरने की क्षतिपूर्ति) या बेरोजगारों को मुद्रावृद्धा जैसे व्यय कम हो जाते हैं. जब मदी आती है तो व्यय बढ़ जाता है और लोगों की आय कम होने से आय भी कम हो जाती है

(ii) Formula Flexibility • सूत्रीय लोचकता :

किसी भी देश में कर व्यवस्था इतनी पूर्ण रूपेण लचीली नहीं होती कि स्वयं वित्तीय व्यवस्था में मुद्रा स्थिति या विस्फीति को ठीक करने की क्षमता हो इसके लिए राज्य किसी निश्चित योजना व आधार पर करो व व्ययों की दरों में परिवर्तन करता है. तेजी काल में दरों को बढ़ा दिया जाता है और मदी काल में घटा दी जाती है

(iii) Discretionary Action • इच्छानुसार परिवर्तन :

इस नीति के अन्तर्गत समय एवं परिस्थितियों के अनुसार ही वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, परिवर्तन के प्रकार एवं परिवर्तनों की मात्रा परिस्थिति के अनुसार ही निश्चित की जाती है.

सारांश :

“राजकोपोय नीति के दो पहलू होते हैं : सत्त्यात्मक व गुणात्मक सत्त्यात्मक पहलू के अन्तर्गत हम यह भीचते हैं कि वित्तनी मात्रा में

खर्च करें एवं कर जब इस बात पर ही देश की आर्थिक उन्नति निर्भर करती है दूसरा पहलु है कि कितना व्यय किन पर करे व किनसे कितना कर लें इस बात पर स्थिरता याय व स्वतन्त्रता निर्भर रहनी है आर्थिक उन्नति व स्थिरता, याय व स्वतन्त्रता यही चार वित्तीय नीति के लक्ष्य है ' (बोल्डिंग)

II कम विकसित एवं विकासशील देशों के लिए राजकोषीय नीति
विकासशील देशों के लिए चक्रविरोधी या क्षति पूर्ति राजकोषीय नीति का उतना महत्व नहीं है क्योंकि यहाँ पर उन्नत देशों की भाँति व्यापार चक्र नहीं आते तथा इन देशों में तेजी या मंदी आन्तरिक मूल्य स्तर में परिवर्तन से उतनी नहीं आती

References —

- 1 Meier & Baldwin op cit p 390-398
- 2 B Higgins op cit chs 20 21, 22 23, and 24
- 3 Raja Chelliah Fiscal policy in under developed countries
- 4 R N Tripathi Fiscal Policy and Economic Development in India
- 5 Nurkse op cit 140-150
- 6 U N Report on Methods of Financing Economic Development in under developed countries "
- 7 Lewis op cit p 396-408
- 8 U N Taxation and Fiscal policy in under developed countries
- 9 Kurihara The keynesian Theory of Economic Development op cit ch ix
- 10 D S Nag Problems of Under developed Economy p 219-232
- 11 Taxation Enquiry Commission Govt of India 1953 54
- 12 H C Wallich III J H Adler Public Finance in Developing country
- 13 C P Kindleberger op cit p 240 247
- 14 W A Lewis The Theory of Economic Growth ch vii
- 15 R N Bhargava Federal Finance & Tax Policy and Economic Development Eastern Economist Feb 23, 1968
- 16 N Kaldor The Role of Taxation in Economic Development ch 8 Williamson & Buhrick op cit
- 17 B R Shenoy Tax Structure and its Effects on Savings & Growth Eastern Economist March 8 1968

जितनी की आयातीत एवं निर्यातीत वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन के कारण आती है

जैसा कि हम जानते हैं कि राजकोषीय नीति के अन्तर्गत (i) राजकोषीय आय (ii) राजकोषीय व्यय (iii) ऋण व्यवस्था तथा होनार्थप्रवन्धन तथा (iv) वजट प्रशासन आता है. हम अब यह देखेंगे कि कम विकसित देशों के विकास के लिए तत्सम्बन्धी नीतियाँ क्या होनी चाहिए.

II A कम-विकसित देशों के विकास के लिए सार्वजनिक आय (विशेषरूप से कर) नीतियाँ

कम-विकसित देशों में विकास की मुख्य समस्या वचत्ता, पूँजी निर्माण, विनियोजन रोजगार, राष्ट्रीय आय (उत्पादन व उत्पादकता) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है. हम सम्बन्ध में कर नीति का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है.

Ragner Nurkse . रैगनर नर्कस ने इस सम्बन्ध में कहा है कि :

'कर वास्तव में राज्य द्वारा जनता की ओर से, की गई भावी वचत्ता है'

उनका अर्थ है कि

"पूँजी निर्माण के दो तत्व होते हैं—वचत्ता एवं विनियोजन ये दोनों मिल-जुलकर और साहम पर निर्भर करते हैं. कोई कारण नहीं कि निजी साहस' के साथ (With private enterprise system) जनता में करो द्वारा यह 'सांभलिक वचत्ता' कराई जाए कि राज्य जितना व्यय बढ़ाये उतनी ही मात्रा में कर ले ले. इस रीति से, फिर भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी."

II A (a) Economists on Fiscal Policy for Development Meier and Baldwin :

मीयर व बाल्डविन के अनुसार कम-विकसित देशों में राजकोषीय नीति का व्यापक व प्रभावशाली प्रयोग विकास के लिए अत्यावश्यक है. राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा उनके लिए आय इकट्ठा करने के कार्य से विकास दर पर चार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं

- (i) इससे साधनों का वितरण (allocation) प्रभावित होता है
- (ii) इससे धन के वितरण में परिवर्तन होता है.

—(iii) इससे पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है, तथा

—(iv) मुद्रा स्फीति नियंत्रित की जा सकती है.

1. राज्य अपने सार्वजनिक व्यय द्वारा (Subsidies included) जहाँ वह चाहता है उद्योगों की स्थापना कर सकता है तथा अधिक व विभेद पूर्ण करों द्वारा उद्योगों को (जिनकी Social costs अधिक हों) हतासाहित कर सकता है. इस प्रकार देश में विनियोजन को इस प्रकार से कर सकता है कि देश में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोजन हो
2. राज्य के प्रगतिशील करो तथा प्रगतिशील सार्वजनिक व्ययों (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों को प्रदान करके) देश में धन व सम्पत्ति की असमानताएँ दूर कर सकता है. इससे विकास के साधनों का व्यापक वितरण हो जाता है.
3. राजकोषीय नीति में पूँजी निर्माण प्रभावित करना अधिक महत्वपूर्ण होता है. पूँजी निर्माण के लिए बचते या तो (1) निजी बचतों से, (11) साख निर्माण में, (111) विदेश से या (1V) राज्य द्वारा आय व ऋण से प्राप्त हो सकती है. अल्पकाल में प्रथम तीन साधनों से बचतें अपेक्षित मात्रा में नहीं बढ़ाई जा सकती इसलिए राज्य के लिये राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण होती है.

इसलिए राज्य या तो कर बढ़ाता है या फिर हीनार्थप्रवन्धन करता है. मीयर तथा बाल्डविन हीनार्थप्रवन्धन से पूँजी निर्माण के पक्ष में नहीं हैं. उनका कथन है कि यहाँ के बाजारों की अपूर्णता, छुपि उपज का बेमौज होना, उपभोग क्षमता का अधिक होने में हीनार्थप्रवन्धन से पूँजी निर्माण के लाभदायक परिणाम नहीं होंगे. इसलिए राज्य को करों में वृद्धि कर के सामूहिक बचतों द्वारा पूँजी निर्माण करना चाहिए. इससे उपभोग कम होवे तथा उनके स्थान पर राज्य द्वारा पूँजी निर्माण होगा. या राज्य इस धन को बैंकों में पहुँचा सकता है (अपने ऋण चुका कर) जिससे वे साख निर्माण कर सकते हैं और निजी पूँजी निर्माण में सहायता दे सकते हैं. मीयर तथा बाल्डविन के शब्दों में :

“The over-all concern of the Government's fiscal policy should be directed towards maximising savings, mobilizing them for productive investment, and canalizing them into directions that will best serve the objectives of a balanced development programme.”

करो के सम्बन्ध में ये अर्थशास्त्री चाहते हैं कि

- (i) कम-विकसित देशों में करदेय क्षमता व व्यापार का विस्तार किया जाए.
- (11) कर प्रशासन योग्य व अन्ध बनाया जाए.

- (iii) राज्य प्रतिभूतियों के बाजार को विस्तृत किया जाए.
- (iv) देश में विभिन्न प्रकार के करों का चयन व उनकी संरचना ऐसी होना चाहिये कि देश की कर व्यवस्था में न्याय, समानता, सरलता व उत्पादन बढ़ाने के गुण बने रहें
- (v) देश में, आय में वृद्धि तथा प्रेरणा को बनाए रखने के लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए.
- (vi) मदी के काम में घाटे व तेजी या मुद्रा स्फीति के काल में अधिक का बजट बनाना चाहिए.

देश में कर व्यवस्था में राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता होना चाहिए

राज्य की राजकोपीय नीति का मुख्य लक्ष्य इन देशों में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखना भी है, जैसा कि विकसित देशों में मदी को दूर करना होता है.

C. P. Kindleberger .

किन्डलबर्जर भी कम विकसित देशों में राज्य की आय व्यवस्था को पूँजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन बनाने की सलाह देते हैं. निजी बचतों के कम होने, विदेशों से पूँजी न मिलने, पूँजी बाजार के विकसित न होने, तथा सार्वजनिक व्यय को कम न रख सकने की अवस्था में पूँजी निर्माण केवल राज्य द्वारा करों की मात्रा को बढ़ाने से ही संभव होगा

विकसित देशों में हमारा ध्यान Ability to pay पर जाता है जबकि कम विकसित देशों में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राज्य में Ability to tax है ? इन देशों में करों को जहाँ उपभोग, विवास्तितों उपभोग तथा गैर जरूरी व अनु-स्वादक विनियोजन रोकना चाहिए. वहाँ कर व्यवस्था को पूँजी निर्माण करने, लाभ कमाने तथा उनकी पुन विनियोजित करने में सहायक होना चाहिए. इसलिए

"These considerations imply a tax programme heavily weighted on the side of consumption and against imposts on income."

1. op cit : p. 392. Ragner Nurkse का भी यही मत है .
"The two components of capital formation, saving and investment, depend on thrift and enterprise; there is nothing to prevent collective thrift from being combined with individual enterprise" . op cit. p. 151.

C. P. Kindleberger : op. cit : p 240-6 : मुद्रास्फीति पर Kindleberger के विचार "मौद्रिक नीति" अध्याय में भी दिए गए हैं.

किण्डलबरजर चाहते हैं कि कम विकसित देश भूमि व उस पर बढ़ती आय पर पर्याप्त मात्रा में कर लगाएँ, विदेशी विनियोजकों पर भी पर्याप्त मात्रा में कर लगाना चाहिए परन्तु इतना नहीं कि वे पुनर्विनियोजन ही न करें.

हीनार्य-प्रवन्धन, मुद्रा स्फीति व राजकोपीय नीति :

किण्डलबरजर यह मानते हैं कि कम विकसित देशों को पूँजी निर्माण करने तथा आवश्यक बाह्यमितव्ययिताओं का सृजन करने के लिए हीनार्यप्रवन्धन करना ही पड़ेगा पर इसको यथासंभव नियंत्रित रखना चाहिए. कम-विकसित देशों में राजकोपीय नीति का मुद्रा स्फीति नियंत्रण करने में प्रभावशीलता कम रहती है मुद्रा स्फीति कम करने के लिए या तो व्यय को कम करें या भारी मात्रा में कर लगाएँ परन्तु कम विकसित देशों में राजनैतिक तथा प्रशासनिक कारणों से संभव नहीं हो पाता. Kindleberger के शब्दों में

“In this circumstance inflation, like the working girl who has slipped, is more to be pitied than scorned An under-developed country with luck or virtue can avoid inflation; but it needs more of either or both than a developed country.”

Dr. R. N. Bhargava .

डा० भार्गव, जो भारत में राजकोपीय समस्याओं पर विशेषज्ञ हैं, के अनुसार विकास के लिए कर नीति में निम्नलिखित मुख्य तत्व होना चाहिए.

श्री शर्मा भी चाहते हैं कि कम-विकसित देश मुद्रा-स्फीति को राजकोपीय नीति का अंग न बनाएँ. उनके शब्दों में :

“Inflation eats into savings through shifting incomes from the masses and wage earners into the pockets of residual income groups when the level of living is already low, consumption being largely limited to necessities of life, these income shifts cannot be met by cuts in Consumption on the part of the victims of inflation cuts in Consumption would be resisted, or savings will decline Inflation in a back ground of poverty would, thus, be a net debit on national savings. op cit.

Dr. R. N. Bhargava : op. cit.

1. राज्य को, कर नीति को साधनों के जुटाने व विकास क्रियाओं को कार्यान्वित करने हेतु धन प्राप्त करने का मुख्य अग्र बनाना चाहिए। अगर करो से पर्याप्त आय न हुई तो हीनार्यप्रबन्धन करना पड़ेगा जिससे मुद्रा स्फीति फैलेगी, जिससे वचनें कम होंगी, उनका मूल्य कम होगा तथा राज्य की करो द्वारा इकट्ठी आय का वास्तविक मूल्य कम होगा। इसलिए Non inflationary measures से या मुद्रा स्फीति न फैलाने वाली रीति से आय प्राप्त करना चाहिए।

2. **Incentive Taxation** कम-विकसित देशों में कर नीति का लक्ष्य समानता लाना होता है और यह लक्ष्य भी होता कि देश में वचनें तथा विनियोजन न केवल हतोत्साहित हो बल्कि प्रोत्साहित हो। ये दोनों लक्ष्य आपस में विरोधाभासी हैं। इनको प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी पड़ेंगी। समानता के पीछे हमको विनियोजन को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। निर्यातवर्धन, पुनर्विनियोजन तथा विदेशी पूँजी या तकनीकी जानकारी लाने के लिए कर सम्बन्धी छूटें देना चाहिए।

3. **Co-ordination** कम विकसित देशों में केन्द्रीय व राज्य सरकारों की कर नीतियों में समन्वय होना चाहिए। समन्वय का यह अर्थ नहीं है कि राज्यों की सरकारें केन्द्र के एकदम अधीन हों।

यह आवश्यक है कि कर, मूल्य, आय व छूटकर नीतियों में पूर्ण समन्वय हो। कर नीति से समाज के विभिन्न-भिन्न वर्गों में समानता आती है, परन्तु हीनार्य-प्रबन्धन से मूल्यों का स्तर विकृत हो जाता है। हीनार्यप्रबन्धन के कालस्वरूप जो मुद्रा स्फीति होती है उससे सामाजिक अन्याय होता है। कम आय पानेवाले तथा निश्चित आय पानेवाले हानि उठाते हैं। कम-बोर मूल्य नीति से विवेकपूर्ण कर नीति विकृत हो जाती है (Thus a weak price policy distorts a sensible tax policy)

4. **Administration** कम-विकसित देशों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करो का प्रशासन बहुधा अक्षम व भ्रष्ट होते हैं। इससे कर वचन बहुत होता है बहुत हद तक बहुत ऊँची प्रत्यक्ष कर की दरें इसके लिए उत्तरदायी हैं। एक सीमा के बाद भारत में ही प्रत्यक्ष कर शत-प्रतिशत से भी अधिक है। इतने अधिक कर इसीलिए बढ़ाए जाते हैं कि इनसे वचन हो सकता है। इससे देश में अन्य लोग भी भ्रष्ट रीतियाँ अपनाने को उत्सुक होते हैं।

किन्हीं किन्हीं कम-विकसित देशों में करो की सरचना इतनी जटिल है कि कर विशेषज्ञों को भी परेशानी हो जाती है, कर विशेषज्ञ N Kaldor ने भारतीय कम्पनी कर व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा था

“The company taxation provisions of India... are apt to strike a detached observer as a perfect maze of un-necessary complications, the accretion of years of futile endeavour to reconcile fundamentally contradictory objectives.”

कम विकसित देशों में कर सरचना न केवल जटिल रहती है बल्कि बार-बार बदलती रहती है हर वित्तमन्त्री अपनी इच्छा के अनुसार (कुछ लाभ कमाने की इच्छा से) हर वर्ष अनावश्यक परिवर्तन करता रहता है. यह इन देशों में विनियोजन आयोजन के लिए अत्यन्त दुविधाजनक स्थिति पैदा करती है. श्री भार्गव के अनुसार .

“It is necessary that a tax policy to be successful must be stable, consistent and certain, this will help investment and enterprise so vital in a developing economy.”

Dr. R. N. Tripathy

कम-विकसित देशों को अपने विकास आयोजन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए इसको हम आन्तरिक व बाह्य दोनों साधनों से प्राप्त करते हैं. आन्तरिक साधनों में यह धन हम

- ✓ (i) करो में वृद्धि व नए कर लगाकर.
- ✓ (ii) मुद्रा स्फीति विहीन ऋण-व्यवस्था से तथा-
- ✓ (iii) हीनार्यप्रबन्धन से प्राप्त करते हैं.

डॉ० त्रिपाठी का कथन है कि .

“कम विकसित देश उपभोग कम करके ही वचत कर सकेंगे, भले ही इन देशों में उपभोग के स्तर पहले से ही नीचे क्यों न हो. इसलिए अनावश्यक विनियोजन व उपभोग पर अधिक कर लगाना ही पड़ेगा.”

कर नीति के दो पहलू होते हैं पहला Static स्थैतिक पहलू तथा दूसरा Dynamic या प्रवर्गिक पहलू. कम विकसित देशों में कर नीति का पहला पहलू तो यह है कि वे उपभोग को न बढ़ने दें और दूसरा पहलू यह है कि जब विकास से उत्पादन बढ़े तो बढ़े हुए उत्पादन में से अधिकाधिक भाग विनियोजन के लिए प्राप्त करें.

श्री त्रिपाठी यह नहीं चाहते कि यह बड़ी हुई आय निजी विनियोजकों के पास ही पुनर्विनियोजन के लिए छोड़ दें. उनका कथन है कि वास्तव में विकास के लिए कम विकसित देशों में पहले सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी और इसलिए करो में वृद्धि आवश्यक होगी ही. उनके शब्दों में

“Tax policy in a developing country as an instrument of development finance for the public sector has to be geared effectively to the taxation of non-entrepreneurial incomes, providing at the same time adequate incentive to the private sector undertaking useful production and essential investment.”

अपनी कृष्ण लेने की नीति को सफल बनाने के लिए राज्य को वित्तीय बाजार का संगठन करना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी ध्याज की दर पर बाँट लेना पड़ेगा. कम-विकसित देशों में हीनार्थप्रवन्धन को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है. हीनार्थप्रवन्धन की मुद्रा स्फीति कारक नीति से बचने के लिए जरूरी उत्पादन करने वाली योजनाओं को, जिनमें श्रम सहन तकनीक के प्रयोग की अधिकता हो, कार्यान्वित करना चाहिए. परन्तु हीनार्थप्रवन्धन को मुद्रा स्फीति नहीं फैलाने देना चाहिए अन्यथा गरीबों पर भार पड़ेगा, मजदूरी स्तर बढ़ने से लागत व पुनः मूल्य बढ़ेंगे, विदेशी विनिमय सुवधी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, सट्टेबाजी बढ़ेगी व ठोस विनियोजन हतोत्साहित होंगे, बचतें व उनका मूल्य कम होगा और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

विकासशील देश में केन्द्र व राज्य की नीतियों में समन्वय होना चाहिए.

II A(b) कम-विकसित देशों में भिन्न-भिन्न करो का स्वभाव व सापेक्षिक संरचना कैसी हो

इस पर कर :

कम-विकसित देशों में अधिकांश राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र से आती है और इसमें

देश की अधिकांश जनता कार्यरत होती है। प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारण इस क्षेत्र पर कर का भार शहरी क्षेत्र से कम होगा। कृषि क्षेत्र के व्यक्ति, लगान, कृषि आय कर के रूप में प्रत्यक्ष कर देते हैं और अपने द्वारा उपभोग की जाने वाले वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर देने हैं।

अधिकांश कम-विकसित देशों में भू-राजस्व या लगान खेतों की आधार के अनुसार लिया जाता है इसलिए यह काफी बेब्याचदार होता है क्योंकि भूमि व उत्पादकता वृद्धि के अनुसार यह नहीं बढ़ता। कृषकों की प्रशिक्षण तथा सदियों में उनका जमींदारों के "दास" के रूप में रहने से वे कठोरता व भ्रष्टाचार के शिकार रहे हैं।

कम-विकसित देशों में विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में भू-राजस्व की दरों में व आधारों में समानता लाई जानी चाहिए। तथा लगान को उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, मूल्य परिवर्तन आदि के अनुसार करके उसे लोचदार बनाना चाहिए।

कालान्तर में लगान को कृषि कर के रूप में बदल देना चाहिए। आधुनिक युग में राज्य सरकारों कृषि को उन्नत करने के लिए बहुत विनियोजन किया है और इससे कृषि में उन्नति होती है। मूल्यों के संबंध में क्षतिपूर्ति सहायता दी गई है। (Price support) इसलिए कृषकों पर भी कर लगाना चाहिए। उदाहरणतः 1967-68 में ही भारत में कृषकों को 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई। परन्तु करो के उतने ही रहने से उन पर कर का भार घट गया आज भारत के 75% लोग गाँवों में रहते हैं, परन्तु वे कुल करो का 15% भाग देने हैं, और 25% जनता जो शहरों में रहती है वह 85% कर देती है। देश की राष्ट्रीय आय का 48% भाग कृषि से आता है पर कुल उपज का 1% ही कृषि से कर के रूप में आता है। 1951 से कृषि करो की आय राष्ट्रीय आय के 4% से बढ़कर 5% हुई पर अकृषि करो का भाग राष्ट्रीय आय का 9% से बढ़कर 14% हो गया।

1. कृषि कर व्यवस्था में कृषकों को बाढ़, सूखा, कीड़े आदि से हानि के दिनों में कर सबधी छूटें दी जाना चाहिए।
2. कृषि भूमि के सट्टात्मक व्यापार को रोकने के लिए कड़े कर लगाना चाहिए Capital gains tax यर्थात् पूँजीगत मूल्य बढ़ने पर कर।
3. जिन खेतों पर खेती न की जाती हो (जिसको केवल समय आने पर बेचने के उद्देश्य से रख छोड़ा हो) उन पर भी कर लगाना चाहिए।

देखिए : O. S. Shrivastava द्वारा लिखित अध्याय 22, "भूदा बेकिंग...
...राजस्व" वंताश पुस्तक सदन, 1969.

4. कृषि क्षेत्र में लगे करो की जहाँ वहाँ कि बचनों को प्राप्त करने का महत्व-पूर्ण साधन होना चाहिए वहाँ यह भी देखना है कि इससे विनियोजन करना कठिन तो नहीं हो जाता है.

“जापान ने कृषि करो को उन्नत कृषि के लाभ से राज्य ने भी अच्छा हिस्सा लिया, तथा वहाँ के कृषकों ने करो की चुकाने के लिए और अधिक मेहनत की.”

आय कर तथा कम्पनी कर :

कम-विकसित देशों में गरीबी है तथा घन की असमानताएँ हैं. इसलिए आम करो को इस प्रकार का होना चाहिए कि ये असमानताएँ कम तो हों परन्तु साहसियों की उत्पादन वृद्धि में बाधा न आयें. कम-विकसित देशों में बहुधा कर की दरों को बढ़ा कर आय बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है. इससे अधिक आवश्यकता कर का आधार (Tax base) या कर देने वालों की संख्या बढ़ाना है. कम-विकसित देशों में अधिकांश जनता द्वारा हिसाब किताब न रखने, बैंकों का प्रयोग कम करने, भ्रष्टाचार के कारण जनता कर का दायित्व ईमानदारी से नहीं चुकाती.

भारत के भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री टी. टी. कृष्णामाचारी ने एक बार कहा था

“अगर भारत में वे सब व्यक्ति जिन्हें कर चुकाना चाहिए. कर चुका दें, तो करो की मात्रा आधी की जा सकती है.”

इसलिए विकास के लिए करो की दरों में वृद्धि के बजाय कर प्रशासन को सुधारना तथा कर का आधार बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण होगा. देश में मौद्रिक क्षेत्र में वृद्धि से भी इस सम्बन्ध में आस बढ़ेगी.

कम विकसित देशों में उत्पादन व विनियोजन वृद्धि की प्रेरणा बनाये रखने के लिए व्यक्ति व कम्पनी कर इतने अधिक नहीं होना चाहिए कि बचत व पूँजी निर्माण ही रुक जाए. नये उद्योगों की शुरु के कुछ वर्षों के लिए कर से छूट देना चाहिए, तथा उद्योगों में उन्नति व तकनीकीकरण में पर्याप्त मात्रा में घिसावट का प्राविधान करने की अनुमति होना चाहिए

गैर कमाई आय पर अधिक कर : सम्पत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, तथा पूँजी-लाभ कर, उपहार कर :

कम-विकसित देशों में गैर कमाई आय पर करो की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इस प्रकार की आय बहुधा विनासिताओं के दिस्तारवटी उपयोग, सट्टे, पूँजी को

इधर-उधर भेजते रहने, जमाखोरी के काम में लाया जाता है इसमें देश में मुद्रा स्फीति ही अधिक फैलती है Harvey Leibenstein इसी प्रकार के कार्यों को जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, Zero-sum enterprises कहते हैं.

इस प्रकार से व्याज पर खया उधार देकर मूदखोरी करने वाले, जमाखोर व पूँजी-गत वस्तुओं के सट्टे करने वालों पर अधिक कर लगाना चाहिए.

कम-विकसित देशों में मृत्यु कर (उत्तराधिकारी कर) को प्रगतिशील रूप में लगाना चाहिए अन्यथा भावी पीढ़ियाँ स्वयं उत्पादक कार्य करने के स्थान पर बँटे-बँटे खाने की क्षमता रखेंगे यह बात देश में अकर्मण्यता को जन्म देती है,¹ कम-विकसित देशों में बहुधा real estates या सम्पत्ति में बहुत धन लगा दिया जाता है. जब देश में इस प्रवृत्ति को रोकना हो तो सम्पत्ति करों को बड़ा देना चाहिए. अगर सम्पत्ति बल-कारखानों के रूप में बढ़ाई जा रही है, जहाँ कि उत्पादन होगा तो इनको कर विमुक्त कर सकते हैं या कम कर लगा सकते हैं. सम्पत्ति कर भाय को असमानताओं को दूर करने का अच्छा माधन भी है

Capital Gains tax : कम-विकसित पंशेवर सम्पत्ति में व्यापार करने वालों (जमीन, मशीन, शेयर, प्रतिभूतियाँ, भूकान व अन्य सम्पत्तियों में व्यापार करने-वाले) पर भी अच्छी तरह कर लगा सकते हैं. Capital appreciation का अर्थ होता है सम्पत्ति का मूल्य बढ़ जाना. जैसे कोई 1,00,000 रु० की सम्पत्ति का मूल्य समय के अन्तर से बढ़कर 3,00,000 हो जाए तो इस प्रकार के काम पर अधिक कर लगाया जा सकता है.

Gift tax कम-विकसित देशों में भाय को बढ़ाने, असमानताओं को कम करने व मृत्युकर से बचन रोकने के लिए देश में उपहार करों को भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए.

कम-विकसित देशों में अप्रत्यक्ष कर : उत्पादन कर, सेल्स टैक्स, आयात निर्यात कर : कम-विकसित देशों में अप्रत्यक्ष करों का कुल आय में महत्व बढ़ता जा रहा है. यू० एम० ए० में आय कर से 78% राज्य की आय प्राप्त होती है, और यू० के तथा जापान में यह प्रतिशत 57 व 50 है. भारत में 99% व्यक्ति आयकर नहीं देते तथा 93% आय पर आयकर नहीं पड़ता है. भारत में प्रत्यक्ष करों का कुल

1. 'साप्ताहिक-हिन्दुस्तान' में एकवार एक सुन्दर कविता आई थी जो इस प्रकार है .

बड़े बाप के बेटे हैं,
जब से पैदा हुए तैटे हैं

आय में जहाँ 1950-51 में योगदान 36% था वहाँ 1968-69 में वह घट कर 24% हो गया अर्थात् अप्रत्यक्ष करों का योगदान इस काल में 64% से बढ़कर 76% हो गया।

विकास के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों का योगदान बढ़ना चाहिए। भारत में ऐसा न होने का मुख्य कारण देश में कर बचन का होना, तथा लोगों का हिसाब न रखना ही है। इस स्थिति को दूर करना चाहिए।

अप्रत्यक्ष करों में Excise duties उत्पादन कर, सेल्सटैक्स, आदि कर आते हैं यह आवश्यक है कि कम-विकसित देश इन करों की लोचदार बनाएँ ताकि आय के साथ इन करों से आय बढ़ती रहे इन करों का मुख्य लक्ष्य देश में अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग व उत्पादन का कम रखना है ताकि देश में बचत हो और उनका प्रयोग ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से हो कि देश में विकास की नींव पड़े तथा अधिकतम लोगों की अधिकतम आवश्यकताएँ पहले मनुष्य हो 1 अप्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील होना चाहिए, अन्यथा उससे न केवल असमानताएँ बढ़ेंगी बल्कि विनियोजन का allocation (वितरण) भी श्रुति पूर्ण होगा, जो देश के लिए ठीक न होगा।

अप्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि इनसे सब वर्गों से आय प्राप्त हो जाती है, परन्तु बहुत ऊँचे अप्रत्यक्ष कर इन देशों में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। अगर वे अप्रगतिशील हैं तो उनसे देश में गरीब वर्गों की कठिनाई होगी और उनका उपभोग कम करने के स्थान पर बचतों को ही कम करेंगे अन्य वस्तुओं पर अधिक मात्रा में अप्रत्यक्ष करों से देश में माँग कम होने से उत्पादन हतोत्साहित हो सकता है, इसलिए 'बहुत अधिक' अप्रत्यक्ष कर भी नहीं होना चाहिए।

कम विकसित देशों में प्रत्यक्ष करों की आय की लोच कम है इस लोच को इकट्ठा तक लाना ही चाहिए ताकि कम-विकसित देशों में अप्रत्यक्ष करों को इतना अधिक लागाने की मजबूरी न रहे कम-विकसित देशों में जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय बढ़ती है उसी अनुपात में प्रत्यक्ष करों से आय नहीं बढ़ती थी जी० एस सहोता के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष करों की लोच 0.674 ही है इसीलिए अप्रत्यक्ष करों को इतना बढ़ाना पड़ रहा है।

अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि फिर भी होनार्थप्रवन्धन के कारण मूल्य वृद्धि से ठीक है।

1. George Bernard Shaw ने एक बार कहा था .

“वह राष्ट्र जो बच्चों के दूध का इन्तजाम करने से पहले शराब उत्पादित करता है वह बेवकूफ राष्ट्र है.”

जहाँ तक आयात व निर्यात करो का प्रश्न है, कम विकसित देशों को इन्हें अपने हित के अनुसार रखना चाहिए अधिकांश कम विकसित देश भुगतान असंतुलन से पीड़ित रहते हैं इसकारण यह आवश्यक होगा कि अनावश्यक तथा विलासिताओं की वस्तुओं पर या तो पूर्ण नियंत्रण हो या उन पर अधिक मात्रा में आयात कर लगाए जाएँ साथ ही इनको चोरी छिपे लाने को रोकने के लिये कठोर प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए. इन देशों में Demonstration effect imports (विदेशों की विलासिताओं की नकल के लिए आयात)

कम विकसित देशों को आयातीत मशीनों तथा आवश्यक कच्चा माल पर कम आयात कर लगाना चाहिए ताकि औद्योगीकरण में आसानी हो. आयातीत कच्चे माल से बने सामान को निर्यात करना हो तो आवश्यकतानुसार (अगर वस्तु की विदेश में माँग लोचदार हो) आयात ड्यूटी वापस भी की जा सकती है

निर्यात करो को भी आवश्यकतानुसार निर्धारित करना चाहिए अगर निर्यातीत वस्तुओं की विदेशों में बेलोचदार माँग है तो निर्यात कर अधिक रखना चाहिए बहुधा विदेशी आयातकर्ता खरीदारों वृज एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं (Monopsonistic or oligopsonistic combines) और कम-विकसित देशों को कम भुक्त्य देते हैं कम विकसित देश भी इसी प्रकार के Monopolistic combines एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं लोचदार माँग की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम रखना चाहिए

लाभ पर कर विदेशी विनियोजकों पर कर

लाभ पर कर तथा विदेशी विनियोजकों के लाभ के प्रति भी Pragmatic approach या यथासंगत नीति अपनाना चाहिए. कम विकसित देशों में पूँति की बेलोचपन से मूल्य बढ़ जाते हैं ऐसे समय में उत्पादनकर्ता व व्यापारी अधिक लाभ कमा लेते हैं कम विकसित देशों इस प्रकार के 'Excess' profits पर (या 'अतिरिक्त' लाभ पर) अधिक कर लगाना चाहिए परन्तु अगर इस अतिरिक्त लाभ को पुन वास्तविक विनियोजन वृद्धि में लगाया जाता है तो फिर उस पर कर सबधी छूट मिलना चाहिए अन्यथा देश में बचतों व पूँजी निर्माण रुकेगा. भारत में Super profit tax, (अत्यधिक लाभ पर कर) 1 अप्रैल 1963 को बची हुई आय पर (कारपोरेशन कर देने के बाद बची आय पर) 50% दर से लगाया, वशर्ते कि यह आय Paid up जमा पूँजी तथा reserves या जमा-कोष से 6% भाग से अधिक हो इसकी दर को इस प्रकार लगाया गया अगर बची हुई आय जमा पूँजी व जमाकोष के 10% से अधिक हो तो 60% कर

के रूप में देना था। वित्तमंत्री ने उस समय आशा व्यक्त की थी कि इससे अत्यधिक लाभ कमाने और मूल्य बढ़ाने की प्रवृत्ति स्केगी। परन्तु वित्तमंत्री ने अपनी भूल अगले ही वर्ष स्वीकार की और यह देखा गया कि इससे औद्योगिक विकास अवृद्ध हुआ। बाद में इस कर के स्थान पर Surtax on profits of joint stock companies लगाया गया इससे देश में पूँजी आधार में वृद्धि हुई (Capital base was widened) और कर अधिक न्यायपूर्ण हुआ और कर की दर को भी कम कर दिया गया।

प्रो० ल्यूस ने भी इसी प्रकार कहा है

“High taxes on profits will destroy development if the proceeds of the taxes are spent by the state on Current purposes, instead of being saved and invested productively, and if the managerial classes are not rewarded both financially and socially”

इसलिए ‘बहुत अधिक’ लाभों पर कर लगाना चाहिए परन्तु लाभ ही पूँजीनिर्माण का स्रोत होते हैं इसलिए लाभ व लाभ कमाने की इच्छा को ही समाप्त कर देना चाहिए।

विदेशी कम्पनियों का जहाँ तक प्रश्न है वहाँ हमको यह देखना चाहिए कि उनपर इतना कर न लगे वे अपनी पूँजी वापस ले जाने का सोचें या और पूँजी न लाएँ, परन्तु उन्हें शोषण नहीं करने देना चाहिए। शोषण क्या है, यह तो परिस्थितियों के अनुसार ही जाँचा जा सकता है। विदेशी विनियोजक पूँजी लाते हैं, तकनीकी जानकारी लाते हैं, अपने विश्वव्यापी सम्पर्क से सामान को निर्यात करके विदेशी मुद्रा लाते हैं, इसलिए इन्हें विकास में सहायता के अवसर देना चाहिए।

II A (c) करो की अधिकता-विकास के लिए घातक .

श्री बी. आर. शेनाय करो की अधिकता को विकास के लिए घातक मानते हैं। श्री शेनाय का कथन है कि करो की अधिकता से बचते घटती है और सामाजिक पूँजी निर्माण भी कम हो जाता है राज्य जो धन करो के रूप में लेता है उसका अधिक-काश भाग तो सार्वजनिक उपयोग में व्यर्थ चला जाता है। श्री शेनाय का कथन है कि भारत में ही 1960-61 से अभी तक (1968) सार्वजनिक उद्योगों में पूँजी

निर्माण के रूप में सार्वजनिक आय का केवल 38% ही प्रयोग में आया. अगर इसी धन को जनता के हाथों में रहने दिया जाता तो कम से कम 25% भाग अवश्य ही पूँजी निर्माण के कार्यों में ले लिया जाता.

इस आधार पर, श्री शेनाय का कथन है, हर 100 करोड़ रु० के कर लगाने से निजी क्षेत्र की 25% बचत कम हो जाती है जबकि राज्य में केवल 3.8 करोड़ रुपये का पूँजी निर्माण हो पाता है. इस प्रकार से राज्य के द्वारा 100 करोड़ रु० की सार्वजनिक आय वृद्धि से 21 करोड़ रुपये की बचत की हानि होती है. या अन्य शब्दों में, अगर देश में 100 करोड़ रु० के कर कम कर दिए जाएँ तो 21 करोड़ रु० की बचत समाज में बढ़ जायेगी.

श्री शेनाय ने हिमाव लगाया कि अगर भारत में कर 1959-60 के स्तर पर रहते जो निजी क्षेत्र की आय, कर देने के बाद, 9800 करोड़ रुपये से अधिक होते और 1966-67 तक हर वर्ष 412 करोड़ रुपये का पूँजी निर्माण अधिक होता.

“अगर किसी भी देश में विकास करना लक्ष्य है तो वह देश समाजवादी कर प्रणाली नहीं अपना सकता.”

भारत में, श्री शेनाय ने बताया, स्वयं 1961, 13 मार्च को भारत के वित्तमंत्री ने राज्य सभा में स्वीकार किया था कि भारत में “15 या 20% व्यक्ति अपनी आय का 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) करो में दे रहे हैं” यह शोषणात्मक कर प्रणाली भारत के विकास के लिए घातक है. एक कम-विकसित देश स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में इस प्रकार के करो से कभी नहीं पहुँच सकती.

भारत में उच्चतम कर की सीमान्त दरें नार्वे, स्वीडन व यू० के० भी ज्यादा हैं और जर्मनी तथा यू० एस० ए० से तो बही ज्यादा है.

पश्चिमी जर्मनी¹ में जो आर्थिक क्रान्ति आई है उसका मुख्य कारण करो की कमी रही है उसके मुख्य कारण ‘राज्य द्वारा व्ययों में कमी’, ‘50% से करो का अधिक न होना’ तथा ‘करो में भिन्न-भिन्न प्रकार की छूटें देना है’ प्रो. शेनाय का कथन है कि अगर कम-विकसित देशों में विकास के लिए विनियोजन को प्रोत्साहन देना है तो व्यक्तिगत कर व कम्पनी करो को बहुत कम रखना चाहिए.

1. Palkhiwala : op. cit. इसी कारण को “Most Taxed Nation in the world” कहते हैं.

2. B. R. Shenoy : op. cit.

प्रो. एक ए. हायेक भी बहुत प्रगतिशील करो को विराम में बाधक मानते हैं। श्री शेनाय का कथन है कि प्रगतिशील करो से उत्पादन हतोत्साहित होता है तथा बचतें व पूँजी निर्माण कम होते हैं, साहसियों और व्यापारियों की प्रेरणा कम होती है, उनकी आगे की उन्नति रुक जाती है प्रगतिशील कर वर्मण्यता, कार्य-क्षमता, मेहनत, लगन तथा समृद्धि पर कर है श्री शेनाय के शब्दों में

“Progressive taxation is a tax on initiative, talent and efficiency. It penalises successful entrepreneurs. It violates the basic doctrine of equality of all before the law. It amounts to paying progressively less for more work by men of the highest productivity It checks capital formation, deprives the society of the full production progressive taxation stifles dynamism of vertical mobility.”

श्री शेनाय तथा अन्य अर्थशास्त्री एक सीमा के बाद समानुपातिक कर चाहते हैं तथा वे चाहते हैं कि राज्य सुरक्षा, न्याय, व्यवस्था, मुद्रा चलन, आधारभूत याता-यात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन तथा कृषि सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त हर क्षेत्र से धीरे धीरे निकल जाए।

II. B : कम-विकसित देशों के लिए सार्वजनिक व्यय करने की नीति व विकास

आज के युग में सार्वजनिक व्ययों की मात्रा व क्षेत्र दोनों में वृद्धि हो रही है। आज समस्त राज्यों में, चाहे वहाँ केन्द्रीय सत्ता प्रणाली हो या विकेन्द्रीय सत्ता प्रणाली हो, चाहे वह छोटा राज्य हो या बड़ा, चाहे वहाँ शान्तिप्रिय सरकार हो या मुद्र-

1 देखिये

- (i) Ludwig Erhard “Prosperity through competition” London 1960 p. 19-24.
- (ii) Lawrence Festing “One Exports Almost Ruined Germany” In ‘Freeman’, August, 1961.
- (iii) अन्य वे अर्थशास्त्री जो प्रगतिशील करो के खिलाफ हैं J. S. Mill (Jr.), Blum, Kalven, Milton Friedman, F. A. Hayek, H. L. Lutz, Lord Lionel Robbins and David Mc Cord Wright.

प्रिय, बढ़ते हुए मार्जिनल व्यय की प्रवृत्ति निश्चित रूप से मौजूद रहती है। दुर्भाग्य से आज कम विकसित देशों में सुरक्षा व्ययों के बढ़ने की प्रगति बढ़ रही है। आज के युग में कम-विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण तथा अधिकाधिक प्रयोग, उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर (जैसे कारखाने स्थापित करना, जंगल लगवाना, भूरक्षण बजर जमीन पाटना, बाढ़ नियन्त्रण, सामाजिक व आर्थिक सिरोपरी सुविधाओं के विस्तार (यातायात व संचार के साधनों में विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास) तथा आधारभूत उद्योगों तथा Public utilities सुविधाओं में व्यय करना पड़ता है। राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण कार्य भी बढ़ गए हैं।

कम विकसित देशों में इन्हीं व्ययों की वृद्धि हुई प्रवृत्ति के कारण ही अधिकाधिक कर लगाये जाते हैं। विकास में सार्वजनिक व्ययों का प्रभाव धरमन्त महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक व्ययों से निजी उत्पादनकर्ताओं व विनियोजकों को जो सामाजिक व आर्थिक सिरोपरी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं उनसे न केवल निजी क्षेत्र का विनियोजन बढ़ता है चरन् वे स्वयं बचतें बढ़ाकर पूँजी निर्माण करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेन्शन आदि पर व्यय से देश की उत्पादन शक्ति का विकास होता है। मार्जिनल व्यय से पूँजी निर्माण बढ़ता है और इसके बढ़ने से जो निजी क्षेत्र के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, उससे देश में कुल विनियोजन वृद्धि से देश में रोजगार बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय से वास्तव में देश की कार्य करने व बचत करने की योग्यता में वृद्धि होती है। राज्य के मार्जिनल से बचत व विनियोजन में समन्वय आता है। पिछड़े वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान देकर देश में विकास का भ्रमतुलन दूर होता है और सतुलित विकास होता है।

राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि, सुरक्षा, प्राकृतिक साधनों का विकास, अनुसंधान, तथा संचार के साधनों के विकास से समाज में उत्पादन व उत्पादकता, विनियोजन तथा रोजगार, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय का महत्व हम इस बात से तब अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब कि हम यह विचार करें कि अगर राज्य यह सब व्यय न करता तो क्या स्थिति होती।

सार्वजनिक व्यय से हम व्यापार चक्रों की हानियों से बचते हैं तथा इससे समाज में वितरण की समानता आती है और हम समाजवाद के निकट आते हैं। सार्व-

जनिक व्यय से हम नियोजित तथा नियन्त्रित पूँजीवाद खाते हैं और देश में गरीबों के लाभ के लिए नियन्त्रण लाकर सामाजिक कल्याण बढ़ाते हैं.

कभी-कभी राज्य के सार्वजनिक व्यय के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. अनियमित व्यय से मुद्रा स्फीति हो सकती है, फिर कर का भार बढ़ता है. देश में बहुधा लाभ में न चलने वाले उद्योगों की स्थापना हो जाती है. भ्रष्टाचार के कारण राज्य का बहुत धन गवन होने लगता है और जैसे पानी में मछली को पानी पीने से नहीं रोक पाते. वैसे ही यह भ्रष्टाचार नहीं रोक पाता. सामाजिक सुरक्षा का व्यय जहाँ अच्छा है वहाँ कार्य करने और बचत की इच्छा को कम भी कर सकता है. राज्य के व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा, निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा की प्रतियोगी वस्तु या पूरक वस्तु है. अगर राज्य की वस्तु प्रतियोगी वस्तु है तो निजी क्षेत्र में उत्पादन कम होगा और अगर वह पूरक है तो उत्पादन कार्य बढ़ेगा. कभी-कभी तो एक व्यय किसी का पूरक व किसी का प्रतियोगी व्यय हो जाता है. उदाहरणतः राज्य द्वारा पुलिस के कार्यों पर किये जाने वाले व्यय से तालों के उत्पादनकर्ताओं को हानी होती है पर इससे निजी सम्पत्ति सचिit करना लाभदायक सिद्ध हो जाता है. उसी प्रकार से अच्छी सड़कों से जहाँ कार खरीदकर रखना कम खर्चोला हो जाता है वहाँ टायर के उत्पादनकर्ताओं को हानि होती है.

प्रो. यूगो पापी ने इसलिए कहा है

“अधिक सार्वजनिक व्यय के लिए अधिक कर लगाने पड़ते हैं इससे देश में बचत व पूँजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है. अत्यधिक सार्वजनिक व्यय से उन वस्तुओं की माँग उत्पन्न हो जाती है, जो पैदा ही नहीं हुई हैं.”

See also :

1. Musgrave : op cit : p. 251-56.
2. Taylor : op. cit : p. 68-71.
3. Keynes : op. cit.
4. U. Hicks : Public Finance ch. II.
5. Lutz : Public Finance p. 164-7.
6. Brownlee & Allen : Economics of Public Finance pt. III. ch. 10.
7. G. Ugo Papi, "Internal Faction Causing and Propagating Inflation from I. E. A. "Inflation."
8. प्रो० एस० श्रीवास्तव : "मुद्रासांख्यिकी" अध्याय 5, 6, 7.

सार्वजनिक व्यय संबंधी नीति :

सार्वजनिक व्यय संबंधी नीति ऐसी होनी चाहिए जो प्रगतिशील हो, अर्थात् गरीब लोगों की अधिक लाभकारी हो, इसे आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने तथा जनशक्ति की किम्मा सुधारने में व्यय करना चाहिए। राज्य को उन्हीं क्षेत्रों में व्यय करना चाहिए जहाँ निजी क्षेत्र वाले व्यक्ति व्यय नहीं करते। आधुनिक युग में जन-सहभागिता नियंत्रण या परिवार नियोजन इत्यादि का अच्छा उदाहरण है व्यय को दूर-दर्शिता, बुद्धिमत्ता, चतुराई, विचार तथा विवेक पूर्णरूप में खर्च करना चाहिए सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक सिरोंपरी, रोजगार व ट्रेनिंग वृद्धि, असमानताओं को दूर करने संबंधी व्यय विकासवर्द्धक होंगे

सबसे मुख्य बात यह होना चाहिए कि राज्य के सार्वजनिक उद्योग लाभ पर चले, अन्यथा ऐसे उद्योगों की स्थापना ही न की जाए

II C कम-विकसित देशों में ऋण व्यवस्था संबंधी नीति

कम विकसित देशों में भी, विकसित देशों की भांति सार्वजनिक ऋण व्यवस्था राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण अंग होते हैं और विकास प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं सार्वजनिक ऋण भी माध्यम के साधन हैं, कम विकसित देशों की सरकारें आधुनिक युग में Pay-as-you go finance (चालू व्ययों) तथा emergency expenditure (संकटकाल के) अतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में उत्पादक कार्यों (direct productive works) तथा सामाजिक व आर्थिक सिरोंपरी (Economic and social overheads or external economies) प्रदान करने के लिए ऋण लेती हैं।

इन कार्यों के लिए जब ऋण लिया जाता है तो करो का भार कम रखा जा सकता है, कर देने से करदाताओं की आय कम होती है परन्तु ऋण देने से वे जो बचत करते हैं उसमें रवैच्छा होती है तथा विकास प्रक्रिया में जो जनता के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है वह प्राप्त होता है तथा उनसे विरोध नहीं मिलता

आज कम विकसित देशों में सामाजिक सुधार कार्यों के लिये भी ऋण लिया जाता है, आज "उत्पादक" शब्द का अर्थ व्यापक है, Musgrave के शब्दों में

पुराने अर्थशास्त्री सामाजिक सुधार कार्यों के लिए ऋण लेने से खिलाफ थे,

वेस्टाविल का कथन था :

“राष्ट्रीय सस्कृति, शिवा तथा सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देना आवश्यक है परन्तु इतना आवश्यक नहीं है कि राज्य ऋण लेकर इसे बढ़ाए।”

"We do not have the cement and steel concept of development" यह अत्यन्त विरोधाभास की बात होगी कि हम शराब के कारखाने से शराब के उत्पादन के कारण इसे 'उत्पादक' समझे तथा शिक्षा प्रसार को उत्पादक न वहे. आज कम-विकसित देश Capital budget पूँजी बचत तथा चानू बजट दोनों के लिए ऋण लेने हैं आज इस विचार को नहीं माना जाता कि राज्य के ऋण व सम्पत्ति बराबर होना चाहिए, क्योंकि राज्य की "सम्पत्ति" बल और कारखाना की वृद्धि से ही नहीं बढ़ती वह तो देश की जनता के उल्लत होने से भी बढ़ती है.

Musgrave ने इसीलिए कहा है

"While the net-worth approach (assets being equal to debts) might serve to sell businessmen on the idea of unbalanced budgets, this is a point in fiscal politics rather than fiscal economics."

कम-विकसित देशों में आज ऋणों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने, पूँजी निर्माण, उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार व सामाजिक व आर्थिक सिरोंपरी उत्पन्न करने के लिए लिया जाता है जो कि उचित है विदेशी ऋणों से देश में मशीनें, आवश्यक कच्चा माल, तकनीकी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को आयात कर सकते हैं जिससे देश में उद्योग-विशेष रूप से निर्यात बर्धक तथा आयात प्रतिस्थापक स्थापित किए जा सकते हैं और देश की वाद में विदेशी आय बढ़ सकती है.

इसलिए कम-विकसित देशों में विकास के शुरु के काल में जो अधिक विनियोजन की आवश्यकता पड़ती है उसका एक भाग ऋण के द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए और दस या पन्द्रह वर्षों के चक्र से सतुलित बजट बनाएँ.

ऋण को वापस करने तथा भार को कम रखने संबंधी नीतियाँ :

कम-विकसित देश ऋण वापस करने की जानी भानी तरीकों के यथोचित समीक्षण द्वारा ऋणों को वापस कर सकते हैं अनुत्पादक ऋणों को यथा शीघ्र वापस करना चाहिए और उत्पादक ऋणों को सम्पत्ति के कार्य-काल में ही वापस कर देना चाहिए. इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ऋण वापस करने

की बहुत जगहों में अधिकाधिक धन को ऋण परिशोध कोष में रखा (और रखा रहने दिया) तो इससे मदों व बेरोजगारी फैलेगी और विकास कार्य आगे नहीं बढ़ सकेगा हमको ऋण कम करने की चिंता से अधिक बेरोजगारी दूर करने व विकास करने की चिन्ता होनी चाहिए

आवश्यकतानुसार राज्य ऋणों को नये ऋणों में भी परिवर्तित कर सकती है अगर कम-विकसित देशों में आयोजन व विकास के शुरु काव में मुद्रा स्फोटि फैलने से व्यापारी वर्ग ने बहुत कमाया हो तथा राज्य उनके साभा पर पर्याप्त मात्रा में कर न लगा सका हो तो राज्य दबा समय पूँजी कर" लगाकर (Capital levy) भी ऋण चुका सकता है इससे कर बचन करनेवालों, सट्टे व चोरी से सम्पत्ति बनानेवालों पर अपेक्षित कर लग जाएगा मूल्य गिरने के काल में इन ऋणदाताओं को लाभ होता है और राज्य (वास्तव में कर दाताओं) को हानि होती है मुद्रा स्थिति के बाद इस प्रकार गे ऋण चुकाये जाना चाहिए, परन्तु इस गदब में यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी व्यक्तियों पर ही यह कर लगे. इससे देश के मुद्रा बाजार में कम एव आतंक का बातावरण न फैले, पूँजी निर्माण, निर-व्ययिता व उत्पादन कम न हो और न विदेशों से पूँजी जाए अन्यथा यह उस प्रकार होगा जैसे कि "कोई अपना भोजन बनाने के लिए अपने ही घर को जलाए" (It would be like burning your own house to roast your pig).

ऋण के भार को कम रखने सम्बन्धी नीति *

(A) सार्वजनिक ऋणों के भार को कम रखने के लिए सर्वप्रथम तो हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि स्वयं ऋण भार कम करती है. यह प्रत्यक्ष रीति या तरीका व परिणाम होता है Evsey domar ने इसी लिए कहा है

‘ वे समस्त व्यक्ति जो राष्ट्र के ऋणों होने के कारण भाग्य देते हैं, भेस निखते हैं, फिऊ करते हैं तथा रात वगैर सोये बेचैनी से गुजारते हैं, अगर वे उससे आधा समय ही राष्ट्रीय आय बढ़ाने में लगाएँ तो वे ऋण समस्या के हल करने में सहायक होंगे ”

E D. Domar, The Burden of the Debt and the National Income, American Economic Review, Dec 1944, p 423

Quoted from "The Economics of Public Finance by P E. Taylor

ऋण का भार कम रखने के दो प्रमुख उपाय और हैं

- (1) सर्वप्रथम ऋणों की व्यवस्था ऐसी हो कि ऋण गरीब से अधिकाधिक प्राप्त हो (जैसे अल्प वचत योजनाओं से) इससे गरीब वर्ग ब्याज प्राप्तकर्ता के रूप में आयेंगा यह बहुत अधिक सम्भव नहीं होता क्योंकि गरीबों से अधिक ऋण देने की क्षमता अमीरों की होती है
- (11) दूसरे करो की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि देश में धनी व्यक्ति अधिग्रहण कर दें इससे ऋण व्यवस्था देश में राजकोपीय नीति के समानता लाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगी.

इसकी उल्टी व्यवस्था नहीं होना चाहिए अमर ऋण दायक तथा कर देनेवाले अर्थात् ब्याज प्राप्तकर्ता और ऋणदाता एक ही वर्ग के व्यक्ति हैं तो ऐसी ऋण व्यवस्था से न तो लाभ होगा और न भार ही पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में ऋण का भार मानसिक भार होगा क्योंकि ऋणदाता जिस लाभ की आशा करते थे वह उन्हें प्राप्त नहीं होती है

(B) कम-विकासित देशों को ऋण व्यवस्था मुद्रा स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए इसका अर्थ होता है कि मुद्रा स्थिति काल में राज्य को अतिरिक्त क्रयशक्ति को खींचने के लिए ऋण लेना चाहिए. इस संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ ऋण देने से मुद्रा स्थिति कम होती है वही ऋणों के बने रहने से मुद्रा स्थिति फैलती है यह इसलिए होता है कि राज्य के ऋणदाता जो प्रतिभूतियाँ अपने पास रखते हैं उन्हें वे आवश्यकता पड़ने पर भुना कर देको से और उधार ले सकते हैं ये प्रतिभूतियाँ Money sitting कहलाती हैं इस प्रकार से दीर्घकाल में पुनः मुद्रा स्थिति फैल सकती है

(C) ऋणों का भार कम रखने लिए¹ जिन कार्यों में ऋण का प्रयोग किया जाता है उनका Gestation period या फल दायक काल के घटाने का काल कम होना चाहिए

जहाँ तक विदेशी ऋणों का प्रश्न है इस संबंध में यह नीति होना चाहिए कि इन ऋणों का सदुपयोग देश में आयात हतोत्साहित व निर्यात प्रोत्साहित करनेवाले उत्पादक कार्य स्थापित हो

अनिवार्य बचतें ?

कम विकसित देशों में बहुधा अल्प बचतों, तथा राज्य के ऋणों से पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आए तो राज्य को अनिवार्य रूप से ऋण लेने की बात सोचनी चाहिए. Nurkse के अनुसार

“अनिवार्य बचतें करो का उत्तम विकल्प है, इनसे आय भी होती है और इनका दुष्प्रभाव कार्य करने की इच्छा व शक्ति पर नहीं पड़ता.”

भारत में भी “अनिवार्य बचत योजना” शुरू की गई थी जो अब केवल बड़ी आय वाले तक (Annuity Deposit Scheme) सीमित है. अनिवार्य रूप से बड़े हुए महंगाई भरो का हिस्सा प्रावोडेन्ट फंड में लगाना भी इसी प्रकार की नीति है

ग्रामीण क्षेत्र :

कम-विकसित देशों में, जैसा कि हम देख चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र राज्य की आय में कम योगदान करता है आज बहुत से कम-विकसित देश ग्रामीण जनता पर प्रशासनिक कठिनाइयों व राजनीतिक कारणों (वहाँ के वोटों को खोने के डर) से कर पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाते. इसलिए इस क्षेत्र से कम से कम बचतें इकट्ठी आवश्यक की जानी चाहिए

यहाँ से बचतों का लेना केवल वैकिक कार्य ही नहीं है इसको राजकोषीय नीति का अंग भी बनाया जा सकता है



अध्याय : 7

विकास के लिए मूल्य नीति

Price Policy for Economic Growth

(A) Market mechanism vrs. Controlled prices

(B) Stable price level vrs. rising price level.

(A)

Market mechanism vrs. Controlled prices.

I. प्रस्तावना :

मूल्य का आर्थिक कार्य.

II. कृषिक्षेत्र में स्वतन्त्र मूल्य पद्धति या नियन्त्रित मूल्य पद्धति :

(a) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति के पक्ष में तर्क या नियमित नीति के विपक्ष में तर्क.

(b) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति के विपक्ष में या नियन्त्रित या नियमित मूल्य नीति के पक्ष में तर्क

(c) नियमित मूल्य या नियन्त्रित मूल्य.

(d) मूल्य नियमित होना चाहिए

(e) ग्यूनतम व अधिकतम मूल्य का प्रश्न

(f) मूल्य नीति positive (प्रत्यक्षालम्बक) होना चाहिए.

III. उद्योग क्षेत्र के लिए मूल्य नीति .

(a) स्वतन्त्र नीति के पक्ष में तर्क : हेरी श्री० जानसन व डा० खटखटे.

(b) स्वतन्त्र मूल्य नीति के विपक्ष में : रोजन्सरोन रोदान.

(B)

Stable price level vrs. rising price level.

विकास के लिए मूल्य नीति

Price Policy for Economic Growth

(A)

Market mechanism vs. Controlled prices.

I. प्रस्तावना :

The Role of Prices .

अर्थशास्त्रियों ने हमेशा Theory of price पर ध्यान दिया है, अर्थशास्त्रियों का सम्प्रदाय मूल्य स्तर में इतना अधिक रहा है कि हम Oscar Wilde (ओस्कर वाइल्ड) के परोक्षी को दुहरा सकते हैं कि अर्थशास्त्री वह है जो "who knows the price of everything and the value of nothing." मूल्य व विकास को अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने "मुद्रा स्थापति व विकास" के रूप में ही अधिकतर अध्ययन किया है परन्तु अधिक उपयुक्त अध्ययन यह होगा कि क्या रवतन्त्र मूल्य प्रणाली विकास के लिए आवश्यक है अथवा नियमित मूल्य प्रणाली आवश्यक है.

जैसा कि हम सब जानते हैं 'मूल्य' अर्थव्यवस्था के Signals हैं (यर्थात् जैसे रेल के ट्रे-साल सिगनल चलने व रुकने के संकेत देते हैं वैसे ही गिरते व बढ़ते मूल्य संकेत देते हैं) 'मूल्य' का मुख्य कार्य माँग व पूर्ति में संतुलन लाना है. अगर कभी किसी वस्तु की माँग अधिक या पूर्ति कम होने के कारण मूल्य बढ़ने लगे तो उत्पादनकर्ता स्वयं ही या तो पूर्ति बढ़ा देते हैं या माँग कम हो जाती है. इसके विपरीत मूल्यों का गिरना इस बात का संकेत है कि उस वस्तु विशेष की पूर्ति अधिक है और माँग कम है. मूल्य गिरने से उत्पादनकर्ता पूर्ति कम कर देते हैं और माँगकर्ता माँग बढ़ा देते हैं

मूल्यों में वृद्धि इस प्रकार से और वृद्धि होने को रोक्ती है और मूल्यों में गिरावट और अधिक गिरावट को रोक्ती है

मूल्यों के इन्ही उच्चावचनों के कारण उपभोगकर्ता अपने भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उपभोग को मात्रा निर्धारित करते हैं मूल्यों में ही फिर भिन्न-भिन्न वस्तुओं की

कुल व सापेक्षिक मात्रा निर्धारित होती है। मूल्य ही भिन्न-भिन्न क्षेत्रों व भिन्न-भिन्न उद्योगों में विनियोजन की मात्रा निर्धारित करते हैं। (They help in allocating scarce resources among various investment fields in optimum manner).

II. Market mechanism or price mechanism and development of agricultural sector. स्वतंत्र बाजार प्रणाली या स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली तथा कृषि क्षेत्र का विकास :

(a) पक्ष में तर्क :

बहुत से अर्थशास्त्रियों का विचार है कि कृषि क्षेत्र का विकास करना ही तो स्वतंत्र मूल्य प्रणाली से ही ऐसा हो सकता है। इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि अगर इन देशों में कृषि वस्तुओं के मूल्यों को स्वतन्त्र बाजार पद्धति के अनुसार निर्धारित होने की स्वतन्त्रता हो तो मूल्य बढ़ेंगे, किसी भी कम विकसित देश में विकास के युग के शुरू में आधारभूत उद्योगों के स्थापित करने तथा अन्य विकास कार्यों पर व्यय करने से देश में एक्कम मुद्रा प्रसार होता है। इस मुद्रा प्रसार से मूल्य स्तर घटता है और कृषि वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते हैं। कम-विकसित देशों में कृषि वस्तुओं की विकास के शुरू के काल में income elasticity of demand अधिक होती है। अर्थात् जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो वे अच्छा व अधिक खाने का सामान माँगते हैं। विकास के 'बहुत बाद के काल' में तो फिर वे आय बढ़ने पर मोटरें, रेफ्रिजरेटर्स आदि माँगते हैं और फिर कृषि पदार्थों की income elasticity of demand कम हो जाती है। इस कारण भी विकास के काल में कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं।

स्वतन्त्र बाजार या मूल्य पद्धति के समर्थकों का कथन है कि यह स्थिति कृषि विकास के लिए अत्यन्त लाभदायक होगी

- (1) इससे कृषकों को अधिक आय मिलेगी और सदियों से सोती हुई कृषि व्यवस्था में बढ़ते हुए मूल्यों की प्रेरणा से कृषक लोगों की आय वृद्धि होगी

इस अध्याय का अधिकार भाग उस अंग्रेजी लेख पर आधारित है जो कि लेखक ने 1966 में Vikram University Economists' seminar में पढ़ा था यह फिर एक पुस्तक "Economics of wages, Productivity and Employment" में भी शामिल किया गया था।

- (ii) उनकी इस आय वृद्धि से वे कृषि में उन्नति कर सकते हैं, कृषक अपने ऋण चुकाकर अपनी वचतों व पूँजी निर्माण बढ़ा सकते हैं, और कृषि की आवश्यक inputs या लागतें ले सकते हैं।
 - (iii) अप्रत्यक्ष रूप से यह ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण उन्नत करता है, जब कृषक स्वयं अच्छा खाएंगे, पहनेंगे, अच्छी शिचा लेंगे व अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करेंगे तो समस्त ग्रामीण जनता की उत्पादकता बढ़ेगी
 - (iv) इस मूल्य वृद्धि से न केवल अधिक उत्पादन की प्रेरणा मिलेगी वरन् इससे कृषक एक से अधिक फसलें उगाएँगे तथा तदनुसार सिंचाई आदि की सुविधाएँ बढ़ा लेंगे, इसी प्रकार से वे खाद्य तथा व्यापारिक फसलों में सतुलन लायेंगे
 - (v) स्वतन्त्र मूल्य या बाजार प्रणाली इसलिए भी आवश्यक होगी कि अगर ऐसा न किया गया तो विकास के दिनों में जहाँ द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के व्यक्तियों (Secondary and Tertiary sector) की वास्तविक आय बढ जाएगी, कृषि क्षेत्र के लोगों की वास्तविक आय नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए कृषिक्षेत्र की वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित नहीं होना चाहिए
- (b) कृषिक्षेत्र में स्वतन्त्र मूल्य व बाजार के विपक्ष में तर्क :
- कम-विकसित देशों में उपरोक्त नीति से गम्भीर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं
- (1) इन देशों में 80-90% व्यक्ति अपनी आय का 60-70% भाग खाद्यान्न पर व्यय करते हैं स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य बढ़ने से इन पर तो मृतभार पड़ जाएगा
 - (ii) कृषि वस्तुओं का जो मूल्य बढ़ेगा यह आवश्यक नहीं कि उस वृद्धि से कृषक पूँजी निर्माण ही करें अगर उन्होंने उसको अपव्यय कर दिया या अगर बड़े हुए लाभ को बीच के विचोर्लियों ने रख लिया तो उत्पादन वृद्धि नहीं हो पाएगी और मूल्य बढ़ते ही चले जाएँगे
 - (iii) कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से उद्योगों को बच्चा माल महँगा प्राप्त होगा और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत बढ़ेगी
 - (iv) कृषि वस्तुओं, विशेषरूप से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने से मजदूर लोग अधिक मजदूरी मांगेंगे और अगर उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई तो cost-push inflation या लागत-वृद्धि से मुद्रास्फीति फैलेगी

(v) कृषि पदार्थों के बढ़ते मूल्यों से सट्टे की प्रवृत्ति फैलेगी

"Profits will flow to speculators in towns and villages, whereas the farmers, specially the smaller ones, will feel acutely all the negative effects of the entire economy which are induced by a violent price increase of agricultural produce"¹

(vi) कृषि में बढ़ते हुए मूल्य की समस्या उस देश के लिए गम्भीर नहीं होगी जिसदेश को किसी प्रकार का विदेशी विनिमय का संकट न हो। ऐसा देश विदेशों से वस्तुएँ मँगा सकता है और मूल्य वृद्धि से निपट सकता है परन्तु अविश्वसनीय कम-विकसित देश तो विदेशी विनिमय के संकट में रहते हैं उनका यह संकट और बढ़ जाएगा, मूल्य वृद्धि से उनके निर्यात कम होंगे या कालान्तर में उन्हें अपनी मुद्रा का अव-मूल्यन करना होगा कम-विकसित देशों को यह समस्या और भी गम्भीर रूप से सामने आएगी अगर उनकी वस्तुओं की विदेश में माँग लोचदार है अथवा विदेशी खरीदार एकाधिकारी स्थितिमें है (When the purchasing countries are in monopsonistic or oligo-psonistic position).

(vii) कम विकसित देशों में बढ़ते हुए मूल्य बहुधा कृषकों को अधिक उत्पादन की प्रेरणा देने में भी सफल नहीं होते मूल्य वृद्धि से कृषक अपनी भिन्न-भिन्न उपजों की मात्रा को एवदम घटाने व बढ़ाते भी नहीं हैं और बहुधा यातायात, तथा अन्य सहायक चीजों के उपलब्ध न होने से कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती

(viii) कम-विकसित देशों में बाह्य मितव्ययिताओं के सृजन में (यातायात शक्ति की सुविधाओं का विकास) विनियोजन की बहुत आवश्यकता होती है श्री एल. के. झा (L.K. Jha)² का मत है कि इस प्रकार की स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली में सामाजिक ख़िरोपरि व्यय नहीं किए

1. Dr. O S Shrivastava "Economics of wages, Productivity & Employment" p 49

2. L. K. Jha's lecture at New Delhi—Ram Memorial lecture : Governor Reserve Bank, 20th April 1968.

जाएँगे 'Given the continuing shortage of capital it would be unrealistic to expect in foreseeable future that through the free play of the price mechanism and by allowing capital to be deployed with higher profits as the prime objective one would secure reasonable investment in sectors important from the point of view of overall growth or social benefit.'

- (1x) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति को तो हम उस देश में अपना सकते हैं जहाँ कि हमको आय व सम्पत्ति के वितरण को ठीक करने के बारे में कुछ नहीं करना है वहाँ मूल्यों के अनुसार उत्पादन होता है और मूल्यों के अनुसार उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं कम-विकसित देश यह पद्धति अपनाएँ तो बड़े हुए मूल्यों पर धनी लोग ही सम्पूर्ण पूंति खरीद सकते हैं और गरीब तो खरीद ही नहीं पाएँगे ; इन देशों में बेरोजगारी पहले ही मौजूद है और अगर मूल्य भी बढ़ने दिए गए तो गरीब तो भिस जाएँगे इसलिए नियन्त्रित मूल्य प्रणाली उचित होगी.

(c) Regulated prices vs controlled prices. नियमित मूल्य पद्धति उचित होगी, परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण नियन्त्रण जरूरी नहीं

हम यह देखते हैं कि कम-विकसित देशों में स्वतन्त्र मूल्य पद्धति में लाभ में अधिक हानियाँ होने की सम्भावनाएँ हैं इसलिए हमको यह पद्धति नहीं अपनाना चाहिए.

स्वतन्त्र मूल्य पद्धति का उल्टा नियन्त्रित मूल्य प्रणाली है इसका अर्थ है कि देश में Control 'कन्ट्रोल' होना चाहिए परन्तु सारी वस्तुओं के मूल्यों पर तो नियन्त्रण नहीं किया जा सकता

कन्ट्रोल की बुराइयाँ व समस्याएँ .

कन्ट्रोल व नियन्त्रित मूल्य पद्धति स्वयं कुछ समस्याएँ उत्पन्न कर देती है कन्ट्रोल करने के बाद तो वास्तव में मूल्य घटते नहीं हैं बल्कि बढ़ जाते हैं. कन्ट्रोल के दिनों में व्यापारी जमाखोरी करने लगते हैं और मूल्य बढ़ जाते हैं राज्य भी मूल्य नियन्त्रित रखने के लिए buffer stock या स्टॉक बनाता है और वह स्वयं जमा करने लगता है, और "यहाँ वह मरना हो जाती है कि पुलिस भी जोर बन

जाती है" ¹ ऐसे समय में राजनीतिज्ञ व 'लीडर' लोग भी कमियों व भावी कमियों को लेकर जोर शोर से भाषण करने लगते हैं जो आग में घी का काम करते हैं इससे सट्टेबाजों को और फायदा होता है

कंट्रोल या नियंत्रित मूल्य कभी कभी देश में बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देने हैं भारत में ही Agriculture Price Commission ने, बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या के निवारण हेतु, खाद्य क्षेत्र (food zones) बनाने की सिफारिश की और नियंत्रित मूल्यों की पद्धति को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया उसकी यह सिफारिश इस विश्वास पर आधारित रही कि अगर मूल्य स्वतन्त्र बाजार पद्धति पर आधारित रहे तो metropolitan centres या बड़े-बड़े शहरों में, जहाँ धन अधिक है, अधिकांश पूर्ति खिंच जाएगी, और छोटे शहरों व गरीब क्षेत्रों में पूर्ति कम हो जाएगी

भारत में जो कुछ हुआ उसने दिखा दिया कि इससे भिन्न-भिन्न राज्यों में ही मूल्यों में बहुत अन्तर नहीं पड़े वरन् एक ही राज्य के अलग-अलग जिलों में अन्तर रहे. ये अन्तर उत्पादन लागतों के अन्तर या यातायात लागत के अन्तरों पर आधारित नहीं थे वरन् कंट्रोल व नियंत्रण के कारण उत्पन्न थे. इस प्रकार के नियंत्रित मूल्यों व नियंत्रित वितरण के कारण भ्रष्टाचार, जमाखोरी, काला बाजारी व चोरी छिपे इधर उधर ले जाना पलपा. राशनिंग, कंट्रोल व नियंत्रित मूल्यों से उन लोगों को लाभ होता है जो नौकरशाही के निकट सम्पर्क में रहते हैं उन्हें प्रतिरिक्त 'कोटा' मिल जाता है और इन दिनों में वाली परमिटों की संख्या बढ़ जाती है.

जब खाद्यान्न के मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है तो कृषक व्यापारिक फसलों की खेती करने लगते हैं अगर किसी एक अनाज के मूल्य नियंत्रित करके उसे बेचा जाता है तो उसकी मांग में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है. ²

1. Dr O S Shrivastava - op cit . p 50.

2. भारत में जब कंट्रोल से गेहूँ मिलते थे, तो उनका भाव ज्वार, मक्का के तुल्य बाजार के भाव से कम था. मतीजा यह हुआ कि मक्का और ज्वार खाने वाले भी गेहूँ माँगने लगे और गेहूँ की पूर्ति विपन्नता और बढ़ गई

See also : Commerce Annual Number Dec. 1966, "Wanted . A Rational price policy" H T. Parekh General manager I C I. C I.

(d) Prices should be regulated, they should not be controlled.

राज्य को मूल्यों को regulate या नियमित करना चाहिए. उन्हें control या नियमित नहीं करना चाहिए. यह कार्य राज्य स्वयं भी एक पूर्तिकर्ता के रूप में कर सकता है जहाँ निजी क्षेत्र के व्यक्ति कृषि वस्तुओं का क्रय विक्रय करें वहाँ राज्य भी monopoly procurement या एकाधिकारी खरीदारी करके आवश्यकता पड़ने पर अर्थात् मूल्य अधिक बढ़ने पर स्वयं बेचना शुरू कर सकते हैं परन्तु ऐसा देखा गया है कि राज्य के पास साधन अधिक होने पर भी निजी क्षेत्र वालों को कृषक लोग फलान बेचना पसन्द करते हैं. वर्मा राज्य में जब राज्य ने सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं को बेचना शुरू किया तो निजी क्षेत्र के एजेंट लाइन में लगकर (क्यू में लगकर) सामान खरीदकर अपनी दुकानों में बेचते थे. वर्मा की सरकार ने फिर इन्हें पूर्ण तरह से समाप्त ही कर दिया. परन्तु कम-विकसित देशों में यह कार्य राज्य, सहकारी संस्थाएँ और निजी क्षेत्र सब मिलकर कर सकते हैं. निजी क्षेत्र के व्यापारियों को एकदम समाप्त करना उचित नहीं होगा. एक तो राज्य की इतनी क्षमता नहीं होगी कि वह समस्त व्यापारिक कार्यों का संचालन कर सके और फिर यह उसे बहुत महंगा पड़ेगा जिसका व्यय वह करो से ही पूरा करेगा. सहकारी संस्थाओं को भी नियमित रूप से कार्य करना चाहिए. श्री पाई, जो भारत के फुड कारपोरेशन के भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, के शब्दों में भारत में सहकारी संस्थाओं ने बहुधा उनसे अधिक मुनाफा कमाया है जितना कि निजी क्षेत्र के लोग कभी नहीं कमाते. देश में इस प्रकार से ऐसी विक्री व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कृषकों और उपभोक्ताओं के बीच कम से कम व्यक्ति हो तथा वे पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर कम में कम लाभ लें.

(e) Minimum or support prices or floor prices /Standard prices/and Maximum prices

कृषि के उचित व शीघ्र विकास के लिए न्यूनतम मूल्य व अधिकतम मूल्यों को निर्धारित करना पड़ेगा. अगर कृषि वस्तु मूल्य कम रहेंगे तो इससे

(i) उपभोग बढ़ेगा.

(ii) Inventory stock piling बढ़ेगा अर्थात् लोग जमा करेंगे.

(iii) कृषक भी स्वयं का उपभोग बढ़ा लेंगे. तथा

(iv) वे उत्पादन कम कर देंगे. इस तरह से एक न्यूनतम सीमा से मूल्य गिरने नहीं देना चाहिए.

राज्य को यह न्यूनतम मूल्य (Floor prices) कमल से पहले ही घोषित कर देना चाहिए. इनको पिछले चार वर्षों या तीन वर्षों के औसत से कुछ अधिक होना चाहिए इनको इतना होना चाहिए कि वे लागत व यातायात व्यय को पूरा कर सकें यह कार्य आसान नहीं है क्योंकि कम-विकसित देशों में input तथा output या लागत व उपज के सही आँकड़े उपलब्ध नहीं होते

“Not much is known about the input data, eg. it is very difficult to reckon in monetary terms such fixed costs & maintaining a peasant's family ”

अगर न्यूनतम मूल्य इतने रखे गए कि पिछड़े से पिछड़े किसान के लागत व्यय पूरा हो जाए, तो यह मूल्य बहुत अधिक रहेंगे इसलिए इनको इतने होना चाहिए कि Sub-marginal cultivators या अनुसीमान्त कृषक अपने उत्पादन में उन्नति करें

अगर मूल्य गिरने लगे तो राज्य को स्वयं खरीद करके न्यूनतम मूल्यों के स्तर से मूल्य गिरने नहीं देना चाहिए.

राज्य को इसी प्रकार से उपभोक्ताओं और उद्योगों के हित को ध्यान में रखकर “अधिकतम मूल्यों” को भी निर्धारित करना चाहिए अगर मूल्य इससे ऊपर जाएँ तो राज्य को अपने buffer stocks को बेचकर मूल्यों को नीचे खाना चाहिए.

(f) Positive policy

लेखक के मत से सर्वोत्तम मूल्य नीति वह होगी जिसमें सब पक्षों के हित को ध्यान में रखा जाएँ बहुत नीचे मूल्य कृषकों को हानिकारक है तो बहुत अधिक मूल्यों से उपभोगकर्ताओं, कच्चे मान के प्रयोगकर्ताओं तथा निर्यात व्यापार में हानि होगी नियन्त्रित मूल्य अल्पकाल के लिए डरूरी हो सकते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य तो उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें स्वतन्त्र मूल्य पद्धति कार्यान्वित हो सके.

दुर्भाग्य से अभी तक बहुत से कम-विकसित देशों ने buffer stock mechanism, साख नियन्त्रण, वितरण नियन्त्रण, तथा अन्य राजकोपीय व वित्तीय

See also -

“Rationale of Procurement Prices” S Venue Eastern Economist February 2, 1968

2. O. S. Shrivastava - op. cit 49.

नीति का सहारा लेकर कृषि क्षेत्र की वस्तुओं की मूल्य नीति को तय किया है। उचित नीति तो यह होगी कि वे देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाएं और उत्पादकता बढ़ाएं जिससे मूल्य नीति पर नियन्त्रण आवश्यक हो नहीं होगा।

देश में आन्तरिक मूल्य नीति विकसित देशों की तटकर नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर भी निर्भर होती है।

श्री एल० के० झा के भी इसी प्रकार के विचार हैं उनके अनुसार

“A successful price policy has to be conceived in a long term perspective, While we may not wish to leave our economy at the mercy of market forces, we should not hesitate to harness market forces to subserve our objectives. A well-conceived price policy should in the short run prevent the exploitation of the consumer in conditions of scarcity and in the longrun provide adequate inducement to the producer to step up his output”

III Price policy for industrial sector and for the economy in general औद्योगिक क्षेत्र तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य नीति

जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र के लिए क्या मूल्य नीति होना चाहिए इसके बारे में मतभेद है उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के लिए मूल्य नीति के बारे में भी मतभेद है। कम विकसित देशों के सवध में अधिकांश अर्थशास्त्री नियमित मूल्य नीति चाहते हैं।

(1) स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के पक्ष में - Harry G Johnson

हैरी जानसन चाहते हैं कि कम-विकसित देशों को चाहिए कि वे स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली में विश्वास रखें और देश में मूल्यों की माँग और पूर्ति में समन्वय लाने

L. K. Jha : op cit

Harry G. Johnson . “The Market Mechanism as an Instrument of Development ” From Money, Trade and Economic Growth George Allen & Unwin, London 1962 p 152-63 q. f. G. Meier : op. cit.

दें. उनका विश्वास है कि एडम स्मिथ की यह मान्यता कि नियंत्रित मूल्य भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता को उत्पन्न करने है आज भी ठीक है.

जानसन यह मानते हैं कि नियंत्रित मूल्य प्रणाली देश में धन की असमानताएँ नहीं बढ़ने देती वरन् वह तो गरीबों के हित को ध्यान में रखती है. जानसन का कथन है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से विकास पनपता है जबकि नियंत्रित मूल्य प्रणाली से धन का वितरण ठीक होता है, जानसन का विचार है कि कम-विकसित देशों को मुख्यतः विकास की ओर ध्यान देना चाहिए. उनका कथन है कि

"We should not worry too much about the distribution of income."

श्री जानसन का कथन है कि स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था का गुण है कि उससे देश के साधनों का उपयोग व उत्पादन तथा उत्पादन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उचित वितरण (Allocation) होता है. जिन चीज का मूल्य बढ़ता है उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है इस प्रकार से अगर किसी वस्तु की पूर्ति कम हो तो वह बढ़ जाएगी, अगर कुशल श्रमिकों को अधिक वेतन मिलता है तो अकुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग लेकर पूर्ति बढ़ाएंगे भिन्न भिन्न स्थानों व उद्योगों के बीच पूँजी वहाँ लगायी जाएगी जहाँ लाभ अधिक होगा और इस प्रकार स देश में न्यून पूँजी का अच्छा उपयोग होगा. स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के आधार पर पूँजी उन उद्योगों में लगाई जाती है जिनमें लाभ अधिक होता है. इससे पूँजीपति और पूँजी निर्माण करते हैं उनका कथन है

"अगर स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली ठीक तरह से क्रियान्वित है तो इससे देश में अर्थव्यवस्था में कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी तथा विकास भी होगा. इस संबंध में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इस प्रकार से विकास करने से देश में न तो केन्द्रीय संचालन संस्था की आवश्यकता होती है, न किसी जटिल कानूनी या प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है."

श्री जानसन यह मानते हैं कि मूल्य प्रणाली या बाजार व्यवस्था का पूर्ण रूप से स्वतन्त्र न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं होने, तो इसमें स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली को नहीं हटाना चाहिए वरन् उन दोषों व कमियों को दूर करना चाहिए. इसी प्रकार से कम-विकसित देशों में बाजार पूर्ण रूप से न तो सगठित रहते हैं और न ही उनमें पूर्ण प्रतिस्पर्धिता व पूर्ण प्रतियोगिता होती है. इस कारण ही राज्य को नियंत्रित मूल्य नीति नहीं अपनाना चाहिए वरन् राज्य को इन देशों में

बाजार व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, अगर बाजार मबधी सभी जानकारी सब लोगों को पूर्ण रूप में उपलब्ध हो तो स्वतन्त्र बाजार की क्रियाओं से कोई हानि-कारक प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकते, और वे फिर कहते हैं कि विकास के शुरू के काल में ही सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, सामाजिक न्याय की बात तो किसी विकास के बाद करना चाहिए :

“एक विकसित देश सामाजिक न्याय के खातिर थोड़े बहुत मात्रा में विकास का त्याग कर सकता है, किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय आय के स्तर नीचे हों तो इस काल समानता की बात महेगी पड़ेगी, हम सब जानते हैं कि विकास के लिए आकस्मिक लाभों की आकांक्षा अधिकता से होती है और यह आकस्मिक लाभ सभी अधिक हो सकता है जबकि इन देशों में बाजार प्रणाली स्वतन्त्र हो.”

श्री जागसम यह नहीं कहते कि मूल्य के सम्बन्ध में एकदम निर्वाधवादी नीति अपना ली जाए, वे तो यह चाहते हैं कि बाजार व मूल्य प्रणाली पर नियंत्रण के अकुश नहीं होना चाहिए, वरन् आयोजन का मुख्य कार्य ही स्वतन्त्र मूल्य व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए

Dr. Khatkhate

डा० खटखटे ने भारत के पिछले अनुभव के आधार पर यह कहा कि निर्यात मूल्य प्रणाली से बहुत ही निराशाजनक परिणाम हासिल हुए हैं, वे भ्रष्टाचार को फैलाने हैं, उन्होने कहा था

“At some stage of growth you have to jettison all price controls and allow the capitalism function to help growth.”

अर्थात्, “विकास के किसी अवस्था में यह आवश्यक हो ही जाएगा कि समस्त मूल्य नियंत्रणों को त्याग दिया जाए (Jettison का अर्थ होता है कि अगर कोई जहाज समुद्र में फँस जाए और फिर उसको चलाने के लिए उसे हट्का करने को सामान फेंक दिया जाए) और स्वतन्त्र पूँजीवादी व्यवस्था को विकास में सहायक होने दें”

Dr. Khatkhate भारत के रिजर्व बैंक में उच्च पद पर हैं, उनकी यह मम्मति उनकी निजी सम्पत्ति है और बैंक की नीति की छोटक नहीं है, उन्होने यह विचार उपरोक्त पृष्ठों में उद्धृत भोपाल में अर्थशास्त्रियों की सेमीनार में व्यक्त किए थे.

डॉ० खटखटे चाहते हैं कि देश में दुहरी मूल्य व्यवस्था रह सकती है। कुछ वस्तुएं जो गरीबों के उपयोग कि है उन्हें नियमित कर सकते हैं। अगर हम मूल्य नियंत्रित करें तो एक मात्रा में basic efficiency भी निर्धारित करना होगा।

(b) In favour of regulated prices - नियमित मूल्य पद्धति के पक्ष में: नियंत्रित मूल्य पद्धति के पक्ष में भी अर्थशास्त्री हैं, जिनमें Rosenstein Rodan के विचार यहां दिए जा रहे हैं।

Rosenstein Rodan :

श्री रोदान, जो सतुलित विकास पद्धति के प्रबल समर्थक हैं, स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के प्रभावशाली होने में बिश्वास नहीं रखते उनका विचार है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से कम-विकसित देशों में विकास नहीं हो सकता क्योंकि इन देशों में पूँजी बाजार बहुत ही अपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं उनका मुख्य तर्क यह है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से सामाजिक हित का विनियोजन नहीं होता। स्वतन्त्र बाजार व मूल्य प्रणाली देश में निजी क्षेत्र वालों को लाभ देती है उससे जो वे कमाते हैं उसे वे सामाजिक सिरोपरी व्यय में नहीं लगाते अर्थात् Social overheads में नहीं लगाने, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में व्यय होता है और इनमें धन लगाने में उन्हें लाभ नहीं होता

"Price mechanism works under the assumption of small changes, and where there is indivisibility or lumpiness of capital, price mechanism does not work. Price mechanism cannot equate private and social net marginal product"

"श्री रोदान" का विचार है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से उपयोग वस्तुओं का अच्छा वितरण हो सकता है परन्तु वह विनियोजन ठीक नहीं करती और न ही मौद्रिक सतुलन लाती है

"Price mechanism cannot equate aggregate supply and aggregate demand and then prices

"The flaw in the Mechanism of Market forces" Paul N Rosenstein Rodan, in Programming in Theory and in Italian Practice in Massachusetts Institute of Technology, Centre for International Studies, Investment Criteria and Economic Growth, Asia : 1961 p 19 22 See also quoted From G. Meier : op. cit.

cease to be reliable parameters of choice and the price mechanism breaks down.....it does not function in the fields of investment and monetary equilibrium ”

पुस्तक के वर्तमान लेखक का भी मत है कि पूर्णरूप से स्वतन्त्र मूल्य उचित नहीं है आज के युग में मूल्य नीति स्वयं उस देश की राजनीति से प्रभावित होती है। अगर देश में निजी क्षेत्र को विकास में अधिक योगदान का मौका दिया गया है तो मूल्य मुख्यतः अनियंत्रित होना चाहिए, फिर भी आज के युग में पूर्णरूप से अनियंत्रित मूल्य नहीं रखे जा सकते, राज्य को यह शक्ति होना चाहिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सके, अगर ऐसा न किया गया होता तो निजीक्षेत्र के उत्पादनकर्ता बहुत अधिक मूल्य ले लेते।

उदाहरणतया

“भारत में हम दवा उद्योग का उदाहरण सामने रखें तो हम पाते हैं कि भारत में Sulpha thalazole को 800 रु पाँउ बेचा जाता है जबकि हेफकीन इन्स्टीट्यूट में यह केवल 20 रु. पाँउ बनाया जा सकता था। इसी प्रकार से भारत में Tetracycline केपस्यूल 20 रु. की 16 बेची जाती है जबकि उसकी लागत केवल 2 रु. प्रति 16 केपस्यूल है। भारत में बहुत सी जीवन रक्षक दवाएँ अपनी लागत व्यय से 17 से 20 गुने अधिक मूल्य पर बेची जाती हैं बहुत सी कंपनियों के लाभ उनके लागत व्यय, अनुसंधान व्यय, विज्ञापन, तथा सेल्स व्यय सबको मिला देने के पश्चात् भी उनसे अधिक थे।¹

देश में मूल्य नीति हमेशा के लिए एक सी नहीं रह सकती, समय-समय पर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है कभी कड़े नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है, कभी नियमन से काम चल सकता है तथा कभी स्वतन्त्र मूल्य ठीक होंगे मूल्य नीति जो भी हो, यह आवश्यक है कि नीति ऐसी होना चाहिए कि उत्पादन में कमी नहीं हो।

दीर्घकाल में जहाँ तक हो सके पूर्ति में वृद्धि करके मूल्यों को स्वतन्त्र ही रखा जाना चाहिए। आज के युग में समाजवादी देश भी Price mechanism के महत्व को मानने लगे हैं

1. An article in Economic Weekly, Dec. 18, 1965 written by the Director of the Institute S. Hazra.

quoted From O. S. Shrivastava's op. cit. p. 52.

(B)

Price Stability vs Rising Prices for Growth¹

विक्रम के लिए स्थिर मूल्य या बढ़ते मूल्य

पिछले अध्यायो में² हम यह देख ही चुके हैं कि विकास के लिए न तो स्थिर मूल्य स्तर उपयुक्त और न ही मुद्रा स्फीति ही लाभदायक है बरन् धीरे-धीरे बढ़ने वाला मूल्य स्तर उपयुक्त है

Dr V. K. R. V. Rao के अनुसार

“A rigid stable general level of prices may be as much of a deadweight on economic growth as a rapidly rising price level.”

जब मूल्य बढ़ते हैं तो निश्चित आय पाने वालों का अहित होता है और वे अधिक आय या मजदूरी माँगते हैं और इससे लागत बढ़ती है और फिर मुद्रा स्फीति फैलती है और पुनः लागत बढ़ती है और मूल्य वृद्धि होती जाती है। अगर मूल्य नीति के साथ-साथ अन्य नीतियाँ इस प्रकार से क्रियाशील हो रही हों कि देश में उत्पादन भी बढ़ जाए (और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उत्पादकता बढ़ जाए) तो मूल्य वृद्धि Self perpetuating (स्वयं बढ़ने वाली) बरन् self-liquidating (स्वयं नष्ट होने वाली) होगी। मूल्य नीति की रोजगार, उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि में सहायक होना चाहिए

वास्तव में कम-विकसित देशों में धीरे-धीरे बढ़ने वाला मूल्य स्तर चाहिए। मूल्य नीति का प्रमुख अंग गरीब जनता के उपभोग की उत्पादक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित रखना है। अगर देश में मूल्य वृद्धि ऐसी विनियोजन के कारण है जिसका फलदायक बाल लम्बा समय बाद शुरू होता है तो देश में उतनी मात्रा में cash holdings बनना चाहिए।

कम-विकसित देशों में मूल्य वृद्धि की एक प्रवृत्ति ही होती है और यह जब तक चलती रहती है जब तक कि देश take-off stage को छोड़कर देश self-sustaining व self-accelerating (निरन्तर विकास) की अवस्था में नहीं पहुँच जाता।

1. पाठकों ने इस सम्बन्ध में (1) पूँजी निर्माण, (11) मौद्रिक नीति तथा (iii) राजकोषीय नीति के अन्तर्गत हम विषय पर पढ़ा है इसको हम Inflation and Growth के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं।
2. Dr. V. K. R. V. Rao . Price Policy and Economic Development in Essays in Economic Development

अध्याय : 8

राज्य का विकास में योगदान : राज्य प्रवर्तित विकास

The Role of Government in Growth Sponsored Growth

I प्रस्तावना

II. राज्य के विकास में प्रत्यक्ष व सक्रिय योगदान की आवश्यकता :

- (i) निर्वाधवादी नीति के दोषों को दूर करना.
- (ii) विकास की नींव रखना.
- (iii) सामाजिक कल्याण के लिए.

III. राज्य द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्य :

- (i) न्याय व व्यवस्था.
- (ii) पूँजी निर्माण करना

- (III) कृषि में क्रान्ति लाना
- (IV) साधनों का अनुकूलतम प्रयोग
- (V) जनसंख्या संरचना सुधार
- (VI) श्रम बाजार संगठन तथा साधनों में समन्वय
- (VII) आवश्यक मात्रा में विनियोजन
- (VIII) उचित मॉडल, राजकोषीय व मूल्य नीति
- (IX) विदेशी व्यापार व विनियोजन को प्रोत्साहन
- (X) पिछड़े वर्गों व इलाकों की समस्या
- (XI) महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन

IV राज्य के योगदान की सीमाएँ

,

Select references

- 1 The role of Government Herman Finer, Ch X Williamson & Bultrick op cit
- 2 Tokyo Conference on Growth A Paper on 'Sponsored Growth A challenge to democracy
- 3 D B Singh op cit ch XVI
- 4 A H Hansen Public Enterprise and Economic Development
- 5 Bayer and Yamey ch XI General Appraisal of the Role of Govt In influencing Economic Development and ch XII on function of Government op cit
- 6 A Lewis op cit ch VII Govt
- 7 Kindleberger op cit 125-132
8. Meier & Baldwin op cit p 366-372

अध्याय : 8

राज्य का विकास में योगदान :

राज्य प्रवर्तित विकास

The Role of Government in Growth
Sponsored Growth.

I. प्रस्तावना

“समझदार व्यक्ति इस वाद-विवाद में नहीं पड़ते कि आर्थिक विकास राज्य के कार्यों से होता है अथवा निजी क्षेत्र की रुचि व उत्साह से होता है. वे जानते हैं कि आर्थिक विकास दोनों के सहयोग से होता है, वे तो केवल उसके समिश्रण की मात्रा के बारे में ही विचार करते हैं. राज्य अगर सही मात्रा में सही कार्य करता है तो विकास होता है अगर राज्य गलत कार्य करता है या सही कार्यों को ही बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में करता है तो विकास रुकता है”

—आर्थर एयुस, (पृ० 377-408)

राज्य का योगदान कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए. इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद है कुछ अर्थशास्त्री जो साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में हैं, राज्य को विकास की पूरी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं उनका विश्वास है कि आज के युग में किसी भी कम विकसित देशों में आर्थिक विकास व आर्थिक कल्याण राज्य के द्वारा (सार्वजनिक उद्योगों के द्वारा ही) हो सकता है इसी मत के, कम उग्रवादी अर्थशास्त्री राज्य को मुख्य व निजी क्षेत्र को गौण स्थान देना चाहते हैं.

दूसरे मत के अर्थशास्त्री चाहते हैं कि राज्य कम-विकसित देशों में Pioneering (नींव डालने का) कार्य करें तथा देश में विकास की आधार शिला रखकर विकास क्षेत्र से निकल जाएं. अन्य अर्थशास्त्रियों का मत है कि राज्य को निजी क्षेत्र को ही विकास कार्य सौंपना चाहिए. राज्य को उमे सहायता देना चाहिए या आवश्यकता पड़ने पर उसका नियमन करना चाहिए.

आज अर्थशास्त्री Gerschenkron के इस मत से सहमत हैं :

‘विकास कार्यों को शुरू करते समय जो देश जितना अधिक पिछड़ा होता है, उसे उतना ही राज्य के कार्यों की आवश्यकता होती है।’

Kindleberger का भी कथन इस संवय में बहुत उपयुक्त है कि राज्य के या निजी क्षेत्र द्वारा विकास में महत्व का प्रश्न सद्दान्तिक नहीं है बरन् यह तो व्यावहारिक प्रश्न है, उनका कथन है

‘जब जनता का या स्वयं निजी क्षेत्र का हित, निजी क्षेत्र के विकास से सिद्ध होता है, तो निजी क्षेत्र को ही कार्य करने देना चाहिए, उन क्षेत्रों में जिनमें निजी क्षेत्र, जन हित के कार्य को नहीं कर सकता जहाँ निजी क्षेत्र बाह्य भित्तियुक्तियों का मूँढन नहीं कर सकता वहाँ राज्य को कार्य कर छाई पाटना चाहिए।’

वे इसे The Vacuum Theory of Government कहते हैं

II. राज्य के कार्यों का विकास में आवश्यकता

औद्योगिक क्रान्ति के बाद विकास की असीमित सम्भावनाएँ सामने आयीं। राष्ट्रीय आय कई गुनी बढ़ने लगी पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था ने सर्व-साधारण को भी राजाओं के समान धनी होने के अवसर दिए परन्तु यह सब होते हुए भी अप्रत्याशित समृद्धि के बीच अप्रत्याशित परीची उत्पन्न हुई। छोटे पैमाने के उद्योग तथा सबसे सम्बन्ध आर्थिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गई। एक ओर बहुत बड़े पैमाने पर कारखाने तथा घन और सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण हुआ दूसरी ओर सारे आर्थिक कष्ट केन्द्रित हो गए। गन्दे वस्त्रियाँ, बन्दे, बरीब व अशिक्षित लोग तथा शोषित मजदूरों व छोटे विकास व नौकर पेशा लोगों की समस्या बढ़ती गई।

कालान्तर में यह पाया गया कि स्वच्छन्द पूँजीवाद अधिक उत्पादन दे सकता है, तथा अधिक विकास की दर दे सकता है परन्तु इसमें सामाजिक व निजी हितों की एकरूपता नहीं रहती। राज्य के हस्तक्षेप के बगैर विकास में स्थिरता नहीं रहती, तथा साथ ही साथ बेरोजगारी, अर्थ बेरोजगारी व बरीबी बन्नी रहती है।

समाजवादी अर्थशास्त्रियों के प्रहार, मार्क्स का दर्शन तथा समाजवादी देशों में विकास का अपना अलग ढंग यह सिद्ध कर चुका था कि राज्य के हस्तक्षेप बगैर या तो स्थिर व स्थायी विकास होगा ही नहीं या फिर इस विकास में सर्वांगीण ब्यापण कदापि नहीं होगा।

1930 के वर्षों की महान् मदी तथा केन्म की विचारधारा ने राज्य के हस्तक्षेप व प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता को औद्योगिक क्रान्ति के बाद योरोपीय देशो ने कम-विकसित देशो में उपनिवेश कायम किये और जब वे आजाद हुए तो वे विकसित देशो के मुकाबले में काफी पीछे रह गए थे इन देशो में साहसियो तथा विकास के लिए आवश्यक पूंजी, संगठन व प्रशिक्षित श्रम शक्ति सब का अभाव था इन देशो में स्वतन्त्रता जिन नेताओ ने दिलाई, स्वाभाविक था कि जनता विकास का उत्तर-दायित्व, राष्ट्रियता की भावना से प्रेरित होकर, उन्हें ही सौंपे ये ही नेता मरकार चलाने लगे और विकास में राज्य के अधिकाधिक योगदान की स्थिति सामने आई कम-विकसित देशो में आधारभूत उद्योगो की स्थापना करने, कृषि की मदियो पुराने पिछड़ेपन से निकालने, देश में वचत, पूंजी निर्माण व विनियोजन में वृद्धि करने, देश को आर्थिक, राजनैतिक व सामरिक दृष्टिकोण से बलशाली बनाने, देश में जन शक्ति व प्राकृतिक साधनो का पूर्ण प्रयोग करने, देश में बाह्य मितव्ययिताओ का सुजन करने, देश में विदेशी विनियोजको व तकनीकी विशेषज्ञो का सहयोग लेने, देश में सतुलित विकास को उत्पन्न कर बढावा देने, तथा देश में सर्वांगीण विकास व कल्याण करने के लिए कोई भी साहसी या साहसियो का समूह योग्य न पाया गया और यह सब कार्य राज्य की ही जिम्मेदारी बने

Dr. Bright Singh के शब्दो में

“The need to telescope a hundred years progress into a decade, call for the state intervention in the matter of economic development”

आज के युग में राज्य अगर प्रत्यक्ष रूप में योगदान न भी दे तो भी राज्य के नियमन व नियंत्रण के कार्य ही इतने व्यापक हैं जितने कि कुछ सदियों पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे

आज के युग में राज्य के कार्य पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए नहीं, बरन् पूंजीवाद को कायम रखने के लिए ही जरूरी हैं

III. राज्य से अपेक्षित कार्य जो विकासवर्धक हैं

विकास के लिए राज्य द्वारा अपेक्षित कार्य क्या हैं ? इसके उत्तर में सही मायनों का पूरा “विकास का अर्थशास्त्र” लिखा जा सकता है लेखक ने अपनी एक पूर्व पुस्तक में लिखा था

“The responsibility of the government cannot

be easily defined. Infact, it is not possible to delimit its functions.”

फिर भी इस पुस्तक में राज्य द्वारा अपेक्षित कार्य, जो विकास प्रक्रिया शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा उसकी सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण में वांछनीय बनाने के लिए आवश्यक है, सूची व विस्तोषण नीचे दिए जा रहे हैं (इनमें से कुछ कार्यों पर पूरे अध्याय इसी पुस्तक में हैं)

(1) न्याय व व्यवस्था, जिसमें आवश्यक उत्पादन कार्य सम्पादित हो सके :

अगर राज्य को देश में विकास सम्भव बनाना है तो उसे देश में व्यवस्था, न्याय तथा ऐसे नियम बनाने होंगे जो सब नागरिकों को उत्पादन करने, अपनी मेहनत से कमाई गई पूँजी को बचाने, विनियोजित करने व सम्पत्ति बनाने में सहायक हो। इन्हीं आवश्यक कार्यों में मुद्रा व्यवस्था तथा नाप-तौल व्यवस्था भी शामिल हैं। आधुनिक युग में दुर्भाग्य से आज इसकी सर्वथा कमी है समाजवादी विचारधारा तथा राजनैतिक मतभेद व गन्दी पदलोपपत्ता के कारण इन देशों में आए दिन सैनिक व असैनिक क्रान्तियाँ होती रहती हैं तथा ताला बन्दी, हड़ताल व हिंसात्मक कार्यवाही चलती रहती है इसमें न केवल निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ता हतोत्साहित होते हैं वरन् स्वयं राज्य के क्षेत्र को गम्भीर हानि होती है (जैसे भारत में हर ऋगडे पर रेल सम्पत्ति को हानि पहुँचायी जाती है) अगर निजी क्षेत्र को कायम रखना है तो उसे लाभ कमाने का अवसर देना होगा

(11) पूँजी निर्माण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कार्य

जहाँ विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का 15% से 25-30% तक बचत कर लेते हैं वहाँ कम-विकसित देशों में यह प्रतिशत 5 से 10 तक ही रहती है। इन देशों को कम से कम 15-20% बचत कर के पूँजी निर्माण करना ही होगा। राज्य को इस सम्बन्ध में प्रयत्न व अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से राज्य को देश में

(1) मुद्रा प्रसार को रोकना होगा.

(11) स्वयं अपने अनावश्यक व अधिक व्यय को कम रखना होगा.

1. C. S. Shivaramaiah : op cit : p 43

2. See also : U N Measures for Economic Development in under developed countries

3. Vikrant : Reforms of Administration, planning and Its Implementation - Commerce Annual No 1966.

- (iii) देश के सार्वजनिक उद्योगों को लाभ या कम में कम वगैरहानि के चलाना होगा, अन्यथा वे पूंजी उपभोग के साधन बन जायेंगे
- (iv) देश में पर्याप्त मात्रा में कर लगा कर (मट्टों के लाभ, अनावश्यक व विलासिता उपभोग) स्वयं पूंजी निर्माण करना होगा
- (v) देश में वचनों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सस्यामों को शुरू करना होगा तथा अपनी मौद्रिक व राजकोपीय नीतियों द्वारा वचन व पूंजी निर्माण को सम्भव बनाना होगा

श्री आर्थर ल्युस ने राज्य के विकास में वृद्धि करने के लिए नौ कार्य बताया है, तथा उन्होंने वे भी नौ कार्य बताए हैं जिनसे विकास रुकता है। वे कार्य निम्न हैं

- (i) देश में सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करना
- (ii) देश में विकास की मनोवृत्ति का पनपाना.
- (iii) आर्थिक समस्याओं को विकास बर्धक बनाना
- (iv) साधनों का प्रयोग बढ़ाना
- (v) धन के वितरण को विकास में सहायक करना
- (vi) मुद्रा का नियंत्रण करना
- (vii) आर्थिक उच्चावचनों को नियंत्रित करना
- (viii) पूर्ण रोजगार की स्थिति लाना, तथा
- (ix) विनियोजन का स्तर बढ़ाना

विकास में अवरोध डालनेवाले नौ कार्य निम्न हैं

- (i) देश में व्याप, सुरक्षा व व्यवस्था को कायम न रख सकना
- (ii) देश में जनता को लूटना या कर व्यवस्था का दोषपूर्ण होना व प्रशासन का भ्रष्ट होना
- (iii) देश में एक वर्ग को दूसरे वर्ग का शोषण करने देना
- (iv) देश में विदेशी विनियोजकों की सहायता न लेना या उन्हें कार्य न करने देना
- (v) देश में विनियोजन को अलाभप्रद ढंग से करना
- (vi) देश में बहुत अधिक निर्वाधवादी नीति अपनाना
- (vii) देश में बहुत अधिक नियंत्रण की नीति अपनाना
- (viii) देश में सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक व्यय करना तथा
- (ix) देश में सार्वजनिक व्यय का फिजूल खर्ची हाना

अप्रत्यक्ष रूप से निजी उत्पादनकर्ताओं के पूँजी निर्माण में सहायता देना चाहिए। इसके लिए

- (I) पूँजी बाजार को मजबूत करना होगा।
- (II) साख निर्माण को सुलभ बनाना होगा।
- (III) कर सबधो विभिन्न छूटो से साहसियो को वचत व पूँजी निर्माण में सहायता पहुँचाना होगा

(III) देश में कृषि को आधुनिक ढंग पर लाना पड़ेगा :

कम-विकसित देशो को सर्वप्रथम कृषि को विकसित करना होगा इसके विकास से ही औद्योगिक क्षेत्र व तृतीयक चेन विकसित होगा, देश में राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। रोजगार वृद्धि होगी व स्याई विकास की नींव पडगी. राज्य की सहायता के द्वारा ही कृषि विकास संभव है राज्य को कृषि विकास के लिए

- (1) भूमि सुधार करना होगा सेतो की मालक्रियन खेतीहर लोगो को देना होगा
- (II) देश की बहुत सी कृषि योग्य भूमि को पाटने का काम हाथ में लेना होगा
- (III) भूमि की चकबन्दी करना व करवाना पड़ेगा
- (IV) भू-क्षरण रोकना होगा.
- (V) कृषि के विकास के लिए साख व्यवस्था मजबूत करके कृषको को महा-जनो के चगुल से छुडाना होगा.
- (VI) उत्तम बीज, खाद कीटनाशक दवाइयाँ व यातायात सुविधाएँ प्रदान करना होगा.
- (VII) कृषि विपणन सुधारने के लिए मण्डियो की स्थापना करनी होगी और गौदामो की सुविधाएँ प्रदान करनी होगी.
- (VIII) कृषि की उन्नत तकनीक कृषको को **Demonstration farms** के द्वारा समझना होगा.
- (IX) भूमि प्रयोग की उपयुक्तता तथा अन्य मामलो के बारे में अनुसंधान करने होमे, तथा
- (XI) कृषि मूल्यो को स्थिर रखने व आवश्यकतानुसार **Price support** देना होगा.

संक्षेप में राज्य को शायद स्वयं कृषि करने को छोड़ कृषि के सबध में सब कुछ करना होगा.

विस्तृत वर्णन के लिए पूँजी निर्माण सबन्धी तथा कृषि अध्याय देखिए.

(iv) साधनों के (प्राकृतिक व मानवीय) अनुकूलतम व अधिकतम प्रयोग कराने में मदद देनी होगी :

हम देख चुके हैं कि किसी देश के विकास में जितना महत्व प्राकृतिक साधनों के होने का नहीं है उससे अधिक उनके उचित व अनुकूलतम प्रयोग का है। राज्य का कर्तव्य होता है कि राज्य देश के प्राकृतिक साधनों की मात्रा व किस्म का धार्मिक सन्तुष्टि के सर्वेक्षण करे तथा उनके प्रयोग के लिए पर्याप्त पूँजी व उचित तकनीक का प्रवर्धन करे। इन साधनों का बहुवैधायीय प्रयोग कराने में सहायता करे तथा देश में बाजार स्थिति के सर्वेक्षण में सहायता करे साधनों का परिरक्षण Conservation का कार्य केवल राज्य ही कर सकता है राज्य का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि Vested interests अपने स्वार्थ के लिए कृत्रिम ग्यूनता बनाए भ्रष्टान प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग करे। देश में इनके प्रयोग सम्बन्धी अनुसंधानों को भी राज्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। इनके गलत प्रयोग पर राज्य को अधिक कर लेना चाहिए।

जैसा कि हम देख चुके हैं मानवीय साधन तो प्राकृतिक साधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है राज्य का कर्तव्य है कि वह देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करे। यह एक बहुत कठिन काम है कि कम-विकासित देश, जहाँ प्रायः जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती है, पूर्ण रोजगार प्रदान कर सकें। फिर भी श्रम गहन तकनीक अपना कर रोजगार के अवसर व रोजगार से धाय बड़ाई जा सकती है। परन्तु दीर्घकाल में (मेरे विचार में ३० वर्षों में) पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँच जाना चाहिए इस काल में

(1) जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण व

(ii) पूँजी निर्माण करके पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जाना चाहिए।

अधिक जनसंख्या वाले देश कुछ अधिक, व कम जनसंख्या वाले देश इससे कम काल में यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर सरकार यह न कर सकती तो बेरोजगार लोग सरकार बदल देंगे

(v) जनसंख्या संरचना सुधार :

विकास जनसाधारण के द्वारा, जनसाधारण के कल्याण के लिए किया जाता है विकास के लिए जनसंख्या संरचना सबकी सुधारों में राज्य का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा जब कम-विकासित देशों में जनसंख्या का दबाव व वृद्धि की मात्रा कम है उन्हें इतनी गम्भीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि उन देशों इस सम्बन्ध में प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या सुवर्धी प्रभाव में विस्तृत वर्णन देखिए

की सरकार को बरना पड़ता है जहाँ जनसंख्या वृद्धि भी अधिक है और जनसंख्या का दबाव भी अधिक है

स्वाभाविक रूप से इन देशों में परिवार नियोजन सबधी प्रचार व उस सबधी सामग्री उपलब्ध कराना शायद राज्य का सबसे मुख्य कर्तव्य होगा Prof. S Enke ने अनुमान लगाया है कि कम-विकसित देशों में परिवार नियोजन पर व्यय, अन्य किसी भी विनियोजन से, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में 100 गुना अधिक प्रभावशील है उदाहरणतया अगर जन्मदर को 40 प्रति हजार से घटाकर 35 प्रति हजार ले आया जाये तो इससे राष्ट्रीय आय में 1 प्रतिशत वृद्धि होगी जिसके लिए बहुत अधिक विनियोजन आवश्यक होता राज्य का कर्तव्य हम दिशा में यह होगा कि यह

(1) जनसंख्या की जन्म दर में, विशेष रूप से गरीब वर्ग की, भारी कमी लाएँ

(11) देश में स्वास्थ्य, शिक्षा व प्रशिक्षण सबधी सुधार करें देश में घनत्व सतुलन लाये

(VI) श्रम बाजार संगठित करें व उत्पादन के साधनों में समन्वय लाएँ :

श्रम ही उत्पत्ति का सबसे सक्रिय साधन है उसकी कुशलता वृद्धि से ही श्रम व पूँजी की उत्पादकता की वृद्धि होती है. राज्य को श्रम बाजार को संगठित करने में सहायता देनी होगी. मजदूरी के चुकाने, कार्य के घटे व वातावरण नियमित करने, श्रमिकों को कार्य पर लेने व निकालने, उनको भुमावजा देने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, देश में रोजगार दिलाने वाले दफ्तर खोलने के कार्य को सम्पादन करना होगा देश में औद्योगिक सघर्षों को निपटाने के लिए उचित संस्थाओं की स्थापना व उन्हें निपटाने के नियम बनाने होंगे. इस सम्बन्ध में सबसे प्रमुख बात देश में हड़ताल व तालाबन्दी को कम से कम रखना है. यह कम विकसित देशों के लिए विलासिता होगी. अधिक उत्पादन से ही श्रम को अधिक भाग मिल सकता है. दुर्भाग्य से, कम-विकसित देशों ने पहले ही समानता के लिए सघर्ष होने लगता है. हमको समृद्धि में समानता लाना चाहिए न कि गरीबी में समानता.

कम-विकसित देशों में राज्य को उत्पादन के भिन्न-भिन्न अंगों में समन्वय भी लाना होगा. इन देशों में Co-operant factors की कमी रहती है. अर्थात्

इस सबध में आप 'कम-विकसित देशों की विशेषताओं' के अध्याय में पढ़ ही चुके हैं.

Cf S. Enke . National Productivity Council, Annual Number, Economic Journal, march 1966

साहसियों, कुशल प्रशामकों तथा कुशल भजदूरो को कमो रहदी है इनकी पूर्ति वृद्धि के लिए राज्य को सहायता करना चाहिए.

(VII) राज्य को देश में आवश्यक मात्रा में विनियोजन कराना चाहिए :

कम विकसित देशों में वचत व विनियोजन में समन्वय अपने आप नहीं होगा और शायद पर्याप्त मात्रा में भी न हो पाए. कम-विकसित देशों में राज्य को कम से कम 7-10% वार्षिक विकास की दर को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों को उसको प्राप्त करने की निश्चित जिम्मेदारियाँ बाँटना चाहिए. राज्य को चाहिए कि वह दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक के रूप में चलाएँ :

राज्य स्वयं इन देशों में Infra-structures में या external economics में (पानापात, संचार सुविधाएँ, शिक्षा व स्वास्थ्य विकास, शक्ति व सिंचाई सुविधाएँ आदि) विनियोजन करे. राज्य को ही देश में आधारभूत (इन्फ्रा, भारी इन्जीनियरिंग, रसायनिक खाद आदि) उद्योगों की स्थापना करनी होगी कृषि व प्राकृतिक साधनों के अधिकतम परीक्षण व प्रयोग में भी राज्य को सहायता करनी होगी.

निजी क्षेत्र को कर सब ढी छूटें देकर तथा उन्हें अन्य सुविधाएँ देकर निर्यात वर्धक व आयात प्रतिस्थापन उद्योगों में विनियोजन करने को प्रोत्साहित करे राज्य को चाहिए कि कुल विनियोजन की मात्रा राष्ट्रीय आय की 20% तक पहुँचा दे. राज्य को अपने उद्योगों का संचालन लाभ या "न लॉस न हानि" के आधार पर करना चाहिए. राज्य को, Herman Finer के शब्दों में

"Government may claim all mineral, power and water resources and the land for the Government and proceed by direct management
"licensing to private firms or co-operatives"
..... "No private economic corporation has ever been close to attaining such power to animate, direct, stimulate or narcotize economic development. In addition to financing, Government can acquire funds by the sale of goods it produces, through power, transportation, communications, fuel and so on, specially in nationalized industries."

(viii) राज्य उचित मौद्रिक, राजकोषीय व मूल्य नीति अपनाएँ :

कम-विकसित देशों में विकास बहुत माना में राज्य की इन तीन नीतियों पर निर्भर रहता है, जैसा कि हम देख चुके हैं राज्य का मुख्य कार्य देश में संस्थागत वृद्धियों में वृद्धि कराना, मुद्रा स्फीति व विस्फीति को नियंत्रित रखना, देश में साख का विस्तार तथा नियंत्रण करना और साख की सुविधाओं को छोटे बड़े समस्त उत्पादनकर्ताओं को उपलब्ध कराना विदेशी विनिमय दर के उच्चावचन रोकना चाहिए, तथा देश में प्रमौद्रिक क्षेत्र को कम करके, मौद्रिक सम्बन्धों का केन्द्रीय बैंक के अन्तर्गत लाना चाहिए

राजकोषीय नीति ऐसी होना चाहिए जो देश में वचतो, पूँजीनिर्माण व विनियोजन को प्रोत्साहन दे, विदेशी विनियोजन व निर्यात प्रोत्साहित करे, समानता राने के साथ साथ देश में पूँजी संचय की प्रेरणा बनाए रखे तथा देश में विभिन्न प्रकार के करो की संरचना ऐसी रखे जो न्याय व उत्पादन के तथ्यों को प्राप्त कर सके. कर इतने अधिक भी न हों कि विनियोजनकर्ताओं को कार्य करना ही कठिन पड़ जाए. राज्य को ऐसी राजकोषीय नीतियाँ अपनानी चाहिए जिससे ऋण का भार कम रहे तथा सार्वजनिक व्यय विकास की नींव डाले, न कि मुद्रा स्फीतिको साधन बन जाए. राज्य को प्रेरणादायक मन्त्रतन्त्र मूल्य नीति को कार्यरूप होने की सुविधा देना चाहिए परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मूल्य नियमन व नियंत्रण भी करना चाहिए

(ix) विदेशी व्यापार व विदेशी विनियोजकों को प्रोत्साहन देना चाहिए :

कम-विकसित देश विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ में फँसे रहते हैं. राज्य एकदम तो इन देशों में विदेशी विनिमय का संतुलन पक्ष में नहीं कर सकता. इस अवस्था में राज्य को निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे :

- (i) आयातक आयातों को होने देना तथा विलासिताओं के आयात को रोकना चाहिए
- (ii) निर्यात वर्धक व आयात प्रतिस्थापन उद्योगों की स्थापना करे. कर सम्बन्धी छूटो, विदेशों में प्रदर्शनियों, सम्पर्कों, राजनैतिक व्यापार समझौतों से निर्यात में वृद्धि करे.
- (iii) विदेशी मुद्रा के सट्टों पर कड़ा नियंत्रण रखे.
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों से कम-विकसित देशों को अपनी निर्याती वस्तुओं में उच्चावचन रोकना चाहिए. निर्यात की मात्रा के साथ-साथ विविध वस्तुओं का निर्यात प्रोत्साहित करना चाहिए

निम्नलिखित तीन अध्यायों में विस्तार से अध्ययन हो ही चुका है

कम विकसित देशों के राज्यों को विदेशों व विदेशी संस्थाओं से ऋण व तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इस संबंध में राज्य को विदेशी विनियोजकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए उन्हें समान अवसर देना चाहिए. देश में इनकी सम्पत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए. हाल के वर्षों में भुगतान में समय की पाबन्दी का न होना, मुद्रा स्थिरता, विनियम नियंत्रण, जन्म करने की घमकियों, भेदभाव पूर्ण कर नीतियों व अम नियमों, राज्य की प्रतियोगिता आदि के कारण कम-विकसित देशों में विदेशी विनियोजक हतोत्साहित हो रहे हैं राज्यों को इस संबंध में विदेशी विनियोजकों के विश्वास को बनाए रखना चाहिए.

(५) धन का न्यायोचित वितरण, पिछड़े वर्ग व इसाको का विशेष ध्यान, आपत-कालीन सहायता :

राज्य देश में धन व आय का वितरण कैसा रहे यह एक गम्भीर समस्या है. राज्य का कर्तव्य है कि वह समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ आर्थिक प्रेरणा को बनाए रखे सही नीति यह होगी कि राज्य "समान व्यक्तियों में असमानता तथा असमान व्यक्तियों में समानता न आने दे" राज्य को गैर कमाई आय को कम करना चाहिए परन्तु मेहनत से कमाई आय तथा साहसियों की आय को अधिक नहीं घटाना चाहिए साहसियों के लाभ पर कम व बमीदारों के लाभ पर अधिक कर लिया जाना चाहिए. तबे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए.

Lewis के शब्दों में

"The less developed countries have awakened into a century where every body wishes to ride two horses simultaneously, the horse of economic equality and the horse of economic development. The U. S. S. R. has found that these two horses will not go in the same direction, and has, therefore, abandoned one of them. Other less developed countries will have to make their own compromises."²

हर कम-विकसित देश में कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के अनुपात में ज्यादा पिछड़े होने हैं अगर राज्य इनके विकास में दिलचस्पी न ले तो निजी क्षेत्र वाले इन क्षेत्रों में भगले चप्याप में इस संबंध में विस्तृत रूप से लिखा है

आर्थिक व सामाजिक सिरोपरी सुविधाओं की कमी से कभी विकास नहीं करेंगे कम विकसित देशों के राज्यों को इन देशों में उद्योग खोलकर "Jobs to the men" नीकरियाँ ले जाना चाहिए।

इन देशों की जनता लगभग जीवन यापन स्तर पर रहती है किसी भी प्राकृतिक प्रकोप का सामना करने की क्षमता उनमें नहीं होती ऐसी अवस्था में वे केवल गरीब ही नहीं रहते बल्कि भूखों मर जाते हैं राज्य का यह कर्तव्य है कि अगर देश की उत्पादन क्षमता का बृहद पैमाने पर नुकसान हो तो उसकी वह क्षति पूर्ति करे

(21) सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं में सुधार किए जाएँ, जिससे वे विकास में सहायक हों ।

विकास मनुष्यों के बदलते हुए आचरण व मान्यताओं के कारण भी होता है। कम-विकसित देशों की जनता का बड़ा भाग पिछड़ा हुआ है और वह विकास करने का न तो इच्छुक दीखता है न प्रयत्न करता है और न क्षमता रखता है। राज्य को देश में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का विकास करना चाहिए। शिक्षा के विकास में रुढ़िवादिता व परम्परावादिता कम होती है विकास की इच्छा बढ़ती है, न्याय व शान्तिप्रियता की ओर रुझान होता है, इमानदारी, कर्तव्यपरायणता, नियमितता, कार्यक्षमता व उत्पादकता बढ़ती है

इन देशों में धर्मान्धता (धार्मिकता नहीं) कम करना चाहिए आधुनिकता को अपनाते राज्य के प्रसार व प्रचार से ही संभव होगा 'संक्षेप में' राज्य के महत्व को हम निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं

"Like the population's physical health, its literacy and knowledge and its mores of honesty and alertness, Governments enterprise, improved and uncorrupt administration is an "Intangible capital " Government should be objective, Requirements of economic development require that personal, religious, 'partisan' 'ideological prejudices be ignored, or indeed suppressed "

(Herman Finer).

Finer आगे लिखते हैं :

“राज्य के द्वारा आर्थिक विकास राज्य द्वारा सही संगठन व निर्णयों पर निर्भर है. राज्य को भी अपने कार्यों में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए, उसके प्रशासन में उचित कार्य-व्यवस्था होना चाहिए Pro-per departmentalization देश में महत्वपूर्ण बातें केन्द्रीय स्तर पर निर्णित होना चाहिए जबकि उनको कार्यान्वित करने में विकेंद्रित कार्यकलाप की भी सुविधा होनी चाहिए.”

IV. राज्य के योगदान की सीमाएँ

राज्य का विकास प्रक्रिया में कहीं तक योगदान होना चाहिए ? क्या उसको आवश्यक कार्य करके हट जाना चाहिए ? राज्य वास्तव में विकास प्रक्रिया से पूरी रूप से नहीं हट सकता. अगर वह पहले विकास की आधार शिला रखेगा तो बाद में उसे देश में आर्थिक स्थायित्व के लिए कार्य करना पड़ेगा :
राज्य का प्रशासन अगर भ्रष्ट व अकर्मस्य है तो देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व राज्य दोनों शोषण करेंगे Tokyo conference में इस सबंध में निम्न-लिखित मत व्यक्त किया गया था

“राज्य के विकास में योगदान के बड़े खतरे भी हैं उसकी प्रकुशलता व भ्रष्टाचार से निजीक्षेत्र का गला घुट सकता है वास्तविक खतरा तो यह है कि अगर राज्य की नीतियाँ कारगर नहीं होती तो वह अपनी नीतियों को मतवाने में तानाशाही का कार्य करेगा.

उदाहरणतया .

बहुत अधिक कर लगाएगा, सामूहिक कृषि चाँपेगा, श्रम तपों को भी निष्क्रिय कर देगा और देश में पूर्णरूप से स्वतन्त्रता नष्ट कर देगा.”

अध्याय : 9

पूँजी-निर्माण व विकास

Capital-Formation & Growth

I प्रस्तावना .

पूँजी-निर्माण का अर्थ.

II. पूँजी-निर्माण को नापने की रीतियाँ :

- (a) Commodity flow approach
- (b) The expenditure approach.
- (c) Aggregate savings approach.
- (d) Changes in physical stock.

पूँजी-निर्माण नापने की कठिनाइयाँ व संतुलित मूल्यांकन.

III. विकसित व कम-विकसित देशों में पूँजी निर्माण : कम-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण कम होने के कारण .

IV. पूँजी-निर्माण रीतियाँ

- (a) बचत व पूँजी निर्माण विकसित व कम-विकसित देशों में बदलने की मात्रा व संरचना, बचत को बढ़ाने के उपाय, धनर्तों का विनियोजन.
- (b) अतिरिक्त जनशक्ति का प्रयोग व पूँजी-निर्माण.
- (c) मुद्रा स्फीति व पूँजी-निर्माण
- (d) पूँजी-निर्माण व राजकोषीय नीति.
- (e) पूँजी-निर्माण व उपभोग में कमी.
- (f) साधनों का पूर्ण प्रयोग.

V. पूँजी-निर्माण व विकास . सीमाएँ, महत्व तथा "भिरन" Leakages :

पूँजी-निर्माण व विकास

Capital Formation & Growth

I प्रस्तावना

Meaning of Capital-Formation पूँजी-निर्माण का अर्थ

जैसा कि सर्वविदित है, धन का वह भाग जो और अधिक धन या धन उत्पन्न करने के कार्य आता है वह पूँजी है पूँजी में वृद्धि ही पूँजी-निर्माण होता है पूँजी-निर्माण के लिए वस्तुओं में वृद्धि की आवश्यकता है और इन वस्तुओं का विनियोजन आवश्यक होता है सामान्यतः (सकुचित अर्थ में) पूँजी-निर्माण का अर्थ मशीनों, गृहों, कारखानों में वृद्धि तथा Inventories accumulation से होता है। Inventories का अर्थ कच्चा माल, बने सामान तथा उत्पादन के अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से होता है। उत्पादन के कार्य में आने वाली सम्पत्ति में वृद्धि ही पूँजी-निर्माण समझी जाती है, उपभोग के कार्य में आने वाली सम्पत्ति में वृद्धि पूँजी-निर्माण नहीं होती।

पूँजी-निर्माण का यह सकुचित रूप हुआ। वास्तव में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग आदि की सुविधाओं के विस्तार से भी देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है अतः यह भी पूँजी-निर्माण कार्य है पूँजी-निर्माण का अर्थ भौतिक साधनों में विनियोजन से ही नहीं लिया जाता, बल्कि मानव साधनों में भी विनियोजन से होता है।

पूँजी-निर्माण का विश्लेषण हम दो रूप से करते हैं। Gross capital formation या कुल पूँजी-निर्माण तथा Net capital formation या शुद्ध पूँजी-निर्माण कुल पूँजी-निर्माण का अनुपात हम कुल राष्ट्रीय आय में से पूँजी-निर्माण के रूप में आकरते हैं जबकि विशुद्ध पूँजी-निर्माण को आबने के लिए हमको पूँजी की पिछावट निकालनी पड़ती है वास्तव में शुद्ध पूँजी-निर्माण में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है, परन्तु इसको मापना अधिक कठिन होता है संक्षेप में

"Domestic capital formation consists of such

domestic output and imports which are neither exported nor consumed by household and by general government but result in the additions to the total stock of capital goods in the country”

II Methods of Measurement or Estimation :

पूँजी-निर्माण की मात्रा को नापने की विधियाँ :

सामान्यतया पूँजी-निर्माण में वृद्धि की मात्रा 4 रूप से आँकी जाती है ये चार रीतियाँ हैं

- (a) Commodity flow approach वस्तु उत्पादन रीति.
- (b) Expenditure approach व्यय गणना रीति.
- (c) Changes in the physical stock of capital goods approach पूँजी की भौतिक मात्रा में परिवर्तन गणना रीति तथा
- (d) Aggregate savings approach कुल बचतों की गणना रीति

(a) Commodity flow approach : वस्तु उत्पादन रीति :

इस रीति में पूँजी निर्माण नापने के लिए देश में समस्त वस्तुओं के उत्पादन तथा आयात का जोड़ लगा लेते हैं और उसमें से उपभोग व निर्यात घटा लेते हैं तथा बचा हुआ भाग उस देश का पूँजी-निर्माण माना जाता है.

इस प्रकार से पूँजी निर्माण की मात्रा आँकने के लिए उपभोग की मात्रा आँकने में काफी कठिनाई होती है, इतनी कठिनाई निर्यात व आयात की मात्रा आँकने में नहीं होती

(b) The Expenditure Approach : व्यय गणना रीति :

इस रीति के अन्तर्गत मशीन, भवनों तथा अन्य उत्पादक सम्पत्तियों (Productive construction and equipment) पर व्यय को आँकते हैं. इसमें हम अन्य सम्बन्धित व्ययों (यातायात, तथा अन्य व्यय) भी शामिल कर लेते हैं. इन आँकड़ों को हम औद्योगिक संस्थानों या व्यापारिक संस्थानों की लेखा-तलपट (Balance sheets) से पता लगा लेते हैं. भिन्न-भिन्न औद्योगिक संस्थानों की लेखा रीतियाँ जहाँ भिन्न होती हैं वहाँ पूँजी आँकने में अन्तर पड़ जाते हैं और इस प्रकार से पूँजी-निर्माण की मात्रा में अन्तर आ जाता है.

पूँजी-निर्माण व विकास

(c) Changes in the physical stock of capital goods

पूँजी की भौतिक मात्रा में परिवर्तन गणना रीति :

इस रीति के अन्तर्गत देश में वर्ष के शुरू व अन्त में पूँजी की मात्रा अंकी जाती है और अगर साल के अन्त में पूँजी की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो उतनी मात्रा में पूँजी निर्माण माना जाता है. परन्तु पहले इसमें से घिसावट, पुरानेपन की हानि व मूल्य परिवर्तनों के अन्तर घटा दिए जाते हैं तब शुद्ध पूँजी-निर्माण का पता चलता है. (मूल्यों के परिवर्तन का आशय यह है कि माना सान के शुरू में एक मशीन 1 लाख की थी और साल के अन्त में उसका मूल्य बढ़कर 1,20,000 हो गया तो वास्तविक पूँजी तो वही रही केवल भौतिक रूप से बढ़ गई इसको हम पूँजी-निर्माण नहीं मानते) फिर कम-विकसित देशों में पूँजी-बाजार के समुचित रूप में उन्नत न होने के कारण इस प्रकार का अनुमान लगाना ठीक नहीं है.

(d) Aggregate savings approach - कुल बचतों की गणना रीति :

इस रीति में देश में एक वर्ष में होने वाली कुल बचतों का अनुमान लगाया जाता है और यह मान लिया जाता है कि पूँजी-निर्माण भी इतनी ही मात्रा में हुआ है. यह बात इस मान्यता पर आधारित है कि बचतें व विनिर्माण बराबर हो जाएँगे. कम-विकसित देशों में न तो ये अनुमान ठीक रूप से लगाए जा पाते हैं और न इस रीति की मान्यताएँ सही होती हैं.

कम-विकसित देशों में पूँजी निर्माण नापने में सामान्य कठिनाइयाँ :

- (1) कम-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण की मात्रा का सही अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन होता है. आयात व निर्यात सम्बन्धी अनुमान तो ठीक से या लगभग ठीक से लगाए जा सकते हैं परन्तु देश में उत्पादन के अनुमान लगाने में बहुत कठिनाइयाँ सामने आती हैं. कम-विकसित देशों में बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन का अनुमान तो लग जाता है परन्तु अत्यन्त छोटे पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं का अनुमान नहीं लग पाता. इससे Commodity flow approach की ठीक

See 1. U N Concepts and Measurements of Capital Formation 1953.

2. S.G. Tiwari "Concept and Measurement of Capital Formation," Unpublished Paper of Vikram University Conference on Capital Formation at Bhopal in 1966.

3. D. B. Singh : op. cit

से नहीं अपना पाते, क्योंकि फिर यह भी ठीक-ठीक पता नहीं होता कि इस उत्पादन में से कितना भाग निर्माण कार्य में लगा है।

- (11) कम-विकसित देशों में पूँजीगत निर्माण कार्यों में मजदूरी आदि के अनुमान भी ठीक से नहीं लग पाते, क्योंकि बहुत से स्थानों में मजदूरी नगद के स्थान पर वस्तुओं के रूप में दी जाती है।
- (111) ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सा निर्माण कार्य अवैतनिक आधार पर किया जाता है, अर्थात् बहुत सा निर्माण कार्य परिवार के लोग मिलकर ही कर लेते हैं इस प्रकार के निर्माण कार्यों का अनुमान ही लगाया जा सकता है

iv) सबसे बड़ी कठिनाई तो Inventories के पता लगाने में आती है। अर्थात् कच्चे, अर्ध बने व बने हुए माल के स्टॉक का अनुमान लगाना कठिन होता है (Inventories में वृद्धि भी पूँजी-निर्माण होता है) Inventories का सही मूल्यांकन तो विकसित देशों में भी कठिन होता है कम-विकसित देशों में तो यह बहुत ही अधिक कठिन होता है।

- (v) पूँजी-निर्माण को नापने के लिए Capital goods पूँजी गत वस्तुओं, Parts of capital goods (पूँजी गत वस्तुओं के भाग) का अनुमान तो किसी प्रकार से लगा भी लिया जाये तो partly capital goods अर्थात् ऐसी वस्तुएँ जिनका उपयोग भी हो सकता है तथा जिनको उत्पादन कार्य में भी ले लिया जा सकता है, का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है

- (vi) कम-विकसित देशों वचतो का बड़ा भाग घरेलू बचतों से प्राप्त होता है और इनका अनुमान नहीं लग पाता क्योंकि बहुत सी बचतें सस्थागत नहीं होती

पूँजी-निर्माण को सही-सही रूप से आकने के सम्बन्ध में बहुत सी सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ भी हैं (Conceptual problems), जो इस प्रकार से हैं :

- (1) कम-विकसित देशों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब assets या सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है तो इसके पूर्ण अनुमान मौजूद नहीं रहते।
- (11) भूमि, जंगल आदि प्रकृतिदत्त मुफ्त के अनुदान हैं इनको पूँजी नहीं माना जाता परन्तु इनमें जनशक्ति करने की पूँजी-निर्माण कार्य मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भूमि को खरीदना पड़ता है और पूँजी मानी जाती है परन्तु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उसे पूँजी नहीं माना जाता है।

पूँजी-निर्माण व विकास

(iii) कितनी भी पूँजीगत वस्तु में सुधार कार्य (Repairs) को पूँजी निर्माण नहीं माना जाता क्योंकि इसमें केवल पूँजी की कार्यक्षमता बनी रहती है, उसमें उन्नति नहीं होती। परन्तु बहुधा ऐम सुधार भी हो जाने है जिनसे पूँजी की कार्यक्षमता या कार्यकाल में वृद्धि हो जाती है इस प्रकार के अन्तर का पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता और इससे पूँजी-निर्माण को सही-सही रूप से नहीं जाँच पाने कम-विकसित देशों में तो Repairs की मात्रा का ही पता नहीं रहता

पूँजी निर्माण का समुचित मूल्यांकन :

कम-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण का कोई एक ही तरीका सतोपजनक नहीं हो सकता, फिर भी सबसे पहले Commodity flow approach का अपना उचित रहता है तत्पश्चात् विकास-कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए देश में समस्त उत्पादक कार्य हेतु निर्माण कार्य (मकान, कारखाने, मशीनें, भूमि विकास, भूमि को पाटना, मेंटें बांधना, कुएँ खोदना, सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाना, वागान लगाना, जंगलों का विस्तार, सड़कें डालना, रेलें तथा अन्य यातायात साधनों में वृद्धि, संचार साधनों में वृद्धि तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि) को आकना पड़ता है संक्षेप में यह इस प्रकार से आक सकते हैं :

1. निम्नलिखित में प्रचल पूँजी-निर्माण	2. निम्नलिखित में स्टॉक वृद्धि
(i) कृषि, जंगल, मछली पालन. (ii) जाना (iii) उद्योगों में (iv) निर्माण कार्यों में, (v) ध्वजली, गैस तथा पानी विकास (vi) यातायात, संचार तथा storage (vii) थोक तथा फुटकर व्यापार. (viii) बैंक, बीमा तथा real estates (ix) सार्वजनिक प्रशासन. (x) आवश्यक सेवाएँ.	(i) कृषि, जंगल व मछली पालन (ii) जाना. (iii) उत्पादन कार्य में लगे पशु (iv) उद्योगों, निर्माण कार्यों. (v) थोक व फुटकर व्यापार (vi) अन्य उत्पादन कार्यों में

III Low Levels of capital formation in under developed countries कम-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की कमी.

कम विकसित देशों में पूँजी निर्माण की मात्रा विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है यह बात निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो सकती है यह तालिका 1959-61 में पूँजी निर्माण की Range दर्शाती है

Gross capital formation as a percent of gross domestic product.	Countries
35—45%	जापान (44), यूगोस्लाविया (37),
30—35%	ब्रिटिश गुयाना (33), नार्वे व फिनलैंड.
25—30%	बार्बेडोस, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, प० जर्मनी, ट्रिनिडाड, इजराइल, ग्रीस तथा अल्जीरिया
20—25%	प्युट्रियोरिको, इटली, आइसलैंड, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, स्वीटजरलैंड, फारमोसा, डेन्मार्क
15—20%	पुर्तगाल, कोलंबिया, कनाडा फ्रांस, जमाइका, लम्बेज्वर्ग, रोडेसिया घाना, पीरू, ब्राजील, सूडान, थाईलैंड, स्पेन, बेने-ज्येला, बेल्जियम, यू० एस० ए०, यू० के०, पनामा, आइरलैंड, बर्मा, केन्या.
10—15%	टगानियाका, इम्पेडार, लका, नाइजीरिया, होन्डुरास, ग्वाटेमाला, युगान्डा, आइरलैंड, मलाया.
5—10%	भारत, चिली, फिलीपीन्स, परागुए

U. N. Statistical Year Book 1963.

Quoted from Kindleberger : op. cit : p. 96.

पूँजी-निर्माण व विकास

कम पूँजी-निर्माण के कारण :

कम पूँजी निर्माण के कारणों के विश्लेषण के लिए किसी महत्वपूर्ण खोज की आवश्यकता नहीं है। ये कारण तो सर्वविदित हैं

1. सर्वप्रथम कम पूँजी निर्माण इन देशों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति आय व बचत के निम्न स्तर के कारण है। इन देशों में विश्व की 63% जनसंख्या रहती है और विश्व की केवल 12% आय प्राप्त करती है। एक तो यहाँ बचतें ही कम हैं और दूसरे जो बचतें हैं वे जमाखोरी (Hoarding) के रूप में अधिक होती हैं और पूँजी निर्माण कम होते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, इन देशों में कम बचतों व कम पूँजी निर्माण का दुष्प्रभाव चलता है। पूँजी की ओर से कम पूँजी से कम विनियोजन होता है, इससे कम उत्पादकता होती है, कम रोजगार होता है, इससे उत्पादन स्तर व राष्ट्रीय आय कम रहती है, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। कम-विकसित देशों में उपभोग क्षमता अधिक होने से बचतें कम रहती हैं और कम पूँजी-निर्माण होता है।
2. माँग की ओर से कम माँग के कारण (प्रभावशील माँग की मात्रा का कम होना व उपभोग क्षमता का अधिक होना साथ-साथ चलता है) विनियोजन भी कम होता है और पूँजी की माँग भी कम होता है।
3. कम-विकसित देशों में ब्याज की दर अधिक होती है। इसका मुख्य कारण इन देशों में बचतों की कमी तथा उपभोग के लिए उधारों की माँग की प्रधिकता होती है परन्तु इससे विनियोजन हतोत्साहित होता है और पूँजी निर्माण कम होता है।
4. कम-विकसित देशों में निम्न आय के कारण शिक्षा के स्तर तथा जीवन स्तर नीचा रहता है। इस कारण बाजार सकुचित रहते हैं और इस कारण भी पूँजी-निर्माण कम रहता है।
5. कम-विकसित देशों में बचतें न केवल कम होती हैं वरन् उनमें से अधिक भाग संस्थागत नहीं होता। बचतों को सौना, भूमि, और सट्टों में लगा दिया जाता है। इस कारण भी पूँजी-निर्माण कम रहता है।
6. कम-विकसित देशों में बढ़ती हुई आय के परिणाम स्वरूप उपभोग क्षमता की अधिकता के कारण, बहुत अधिक आय व्यय कर दिया जाता है। इन देशों में demonstration effect expenditure (अच्छी व बिलासिताओं)

की वस्तुओं पर नकल व्यय) बहुत व्यय हो जाता है सामाजिक रीतिरिवाजों पर भी बहुत अनावश्यक व्यय कर दिया जाता है.

- 7 कम-विकसित देशों में साहसियों की नितान्त कमी रहती है. अगर साहसी कुशल, सुभ-बुद्धि वाले तथा प्रतिस्पर्द्धा रखनेवाले होते हैं तो वे स्वयं पूँजी खींच लेते हैं.

IV. Methods of Capital Formation : पूँजी-निर्माण रीतियाँ -

पूँजी-निर्माण बचतों का परिणाम होता है बचतों की वृद्धि की रीतियाँ ही पूँजी-निर्माण रीतियाँ हैं, यद्यपि कि इन बचतों को उत्पादक कार्य में लगाया जा सके कम-विकसित देशों में हम बचतों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा फिर पूँजी-निर्माण की रीतियों का अध्ययन करेंगे. पूँजी-निर्माण की मुख्य रीतियाँ यह हैं :

- (I) बचतों को सत्यागत करना
- (II) अतिरिक्त जनशक्ति के प्रयोग से पूँजी-निर्माण (नवर्स व ल्युम का थोसिस)
- (III) मुद्रा स्थिति फैलाकर या वास्तविक मजदूरी गिराकर पूँजी-निर्माण (मौद्रिक व राजकोषीय नीति का सहारा लेकर)
- (IV) राजकापीय नीति का प्रयोग व पूँजी-निर्माण अर्थात् राज्य द्वारा सामूहिक बचतों का करना.
- (V) उपभोग में कमी करके पूँजी-निर्माण
- (VI) साधनों का पूर्ण प्रयोग करके पूँजी-निर्माण

(A) Savings, Capital Formation and Growth : बचत, पूँजी निर्माण तथा विकास.

1. विकसित व कम-विकसित देशों में बचतें :

कम-विकसित देशों में विकसित देशों के मुकाबले में बचतें न केवल कम रहती हैं बल्कि उनमें स्थिरता भी नहीं रहती निम्नलिखित तालिका से विकसित व कम-विकसित देशों की सापेक्षिक स्थिति की तुलना की जा सकती है.

Levels of Gross and Net Domestic Saving 1950-59 (percent of gross domestic product)

High Income Countries			Low Income Countries		
देश	Domestic Savings		देश	Domestic Savi	
	Gross	Net		Gross	Net
जापान	28.7	21.1	रोडेसिया व	20	14
नार्वे	27.1	17.2	न्यासायंड	24	16
फिनलैंड	26.7	21.7	बेनेज्वेला	24	16
प जर्मनी	26.3	17.2	कांगो	12	5
भारतद्वेलिया	26.1	20.2	जमाइका	2	4
नीडरलैंड	25.7	15.9	प्यूरटोरिको	18	8
कनाडा	22.5	11.4	घरजेन्टिना	20	14
भ्यूजीलैंड	22.5	15.9	वर्मा	15	8
भारतद्विया	20.4	13.3	स्पेन	18	9
इटली	19.5	10.6	बोताम्बिया	9	4
यू एल ए	18.6	9.9	ग्रीस	15	10
डेनमार्क	18.5	12.4	ग्राजील	17	13
फ्रान्स	18.4	9.1	इराक	12	8
बेल्जियम	17.6	8.0	टर्की	11	9
यू. के.	15.2	7.2	लक्सा	8	1
			चिली	7	2
			फिलीपीन्स	5	2
			इन्डोनेशिया	-	7
			भारत		

References :

All references cited before with particular reference to Dr. D. Bright Singh's op. cit : ch. vi and Dr. (Miss) Ishrat Z. Husain's op. cit : ch. ix.

World Economic Survey 1960; 1

समीक्षा -

अधिकांश कम-विकसित देशों में बचते 10% से भी कम हैं जबकि अधिकांश विकसित देशों में बचतें 20% तक रहती हैं कुछ देशों में बचते कम अवश्य हैं परन्तु राज्य व अन्य मस्थागत बचतों में वृद्धि हुई. उधर कुछ कम विकसित देशों में जो अधिक बचते हैं वह विरोधरूप से विदेशी विनियोजकों की बचतों की अधिकता के कारण रहा है

विकसित देशों में बचतों का प्रतिशत कम विकसित देशों के अनुपात में अधिक अवश्य है परन्तु इन देशों में आय वृद्धि के साथ साथ बचतों में वृद्धि नहीं हुई है Simon kuznets Modigliani, W A Lewis, Dusenberry आदि ने इस बात के कारणों का अध्ययन किया और कई कारण बताए. (सामान्यतया आय बढ़ने के साथ-साथ बचतें बढ़ना चाहिए) इन्होंने जो कारण बताए वे इस प्रकार हैं

- (I) इन देशों में शहरीकरण के साथ साथ माँग बढ़ती जाती है
- (II) इन देशों में नई-नई वस्तुएँ या उनके नए नए मॉडल निकलने हैं और Demonstration effect के कारण (नकल करने की भावना) उपभोग में कमी नहीं आती
- (III) इन देशों में real profits वास्तविक लाभ कम हो रहे हैं और वास्तविक मजदूरी बढ़ रही है
- (IV) इन देशों में औसत आय बढ़ने से बूढ़ों की संख्या में वृद्धि होती है और ये व्यक्ति dissavers या बचतों को खर्च करने वाले होते हैं.

विकसित देशों में बचते व विनियोजन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा की जाती है इसलिए वे शायद ही कभी बराबर हो पाते हैं स्वतन्त्र मूल्य व्यवस्था उन्हें एक स्तर पर नहीं ला पाती इसलिए जब कभी बचतें अधिक व विनियोजन कम रहता है तो मुद्रा विस्फोति व बेरोजगार फैलता है तथा भुगतान संतुलन सुधरता है और अगर विनियोजन अधिक होता है तो मुद्रा स्फीति फैलती है और भुगतान संतुलन खराबी सुधार हो सकता है (दीर्घकाल में यह नहीं होगा).

कम विकसित देश :

कम विकसित देशों में जहाँ अधिक बचतों की आवश्यकता है वहाँ बचतें कम हैं. समस्त कम विकसित देश 1950 में अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 5% भाग

पूँजी-निर्माण व विकास

बचत करते पाये गए लेटिन अमेरिकी कुछ देशों में बचत 10 व 12% तक हो जाती है परन्तु एशिया व अफ्रीका के कई देश तो 5% में भी कम बचत कर पाते हैं। एशिया में औसतन प्रति व्यक्ति बचत \$2 डालर प्रति वर्ष रहती है जबकि न्यूजीलैंड में यह बचत \$125 से भी ऊपर रहो। 1950 में न्यूजीलैंड में एशिया के अनुपात में केवल 1/600 भाग जनसंख्या थी, परन्तु बचतों में उसकी बचतें एशिया की बचतों का 1/10 भाग ही थीं।

कम विकसित देशों की बचत सम्बन्धी प्राथमिकतम जानकारी का अध्ययन करे तो हम पाते हैं कि बहुत से कम-विकसित देशों में बचतों की प्रतिशत घट रही है। अधिकांश कम-विकसित देशों में सार्वजनिक व्यय के बढ़ने तथा करो सम्बन्धी प्राथमिकता न बढ़ने के कारण राज्य की बचतें कम हो रही हैं। निजी क्षेत्र में छोटे व्यापारी या कम गाय पाने वाले व्यक्तियों की बचतें भी मुद्रा स्फीति के भार से कम हो जाती हैं। रागतों में वृद्धि, मजदूरी दरों में वृद्धि, करो में वृद्धि आदि से Corporate क्षेत्र (कम्पनी क्षेत्र) में भी बचतें अपेक्षित दर से नहीं बढ़ीं। (अगले पृष्ठ 448 पर टेबिल देखिए)।

गलत प्रयोग :

बचतों का गलत प्रयोग भी बहुत होता है। सामान्य रीति-रिवाजों, सोना, चाँदी के संचित करने, भूमि के सट्टों में भी बचतों को लगा देते हैं। राज्य भी आवश्यकता से अधिक बड़ी इमारतों या मंडियों पर व्यय करने लगती हैं। उदाहरणतया इंडोनेशिया में जहाँ राष्ट्रपति सुकर्णो के शासन के अन्तिम वर्षों में बेरोजगारी व गैहगाई चरम सीमा पर थी, वहाँ उनका शासन विश्व की सबसे बड़ी मसखिंद तथा खेल के स्टेडियम आदि बनाने में व्यस्त था।

एशिया में, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, लका, नेपाल आदि में जेबरो में बहुत धन लगा देते हैं। भारत में अनुमानतः विश्व का 7% सोना तथा 26% चाँदी संचित है। भारत में मात्रक अनुमानतः 1 हर वर्ष 50 से 100 करोड़ रु० का सोना चोरी छिपे लाया जा रहा है और मात्र भारत में 3000-4000 करोड़ रु० का सोना होने का अनुमान है।

1. देखिए 'धर्मयुग' में Anti-Smuggling operations के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मिरान्डा का लेख : 1969 जून के दूसरे हफ्ते का धर्मयुग।

Increase or decrease (-) in the level of Savings in
Under developed Countries 1950-52 to 1957-59,
as Percentage of Gross domestic products.

देश	कुल शुद्ध वचन	विदेशी वचन	घरेलू वचन	सरकारी वचन	निजी वचन		
					कुल	कारपोरेट	घरेलू
जमाइका	10	2	8	2	6	2	4
बर्मा	7	10	-3	-3	—	—	—
भारत	5	3	2	—	2	—	—
पनामा	4	2	2	—	2	3	-1
ग्रीस	4	2	3	—	3	—	—
इक्वेडोर	4	2	2	4	-2	-1	-1
चिली	4	2	2	1	1	—	—
रोडेशिया न्यासलैंड	3	7	-4	—	-4	-5	1
फिलीपीन्स	2	1	1	1	—	1	-1
प्यूरटोरिको	1	8	-7	—	—	1	—
कोरिया (दक्षिण)	1	2	-2	—	-2	—	—
ट्रिनिडाड टोबैगो	—	—	—	2	-1	—	-1
ब्राजील	—	-1	—	—	1	1	—
कोलंबिया	-1	-1	—	1	-1	1	-2
पुर्तगाल	-1	2	-3	1	-3	—	—
वनेज़ुएला	-1	4	-5	1	-6	1	-7
लक्सा	-2	5	-7	-3	-4	-2	-2
होन्डुरास	-2	2	-3	-2	-2	1	-2
द० अफ्रिका	-4	-3	—	—	—	1	-1
नागो	-10	9	-19	-5	-14	-14	—
मोरक्को	-14	-9	-5	-2	-3	1	-2

बचतों व बचतों से पूँजी निर्माण बढ़ाने के उपाय :
बचतों व पूँजी निर्माण बढ़ाने के लिए मुख्यतया तीन कदम उठाने पड़ते हैं

- (i) बचतों को बढ़ाना.
- (ii) बचतों को सस्थागत करना तथा
- (iii) बचतों को विनियोजित करना

बचतों को बढ़ाना :

बचतों की, किसी भी देश में, न्यूनतम व अधिकतम सीमाएँ होती हैं. हर देश को एक न्यूनतम मात्रा में बचत करनी ही पड़ेगी अन्यथा जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय गिर जाएगी. इसी प्रकार से बचतों की अधिकतम सीमा भी होती है. यह सीमा देश के साधनों, उनके प्रयोग, रोजगार स्तर, भ्रम व तबनीकी स्थिति, साहसियों के कार्य तथा करो की मात्रा पर निर्भर करती है. सर्वप्रथम कम विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रति-इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए पूँजी की मात्रा नापने की आवश्यकता पड़ेगी. इसको हम Capital-output ratio या Capital co efficient प्राँक्का कहते हैं. सामान्यतया Average capital-output ratios निकाले जाते हैं, परन्तु पूँजी की मादरयकता नापने के लिए Incremental capital-output ratio निकालनी पड़नी है.

इन प्राँक्कों के माधार पर हम अपेक्षित बचतों के अनुमान निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम उत्पादन को 20 रूपयों के बराबर बढ़ाना चाहते हैं, और हमारा Incremental capital output अनुपात 4 : 1 है तो जाहिर है कि हमें $20 \times 4 = 80$ रूपयों की पूँजी की आवश्यकता पड़ जाएगी.

हम इन्हीं माधारे पर विकास की सम्भावित दरों का पता लगा सकते हैं. जैसे माना कि राष्ट्रीय आय 1000 रु० है, और इनमें से 60 रु० बचाए जाते हैं तो बचत अनुपात 0.06 हुआ अब अगर उस देश में ICOR, चार हो उपर में 15 रु० के बराबर वृद्धि होगी (60 - 4) और इस प्रकार से विकास दर 1.5% हुई. अगर उत्पादन का Gestation period (फल देने शुरू होने के बाल) लगा हुआ तो बिपात की दर कम होगी और इसका वही प्रभाव होगा जो बचतों के अनुपात घटने या ICOR के बढ़ने का होता है.

Ecale : Estimates of Capital Requirements : Programming Technique of the first Group of Experts on Programming-The Role of Capital of G. Meier., op. cit :

हम इन्ही आधारों पर बचत का वांछनीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। जैसे माना कि किसी देश में जनसंख्या 1.5% प्रतिवर्ष के हिमाव से बढ़ती है, और बचत अनुपात 6% है तथा ICOR 4 है। यह क्रम देश के जीवन स्तर को ऊँचा नहीं उठा सकता है अब अगर हम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को 2% से बढ़ाना चाहें तो राष्ट्रीय आय को $1.5 + 2\% = 3.5\%$ से बढ़ाना होगा। अगर ICOR वही 4 रहे तो बचत अनुपात 06 से बढ़कर 14 होना होगा, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना होगा।

बचतों की वृद्धि रीतियाँ :

कम-विकसित देशों में बचतों की मात्रा बढ़ानी होगी तथा उन्हें संस्थागत बनाना जरूरी है। बैंकों, पोस्ट ऑफिसों, इन्स्योरेन्स कंपनियों, तथा सहकारी संस्थाओं व राज्य को इन देशों में बचतों को बढ़ाने का अभियान अत्यन्त दृढ़ मात्रा में करना होगा। आज कम-विकसित देशों में ये अभियान “भरपूर बचत योजनाओं” बीमा योजना आदि के रूप में चल रहे हैं। इनमें कभी शिथिलता नहीं आना चाहिए।

इन देशों में राज्यों को ऋणपत्र निर्गम करके बचतों को इकट्ठा करना चाहिए। इनको प्राप्त करने के लिए कम से कम कार्यवाही करना आवश्यक होना चाहिए विशेष क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली, विशेष योजनाओं के लिए, उन्हीं विशेष क्षेत्रों में राज्य को ऋणपत्र निर्गम करना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता तो इन ऋणपत्रों की Real value या वास्तविक मूल्य को कायम रखना है। मुद्रा स्कीति से ऋणदाताओं को हानि होती है, राज्य को कोई मुआवजे की योजना बनाना चाहिए, यर्थात् अगर मूल्य बढ़ जाएँ तो ऋणपत्रों के चुकाने में उतनी ही प्रतिशत धन अधिक दिया जाए।

सहकारी संस्थाएँ भी कम-विकसित देशों में बचतों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बीमा योजना का विस्तार भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली या निम्न जीवन यापन स्तर के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति असुरक्षा को उतनी गम्भीर समस्या नहीं समझते विकास से जैसे-जैसे उनका जीवन स्तर बढ़ेगा वे निम्नजीवन स्तर पर जाने की असुरक्षा की गम्भीरता समझने लगेगे और राज्य को इन क्षेत्रों में कम से कम औपचारिकता में बीमा पालिसियाँ देना चाहिए।

राज्य को बचत करने के लिए कुछ कर सचधी छूटें भी देना चाहिए राज्य को साहसियों को विकास कार्य व उत्पादन कार्य करने की सुविधाएँ देना चाहिए अगर

पूंजी-निर्माण व विकास

साहसियों को उचित कार्य वातावरण मिला तो स्वयं ही बचतों को खींच लेंगे। राज्य लाटरियों को शुरू करके भी बहुत-सी बचतें खींच सके हैं। C C Liang ने कम-विकसित देशों में बचतों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताई हैं :

- (a) सुरक्षा (Security) • देश में बचत करनेवालों को बैंकों के फेल होने के तथ्य में सुरक्षा होना चाहिए
- (b) आय (Yield) बचत योजनाएँ इस तरह की होनी चाहिए कि बचत करनेवालों को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके परन्तु बहुत ऊँची ब्याज की दर से देश में विनियोजन हतोत्साहित होगा
- (c) तरलता Liquidity देश में बचतों को इकट्ठा करने की रीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जमा कराने वाले व्यक्ति अपनी बचतों को अपनी आवश्यकतानुसार यथारीघ निकाल सकें
- (d) आसान पहुँच Accessibility कम विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंकों व पोस्ट आफिसों को खोलना चाहिए Mobile या गाँव-गाँव जाने वाली गाड़ियों से भी बीमा, जमा व लाटरियों के लिए बचतें इकट्ठी की जानी चाहिए
- (e) Divisibility भिन्न-भिन्न बचत योजनाओं को इस प्रकार बनाना चाहिए कि सब स्तरों की आय वालों को भिन्न-भिन्न बचत योजनाओं में धन लगा सके की सुविधा हो
- (f) Simplicity privacy and personal relations बचत योजनाओं में धन जमा करने व निकालने की कार्यविधि सरल होना चाहिए तथा बचत करने वालों की बचतों की मात्रा को अन्य व्यक्तियों से गुप्त रखना चाहिए तथा बचत करने वालों को व्यक्तिगत सेवा मिलना चाहिए

See

- 1 C C Liang • "Mobilization of Rural Savings with Reference of the Far East" Mobilization of Domestic Capital Report and Documents of the First working party of Experts, U N 1952 p 152-53
- 2 C Wolf and S C Sufrin Capital Formation and Foreign Investment in Under developed Countries, 1958
- 3 S Howard Ellis • The Financing of Economic Development in under-developed Areas Indian Economic Journal, 1956 p 266 cf D B Singh • op cit

बचतों का विनियोजन¹ :

बचतो को इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं होता, और न बचतो के बढ़ने से पूँजी निर्माण हो जाता है या उत्पादन व विकास वृद्धि होने लगती है. देश में विनियोजन प्रोत्साहन के लिए भी बैंक तथा अन्य संस्थाएँ स्थापित करना चाहिए.

शीघ्र फलदायक योजनाओं में अधिकाधिक विनियोजन आवश्यक है. इससे देश में मुद्रा स्फीति नहीं फैलेगी और बचत करने वालों की बचतों के मूल्य में ह्रास से उन्हें हानि नहीं होगी.

बचतों को विनियोजन में लाभदायक रूप से लगाया जा सके इसके लिए साहसियों को कार्य करने की सुविधा होना चाहिए तथा राज्य द्वारा संचालित उद्योगों को भी लाभ अर्जन करना चाहिए, अन्यथा देश में बचतों का उचित लाभ नहीं उठाया जा सकेगा.

(b) Capital formation through surplus manpower-Nurkse-Lewis Thesis or Disguised unemployment as a potential source of capital formation

जैसा कि हम देख चुके हैं² ल्युम तथा नर्क्स श्रम शक्ति के प्रयोग से ही पूँजी निर्माण की सम्भावनाएँ देखते हैं. इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि कम-विकसित देशों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत से व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जहाँ उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है जैसे एक खेत पर जहाँ चार व्यक्ति ठीक से खेती कर सकते हैं वहाँ पर व्यक्ति कार्य करते हैं क्योंकि अन्य दो व्यक्तियों के पास कुछ और करने की नहीं होता है इस प्रकार से ये व्यक्ति कृषि आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त होते हैं क्योंकि इनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है.

इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि अगर इन व्यक्तियों से पूँजी निर्माण कार्य कराया जाये (जैसे बाघ बनवाना, भूमि सुधार कराना, जंगल लगवाना, सड़कें बनवाना तथा खान व कारखानों के निर्माण कार्य कराना) तथा उन्हें वेतन न दिया जाये तो पूँजी-निर्माण "सागत-हीन" (free or self financing) हो जाएगा.

1. अगला अध्याय Investment Criteria पर विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए.
2. इस सम्बन्ध में आय Lewis तथा Nurkse के मॉडल में पढ़ चुके हैं. सदर्भ भी वही है.

उनका कथन है कि इनका थो कुछ दिया जाये वह उन्हीं परिवारों से ले लिया जाए जहाँ ये व्यक्ति पहले रह रहे थे और खाले पीते थे. इस प्रकार वे वगैर बेतन के कार्य कर सकेंगे, अर्थात् उनके बेतन के बराबर वन उनके परिवारों से Mobilize करना चाहिए. अर्थात् करो या भ्रष्ट रीतियों द्वारा प्राप्त करना चाहिए. इस प्रकार से इन अतिरिक्त व्यक्तियों के पूर्ण प्रयोग से वचन व पूँजी-निर्माण की सम्भावनाएँ हैं.

स्पुस के अनुसार :

“विकास सिद्धान्त की मुख्य समस्या यह है कि वह उस प्रक्रिया को समझे जिससे एक ऐसी सम्बन्धवस्था, जो अपनी राष्ट्रीय भाग का केवल 4 से 5 प्रतिशत तक बचाती है वह अपनी राष्ट्रीय भाग का 12 से 15% भाग बचत करके विनिर्मुक्त करे.”

स्पुस के अनुसार कम-विकसित देशों में बचती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को निरस्त करने व उचित विकास स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 4% राष्ट्रीय भाग में वृद्धि आवश्यक होगी. इस विकास दर को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय भाग का 25% भाग को उपभोग नहीं करने दिया जाना चाहिए और इसी पूँजी-निर्माण करना चाहिए. इस 25% भाग का विवरण इस प्रकार से करना चाहिए .

- (i) राष्ट्रीय भाग का 13% भाग पूँजी निर्माण में.
- (ii) “ “ “ 12% भाग व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदान करने में
12% का बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए
3% शिक्षा पर.
2% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर.
3% उद्योग, कृषि व नृधर्म संबंधी खोजों पर.
4% सामान्य प्रशासन व कल्याण पर

स्पुस का कथन है कि आज कम-विकसित देश लगभग 85 प्रतिशत राष्ट्रीय भाग उपभोग करते हैं और केवल 15% बचतों हैं जो पूँजी निर्माण व व्यक्तिगत

See also :

1. W. A. Lewis : Some reflection on Economic Development : Economic Digest, Institute of Economic Development, Karachi, Pakistan, vol No. 3, No. 4. winter 1960 p. 3-5, G. Meier : op cit : 95-98

सेवाओं दोनों के काम लेते हैं। यह मात्रा कम है। इसी 15% में से जमीन व जेबरो में भी विनियोजन हो जाता है। इस कारण वास्तविक पूंजी-निर्माण बहुत कम हो पाता है।

ल्युस चाहते हैं कि राज्य कम से कम राष्ट्रीय आय का 20% भाग करों के रूप में ले ले जिसमें से 12% राज्य कार्यों पर व्यय करे और 8% का पूंजी-निर्माण करे 5% पूंजी-निर्माण निजी क्षेत्र से आना चाहिए और इस प्रकार से 13% वास्तविक पूंजीनिर्माण राज्य आसानी से शुरू कर सकता है।

नक्स व ल्युस की अतिरिक्त जनसंख्या के पूर्ण प्रयोग से पूंजी निर्माण की रीति में कई कमियाँ हैं, जिनका उल्लेख हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। संक्षेप में ये इस प्रकार हैं

- (1) उन परिवारों से, जहाँ 'अतिरिक्त' रह रहे ये खास सामग्री लेना कठिन होगा परिवार के बाकी सदस्य अपने उपभोग स्तर को ऊँचा कर लेंगे, क्योंकि उनमें से कई परिवार जीवन माफ़न स्तर के बराबर ही उपभोग कर रहे होते हैं।
- (11) इस प्रकार से साधना को इकट्ठा करने में बहुत सी प्रशासनिक व मानवागत सबधी कठिनाइयाँ आएँगी।
- (111) कम विकसित देशों में श्रमिक गतिशील नहीं होते और उन्हें अन्य स्थानों पर पूंजी निर्माण के लिए ले जाना अत्यन्त कठिन होगा शायद इसके कड़े कदम शासन को उठाना पड़ सकते हैं।
- (1V) कृषि से निकले अतिरिक्त व्यक्तियों को ट्रेनिंग दिए बगैर पूंजी-निर्माण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार से पूंजी-निर्माण Self financing नहीं हो सकता।

लेकिन इस रीति को हम महत्वहीन नहीं कह सकते भारत में 'धर्मदात' पद्धति वास्तव में अतिरिक्त क्षमशक्ति के प्रयोग से पूंजी निर्माण का ही तरीका है थोड़ी बहुत मात्रा में इस रीति से पूंजी निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हो इस प्रकार से पूंजी निर्माण हो सकता है। चीन में अतिरिक्त जनसंख्या से Communes पद्धति के अन्तर्गत बहुत से पूंजी निर्माण कार्य सेना को अनुशासन पद्धति से कराये गए, जो कि काफी हद तक जबरन कराए गए।

बालान्तर में इस रीति से बहुत अधिक पूंजी-निर्माण नहीं हो सकेगा।

(c) Capital Formation through Inflation :

मुद्रा प्रसार¹ से या हीनार्षप्रवन्धन से पूंजी निर्माण करने के पक्ष में बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। वास्तव में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने अपने आर्थिक विकास के लिए कभी न कभी इस रीति को न अपनाया हो हम देख ही चुके हैं कि इस रीति को न अपनाने की खलाह देते हैं हम यह देखेंगे कि किन परिस्थितियों में मुद्रा स्फीति या हीनार्षप्रवन्धन से पूंजी निर्माण होता है या नहीं होता है।

1 अपने मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति के अध्येष्टों में भी इस सम्बन्ध में पड़ा है।

References :

- 1 K. K. Kurihara . The Keynesian Theory of Economic Development.
2. Keynes : Treatise on Money II; 1934, p. 149-177.
3. E. J. Hamilton : Profit Inflation and Industrial Revolution, Quarterly Journal of Economics, 1942, p. 263.
4. C. P. Kindleberger : Economic Development, 1958, p. 189-90.
5. P. H. Douglas : Real wages in U. S. 1890, 1926, 1930, p. 219, 46, 540
6. A. L. Bowley Wages and Income in the U. K. since 1860, p. 30, 34, 99.
7. F. Brown . The course of wage rates in five countries 1860-1939, Oxford Economic Papers.
8. U. N. O. : Conditions of Economic Progress, 1958.
9. A. V. Phillips : Public Finance in under developed countries.
10. Bayer & Yamey : op. cit.
11. Palekar : The Problems of wage Policy for Economic Development
12. Felipe Pazos : Economic Development and Financial Stability, IMF staff Papers 1952, p. 377.
13. U. N. Ecafe : "Inflation and Capital formation in under developed countries of Asia" Economic Bulletin of Asia and the far East," Vol II, No. 3, 1951, pp. 22-5.
14. Gardner Patterson : Impact of Deficit financing in under-developed countries : Some Neglected aspects, Journal of finance, Vol. XII, No. 2, May 1957, pp. 179-89.

दम-विकसित देश पूँजी निर्माण या तो

- (i) अधिक घटो तक (उतनी ही आय पर) काय करके पूँजी निर्माण कर सकत है या
- (ii) अधिक कर सकर सामूहिक पूँजी निर्माण कर सकत है या
- (iii) अधिक दबत बढ़ाकर (विशेषरूप से अनिवार्य बचत को) तथा
- (iv) मुद्रा स्तरीन फलाकर

- 15 H W Singer Deficit financing of Public Capital formation, Social and Economic studies sept 1958 Special Number pp 91-6
- 16 Gertrude Lovasy : Inflation and Exports in Primary Producing countries I M F Staff Papers 1962 March p 38-40
- 17 Graeme S Dorrance The Effect of Inflation on Economic Development I M F Staff Papers March 1963, p 1-31
- 18 H J Bruton Inflation in a Growing Economy Annual Lectures by Visiting Professor of Monetary Economics 1960-61, University of Bombay
- 19 Arthur I Bloomfield Monetary Policy in under developed countries in Public Policy Vol VII Edited by C J Friedrich and S E Harris Harward University Press 1956, p 244-72
- 20 U Tun Wai The Relation Between Inflation and Economic Development A Statistical Inductive study, staff Papers Vol VII 1959 60 p 302-17
- 21 O S Shrivastava op cit p 39 44 on Inflation Vrs Capital Formation
- 22 W W Lockwood Economic Development of Japan p 300 01
- 23 Kuczinsky, Jurgen, A short History of Labour conditions under Industrial Capitalism Germany 1800 to the Present Day, 1945 Vol III, pt 1
- 24 Harry Schwartz Russia's Soviet Economy p 840-42 1950
- 25 A Baykov The Development of Soviet Economic system
- 26 P, A Baran The Political Economy of Growth 1958 p 40
- 27 J A Schumpeter The Theory of Economic Development p 154
- 28 Dr V K R V Rao Deficit Formation and capital Formation in op cit
- 29 Cf G Meier op cit IV Part complete

पूँजी-निर्माण व विकास

प्रथम तीनों रीतियों को अपनाने की अपनी अपनी सोमाएँ हैं. कन विकसित देशों में जितनी पूँजी-निर्माण की आवश्यकता पड़ती है उतनी मात्रा में करो से घाय प्राप्त नहीं हो सकती. भारत में जहाँ राष्ट्रीय आय का केवल 10% भाग करो के रूप में प्राप्त होता है वहाँ यू० के० में राष्ट्रीय आय की 33% भाग करो में ले लिया जाता है. राज्या को इतनी अधिक मात्रा में कर लगाने की राजनैतिक हिम्मत भी नहीं होती.

मुद्रा स्फीति फैलाकर पूँजी-निर्माण करने के समर्थक अर्थशास्त्रियों का कथन है कि राज्य को चाहिए कि वह हीनार्थप्रवन्धन करके मुद्रा स्फीति फैलाएँ. राज्य को चाहिए कि वह मूल्य तो बढ़ने दें परन्तु मजदूरी को उसी अनुपात में न बढ़ने दें मजदूरी को अगर न बढ़ने दिया गया तो उत्पादनकर्त्ताओं के लाभ बढ़ेंगे तथा वे बचत करके पूँजी-निर्माण कर सकेंगे. मुद्रा स्फीति से अनावश्यक वस्तुओं का उप योग भी कम होगा और बचतों में वृद्धि होगी. मुद्रा स्फीति से जो उत्पादनकर्त्ताओं को लाभ होता है उसमें से वे अधिकधिक भाग से पूँजी निर्माण कर लेते हैं क्योंकि उनकी उपभोग क्षमता कम होती है. उत्पादनकर्त्ता यह लाभ दो रूप से उठा सकते हैं :

(1) मूल्य वृद्धि से उन्हें लाभ उठाने दे तथा उनकी मजदूरी व कच्चे माल संबंधी लागतों को न बढ़ने दिया जाए, तथा

(2) जब उत्पादकता बढ़ रही हो तब उनको मूल्य घटाने को न कहा जाए. इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि इस प्रकार से पूँजी-निर्माण करने में अल्पकालिक कठिनाई ही हो सकती है. जो मुद्रा स्फीति होगी वह Self-Liquidating होगी, अर्थात् स्वयं समाप्त हो जाएगी. मुद्रा स्फीति से पूँजी-निर्माण होगा, और इस पूँजी से उत्पादन बढ़ेगा जिससे मूल्य स्वयं घिर जाएंगे. उधर राज्य को भी अधिक उत्पादन व माय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से आय बढ़ जाएगी, और राज्य को हीनार्थप्रवन्धन की आवश्यकता नहीं रहेगी.

प्रत्येक देश ने, इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अपने विकास के शुरू के काल में इस नीति को अपनाया है.

U S A. में, युद्ध काल में मूल्यों में 50% वृद्धि हुई और अगर इतनी वृद्धि नहीं होती तो पूँजी-निर्माण संभव न होता. जापान ने भी (विशेष रूप से 1929-39 में) मुद्रा स्फीति फैलाकर ही पूँजी-निर्माण किया. जर्मनी में भी 1919-1923 की मुद्रा स्फीति ने पूँजी-निर्माण में सहायता की. जर्मनी में 1801-1914 के

बीच उत्पादन 50 गुना बढ़ा परन्तु वास्तविक मजदूरी को केवल 16 प्रतिशत ही बढ़ने दिया गया और इस प्रकार पूँजी-निर्माण किया गया

स्वयं रूस में 1929-39 के बीच मूल्य 700% बढ़ गए और 1928 से 1952 तक वास्तविक मजदूरी बराबर गिरती रही 1948 में तो वास्तविक मजदूरी 1928 के अनुपात में केवल 45% रह गई थी इस प्रकार से रूस में मूल्य वृद्धि करके, तथा वास्तविक मजदूरी कम रखकर पूँजी-निर्माण किया गया

संक्षेप में यह कहा जाता है कि कालान्तर में मुद्रा स्फीति की निशानी स्वरूप केवल बाँव, सड़कें व कारखाने रहेंगे जो आर्थिक विकास के ठोस प्रमाण होंगे.

Arguments against विपक्ष में तर्क :

1. आज के युग में मुद्रा स्फीति से पूँजी निर्माण के विपक्ष में अधिकाधिक अर्थ-शास्त्री होने जा रहे हैं मुद्रा स्फीति में पूँजी-निर्माण करने को Ostrich Mentality "शुनुरमुर्ग मनोवृत्ति" कहा जाता है, अर्थात् तथ्यों के सामने झिल्ले बन्द करना है.¹ जिन देशों ने पुराने जमाने में इस नीति को अपनाया था उसकी विशेष परिस्थितियाँ थीं जापान में हर व्यक्ति एक उत्साही साहसी था, रूस में राज्य का अकुश था, इंग्लैंड में आवश्यक कच्चा माल व खाद्य सामग्री सस्ते मूल्यों पर बाहर से आ जाती थी आज ये परिस्थितियाँ बहुत से कम-विकसित देशों में नहीं हैं.

U. Tun Wai .

2. (जिनके सन्दर्भ का उल्लेख किया जा चुका है) के अनुसार मुद्रा स्फीति व पूँजी-निर्माण व विकास में सह सम्बन्ध नहीं है मुद्रोत्तर काल के विकसित देशों के सन्दर्भ में उन्होंने बताया कि स्थिर मूल्यों पर जहाँ 4% विकास दर प्राप्त हुई वहाँ कम मात्रा में मुद्रा स्फीति से इसमें आधी ही विकास दर प्राप्त हुई और अधिक मुद्रा स्फीति से तो और कम हो गई. निम्न तालिका इसी बात को दर्शाती है :

-
1. रेगिस्तान में जब तूफान आता है तो शुनुरमुर्ग चौच व झिल्लें रेत में घोंसा लेता है और जब तक तूफान बन्द नहीं होता देखता ही नहीं है

हाल के वर्षों में मुद्रा स्फीति व आर्थिक विकास में सम्बन्ध.

	प्रति व्यक्ति विकास दर का वार्षिक प्रतिशत		
	स्थिर स्थिति	कम-मुद्रा स्फीति	अधिक मुद्रा स्फीति
यू० एन० प्रो० के अनुमान	2	2	2
U. Tun Wai के (i) Unadgusted अनुमान	6	2	3
(ii) भुगतान की शर्तों के अनुसार सशोधित	4	1	1
Per capita Social Productivity	4	3	—

- मुद्रा स्फीति से अगर पूँजी-निर्माण बढ़ता है तो विनियोजन की लागत भी तो बढ़ जाती है वास्तविक आय के अनुपात में मौद्रिक आय अधिक बढ़ जाती है। कृषि क्षेत्र में पूँति की वेलोचपन के कारण उत्पादन शीघ्र नहीं बढ़ता और अनुपात से कम बढ़ता है, इससे और मूल्य बढ़ने लगते हैं। राज्य की कठोर द्वारा प्राप्त की गई आय का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है और उसे और अधिक मात्रा में मुद्रा स्फीति हीनार्थ प्रचन्धन से करनी पड़ती है। मुद्रा स्फीति फिर बढ़ती ही जाती है
- मुद्रा स्फीति के कारण व्याज, लगान व मजदूरी प्राप्त कर्ताओं को हानि होती है। कृषकों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के मुकाबले में उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक बढ़ जाता है जिससे वे भी उतनी मात्रा में लाभान्वित नहीं होते।

मुद्रा स्फीति के कारण वे ही वर्ग नुकसान उठाते हैं जो सबसे कम बोन सकने वाले व कमजोर होने हैं. विकास गरीबों की भलाई के लिए किया जाता है जब कि मुद्रा स्फीति से इनका ही अहित होता है. इससे वर्गसंघर्ष बढ़ता है और ग्राह्य के युग में समाज इसे सहन नहीं करेगा.

5. मुद्रा स्फीति से जो वचतें पनपती हैं, यह आवश्यक नहीं कि वे पूँजी-निर्माण के कार्य में ही लाई जाएँ. बहुधा वे सट्टों (वितरण में लाभ) सम्पत्ति व Inventory accumulation (सामान इकट्ठा करने) में लगा देने हैं. वचतों को सोना, चाँदी आदि में भी लगा दिया जाता है.
6. मुद्रा स्फीति से फिजूल खर्चों, अयोग्यता व लागत बढ़ती हैं. ऐसे उद्योगों का निर्माण हो जाता है और ऐसी वस्तुएँ बिकने लगती हैं जो कि केवल मुद्रा स्फीति के बने रहने पर ही बिक सकती हैं. विनियोजन मूलतः मदों में हो जाता है और बहुधा Excess Capacity (आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्षमता) का निर्माण हो जाता है U. S. A. में 1952 के तैयारी के काल में भी केवल 52% उत्पादन क्षमता का प्रयोग हो सका था.
7. मुद्रा स्फीति से निर्यात हतोत्साहित होने हैं और आप्यात या चोरी छिपे माल लाना प्रोत्साहित होता है और इससे विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं. विदेशी विनियोजक भी स्थिर मुद्रा के देशों में विनियोजन पसंद करते हैं.
8. I. M. F. के Staff Papers की गवेषणा के अनुसार दीर्घ काल में मुद्रा स्फीति पूँजी-निर्माण के स्थान पर पूँजी-ह्रास का कारण बन जाती है. Chile (चिली) में जहाँ 1944 में राष्ट्रीय आय का लगभग 7% भाग का पूँजी-निर्माण हुआ वहाँ 1951 में वह मुद्रा स्फीति के कारण 4.7% ही रह गया. कोलम्बिया में मुद्रा स्थिरता के कारण इसी काल में पूँजी-निर्माण का प्रतिशत 12.1% रहा इन्डोनेशिया में प्रेसीडेन्ट सुकर्णो के शासनकाल के अन्तिम कुछ वर्षों में ही मूल्य 10000% बढ़ गए परन्तु पूँजी-निर्माण भारत के मुकाबले में जहाँ इस काल में केवल 100% वृद्धि हुई पूँजी-निर्माण घट गया.
9. दीर्घकाल तक बने रहने वाली मुद्रा स्फीति से सामाजिक कल्याण घटता है और मुद्रा स्फीति "self-liquidating" होने के स्थान पर self-limiting तथा "self-frustrating" हो जाती है. गरीब लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय घटाना पड़ता है. इससे भूखीनी व भौतिक पूँजी चाहे बढ़ जाए परन्तु मानवीय पूँजी का तो ह्रास होता है. कम-विकसित देशों में कम

कुशल व्यक्तियों को ही काम नहीं देना होता है, बल्कि कुशल व्यक्तियों की कमी के कारण उन्हें भी रोज़गार नहीं दे पाते।

10. मुद्रा स्फीति के काल में हर वर्ग अपनी वास्तविक आय बनाए रखने का प्रयत्न करता है। मजदूर अपनी मजदूरी बढ़वाते हैं, राज्य को सस्ते दर पर आवश्यक सामान उपलब्ध कराना पड़ता है, मूल्य नियन्त्रण चरने पड़ते हैं। जब यह सब करना पड़े तो उत्पादनकर्तृओं को लाभ भी न होंगे और फिजूल में प्रशासनिक समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।

इसलिए इस नीति को अल्पकाल में, शीघ्र उत्पादन कार्यों (with short gestation period) के लिए अपनाया चाहिए। उत्पादकता वृद्धि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। अन्य राजकोपीय तरीकों से करो से पर्याप्त धन लेना चाहिए तथा निजी बचती को प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरे विचार में :

“Inflationary finance as a means of capital formation should be resorted to as a last resort and within sober limits and should not be made a permanent policy”

- (d) Fiscal Measures for Promoting Capital Formation :

पूँजी-निर्माण व राज्य की राजकोपीय नीतियाँ :

(इस अवधि में कृपया 'राजकोपीय नीति' सवधी प्रध्याय में ध्यान पुन पढ़िए)

- (e) Capital Formation by Reducing Consumption :

पूँजी-निर्माण उपभोग कम करके :

यह प्रत्यक्ष रीतियों को दूसरे रूप में व्यक्त करना है। Lewis रीति में भी उपभोग कम करके पूँजी-निर्माण करने की सलाह दी थी। राजकोपीय नीति का भी एक उद्देश्य करो से उपभोग कम रखने की सलाह दी जाती है। मुद्रा स्फीति फैलाकर भी उपभोग को नियन्त्रण रखने का लक्ष्य रखता है।

परन्तु कम-विकसित देशों में उपभोग को कम करने की संभावनाएँ कम ही हैं। पर इस बात की सम्भावनाएँ भी कम हैं कि उपभोग को बढ़ने से रोका जाए। पिछले जमाने में भिन्न-भिन्न देशों में उपभोग कम रखने के जो भी कारण रहे हैं आज कम-विकसित देशों में समान इस बात को गवारा नहीं करेगा कि प्रचि-काश जनता का उपभोग कम रखा जाए। जनता को भी विकास में लाना-बित

होना चाहिए दूसरे जितनी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में उपभोग कम भी तो नहीं हो सकता. उतनी मात्रा में उपभोग को पुन प्राप्त करने में कई साल लग जायेंगे केवल 1.5 या 2% राष्ट्रीय बढ़ाने के लिए लगभग 15% उपभोग कम करना पड़ेगा इतना उपभोग हर वर्ष कैसे कम हो सकता है ?

वास्तव में कभी तो अनावश्यक व विलासिताओं के उपभोग में (जिसे James S Duesenberry, "Demonstration effect expenditure" कहते हैं) कमी लाना चाहिए, अनावश्यक आयातों पर भी इसी तरह नियंत्रण होना चाहिए.

(f) Better Utilisation of Resources : साधनों के पूर्ण प्रयोग से पूँजी-निर्माण :

कम-विकसित देशों में पूँजी की कमी होते हुए भी पूँजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है. बहुत कुछ इसका कारण देश में Complementary resources या पूरक साधनों (विशेष रूप से कुशल प्रशासक व तकनीकी व्यक्ति) का न होना रहता है. नई मशीनें लगाने से पूर्व, पुरानी मशीनों का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए यह कार्य पालियाँ (Shifts) बढ़ाकर किया जा सकता है. कभी कच्चे माल के समय से न मिलने, शक्ति की कमी या यातायात की सुविधाओं के समय पर न मिलने से पूँजी का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता और एक कम-विकसित अपने सबसे दुर्लभ साधन का दुरुपयोग नहीं कर पाता अगर देश में पूँजी का पूर्ण प्रयोग हो तो Capital-output ratio पूँजी-निपज अनुपात घट जाता है और देश के विकास में सहायता मिलती है. जैसे युद्ध के काल में पूँजी का पूर्ण प्रयोग होता है वैसे ही अगर शान्ति काल में हो तो विकास के लिए नई पूँजी की आवश्यकता कम रहेगी.

विकास के लिए केवल पूँजी ही महत्वपूर्ण नहीं होती पूँजी से अधिक महत्वपूर्ण "तकनीकी उन्नति" होती है. आज अगर कम देशों में अमेरिका के बराबर प्रति व्यक्ति पूँजी उपलब्ध हो भी जाए तो उत्पादन व उत्पादकता के अमेरिकी स्तर पर नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इन देशों को अम शक्ति उन तकनीकों को अपनाने की योग्यता नहीं रखती. जरूरत तो इस बात की है कि कम-विकसित देश ऐसी तकनीक अपनाएँ और ऐसी तकनीकी उन्नति करते रहे जिसमें उनकी अमशक्ति का भी पूर्ण प्रयोग हो, जो सस्ती हो तथा जो शीघ्रता से सीखी जाएँ. पूँजी वृद्धि के साथ साथ तकनीकी उन्नति भी पूँजी निर्माण का अंग मानना चाहिए.

श्रम-शक्ति :

श्रम-शक्ति का पूर्ण प्रयोग भी पूँजी निर्माण के लिए आवश्यक है इस संबंध में एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना है यह कहा जा सकता है कि जब तक पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तब तक श्रम-शक्ति का पूर्ण प्रयोग नहीं हो सकता परन्तु यह भी तो सही है कि जब तक साधनों (श्रम व प्राकृतिक) का पूर्ण प्रयोग नहीं होगा तब तक देश में उत्पादन वृद्धि नहीं होगी और तब तक पूँजी निर्माण नहीं होगा। कम-विकसित देशों में प्रायः आर्थिक उत्पादकता वृद्धि पर जोर दिया जाता है (कम लागत पर अधिक उत्पादन) पर सामाजिक उत्पादकता वृद्धि (अधिक रोजगार) पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता अगर उपर्युक्त आर्थिक नीतियों की अपेक्षा साधनों का पूर्ण प्रयोग किया जा सके तो इससे स्वयं वक्तों में वृद्धि होगी और पूँजी-निर्माण बढ़ेगा

श्रम ही उन्नत तकनीक को जन्म देता है या उन्नत तकनीक को कार्यान्वित करता है, तथा श्रमद्वारा उत्पादित धन में से ही पूँजी-निर्माण होता है (Capital is stored up labour). Solomon Fabricant के अनुमानों के अनुसार, U. S. A. में 1869-73 में 1949-53 के बीच प्रति-व्यक्ति उत्पादन 190% के हिसाब से बढ़ा। इसमें से केवल 1/10 भाग पूँजी की वृद्धि से हुआ तथा बाकी का 9/10 भाग श्रम की कार्यक्षमता, लगन व उत्पादकता वृद्धि के कारण हुआ। इसलिए कम-विकसित देश अगर बेरोजगारी की समस्या का निराकरण न कर सके और बेरोजगारी को बढ़ने देते रहे तो पूँजी-निर्माण करने में ही विफल नहीं होंगे बल्कि उस पूँजी-निर्माण के लाभ भी कम होंगे U. N. O के Experts के अनुसार अगर कम-विकसित देश अपनी अर्थरोजगार क्षीरित जनता या शहरी मजदूरों को उनके खाली समय में कुर्पा, तालाब, नहरें, दवा, स्कूल, अस्पताल, सबकी के निर्माण, जंगल लगाने आदि पर लगा सके तो पूँजी-निर्माण बढ़ेगा।

V. Capital Formation and Economic Growth :

पूँजी-निर्माण व आर्थिक विकास-महत्त्व .

पूँजी-निर्माण व आर्थिक विकास में क्या संबंध है इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद है। परन्तु मुख्यतया आज इस बात पर सहमति है कि पूँजी का

1. Shultz, Theodor W. : "The Role of the Government in Promoting Economic Growth" State of the Social Sciences, (Ed). White Lcoraw. D Chicago, 1956, p. 372.
Quoted from D. B. Singh : op. cit. 176.

विकास में बहुत अधिक महत्व नहीं होता। Alec Cairncross पूँजी को विकास कारक घटक के रूप में कम महत्व देते हैं। उनका कथन है -

“अतिरिक्त पूँजी, चाहे वह विदेशों से उधार ली गई हो या देश में अतिरिक्त जनशक्ति के पूर्ण प्रयोग से संचित की गई हो, स्वयं में, देश में औद्योगिकरण का चक्र शुरू करने में पर्याप्त नहीं होती पूँजी-निर्माण के साथ-साथ, कुशल संगठन, प्रशासकों व मजदूरों की उचित ट्रेनिंग तथा उचित वातावरण बनाना भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण देश में नवप्रवर्तन करने व विकास करने की मनोवृत्ति का निर्माण करना होगा।”

“श्री ब्रेनक्रास” के अनुसार पूँजी विकास कारक नहीं होती वरन् विकास के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होती है। (Capital formation is not a causal factor of growth but a concomittant phenomenon) उन्होंने बताया कि

“18वीं सदी में पूँति की ओर से नये-नये आविष्कारों तथा नवप्रवर्तनों के कारण विकास हुआ और माँग की ओर से बढ़ने हुए बाजारों से विकास हुआ”

इन कारणों में जो लाभ हुए उनमें पूँजी-निर्माण सम्भव हो सका। वास्तव में पूँजी के साथ-साथ अन्य सहयोगी व पूरक घटक (Co-operant factors) भी महत्वपूर्ण होते हैं

कभी-कभी पूँजी को बहुतायत होने हुए भी कुशल साहसियों, संगठनकर्ताओं और श्रमिकों की कमी के कारण, विकास नहीं हो पाता इसी प्रकार में कभी-कभी साहसियों को पूँजी के अभाव में (जब पूँजी-निर्माण कम हो तथा जब पूँजी को भूमि व सोने के रूप में संचित कर रखा हो) विनाम कार्यक्षेत्र में लेना सम्भव नहीं होता

See

I J. H. Adler & K. S. Krishnaswamy - “The supply of capital and the supply of other factors” in Economic Development for Latin America, Proceedings of a conference held by International Economic Association, (Ed) by H. S. Ellis, St. Martin's Press N. Y. 1961, p 126-30

II Alec Cairncross : “The place of Capital in Economic Progress (Ed), Dupriez Economic Progress, Papers and Proceedings, I. E. A 1955 p 248

Bayer and Jamey, ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने भी कहा है कि

“पूँजी विकास के लिए आवश्यक अंग आवश्यक हो सकती है, परन्तु उसका होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम एक कम-विकसित देश को विकसित देश की भाँति पूँजी या मशीनें प्रदान भी कर दें तो उससे विकास मुनिश्चित नहीं होता।”

सच्चाई की बात तो यह है कि विकास की प्रक्रिया पूँजी-निर्माण को जन्म देती है न कि विकास पूँजी-निर्माण का परिणाम है।

इन प्रवर्धनात्मकियों के अनुसार आर्थिक विकास को जन्म देने और बनाये रखने में बहुत से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक वस्त्र महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनमें सह-सम्बन्ध पूर्णरूप से नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा, हम यह कह सकते हैं कि, अन्य बातों के साथ साहसियों की मनोवृत्ति, पूँजी की मात्रा, तकनीक, श्रम की कुशलता इन सबसे विकास होता है, इनका अलग-अलग योगदान निकालना कठिन है। Simon Kuznets ने भी कहा है :

“The major Capital stock of an industrially advanced country is not its physical equipment; It is the body of knowledge amassed from tested findings and the capacity and training of the population to use this knowledge effectively.”

Dr. (Miss) Ishrat Z Husain ने भी पूँजी व विकास में सह-सम्बन्ध को तापा है और उनके निष्कर्षों का सार हम नीचे दे रहे हैं उनके अनुसार :
समस्त देशों की जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कुल प्रान्तरिक पूँजी-निर्माण (Gross domestic capital formation) तथा देश के कुल प्रान्तरिक उत्पादन दर (The rate of growth of gross domestic product) में घनात्मक सह-सम्बन्ध तो है परन्तु वह बहुत कम है। उनके

See .

Bayer & Jamey : op. cit ch X : Capital p. 127 ff.
Simon Kuznets quoted in United Nations, Process and Problems of Industrialization in under-developed countries New York 1955, P. 5.

अनुसार यह संबंध (Correlation) $+0.44$ है, हालांकि यह संबंध विकसित देशों के लिए अधिक है

निम्नलिखित तालिका में इसका विवरण है :

Co-efficient of Correlation Between The Rate of G.D.C Formation Proportion and the Annual Rate of Growth of Real G D P

1. Value of r (Correlation) for 34 countries	+ 0.44
2. " " " for 11 industrialized "	+ 0.50
3. " " " " 10 (Excluding Germany)	+ 0.71
4. " " " " 8 Semi-industrialized "	+ 0.88
5. " " " " 15 Under-developed "	+ 0.51

महत्व :

उपरोक्त विश्लेषण का अर्थ यह सिद्ध करना नहीं है कि पूँजी का विकास में बहुत कम महत्व है। वास्तव में लक्ष्य यह था कि यह बताया जाए कि पूँजी "सबसे अधिक महत्वपूर्ण" नहीं है। पूँजी-निर्माण किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है पूँजी का महत्व इसलिए अधिक है कि जहाँ भूमि की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता तथा श्रम की पूर्ति को भी बहुत से मनो-वैज्ञानिक अवरोधों के कारण शीघ्रता से नहीं बढ़ाया जा सकता। पूँजी की पूर्ति की गतिशीलता अधिक होने के कारण तथा उसकी किस्म में सुधार की ज़रूरत को देखते हुए सम्भावना के कारण, पूँजी का महत्व बढ़ जाता है। अन्ततः पूँजी की मात्रा में वृद्धि से ही विनियोजन में वृद्धि हो सकती है तथा श्रम व भूमि की किस्म सुधारी जा सकती है। पूँजी के प्रयोग से ही हम उन्नत तकनीक या उत्पादन के जटिल Round about methods of production को अपना सकते हैं पूँजी के होने से ही हम (Capital deepening) गहन-पूँजी विनियोजन (अर्थात् उद्योगों में अधिक पूँजी लगाना) तथा बहुत से क्षेत्रों में विनियोजन (Capital widening) कर सकते हैं। अन्य शब्दों में हम पूँजी से बड़े पैमाने के उत्पादन से आन्तरिक मितव्ययिताएँ प्राप्त कर सकते हैं (By capital deepening)

For a detailed and excellent discussion See her "Economic Factors in Economic Growth", p. 155-173.

"Capital-output Ratio तथा भारत में पूँजी-निर्माण व पूँजी-निपज अनुपात पर आगे अलग अध्याय देखिए

पूँजी-निर्माण व विकास

तथा capital widening से हम देश में सतुलित विकास को या बाह्य मित-व्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं

Shri P. C. Malhotra के शब्दों में :

"One cannot take more out of the pot than one has put into it"

इसलिए पूँजी-निर्माण के ऊपर विकास बहुत अधिक निर्भर है.

देश में पूँजी-निर्माण से देश लाभान्वित हो इसके लिए पूँजी-निर्माण में मे Leak-ages या "भ्रिस्ल" नहीं होना चाहिए

Leakages and capital formation

पूँजी-निर्माण में मे कम से कम Leakages या "भ्रिस्ल" होना चाहिए श्री मल्होत्रा के अनुसार यह Leakages निम्नलिखित हो सकती हैं

1. उपभोग तथा आयात पूँजी-निर्माण में से Leakages होती हैं. समस्त उप-भोग व आयात तो कम नहीं हो सकते हैं इसलिए अनावश्यक आयात व उप-भोग कम करना चाहिए.
2. "भ्रिस्ल" मुद्रा स्फीति से होती है और इसे नियंत्रित रखना चाहिए.
3. भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक अकर्मण्यता व फंनाव (Parkinson's Law) भी पूँजी-निर्माण का "भ्रिस्ल" करते हैं और इसे भी रोकना होगा.
4. बड़े-बड़े "इम्प्रेजत बढ़ानेवाले कार्य" Prestige projects तथा अनावश्यक सार्वजनिक व्यय से सबसे अधिक बरबादी होती है. मार्च के अन्त में जो राज्य के डिपार्टमेंट या विभाग फिन्ल खर्ची करते हैं (Racing of March hares) वह पूँजी की बर्बादी करते हैं
5. साधनों का अपूर्ण प्रयोग भी महत्वपूर्ण भ्रिस्ल होती है. अन्त में

"The most important of all leakages is that resulting from self-complacency, self exoneration, perfunctory insistence on the forms of democratic management and control of public under-takings and the creation of a climate in which initiative is sapped ..."

(Retd) Principal P C Malhotra's, paper "Fundamentals of capital Formation for development" at Bhopal Seminar in 1966. He was the Director of the seminar "Leakages & capital Formation" This discussion is based on his paper.

अध्याय : 10

विनियोजन मानदण्ड

Investment Criteria

I. प्रस्तावना .

II. विनियोजन के मानदण्ड

- (a) कम गहन तकनीक : कम-पूँजी-उत्पादन अनुपात या अधिकतम रोजगार का मानदण्ड : Factor Endowment criteria/Labour Intensive technique/Low capital output ratio.
- (b) पूँजी गहन तकनीक : अधिक दर से आर्थिक विकास के लिए अधिक पुन-विनियोजन Capital Intensive Investment/Criteria to accelerate growth/The reinvestment quotient.
- (c) सामाजिक उत्पादकता वृद्धि का मानदण्ड
Social Marginal productivity.
- (d) विशिष्ट समस्या के निवारण हेतु विनियोजन.
Investment to solve specific problem
- (e) समयानुसार आयोजन का मानदण्ड.
The time factor criteria.

III. निष्कर्ष तथा व्यावहारिक मानदण्ड

IV. विनियोजन व स्वतंत्र मूल्य प्रणाली व राज्य द्वारा संचालन.

अध्याय : 10

विनियोजन मानदण्ड

Investment Criteria

I. प्रस्तावना :

कम-विकसित देशों के विकास के लिए पूंजी-निर्माण के पश्चात् पूंजी को उचित रूप से विनियोजित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

Everelt B Hagan के शब्दों में :

“विकास के लिए आयोजन कार्यक्रम निर्धारित करने समय सर्वप्रथम के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विनियोजन करने की समस्या मुख्यरूप से सामने आती है। पूंजी को भिन्न-भिन्न उद्योगों, भिन्न-भिन्न उत्पादन रीतियों, भिन्न-भिन्न प्रायिक क्षेत्रों तथा भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विनियोजित करने का प्रश्न सामने आता है, जिसको पूर्ण समन्वय पूर्ण रीति से करना चाहिए”

कम-विकसित देशों में विनियोजन के मानदण्ड चुनने का प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन देशों में पहले ही बचते व पूंजी कम रहती है इसलिए ये देश पूंजी की बरबादी को बर्बरित नहीं कर सकते यहाँ पर पूंजी का

- (i) कृषि उद्योग व तृतीयक क्षेत्र के बीच
- (ii) सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच
- (iii) पूंजी गत व उपभोग उद्योगों के बीच, तथा
- (iv) भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच

किस प्रकार वितरण हो, एक महत्वपूर्ण समस्या व कार्य होता है।

References :

1. Everelt E Hagan "The Allocation of Investment in under-developed countries", observations based on the experience of Burma
2. Jan Tinbergen . 'Investment criteria and Economic Growth'. Oct. 1954 Conference on Investment criteria and Economic growth in Cambridge, Asia Publishing house 1961, Reprinted 1964

विनियोजन के मानदण्ड केवल आर्थिक कारखों पर ही आधारित नहीं होते वरन् सामाजिक व राजनैतिक मानदण्डों के आधार पर भी निर्धारित होते हैं कम-विकसित देशों में कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में अधिक पिछड़े होते हैं। इन क्षेत्रों में साख, यातायात, व संचार की सुविधाएँ कम होती हैं और इन क्षेत्रों में कुशल श्रमिक संगठनकर्ता व साहसियों की भी कमी रहती है बाजार भी इन क्षेत्रों में संकुचित रहता है इन कारणों से, केवल आर्थिक मानदण्ड के आधार पर, इन क्षेत्रों में विनियोजन कम रखा जा सकता है। परन्तु आजकल सामाजिक व राजनैतिक कारणों से इन क्षेत्रों में भी विनियोजन करना पड़ता है।

Gerald Meier के अनुसार

विनियोजन के कई मानदण्ड हैं परन्तु हमको मुख्यतया निम्नलिखित मानदण्डों पर ध्यान देना चाहिए

- (I) Maximum employment absorption अधिक रोजगार वृद्धि
- (II) Maximum Social marginal productivity of capital पूँजी की अधिकतम सामाजिक उत्पादकता
- (III) Minimum Capital output Ratio न्यूनतम पूँजी-निपज अनुपात
- (IV) Maximum Reinvestment quotient अधिकतम पुनर्विनियोजन अनुपात.

Meier के अनुसार ये सब मानदण्ड आपस में एक दूसरे के परक नहीं हैं वरन् आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। उदाहरणतया यह सर्वथा उचित है कि कम-विकसित देश को अपने पूँजी-निपज अनुपात को कम रखने के लिए श्रम गहन तकनीक अपनाना चाहिए, परन्तु अधिकतम पुनर्विनियोजन के लिए पूँजी-गहन तकनीक ही आवश्यक होगी क्योंकि इसी क्षेत्र में अधिकतम लाभ होगा,

वस्तुतः इस अध्याय में मुख्य रूप से “श्रमगहन तकनीक” व “पूँजीगहन तकनीक” के सम्बन्ध में अध्ययन महत्वपूर्ण है।

Gerald Meier : Ch. V . Introductory Note . Leading Issues of Development Economics

D. B. Singh : op. cit - ch VII.

II. Various Investment Criteria • विभिन्न विनियोजन मानदण्ड :

- (a) Factor Endowment Criteria / Labour Intensive Technique / Nurkse - Lewis - Hekscher - Ohlin - Hayek Thesis / Low Capital - Output Ratio : श्रमगहन तकनीक : अधिकतम रोज़गार मानदण्ड : कम पूँजी-निपज अनुपात.

पक्ष :

उपरोक्त अर्थशास्त्रियों का कथन है कि कम-विकसित देशों को ऐसी विनियोजन नीति अपनाना चाहिए जिससे वे अपने उच्च साधनों का प्रयोग कर सकें जो उनके पास सबसे अधिक मात्रा में हैं, अर्थात् वे अपने श्रम का पूर्ण प्रयोग कर सकें. कम-विकसित देशों में पूँजी की कमी तथा श्रम की अधिकता रहती है, इसलिए कम-विकसित देशों को चाहिए कि वे श्रम-गहन तकनीक अपनाएँ और कम से कम पूँजी से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें.

इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि जैसे कम-विकसित देशों को उपभोग के क्षेत्र में 'नकल से प्रभावित उपभोग' नहीं करना चाहिए उसी प्रकार से कम-विकसित देशों को विकसित देशों की नकल कर के पूँजी-गहन तकनीक पूरी-पूरी तरह से नहीं अपनाना चाहिए. (This will be demonstration effect in production).

श्री हाएक का कथन है "एक ऐसा देश जिसके पास U. S. A. के बराबर पूँजी नहीं है उसको U. S. A. की तकनीक नहीं अपनाना चाहिए." कम-विकसित देश अगर पूँजी-गहन तकनीक अपनाएँगे तो इससे कुछ ही क्षेत्र में पूँजी केन्द्रित रहेंगे (Capital deepening in a limited sector) जाएंगी परन्तु अगर वे श्रम-गहन तकनीक अपनायेंगे तो पूँजी एक बड़े क्षेत्र में बँट जाएगी (Capital widening over a large field)

इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह Hekscher ohlin के तुलनात्मक सिद्धांत के अनुरूप है. श्रम लागत के कम होने के कारण उसे प्रयोग में लाना चाहिए. इन देशों में पूँजी-गहन तकनीक अपनाने से पूँजी का पूर्ण प्रयोग नहीं होता क्योंकि

See : Nurkse : op. cit.
Lewis : op. cit.
Hayek : op. cit.

} आप पुन. इनके मॉडल देखें.

वह कुछ ही सत्रों को सामान्वित करती है अगर एक बुलडोजर (Bulldozer) \$ 5000 म याता हो और जितनी मिट्टी वह हटा सकता है उसनी ही मिट्टी 1500 व्यक्ति हटा पाते हो जिन्हे \$ 2 5 का फावडा प्रत्येक को देना पड़े तो इससे केवल \$ 3750 की पूँजी लगेंगी और बेरोजगारी भी दूर होगी

कम-विकसित देशों में कृषि की जोतों का आकार भी इतना छोटा होता है कि पूँजी गहन तकनीक अपनाने से पहले महत्वपूर्ण भू-सुधार आदि करने होंगे,

विपक्ष आलोचनाएँ :

उपरोक्त विचार कि, जैसा कि अर्थशास्त्र में होता है, कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है. इन अर्थशास्त्रियों में Maurice Dobb, Kuznets, Bruton, Gerschenkron A O Hirschman तथा J. J. Polak Leibenstein मुख्य हैं उनकी मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार हैं

(i) श्रम-गहन तकनीक अपनाने से हम वर्तमान अवस्था को बनाए रखेंगे.

अगर कम-विकसित देश पिछड़ी तकनीक ही अपनाए रहे तो उत्पादकता भी कम बनी रहेगी आज का युग प्रवर्धित अवस्था का युग है और श्रम गहन तकनीक में ही विनियोजन करते रहना स्थगिक अवस्था में बने रहने के बराबर है कम-विकसित देश अगर इस नीति को अपनाते रहे तो विकास नहीं होगा. (Dobb)

(ii) कम-विकसित देश श्रम गहन तकनीक को पूँजी की कमी के कारण अपनाने हैं, परन्तु इससे तो पूँजी निर्माण और कम बन्ता रहेगा क्योंकि देश में पूँजी का आधार ही व्यापक नहीं हो पाता

(iii) J J Polak का कथन है कि यह सर्वथा गलत बात होगी कि एक Project को केवल इसलिए छोड़ दिया जाए कि उसमें Capital-output ratio अधिक है (अर्थात् उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक पूँजी लगानी पड़ती है) यह हो सकता है कि इस प्रकार के project (योजना या कार्य) से अन्य उद्योगों में Capital-output अनुपात कम होता हो, अर्थात् यह Project अन्य Projects का पूरक हो.

(iv) इसी प्रकार से उनका कथन है कि श्रम-गहन तकनीक अल्प-काल में तो कम खर्चीली होती है परन्तु दीर्घकाल में यह महंगी पड़ती है. बहुत से उद्योगों में वर्तमान कम पूँजी-निपज अनुपात देखने में ही कम

विनियोजन मानदण्ड

होते हैं, जैसे कृषि में श्रम-गहन तकनीक अपनाने से अधिक साद या उर्वरक देने पड़ सकते हैं।

(v) दीर्घकाल में कम पूँजी-गहन तकनीक अपनाने पर, श्रमिक सग इन्ही तकनीकों को बनाए रखने के लिए जोर देते रहते हैं और वे मशीनीकरण के खिलाफ हो जाते हैं, और देश को हमेशा पिछड़ी अवस्था में बनाए रहते हैं।

(vi) यह धारणा भी सही नहीं है कि श्रम-गहन तकनीक से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। पूँजी-गहन तकनीक से तीनों चरों में रोजगार के अवसर (primary, secondary and tertiary) बढ़ते हैं और दीर्घकाल में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

(vii) इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ श्रम-गहन तकनीक अपनाई हो नहीं जा सकती जैसे इस्पात, पेट्रोल, जल या वातायत योजनाएँ आदि।

(ix) Gerschenkron का कथन है : 'जितना जो देश तकनीकी नव-प्रवर्तनों में पिछड़ा हो उतना ही उसे औद्योगीकरण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, जैसा कि Veblen ने सही रूप से बताया है, उन्नत देशों की तकनीक को नकल करके ही पिछड़ा देश औद्योगीकरण कर सकता है।'

(x) Leibenstein ने भी इस विनियोजन मानदण्ड को उचित नहीं बताया है। उन्होंने कहा

"There is no evidence to lead us to believe that

(v) J. J. Polak. Balance of Payments Problems of Countries Reconstructing with the help of foreign loans, Quarterly Journal of Economics, Feb, 1943, 208-40 cf G. Meier : op. cit.

(vi) U. N. Ecafe : Criteria for allocating investment Resources among Various fields of Development in under-developed Countries : Economic Bulletin for Asia and the Far East, 1961 p. 30-33 - cf G. Meier : op. cit.

(vii) A. O. Hirschman : Economics & Investment Planning : Reflections based on experience in Colombia : cf Asia op. cit.

the particular technique suggested by Nurkse is the best way of obtaining the forced savings or that the amount so saved is optimum amount ”

- (b) पूँजी-गहन तकनीक अधिक विकास के लिए अधिक पुनर्विनियोजन :
 Capital Intensive Investment/or Criteria to Accelerate Growth/or The Reinvestment Quotient
 Rostow—Galenson—Leibenstein—Hirschman

ये अर्थशास्त्री प्रथम वर्ग के अर्थशास्त्रियों के विपरीत मत के हैं। इनका मत है कि किसी देश का विकास इसलिए रुका रहता है कि उस देश में पूँजी-गहन तकनीक नहीं अपनाई गई है और विकास के लिए पूँजी-गहन तकनीक के अपनाने से विकास होने लगेगा। आधुनिक तकनीक का साहसियों पर प्रवर्गिक असर होता है इस प्रकार की तकनीक अपनाने में अधिक लाभ होते हैं और फिर उनसे और अधिक बचतें होती हैं। पूँजी-गहन तकनीक अपनाने से सामाजिक अवरोध दूर होंगे।

A O Hirschman का कथन है कि कम-विकसित देशों को पूँजी-गहन तकनीक अपनाना चाहिए जिसके अन्तर्गत वे Project planning करें अर्थात् कुछ कार्य विशेष करें और इस प्रकार से असंतुलित विकास पद्धति अपनाएँ, वे संतुलित विकास पद्धति¹ के बारे में कहते हैं।

“Integrated development planning is a myth.”

उनका कहना है कि आजकल सरकारों, विदेशी विनियोजकों, अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजक सभों तथा आर्थिक सलाहकारों की ‘प्राकृतिक प्रवृत्ति’ यह है कि वे ऐसे

See also	Kindleberger	op cit
	B Higgins	“
	Meier & Baldwin	“
	Leibenstein	“
	Gerschenkron	“
	Singer	“

1. पाठक इस सबंध में “Balanced Vs Unbalanced Growth” के अध्याय को भी पुनः देखें। वास्तव में अमगहन तकनीक वाले विचार “संतुलित विकास पद्धति” तथा पूँजी-गहन तकनीक के विचार “असंतुलित विकास पद्धति” में मिलते हैं।

projects या योजनाओं को कार्यान्वित करने की सलाह देने हैं जो देश का नक्शा बदलते हैं न कि देश के व्यक्तियों की स्थितियाँ बदलती हैं वे कहते हैं
 "All Governments... .. show a preference for projects that can be inaugurated"

उनका कथन है

"यह बात कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की विशिष्ट योजनाएँ (specific projects) छोटे हुए समाज को जगा देने हैं, वे जागरूकता बढ़ाने के लिए उदाहरण तो बन जाते हैं. उनका कथन है कि निजी क्षेत्र के व्यक्ति स्वयं ही अपनी-अपनी योजनाओं के लिए Infra-structure तैयार कर लेंगे (घरों, पानी, बिजली, कुराल श्रमिकों की व्यवस्था कर लेंगे)"

वे मानते हैं कि इस प्रकार की तकनीक अपनाया उल्टा कार्य होगा. (It is no doubt inverted development) परन्तु कालान्तर में इससे मजबूत आधार शिला पर सर्वाङ्गोष्ण विकास हो सकेगा उदाहरणतया अगर हम पहले शराब बनाने या खड के टायर बनाने के कारखाने स्थापित करें और कच्चा माल बाहर से मगाएँ तो कालान्तर में वे देश में कच्चे माल को स्वयं उत्पादन करने लगेंगे और फिर Secondary sector द्वितीयक क्षेत्र की उन्नति से Primary sector या कृषिक्षेत्र भी उन्नत हो जाएगा इस सवय में हिशमैन कुछ अन्य बातों की ओर भी ध्यान खींचना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं

- (1) बड़ी-बड़ी विशिष्ट योजनाओं के साथ-साथ शिक्षा, छोटे उद्योग तथा सहयोगी उद्योगों पर भी ध्यान देते रहना चाहिए.
- (11) विशेष रूप से ऐसे उद्योग स्थापित करना चाहिए जिनमें सुधार कार्य maintenance बहुत कम हो या फिर सुधार कार्य इतने महत्वपूर्ण हो कि उन्हें टाला नहीं जा सकता है. हिशमैन उदाहरण देते हैं. सड़क का सुधारकार्य टाला जा सकता है परन्तु हवाई उड़ान संबंधी किसी भी सुधारकार्य को टाला नहीं जा सकता. इसलिए अगर विशिष्ट कार्य हाथ में लिए गए तो वे हमेशा अच्छी हालत में रहे जाएँगे, और specific projects से ही कार्य-क्षमता बढ़ाई जा सकती है¹

1. He says :
 "Under-developed countries are characterized not only by a low rate of investment, but also by the low efficiency of

- (iii) विनियोजन करने से पहले कई मुद्दों पर विचार कर लेना चाहिए जैसे
 (a) क्या विनियोजन आयात प्रतिस्थापन करे या निर्यात वर्धन में सहायक हो, (b) क्या विनियोजन से उत्पादकता बढ़ सकती है और क्या (c) उद्योग व कृषि में समन्वय आवश्यक है.

The Reinvestment quotient

Galenson तथा Leibenstein ने एक "अत्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" में विनियोजन की कल्पना की है. अगर विवास करना है तो इसके लिए इस "अत्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" से कम विनियोजन से कोई लाभ न होगा. अगर इस मात्रा से कम-विनियोजन किया गया तो अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में ही बनी रहेगी. विनियोजन की यह न्यूनतम मात्रा इतनी होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों का मुकाबला करते हुए भी विकास संभव हो सके. विनियोजन इतना और इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें लाभ हो और जिससे बचती व पूँजी-निर्माण में वृद्धि हो सके. इसके लिए मजदूरी दरों को कम रखना भी आवश्यक होगा. इनका विश्वास है कि पूँजी-गहन तकनीक से ही और अधिक विनियोजन के लिए पूँजी मिलेगी तथा दीर्घकाल में अधिक रोज़गार का सृजन होगा

विनियोजन को "Highest marginal per-capita reinvestment quotient." देना चाहिए, अर्थात् अधिकतम पुनर्विनियोजन योग्य धन उपलब्ध कराना चाहिए. Reinvestment quotient को हम "प्रति व्यक्ति उत्पादकता में से प्रति व्यक्ति उपभोग घटाकर अनुपात निकाल कर पता लगाते हैं."

विषय : आलोचनाएँ :

Hollis B Chenery, Henry villard तथा O. Eckstein ने पूँजी-गहन तकनीक की आलोचना की है. उनका कथन है कि इस नीति से :

much of the investment that is actually undertaken. This is due in part to the many false starts that will necessarily be made before a country's economy is really launched on a secure course, and in part of the lack of qualified engineers, agronomists, economists etc, who can produce really useful and well thought, though specific, investment projects".... . thus the most important-task for the economist is ■ make a contribution to the elaboration of sensible sector programmes and specific investment projects." op. cit p. 42-43. .

विनियोजन मानदण्ड

- (i) कम-विकसित देशों को पूंजी जुटाने के लिए बहुत अधिक कर लगाना पड़ेगा, उपभोग (जो पहले से ही कम है) कम करना पड़ेगा, या फिर विदेशों से बहुत अधिक ऋण लेना पड़ेगा.
- (ii) मजदूरी कम रखने से मजदूरों का जीवन स्तर गिरा रहेगा उनकी कार्य-क्षमता शिक्षा व ट्रेनिंग कम रहेगी तथा सामाजिक असन्तोष बढ़ेगा.
- (iii) बेरोजगारी को बनाए रखना देश के लिए घातक दृष्टिकोण से न केवल घातक होना वरन् इसके सम्भार राजनैतिक व सामाजिक दुष्परिणाम होंगे.
- (iv) इस पद्धति में वर्तमान उपभोग को नष्ट करने की सलाह दी जाती है ताकि भविष्य में उपभोग स्तर ऊँचे हो सकें परन्तु जनसाधारण इस सम्भावित वृद्धि के प्रति उदासीन हो जाते हैं

"After all investment choice is to be so made as to maximize the present value of the future consumption stream.....endless growth for its own sake does not make to much sense. There may be circumstances in which the current consumption may be a more immediate concern"

- (c) The Concept of Social Marginal Productivity सामाजिक उत्पादकता वृद्धि का मानदण्ड : A. E kahn, H. B. chen-cry, Everelt. E Hagan,

यह मानदण्ड सर्वप्रथम काहन् Kahn ने 1951 में प्रतिपादित किया. यह सिद्धांत भ्रम्यशास्त्र के जाने माने "सीमान्त उपयोगिता या उत्पादकता सिद्धान्त" का ही प्रतिरूप है. यह सिद्धांत इन शब्दों में व्यक्त किया गया

- (i) W. Galenson and H Leibenstein, "Investment Criteria, Productivity and Economic Development", Quarterly Journal of Economics August 1955 p. 343-70
- (ii) राय Leibenstein Model का अध्याय भी देखें Eckstein : Investment criteria for Economic development and the Theory of Inter-temporal welfare Economics, Quarterly Journal of Economics Feb. 1957. p. 56 85.

"The correct criteria for obtaining the maximum return from limited resources is the social marginal productivity, taking into account the total net contribution of the marginal unit to national product and not merely that portion of the contribution (or its costs) which may accrue to the private investor"

अर्थात् कम-विकसित देशों में दुर्लभ साधनों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए "सीमान्त सामाजिक उत्पादकता" सिद्धान्त अपनाया चाहिए अर्थात् विनियोजन से होनेवाले निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को ध्यान में रखना चाहिए.

अन्य शब्दों में कम विकसित देशों में भिन्न-भिन्न योजनाओं में विनियोजन इस प्रकार से किया जाए कि समस्त उद्योगों की सीमान्त सामाजिक उत्पादकता बराबर या लगभग बराबर हो. अगर वही विनियोजन की सीमान्त सामाजिक उत्पादकता कम हो तो वहाँ से साधनों का हस्तान्तरण वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ विनियोजन की सीमान्त उत्पादकता अधिक हो

Hagan के शब्दों में

"In a sense there is only one relevant economic criterion. In its usual statement it is that

A K Khan : Investment-criteria in Development Programmes, Quarterly Journal of Economics, Feb 1951. p 38 61

H. B. Chenery The application of Investment criteria, Quarterly Journal of Economics, Feb 1953, p. 76-96.

E V. Hagan : op. cit

See : Meier's : op cit & Asia Publishing House's op. cit.

See also :

I L O , "Social Productivity and Factor intensity criteria some aspects of the investment Policy in under-developed countries International Labour Review Vol Lxx VII, No. 5 May 1958 p p 289-90, 393-7, 400-4, 411-15,

Hagan : op-cit : Cf G Meier op-cit p. 58.

projects which comprise an investment programme should be so selected among alternative sectors, projects, methods and geographical locations that no included use of capital yields a lower social marginal product than any excluded use and by marginal product is meant total net value added, and not merely return to Capital."

"वास्तव में, एक मापने में, विनियोजन का एक ही मानदण्ड है और वह यह है कि भिन्न-भिन्न योजनाओं, कार्यों, क्षेत्रों व कार्य प्रणालियों में विनियोजन इस प्रकार से किया जाए कि जिसमें विनियोजन किया गया है उसमें सीमान्त सामाजिक उत्पादकता उससे कम न हो जिसे छोड़ दिया गया है"

इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि अगर इस मानदण्ड के आधार पर विनियोजन किया गया तो "Accounting Prices" या "Shadow prices" का सहारा लेना होगा Shadow prices "वे काल्पनिक मूल्य हैं जो अगर बाजार में हों तो अपेक्षित साम्य स्थापित किया जा सकता है" यह विचार] Tinbergen, Chenery तथा K S Kretschmer ने प्रस्तुत किया Accounting or shadow prices की यह परिभाषा प्रस्तुत की

"Shadow prices are the values of the marginal productivity of factors when a selection of technique has been made which produces the maximum possible volume of output, given the availability of resources, the pattern of final demand and the technological possibilities of production"

(अर्थात् ये वे मूल्य हैं जो अगर स्थापित कर दिए जाएं तो अधिकतम उत्पादन करने में सहायक होंगे)

See also :

R. S. Eckaus Technical change in the less Developed Areas, in the Development of the Emerging countries, Making an optimal choice of Technology.

इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि राज्य का कर्तव्य यह है कि वह उत्पादन के अग्रे व क्षेत्रों की सीमान्त उत्पादकता को अग्रे तथा अर्थव्यवस्था को, करो व सहायता द्वारा, इस प्रकार से संचालित करें कि समस्त पूर्ति के अग्रे की सीमान्त उत्पादकता बराबर हो। इस मानदण्ड के अनुसार विनियोजन करने के लिए केवल यह ही आवश्यक नहीं है कि अलग-अलग क्षेत्रों की सीमान्त उत्पादकता का पता लगा लिया जाए। मुख्य समस्या तो उत्पादनकर्ताओं को करो व सहायताओं से संबंधित प्रतिक्रिया को अध्ययन करना है।

अलोचना :

S M P Criteria या सीमान्त उत्पादकता के मानदण्ड की सबसे मुख्य अलोचना तो यह है कि सीमान्त उत्पादकता का निकालना कठिन है। कम-विकसित देशों में मूल्य निर्धारण पद्धति आधुनिक नहीं होती और न ही सारी अर्थव्यवस्था मौद्रिक मान पर संचालित होती है। इन देशों में श्रम की बेरोजगारी व मुद्रा स्थिति की प्रवृत्ति के कारण मूल्य स्तर 'वास्तविक' नहीं होता वास्तव में इन देशों में मूल्यों में कितने ही परिवर्तन करें, देश में सामाजिक सीमान्त उत्पादकता बराबर नहीं की जा सकती।

Otto Eckstein, Galenson तथा Leibenstein इस मानदण्ड की अलोचना करते हैं। इस मानदण्ड में जनसंख्या की वृद्धि का विनियोजन पर क्या प्रभाव पड़ता चाहिए। यह अध्ययन नहीं किया जाता इनका विचार यह भी है कि सीमान्त उत्पादकता के स्थान पर "औसत उत्पादकता" वृद्धि का विचार

"The more extensively one adjusts market prices upwards or downwards to allow for social factors the more one uses shadow or accounting prices in calculating social marginal productivity, the farther one gets from the realm of objective facts and the more heavily one relies on subjective value judgements. It is arguable that by the time one has finished making all the adjustments to private marginal productivity that would be needed to convert it into social marginal productivity one will be left with a concept so tenuously related to anything. That is objectively measurable that one might as well sever the connection altogether and admit that marginal analysis can provide no practical guidance to governments in taking investment decisions."

I. L. O. op. cit.

अधिक महत्वपूर्ण है। इस मानदण्ड के आधार पर ऐसी योजनाएँ भी हाथ में ली जा सकती हैं जो शून्य लाभ देती हों और इस मानदण्ड के अनुसार विनियोजन करने से बहुत अधिक कर लगाने पड़ेंगे (क्योंकि सामाजिक अधिक सिरोपरी का मूजन करना होगा)।

(d) Investment to control specific problem विशिष्ट समस्याओं के निवारण हेतु विनियोजन।

भुगतान संतुलन हेतु :

कम-विकसित देश विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गम्भीर कठिनाइयों में फसे रहते हैं उनका भुगतान संतुलन बहुधा विपन्न में रहता है और इससे उनकी अर्थव्यवस्था "drain economy" बनो रहती है धन विकसित देशों में आयात प्रतिस्थापक उद्योग तथा निर्यात-वर्धक उद्योगों की स्थापना के लिए विनियोजन किया जा सकता है वास्तव में यह बात उतनी सरल नहीं है, क्योंकि इन उद्योगों की स्थापना हेतु और अधिक विदेशी मुद्रा चाहिए होती है- इसलिए इस प्रकार का विनियोजन विदेशी सहायता के बिना संभव नहीं रहता, दूसरी कठिनाई इस सम्बन्ध में यह आती है कि इस प्रकार के विनियोजन से जो मुद्रा स्थिति फैलती है उससे निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित होते हैं इसलिए मुद्रा स्थिति को उत्पन्न न होने देना चाहिए अथवा नियंत्रित रखना चाहिए

निर्यात-वर्धक या आयात प्रतिस्थापक विनियोजन स्वयं में विकास नहीं लाता, कम विकसित देशों में विदेशी विनियोजकों ने इन देशों के कच्चे सामान के निर्यात-वर्धक उद्योग व वागान चलाए परन्तु फिर भी इन देशों में प्राथमिक विकास नहीं हुआ।

मुद्रा स्थिति नियंत्रण :

कम-विकसित देशों में मुद्रा स्थिति की स्थितियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं, विकास न होने पर वस्तुओं की कमी के कारण अथवा विकास के शुरु के दिनों में विनियोजन के कारण मौद्रिक प्रसार वृद्धि के कारण मुद्रा स्थिति फैल जाती है, ऐसे दिनों में विनियोजन नीति में परिवर्तन करके मुद्रा स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है, पूँजी महन उद्योगों में विनियोजन के स्थान पर धन-महन उद्योगों में, शीघ्र उत्पादन करने वाले उद्योगों में, तथा मुख्य रूप से उपभोग उद्योगों में विनियोजन बढ़ाकर मुद्रा स्थिति नियंत्रित की जा सकती है।

इस नीति में विकास के लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान न देकर स्थायित्व की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है।

(e) The time factor Criteria समयानुसार आयोजन का मानदण्ड : अगर किसी देश में आयोजन के फल अल्पकाल में ही सामने लाना है तो श्रम-गहन तकनीक में विनियोजन करना होगा और अगर ऐसी कोई जल्दी न हो तो पूँजी-गहन तकनीक में विनियोजन किया जा सकता है। समाजवादी देशों में दीर्घ-कालीन आयोजन इसलिए भी आसानी से कर लिया जाता है कि इन देशों में जनता अल्पकालिक फल के लिए उत्तावली नहीं होती क्योंकि राज्य का कड़ा नियंत्रण रहता है।

III Conclusion & Practical Considerations निष्कर्ष तथा विनियोजन मानदण्ड का व्यावहारिक पक्ष

उपरोक्त विनियोजन मानदण्ड में से कौन सा अच्छा है यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता।

D. Bright Singh के शब्दों में

“विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित विनियोजन के मानदण्ड वुट्टिपूर्ण हैं। विनियोजन मानदण्ड की समस्या इतनी जटिल है कि एक ही सही मानदण्ड का चयन असंभव है विकास के लक्ष्यों में ही समन्वय व एकरूपता नहीं होती, तो विनियोजन के मानदण्डों में भी समन्वय नहीं हो सकता।”

Gerald Meier का भी कथन है

“No criteria is good for all times and under all conditions No single criteria can be selected Then there is still the problem of practical application” op. cit

Rosenstein Rodan के अनुसार -

“विनियोजन के मानदण्ड को निर्धारित करने का अर्थ, प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं में विनियोजन करना है। हमको

1 D B Singh op cit p. 253

2 Douglas Dosser Practical conditions facing Investment choice—General Investment criteria for less developed countries A post mortem Scottish Journal of Pol Econ Vol-IX No 2 June 1962, cf G Meier. p. 247-50

विनियोजन मानदण्ड

इस सबध में यह निश्चित करना पड़ता है कि क्या यह योजना या कार्य आवश्यक है, क्या वह सही स्थान पर है, क्या उसका संचालन ठीक है, आदि "

परन्तु व्यवहार में शायद ही कोई कार्य या योजना इतनी अधिक मात्रा में पूर्व अनुमानों पर आधारित होती है, अथवा सही मायने में समस्त मानदण्डों के आधार पर विनियोजन किया जाए तो शायद कुछ ही योजनाओं पर ही कार्य शुरू किया जा सकेगा यू. एस. ए. जैसे देशों में आधे से ज्यादा कार्य शुरू ही नहीं किए जा सकेंगे

निष्कर्ष :

विनियोजन का एक मान-दण्ड नहीं है फिर भी इन बातों को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए.

1. कुछ उद्योग पूँजी-गहन हो तो छोटे पैमाने के (थम-बहन) उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए.
2. विनियोजन को रोजगार में वृद्धि लाना चाहिए.
3. देश में विकास की दर में वृद्धि होना चाहिए, उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य भी प्राप्त होना चाहिए.
4. वर्तमान व भविष्य की पूँजी व उपयोग आवश्यकताओं में समन्वय होना चाहिए.
5. निर्यात-वर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए.
6. किसी भी देश की तकनीक की अन्धाधुन नकल नहीं करना चाहिए.
7. विनियोजन नीतियों को सामाजिक व राजनैतिक स्थिति के अनुसार भी बनाना चाहिए. विनियोजन नीतियों से अधिक से अधिक लोगों को सन्तुष्टि प्राप्त होना चाहिए. देश की सामाजिक रूढ़ियों को भी दूर करना चाहिए.
8. विनियोजन कार्यक्रम कुशल कार्यकर्ता, मीनेजर आदि के कारण अफ़ल हो जाता है इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग सुविधाओं में भी विनियोजन करना चाहिए

See .

General characteristics of the Problem and comments on the conference on Investment criteria, in Asia's op. cit. by William veinner. p. 122-155

IV. Should Investment be controlled by market mechanism or should it be controlled by Government : क्या विनियोजन मूल्य प्रणाली से संचालित हो या राज्य द्वारा निर्धारित हो ?

पुराने अर्थशास्त्री यह विश्वास करते थे कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से देश में अधिकतम व अनुकूलतम विनियोजन होगा और इससे अधिकतम उत्पादन व विकास दर प्राप्त होगी परन्तु बहुत से कारण ऐसे हैं जिससे यह सक्ष्य स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से प्राप्त नहीं होगा ये कारण सक्षेप में निम्नलिखित हैं

- (1) निजीक्षेत्र के उत्पादनकर्ता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही विनियोजन करते हैं इनके विनियोजन से बाह्य मितव्ययिताओं का मूजन नहीं होता.
- (11) निजीक्षेत्र के किसी भी उत्पादनकर्ता या विनियोजक का दृष्टिकोण व्यापक नहीं होता और उसमें इतनी दूरदर्शिता नहीं होती कि वह समस्त अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप विनियोजन करे.
- (111) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति से Lump Investment बड़े पैमाने का विनियोजन संचालित नहीं होता

Paul N. Rosenstein-Rodan का कथन है

“स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली उपभाग को तो नियंत्रित कर सकती है परन्तु विनियोजन को नियंत्रित नहीं कर सकती इसके लिए विवेकपूर्ण, विचार पूर्ण, एकरूपता लिए हुए व समन्वित नीति आवश्यक होगी. राज्य का सक्ष्य रोजगार व उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए.”

इनका विचार है कि मूलभूत निर्माणों को¹ (कितना व किन क्षेत्रों में) राज्य करे तथा प्रशासनीय व व्यवस्था सबधी निर्माणों को विकेंद्रित रूप से किया जाना चाहिए जबतक कि इन बड़-बड़े निर्माणों को राज्य नहीं लेगा तब तक देश में सतुलित विकास नहीं होगा क्योंकि देश में आर्थिक व सामाजिक सिरोंपरी सुविधाओं का सृजन नहीं होगा.



See :

Programming in the Theory in the Italian Practice Paul N. Rosenstein-Rodan. Asia's op cit.

मूल्य नीति सबधी अध्याय भी पुन देखिए.

- 1 “Decision as to how much to invest cannot be taken on dispassional basis The collective choice may be philosophically indefensible but it is practically irrefutable.”

अध्याय : 11

जनसंख्या व विकास

Population and Economic Growth

भाग 1

I. प्रस्तावना : सह-संबंध का स्वभाव :

- (a) जनसंख्या व पूँजी-निर्माण,
- (b) जनसंख्या व तकनीक का अध्ययन,
- (c) जनसंख्या व राष्ट्रीय आय.
- (d) जनसंख्या व रोजगार.

भाग 2

जनसंख्या-नीति

I. "जनसंख्या नीति" का अर्थ व क्षेत्र :

- (a) परिवार नियोजन : जन्म दर में कमी लाने की आवश्यकता : अर्थ : महत्व : दकावटें व विरोध : आपत्तियों की निर्धूलता : क्या किया जा रहा है भारत में परिवार नियोजन . कम-विकसित देशों में परिवार नियोजन को सफल बनाने के उपाय.
- (b) खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि व संतुलित आहार.
- (c) जनसंख्या का देश व विदेशों में विवेकशील वितरण.
- (d) शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास व सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन.
- (e) अनुकूलतम जनसंख्या.
निष्कर्षरूपीय नोट.

जनसंख्या व विकास

Population and Economic Growth

भाग 1

I. प्रस्तावना . सह-सवय का स्वभाव

जनसंख्या और विकास में महत्वपूर्ण सह-सवय होता है विकास से जनसंख्या की जन्म व मृत्यु दर में, जीवन काल या आयु में, जनसंख्या की संरचना पर, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण, घनत्व आदि सब पर प्रभाव पड़ता है.

उसी तरह से जनसंख्या के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर, उन्नत तकनीक के प्रति मनोवृत्ति, परिवार नियोजन के प्रति मनोवृत्ति, जन्म व मृत्यु दर आदि का पूँजी-निर्माण, विनियोजन, तकनीक आदि अर्थात् राष्ट्रीय आय या विकास पर महत्वपूर्ण असर होता है

परन्तु यह समझना भूल होगी कि यह सह-सवय पूर्णतया घनात्मक है. यह स्थिति भी है कि विकास को दर के अधिक होने पर भी जन्मदर में परिवर्तन नहीं आता या कई ऐसे भी विकसित देश हैं जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम-विकासत देशों से कम न होते हुए भी (यू० एम० ए०, आस्ट्रेलिया, कनाडा व न्यूजीलैंड¹) विकास दर कहीं अधिक है आज विश्व में कम व अधिक घनत्व दोनों प्रकार के कम-विकसित देश हैं तात्पर्य यह है कि जनसंख्या विकास का एक घटक है और यह विकास में बाधक व सहायक दोनों हो सकती है.

हम सब जानते हैं कि एशिया में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव मूल रूप से विकास में बाधा के रूप में सामने आता है, जबकि योरोप और अमेरिका में वह सहायक है जनसंख्या वृद्धि मुख्यतया चार प्रकार से विकास में बाधक होती है .

(1) इसमें भूमि व प्राकृतिक साधनों पर दबाव डालती है.

1 Villard op cit

See 'ch 6. The Population obstacle to economic Betterment : Spengler & Duncan.

जनसंख्या व विकास

- (ii) इससे प्राकृतिक साधनों का ह्रास होता है और उत्पादन सामग्री बढ़ती है.
- (iii) इससे वचनें व पूँजी निर्माण कम होती है और
- (iv) बहुत सा विनियोजन देश को यथा-स्थिति में रखने में ही निकल जाता है. देश में 2% विकास दर तो इसी वृद्धि के कारण आवश्यक हो जाती है.

कम-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि से गम्भीर समस्याएँ पैदा होती हैं एक जोड़ा ही (स्त्री व पुरुष) 1% प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर से दसहजार सालों में :

$$1340,000,000,000,000,000,000, (1340 \times 10^{18})$$

तक जनसंख्या ले जाती है.

किसी भी देश में "अनुकूलतम जनसंख्या" से ऊपर जनसंख्या विफलने पर आर्थिक विकास रुकता है. आज विश्व की वही जनसंख्या जिसमें वृद्धि एक गई है या बहुत कम है (50 वर्षों में 50%) वही समृद्ध है. विश्व की 40% जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक है और यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता सस्ते परिवार नियोजन के साधन की है.

इस अध्याय में हम निम्नलिखित बातों पर विचार करेंगे

- जनसंख्या व पूँजी-निर्माण
- जनसंख्या व विनियोजन तथा तकनीक चयन.
- जनसंख्या व प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय
- जनसंख्या बढ़े, स्थिर रहे या घटे.

(a) Population and Capital Formation जनसंख्या व पूँजी-निर्माण :

पूँजी-निर्माण के अध्याय में हम पूँजी-निर्माण का महत्व पढ़ चुके हैं जिस देश में जितना अधिक पूँजी-निर्माण होगा उस देश में उतनी ही अधिक जनसंख्या को उच्च स्तर दे सकते हैं. अधिक पूँजी-निर्माण से जो विफल होता है वह स्वयं ही जमादर घटा देता है और जनसंख्या वृद्धि ही कम हो जाती है यहाँ पर हमने जनसंख्या का पूँजी-निर्माण पर प्रभाव अध्ययन करना है. जनसंख्या का पूँजी-निर्माण पर क्या असर पड़ेगा अबदा कितनी मात्रा में पूँजी-निर्माण की

आवश्यकता होगी। यह जन्म व मृत्यु दर की अवस्थाओं पर निर्भर करेगा यह अवस्थाएँ इस प्रकार हो सकती हैं।

ऊँची जन्मदर व ऊँची मृत्युदर :

अधिकांश पिछड़े कम-विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दरें ऊँची होती हैं। कम आय व निम्न जीवन स्तर, पिछड़ी व कम मात्रा में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं के कारण आयु कम होती है वच्चे भी अधिक पैदा होते हैं। ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। इस स्थिति से पूँजी-निर्माण कम होता है अधिक जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय व वचतें कम होती हैं। पिछड़ेपन के कारण बहुत सी वचतें "अनार्विक रूप" में रहती हैं या फिजूल खर्चों में उपभोग कर ली जाती हैं। दूसरी ओर इस अल्पपूँजी-निर्माण का भी पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। बहुत से बच्चे जवान होने से पूर्व ही मर जाते हैं और वे केवल उपभोगकर्ता के रूप में जीवित रह कर, अर्थात् बगैर उत्पादनकर्ता बने, ससार से चले जाते हैं यह समस्त विनियोजन बेकार जाता है, इस प्रकार की जनसंख्या में इस प्रकार से कम पूँजी-निर्माण होता है और पूँजी की बर्बादी भी होती है ऐसी अवस्था से निकलने के लिए पूँजी-निर्माण अधिक होना चाहिए और जन्म व मृत्यु दरों को नीचे आना चाहिए

ऊँची जन्मदर व कम मृत्युदर :

जब कम-विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दरों को घटाने के प्रयास किए जाते हैं तो पहले मृत्युदर घट जाती है स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर शीघ्र गिर जाती है परन्तु जन्मदर के गिरने में समय लग जाता है। यह "संक्रामक काल" होता है इस काल में बहुत अधिक माना में पूँजी-निर्माण की जरूरत होती है। इन अल्पकाल में बहुत त्याग की आवश्यकता होती है, इस काल में ही हर तरह से (मौद्रिक, राजकोपीय व अन्य नीतियों से) पूँजी-निर्माण की आवश्यकता होगी।

नीची जन्मदर व मृत्युदर :

इस अवस्था में देश काफी उन्नति के वाद प्राप्त करता है। इस अवस्था में स्वयं ही अधिक पूँजी-निर्माण, विनियोजन व उपभोग सम्भव होता है यह अवस्था उन्नत देशों में रहती है।

नीची जन्मदर व ऊँची मृत्युदर : या नीची मृत्युदर व उससे भी नीची जन्मदर :

ऐसे समाज में पूँजी-निर्माण की समस्या पैदा नहीं होती। इस समाज की मुख्य समस्या तो अपनी जाति या जनसंख्या को गमास होने से बचाना रहती है

जनसंख्या व विकास

अधिक घनत्व व पूँजी-निर्माण .

जिन देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है उनमें खाद्य सामग्री पैदा करने, जमीन की उत्पादकता बढ़ाने, नई जमीन पाटने व उसमें उन्नति करने, कृषि को उन्नत करने, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएँ बढ़ाने, सामाजिक व आर्थिक सरो-पर सुविधाएँ प्रदान करने, तथा आवास व उद्योग की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अधिकतम पूँजी की आवश्यकता होती है.

जैसा कि हम देख चुके हैं कम-विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 5-7% भाग बचाते हैं जब कि विकसित देशों में यह भाग 25-30% तक होता है. अगर कम विकसित देशों में जनसंख्या में 1.25% वार्षिक वृद्धि हो और अगर Capital-output ratio हो तो 5% पूँजी तो जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थिति को यथावत् रखने में ही निकल जाएगी

Hobbs का कथन है

“जब जनसंख्या बढ़ती है तो व्यक्तियों के Time horizons (समय क्षितिज) बहुधा छोटे हो जाते हैं (अर्थात् वे दूर भविष्य की बात नहीं सोचते) वे वर्तमान की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में ही अधिक धन खर्च कर देते हैं उनको भविष्य के वजाय वर्तमान की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इससे पूँजी-निर्माण कम हो जाता है परन्तु अगर परिवार के सदस्य विवेक-शील हैं तो यह Time horizon लम्बा हो जाता है. ऐसे लोगों की बचत क्षमता उतनी ही रहते हुए वे बचतों को बढ़ाने के लिए प्रेरित रहते हैं.”

संक्षेप में जनसंख्या और पूँजी-निर्माण में सह सम्बन्ध है. अधिक पूँजी-निर्माण से जो विकास होता है उससे अधिक ऊँचा जीवन स्तर होता है अधिक जनसंख्या पूँजी-निर्माण में बाधक है परन्तु अधिक जनसंख्या के लिए अधिक पूँजी आवश्यक होती है

(b) Population Growth and Technology जनसंख्या व तकनीक जनसंख्या का तकनीक स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है अगर देश की जनसंख्या शिक्षित है तथा उन्नति की आकांक्षी है तो वे नई तकनीक को खोजते हैं या अपना लेते हैं अशिक्षित व उदासीन जनसंख्या पिछड़ी तकनीक ही अपनाएँ रहती है इसीलिए शहरी जनसंख्या पहले उन्नत तकनीक को अपना लेती है जनसंख्या की मात्रा तथा उसकी वृद्धि दर भी तकनीक या विनियोजन मानदण्ड

को अपनाने पर प्रभाव डालती है, जैसा कि हम देख चुके हैं,¹ अगर किसी देश में जनसंख्या अधिक है तो ऐसे देश में श्रम-गहन तकनीक को अपनाना पड़ जाता है अगर ऐसा देश पूँजी-गहन तकनीक अपनाता है तो यह महंगा भी पड़ता है और देश में बेरोजगारी की समस्या का निराकरण भी नहीं हो पाता अल्पकाल में ऐसे देश को श्रम गहन तकनीक के कार्यों को अधिक मात्रा में हाथ में लेना चाहिए परन्तु एक अधिक जनसंख्या वाला देश पूर्ण रूप से पूँजी-गहन तकनीक के उद्योगों को नहीं त्याग सकता।

अगर किसी कम-विकसित देश में जनसंख्या का घनत्व कम है अथवा जनसंख्या वृद्धि की दर कम है तो ऐसे देश में पूँजी-गहन तकनीक को अपनाना सरल होगा ऐसे देश में तकनीकी उन्नति भी शीघ्र हो सकेगी। इन देशों में पूँजी-गहन तकनीक अपनाने पर श्रम आन्दोलन भी नहीं होगा।

जहाँ तक विकास का प्रश्न है वह तो किसी भी तकनीक के अपनाने से हो सकता है वास्तव में कोई भी देश पूर्ण रूप से श्रम-गहन तकनीक के उद्योग या पूँजी-गहन तकनीक के उद्योग नहीं अपना सकता उसको दोनों तकनीकों के उद्योग रखने पड़ते हैं। प्रश्न केवल अधिक या कम मात्रा का रहता है।

(c) Population And Per-Capita Income & Economic Conditions : जनसंख्या तथा प्रति-व्यक्ति आय व आर्थिक स्थितियाँ :

जनसंख्या में परिवर्तन से प्रति-व्यक्ति आय व आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता इनमें सह-संबंध जटिल है। जनसंख्या वास्तव में परिवर्तन से दूसरे घटक पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिवर्तन होते हैं और इससे भी पुन जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या परिवर्तनों का वास्तविक आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कई बातों पर निर्भर करती है

अगर जनसंख्या का अनुपात अन्य उत्पादन अंगों के मुकाबले में बढ़ता है, तो अन्य बातें समान रहे, तो प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन व आय घट जाएगी इसका मूल कारण यह है कि श्रम, भूमि, पूँजी तथा समूह का पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं है कम-विकसित देशों में पूँजी की मात्रा उसनी ही रहने के कारण, जनसंख्या बढ़ने से हर व्यक्ति के पास पहले से कम पूँजी रह जाती है (Increase in population or labour force means that it becomes less equipped than before with capital remaining the same) जनसंख्या बढ़ने का प्रति व्यक्ति उत्पादन पर प्रभाव उस समय अधिक होता है

1 पिछला अध्याय देखिए

जबकि उत्पादन मुख्यतया भूमि या बढ़ाए न जा सकने वाले प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहता है जहाँ भूमि व प्राकृतिक साधनों का योगदान कम रहता है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि का उत्पादन पर कम प्रभाव पड़ता है अगर कोई पर्याव्यवस्था, विदेशी विनिमय प्राप्त करके अथवा किसी अन्य युक्ति से उत्पादन में भूमि व प्राकृतिक साधनों के योगदान के अनुपात में पूँजी का योगदान बढ़ा दे (अर्थात् पूँजी बढ़ा दे) तो जनसंख्या बढ़ने के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे।

अगर किसी देश में जनसंख्या कम हो रही हो तो वह देश घटिया भूमि या घटिया प्राकृतिक साधनों का प्रयोग छोड़कर, उत्तम तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकता है।

(d) Should there be Increasing, Declining or Stationary Population for full employment? क्या देश में पूर्ण रोजगार के लिए बढ़ती, घटती या स्थिर जनसंख्या आवश्यक है?

विकसित देशों में पूर्ण रोजगार के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या ?

A. H. Hansen's Thesis

A. H. Hansen ने यह विचार प्रतिपादित किया है कि विकसित देशों में पूर्ण रोजगार बरामद करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या आवश्यक है। उनकी यह विचारधारा केन्स के "सामान्य सिद्धान्त" पर आधारित है केन्स के अनुसार घटती हुई जनसंख्या से प्रभावशील माँग कम होती है और विनियोजन के कम होने से रोजगार कम होता है। D. H. Handerson ने भी यही ढर ब्यक्त किया है कि घटती हुई जनसंख्या विकसित देशों का विकास रोक सकती है बहुत से पश्चिमी देशों में इस बात से बहुत चिंता उत्पन्न हो रही है कि बच्चे पैदा करने वाली स्त्रियाँ अपना पुन स्थापन ही नहीं कर रही हैं।

"आस्ट्रिया में यह कमी 36, फ्रान्स में 14, स्वीडन में 30, जर्मनी 11, इंग्लैंड व बेल्ज में 24 तथा यू० ए० ए० में 06 है"

(Population Index 1939)

Myrdal भी घटती जनसंख्या की प्रवृत्ति से भयभीत हुए हैं उनके अनुसार "विकासशील पूँजीवादी प्रणाली में प्रगतिशील जनसंख्या विकास की प्रथम आवश्यकता है घटती हुई जनसंख्या से चारों ओर विनियोजन जोखिम बढ़ जाता है।"

(Population, A problem for democracy p. 164.)

A. H. Hansen ने विकसित देशों में पूर्ण रोजगार कायम रखने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने माल्थस की कड़ी आलोचना की कि उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि में रूकावट को अच्छा माना था हन्सेन का कथन है

‘माल्थस कि तुलना में एडम स्मिथ के विचार बहुत अधिक सतुलित थे बढ़ती हुई जनसंख्या से धन-विभाजन जटिल होता है और अधिक उत्पादन व उत्पादकता की वृद्धि होती है इससे पूँजी-निर्माण बढ़ता है और स्वयं धन की मांग बढ़ती है हन्सेन का कथन है कि वास्तव में आज भी एडम स्मिथ का यह विचार ठीक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने आर्थिक उन्नति होती है। आज पुनः एडम स्मिथ के प्रवैगिक विश्लेषण को अपनाने की आवश्यकता है”

बढ़ती हुई जनसंख्या से देश में प्रभावशील माँग कायम रह सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या से आवास सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पूँजी को विस्तृत क्षेत्र में विनियोजित करना पड़ता है हन्सेन के शब्दों में

“It is my growing conviction that the combined effect of the decline in population growth, together with the failure of any really important innovations of a magnitude sufficient to absorb large capital outlays, weighs very heavily as an explanation for the failure to recent recovery to reach full-employment.....Developed countries may face the problem of declining investment opportunities as a result of cessation of population growth and disappearing of new territories for settlement and expansion.....”

(अर्थात् यह मेरा बढ़ता हुआ पक्का विश्वास है कि जनसंख्या के घटने

Ch. 5 of Spengler & Duncan's "Population Theory and policy"
The Free Press of Glencoe 1963 — "Populations movements
Employment & Income" p 252 & 272, ch 9. p 448
Hansen's paper : Economic progress & Declining population
Growth.

जनसंख्या व विकास

का (साथ साथ महत्वपूर्ण नवप्रवर्तन के न होने से) कुल मिलाकर यह प्रभाव पड़ता है कि मंदी की स्थिति पूर्ण तरह से समाप्त होकर पूर्ण रोजगार की स्थिति तक नहीं पहुँच पाती है.....प्रायः विकसित देशों में घटती हुई विनियोजन की सम्भावनाओं का मुख्य कारण घटती हुई जनसंख्या व नए इलाकों को पता लगाने की सम्भावनाओं की समाप्ति है)

इन्हीं कारणों वृद्धि हुई जनसंख्या चाहते हैं.

आलोचना :

उपरोक्त विचारधारा की काफी आलोचना की गई है.

Dr. Ellis ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा है

“क्या हम यह कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी का इलाज और बचने पैदा करना है.”

B. M. Anderson भी इस विचारधारा को सर्वथा गलत मानते हैं. और कहते हैं

“घटती हुई जनसंख्या से बेरोजगारी होना आवश्यक नहीं है. इससे माँग कम नहीं होती, वरन् माँग का स्वभाव बदल जाता है. घटती हुई जनसंख्या से “पालतों” की माँग कम होगी तो “पहिएदार कुत्तियों” की माँग बढ़ेगी.

Fellner-Teisborgh के अनुसार जनसंख्या घटने से उपभोग उन्ही मात्रा में नहीं घट सकता. इस कारण जनसंख्या के घटने में बेरोजगारी का फैलने का भय निर्मूल है उन्होंने कहा

“High population need not give rising population consumption function for the aggregate population tends toward linearity with minor oscillations that seem to be unrelated to changes in population growth”

Meivin D Brockie ने अपने लघु ‘Population growth and the rate of investment’ में हुन्सेन की विचारधारा की बहुत आलोचना की है. उन्होंने लिखा .

“स्थिर जनसंख्या में कम पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी, कम मकानों की आवश्यकता पड़ेगी और हर व्यक्ति पर बच्चों का भार कम रहेगा.

स्थिर जनसंख्या से कम मात्रा में पूंजीगत वस्तुएँ अवश्य उत्पादित की जाएंगी परन्तु उपभोग वस्तुएँ तो अधिक मात्रा में उत्पादित की जा सकती हैं. "व्यक्तिगत सेवाओं" का अधिक सृजन किया जा सकता है. जनसंख्या कम होने से माँग में कमी हो, तो कम लोगों को रोजगार भी तो देना पड़ता है जनसंख्या के कम होने से मदी नहीं आती है वरन् मदी काल में जनसंख्या कम हो जाती है क्योंकि लोग देर से शादी करते हैं तथा अधिक परिवार नियोजन अपनाते लगते हैं 1"

निष्कर्ष :

विकसित देशों में भी बढ़ती हुई जनसंख्या आवश्यक नहीं है आज के युग में स्थिर जनसंख्या ही उचित है कम विकसित देशों में भी इसलिए जनसंख्या वृद्धि रोकना आवश्यक है.

Spengler के शब्दों में

"आज की साधनों की स्थिति तथा समस्त तकनीक सबधी उन्नति को ध्यान में रखकर भी यह कहा जा सकता है कि विरबध्यापी गरीबी को दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को शीघ्र ही रोकना होगा. उन्नति व विवास के किसी भी आयोजन में जिसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा, वह असफल हो जाएगा "

-
1. "One might thus aver that although population growth historically has provided broad investment opportunities for saving, a stationary population need not be the prelude to secular stagnation. Alternative investment outlets exist today and have existed for generations, population growth of the past simply created opportunities which were more lucrative at a particular time. Savings could just as easily gravitate toward qualitative improvements and a featherence of the standrad of living of already existing numbers.
—Parenthetically, there appears to be little validity to the argument which concerns itself with increasing numbers as a device for keeping the mature population employed. The tribulations of over population are perhaps more serious than the trials of under-population."

जनसंख्या नीति

Population Policy

I What is a "Population Policy"

जनसंख्या नीति का अर्थ
 "जनसंख्या नीति" का विस्तृत व संकुचित दोनों अर्थ लिए जाते हैं Myrdal
 (मिरदाल) के अनुसार

' जनसंख्या नीति वास्तव में गोंटे रूप से सम्पूर्ण समाज नीति ही होती है अगर हम समाज नीति के व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान नहीं देते तो जनसंख्या नीति का खोंन अनावश्यक रूप से संकुचित हो जाएगा जनसंख्या नीति को अन्य सामाजिक नीतियों पर प्रभाव डालना चाहिए और अन्य नीतियों से प्रभावित होना चाहिए '

इस प्रकार से अगर हम परिभाषा लें तो वास्तव में समस्त आर्थिक नीतियाँ ही "जनसंख्या नीति" के अंतर्गत आ जाएगी विदेशी आयात निर्यात नीति से भी जीवन स्तर ऊँचा होता है, विनियोजन वृद्धि से जनसंख्या का अधिक रोजगार मिलता है इसी तरह यातायात सुविधाओं की वृद्धि से भी जनसंख्या लाभान्वित होती है इन सब कार्यों को हम जनसंख्या नीति के अंतर्गत नहीं ले सकते अन्यथा समस्त प्रबंधशास्त्र ही जनसंख्या शास्त्र हो जाएगा ऐसा करना उचित नहीं होगा और हमको जनसंख्या नीति की सीमित रूप में अध्ययन करना चाहिए

A Population Policy can be nothing less than a social policy at large If practical social science is not on the watch, there is a Palpable danger that Population Policy will be Irrationally narrowed down and forced into remedial quackery A population programme must work itself into the whole fabric of social life and inter-penetrate and be interpenetrated by all other measures of social change The population crisis must, if we are to react rationally, make us rethink all social objectives and programmes
 Myrdal, A Nation & Family, 1941, p 101.

हम जनसंख्या नीति के अन्तर्गत

- (I) जन्मदर.
- (II) मृत्युदर.
- (III) जनसंख्या वृद्धि दर
- (IV) जनसंख्या नियन्त्रण.
- (V) जनसंख्या की संरचना सुधार आदि को अध्ययन करते हैं

Dr Terao के शब्दों में :

“जनसंख्या की समस्या निवारण हेतु कदमों को ही जनसंख्या नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है. इस नीति में मुख्यतया वृद्धि करना या सीमित करना आता है.” जब अर्थ व्यवस्था के अनुरूप जनसंख्या को करना होता है तो वह जनसंख्या नीति में आएगा और जब जनसंख्या के अनुरूप अर्थ व्यवस्था को करना होगा तो वह आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत आएगा श्री तेराव के अनुसार मन्दी के कारण बेरोजगारी की समस्या “जनसंख्या की नीति” की समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक समस्या है, परन्तु कम-विकसित देशों में अतिरिक्त जनशक्ति की बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या की समस्या है”

जनसंख्या नीति के मुख्यतया दो पहलू हैं

- (1) संख्या सम्बन्धी तथा
- (II) विस्म सम्बन्धी (कम-विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दरें दोनों अधिक रहती हैं और विकास के फलस्वरूप मृत्युदर पहले गिरती है जिससे जनसंख्या विस्फोट हो जाता है और जन्मदर गिराने की समस्या मुख्य हो जाती है)

जहाँ तक विस्म सुधारने का प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सतुलित आहार प्रदान करना, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध करना, निर्वैयर्थपूर्ण वितरण करना आदि मुख्य हैं.

हम इस अध्याय में जनसंख्या नीति के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करेंगे :

1. जन्मदर कम करना या परिवार नियोजन का प्रसार
2. देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सतुलित आहार का प्रदान करना.

Tokuma Terao, The Meaning of Population Policy in the Report of the Fifth International Planned Parenthood Conference 1955. p 16.

3 Emigration outside and inside the country • जनसंख्या का देश में उपयुक्त वितरण

4 शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नति

5 बिन्ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में सुधार

6 आर्थिक विकास व अनुकूलतम जनसंख्या

उपरोक्त प्रश्नों को ही जनसंख्या नीति का अंग माना गया है

(2) Reduction in birth rate and family planning जन्मदर में कमी व परिवार नियोजन

1 अर्थ, 2 आवश्यकता, 3 कुछ समस्याएँ, आचरण व विरोध, 4 क्या किया जा रहा है, 5 क्या और किया जाना चाहिए.

1. Meaning अर्थ

“Birth control” शब्द का अर्थ आज सबको मालूम है परन्तु यह शब्द सही मायने में गलत है. गरीब शब्द “Conception control” या ‘गर्भधारण नियंत्रण’ होना चाहिए. सही मायने में हम गर्भधारण न हो सके यह चाहते हैं. गर्भधारण हो जाए तो ‘जन्म नियंत्रित’ नहीं कर सकते फिर भी आज “Birth control” शब्द चल निकला है और जब कभी भी “Birth control” शब्द प्रयोग में आए तो इसका आशय हमको “conception control” में ही लेना है.

गर्भधारण के नियंत्रण में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों तरीके इस शब्द के अन्तर्गत लिये जाते हैं.

2 Need, objectives, Necessity, Importance and Philosophy of Family Planning परिवार नियोजन की आवश्यकता व महत्व •

बहु विकासी देशों में, विशेषरूप से एशिया के कम-विकासी देशों में, परिवार नियोजन की आवश्यकता को Crying need of the hour या समय की सबसे प्रमुख आवश्यकता कह सकते हैं. आज जन्म दर में कमी की इसलिए भी बहुत आवश्यकता है कि इन देशों में मृत्युदर में कमी आ गई है और चूँकि मृत्युदर को बढ़ाया नहीं जा सकता या बढ़ी हुई नहीं रहने दिया जा सकता, इसलिए केवल जन्मदर को कम करके ही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है जन्मदर

References . Appended at the end of the chapter

नियन्त्रित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शारीरिक सभी कारण महत्वपूर्ण हैं

आर्थिक :

पिछले पृष्ठों के अध्ययन के पश्चात्, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता के सबर में किसी को मतभेद की गुंजाइश नहीं रहती कम-विकसित देशों में भूमि की कमी, दक्षता की कमी, बेरोजगारी व निम्न प्रति व्यक्ति आय के कारण जन्मदर को यथा-वत रखना न केवल विकास की राह में बड़ा रोड़ा बनाए रखता है वरन् स्वयं अर्थव्यवस्था की अवनति की राह में फंसा जाना होगा।

भारत का ही उदाहरण ले तो हमको महत्वपूर्ण आकड़े परिवार नियोजन की आवश्यकता समझाते हैं

भारत में पिछले 5000 वर्षों के बाद 1968 तक जनसंख्या 52.6 करोड़ हुई। परन्तु प्रगले सन् 2000 तक अर्थात् केवल 32 वर्षों में यह संख्या दुगुनी हो जाएगी भारत में हर डेढ़ सेकेंड में एक बच्चा पैदा होता है और एक वर्ष में 2 करोड़ 10 लाख बच्चे पैदा हो जाते हैं भारत में हर वर्ष आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या जुड़ जाती है। भारत में हर दशक में जनगणना होती है 1881-91 तथा 1911-21 के बीच तो जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर घट गई थी, और अन्य दशकों में औसत रूप से 2 से 3 करोड़ प्रति दशक बढ़ती थी। परन्तु 1961-71 के बीच यह जनसंख्या 12.5 करोड़ से बढ़ जाएगी, अर्थात् एक ही दशक में आधी सदी के बराबर जनसंख्या बढ़ जाएगी

भारत में 87% परिवार केवल जीवन निर्वाह के बराबर आय पाते हैं। 1960 में 25.5% परिवारों की औसत आय प्रतिदिन केवल 75 पैसे थी, 38.3% परिवारों की प्रतिदिन की औसत आय 39 पैसे थी और 23.2% परिवारों की प्रतिदिन की औसत आय मात्र 14 पैसे ही थी। समस्त 87% परिवारों की औसत आय प्रतिदिन केवल 35 पैसे ही थी यह आकड़े स्वयं अपने में समस्या की गंभीरता बतलाते हैं

आज भारत में 1.5 करोड़ व्यक्ति पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं और लगभग 1 करोड़ व्यक्ति अर्ध बेरोजगार हैं। रहन सहन के स्तर अत्यन्त शोचनीय हैं भारत में 1968 में दिल्ली में 63%, कलकत्ते में 72%, बम्बई में 72.3%, भद्रास में 67.5%, अहमदाबाद में 65.3%, हैदराबाद में 46% तथा वानपुर में 62% व्यक्ति केवल एक कमरे के मकान में रहते थे।

जनसंख्या नीति

1968 में आज भारत में 95 करोड़ जोड़े (पति-पत्नी) 15 से 45 वर्ष की आयु के हैं अर्थात् बच्चे पैदा करने वाली आयु के हैं। और इनमें से केवल 8% परिवार नियोजन का पालन कर रहे हैं जब 92% अभी भी अनियंत्रित रूप से बच्चे पैदा करने में लगे हैं। भारत में 6 करोड़ पति-पत्नियों के तीन से अधिक बच्चे हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के कारण बच्चों की मृत्युदर कम हो गई है और आज 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जनसंख्या के 40% हैं। कुछ वर्षों में इनके भी बच्चे पैदा होने लगेंगे और फिर Population explosion या "जनसंख्या का विस्फोट" और भयानक हो जायेगा। स्त्रियों की अधिकांश आयु बच्चे पैदा करने में ही निकल जाती है और बच्चे पैदा करने की आयु में 2/3 स्त्रियों की मृत्युएँ बच्चे पैदा करने में ही हो जाती हैं।

प्रगत्त कम-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ना हो और समानता तथा इज्जत की जिन्दगी देना हो तो परिवार नियोजन सर्वप्रथम आवश्यक होगा। विश्व में जो 18 सदियों में जनसंख्या एक मिलियन बढ़ती थी अब केवल 15 वर्षों में जाती है।

भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रावधान में यह मान्यता है कि जनसंख्या के नियंत्रण के बिना आर्थिक उन्नति असम्भव है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही नई भूमि खेती योग्य बनाई गई और उत्पादन में भी वृद्धि की गई परन्तु उसके लाभ प्राप्त नहीं हुए और बढ़ती हुई जनसंख्या से समस्त लाभ Neutralize निरस्त हो गए। प्रगत्त यह कम चलता रहा तो हमको योरोप के वर्तमान स्तर को पहुँचने के लिए 200 वर्ष लग जाएंगे, परन्तु अगर हम परिवार नियोजन के कार्य को व्यापक करके जनसंख्या वृद्धि को 1% प्रतिवर्ष ला दें तो राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि करके हम यह स्तर 70-80 वर्षों में ही पहुँचा सकते हैं।

सामाजिक -

परिवार नियोजन से महत्वपूर्ण सामाजिक उन्नति होगी। विरोध रूप से स्त्रियाँ बच्चे पैदा करने की मशीन मान बनकर नहीं रह जाएँगी वे फिर सामाजिक कार्यों में अधिक हिस्सा ले सकती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो लड़कियों की शिक्षा में भी वृद्धि होती है। गरीब परिवारों में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। परिवारों का रहन-सहन का स्तर बढ़ता है, पति पत्नी अपना वैवाहिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन का अच्छी तरह से आनन्द ले सकते हैं और

इस कारण सुखी परिवार बनते हैं। पारिवारिक कलह, तनाव, चिन्ताओं और परेशानियों को दूर करने का एक मात्र उपाय है

Aldous Huxley के शब्दों में

“A rational control of human density depends on the existence of a stable world population with low death ratio. It does not make sense to talk about Human Dignity and the four freedoms in relation to source far Eastern countries where, say almost half of the inhabitants die before they are 30, and where, none the less, the total population rises by tens of millions every decade. The giant misery of the world cannot be mitigated by inspirational twaddle, but only by an intelligent attack upon the cause of that misery, viz, by controlling the future progeny.”

Sir Julian Huxley ने बहुत सुन्दर शब्दों में परिवार नियोजन की आवश्यकता को समझाया है

“People do not exist just to provide bomb-fodder for rival churches, or cannon-fodder for rival parasites, or labour-fodder for rival economic system, or ideology fodder for rival economic systems, or even consumer fodder for profit making systems. It cannot be their destiny to exist in ever larger megapolitan sprawls, cut off from contact with nature and from the sense of human community and condemned to increasing frustrations noise, mechanical routine, traffic congestion and endless commuting, nor to live out their undernourished lives in some squalid Asian or African village. If man is not to become the planet's cancer instead of its partner and guide, the threatening plethora of the unborn must be for ever banished from the scene.”

—Sir Julian Huxley, F R. S. in Population review, July 1962

राजनैतिक :

पहले कुछ देशों व उनके नेताओं (विशेष रूप से धार्मिक आधार पर स्थापित राज्यों में) का विचार था कि जब तक कि देश में जनसंख्या अधिक न होगी वह देश अपनी सामरिक सुरक्षा नहीं कर पाएगा परन्तु आज युद्ध केवल जनसंख्या की (या लिंगाधिक्य की) अधिकता पर निर्भर नहीं करता वरन नवीनतम सामग्री, सामरिक ब्युह रचना तथा तथा मनुष्यों की शक्ति व भावना पर निर्भर करता है युद्ध जीतने या देश को शक्तिशाली रखने के लिए आर्थिक क्षेत्र में शक्तिशाली होना चाहिए और आज इसके लिए परिवारों का सीमित होना आवश्यक है सीमित परिवारों के कारण देश में बेरोजगारी नहीं रहती है और प्रति व्यक्ति घाय अधिक रहती है और देश में राजनैतिक असंतोष नहीं रहता। शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है शिक्षित व्यक्तियों से देश में ही, सही प्रजातन्त्र स्थापित होता है।

अगर मनुष्य को इस पृथ्वी का केंसर के रूप में बनकर नहीं रहना है तो समस्या-शित रूप से बच्चे पैदा होते रहने की स्थिति बदलना चाहिए।

भौतिक : Physical and Eugenic .

परिवार नियोजन से न केवल कम बच्चे पैदा किए जाएंगे वरन् इससे बच्चों के बीच भ्रष्टाचार भी रखा जा सकता है। इस कारण माँ-बाप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं तथा सतान पर भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। बच्चों को बचपन में अच्छी स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। इससे परिवार के सदस्यों या सही भाषणों में देश की जनता की किस्म सुधरती है

Eugenic practices को पालन लिया जा सकता है Eugenic practice का अर्थ यह है कि प्रयोग्य व्यक्तियों को बच्चे पैदा न करने दिए जाएँ, वे प्रयोग्य व्यक्ति हैं जो कोढ़, तपेदिक, पागलपन, सिफिलिस या गिनोरिया (यौनिक बीमारियाँ) आदि बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी सभाग करते हुए बच्चे पैदा करने से तो बचे रह सकते हैं।

परिवार नियोजन के निम्न-निम्न सर्वेक्षणों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है .

- (i) जैसे-जैसे बच्चों की संख्या अधिक होती है तथा
- (ii) उनके बीच भ्रष्टाचार कम रहता है, वैसे-वैसे बच्चों की मृत्यु की दर अधिक रहती है

Dr. Woodbury ने "Maternal Mortality" में लिखा है

"अगर दुसरा बच्चा 1 ही सप्ताह बाद पैदा हो जाए तो 1000 में से

147 शायद अपने पहले जन्मदिन को न देख पाएँ, अगर दो साल बाद पैदा हो तो यह मृत्युदर 99/1000 रहेगी और तीन साल बाद पैदा होने पर यह दर घटकर 86 5/1000 हो जाएगी "

इसी प्रकार के एक अन्य अध्ययन में Drs. Bruine तथा Lange के अनुसार रही

परिवार में एक ही बच्चा हो तो बच्चों की मृत्युदर	20 1%
" " दो " " " " " "	20 1%
" " तीन " " " " " "	25.1%
" " चार " " " " " "	23.4%
" " पाँच " " " " " "	24.5%

नौ बच्चों के परिवार में मृत्यु अनुपात (बचपन में ही मर जाने का) 52 5 तक पाया गया.

3. Some resistances, difficulties & attitudes .

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कुछ रुकावटें - विरोध व भावचरणों का प्रश्न :
 आपत्तियाँ :

- 1 घाज के युग में भी परिवार नियोजन के विरोध में काफी कुछ सुनने को मिलता है. धर्म के रूढ़ीवादी रूप से मानने वाले व्यक्ति इसे अधार्मिक कार्य मानते हैं. वे न केवल बच्चे को गिराने (abortion) को बुरा मानते हैं. वरन् गर्भधारण को रोकने को भी बुरा मानते हैं वे इसे भी अनैतिक, अधर्मी तथा ईश्वर विरोधी कार्य मानते हैं वे इसे भी भ्रूण की हत्या मानते हैं. Roman Catholic Church के सब पोप इसके विरोध में रहे हैं और स्वयं इस सदी के पोप ने अपने Encyclical में परिवार नियोजन को बुरा माना है मुसलमान वर्ग के अनुयायी भी सामान्यतया इसके विरोध में पाए जाते हैं, जब कि उनकी धर्मपुस्तक "कुरान शरीफ" में आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन को अपनाने की भी सलाह दी गई है. मिश्र के इस्लाम के सबसे बड़े स्कूल के बड़े मुफ्ती (Mufti) ने भी यह विचार प्रस्तुत किया है कि इस्लाम परिवार नियोजन को इजाजत देता है. किन्हीं परिस्थितियों में तो यह Abortion या बच्चे को गर्भ से गिराने को भी मान सकता है.
- 2 भारत में कई व्यक्ति परिवार नियोजन के इसलिए विरोध में हैं कि इससे देश में हिन्दू व गैर हिन्दुओं में अनुपात बिगड़ जाएगा. भारत में 1821 से 1941 के बीच हिन्दुओं के अनुपात में मुसलमानों का Child-ratio

जनसंख्या नीति

अधिक रहा है इसका मुख्य कारण हिन्दुओं का परिवार नियोजन के पक्ष में होना तथा विधवा विवाह के विपक्ष में होना है, जबकि मुसलमानों में इसके विपरीत मनोवृत्ति है। कुछ हिन्दू "नेताओं" का कथन है कि कालान्तर में इस प्राय द्वीप की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण पुन पाकिस्तान के जन्म के समय जैसी मनोवृत्ति उत्पन्न हो सकती है।

- 3 कुछ सामाजिक प्राचारों पर भी परिवार नियोजन का विरोध किया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पिट्रिम सोरोकिन (Pitrim Sorokin के शब्दों में :

"परिवार नियोजन के प्रसार से हम "लाइसेंसयुक्त" यौनमोग के भूले लड़के लड़कियों को बढावा देंगे व उत्पन्न करेंगे। समाज में अनुशासित व्यक्तियों के स्थान पर अपराधी पनपेंगे हर सार्वजनिक स्थान यौनिक खेलों का स्थान बन जाएगा। स्कूल व कॉलेज "स्कैटिंग ग्राउंड" बन जाएंगे, टुरिस्ट व वास्तव्य घर बन जाएंगे हमारा युवा ममाज पतवार हीन नाब बन जाएगा मानसिक सतुलन बिगड़ जाएगा। भ्रान्त-रिक्त शान्ति नहीं मिलेगी और शादी की पवित्रता ही नष्ट हो जाएगी।"

बहुत से व्यक्तियों का विचार है कि परिवार नियोजन की सुविधा की उपलब्धी से लड़कियाँ अपने शील को कायम नहीं रख पाएंगी। शादी से पहले यौनिक संबंध ग्राम बात हो जाएगी, पुरुषों द्वारा स्त्रियों को कुसलाना या स्त्रियों द्वारा पुरुषों को कुसलाना साधारण बात हो जाएगी। नौकर-पेशा लड़कियाँ यौनिक व्यापार भी करने लगेंगी। वैश्यावृत्ति बढेगी तथा यौन सबसे बड़ा खेल व व्यापार बन जाएगा। विकसित समाज में यह बात सार्वभौमिक हो गई है कम-विकसित देशों में भी यह हो जाएगा और फिर वैतिकता लगभग समाप्त हो जाएगी।

- 4 कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भी परिवार नियोजन का विरोध किया जाता है George Bernard Shaw ने तो इसे Suicide of the intellectual race कहा था। इन बुद्धिजीवियों की धारणा यह है कि व्यवहार में परिवार नियोजन पड़े जिसे और घनी सोम हो अधिक अपनाते हैं कुनक, मजदूर व अन्य कम पढ़े लिखे लोग नहीं अपनाते एक कुली के चार लड़के वर्तमान स्थितियों में कुली ही रह जाएँ परन्तु एक इंजीनियर के चार लड़के शायद समाज के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं इसलिए वर्तमान स्थितियों में कुशल व व्यक्तियों की संख्या गिरती जाएगी और अनुकूल की बढती जाएगी।

कठिनाइयाँ :

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं विभिन्न वर्गों द्वारा विरोध के अलावा अभी भी दृढ़ उदासीनता पाई जाती है. शिक्षा की कमी, भूटो शर्म व धन की कमी भी परिवार नियोजन के प्रसार में बाधक रहती हैं. निम्न जीवन स्तर, मनोरंजन के अन्य साधनों की कमी, परिवार नियोजन सामग्री की अनुलब्धता या महंगापन, विवेक व सूक्ष्म-सूक्ष्म की कमी भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को असफल बनाती हैं सफाई की कमी (यौनिक क्रिया के पहले व बाद में साबुन के प्रयोग से शुक्राणु मरते हैं Soap is spermicidal) भी जन्मदर अधिक रखती हैं घरों में जगह की कमी के कारण भी यह सब उपकरण प्रयोग में नहीं ला पाते और यौनिक सहवास क्रिया में जुट जाते हैं. हाल के वर्षों तक राज्य व समाज भी इस कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहा आज भी आवश्यकतानुसार धन व व्यक्ति, विशेष रूप से डॉक्टर आदि, उपलब्ध नहीं हैं.

आपत्तियों की निर्मूलता :

1. बहुत सी आपत्तियाँ वास्तव में निर्मूल हैं, जहाँ तक वैश्यावृत्ति पनपाने का प्रश्न है शायद उसमें परिवार नियोजन अपनाते में कमी आ सकती है आज बहुत से पुरुष घर में यौनिक सम्बन्ध स्थापित करने के स्थान पर वैश्याओं के यहाँ इसलिए जाते हैं कि उन्हें घर में बच्चों की सत्पा बढ़ने का डर रहता है परिवार नियोजन के बाद वे कितनी ही बार घर में सहवास कर सकते हैं और इससे पति-पत्नी में बगैर डर के सुखी वैवाहिक जीवन चल सकता है
2. परिवार नियोजन के कारण तनाव व फिक्का में कमी होती है. यौनिक सहवास स्त्रियों व पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक है इससे (अगर इसकी बहुत घनिष्टता न की गई तो) शरीर स्वस्थ होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, यहाँ तक कि आयु में भी वृद्धि होती है स्त्रियों को सहवास (और सतोष-जनक) न मिलने की स्थिति में hysteria, neurosis (मानसिक अशांति व असंतुलन, चिड़चिड़ापन) तथा अनियमित माहवारी हो जाती है. परिवार नियोजन से यह दूर हो जाते हैं, पति-पत्नी शारीरिक व मानसिक रूप से पास आते हैं, परिवार सुखी रहता है परिवार नियोजन से "यौन" के दोनों कार्य—बच्चे पैदा करना तथा वैवाहिक जीवन का आनन्द लेना—प्रलग हो जाते हैं.
3. जहाँ तक कि Suicide of the intellectual race का प्रश्न है यह भी कालान्तर में नहीं रहेगा. धीरे-धीरे गरीब वर्ग भी, सम्मान-बुझाने से,

परिवार नियोजन अपनाते लगे। सबसे बड़ी आपत्ति इस सम्बन्ध में यह की जाती है कि यह जरूरी नहीं है कि "उच्च वर्ग" के व्यक्तियों के बच्चे हमेशा कुशल निकले।

4. आज के युग में केवल स्वार्थी व्यक्ति (Vested Interests) ही परिवार नियोजन के खिलाफ हो सकते हैं।

Prof. T. N. Carver के शब्द में

"लौमड़ियाँ चाहती हैं कि सरणियों की संख्या बढ़े, स्वार्थी उत्पादन-कर्ता चाहते हैं कि धार्मिक वर्गों में अधिक बच्चे हों जिससे उन्हें सस्ते मजदूर मिलें, 'धर्म के नेता' अधिक संख्या में अपने अनुयायी चाहते हैं, नेता के नेता अपनी बन्दूकों के लिए "अधिक पाउडर" चाहते हैं, राजनीतिज्ञ बड़ी संख्या में अधिक प्रज्ञानी मतदाता चाहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति गरीब वर्ग की जनसंख्या घटाने की सलाह दे सकते हैं।"

5. परिवार नियोजन की प्रालोचना जो अप्राकृतिक कार्य के रूप में की जाती है वह भी सर्वथा गलत है आज के युग में प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने का अर्थ जंगली जीवन व्यतीत करने की दिशा में कदम होना। हम सुबह से शाम तक प्राधुनिकतम चीजों का प्रयोग खाने, पहनने व रहने में करते हैं। अगर परिवार नियोजन की सुविधाओं का दुरुपयोग होता है तो यह तो व्यक्तिगत चरित्रहीनता के कारण। जिनको Adultery (एक से अधिक स्त्री भोग या पुरुष के साथ सहवास) का शौक है वे तो हर हावत में यह करेंगे।

Dr. C. B. Mamore के शब्दों में :

"शादी के बाहर यौनिक सम्बन्ध हमेशा बने रहे हैं, हर बात का किसी न किसी वर्ग द्वारा दुरुपयोग होता रहता है। लोग ब्लेड से अपना या दूसरे का गला काट लेते या देते हैं, पर हम इस कारण ब्लेड से दाढ़ी बनाना तो नहीं छोड़ सकते, सोम कुम्भों या ताकियों में गिर जाते हैं परन्तु हम उन्हें बन्द तो नहीं कर देते।"

4. क्या किया जा रहा है ?

विषय में परिवार नियोजन बहुत पुरानी रीति है। आदि काल से मनुष्य को दफ़ पैदा न करने की कुछ न कुछ रीति मान्य थी तथा किसी न किसी रूप में परिवार नियोजन प्रयत्न किया जा रहा है। पुराने जमाने में भी जड़ो-बूटियों से बच्चे का जन्म रोका जाता था (चित्रक, कल्मशा, भर्दनगैरंगा, साल मिट्टी, आदि)। बच्चों को गर्भवस्था में मिराना (Abortion), मार डालना (Infanticide)

ब्रह्मचर्य, सहवास के पश्चात् योनि से बाहर स्खलित होना, सहवास करना परन्तु स्खलित ही न होना, रुई में तैल या फिटकरी लगाकर योनि में रखना आदि रीतियाँ पहले से प्रचलित थीं।

कन्डम (Condom or prophylactic sheath or F. L.) वास्तव में पहले मलमल तथा बाद में जानवरों की भिल्ली से बना और 1564 में इटली के Fallopius ने इसे सुझाया था। Diaphragm का प्रयोग 1880 के बाद और जैर्मा का इस शताब्दी के आरम्भ में प्रयोग शुरु हुआ। हाल के वर्षों में नई गोलियों का (खाने और रखने की) प्रयोग शुरु हुआ है। आपरेशन को भी सरल, जल्द होने वाला, जन्म असम ठीक होने वाला, निरापद तथा ओखिम रहित बनाया गया है।

यूरोप व अमेरिका में परिवार नियोजन का अपना बहुत आम बात है। इन देशों में प्रायः की अधिकता, शिक्षित दम्पतियों की चाह, स्त्रियों की स्वतन्त्र मनोवृत्ति, शहरीकरण, उच्चजीवन स्तर की चाह आदि के कारण परिवार नियोजन 1870 से ही काफी प्रचलित है। अमेरिका में तो लगभग 70% शादीशुदा व्यक्ति किसी न किसी रूप में परिवार नियोजन सामग्री प्रयोग में लाते हैं। फ्रान्स में तो घटती हुई जनसंख्या की समस्या सामने रहती है और 1936 से ही फ्रान्स में अधिक बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस में भी इसी प्रकार से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। आज वहाँ चौथा बच्चा पैदा करने पर 250 एबल तथा पाँचवें पर 375 एबल और नौवें बच्चे पर 775 एबल इनाम दिया जाता है। अधिक बच्चे पैदा करनेवाली माँ को तमगे दिए जाते हैं। एशिया में चीन व जापान में परिवार नियोजन का बहुत रिवाज है। जापान में तो बच्चा गिराना (Abortion) कानूनी रूप से वैध है। चीन सरकार परिवार नियोजन को पूँजीवादी विचारधारा मानती है। वह जनशक्ति को सीमित नहीं करना चाहती। परन्तु हाल के वर्षों में साखान्न के सकट के कारण उसने भी परिवार नियोजन के पक्ष में कार्य करना शुरु कर दिया है। उसका कहना यह है कि इससे चीन की माताओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वे देश की उन्नति में अधिक योगदान देगी।

दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में परिवार नियोजन निजी मामला माना जाता है और अभी तक राज्य ने कोई उल्लेखनीय दिनचस्पी नहीं दिखाई है।

भारत में परिवार नियोजन :

भारत में परिवार नियोजन संवन्धी आन्दोलन बहुत पुराना नहीं है। प्रो० वाताल

(Wattal) ने सर्वप्रथम इस संबंध में अपना मन व्यक्त किया और प्रो० धार० बी० कार्वे ने 1925 में बम्बई में, घोर विरोध के बीच, एक बनीविक लोहा मद्रास में नव मातृसू लीग की स्थापना हुई और 1930 में विश्व में प्रथम बार एक सरकारी परिवार नियोजन क्लिनिक मैसूर में खुला. 1936 में बम्बई में प्रथम स्त्री क्लिनिक परिवार नियोजन के लिए खुला. 1939 में उज्जैन में मात्र सेवा सघ द्वारा तथा उत्तर प्रदेश में भी कुछ बनीविक सुले 1949 में प्रथम "कैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इन्डिया" की स्थापना हुई स्वतंत्रता के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को योजना का अंग बना दिया. भारत इस प्रकार से विश्व में पहला देश बना जिसमें परिवार नियोजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण देश की योजना में स्थान दिया पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन को उतना महत्व नहीं दिया गया था जितना कि तीसरी योजना में दिया गया. प्रथम योजना में केवल 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और द्वितीय योजना में 4.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया इन दस वर्षों में 28 परिवार नियोजन सचवी भण्डयन संचालित किए गए.

तीसरी योजना में इसे सजीव और उच्चस्तरीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया. इस कार्यक्रम को स्पष्ट एवं ठोस रूप मिला इस योजना में 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें से लगभग 26 करोड़ रुपये व्यय किए गए योजना में यह बात मूल रूप में मान ली गई कि "योजनावद्ध विकास का केन्द्र बिन्दु निश्चित अवधि के लिए जनसंख्या में वृद्धि की निर्धारित दर बनाए रखना होना चाहिए. तथा इसे एक ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में अपनाने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति, परिवार तथा देश के लिए उन्नत जीवन सुलभ करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना हो." तृतीय योजना काल में 23 लाख स्त्रियों ने किसी न किसी रूप में परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाया.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 145 करोड़ रु० खर्च करने का प्रावधान है इस राशि को Family planning education committee की सिफारिश के अनुसार दस राशि को 240 करोड़ रु० तक कर दिया जाएगा. चतुर्थ योजना में किसी भी आर्थिक-सामाजिक नीति को इतना महत्व नहीं दिया गया है. यद्यपि परिवार नियोजन एक प्रांतीय विषय है तथापि इसे केन्द्रीय सरकार के

कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम का संचालन और समन्वय अधिक प्रभावशाली ढंग से होगा। योजना का लक्ष्य यह है कि जन्म दर को 40 प्रति हजार में कम करके 25 प्रति हजार तक ले आया जाए। इसके लिए यथाशीघ्र समस्त 5000 विकास ब्लॉक तथा शहरी क्षेत्रों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग से दफ्तर खोलें व कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है। हर शहर, ब्लॉक में केन्द्र है तथा निजी संगठनों व डाक्टरों की भी सेवाएं ली गई हैं। लेडी डाक्टरों के अभाव को पूरा करने के हेतु एक Central Family Planning Corps of Doctors बनाया गया है, जिसमें से राज्यों को आवश्यकतानुसार सख्या में डॉक्टर भेजे जाते हैं। अधिकांश राज्यों में पूरे समय के सन्तति-निग्रह अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। केन्द्रीय संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए अगस्त 1965 में एक परिवार नियोजन कमिशनर नियुक्त किया गया है। छ प्रदेशिक कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। अब तक लगभग 80,000 व्यक्ति प्रशिक्षित कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों में तत्संबंधी अध्ययन शुरू हो गया है।

1967 में अनुमानतया 20 लाख व्यक्तियों ने आपरेशन कराए और 20 लाख स्त्रियों ने लूप लगाए। इसके अतिरिक्त 20 लाख अन्य स्त्रियों द्वारा किसी अन्य तरीके से, परिवार नियोजन के तरीके अपनाए हुए थीं। अत्यंत लक्ष्य यह है कि हर वर्ष 60 लाख स्त्रियों को लूप लगाए जाए तथा भारत में 9.5 करोड़, वच्चे उत्पादन कर सकने योग्य, पति पत्नियों के परिवार नियोजन करा दिये जाएँ। योजना के अनुसार 1968-69 में प्रत्येक हजार में से 16 तथा 1973-74 में 33 स्त्रियां लूप धारण किए हुए हों। 1971 के अन्त तक लगभग 35 लाख आपरेशन करने का भी लक्ष्य है। कानपुर में लूप बनाने का कारखाना भी स्थापित हो चुका है जिसमें 30 हजार लूप प्रतिदिन तैयार होते हैं। आपरेशन करने पर नगद रकम दी जाती है तथा छुट्टियां भी दी जाती हैं। भारत में अब गर्भ निरोध वस्तुएँ बहुत ही सस्ती कीमतों पर बाजार में उपलब्ध हैं।

1968 तक (1-11-1968) 53 लाख व्यक्तियों का आपरेशन हो चुका था और कुल 26 लाख लूप लगाए गए। शहरों में परिवार नियोजन केन्द्रों की सख्या 1880 हो गई थी तथा गांवों में भी लगभग 24400 केन्द्र स्थापित हो गए थे। इनके अतिरिक्त 9130 अन्य निजी डिस्पेंसरियों में परिवार नियोजन संबंधी सुविधाएं मौजूद थीं। आज भारत में 1,25,000 व्यक्ति परिवार नियोजन के कार्य

में सगे हुए हैं, भारत में 30 अनुसंधान केन्द्र, 43 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा 5 ट्रेनिंग सेंटर हैं आगे भी भारत में इस दिशा में बहुत प्रगति सुनिश्चित है।

5 कम-विकसित देशों में परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए बाह्यनीय कदम या सुझाव :

कम-विकसित देशों में परिवार नियोजन को सफल बनाने में कोई शिथिलता नहीं बरतना चाहिए, यह तो जिन्दगी और मौत का प्रश्न है (It is a question of do or die) तथा इस कार्यक्रम को युद्ध की गम्भीरता से सफल बनाना होगा (on war footing). कम-विकसित देशों में परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे

1. सर्वप्रथम, इसके लिए हर देश को पर्याप्त माना में धन का आभोजन करना चाहिए हम देख ही चुके हैं कि बच्चे के जन्म को रोकने का व्यय उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने व रहने के इन्तजाम के व्यय से कहीं कम पड़ेगा यही बात सभी देशों के लिए भी लागू होती है विकसित देश भी इसके लिए धन, तकनीकी सहायता तथा आवश्यक उपकरण दे सकते हैं आज के युग में यह सहायता शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगी।
2. दूसरे इसके लिए इन देशों में प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, प्रणीत डाक्टरों नर्सों, हेल्थ विजिटर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। इन व्यक्तियों में योग्यता व लगन दोनों होना चाहिए, अगर एकदम डॉक्टरों की संख्या न बढ़ाई जा सके तो अस्पतालिक 'ट्रेनिंग' देकर भी कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा सकता है इन कार्यकर्ताओं का कार्य-क्षेत्र विशेष रूप से गाँवों में रहेगा और इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए
3. तीसरे, इसके लिए आधुनिक उपकरण व अस्पताल सुविधाओं की भी आवश्यकता रहेगी राज्यों को इसे प्रदान करने में महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए, गाँवों में इन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए चक्की फिरती गाड़ियाँ (Motorable vans) प्रयोग में लाई जाना चाहिए, हर अस्पताल में परिवार नियोजन शाखा होना चाहिए।
4. परिवार नियोजन सबसे सामग्री सस्ती दरों पर सुलभ होना चाहिए, जैसाकि सर्वविदित है खंड के गन्धम, 'आयुधर गोतिरियां जैलो व विवकारी, तथा खाने की गोतिरियां तो बाजार में ही उपलब्ध की जा सकती हैं परन्तु स्त्रियों के प्रयोग के लिए 'पेसरीज, व 'डायामा' जो गर्भाशय के मुँह पर

जैली डालकर प्रयोग किए जाते हैं, वे केवल अस्पतालों में ही (योनी के नाप के अनुसार) दिए जाते हैं.

I U C D (Intra uterine contraceptive device) या ' लूप' भी अस्पताल में ही फिट किए जाते हैं. इन्हें भी कम-विकसित देशों में अधिकाधिक मात्रा में सुलभ होना चाहिए.

परिवार नियोजन का सबसे अच्छा तरीका पुरुषों व स्त्रियों का आपरेशन है और इनके लिए सुविधाएँ व पुरस्कार प्रदान किए जाना चाहिए. आपरेशन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए.

5. शायद सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता परिवार नियोजन का प्रचार होगी. कम-विकसित देशों में शिक्षा की कमी के कारण यौन संबंधी जानकारी कम रहती है बहुत से बयस्क, यहाँ तक कि शादीशुदा व्यक्ति भी, यौन संबंधी समस्याओं के ज्ञान में अनभिज्ञ रहते हैं केवल सभोग क्रिया का ज्ञान ही सब नहीं होता वरन् स्त्रियों व पुष्ट्या की संरचना व तत्संबन्धित बीमारियों या प्रजनन प्रक्रिया का ज्ञान भी आवश्यक होता है

अधिकाधिक प्रचार से जनता को परिवार नियोजन के लाभ समझाए जाना चाहिए तथा उन्हें परिवार नियोजन के लिए राजी करना चाहिए इसके लिए प्रचार विज्ञानदित होना चाहिए अर्थात् नगरपालिकाएँ, बोर्ड, पञ्चायतें या वि. मा. सं. संघों आदि लोगों को उन्हीं की भाषा में इन बातों की आवश्यकता समझाना चाहिए पोस्टर, मॉडल, पत्रों, सिनेमा फिल्मों तथा स्लाइड्स, ड्रामे, कहानियों, कविताओं आदि सभी का सहारा लेकर उनका प्रचार आवश्यक होगा

आवश्यकता इस बात की है कि इतना अधिक प्रचार हो कि किसी भी व्यक्ति को परिवार नियोजन सामग्री का प्रयोग करने या जानकारी हासिल करने में क्लिष्ट या झूठी शर्म न बाकी रह जाए परिवार नियोजन की सफलता तो सब होगी जब कि निम्नस्तर के जीवनयापन करनेवाले कृषक व मजदूर लोग तथा विपक्षी समूह भी इस कार्यक्रम को अपना लें.

- 6 परिवार नियोजन के हर तरीके को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोग अपनी इच्छानुसार इसको अपना सकें. परिवार नियोजन को बच्चे के जन्म को रोकने तथा Spacing या बच्चों के बीच समय के अन्तराल के लिए अपनाया जाता है परन्तु अधिकतर आपरेशन या लूप पर जोर दिया जाना

- चाहिए, नूप के बाद स्त्रियों को बहुधा अधिक रक्तस्राव की शिकायत हो जाती है जिसकी नियोजन केंद्रों को अच्छी देखभाल करना चाहिए। भाव-स्थितानुसार देशों में बच्चे गिराने को भी कानूनी बनाया जा सकता है, ताकि जिस बच्चे की चाह न हो उसे गिराया जा सके।
7. बड़े-बड़े कारखानों एवं डिपेन्सरियों में भी इन सुविधायों को प्रदान किया जाना चाहिए। इन कारखानों में श्रमसंघों को भी इस ग्रान्टोमन को सफल बनाने के लिए सहायता देना चाहिए कारखानों के मजदूरों को भी हमें अपनाते पर भी छुट्टियाँ आदि की सुविधा देना चाहिए।
8. परिवार नियोजन अपनाते के लिए आर्थिक प्रलोभन भी आवश्यक होया। प्रत्येक स्त्री या पुरुष जो परिवार नियोजन के लिए आपरेशन कराता है उसे कुछ आर्थिक अनुदान देना चाहिए, उसका तलाक़ भी इलाज मुफ्त होना चाहिए कुछ अन्य निरम को रूकावटें भी लगाई जाती हैं, जैसे अगर 3 या 4 से अधिक बच्चों के होने पर शिक्षा में बच्चे या मातुल अवकाश न दिया जाये आदि।
9. कम-विकसित देशों में Eugenic programme अपनाता चाहिए अर्थात् लय, कोड तथा अन्य प्रभाव्य बीमारियों या यौनिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का अनिवार्यरूप से वन्धीकरण कर देना चाहिए। असह्य भिखारी, या भिखारियों जैसे जीवन व्यतीत करने वालों को अनिवार्य रूप से या सम-झाकर बच्चे पैदा करने के अयोग्य कर देना चाहिए।
10. अन्य आवश्यक कदम जो इस दिशा में उठाये जाना चाहिए उनमें अनुसंधान व सामाजिक सहयोग प्राप्त करना मुख्य होगा।
- Dr C. B. Mamoria के शब्दों में
- “Medical men and women, nurses and health visitors, demographers, economists, chemists, nutrition experts, sexologists, psychologists, psychiatrists, pathologists, research workers, clinicians, statisticians and social workers would all have to co-operate in building a satisfactory programme to cover all aspects of the vast field that must be tackled.”

देश में आर्थिक विकास के साथ-साथ परिवार नियोजन को स्वयं ही अधिकाधिक मात्रा में अपनाया जाएगा परन्तु आज के युग में परिवार नियोजन का संदेश घर-घर पहुँचना चाहिए.

Sir Winston Churchill ने एकबार कहा था

“अगर मुझे समय मिले तो मैं हर घर के सामने लिख दूँगा कि बीमा कराइए.”

उस स्थान पर मैं यह कहना चाहूँगा

“आज हर घर में यह संदेश पहुँचना चाहिए कि परिवार नियोजन कराओ.”

(b) Increasing Food Supply & better nutritional diet :
खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तथा संतुलित आहार :

(कृषि उत्पादन संबंधी अध्याय देखिए इसमें आप संक्षेप में यह अध्ययन कर सकते हैं कि कम-विकसित देशों में कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है तथा उनका क्या महत्व है).

संतुलित आहार :

कम-विकसित देशों में कृषि का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ानी होगी कृषि उपज के यातायात व संचय की सुविधाओं को सुधारना होगा. कृषि की Inputs (सिंचाई, खाद, बीज आदि) को बढ़ाकर, उन्नत तकनीक अपनाकर, कृषि योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि करके, फसलों की रक्षा करके, एक से अधिक फसलें उगाकर, उन्नत बिस्म की फसलें उगाकर, कम-विकसित देशों को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म निर्भर होना होगा आज अमेरिका की अधिकाधिक खाद्यान्न की कमी पूरी करने की क्षमता कम होती जा रही है इससे कम-विकसित देशों की कृषि उपज व राष्ट्रीय आय बढ़ानी होगी.

केवल अधिक मात्रा में खाने से ही शरीर पुष्ट नहीं होता. वास्तव में संतुलित आहार अधिक महत्वपूर्ण होता है कम-विकसित देशों में आहार के असंतुलन व आहार में प्रोटीन की कमी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं.¹

अगर विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1965 की वृद्धि दर की भाँति ही रही तो 1985 में 52% और अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होगी और अगर परि-

1. See : Characteristics of under developed Countries Demographic Characteristics.

वार नियोजन का आन्दोलन प्रभावकारी रहा तो भी 43% अधिक केनोरीज की आवश्यकता होगी यह तो विश्व का औषत है कम-विकसित देशों में तो केनोरीज की आवश्यकता और भी अधिक रहेगी, जैसे भारत में 88% से 108% और अधिक केनोरीज प्रदान करनी पड़ेगी पाकिस्तान में 118% से 146% अधिक केनोरीज प्रदान करनी पड़ेगी इसी प्रकार ब्राजील में 91% से लेकर 105% तक अधिक केनोरीज युक्त भोजन देना पड़ेगा। अगले 20 वर्षों में (1986 में) इन देशों में आद्यान्न की आवश्यकता दुगुनी हो जाएगी। इसलिए कम-विकसित देशों में उत्पादन में भी वृद्धि करनी होगी और जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वव्यापी भुखमरी भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की ही समस्या है।

असंतुलित आहार की कमी दूर करने के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होगी, जिसे हम Single-cell Protein से दे सकते हैं इसे हम Yeast या Bacteria of Carbohydrates, Hydrocarbon या Cellulose से तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से अगर हम प्रोटीन उत्पादित करके वितरित कर सकें तो विश्व के व्यक्तियों का स्वास्थ्य आद्यान्न पर ही निर्भर नहीं रहेगा फूलगन्तियों में तथा ऐल्गी (Algae) से भी प्रोटीन प्राप्त करने के सवध में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुके हैं Algae के फोक (waste elements) को हम जानवरों को भी खिला सकते हैं हम गोشت का उत्पादन व मछली का उपयोग भी बढ़ा सकते हैं पेट्रोलियम में भी प्रोटीन प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहे हैं शायद भविष्य में खाद्य समस्या के निराकरण में समुद्र पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान रहे। यह साधन अभी लगभग असीमित मात्रा में खाद्य पदार्थ दे सकता है कम-विकसित देशों में बच्चों को प्रोटीनयुक्त खाना दिया जाना चाहिए सोयाबीन, मूँगफली, धीरे-धीरे बपासिए से 'शाकाहारी प्रोटीन' प्राप्त हो सकता है। मांस से प्राप्त होने वाला प्रोटीन उन जानवरों से अधिक प्राप्त करना चाहिए जो अपने भोजन के लिए मानव जाति से प्रतिस्पर्धिता न करें

(c) Rational Distribution of Population : Emigration.

जनसंख्या का विवेकपूर्ण वितरण :

जनसंख्या की समस्या के निवारण हेतु जनसंख्या का विवेकपूर्ण वितरण भी आवश्यक होता है। यह जनसंख्या का हस्तान्तरण देश में तथा विदेशों में किया जा सकता है बहूधा यह सलाह दी जाती है कि विश्व की जनसंख्या समस्या के विवेकपूर्ण रूप से हल करने हेतु अधिक जनसंख्या वाले देशों से 'अतिरिक्त' जनसंख्या को

कम जनसंख्या वाले देशों में भोजना चाहिए। आज विश्व में आस्ट्रेलिया, पश्चिमी-उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा तथा दक्षिणी अमेरिका में लाखों एकड़ भूमि पर उन्नति करने एशिया की जनसंख्या को बसाया जा सकता है। इन देशों के ऊष्ण क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान, चीन व जापान के व्यक्ति बसाए जा सकते हैं। इन देशों के व्यक्ति इन कम जनसंख्या वाले देशों में जाकर वहाँ के वनों, कृषि योग्य भूमि व साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं।

परन्तु आज के इस “सर्वांगीण राष्ट्रीयता” के युग में यह संभव नहीं दीखता। आज विश्व बंधुत्व कोरा कल्पना है। आज हमारे देशों की जनसंख्या अपने देश में लेना तो दूर की बात रही, शक्ति कई देश तो आज उन विदेशियों को ही बाहर निकालने लगे जिन्होंने उन देशों की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय प्रवासियों का ही हम उदाहरण ले सकते हैं। हम भारतीय प्रवासियों को लगभग विश्व के समस्त देशों में देख सकते हैं, परन्तु मुख्यरूप से ये वर्मा, लका, द० अफ्रीका, केन्या, मलाया, सिंगापुर, मारीशस, फिजी, ब्रिटेन, क्रुवैन, ब्रदन, वेस्ट इन्डिज, ब्रिटिश गायना आदि में हैं। अन्य देशों में भी (यू. एस. ए., कनाडा, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, तनजानिया व अन्य देश) भारतीय प्रवासी कारी संख्या में पाए जाते हैं। अनुमानतया आजकल 50 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व के अन्य देशों में हैं। ये व्यक्ति मुख्य रूप से ऊष्ण देशों में हैं और मुख्य रूप से सस्ते मजदूरों के रूप में भारत में से जाए गए थे और 75% से अधिक वे ‘कामनवेल्थ’ देशों में हैं। इन प्रवासियों को वागान, खानो, रेलवे-लाइनें बनाने आदि में कार्य करने के लिए ले जाया गया था। वर्मा, लका, केन्या व दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों को निकाला जा रहा है और उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त विश्व के भिन्न-भिन्न देशों के प्रवासी न तो नए देशों के व्यक्तियों से और न अन्य स्थानों से आए हुए प्रवासियों के साथ घुलमिल पाते हैं। भाषा, धर्म, रंग व अन्य रीति-रिवाजों के भेदों के कारण बहुधा खून खराबा हो जाता है, जैसे हाल के दिनों में मलाया में मलाया वासियों (चीनी, भारतीय व मलय) के बीच खून खराबा चल रहा है।

Kingsley Davis के अनुसार

“कम-विविधता देशों से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में जो व्यक्ति उन्नत देशों द्वारा लिये जाते हैं, वे सामान्य में कुशल व्यक्ति होते हैं—जैसे डाक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि कम-विविधता देशों में इनकी आवश्यकता अधिक रहती है, परन्तु केवल कुशल व्यक्तियों

जनसंख्या नीति

के लिए जाने से कम-विकसित देशों की जनसंख्या की निम्न सराव होती है और इन देशों में Brain Drain या कुशलता का निर्यात हो जाता है”

देश के प्रकार :

जहाँ तक किसी देश में जनसंख्या के स्थानांतरण का दावा को ठीक करने का प्रश्न है, जनसंख्या का एक स्थान से (अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में) दूसरे स्थान या क्षेत्र (कम घनत्व वाले) में ले जाने से अनेक समस्याओं का निराकरण होगा भारत में दक्षिण भारत में वेस्ट, तथा पूर्व में बंगाल से अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या का लाना वांछनीय होगा। इंडोनेशिया में जावा द्वीप में ही 90% जनसंख्या रहती है और जनसंख्या का घनत्व सम्पूर्ण देश में बहुत अधिक न होते हुए भी, जावा विषय के बहुत अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में एक है।

इस मद में सबसे बड़ी समस्या अनुपयोग में गतिशीलता की कमी की रहती है। भारत में आज भी 90% जनता अपने जन्म स्थान के जिलों में ही रहती है और 5% घागपास के जिलों में रहती है केवल 5% जनता ही उल्लेखनीय रूप से प्रवासी हुई है भाषा की भिन्नता, धन की कमी, यातायात व आवास संबंधी कठिनाइयाँ, परिवार व स्थान प्रेम आदि के कारण गतिशीलता कम रहती है बहुधा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में ही जनसंख्या प्रवासी होती है, परन्तु

“There is obviously not much scope for relieving over-population by emigration” Spatt O H K, India & Pakistan, p 113.

“Emigration will not check growth in the most important areas of population pressure at the present stage of the demographic situation” Review of Demographic Studies of Selected Areas of Rapid Growth, 1947, p 318

“In our present nationalised world, in which the best lands have been occupied and restrictive measures are in force, migration is no answer to economic and social strain induced by so-called overpopulation” 1 Bowman, Limits of Land Settlement, 1937, p 1.

“As a sole relief for population pressure, emigration is a palliative rather than a solution To be effective it must not only remove people from the region, but by hastening social change, aid in reducing fertility.” Davis, Population of India and Pakistan, 1951, q f. Mamoria, op. cit, p. 97.

दुर्भाग्य से आज भारत में ही एक क्षेत्र की जनसंख्या का दूसरे क्षेत्र में स्वागत नहीं होता। प्रांतीयता बढ़ती जा रही है, इस प्रवृत्ति का मूल कारण देश में बेरोज़गारी की समस्या है। आज अगर यह समस्या नहीं रहती है तो पुनः भारतीयों में हर क्षेत्र के लोगों के साथ प्रेम से रहने की प्रवृत्ति कायम हो जायेगी।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या ले जाने से देश के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देश में अघिन्न घनत्व के क्षेत्र से कम घनत्व के क्षेत्र को जनसंख्या ले जाने के लिए यातायात, आवास, स्कूल, अस्पतालों में विनियोजन बढ़ता है। इससे देश में रोज़गार भी बढ़ता है। उत्पादकता बढ़ती है और साधनों का विवेकपूर्ण वितरण होता है और अनुकूलतम प्रयोग होता है।

जनसंख्या के विवेकपूर्ण वितरण के लिए आन्तरिक हस्तान्तरण महत्वपूर्ण सभाबनाएँ रखता है।

(d) Extension of educational and medical facilities and suitable institutional changes. शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास व सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन :

शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का भी जनसंख्या समस्या निराकरण में बहुत महत्व है। शिक्षा के विकास से परिवार नियोजन का विरोध शिथिल होता

References :

Apart from the books mentioned in previous chapters this chapter has been prepared using the matter of under-mentioned books and papers

1. The World Food Problem - A Special Report to President Johnson, May 1967, U. S. I. S., New Delhi
2. U. N. World Population Conference Papers, Belgrade, Yugoslavia, 30 August to 10th September 1965, Manpower Structure in Relation to Economic Growth by K. S. Gnanasekaran.
3. Yojana, Vol. XII No. 18, Sept 15, 1968 - A Special Number on Family Planning, with following articles :
 - (i) Jaya Prakash Narain - Graver than an Invasion.
 - (ii) Dr. S. Chandrasekhar - Towards a People's Programme
 - (iii) Dr. Ashish Bose : Life begins at Twenty
 - (iv) Dr. S. N. Agarwal : Demography & Development.

जनसंख्या नीति

है, रोग निरोधक कदम जल्द उठा लिये जाते हैं और औसत आयु में वृद्धि होती है। शिक्षा का विकास पर भी महत्व होता है, शिक्षित समाज अधिक पूँजी संचित करता है, उन्नत तकनीक से अधिक उत्पादन होता है और इन सबका जन्म दर गिराने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से भी आयु बढ़ती है और फिर कम बच्चे पैदा करने की आवश्यकता रहती है।

वहाँ तक समस्याओं में परिवर्तन का प्रयत्न है, सबसे महत्वपूर्ण बात दो देशों में शादी की आयु को बढ़ाना होगा। अगर पुरुषों की शादी की आयु 25 व लड़कियों की 20 कर दी जाय तो भी आधी समस्या तो हल हो जाए इस सम्बन्ध में कानूनी नियम बनाए जाना चाहिए।

स्त्रियों को उच्च सामाजिक दर्जा देने व उन्हें शिक्षा देने से भी जन्मदर कम होगी। जहाँ स्त्रियाँ शिक्षित, स्वतन्त्र व समाज में ऊँचा दर्जा पाती हैं वहाँ जन्मदर कम हो जाती है। इसी प्रकार से स्त्रियों द्वारा नौकरियों करने से भी जन्मदर में कमी आती है।

-
- (v) Govind Narain : A target-and time-oriented programme.
 - (vi) Frank Wilder . Telling the Millions.
 - (vii) G K Mathur . Crossing the Mental Barrier.
 - (viii) Dr Dipak Bhatia World's biggest drive.
 - (ix) Dr. J. N. Sinha : More people, less food.
 - (x) Dr. K. C. Sehgal : Small families, better living.
 - (xi) Dr Raina : Role of Research.
 - (xii) K. B. Suri : Education & Population Growth.
 - 4 Bowen : Population (contains good information and discuss on world population, various factors that govern population growth, population & food supply, ideas of maximum, minimum population, optimum population and ecological equilibrium and international migration.)
 5. Coontz : Population Theories and the Economic Interpretation.
 6. Sadler : Biology & Population Growth & Studies in Human Biology.
 7. Josue De Castro : Geography of Hunger.
 8. Nirmal Sethi : A very mixed attitude to Family Planning.

(e) An optimum population to be conceived : अनुकूलतम जनसंख्या

हर देश के प्राकृतिक साधना, विदेशी आय व महायता व तकनीक के आधार पर एक अनुकूलतम जनसंख्या होती है यह जनसंख्या वास्तव में एक सैद्धान्तिक कल्पना है परन्तु फिर भी हर देश को अपनी जनसंख्या इससे ऊपर नहीं जाने देना चाहिए.

Imre Ferenczi के अनुसार

"All population considerations be fitted into the frame of reference known as optimum population This concept will very likely always be more of a desideratum than a precise formula We may make two approaches in the

-
9. U N. World Demographic Year Books
 10. U N. The Determinants and Consequences of Population Growth
 11. C B. Mamoria Population Growth and Economic Development in India
 12. C B. Mamoria Population & Family Planning in India.
 13. Philip M Hansen & Otis Dudley Duncan • The Study of Population, Yojana July 9, 1967.
 14. G C Hallen . A National Population policy to be evolved by a National Population Commission—Some doubts and questions
 15. Planning Commission of India : Draft Fourth Five year Plan.
 16. Warren S Thompson Population Problems, Assistant, Evelyn D. Minnis
 17. S. Chandrasekhar Areas of Light & Darkness : Yojana, Vol. XI. No 3. July 9, 1967.
 18. " " Asia's Population Problem
 19. " " Hungry People & Empty Lands.
 20. Jesselyn Hennessy . Food Problems in Developing countries—Eastern Economist, Feb. 23, 1968. & two further members—March 8, 1968
 21. George C. Zaidan • Population Growth and Economic Development

search for an optimum population. Quantitatively, it implies a set of economic and social conditions which will allow each citizen an opportunity to satisfy his fundamental needs according to certain minimum standards. Qualitatively, it means a population programme which, while guaranteeing the continued maintenance of a people, takes into account the eugenic as well as euthenic improvement of the population. Obviously, a fixed optimum is an impossibility."

-
- 22 J N Shrivastava : Occasional Papers No 2 Family Planning in India, Demographic Research centre, Lucknow University.
 - 23 American Reporter • Aug 16, 1967 A 20 year Graphic Projection of India's Food-Population Problem
 24. Also in details in Economic & Political Weekly, July 8, 1967.
 - 25 H W. Singer : op cit : ch. 8.
 26. H Vellard • op cit : ch 16,17.
 27. William Fielding Ogburn : Population, Resources, Technology & levels of Living
 - 28 Manuel Gottlieb . The Theory of optimum population for a closed Economy.
 - 29 Joseph Spengler : Population & per capita income.
 - 30 Alan T. Peacock . Theory of Population & Modern Economic Analysis
 31. Joseph Spengler Population Movements, Employment and Income.
 - 32 Alvin H. Hansen : Economic Progress & Declining Population Growth.
 - 33 Meivin D. Brockie • Population Growth & the rate of Investment.
 - 34 Clarence L. Barber : Population Growth and the demand for Capital.
 - 35 August Losch : Population cycle as a cause of business cycle

नलषकरुव :

ऑनसखुडल नुतल नुँ सुखुडतुडल ऑन डलतुु कल सडलडेश हुनुल ऑलहुल :

- (1) डऑऑु कल ऑनुडडर नलडऑऑत हुु, वु डलतल-डलतल कल ऑऑऑलनुसलर डुँडल हुु.
- (II) डेश डु ऑनसखुडल कल सडुऑऑत डुँडऑलरल हुु.
- (III) डेश कल ऑनसखुडल कल वलडुड सुडरु, अरुडलतु ऑनकल शलऑल, सुवलसुडु, सलसुऑऑऑऑऑऑ सुतर डुँ वुऑऑ हुु.
- (IV) सडलऑ कल डलनु-डलनु वरुु कल अलवशुडऑलनुसलर डुऑऑत हुु.
- (V) अरुऑऑ ऑनसखुडल कल सडसुडल वु नलरलकरलु हुुतु खलऑलनु कल डुऑऑत डुँ डुँ वुऑऑ हुु, तलडल ऑनुड डर डुँ डुँ वुडु ललई ऑलल.



-
36. Joseph Spengler : The Population obstacle to Economic Betterment.
 37. A. B. Wolfe : The Population Problem since the World War I.
 38. Donald ofen Cowgill : The Theory of Population Growth.
 39. Kingsley Davis . Population and the Further Spread of Industrial Society.
 40. Kingsley Davis : Population Growth & International Relations.
 41. Spengler & Duncan : Population Policy.
 42. Spengler : Socio-economic Theory and Population Policy.
 43. Frank W. Notestein : Problems of Policy in Relation to Areas of Heavy Population Pressure,
- News in Indian Express and other Newspapers and many other Journals.

अध्याय 12

आयोजन

Planning

I प्रस्तावना

आयोजन का अर्थ
संकुचित व सही विचारधारा, राबिन्स, डींग, डाब, स्मूथ, लवी, नेहरू
डिक्किसन, मिरडाल, लारकिन, बूटन, डाल्टन, फिश की परिभाषाएँ, सारयुक्त
परिभाषा

II आयोजन के उद्देश्य व विशेषताएँ

आर्थिक राजनैतिक सामाजिक

III आयोजन की मुख्य विशेषताएँ

IV आयोजन के प्रकार

(a) भौतिक व वित्तीय आयोजन

(b) संरचनात्मक व क्रियात्मक

(c) सुपाराम्क व विकास के लिए आयोजन

(d) प्रोत्साहन मूलक व प्रजातन्त्रीय आयोजन

(e) निर्देशन, केन्द्रीय सत्त्वा द्वारा समाजवादी शासकीय या फासिस्ट
आयोजन

V आयोजन की सफलता के आवश्यक तत्व

सिगर के बिचारों के नोट सहित

VI आयोजन व अनायोजित अर्थव्यवस्था

VII आयोजन की अवस्थाएँ

VIII आयोजन कार्यक्रमों की कमियाँ व कठिनाइयाँ

आयोजन

Planning

I. प्रस्तावना

आयोजन का अर्थ

संकुचित व सही विचारधारा .

आयोजन के अर्थ के संघर्ष में अर्थशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है. कुछ अर्थशास्त्री, जो पूँजीवाद के कट्टर समर्थक हैं वे राज्य के निजी सम्पादन व वितरण, थोड़े से हस्तक्षेप को "आयोजन" कहने लगते हैं इनके अनुसार 'आयोजन' व 'संगठनवाद' एक ही चीज है अर्थात् थोड़े से नियमन व हस्तक्षेप को वे अर्थशास्त्री 'समाजवाद' का आना मानने लगते हैं यह संकुचित मत है, और जैसा कि प्रो० हाएक ने कहा है.

"हो सकता है कि बहुत अधिक आयोजन के होते हुए भी, बहुत कम समाजवाद आए और उल्टा समाजवाद में बहुत ही कम आयोजन हो।"

इसके प्रतिरिक्त कट्टर समाजवादों तब तक आर्थिक व्यवस्था को आयोजित नहीं मानते जब तक कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का अधिकार न हो और वह ही उसे संचालित न करे वे थोड़ी सी भी आर्थिक स्वतन्त्रता को आयोजन का विरोधाभास मानते हैं. यह भी संकुचित मत है.

सही मत यह है कि आयोजित व्यवस्था में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में समन्वय होता है चाहे कुछ उद्योगों या मस्थानों की मालिकियत निजी क्षेत्र में हो क्यों न हो अधिकतर अर्थशास्त्री इसी मत के हैं.

आयोजन कोई नई चीज नहीं है :

आयोजन के अनुसार हर व्यक्ति हर समय कार्य करता रहा है हर व्यक्ति, थोड़ी या अधिक मात्रा में उपभोग में, भ्रमण करने में, खर्च व बचत करने आदि में आयोजन करते हैं. हर समाज, हर राष्ट्र और हर राज्य आयोजन करता है एमिल लेडरर (Emil Lederer) के अनुसार सभी भी कोई समाज आयोजन रहित

आयोजन

नही रहा है। समाज के कुछ या सम्पूर्ण भाग या थोड़ा बहुत आयोजन हमेशा किया गया है प्रो० राबिन्स (Prof. Robbins) ने इसीलिए कहा है कि "आज के युग में आयोजन हमारे लिए सर्वरोगघ्न औषधि या वैनोम चितामणि (Grand panacea) है"

आयोजन की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ :

राबिन्स :

"आयोजित व्यवस्था में निजी उत्पादन व विनिमय पद्धति पर राज्य का निर्देशन होता है। देश के निजी उत्पादनकर्ताओं की योजनाओं के लक्ष्यों में समन्वय लाया जाता है। आयोजन में हम देश के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधनों का चयन करते हैं।"

फर्डिनेण्ड ज्वेग (Ferdinand Zweig) के अनुसार :

"आयोजन एक विवेकपूर्ण कार्य है क्योंकि आयोजन का लक्ष्य देश के उपलब्ध साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है" राज्य द्वारा लगाए गए हस्तक्षेपों से अर्थव्यवस्था आयोजित नहीं हो जाती है हर राज्य में उपभोग, उत्पादन, मूल्य, वितरण, व्यापार, विनियोजन पर कुछ न कुछ नियंत्रण व नियमन रहता है। पर यह आयोजन नहीं होता। आयोजित अर्थव्यवस्था में पूर्ण अर्थव्यवस्था का आयोजित होना आवश्यक है। समुक्तराष्ट्र अमेरिका में भी थोड़ा बहुत आयोजन है, पर हम इसे आयोजन नहीं कह सकते।

आयोजन से शक्तिशाली केन्द्र सरकार की उत्पत्ति होती है और शक्तिशाली केन्द्रीय शासन व्यवस्था से आयोजित व्यवस्था सकल होती है।"

मॉरिस डॉब (Maurice Dobb) के अनुसार

"आयोजन में हम देश के महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को समन्वित रूप में कार्यान्वित करते हैं। आयोजित अर्थव्यवस्था में हम समस्त आर्थिक मुद्दों पर (प्रश्नों पर) तयकृत निर्णय लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के समस्त अंगों में अनुस्यूता रहे।"

जॉन ल्यूस (John Lewis) के अनुसार

"किसी देश में केन्द्र द्वारा आयोजित व संचालित अर्थव्यवस्था में राज्य ही देश की कुछ विनियोजन की मात्रा, देशवासियों के व्यवसाय या कार्य व उपभोक्ताओं द्वारा किए जानेवाला उपभोग-चयन निर्धारित करता है। आयोजित अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति की सस्था धीरे-धीरे

समाप्त हो जाती है अन्त में ऐसी अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भरता को प्राप्त कर लेती है.”

हारमन लेवी (Harman Levy) के अनुसार

‘आर्थिक नियोजन का लक्ष्य देश के अन्दर माँग और पूर्ति में समानता लाना है आयोजन में हम सोच विचार कर, ज्ञान पूर्ण रीति से, उत्पादन या वितरण या दोनों पर नियंत्रण करते हैं. आयोजित अर्थव्यवस्था में हम स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के विपरीत, माँग और पूर्ति में सक्रिय कार्य से समानता लाते हैं.”

श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार

“आयोजन का अर्थ केवल कार्य सूची बना लेने से नहीं होता और न ही यह एक राजनैतिक आदर्शवाद है. आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं व प्राप्त कर सकते हैं.”

एच. डी. डिकिन्सन (H D Dickinson) के अनुसार :

“जब एक केन्द्रीय शक्ति समस्त अर्थव्यवस्था के वृहत सर्वेक्षण के पश्चात् यह निश्चित करती है कि कितना पैदा करना है, क्या पैदा करना है तथा किस प्रकार से वितरण करना है, तो इस कार्य को हम आयोजन कहेंगे ”

गुन्नार मिरडाल (Gunnar Myrdal) के अनुसार

“आयोजित अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की सरकार स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था में इस प्रकार हस्तक्षेप करती है कि अर्थव्यवस्था से अधिवाधिक सामाजिक उन्नति हो ”

ल्यूस लारविन (Lewis Larwin) के अनुसार

“आयोजित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का इस प्रकार से गठन किया जाता है कि देश के अलग अलग चलनेवाले उद्योगों या व्यापारिक संस्थानों के विकास में समन्वय रहे ताकि कम से कम काल में अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक संतुष्टि मिले.”

श्रीमती बारबरा वूटन (Mrs. Barbara Wootton) . इनकी परिभाषा डिकिन्सन की परिभाषा की भाँति है अर्थात्

“आयोजित व्यवस्था वह है जिसमें स्वतंत्र बाजार पद्धति में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि वांछित नतीजे प्राप्त हो सकें.”

आयोजन

डाल्टन (Dalton) के अनुसार

“आयोजन में हम अपने पहले से चुने हुए तत्वों को प्राप्त करने हेतु धर्मव्यवस्था को संचालित करते हैं।”

रेगनर फ्रिश (Ragner Frisch) के अनुसार

“आयोजन हम उस उस वैज्ञानिक नियोजन को कहेंगे, जिसके अन्तर्गत हम आर्थिक समस्याओं और विकास कार्यों का एक हृदय विह्वल पण करते हैं तथा विकास कार्यों को अधिकतम (Optimum) लाभ प्राप्त करने हेतु करते हैं इसके अन्तर्गत हम इस प्रकार से एक साथ कार्य करते हैं कि हर एक कार्य हर दूसरे कार्य को प्रभावित या निर्धारित करता है”

एक ऐसी परिभाषा जो सबका सार देती है :

आयोजित धर्मव्यवस्था में

- (1) देश के व्यक्ति व्यापारिक व औद्योगिक स्थान व राज्य के कार्यों में समन्वय होता है और वे एक दूसरे के पूरक होते हैं
- (ii) आर्थिक आयोजन व्यक्तिगत लाभ के बढ़ाने के स्थान पर समाज के गरीब वर्गों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए किया जाता है
- (iii) इसका लक्ष्य देश के साधनों का अधिकतम उपयोग (जिसमें कम से कम बर्बादी हो) करके देश की राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जाए व जीवन स्तर को ऊँचा किया जाए व रोजगार वृद्धि हो और
- (iv) यह सब कार्य एक निश्चित समय में किए जाएँ

II Aims and characteristics of planning : आयोजन के उद्देश्य व विशेषताएँ

किसी भी देश के आयोजन में एडवर्ड हीमैन (Edward Heimann) के अनुसार तीन मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं

- (1) देश में साम्य स्थापित करना.
- (ii) अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाना तथा
- (iii) देश में महत्वपूर्ण सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तन लाना ।

(a) सर्वप्रथम हम आर्थिक उद्देश्यों का अध्ययन करें :

1 सर्वप्रथम आर्थिक उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपभोग व अनुकूलतम वितरण लाना होता है इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोजन देश के प्राकृतिक साधनों का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग कर लिया जाए इसका अर्थ यह होता है कि देश के साधनों का प्रयोग देश की बड़ी जनता के हित के लिए हो, कुछ एकाधिकारियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं माय ही प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग व बरबादी न हो

2 पूर्ण रोजगार देश के उत्पादन के भ्रगों में मनुष्य मुख्य साधन है आयोजित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कभी दूर नहीं होती व्यापार शत्रु के कारण उत्पन्न बेरोजगारी तो बनी ही रहती है ज्वोग के अनुसार "आयोजित अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार देना मुख्य लक्ष्य होता है और आयोजित क्रियाओं का मुख्य फल ही पूर्ण रोजगार स्थापित करना है हम एक भी आयोजित अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं बना सकते जिसमें पूर्ण रोजगार अथवा लगभग पूर्ण रोजगार न हो "

रूस व अन्य समाजवादी देशों में पूर्ण रोजगार है भारत में हमारी आयोजित व्यवस्था पूर्णरूप से आयोजित नहीं है इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति भी नहीं है

बेरोजगारी समाप्त करना तो आज हर देश का लक्ष्य बन गया है अमेरिका में "न्यू डील" का भी यही लक्ष्य था परन्तु हर देश पूर्ण रोजगार की स्थिति पर नहीं पहुँच पाता है, युद्ध के काल में रोजगार स्वयं बढ़ जाता है परन्तु शान्तिकाल में आयोजित व्यवस्था से ही पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ¹

आयोजित अर्थव्यवस्था में कृषि में अर्थ-बेरोजगारी को समाप्त करते हैं, कृषि विकास से जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में फालतू हो जाते हैं उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में आयोजन के अन्तर्गत रोजगार देते हैं

3 उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना आयोजित अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन व अनुकूलतम उत्पादन का लक्ष्य रहता है इस प्रकार की व्यवस्था में, जिन क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होता है, उसे या तो घटा दिया है या उसके लिए आन्तरिक माँग बढ़ाई जाती है व निर्यात किया जाता है.

आयोजन

अत्युत्पत्ति को देश पर सबट नहीं लाने दिया जाता है, जिन क्षेत्रों में उत्पादन कम होता है। उनमें बढ़ा दिया जाता है। अनायोजित व्यवस्था में मूल्य गिरने से अत्युत्पत्ति समाप्त होती है और वृद्धि से कम उत्पादन की स्थिति इन दोनों प्रकार की स्थिति से व्यापार चक्र आते हैं और देश को मूल्य गिरने या महंगाई बढ़ने के कष्ट उठाने पड़ते हैं। सफल आयोजन में यह नहीं होता उत्पादन बढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादनता बढ़ाना होता है। उत्पादकता का अर्थ उत्पादन बढ़ने की दर में वृद्धि से होता है अर्थात् कम समय में अधिक सामान पैदा होता है यह विकास की कुजी है अधिक उत्पादकता से लाभ व मजदूरी अधिक होती है व अधिक पूँजी प्राप्त होती है। आयोजन का मुख्य उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि लाना है

4. संतुलित विकास व पिछड़े इलाकों व वर्गों की उन्नति . अनायोजित अर्थ व्यवस्था में उन्ही इलाकों में उन्नति होती जाती है जहाँ सामाजिक व आर्थिक सुविधाएँ मौजूद रहती हैं (जैसे भारत में दम्बई क्षेत्र में) अन्य क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। वहाँ बेरोजगारी, पिछड़ापन व कम आय के स्तर बने रहते हैं आयोजित अर्थव्यवस्था में इन्ही पिछले इलाकों व वर्गों (जैसे आदिवासी या हरिजन) के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसके देश का विकास संतुलित रहता है
5. देश में समानता लाना वैसे तो अधिक उत्पादन बढ़ाने व देश में पूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने से स्वयं ही असमानताएँ दूर होती हैं। यहाँ जन्म दर अधिक बढ़ती है, उत्पादन कम बढ़ता है। आयोजित व्यवस्था का उद्देश्य इस प्रकार के असंतुलन को दूर करना होता है
5. देश में समानता लाना वैसे तो अधिक उत्पादन बढ़ाने व देश में पूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने से स्वयं ही असमानताएँ दूर होती हैं परन्तु आयोजित व्यवस्था से व्यय, सम्पत्ति व आय की इन असमानताओं को वित्तीय व राज-कोपीय नीति से भी दूर किया जाता है।

आयोजित अर्थव्यवस्था में उद्देश्य यह होता है कि "समृद्धि में समानता" लाई जाए ॥ कि "गरीबी की समानता" अर्थात् अधिक उत्पादन व समान वितरण से समानता लाई जाना चाहिए। धन व उत्पादन बढ़ाएँ समान वितरण अधिक उपयोगी न होगा। पहले समानता करने से पूँजी-निर्माण व उत्पादन रुक जाता है। पूर्णरूप से आयोजित व्यवस्था (जैसे रूस में) में भी पूर्णरूप से न तो समानता लाई जा सकी है और न ही लाई जा सकेगी। वृद्धि व योग्यता,

उत्पादकता व उद्योगों के स्वभाव के अन्तरो के कारण अधिक अन्तर बने ही रहते हैं. कृषि व उद्योग क्षेत्र में भी अन्तर रहेंगे.

परन्तु आयोजित अर्थव्यवस्था में "जन्म के लाभ" (धनी व्यक्ति के पुत्र होने) नहीं मिलते. योग्यता के अनुसार अवसर मिलने हैं और एक सीमा के ऊपर आय न रहने देने का उद्देश्य होता है.

' आयोजित व्यवस्था में जनसंख्या के बड़े भाग की आवश्यक आवश्यकताओं को धनी व्यक्तियों की मामूली आवश्यकताओं के सन्तुष्ट होने से पहले सन्तुष्ट किया जाता है न्याय व व्यावहारिक औचित्य की यही माँग होती है. जिस समाज में अन्यायपूर्ण असमानताएँ मौजूद रहती हैं उसमें बुराईयाँ व पनपन की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं देश में 'राजनैतिक प्रजातन्त्र' में अर्थिक सामाजिक प्रजातन्त्र आवश्यक होता है. समाज में दुःख व सुख का समान वितरण होना चाहिए देश में निरपेक्ष समानता को नहीं बरन् उचित समानता की आवश्यकता होती है."¹

- 6 सामाजिक सुरक्षा • आयोजित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य देश में सामाजिक सुरक्षा उत्पन्न करना है. यह सामाजिक सुरक्षा शिक्षा व रोजगार के समान अवसर के प्राप्त होने तथा बेरोजगारी को समाप्त करने से उत्पन्न होती है "सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रोजगार, उचित मजदूरी, उचित लाभ, उचित मूल्य, लगान, व्याज व विनिमय की दरों के स्थापित करने से उत्पन्न होती है "
7. देश में एकाधिकारियों पर नियन्त्रण करना तथा शोषण को समाप्त करना भी आयोजित अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य हो गए.

सक्षेप में आयोजन के आर्थिक उद्देश्य ये हैं

- (1) प्राकृतिक साधनों का अधिकतम व अनुरूपतम उपयोग.
- (ii) पूर्ण उत्पादन करना
- (iii) अधिक उत्पादकता वृद्धि लाना.
- (iv) पूर्ण रोजगार बढ़ाना
- (v) देश में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए.
- (vi) राष्ट्रीय आय व प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि लाना
- (vii) देश में जन साधारण का जीवन स्तर ऊँचा करना
- (viii) देश में माँग व पूर्ति में संतुलित लाना.

आयोजन

- (ix) धन, धन्य व सम्पत्ति की असमानताओं को दूर करना.
- (x) अधिकतम आर्थिक व सामाजिक उन्नति को एक निश्चित काल में प्राप्त करना
- (xi) देश में औद्योगीकरण का आधार रखकर समुचित विकास लाना
- (xii) पिछड़े वर्ग व दलकों को उन्नत करना.
- (xiii) मजदूरी, लगान, व्याज, लाभ के रूप में राष्ट्रीय आय का व्यापक वितरण करना
- (xiv) एकाधिकारों को तोड़ना व शोषण समाप्त करना.
- (xv) कृषि को उन्नत उद्योग बनाना
- (xvi) देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा देश का सर्वांगीण विकास करना
- (xvii) देश को आत्मनिर्भर व बलशाली बनाना.
- (xviii) देश में सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर को प्राधुनिक व ऊँचा करना.

(b) राजनैतिक व सामाजिक उद्देश्य .

समस्त साम्यवादी देशों में आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना होता है. हिटलर ने देश में आर्थिक आयोजन तो अन्य देशों को आधिपत्य लाने के लिए किया थीं भी प्राधुनिक समय में अपने पड़ोसी देशों को आधिपत्य में लाने या प्रभाव में लाने के लिए आर्थिक आयोजन कर रहा है. हटली में भी फासिस्ट आयोजन का उद्देश्य रोमन साम्राज्य की स्थापना करना था. इस प्रकार का आयोजन वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शस्त्रों की होड़ को जन्म देता है और फिर आर्थिक क्षेत्र में कम साधन प्राप्त होते हैं तथा करो की बहुत अधिकता रहती है

आयोजित व्यवस्था का उद्देश्य देश में अधिकाधिक राज्य संचालित उद्योगों की स्थापना करना होता है

सामाजिक क्षेत्र में आयोजन का उद्देश्य देश में जाति, धर्म, रंग के भेदों को मिटाना है एक संपूर्ण विहीन देश ही आयोजित व्यवस्था का उद्देश्य होता है देश में उन्नत जीवन स्तर की स्थापना होती है. यह जीवन स्तर अधिक दृष्टिकोण से ही उन्नत नहीं होता बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उन्नत होता है.

यह सब कार्य एक निश्चितकाल में किए जाते हैं. कम से कम काल में अधिकाधिक अच्छे आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों का प्राप्त करना ही आयोजन का उद्देश्य होता है.

“आर्थिक आयोजन का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में अधिकाधिक बढ़ाना ही नहीं है बल्कि स्वयं सामाजिक व्यवस्था को भी अनुकूल बनाना है। आयोजित व्यवस्था में कार्य प्राप्त करने का हक, उचित आय कमाने का हक, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने का हक, बीमारी, बुढ़ापा व बेरोजगारी से सुरक्षा पाने का हक देने का उद्देश्य सर्वोपरि रहना है।”

Social Planning : सामाजिक आयोजन :

आर्थिक नियोजन में सामाजिक उन्नति का लक्ष्य होता है। U. N. O. ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक तत्वों को आर्थिक विकास के कार्यक्रम में शामिल करने पर महत्व दिया है। रिपोर्ट के अनुसार

“देश में आर्थिक विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि उस देश के व्यक्ति उसे नहीं चाहेंगे उनमें जब आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक ढाँचे को बदलने की इच्छा बनवती होगी, तब ही आर्थिक विकास होगा। जिस समाज में कार्य के समान अवसर न हों, जिस समाज में प्रशिक्षित, अज्ञानी, रुढ़िवादी, निरुत्साही, जाति-पाँति के बंधनों में जकड़े हुए तथा रीति रिवाजों के गुलाम व्यक्ति रहते हों वहाँ आर्थिक उन्नति संभव नहीं होती।”

विकास पुरानी मान्यताओं को समाप्त करता है। समाज को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति साथ-साथ लाना होगा इसके लिए समाज की रूढ़िभक्ति लेकर चलना होगा

सामाजिक आयोजन में आयोजन का लक्ष्य समाज का अधिकतम कल्याण बढ़ाना होता है इस प्रकार के आयोजन का लक्ष्य केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना ही नहीं है बल्कि उसके उचित व न्यायपूर्ण वितरण का भी लक्ष्य होता है। Proudhon (प्रोथो), Gray (ग्रे), Owen (ओवेन) तथा Marx (मार्क्स) ने इसीलिए सामाजिक आयोजन को आर्थिक आयोजन का अंग नहीं माना बल्कि आर्थिक आयोजन को सामाजिक आयोजन का अंग माना गया है। समाज के लिए आर्थिक नियोजन होता है न कि आर्थिक आयोजन के लिए समाज है

सामाजिक आयोजन का लक्ष्य अधिकतम लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को

See : U. N. O., Measures for Economic Development in Under-developed Countries.

आयोजन

पूरा करना होता है कुछ लोगों की विलासिताओं को पूरा करने में पहले अधिक-तम लोगों को प्रतिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा

Pepalasis (पेपालसिस) ने इसी प्रकार के आयोजन के बारे में लिखा है

"The process of economic development is not restricted to economic change but is essentially a transformation of the human agent and his social environment."

Shri Wadia के अनुसार

"आर्थिक आयोजन उचित सामाजिक वातावरण में ही संभव है। (Economic planning is not done in a social vacuum) केवल आर्थिक साधनों के खर्च करने से ही आयोजन नहीं हो जाता है। भौतिक सत्वों में मानव तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं आयोजन का मुख्य लक्ष्य मानव साधनों का पूर्ण प्रयोग करना होता है."

सामाजिक आयोजन का लक्ष्य देश में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रोजगार में वृद्धि लाना है। धन की सममानताओं को दूर करना चाहिए। सामाजिक आयोजन "शान्ति के युद्ध" पर विजय पाना होता है (अर्थात् गरीबी व शोषण पर विजय पाना होता है)।

III Main Features of Planning : आयोजन की मुख्य विशेषताएँ .

किसी भी देश में आयोजन को निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं

एक निश्चित लक्ष्य

हर देश में आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य हो सकता है। यह लक्ष्य भ्रष्ट-नालम देशों में भ्रष्ट हो सकते हैं। बहुत समतल देशों में यह लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता रखना या बेरोजगारी को रोकना हो सकता है। कम-विकसित देशों में मुख्य लक्ष्य

(i) देश में उत्पादन बढ़ाना

Pepalasis . op. cit.

S S. Wadia : Techniques of Planning.

- (11) देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग.
- (111) देश में उत्पादकता बढ़ाना
- (1V) देश की अतिरिक्त (Surplus) जनशक्ति का प्रयोग करना.
- (V) धन में समानता लाना आदि हो सकता है

कभी-कभी आयोजन के एक से अधिक लक्ष्य हो सकते हैं. फिर कोई एक लक्ष्य मुरप होता है समस्त कार्य फिर उन्ही लक्ष्य के आधार पर किए जाते हैं.

एक केन्द्रीय शक्ति

किसी भी देश में एक केन्द्रीय शक्ति के बगैर आयोजन संभव नहीं होता. अगर केन्द्रीय शक्ति न हो तो अर्थव्यवस्था की इकाइयों (जैसे अलग अलग राज्यों या उद्योगों द्वारा बनाई योजनाओं) में समन्वय नहीं रहेगा. परस्पर विरोधी योजनाएँ भी तैयार हो सकती हैं. केन्द्रीय शक्ति ही साधनों के अनुसार अधिकतम लाभ देने वाली योजना बना सकती है.

यह योजना केन्द्रीय सरकार (सत्ताकण्ड राजनैतिक पार्टी) द्वारा बनाई जा सकती है या सब राजनैतिक पार्टियों के सहयोग से बनाई जा सकती है. तकनीकी विशेषज्ञों की हमेशा सहायता ली जाती है

निजी क्षेत्र भी आयोजन क्षेत्र में

आयोजन का लक्ष्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को ही आयोजनानुसार चलाना नहीं होता. निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी उत्पादन लक्ष्य दे दिए जाते हैं और उनसे उन्हें पूरा करने का कहा जाता है दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं. (Complementary and Supplementary) भिन्न भिन्न उद्योगों को इस प्रकार से बढ़ने दिया जाता है कि एक की वृद्धि दूसरे को भी लाभदायक हो. वे एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं.

प्राथमिक लक्ष्यों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है :

कम-विकसित देशों में साधन तो कम रहते हैं और आवश्यकताएँ अधिक रहती हैं. सही प्राथमिकताओं के निर्धारण से साधनों के प्रयोग में मितव्ययिताएँ होती हैं प्राथमिकताओं के निर्धारण में निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखा जाना है

- (1) कृषि व उद्योगों में समन्वय, कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सर्व-प्रथम लक्ष्य होना चाहिए. इससे उद्योगों को सस्ता व अधिक बच्चा मान मिलता है, देश में मूल्य वृद्धि नहीं हो पानी व समस्त विकास की नींव ठोस पड़ जाती है

- (11) कम-विकसित देशों में विदेशी मुद्रा की अत्यन्त कमी रहती है। इसके लिए आयात-वर्धक व निर्यात कम करने वाले उद्योगों को पनपाना चाहिए। हो सकता है कि आयात-वर्धक उद्योगों के विकास के लिए पहले बहुत सी मशीनें मँगाने से आयात बढ़ें। परन्तु हर देश को उन उद्योगों को प्राथमिकता देना चाहिए जिनसे भुगतान सतुलन सुधरे।
- (111) भौतिक उत्पादन वृद्धि के साधनों (जैसे उद्योग, यातायात, कृषि आदि) तथा अर्थगतिक वृद्धि के साधनों में समुचित प्राथमिकता दी जाती है हम देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व कुशलता वृद्धि को भी ध्यान में रखते हैं।
- (1V) समस्त उद्योगों में कुछ न कुछ आयोजन का प्रभाव अवश्य होना चाहिए। किसी एक उद्योग में ही समस्त साधनों का विनियोजन नहीं किया जाता है। उपभोग उद्योग व भारी उत्पादन उद्योगों को इस प्रकार प्राथमिकताएँ दी जाती हैं कि विकास भी आगे बढ़े तथा जनता की माँगे भी यथासंभव पूरी हो सकें

आर्थिक उत्पादकता के साथ-साथ सामाजिक उत्पादकता वृद्धि—दोनों पर ध्यान रखा जाता है :

योजनायोजित अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक इकाइयों अपने यहाँ वस्तुगत उत्पादकता या आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। कभी-कभी तो यह भी संभव नहीं हो पाता। क्योंकि किसी भी उद्योग में उत्पादन वृद्धि बहुत से अन्य क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि पर निर्भर रहती है। आयोजन में इस प्रकार से समन्वित विकास किया जाता है कि हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े इसके अतिरिक्त सामाजिक उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिक उत्पादकता देश में शिक्षा, ट्रेनिंग व स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास व पूर्ण रोजगार बढ़ाने से बढ़ती है

देश की अल्प व दीर्घकालिक योजनाएँ व आवश्यकताएँ :

आयोजन में 'समय' आयोजन का मुख्य अंग होता है। हर देश एक दीर्घकालीन योजना बनाता है। यह योजना दस या बीस वर्ष की हो सकती है फिर इसको चार-साता या पाँच-साता योजनाओं में बाँट दिया जाता है। फिर हर इस प्रकार की योजना को वार्षिक योजनाओं में बाँट देने है। हर बड़ी योजना के छोटे टुकड़े इसलिए कर दिए जाते हैं कि अगर ऐसा न किया जाये तो योजना के शुरू में काम धीमी गति से होये और बाद के वर्षों में बहुत काम इकट्ठा हो जाएगा इसलिए

आयोजन की यह विशेषता होती है कि इस प्रकार की योजनाओं में देशवासियों की प्रल्प व दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

साधनों का विवेकपूर्ण वितरण :

हर देश में कुछ न कुछ साधन सबधी कमियाँ रहती हैं कहीं प्राकृतिक साधन कम होते हैं तो कहीं पूँजी की कमी रहती है और कहीं दोनों की कमी रहती है आयोजित अर्थव्यवस्था में इनका बँटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि अधिकतम खेती को कम से कम खर्च से अधिकतम लाभ प्राप्त हो।

IV. Types of Planning . आयोजन के प्रकार :

(a) Physical and Financial Planning

Physical Planning भौतिक आयोजन :

आयोजन का लक्ष्य भौतिक वस्तुओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि Financial Planning वित्तीय आयोजन में लक्ष्य वित्तीय व्यय को प्राप्त करना होता है, उदाहरण के रूप में प्रथम प्रकार के आयोजन में राज्य यह निश्चय करता है कि 200 कॉलिज, 2000 मील सड़कें, 8 बाँध, 20 अस्पताल आदि का निर्माण करना है। राज्य तदनुसार आय जुटाता है और व्यय करता है। द्वितीय प्रकार के आयोजन में राज्य के लक्ष्य इस प्रकार से व्यक्त किये जायेंगे, शिक्षा पर 80 लाख रुपया, सड़क निर्माण पर 20 लाख रुपया, सिंचाई पर 100 लाख रुपया व स्वास्थ्य पर 80 लाख रुपया इनके अनुसार खर्च होया

प्रथम प्रकार के आयोजन में लक्ष्यों को "वास्तविक रूप में" (in real terms) में व्यक्त किया जाता है और यह विकास में वृद्धि करता है, द्वितीय व्यवस्था में एक त्रुटि है, अगर मूल्य दुगने बढ़ जायें तो वही 80 लाख रुपये में 200 कॉलिजों के स्थान पर केवल 100 कॉलिज ही स्थापित हो सकेंगे

Physical Planning में लागत व लाभ का ध्यान रखा जाता है।

Financial Planning : वित्तीय आयोजन : इसमें एक निश्चित मात्रा में व्यय करने का लक्ष्य होता है। इस प्रकार के आयोजन का महत्व मुद्रा विस्फीति या मंदी काल में होता है जबकि बाजार में एक निश्चित मात्रा में खर्च करने की आवश्यकता होती है।

पर दोनों प्रकार के आयोजन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, साधनों की कमी से कभी-कभी भौतिक लक्ष्यों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। या कभी कभी

कुछ भौतिक लक्ष्यों का प्राप्त करना इतना आवश्यक हो सकता है कि उनके अनुसार साधनों की व्यवस्था करना पड़ सकती है, दोनों प्रकार का आयोजन एक दूसरे का पूरक है, विरोधाभासी नहीं, कम-विकसित देशों में सार्वजनिक पद्धति व प्रशासन के पूर्ण रूप से उन्नत न होने के कारण बहुधा दोनों प्रकार के लक्ष्यों में समन्वय नहीं आ पाता इस कारण आयोजन में बाधाएँ आती हैं व असफलताएँ हाथ लगती हैं

भारत ने तो लक्ष्यों को Global आधार पर (सम्पूर्ण क्षेत्रों में) इस प्रकार निर्धारित किया कि बाद में उनकी लागतें बढ़ती गईं और उनके वित्तीय लक्ष्य अक्सर बढ़ते गये और मुद्रा स्फीति पैदा हुई.

(b) Structural Planning and Functional Planning :

Revolutionary Planning and Evolutionary Planning.

Structural Planning : संरचनात्मक आयोजन :

समाज का आर्थिक व सामाजिक ढाँचा हो बदल दिया जाता है और नए आर्थिक व सामाजिक ढाँचे का निर्माण होता है इस प्रकार के आयोजन में थोड़े बहुत सुधारात्मक कार्य ही नहीं किए जाते हैं, बरन् सम्पूर्ण नया समाज उत्पन्न कर दिया जाता है इस प्रकार के आयोजन में रचनात्मक कार्य के साथ साथ पुरानी पद्धतियों, पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाता है. समाजवादी देशों में इसी प्रकार का आयोजन होता है. इस कारण हम इस प्रकार के आयोजन को क्रान्तिकारी आयोजन या Revolutionary Planning भी कहते हैं

Functional Planning : क्रियात्मक आयोजन :

वर्तमान आर्थिक ढाँचे व सामाजिक व्यवस्था को कायम रखा जाता है और जो कुछ कमियाँ होती हैं उन्हीं में सुधार कर दिया जाता है. यह Evolutionary Planning हुआ.

इस संबंध में एक बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि कालांतर से Structural Planning, Functional Planning में परिणत हो जाती है. जैसे रूस या चीन में जब आयोजन शुरू हुआ तो वहाँ के आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक ढाँचे को उखाड़ फेंका गया और फिर उसमें आयोजन किया गया पर एक बार जब समाजवाद स्थापित हो गया तो फिर कोई क्रान्तिकारी परिवर्तनों की गुंजाइश या सम्भावनाएँ ही नहीं रही और आयोजन Functional हो गया.

दूसरी ओर Functional Planning में धीरे-धीरे आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन हो जाता है और धीरे-धीरे सुधार से नयी आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। सारांश में पहले प्रकार के आयोजन में नए समाज को शीघ्रानिश्चिन्त लाया जाता है, तो दूसरे प्रकार के आयोजन में केवल सुधार किए जाते हैं पर धीरे-धीरे यही सुधार समाज बदल देता है। आज के कम-विकसित देशों में समाज व आर्थिक व्यवस्था को बहुत बदलने की आवश्यकता है अगर यह क्रान्तिकारी तरीकों से नहीं बदला जा सकता है तो कम से कम काल में यह परिवर्तन लाने होंगे भारत की प्रथम योजना में वर्तमान व्यवस्था को एकदम बदलने की बात नहीं की गई है वरन् धीरे-धीरे परिवर्तन की बात कही गई है।

(c) Corrective and Development Planning : सुधारात्मक व विकास के लिए आयोजन :

Corrective Planning or Emergency Planning, or Preventive Planning or Restorative Planning

विकसित देशों में, विशेष रूप में पूँजीवादी देशों में, सुधारात्मक आयोजन ही किया जाता है। जब ऐसा देश विकास के रास्ते से हट जाता है या मदी का शिकार हो जाता है तो मदी लाने वाले तत्वों को 'सुधारात्मक आयोजन' से दूर कर दिया जाता है। 1930 की महान विश्व मदी के बाद आज पूरी अर्थव्यवस्था को काफी मात्रा में निर्देशन दिया जाता है आज बाजार मूल्यों तथा मजदूरी की दरों को नियमित व नियंत्रित किया जाने लगा है। आज समस्त विकसित देशों में 'बेरोजगारी' को दूर करना आयोजन का लक्ष्य बन गया है आज ऐसे विकसित देशों में भी जो अनियोजित व्यवस्था के उदाहरण रहे। उपरोक्त प्रकार का सुधारात्मक आयोजन अर्थव्यवस्था का अंग बन गए हैं।

परन्तु सुधारात्मक आयोजन में राज्य अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करता। इस प्रकार के आयोजन में राज्य निजी उत्पादकों व विनियोजकों को सहायता देता है, निर्देशन देता है और आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण करता है इसका मुख्य लक्ष्य देश में 'आर्थिक अस्थिरता' दूर करना है।

मुद्रा स्फीति (महंगाई) के काल में राज्य बचत के बजट बनाती है (खर्च कम, आमदनी ज्यादा) जिससे बाजार का अधिक पैसा खिंच आये व मूल्य गिरे। इस काल में व्याज की दरों, मूल्यों, मजदूरी की दरों व सट्टे को नियंत्रित किया जाता है साथ ही साथ अधिक उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने की सुविधाएँ दी जाती हैं

मन्दो काल में घाटे का बजट प्रस्तुत करके (खर्च अधिक आमदनी कम) नए नोट छाप कर बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है इस अतिरिक्त मुद्रा से राज्य राहत व विकास कार्य हाथ में लेता है. इसी काल में राज्य सामाजिक सुरक्षा के लाभों को बढ़ाता है. करों में कमी करता है तथा बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख्त बढ़ाने की सुविधायें देता है

इस प्रकार के आयोजन में जैसे ही अस्थिरता का भय दूर होता है. आयोजन बन्द हो जाता है, इस प्रकार का आयोजन एक राजनैतिकवाद पर निर्धारित नहीं होता यह बरु विरोधी नीति का अंग होता है.

Development planning : विकास के लिए आयोजन :

कम-विकसित देशों में आयोजन का लक्ष्य केवल आर्थिक व्यवस्था में थोड़े बहुत सुधार करना नहीं होता, बरन् समस्त आर्थिक व्यवस्था का जीर्णोद्धार करना पड़ता है. इस कारण "विकास के लिए किए जाना वाला आयोजन सुधारात्मक आयोजन से अधिक जटिल, कठिन व महत्वपूर्ण होता है. इस प्रकार के आयोजन में आर्थिक ढाँचे के साथ-साथ सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनीय और कानूनी ढाँचों को भी बदलना पड़ता है. इस प्रकार के आयोजन में सुधारात्मक आयोजन से कई लक्ष्य भिन्न होते हैं, उदाहरणतया जबकि सुधारात्मक आयोजन में आय की असमानताओं को कम करने पर जोर दिया जाता है. "विकास के लिए" आयोजन में असमानताओं को दूर करने से पूर्णोपतियों द्वारा किए जाने वाला पूँजी-निर्माण रुक जाएगा और देश में उत्पादन व रोजगार स्तर गिर जाएँगे "विकास के लिए आयोजन" में "समृद्धि में समानता" लाना चाहते हैं कि "गरीबी में समानता" लाना चाहते हैं.

"विकास के आयोजन" में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाँच कदम उठाए जाते हैं :

- (i) सर्वप्रथम हमें देश के प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण करना पड़ेगा और फिर उनके प्रयोग करने के लिए साधन का अनुमान लगाना पड़ता है.
- (ii) इसके बाद यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन से प्राकृतिक साधनों का प्रयोग पहले हो और कौन से साधनों का प्रयोग बाद में हो.
- (iii) इसके पश्चात् पूरे देश का एक बृहत् और दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है फिर देश के भागों की छोटी-छोटी व अल्पकालीन योजनाओं को बनाया जाता है
- (iv) इसके बाद इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है.

(v) कार्यान्वित करने में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना जिसमें योजना लचीली रहे

‘विकास के आयोजन’ में कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश के व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सबका विकास किया जाता है. देश में रोजगार, धाय, प्रति व्यक्ति आय आदि के स्तर को उन्नत किया जाता है, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विनियोजन में वृद्धि की जाती है. देश में बचते व पूँजी-निर्माण बढ़ाया जाता है. देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम प्रयोग करके उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाई जाती है तथा माँग और पूर्ति में असमन्वय लाया जाता है.

(d) Planning by Inducement and Planning by Direction'
आर्थिक प्रोत्साहन देकर आयोजन तथा निर्देशन देकर आयोजन

Planning by Inducement or Democratic Planning :
प्रोत्साहन मूलक या प्रजातन्त्रीय नियोजन :

पहले तो यह माना जाता था कि अगर आयोजन है तो प्रजातन्त्र नहीं रहता, पर अब ऐसा नहीं माना जाता इस प्रकार के आयोजन में निजी सम्पत्ति को समाप्त नहीं किया जाता है. सरकारी व निजी क्षेत्र के कारखाने व व्यापारिक संस्थान साथ-साथ चलते हैं देश की योजना किसी एक राजनैतिक दल द्वारा नहीं बनाई जाती है बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा तकनीकी व्यक्तियों की सलाह से बनाई जाती है किसी प्रकार के ‘दबाव’ के स्थान पर ‘समझने’ की पद्धति से कार्य लिया जाता है.

निजी क्षेत्र के उद्योगों को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थिति में कुछ उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जा सकता है राज्य देश की विनियोजन की मात्रा व क्षेत्रों को अपनी मौद्रिक व राजकोपीय नीति से प्रभावित करता है अर्थात् जिस क्षेत्र में राज्य विनियोजन की मात्रा बढ़वाना चाहता है उसे अधिक धन उधार दिला सकता है या कर सम्बन्धी छूट दे देता है

ल्युस (Lewis) ने इस प्रकार के आयोजन का उदाहरण दिया है. जैसे अगर राज्य चाहता है कि देश के बच्चे रोज एक निश्चित मात्रा में दूध का प्रयोग करें. राज्य इससे लिए या तो दूध के उत्पादनकर्ताओं को कर से मुक्त कर सकता है या दूध को सस्ते दामों पर विक्रय सकता है और दूध के उत्पादनकर्ताओं को कुछ धन अपने पास से दे सकता है.

Lewis इस प्रकार के आयोजन को निर्देशन के द्वारा संचालित आयोजन में

अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. वे चाहते हैं कि यथा सम्भव स्वतन्त्र बाजार प्रणाली को अपनाये रहकर भी आयोजन होना चाहिए.

कम-विकसित देशों में उत्पादन कम होता है जिससे मूल्य अधिक रहते हैं. देश में उत्पादन के अंग गतिशील कम होते हैं. बहुधा सरकार ऐसे समय में राशनिंग या कंट्रोल करती है और मूल्य नियंत्रण करती है, पर अच्छा यह हो कि राज्य की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाए. Lewis का कथन है

“आयोजन की सफलता उत्तम राशनिंग पद्धति और कठोर मूल्य नियंत्रण से नहीं आती जाती, बल्कि इस बात से आती जाती है कि कितने शीघ्र इस न्यूनता को समाप्त करके राशनिंग व मूल्य नियंत्रण को अनावश्यक कर दिया जाए.”

हम सबको विदित है कि लिंकन ने प्रजातन्त्र की परिभाषा यह दी थी

‘ प्रजातन्त्र में राज्य सरकार जनता द्वारा स्थापित, जनता के लाभ के लिए जनता के द्वारा गठित होती है’ उसी प्रकार से इस प्रकार का आयोजन भी “Planning by the people, for the people and of the people” कह सकते हैं. इस प्रकार के आयोजन में राज्य जनता पर हावी नहीं होता. जनता राज्य के आयोजन की आलोचना कर सकती है आयोजन में जनता सहयोग भी करती है इस प्रकार के आयोजन को इसीलिए Planning from the bottom अर्थात् आधार से या नीचे से आयोजन कहते हैं.”

परन्तु इस प्रकार का आयोजन वहाँ सफल होता है जहाँ के देशवासी शिक्षित, समझदार व अनुशासित होते हैं फ्रांस में इस प्रकार का आयोजन इसी कारण सफल रहा. इस प्रकार के आयोजन की सफलता एक तो इस बात पर निर्भर करती है कि निजी क्षेत्र के उद्योग सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर समाज का अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करे और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग मुक्त रूप से कार्य करें अर्थात् घाटे में न चले

प्रजातान्त्रिक आयोजन की सबसे बड़ी समस्या समन्वय की होती है आयोजन में भिन्न-भिन्न योजनाएँ इस प्रकार से अलाई जाना चाहिए कि वे एक दूसरे की प्रतियोगी होने के स्थान पर पूरक हों. (They should supplement each other, not supplant each other).

बहुधा प्रजातन्त्र व स्वतन्त्रता के नाग पर इन प्रकार के आयोजन के सफल होने की राह में रुकावटें डाल दी जाती हैं.

(e) **Planning by Direction** : निर्देशन से आयोजन or **Planning by Central Authority** : केन्द्रीय सत्ता के द्वारा आयोजन or **Socialist Planning** समाजवादी आयोजन or **Authoritarian Planning** शासकीय आयोजन or **Fascist Planning** फासिस्ट आयोजन :

इस प्रकार के आयोजन में उत्पादन के समस्त अंगों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है निजी क्षेत्र के पास सम्पत्ति नहीं छोड़ी जाती या बहुत थोड़ी मात्रा में छोड़ी जाती है वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण राज्य के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इस प्रकार का आयोजन कठोर होता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जैसी कि प्रजातन्त्र देशों में होती है या तो समाप्त हो जाती है या नाम मात्र रह जाती है, धमोचना करने से दंड के भागी हो सकते हैं। एक केन्द्रीय आयोजन समिति योजना के लक्ष्य निर्धारित करती है जिनको एक निश्चित काल में पूरा करना होता है। देश के इस प्रकार में औद्योगीकरण करने पर बल दिया जाता है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए अनुचित राष्ट्रीय भावना का जन्म होता है

देश में बचत की मात्रा कितनी होना चाहिए यह राज्य निर्धारित करता है यह बचतें या तो अनिवार्य रूप में वेतन में से काट ली जाती हैं या फिर उत्पादन करों के रूप में ले ली जाती हैं। कभी-कभी तो इससे जनता को महान् कष्ट हो जाता है

इस प्रकार के आयोजन में देश की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था ही कठोर होती है, जनता उपभोग कम करके या जो बचत करते हैं वे उज्ज्वल भविष्य की आशा में ऐसा करते हैं। बहुधा उनके सामने कोई और विकल्प भी नहीं होता। इस प्रकार के आयोजन में निजी लाभ, व्यापारिक ध्यात्र व लगान समाप्त हो जाते हैं। देश के आर्थिक कार्यों से जो लाभ होते हैं वे राज्य को प्राप्त होते हैं और इनमें से प्रशासनिक व्ययों को निकाल कर जो बचता है उससे पूंजी निर्माण होता है और इसके लाभ जनता को ही बाँट दिए जाते हैं।

Dickenson **डिकिन्सन** व **Pigou** पोगू इस प्रकार के **Authoritative** आयोजन को उत्तम आयोजन पद्धति मानते हैं। क्योंकि इसमें समस्त साधनों पर पूर्ण अधिकार होता है, लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं तथा कार्यान्वित करने में समन्वय की कमी नहीं रहती

Darbin भी इस प्रकार के आयोजन को उत्तम मानते हैं।

पर इस प्रकार के आयोजन में हर चीज राज्य की आज्ञा में होती है। हम तुम

के दूध वाले उदाहरण को यहाँ भी ले सकते हैं इस प्रकार के आयोजन में अगर राज्य बच्चों को एक निश्चित मात्रा में दूध का सेवन कराना ही चाहता है तो वह अनिवार्य रूप से ऐसा निम्नलिखित किसी भी युक्ति द्वारा कर सकता है .

- (1) राज्य स्कूलों में अनिवार्य रूप से दूध बटवाए
- (11) अन्ध बच्चों के बाई वना दिए जाएँ और उन्हें रोज दूध लेना पड़े.
- (111) स्वयं दूध की उत्पादन वृद्धि अपने हाथ में ले और उस दिशा में कार्य करे.

त्युस में इस प्रकार के आयोजन में बहुत सा बुराडयाँ बताई है जो इस प्रकार है .

- (1) इस प्रकार के आयोजन में रोजगार बचन राज्य करता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेशे की चुनने की उन्मुक्त स्वतन्त्रता नहीं होती पर यह आलोचना निर्मूल है मही अर्थ में तो पूँजीवाद में यह स्वतन्त्रता नहीं होती. वहाँ इतनी बेरोजगारी होती है कि जिसको जो कार्य मिल गया उसको वही करते रहना पड़ता है. समाजवाद में हर व्यक्ति को रोजगार, मौलिक अधिकार के रूप में, प्राप्त होता है. राज्य अपनी आवश्यकतानुसार लोगों को शिक्षा व ट्रेनिंग देती है.
- (11) यह आयोजन प्रणाली कठोर होती व लोचदार नहीं होती है इसमें लक्ष्यों में शीघ्र परिवर्तन नहीं होता.
- (111) आयोजन के कार्यान्वित करने में अक्सर समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं उदाहरण के तौर पर आयोजित हर उद्योग को कोयले का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है. परन्तु अगर मौसम की खराबी, हड़ताल अथवा किसी भी कारण से कोयले का उत्पादन कम हुआ तो भिन्न भिन्न कारखानों के लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते. इनको पेट्रोल भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि पेट्रोल का भी तो पूर्ण वितरण (allocation) पहले से हो चुका होता है पूँजीवादी आयोजन में कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं और बढ़े हुए मूल्यों पर माग में कमी आती है और माग व पूर्ण का नया साम्य उत्पन्न हो जाता है, पर इन दोषों को भी बढ़ाचढ़ाकर बताया गया है. असाधारण परिस्थिति में लक्ष्य भी दुहरा लिए जाते हैं और संचित स्टॉक में कमियाँ पूरी की जाती हैं
- (1V) त्युस के अनुसार ऐसे आयोजन वाले देशों में अर्थशास्त्रियों की भरमार हो जाती है. इस में 10 लाख से अधिक इस प्रकार के अर्थशास्त्री हैं.

V. Conditions for Successful Planning . आयोजन की सफलता के आवश्यक तत्व

- 1 किसी भी देश में आयोजन शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आवश्यकता आयोजन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न आर्थिक क्षेत्रों के "सही और विस्तृत आंकड़े प्राप्त करना" होता है जैसे जनसंख्या के स्तर तथा बढ़ने सम्बन्धी आंकड़े व देश में बचत, पूँजी निर्माण, उत्पादन, उत्पादकता विनियोग, रोजगार, बेरोजगार, लागत और उत्पात आदि के आंकड़े जानें बिना योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित होता असम्भव है इसलिए सही और व्यापक सर्वेक्षण करना व सांख्यिकीय विभाग खोलना आवश्यक हो जाता है
- 2 देश में "आयोजन के चार पद" होने हैं
 - (I) योजना बनाना.
 - (II) योजना स्वीकार करना
 - (III) योजना कार्यान्वित करना.
 - (IV) योजना का मूल्यांकन करना

जुईग (Zweig) के अनुसार योजना को विकेन्द्रित रूप से तैयार करना चाहिए पर उसकी स्वीकृति केन्द्र से होना चाहिए उसको कार्यान्वित करना और मूल्यांकन करना विकेन्द्रित रूप से होना चाहिए. योजना को बनाने का कार्य और मूल्यांकन का कार्य मुख्य रूप में विशेषज्ञों को करना चाहिए. उसकी स्वीकृति का नाम पार्लियामेन्ट अर्थात् राजनैतिक स्तर पर करना चाहिए और उसका संचालन प्रशासनीय अफसरों द्वारा करना चाहिए. एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए
3. सफल आयोजन के लिये लक्ष्यो का सही चयन होना चाहिए अर्थात् विचार-पूर्ण आयोजन होना चाहिए यह लक्ष्य देश की युद्ध में तात्कालिक या रोजगार में वृद्धि करना या दीर्घकालीन उन्नति की ओर ले जाना आदि कुछ भी हो सकता है
- 4 अगर लक्ष्य बहुत है और स्पष्ट रूप है, जैसा कि अधिकांश देशों में होता है तो उनकी प्राथमिकता निश्चित करना चाहिए, अगर बहुत से लक्ष्य एक साथ चुन लिए गये तो इससे देश के आर्थिक साधनों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और जनता में असंतोष बढ़ेगा. उदाहरण के लिए भारत ने अपने लक्ष्यों को बहुत ऊँचा रखा और परिणाम स्वरूप जनता के सामने लक्ष्य पूर्ण न होने का दृश्य सामने आया जबकि पाकिस्तान ने अपने लक्ष्यों को नीचा रखकर उनसे

अधिक कार्य किया और उससे जनता के सामने सफल आयोजन का दृश्य प्रस्तुत किया आयोजन को कभी भी अत्यधिक आशावादी नहीं होना चाहिए

- 5 “देश में मजबूत, कुशल, उत्साही तथा ईमानदार राजनीतिज्ञ तथा सरकार होना चाहिए” युद्ध काल में जुर्ग के अनुसार प्रजातन्त्र में आयोजन सफल होता है जिसका मुख्य कारण उस समय सरकार का शक्तिशाली होना होता है लेकिन जुर्ग का यह भी कथन है कि सरकार की यह शक्ति भौतिकरूप में नहीं की जानी चाहिए बल्कि नैतिक रूप में सरकार को शक्तिशाली होना चाहिए अर्थात् सरकार को कुशल व ईमानदार होना चाहिए जिससे जनता का विश्वास हो इस में आयोजन के सफल होने का कारण वहाँ राज्य का शक्तिशाली होना या व फ्रांस में Blum-experiment व अमेरिका में New Deal के असफल होने का कारण सरकार का कमजोर होना था
- 6 सफल आयोजन के लिए “प्रलोभन” अनिवार्य है यह प्रलोभन आर्थिक और अनार्थिक दोनों हो सकते हैं आर्थिक प्रलोभन का अर्थ होता है कि देश में ऐसी व्यवस्था हो कि कुशल उत्पादनकर्ता को उचित पारितोषिक मिले और अकुशल को उचित दण्ड अनार्थिक प्रलोभन का अर्थ होता है कि ऐसे प्रलोभन जैसे यश या इज्जत, भंडार अथवा पदवी प्रदान की जाय, जैसे, रूस में Stakhanovist आन्दोलन अथवा भारत में कृषि परिदूत व श्रमवीर प्रादि
7. जनता का सहयोग देश के आयोजन के लिए प्रचार व्यवस्था कुशल व व्यापक होना चाहिए जनता का सहयोग आयोजन रूपी मशीन चलाने के लिए तेल व पेट्रोल दोनों का काम करता है, भारत में आयोजन शुरू होने के काल में जनता का काफी सहयोग था परन्तु बाद में राजनीतिज्ञों और प्रशासनीय भ्रष्टाचार के कारण वह उसाह अब नहीं दिखता है आयोजन कितना भी वैज्ञानिक क्यों न हो, अब तक देश के नेताओं में सम्पूर्ण देश को जाग्रत करने और कार्य का उत्साह भरने की शक्ति नहीं होगी आयोजन सफल नहीं होगा.
8. जनता के सहयोग के लिए यह जरूरी होता है कि आयोजन में “उचित समानता” पाई जाय अन्यथा गरीब लोगों में कोई उत्साह नहीं रहेगा। परन्तु बहुत अधिक समानता से पूंजी-निर्माण रुक जायगा Oscar Lange के अनुसार आयोजन में निजी क्षेत्र की शोषण शक्ति समाप्त होनी चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कुशलता व लाभ सहित कार्य करना चाहिए.

9. आयोजन की एक खास बात यह होनी चाहिए कि Richard S. Euckas के अनुसार "आयोजन की एक योजना नहीं होना चाहिए" बल्कि उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक से अधिक योजनाएँ होना चाहिए. जैसे भोजन करने के लिये एक से अधिक भोज्य-पदार्थ होते हैं दुर्भाग्य से कम-विकसित देशों में एक ही योजना बनाई जाती है और उसमें सुधार और संशोधन भी बहुत कम होते हैं इकाम का कथन है कि कोई भी देश हमेशा समस्त आर्थिक घटकों के बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता और कही न कही गलती अवश्य होगी इसलिए आयोजन में लोच होना चाहिए.
- 10 जहाँ तक समब हो छोटा "आयोजन क्षेत्र" होना चाहिये अर्थात् बहुत विस्तार में नहीं होना चाहिए जितना अधिक आयोजन का विस्तार होगा उतना ही उसकी सफलता को कम आशा है।
- 11 समस्त आयोजन में "समय का महत्व" है और इसलिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों को अलग-अलग रखना चाहिये

H. W. Singer on conditions for successful planning :

हेन्स सिंगर ने सफल आयोजन के कुछ अलग ही अन्वेष सिद्धान्त बताए हैं जिनका सार नीचे दिया जा रहा है

1. बचतों में वृद्धि कर पूँजी-निर्माण करना :

विकास की किसी भी योजना को बनाने व कार्यान्वित करने से पहले उतनी मात्रा में पूँजी आवश्यकता को धक्का पड़ेगा देश में किस तकनीक को अपनाया जाएगा तथा देश में ICOR (Incremental capital output ratio) क्या है ? इसके आधार पर पूँजी की आवश्यकता आँकी जा सकती है. तदनुसार बचतों को बढ़ाकर तथा अन्य रीतियों से पूँजी-निर्माण किया जाना चाहिए

- 2 The principle of cumulation : संचयिता का सिद्धान्त :

इसके बाद योजनाएँ (projects) का चयन करना चाहिए जिनसे एक से

आयोजन की सफलता के लिए प्रमुख आर्थिक नीतियाँ अन्वी होना चाहिए, अर्थात् देश में (1) उचित कृषि नीति, (II) प्राकृतिक साधनों के उपयोग नीति (III) पूँजी निर्माण नीति . जिनका उल्लेख इस पुस्तक में किया जा चुका है, होना चाहिए.

भिन्न-भिन्न प्रमुख नीतियों का संचित सारांश लिखा जाना चाहिए.

1. पूँजी निर्माण सम्बन्धी अध्याय देखिए.

अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो, जैसे सर्वप्रथम Multipurpose river valley projects बहुउद्देश्यीय नदीघाटी योजनाएँ हाथ में ली जा सकती हैं। इन योजनाओं के हर पहलुओं को पहले से योजनाबद्ध कर लेना चाहिए तथा उनको समन्वित रूप से कार्यान्वित करना चाहिए।

3. Co-ordination between public and private projects : निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में समन्वय :

कम-विकसित देशों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्याप्त समन्वय नहीं होता। बहुधा दोनों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। हर क्षेत्र को उन कार्यों को हाथ में लेना चाहिये जिनके लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त हो। देश में प्राथमिक सामाजिक सिरोपरि सुविधाओं की योजनाएँ राज्य ही को हाथ में लेना चाहिए देश में आय सृजन करनेवाले (जैसे बिजली उत्पादन) तथा आय को उपयोग करनेवाले (जैसे अस्पतालों) क्षेत्रों में समन्वय होना चाहिए

4. Research and importance of timing अनुसंधान तथा समय का महत्व *

देश में हर चीज पर्याप्त व व्यापक अनुसंधान के बाद होनी चाहिए जैसे कृषि के विभाग के आयोजन को करने से पहले भिन्न-भिन्न किस्म की भूमियों की मिट्टी का सर्वेक्षण व बिचाई व कीटनाशक दवाइयों की जरूरत का अन्दाज लगा लेना चाहिए उसी प्रकार से साख, बीज आदि का प्रावधान भी कर लेना चाहिए अनुसंधान के बगैर गलतियाँ हो जाती हैं श्री सिंगर के शब्दों में

“Probably one of the most common sources of mistakes in economic development programming has been to wait too long without having a programme at all and then, having drawn up a programme, to rush it through without sufficient research. Great mistakes are made and large sums of money wasted by not allowing a year or two for research after the

outline of the plan has been prepared. The important thing is to be patient at the right time and impatient at the right time."

हर योजना की लाभ-नागती का अनुमान सगा लेना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हर योजना को साधनों का मृजन करना चाहिए.

5 Dispersal vrs. Centralisation विवेन्द्रित आयोजन वा केन्द्रित आयोजन¹.

सिंगर के अनुसार विकास के लिए आयोजन "असतुलित विकास पद्धति" के आधार पर होता चाहिए उनका कथन है कि यह बात सही है कि विकास की आवश्यकता उन्ही क्षेत्रों में अधिक होती है जो पिछड़े हुए होते हैं. परन्तु इन क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक सिरोपरि सुविधाओं के न होने से इस प्रकार से विकास महेगा पड़ेगा पहले उन्नत क्षेत्रों में विकास करके साधनों का सृजन करना चाहिए और फिर पिछड़े क्षेत्रों में नियोजन करना चाहिए

6 Allocation of resources साधनों का आवटन :

Singer के अनुसार

"Resources are horses and projects are carts, and it does not make sense to put the cart before the horse."

नियोजन के शुरू में साधनों के अनुसार योजना बनाना चाहिए एक साध कई योजनाओं को हाथ में नही लेना चाहिए आयोजन आवश्यकताओं के आधार के स्थान पर साधनों के आधार पर बनाना चाहिए. साधनों को अधिकतम लाभ के आधार पर आवटित करना चाहिए.

7. Inflation to be avoided मुद्रास्फीति नहीं होना चाहिए :

विकास की वही योजना अच्छी होगी जिसमें मुद्रा स्फीति बिल्कुल न फैले. सिंगर का कथन है कि मुद्रा स्फीति से तो कभी भी विकास आयोजन को नही चलाना चाहिए. केवल मौद्रिक पूति बढा देने से नकनीक व शिचा का विकास तो नही हो सकता उनका कथन है

"In under-developed countries the trouble is not insufficiency of monetary demand In un-

op. cit : p. 95.

1. आप Balanced vrs. unbalanced growth के अध्याय ५ पढ चुके हैं.

der-developed countries, production is limited by technical factors, by absence of capital, by absence of skills, by the absence of raw materials, by the absence of public servants and by the absence of the machinery and you cannot cure these physical deficiencies by monetary devices”¹ (p. 99)

आगे उन्होंने एक और महत्वपूर्ण लाइन लिखी है

“Finance can never make possible what is physically impossible.”

8. Every project to be self-liquidating or atleast not yielding losses

हर आयोजन कार्य को अपनी लागत अपने लाभ से निवाल लेना चाहिए. अगर ऐसा न हो सके तो कम से कम हानि तो नहीं होना चाहिए. परन्तु समस्त उद्योग लाभ पर नहीं चल सकते बिजली उद्योग का लाभ पर चलाने के लिए अगर बिजली की दर अधिक रखी गई तो अन्य उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी. इसलिए यह भी देखा जा सकता है कि एक उद्योग के हानि से चलने से क्या बहुत से अन्य उद्योग लाभ पर चल सकते हैं.

9. Flexibility लोचकता :

आयोजन हमेशा लोचदार होना चाहिए. हमको मध्यों का गुलाम होकर हो नहीं रह जाना चाहिए आवश्यकतानुसार तथ्यों को ध्यान में रखकर योजना को कार्यान्वित करने की रीति को बदला या सुधारा जाना चाहिए

VI. Planned Vs. Unplanned Growth : आयोजित व अनायोजित अर्थव्यवस्था :

अनायोजित अर्थव्यवस्था :

Prof. Hayek (Road to Serfdom) :

प्रो. हाएक आयोजन के पूर्ण विरोधी हैं उनके अनुसार आयोजित अर्थव्यवस्था 'गुलामी की सड़क' पर ले जाती है. उनका विश्वास है कि जैसे जैसे आयोजित व्यवस्था समाज में बढ़ेगी वैसे धीमे देश में 'जुन्न के राज्य' की स्थापना होगी.

1. हम उनके इस मत से असहमत हो सकते हैं. अल्पकाल में व उचित मात्रा में मुद्रा स्फीति से लाभान्वित हो सकते हैं.

उनका कथन है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता नहीं है तो राजनैतिक स्वतन्त्रता भी नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति को जब अपना व्यवसाय चुनने व सम्पत्ति बनाने की स्वतन्त्रता होगी तब ही आर्थिक व राजनैतिक स्वतन्त्रता होती है और आयोजित व्यवस्था में यह स्वतन्त्रता नहीं होती।

परन्तु प्रो. हाएक पूर्ण अहस्तक्षेप नीति के समर्थक नहीं हैं वे राज्य द्वारा एकाधिकार पर नियंत्रण को बुरा नहीं समझते। वे यह भी नहीं कहते कि राज्य अपने देश में आर्थिक रूप में ताकतवर लोगो द्वारा कमजोरों का शोषण होने दे।

वे तो *planning by direction* के खिलाफ हैं उनका विश्वास था कि इस प्रकार के आयोजन में तानाशाही का जन्म होगा। योजना एक केन्द्रीय शासन द्वारा बनाई जाएगी इस प्रकार की योजना कभी सभी वर्गों को सतुष्ट नहीं कर सकेगी ऐसी व्यवस्था में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था समाप्त हो जायेगी थॉलियामेंट, ऐसी व्यवस्था में, केवल "वतियाने वाले घर" रह जायेंगे

ऐसी व्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता नष्ट हो जाएगी। जनता को वह उपभोग करना पड़ेगा जो राज्य पैदा करता है। उपभोक्ताओं की मांग व रुचि को देखकर उत्पादन करने की पद्धति समाप्त हो जायेगी। इसी प्रकार से व्यक्तियों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता भी नहीं रहेगी।

प्रजातन्त्र के प्रक्रियावादियों के रूप में बुरे से बुरे लोग शक्ति हथिया लेते हैं ऐसी व्यवस्था में राज्य जनता को दवाने के लिए *Concentration camps* (जहाँ हिटलर यहूदियों को बन्द कर यातनाएँ देता था) तथा *Torture chambers* (जहाँ कैदियों को यातनाएँ दी जाती थी) की स्थापना करता है देश में हिंसा की अग्नि भड़क उठती है और ऐसे समाज में अन्न में हिंसा का सहारा लेकर ही सब कार्य कराए जाते हैं जनता को दवाव व धोखे से कुछ मन्थनाओं का गुलाम बना दिया जाता है और उनके स्वतन्त्र चिन्तन कार्य करने की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया जाता है।

अन्त में देश में नैतिकता का नाम नहीं रहना निजी स्वतन्त्रता समाप्त होने के बाद राज्य की बागडोर *gangsters* (गुंडों) व *Sadists* (विकृत प्रवृत्ति) के हाथों में चली जाती है

हाएक ने कहा :

"यह सर्वथा वास्तविक है कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करें, पर समाज पर विजय पाने से हमारी सभ्यता का नाश होगा सामाजिक उन्नति रुकेगी और तानाशाही का जन्म मिलेगा "

Walter Lipmann आयोजित व्यवस्था के खिलाफ हैं उनका कथन है कि :

“इससे देश की विभिन्नता नष्ट होती है स्वतन्त्र समाज में हम शासक वर्ग की आलोचना कर सकते हैं और स्वयं विरोध करना सवैधानिक कार्य है, जबकि आयोजित व्यवस्था में यह देशद्रोह समझा जाता है. आयोजित व्यवस्था में लोगों को इच्छानुसार योजना को नहीं बनाया जाता, बल्कि योजना के अनुसार लोगों की विचारधारा को बनाया जाता है”

John Jewkes का कथन है

“आयोजित अर्थव्यवस्था में पूरे समाज पर आतंक छा जाता है. जनता की स्वतन्त्रता प्रभुरक्षित हो जाती है और विकृत मनोवृत्ति की यातनाएं दी जाती हैं कला दुर्बल होती है, मानवता कम होती है तथा दयाभाव समाप्त हो जाता है”

Von Mises आयोजित पद्धति के विरोधी हैं. उनका कथन है कि .

“आयोजित प्रणाली में स्वेच्छाचारी रूप में बजट बनता है. स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में मूल्यों के द्वारा ही माप व पूर्ति में साम्य होता है वे अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाले Lever (इण्ड) हैं. (अगर किसी देश में किसी वस्तु की पूर्ति कम है तो मूल्य बढ़ जाते हैं इसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो माग कम होती है और दूसरी ओर पूर्ति बढ़ा दी जाती है, और सतुलन पैदा हो जाता है) आयोजित अर्थ व्यवस्था में जब मूल्यों की स्वतन्त्र पद्धति छोड़ दी जाती है तो फिर आयोजक स्वेच्छाचारी निर्णय लेते जो बहुधा गलत होते हैं और फिर बार बार ठीक करना पड़ता है और इससे केवल गड़बड़ ही फैलती है”

Weber का कथन है :

“आयोजित अर्थव्यवस्था में जो साम्य होता है वह अस्वाभाविक व कृत्रिम होता है इसलिए अनुचित होता है.”

Robbins का कथन है :

“जब एक देश में आयोजित व्यवस्था स्थापित होती है तो वह देश यह चाहता है कि अन्य देश भी आयोजित व्यवस्था अपनाएं. फिर आर्थिक सम्बन्धों को राजनैतिक पुट दे दिया जाता है. रूस में जब आयोजित अर्थव्यवस्था स्थापित हुई तो उसने अन्य “आधिपत्य” के देशों में भी यही व्यवस्था फैलायी और यह भी एक नए प्रकार का “साम्राज्यवाद” है.”

भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर अनियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में, तथा आयोजित व्यवस्था के विपक्ष में मुख्य तर्क :

1. आयोजित व्यवस्था में स्वतन्त्रता नहीं रहती. पहले आर्थिक स्वतन्त्रता नष्ट होती है क्योंकि अपने व्यवसाय चुनने व सम्पत्ति बनाने की स्वतन्त्रता नहीं होती, मन चाही वस्तुओं का उपभोग सम्भव नहीं हो पाता. धीरे-धीरे सामाजिक व राजनैतिक स्वतन्त्रता भी नष्ट हो जाती है आलोचना का अधिकार नहीं रहता. योजना ऊपर से लाद दी जाती है. एक बार समाजवादी आयोजन पद्धति आ गई तो इसको बदलना ही सम्भव नहीं होता है.
2. इस प्रकार की व्यवस्था में तानाशाही, लालफीताशाही व भ्रष्टाचार बढ़ता है. पूँजीपतियों का स्थान बड़े ओहदे वाले, पार्टों के व्यक्ति व बड़े भ्रष्टसर लेते हैं जो भ्रष्ट होते हैं. शासन में शिथिलता रहती है मन लगाकर काम नहीं होता इस कारण जोर जबरदस्ती में कार्य कराया जाता है
3. अगर अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित नहीं हो तो "परमिट-कंट्रोल" राज्य स्थापित हो जाता है अर्थनियन्त्रित व अर्ध-आयोजित अर्थव्यवस्था में बड़े व्यापारी व सरकारी कर्मचारी रिश्वतें देते-लेते हैं
4. उपभोक्ता की सार्वभौमिकता नष्ट हो जाती है
5. आयोजित व्यवस्था में राज्य ही यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा लेना चाहिए तथा किस प्रकार की नौकरी करना चाहिए
6. जब कभी भी देश में आयोजित अर्थव्यवस्था शुरू की गई तो एकदम बहुत गड़बड़ी सामने आयी एकाएक उत्पादन रुक जाता है राज्य के आलोचक व आयोजन के विरोधी रुकावटे डालते हैं राज्य इनको बुरी तरह से दबाता है, कभी-कभी तो लाखों व्यक्तियों को मरवा दिया जाता है. बाद में फिर राज्य खूब कर लगाता है क्योंकि उसकी पूँजी की आवश्यकता होती है रूस में तो आयोजन के प्रथम 30 वर्षों में मजदूरों की वास्तविक मजदूरी घट गई, मूल्य 800 प्रतिशत बढ़ा दिए गए और मजदूरों को बहुत कष्ट हुआ.

आयोजित व्यवस्था के पक्ष में तथा अनायोजित व्यवस्था के विपक्ष में तर्क :

प्रो० डुरविन ने "हाएक की तीव्र आलोचना" की है उनका कथन है :

1. हाएक के विचारों में "मानसिक व राजनैतिक" हठधर्मी हैं तथा उनके विचार भ्रान्तिपूर्ण हैं
2. यह कहना बिल्कुल गलत है कि आयोजित अर्थव्यवस्था में मूल्य व लागत का निर्धारण ठीक से नहीं हो पाता

- 3 जहाँ तक उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का प्रश्न है वह तो केवल पुस्तको में लिखने के लिए है एक व्यक्ति के पास जब धन ही नहीं है तो उपभोग की स्वतन्त्रता कोई भायने नहीं रखती।
- 4 आज के युग में अनायोजित अर्थव्यवस्था "पूर्ण प्रतियोगिता" की व्यवस्था नहीं होती, जिसके हाएव गुण गाते हैं, वरन् एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रति-योगिता की व्यवस्था होती है जिसमें जनता को भला नहीं होता वरन् शोषण होता है (Social good is damnified instead of being served)
5. अनायोजित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा और अज्ञानता बनी रहती है हाएक का यह कथन तो चूल्हा ही है कि आर्थिक स्वतन्त्रता के न होने से राजनैतिक स्वतन्त्रता नहीं होती. वारतव में अनायोजित अर्थव्यवस्था में राजनैतिक स्वतन्त्रता बेकार है क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी व असुरक्षा के कारण यह सब निर्मूल होती है.

Durbin : इतिन कहते हैं¹ :

"Planning is likely to be a more efficient method of reaching any set of ends because reason is superior to instinct and knowledge to ignorance" "Political liberty without economic liberty is a plain case of post hoc propter hoc.

Lewis के अनुसार

' नियोजन व स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था व अराजकता के बीच का झगडा नहीं है नियोजन तो आज हर जगह मौजूद है प्रश्न यह है कि कितना नियोजन अदृश्य रूप से हो (स्वतन्त्र बाजार प्रणाली से) तथा कितना प्रत्यक्ष रूप से हो बाजार व्यवस्था या अनियोजित अर्थव्यवस्था से भी सामाजिक उत्पन्न हो सकता है नियोजित अर्थव्यवस्था से यह उत्पन्न और अधिक हो सकता है और नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार व्यवस्था को भी सहायता मिलती है. थोडा बहुत आयोजन हमेशा रहा है और यह आवश्यक नहीं है कि नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था ही

हो, "The dispute about planning cuts right across left and right, and has nothing to do with the dispute about socialism"

आयोजन के पक्ष में :

1. आयोजित व्यवस्था में हम सब कार्य सुचारु रूप से करते हैं. वास्तव में "We all are planners today" आज हम सब आयोजक हैं. योजनाबद्ध कार्य तो जीव जन्तु भी करते हैं.
2. अनायोजित अर्थव्यवस्था में सब कुछ 'अहस्तक्षेप की नीति' के कारण पूँजी-पतियों के हाथ में छोड़ दिया जाता है. जिसके कारण प्राकृतिक साधनों का अधिक में अधिक ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं. अधिकतम उत्पादनतो होता है परन्तु अधिकतम सामाजिक लाभ नहीं होता. आयोजित व्यवस्था इन दोषों को दूर करती है.
3. अनायोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन में समन्वय नहीं होता. बहुत से उत्पादनकर्ता पूर्णरूप से एक दूसरे के पूरक नहीं होते. कभी-कभी आवश्यकता से अधिक पैदा कर लेते हैं जिसमें मदी व बेरोजगारी बढ़ती है या कम वस्तुएँ पैदा करते हैं जिससे महँगी वस्तुएँ हो जाती हैं और गरीबों को कठिनाईयाँ होती हैं.
4. अनायोजित अर्थव्यवस्था में वितरण व्याप्तपूर्ण नहीं होता. एक तरफ तो अमीरों की बिलासिताओं व सब शौक के अनुसार ही, वस्तुएँ उत्पादित होती हैं और दूसरी तरफ गरीबों को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में जार्ज वर्नार्ड शॉ ने कहा है

"ऐसा राष्ट्र जो गरीब वर्गों के लिए दूध का इन्तजाम करने से पहले शराब का उत्पादन करता है, वह पायलो का राष्ट्र है."

आयोजित अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार से मुनियोजित उत्पादन व वितरण होता है. इस व्यवस्था में एक सीमा के बाद अमीर लोगों को आय नहीं लेने दिया जाता अथवा उन्हें समाप्त हो कर दिया जाता है.

5. आयोजित अर्थव्यवस्था में मजदूरों का शोषण नहीं हो सकता. अनायोजित व्यवस्था में या तो थम भ्रष्टों की कमजोरियों के कारण उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती या फिर बेरोजगारी बनी रहती है.
6. आयोजित अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार में संतुलन बढ़ाया जा सकता है. अनायोजित अर्थव्यवस्था में गरीब देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत हानि

होती है ऐसे देशों में यमीरो के उपभोग के लिए बाहर से जिलासिताओं की वस्तुएँ आती हैं व देश से बाहर जाने वाली चीजों को अमीर देश सस्ता खरीद लेते हैं। आयोजित अर्थव्यवस्था में देश के औद्योगीकरण के लिए मशीनों मँगाने के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का प्रयोग होता है।

7. अनियोजित व्यवस्था में अस्थिरता का दोष है। नियोजित अर्थव्यवस्था में यह दोष नहीं होता। अनियोजित अर्थव्यवस्था में आये दिन व्यापार चक्र घाते रहते हैं तेजी व मंदी के चक्र में कई उद्योग बरबाद हो जाते हैं कई लाख व्यक्ति बेरोजगार व गरीबी के चक्र में पस जाते हैं
8. अनियोजित अर्थव्यवस्था में राज्य कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा भाग पैदा करता है। इस कारण वह अपने कार्यों के परिणाम से अनभिज्ञ रहता है। आयोजित अर्थव्यवस्था में राज्य परिस्थिति और कार्यों के प्रभाव का अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकता है आयोजित अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग होता है आयोजित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य देश में संतुलित विकास उत्पन्न करना होता है।
9. अनियोजित व्यवस्था से भी विकास होता है पर आयोजित व्यवस्था से विकास भी होता है और सामाजिक कल्याण भी बढ़ता है।
Lewis का कथन है .

“अनियोजित अर्थव्यवस्था में अराजकता है। आयोजित अर्थव्यवस्था में सुव्यवस्था है”

Darbin ने इसीलिए कहा है .

“आज के युग में केवल पगल व्यक्ति ही अनायोजित व्यवस्था की बात कर सकते हैं.”

VII. Stages of Planning : आयोजन की अवस्थाएँ :

किसी भी देश में आयोजन की मुख्यतः पांच अवस्थाएँ होती हैं, जो इस प्रकार हैं .

- (i) सर्वप्रथम राज्य को भिन्न-भिन्न आकड़ों का अनुमान लगाना पड़ेगा, जैसे राज्य को राष्ट्रीय आय, रोजगार स्तर, उपभोग स्तर, वचतो व विनियोजन के अनुमान लगाने होंगे। भिन्न-भिन्न वस्तुओं की कमियों या अधिकता का अनुमान लगाना होगा। राज्य को केवल वित्तीय बजट ही नहीं बनाना चाहिए वरन् हर क्षेत्र का बजट बनाना चाहिए, जैसे वस्तुओं का बजट, विदेशी व्यापार बजट आदि।

"From these data . . . a budget for each industry which seems likely to be in serious disequilibrium, a budget for each raw material that will be in short supply, setting demands against availabilities, a manpower budget, and a foreign trade budget will have to be prepared."

(11) जब देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की पूर्ति सबन्धी कमियों का अनुमान लगा लिया जाता है तो राज्य को मुख्यतया दो कार्य करने होते हैं। सर्वप्रथम तो यह करना होता है कि राज्य प्राथमिकताओं के आधार पर इन क्षेत्रों में पूर्ति बढ़ाए, यही बात नियोजन की औचित्यता की द्योतक होती है। दूसरा कार्य यह करना पड़ता है कि मूल्य नीति या 'कौटा प्रणाली' से माँग को सीमित करे। इस प्रकार से पूर्ति बढ़ा कर माँग कम करके माँग और पूर्ति में समन्वय लाना आयोजन की द्वितीय अवस्था होती है।

(111) आयोजन की तृतीय अवस्था में लक्ष्यों को निर्धारित करना पड़ता है। "लक्ष्य" वह आँकड़ा है जिसे अपेक्षित कार्य द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। इन लक्ष्यों को काल्पनिक नहीं होना चाहिए वरन् उन्हें वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। अगर लक्ष्य "हवाई लक्ष्य" हुए तो सम्पूर्ण योजना ही अवास्तविक हो जाएगी। इससे साधनों का वृद्धि-पूर्ण आवंटन हो जाएगा। उसी तरह लक्ष्यों को बहुत नीचा रखने की प्रवृत्ति, जिससे बाद में लक्ष्यों से अधिक कार्य करना सिद्ध हो सके, भी गलत प्रवृत्ति है।

"Overfulfilment is just as much a sign of bad planning as is underfulfilment."

योजना को लोचपूर्ण होना चाहिए। अगर योजना पंचवर्षीय योजना है तो भी हर वर्ष योजना की प्रगति का मूल्यांकन होना चाहिए।

(1V) इस अवस्था में सम्पूर्ण योजना देश के मसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मसद में इसकी आलोचना व सुधारों के अनुसार यथासंभव सुधार किए जाना चाहिए। यही बात योजना के जनतन्त्रीय होने का

स्रोतक होती है. मसद का अनुमोदन का अर्थ यह नहीं होता कि हर व्यक्ति की आलोचना को दूर किया जाए. अगर ऐसा किया गया तो योजना की कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा. फिर भी ययासभव सश'धनो को अपनाने के लिए तैय्यार रहना चाहिए.

- (v) पाँचवी अवस्था, योजना को कार्यान्वित करने की अवस्था होती है. इस कार्य को पूरी लगन से करना होगा. भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता व व अयोग्यता को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए यह नहीं होगा तो फिर आयोजन सफल नहीं हो सकता, नेताओं को केवल भाषाबाजी नहीं करना बरना योजना को कार्यान्वित करने के कार्य पर उचित मार्गदर्शन व नियन्त्रण रखना चाहिए

“Governments frequently take action to reduce demand but are not good at taking action to increase supply. The leaders try to plan by exhortations, making speeches urging people to produce more but in fact have no plans, whether of inducement or of direction, to shift resources into the right places. They are then surprised and hurt at the end of the year, when their plans have not been fulfilled, and they make still more speeches. Planning by exhortation is not planning.”

VIII. Defects, Limitations and Difficulties in Planning Programmes of Under-developed Countries कम-विकसित देशो मे नियोजन कार्यक्रमो मे कमियाँ, सीमाए तथा कठिनाइयाँ :

आज हर देश मे नियोजन किया जाता है. समाजवादी देश तो पूरी तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था मे रहते हैं परन्तु स्वयं Stalin (स्टालिन), जो रूस के प्रधानमन्त्री रहे थे, लिखा है

“नियोजन के महत्व व योगदान को कम बताना गलत होगा, परन्तु उसको आवश्यकता मे अधिक महत्व देना भी गलत होगा हम ऐसी अवस्था को कभी नहीं पहुँच सकते जबकि हम हर चीज को नियंत्रित

या नियोजित कर सकें. हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर कुछ क्षेत्रों में नियोजन हो सकता है तो कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ नियोजन संभव नहीं है”

U N O ने भी कम-विकसित देशों में आयोजन की कठिनाइयों व कमियों पर विचार किया है

आंकड़ों व आवश्यक सूचनाओं की कमी :

कम-विकसित देशों में अभी भी सांख्यिकीय विभाग विकसित नहीं हुए हैं, आंकड़े या तो पर्याप्त मात्रा में इकट्ठे नहीं किये जाते या फिर कुछ ही क्षेत्रों या घटकों से इस संबंध में इकट्ठे किए जाते हैं. कुछ देशों में तो बहुत आवश्यक क्षेत्रों (जैसे जनसंख्या, बचतों व पूँजी उपज अनुपातों) के आंकड़े भी ठीक मात्रा में व सही किस्म के नहीं होते हैं. इस प्रकार से वगैर पर्याप्त अनुसंधान, अध्ययन, मूल्यांकन के आयोजन भी सफल नहीं होते.

पूँजी-निर्माण की कमी :

हम पढ़ ही चुके हैं कि कम-विकसित देशों में बहुत से कारणों से बचतों की कमी रहती है और बचतों के दुरुपयोग से पूँजी-निर्माण कम रहता है जो पूँजी होती है उससे स्थिर व चक्र पूँजी दोनों की आवश्यकता पूरी नहीं होती. इन देशों में मशीनों का रख रखाव (Maintenance) भी उचित नहीं होता

इधर सार्वजनिक वित्त प्रदब्धन भी ठीक नहीं रहता. करो से आय कम प्राप्त होती है. करो का बचन अधिक होता है. कहीं-कहीं राज्य की करनीतियाँ निजी क्षेत्र के विकास में भी बाधक हो जाते हैं.

उन्नत तकनीक की कमी :

कम-विकसित देशों में जनसंख्या की अधिकता, पूँजी की कमी, शिक्षा के निम्नस्तर तथा कुशल व्यक्तियों की कमी के कारण नियोजन की सारी योजनाएँ सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं. नियोजन की लागत बढ़ जाती है

प्राथमिकताओं का उचित न होना : विनियोजन का त्रुटिपूर्ण आवंटन :

कम-विकसित देशों में बहुधा सार्वजनिक कार्यों की आवश्यकता से अधिक महत्व मिल जाता है और कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि को उतना महत्व नहीं मिल पाता. सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोजन से कभी निजी क्षेत्र के विनियोजन को

सहायता देने के स्थान पर बाधा उत्पन्न हो जाती है। सार्वजनिक उद्योग पूँजी-निर्माण के साधन के स्थान पर पूँजी-उपभोग के कारण बन कर रह जाते हैं। और फिर मुद्रा स्फीति या अधिवाधिक कर लगाने के कारण बन जाते हैं।

दोषपूर्ण शासन व्यवस्था :

आज कम-विकसित देशों के शासन अत्यन्त दोषपूर्ण हैं। बहुत से कम-विकसित देशों ने साम्राज्यवादियों के शासन से स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर ली परन्तु सत्तम, भ्रष्टाचार रहित व उत्साही प्रशासन देने में असफल रहे। बहुत से कम विकसित देशों में बहुधा "तर्क पलट" दिए जाते हैं। भारत में भी उदाहरणतया राज्य सरकारों में पार्टों परिवर्तनों के कारण राज्य शासनों में अस्थिरता बनी रहती है। विधानसभा के सदस्य राजनीति में ही उलझे रहते हैं। प्राथिक नीतियों के निर्धारित करने व उन्हें कार्यान्वित करने की फुरसत ही नहीं रहती। आज कम विकसित देशों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञों द्वारा ही पनपाया जाता है। नियोजन के लिए जो धन इकट्ठा होता है उसका बहुत बड़ा भाग भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, प्रशासकों व ठेकेदारों के पास चला जाता है। जनता का कल्याण कम हो पाता है।

राज्य के आयोजन के कार्य कागजों पर अधिक होने रहते हैं। नियोजन की सफलता के लिए उत्साही जनता व ईमानदार शासक चाहिए। जापान में यही था इसी कारण वहाँ नियोजन सफल हो सका है।

जन सहयोग की कमी :

कम विकसित देशों में जनसहयोग की कमी से भी आयोजन असफल हो जाता है। हर देश में आयोजन के शुरू में जनता का सहयोग रहा है। भारत में भी 'श्रम दान' द्वारा बहुत कुछ कार्य हुए। बालाभन्तर में जब आम जनता उम्मीद के अनु-

Select Bibliography •

Apart from the books mentioned in previous chapters, following books and articles were consulted

Books •

1. E F M Durbin • Problems of Economic Planning
2. Maurice Dobb • An Essay on Economic Growth and Planning.
3. Herman Finer • Road to Reaction.
4. Ragner Frisch : Planning for India : Selected Exploration in Methodology
5. S. E Harris • Economic Planning.
6. P von Hayek . The Collectivist Economic Planning

सार लाभान्वित नहीं होती और अन्य लोगों को भ्रष्टाचार से लाभान्वित होते देखती है तो वह सहयोग के स्थान पर असहयोग करने लगती है। अगर आयोजन में बेरोजगारी, निम्न आय की समस्या को 15-20 वर्षों के आयोजन से कम न किया गया तो निश्चित ही जनता असहयोग करती है। आज भारत में भी इतनी बेरोजगारी व गरीबी है कि हर छोटी से छोटी समस्या के कारण फलतः व्यक्ति लूटपाट, आगजनी आदि करने के लिए मिल जाते हैं।

बहुत लम्बी अवधि का आयोजन तथा अल्पकालिक समस्याओं की अवहेलना : आज कम-विकसित देशों के नियोजक, परम्परागत अर्थशास्त्रियों की भांति 'दीर्घ-काल में सब ठीक हो जायेगा' की बात करते हैं। कुछ वर्षों तक जनसाधारण इस उम्मीद में रहता है कि नियोजन से उसे लाभ होगा। परन्तु अगर बहुत दीर्घ-कालिक नियोजन हुआ तो वह सफल नहीं होता। राज्य का जीवन घसीमित है

7. Indian Planning Commission . Various Five year Plans.
 8. Oskar Lange : Essays on Economic Planning.
 9. W. A. Lewis . The Principles of Economic Planning.
 10. Ludwig von Mises : Planning for Freedom
 11. Lionel Robbins : Economic Planning & International Order.
 12. Ferdynand Zweig : The Planning of Free Societies.
 13. W. Birmingham & A. G. Ford . Planning and Growth in Rich and Poor Countries.
 14. Charles Bettelheim : Studies in the Theory of Planning.
 15. S. S. Wadia : Techniques on Planning.
 16. Zinkin : Growth, Change and Planning.
 17. Maurice Dobb : Economic Growth and Planning.
- Papers :
18. Edward S. Mason Some Aspects of the Strategy of Development Planning : Centralization vrs Decentralization.
 19. Gernard Colm and Theodore Geiger : Public Planning and Private Decision-making in Economic and Social Development.
 20. Max F. Millikan - Criteria for Decision-making in Economic Planning—The Planning Process.
 21. Howard S. Ellis : National Development Planning and Regional Economic Integration.
 22. Harvey S. Perloff and Raul Saer : National Planning and Multinational Planning under the Alliance for Progress.

परन्तु जनता का Time Horizon (समय सीमा) सीमित होती है. नियोजन को इस काल में ही परिष्कार प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा नियोजन सफल नहीं हो सकता.

आवश्यकता से अधिक नियंत्रण :

Planning fails because of the too little or too much action कम-विकासित देशों में कहीं-कहीं राज्यों का हर क्षेत्र में बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है. बहुत अधिक हस्तक्षेप से भी आयोजन असफल होता है. मांग और पूर्ति के नियम तो नियोजित अर्थव्यवस्था में भी लागू होते हैं इसलिए पूर्ण रूप से मूल्य नियंत्रण भी उचित नहीं होंगे. नियोजन में भी बाजार व्यवस्था का ध्यान रखना होगा. पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मुद्रा स्फीति फैलने दी जाए. बहुधा मुद्रा स्फीति ही नियोजन की असफलता का मुख्य कारण बन जाती है.



-
- 23 P. N. Rosenstein-Rodan Determining the need for and Planning the use of External Resources.
 - 24 Hollis B. Chenery : A Model of Development Alternatives.
 25. Gustav F. Papanek and Moeen A. Qureshi . The use of Accounting Prices in Planning
 - 26 Kenneth R. Hansen : Planning as a Continuing Process.
 27. Stephen K. Bailey : The Place and Functioning of a Planning Agency within the Government Organization of Developing Countries

All United States papers prepared for the United Nations Conference on the Application of Science and Technology for the benefit of the less developed areas.

28. Richard S. Eckaus : Appendix on Development Planning in Kindleberger's op cit

Books :

29. Edward Helmann : Types and Potentialities of Economic Planning
30. A. B. Bhattacharya : Theory and Practice of Planning.
31. B. G. Gupta : Economics of Planning.

विदेशी सहायता व आर्थिक विकास

Foreign Aid and Economic Development

I प्रस्तावना

विदेशी सहायता का अर्थ

II कम-विकसित देशों को विकसित देशों से मिलने वाली सहायता का आकार व प्रकार भिन्न भिन्न सस्याओं व देशों का योगदान

III भारत का विकास व विदेशी सहायता

विश्व बैंक व सहायक सस्याएँ, U S A , U S S R का योगदान :

IV. कम-विकसित देशों के लिए आवश्यक सहायता के अनुमान

V. कम विकसित देशों के लिए विदेशी सहायता संबंधी नीति के आवश्यक तत्व

(a) अधिकाधिक अनुदान आवश्यक

(b) Soft loans या कम विकसित देशों की मुद्रा में चुकाए जानेवाले ऋण अधिक हों

(c) तकनीकी सहायता मिलना चाहिए

(d) Hard loans की शर्तें आसान हों

(e) Special or project loans तथा General loans का समन्वय

(f) अन्य प्रमुख बातें

आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का महत्व व सीमाएँ : विदेशी सहायता व तीन जमताएँ

अध्याय : 13

विदेशी सहायता तथा आर्थिक विकास

Foreign Aid and Economic Development

I. प्रस्तावना .

विदेशी 'सहायता' का अर्थ :

समान्यतया "सहायता" से हमारा आशय अनुदान से होता है. इस प्रकार से विदेशों से मिलनेवाला अनुदान (grant) ही वास्तव में "सहायता" हुई, परन्तु व्यवहार में विदेशों से मिलने वाले अनुदान, नरम ऋण (soft loans), व्यापारिक ऋण, विदेशी पूँजी आदि सब को "सहायता" के अन्तर्गत शामिल कर लेते हैं. सर रॉय हारोड (Sir Roy Harrod) के अनुसार :

"मगर विदेशी ऋण-दाता अपने द्वारा दिए जानेवाले ऋण पर सामान्य लाभ कमाता है तो हम इसे "सहायता" नहीं कह सकते. "सहायता" के अन्तर्गत तो हम केवल अनुदान (grants) तथा "नरम ऋण" (soft loans)¹ को ही शामिल कर सकते हैं.

इसलिये विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण भी "सहायता" नहीं कहे जा सकते, क्योंकि विश्व बैंक उतनी ही दर से ब्याज लेता है जितना कि उसे अपनी सरकार को ऋण देने पर ब्याज मिलता है. यह दर भले ही उस ब्याज की दर से कम हो जो कि बाजार में प्रचलित है पर इतनी कम नहीं कि इसके ऋणों को 'सहायता' कहा जा सके. 'सहायता' का अर्थ है कि देनेवाले व्यक्ति ने कुछ त्याग किया है. इस प्रकार के ऋणों में किसने त्याग किया है "

1. Soft Loans वे हैं जिनकी अदायगी कम विकसित देश अपनी ही मुद्रा में करते हैं.

Cf : Sir Roy Harrod : "Aid to the Less-developed Countries" Commerce, Annual Number, Dec. 1965.

लेखक सर राय हरोड की परिभाषा से सहमत है, परन्तु विकास व "सहायता" के सह-स्रवध को अध्ययन करने के लिए अनुदान, नरम ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, तकनीकी सहायता व वस्तुगत सहायता सब को 'सहायता' मान लिया है

II कम-विकसित देशों को विकसित देशों से मिलने वाली सहायता का आकार व प्रकार

विकसित देश कम-विकसित देशों को आज पहले से बहुत अधिक सहायता दे रहे हैं. जहाँ 1950's के काल (mid-50's) में कम-विकसित देश 2.5 billion dollars की सहायता प्राप्त करते थे. मध्य 1960 में यह सहायता 5.5 billion dollars हो गई. आज भी सहायता की मात्रा बढ़ती ही जा रही है. विदेशी विनिमय का यह सबसे सुनिश्चित साधन है. जहाँ 1954 में विदेशी सहायता निर्यात का 3% थी वहाँ अब निर्यात का 20% हो गई है जहाँ विदेशी सहायता पहले कम-विकसित देशों की केवल 1% राष्ट्रीय आय के बराबर योगदान करती थी वहाँ अब लगभग 3% से अधिक है. आजकल विदेशी सहायता की मात्रा में हर वर्ष लगभग 15% वृद्धि हो रही है.¹

जहाँ ये आँकड़े बढ़ती हुई सहायता की बात बतलाते हैं वहाँ यह सहायता बहुत ही अग्रणी है. U.N.O. की E/3131 रिपोर्ट जो 1958 में 26 वें सम्मेलन में प्रस्तुत की गई, उसमें निम्नलिखित आँकड़े दिये गये हैं.

(a) 1956-57 में वे 20 देश जिनमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय \$ 100 से कम थी उनको कुल \$ 1004 million की सहायता मिली थी यह वितरण इस प्रकार था

\$ 336	Million	द० कोरिया
\$ 246	"	द० वियतनाम
\$ 41	"	कम्बोडिया
\$ 49	"	लाओस
\$ 34	"	लीबिया

1. For estimates

See : I. H.W. Singer : op. cit , p 32-33

2 Frederick Benham

3 Gatt . estimates

4. U N O. estimates

5. I.B.R.D. : M.F. Bulletins

6. मुद्रा, बैंकिंग .. सांख्यिकीय मेहता, श्रीवास्तव, गुप्ता.

} all references at the end
of the chapter

अन्य 15 देशों में बाकी का 400 million डालर दिया गया। इन 15 देशों में 67 करोड़ जनसंख्या का निवास था और इस प्रकार प्रति व्यक्ति केवल 60 सेंट सहायता प्राप्त हुई। भारत को तो यह सहायता केवल 10 सेंट प्रति व्यक्ति ही थी।

(b) अन्य 18 देश जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 100 तथा 200 डालर के बीच थी, को कुल 464 billion dollars सहायता के रूप में दिए गये जिसका वितरण यह था.

ताइवान (फारमोसा)	\$ 111	million.
बोलिविया	\$ 24	"
गोटेमाला	\$ 26	"
मोरक्को	\$ 79	"
ट्यूनिशिया	\$ 50	"
अन्य 13	\$ 174	"

इन अन्य 13 देशों में प्रति व्यक्ति 1 डालर मिला (इनकी जनसंख्या 175 m थी)

(c) प्रति व्यक्ति सहायता को माना बहुत कम है सब मिलाकर अभी भी सब देशों को 1 डालर प्रति व्यक्ति से भी कम प्राप्त होता है। कुछ देश जो सामरिक दृष्टि से पश्चिमी देशों के गट में हैं, उन्हें अवश्य अधिक सहायता मिलती है। निम्नलिखित तालिकाएँ इस स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। यह सहायता 1954-56 के साल की है

तालिका I

Group A 100 डालर प्रति-व्यक्ति प्रति-वर्ष GNP (Gross National Product) से कम वाले देश	
देश	प्रति-व्यक्ति सहायता
1. बर्मा	·9 डालर
2. भारत	·6 "
3. इन्डोनेशिया	·5 "
4. पाकिस्तान	3 8 "
5. थाइलैंड	2·0 "
6. द० कोरिया	31·4 "

तालिका II

Group B : \$ 100-200 डालर प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष GNP वाले देश

देश	प्रति-व्यक्ति सहायता
1. लका	2.1 डालर
2. मिय	2.1 "
3. लीबिया	54.8 "
4. परागुए	3.8 "

तालिका III

Group C : \$ 200-300 डालर प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष GNP वाले देश

देश	प्रति व्यक्ति सहायता
1. एल सेलवाडोर	4.0 डालर
2. मेक्सिको	2.7 "
3. फिलीपीन्स	2.0 "
4. इजराइल	83.0 "

उपरोक्त तालिकाओं में इजराइल, लीबिया व द. कोरिया को अधिक सहायता प्राप्त करते हुये दिखाया गया है. ये देश पश्चिमी देशों के अधिक निकट होने के कारण सहायता प्राप्त करते हैं

इतने अध्ययन के बाद हम देख सकते हैं कि कम-विकसित देशों को अभी पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं मिल रही है. U. N. O. के वर्तमान महासचिव श्री ऊ थाँ (U Thant) ने समस्त विकसित राष्ट्रों से अपील की है कि वे अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 1% कम-विकसित देशों को सहायता के रूप में दें. परन्तु यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है. वास्तव में इस प्रतिशत तक पहुँचने के बजाय और दूर हो रहे हैं. 1961 में विकसित देशों ने अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 0.8% सहायता के रूप में दिया और 1965 में यह प्रतिशत गिर कर केवल 0.6% रह गया. इसके अतिरिक्त जितनी सहायता का वायदा किया जाता है उसका केवल 60-65% ही दिया जाता है.¹

1. See : Patriot : Sept. 27, 1966.

एक बात ध्यान देने योग्य है कि विकसित देशों की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है इस लिए अगर सहायता का प्रतिशत उतना ही रहे तो भी निपेक्ष रूप में सहायता की मात्रा तो अधिक हो जाती है। परन्तु इस लाभ के विपरीत कम-विकसित देशों को मूल्य वृद्धि के कारण इस सहायता का वास्तविक मूल्य भी कम हो जाता है। यह मात्रा निश्चित ही बढ़ाया जाना चाहिए। विकसित देश जितना युद्ध की तैयारी व हथियारों की होड़ में खर्च कर देते हैं यह तो उसका केवल 5% ही है, और अभी भी सहायता की शर्तें बहुधा उतनी उदार नहीं रहती जितनी होना चाहिए।

विश्व बैंक तथा सहायक संस्थाओं द्वारा सहायता¹

विश्व बैंक की स्थापना वैसे तो युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए हुई थी परन्तु कालान्तर से यह कम-विकसित देशों को दीर्घकालीन पूँजी की सहायता देने लगा या दिलवाने लगा यह अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन को भी प्रोत्साहित करता है, निजी विदेशी विनियोजकों को "गारन्टी प्रदान" कर या उसमें हिस्सा बढ़ाकर भी सहायता करता है। यह बैंक उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देता है और कम-विकसित देशों को उनके साधनों के विकास में सहायता देकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और भुगतान मतुलन की स्थापना में सहायता करता है। बहुधा यह बैंक 15 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण देता है। बैंक खर्चों पर नियंत्रण रखता है तथा आवश्यकता अनुसार ऋण की अदायगी करता है। बैंक कम-विकसित देशों को आयोजन व वित्तीय साधन जुटाने में भी सलाह देकर सहायता करता है तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराता है तथा प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करता है। कुछ देशों को सहायता के लिए विशेष "सहायता क्लब" जैसे Aid India club व Aid Pakistan club बनाए हैं। साधनों के सर्वेक्षण में भी मदद करता है। इससे लिए गए ऋणों व व्याज का भुगतान विदेशी मुद्रा में ही किया जाता है।

शुरू में विश्व बैंक बहुत कम ऋण देता था परन्तु अब वह प्रति वर्ष \$ 600 से \$ 700 Million तक ऋण उधार देता है। 1965 में बैंक के द्वारा दिए गए बकाया ऋणों की मात्रा \$ 6 Billion थी 1967 के मार्च के अन्त तक बैंक व उनकी सहायक संस्थाओं ने 40 मुद्राओं में 8 Billion डालर के 500 से अधिक ऋण प्रदान किए थे

1. विश्व बैंक पर श्री चार. पी. गुप्ता द्वारा लिखित अध्याय 7 व 8, "वैकिंग मुद्रा ... " "साप्थकीय", लेखक मेहता, धीवास्तव व गुप्ता : कलाश पुस्तक सदन.

निम्नलिखित तालिका 30 जून 1965 तक दिए गए ऋणों का विवरण देती है :

क्षेत्र	राशि की मात्रा करोड़ डालर में	कुल का प्रतिशत
1. एशिया तथा मध्यपूर्व	309.2	34
2. दक्षिणी और मध्य अमेरिका	220.8	25
3. यूरोप	199.1	23
4. अफ्रीका	110.4	13
5. आस्ट्रेलिया	45.7	5
	<u>877.2</u>	<u>100%</u>

विश्व बैंक ने सन् 1966 में 90.1 करोड़ डालर के ऋण प्रदान किए हैं और सन् 1967 के प्रथम तीन माह में 14.47 करोड़ डालर के ऋण प्रदान किए हैं।

I. F. C. व I. D. A.

International Development Agency. (I. D. A.) तथा International Finance Corporation (I. F. C.) दोनों विश्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में स्थापित की गईं। I. F. C. की स्थापना जुलाई 1950 में हुई और I. D. A. की अक्टोबर 1959 में हुई। I. F. C. निजी क्षेत्रों की औद्योगिक योजनाओं को "इक्विटी पूंजी" तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, विश्व बैंक की भांति यह संस्था भी तब ऋण प्रदान करती है, जब अन्य क्षेत्रों से ऋण मिलने की सम्भावना नहीं रहती है तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है व प्रदान कराता है, प्रायः 5 से 15 वर्ष तक के लिए निगम सहायता करता है। I. F. C. ने 1967 तक 20 करोड़ डालर से अधिक ऋण, मुख्यतया लेटिन अमरीकी देशों को प्रदान किए, परन्तु हाल में ही यह एशिया व अफ्रीका में भी दिलचस्पी लेने लगा है, यह निगम कम-विकसित देशों में वित्त निगमों को स्थापित करने में सहायता देता है और ये वित्त निगम फिर इन देशों में निजी क्षेत्र के विकास में सहायक होते हैं और इन देशों में पूंजी बाजार का विकास होता है अब 1966 के बाद विश्व बैंक ने इसे और 40 करोड़ डालर दिए हैं जिससे इसकी

See also - Kindleberger, op cit., p 337.

Norman G. Jones : "Disbursing Bank Loans", Finance and Development, March 1967, p. 55.

David Grenier, I.F.C., An Expanded Role for Venture Capital, Finance and Development, June 1967, p. 139.

क्रियाओं में और विकास हुआ है, इसके द्वारा सहायता किए गए उद्योग लगभग औसत 12.15% लाभ प्रतिवर्ष बना रहे हैं वित्त निगम के द्वारा 21 देशों में 25 वित्त कम्पनियों को अब तक 56 करोड़ डॉलर का ऋण प्रदान कर उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

I. D. A. मुख्यतया सामाजिक-आर्थिक सिरोपरि व्यय के विनिर्भोजन (शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का विकास) करता है I.D.A. की ब्याज की दरें भी नीची होती हैं तथा ऋण भी काफी दीर्घकाल के लिए होते हैं, विकास संध द्वारा अब तक प्रदत्त ऋणों के चुकाने की अवधि 50 वर्ष है और ऋण आसान किस्तों में चुकाए जाते हैं एवं प्रथम किस्त ऋण प्राप्त करने के 10 वर्ष पश्चात् शुरू होती है, विश्व बैंक के ऋणों की भांति I.D.A. भी बहुत जांच पड़ताल के बाद ऋण प्रदान करती है विकास संध द्वारा कार्य 8 नवम्बर 1961 को शुरू किया गया अपने कार्य-काल के प्रथम चार वर्षों में विकास संध द्वारा 70 योजनाओं के लिए 100 करोड़ डॉलर से भी अधिक ऋण प्रदान किया है, सन् 1966 के वर्ष में 47.55 करोड़ डॉलर के ऋण और प्रदान किए गये, विकास संध ने रेलवे, सिंचाई, बन्दरगाहों के विकासार्थ, कृषि विकास आदि कार्यों के लिए ऋण प्रदान किए हैं, विकास संध ने अप्रैल 1966 से मार्च 1967 के बीच निम्नलिखित ऋण दिए .

भारत	रेलों के लिए	6.8	करोड़ डॉलर
भारत	औद्योगिक आयात	6.5	" "
भारत	विद्युत	2.5	" "
पाकिस्तान	औद्योगिक आयात	2.5	" "
पाकिस्तान	शिक्षा	1.3	" "
केमरून	कृषि	1.1	" "
पेरु	पर्यावरण	0.75	" "
दयूनिसिया	कृषि	0.6	" "
अन्य		3.1	" "
		24.95	" "

U.N.O की आमसभा ने U.N.O. के अन्तर्गत एक विशेष कोष Special U.N Fund for Economic Development (SUNFED) बनाया जिसके लिए भिन्न-भिन्न देशों से उनकी योग्यतानुसार धन इकट्ठा करके कम-विकसित देशों में उनकी गरीबी के अनुसार, अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की,

U. S. A. इस SUNFED को सबसे प्रमुख अनुदान देनेवाला बनता परन्तु उसने इसका घोर विरोध किया. फिर केवल 100 m. डॉलर से एक U. N Special Fund की ही स्थापना हो सकी इससे विशेष तकनीकी सहायता व सर्वेक्षण के लिए ऋण दिया जाता है.

III. भारत का विकास व विदेशी सहायता :

ऋण :

भारत को मार्च 1, 1969 के दिन 1877.42 करोड़ रु० (P. L. 480 के ऋणों को छोड़कर) की सहायता आ रही थी. (Was in the pipeline) 28, February 1969 तक भिन्न-भिन्न देशों से (जिनमें विश्वबैंक व उसकी सहायक संस्थाओं के ऋण शामिल हैं) 7788.18 करोड़ रुपये की सहायता के समझौते हो चुके थे. इसमें से 6484.35 करोड़ रुपये के ऋण विदेशी मुद्रा में चुकाए जाएंगे तथा 1303.83 करोड़ के ऋण U. S. S. R. व अन्य साम्यवादी देशों के हैं जिन्हें सामान्यतया निर्यात में चुकाया जाएगा

P L 480 के ऋण, जो अबतक 1423.87 करोड़ रुपये के हो चुके हैं, तथा अन्य रुपये के ऋणों को, जो 509 करोड़ रुपये के हैं, मिलाकर 28 फरवरी 1969 तक 9721.38 करोड़ के विदेशी ऋण हो गए हैं

इस 7788.18 करोड़ रुपये के ऋणों के लिए 6484.43 करोड़ के सामान मगाने के लिए आर्डर जा चुके हैं अभी तक 5910.76 करोड़ का पूर्ण प्रयोग हो चुका है और केवल 1877.42 करोड़ का प्रयोग और होता है.

Rupee loan या रुपये में विदेशी ऋण (1933.20 करोड़) में से 1715.69 करोड़ रुपये के ऋणों का पूर्ण प्रयोग हो चुका है और केवल 217.51 करोड़ रुपये के ऋण का प्रयोग बाकी है. इस प्रकार विदेशी ऋणों में से अभी 2094.93 करोड़ का प्रयोग बाकी है. (1877.42+217.51)

See :

1. Free Press Journal : 18th July 1969.
2. The Financial Express : 28th July 1969.
3. India's Fourth Five Year Plan, 1969-74: p. 91-95. draft.
4. Foreign Aid & India's Economic Development. VKRV Rao and Dharam Narain.
5. Free Press Journal : 14th Feb. 1969, for America's Economic Aid to India.

28 फरवरी 1969 तक विदेशी मुद्रा ऋण में से 1060 करोड़ रुपये मूलधन के रूप में तथा 630 करोड़ व्याज के रूप में चुकाए जा चुके हैं और अब 4850 करोड़ रुपये के ऋण विदेशी मुद्रा में और 1225 करोड़ के ऋण रुपये में वापस करना है।

सहायता अनुदान :

भारत को 1969 फरवरी तक 1108 करोड़ रुपये दान के रूप में प्राप्त हुए जिसमें से 1028 करोड़ रुपया का प्रयोग कर लिया गया है और 80 करोड़ रुपये के बराबर का अनुदान और प्रयोग करना है।

चतुर्थ योजना •

भारत की चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना (1969-74) के लिए 10050 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी जिसको निर्यात-आय व विदेशी सहायता से प्राप्त किया जाएगा इसके अतिरिक्त 2280 करोड़ रुपये के विदेशी ऋणों के मूलधन व व्याज का व्यव होगा इसमें से 1750 करोड़ रुपये ही (ऋण भुगतान के अतिरिक्त) विदेशी सहायता के रूप में आवश्यक होंगे, भारत की तृतीय योजना में 3500 करोड़ रु० की विदेशी सहायता प्राप्त हुई, और तीन वार्षिक योजनाओं के काल में भी (1966-1969) इसी योजना काल के औसत के अनुसार सहायता प्राप्त हुई चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में अधिक मात्रा में व सुनिश्चित रूप से सहायता की आवश्यकता होगी इस 1750 करोड़ की सहायता के सबंध में चतुर्थ योजना में लिखा है

‘This will be available only if the gross aid utilisation in the economy is of the order of Rs 4030 crores comprising PL 480 food aid of Rs. 380 crores and the project and non project aid of Rs 3650 crores.’

विश्व बैंक व सहायक संस्थाओं द्वारा ऋण व सहायता ।

भारत को विश्व बैंक से तीनों योजनाओं के काल में 462 81 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हुए और 379 97 करोड़ के ऋण प्रयोग कर लिए गए थे, उस समय इस प्रकार से 82.84 करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे, विश्व बैंक के 34 ऋणों

See . Ch. 21 on Public Finance written by Dr. O. S. Shrivastava in “मुद्रा . सांख्यिकीय” मेहता, श्रीवास्तव, गुप्ता, Eastern Economist, Annual No., 1968.

में से 13 यातायात, 12 उद्योग, 7 शक्ति विकास, 1 कृषि, 1 बहुमुखी योजना के लिए दिया गया. Aid India club से भारत को तृतीय योजना काल में 540 करोड़ रु० में ऊपर सहायता प्राप्त हुई I. F. C. से भारत को पिछले तीन वर्षों में 70 लाख डालर ऋण प्राप्त हुए. I. D. A. से जो ऋण प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार रहे हैं

स्वीकृति का दिनांक माह सन्	ऋण का उद्देश्य योजनाएं	ऋण की मात्रा लाख डालरों में
जून 1961	सड़क निर्माण तथा सुधार	600
सितम्बर 1961	ट्यूबवेल का निर्माण	60
मार्च 1962	वाढ नियन्त्रण	100
जून 1962	मोन नदी सिंचाई	150
जुलाई 1962	पूरना नदी घाटी	130
अगस्त 1962	कोयला विद्युत शक्ति	171
सितम्बर 1962	सवाद वहन	420
सितम्बर 1962	बम्बई बन्दरगाह सुधार हेतु	180
मार्च 1963	भारतीय रेलों का विस्तार	675
मई 1963	काठगोदाम विकास विद्युत शक्ति	200
जून 1964	व्यावसायिक वाहन, औद्योगिक मशीन तथा निर्माण उपकरण	900
अक्टूबर 1964	सवाद वहन का विस्तार	330
दिसम्बर 1964	भारतीय रेलों का विकास	620
मई 1966	भारतीय रेलें	680
जून 1966	विद्युत शक्ति	230
फरवरी 1967	औद्योगिक आयात	550

I. D. A. ने भारत को सर्वाधिक ऋण दिए हैं

See Also :

John Mc Diarmid : "International Action for Economic and Social Progress" Indian Finance, 11 November 1967.

U S A द्वारा भारत को सहायता

भारत को सबसे अधिक आर्थिक सहायता U S A से प्राप्त हुई है परन्तु भारत उसका उतना आभार मानता नजर नहीं आता जितना कि वह सोवियत यूनियन का भारत को U S A न सवप्रथम 1951 म आर्थिक सहायता दी उसके बाद जनवरी 1969 तक उसने 8994 1 million dollars (6745 58 करोड़ रुपये) की सहायता दी है निम्नलिखित तालिका इसको दर्शाती है

	करोड़ रु० म
1 USAID Mission Technical Cooperation Programme	
(a) अनुदान	310 58
(b) ऋण रुपये या डालर म वापस करना बाल	115 58
2 USAID development loans (विकास ऋण)	
(a) डालर में जिनका भुगतान होना है	1770 90
(b) रुपये म जिनका भुगतान करना है	396 53
3 P L 480—Title I (अनुदान व रुपये म चुकाए जान बाल ऋण)	2365 40
4 P L 480—Title II अनुदान	370 65
5 बाड व दुर्भिक्ष दान	4 13
6 U S Export Import Bank loans (डालर म वापस करना है)	343 70
7 1951 का गृह ऋण (डालर म ऋण)	142 28
	<hr/> 6745 58

U S A न जो कुछ दिया उसका

19 5% अनुदान है

45 3% रुपये म वापस करना है

33 4% डालर म वापस करना है

1 8% डालर या रुपये म (U S A की मर्जी पर)

वापस करना है

100 00%

U. S. A. की सहायता तीन संस्थाओं द्वारा प्राप्त होती है ये तीन संस्थाएँ हैं

(i) United States Agency for International Development (USAID)

(ii) P. L. 480 (शान्ति के लिए खाद्य) तथा

(iii) U. S. Export—Import Bank.

U. S. A ने भारत को अभी तक 2715 विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्री क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है यह शहर ऋण 40 वर्ष की अवधि के हैं और प्रथम दस वर्षों में कुछ भी वापस नहीं करना पड़ता है तथा व्याज 2% लिया जाता है तत्पश्चात् व्याज की दर 3% होती है. P. L. 480 के अन्तर्गत खाद्य सहायता देकर अमेरिका ने न केवल देश को भुखमरी से बचाया है बल्कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई को दूर किया और वह धन जो हम खाद्यान्न के आयात में व्यय करते उसे विकास के कार्य में ले सके (अब तक 57 m tons से ऊपर खाद्यान्न मिल चुके हैं) इस सहायता से भारत में मुद्रा स्थिति व भुखमरी के संकट को टाला जा सका है या बहुत कम रखा जा सका है

U. S. A की आर्थिक सहायता (केवल 1969 जनवरी तक) के महत्व को तो हम इस ही बात से समझ सकते हैं कि यह पूरी सहायता सम्पूर्ण द्वितीय योजना की धनराशी के बराबर है. इससे ही हम समझ सकते हैं कि अमेरिका का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है मोटे-मोटे रूप से U. S. A की सहायता का प्रयोग इस प्रकार हुआ है

46%	खाद्यान्न व आवश्यक कच्चे मानव के लिए
33%	उद्योग व शक्ति के लिए
13%	यातायात जिसमें 12% रेलों के विकास को
10%	कृषि, सिंचाई व सामुदायिक योजनाएँ, मत्स्य व जंगल.
<u>100%</u>	

U S S. R की आर्थिक सहायता व कम विकसित देशों, विशेष रूप से भारत का विकास :

U. S. S. R. ने हाल में कम-विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायता देना शुरू किया है. इसकी सहायता अमेरिका के अनुपात में तो बहुत कम है परन्तु फिर भी इसका योगदान महत्वपूर्ण है. U S. S. R. का दावा है कि जहाँ पश्चिमी देशों का सहायता देने का मन्दय कम-विकसित देशों को अपने अधीन या प्रभाव में

रखना है, वहाँ U. S. S. R. का लक्ष्य कम-विकसित देशों को कम से कम समय में आत्मनिर्भर करना है। लेनिन ने रूस की क्रान्ति से पहले ही कहा था

“हम पिछड़े व दलित देशों की जनता को नि स्वार्थ सहायता देगे. हम उन्हें मशीनों का प्रयोग, श्रम के भार को कम करना तथा समाजवादी प्रजातन्त्र सिखाएँगे ”

(Lenin : Collected Works, Vol 23., p. 67)

सोवियत यूनियन ने 1930's के काल में टर्की को आर्थिक सहायता दी और वहाँ तथा अफगानिस्तान में कपड़ा मिलों की स्थापना की. द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत यूनियन की सहायता बड़ गयी. 1955 में सोवियत यूनियन के सहायता सम्बन्धी समझौते केवल दो देशों से थे—और ये देश थे भारत व अफगानिस्तान, परन्तु सोवियत यूनियन की क्रान्ति की 50 वी वर्षगांठ के अवसर पर उसके अफ्रीका, एशिया व लैटिन अमरीका के 37 देशों से समझौते थे ये देश थे, भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, इन्डोनेशिया, इराक, इरान, यमन, कम्बोडिया, कुवैत, लाओस, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, सीरिया, टर्की, लका, अलजीरिया, धाना, ग्याना, कामारून, केन्या, कांगो, माली, मिश्र, सेनेगाल, सोमालिया, सूडान, तनजानिया, द्यूनीशिया, यूगान्डा, इथोयोपिया, मोरक्को, चिली व ब्राजील.

1967 के अन्त तक सोवियत यूनियन ने कम-विकसित देशों को 4000 million रुबल की सहायता दी थी. इससे 600 औद्योगिक संस्थान शुरू किए गये हैं. इनमें से 220 projects तो पूरे हो ही गए हैं 1956-66 के दस वर्षों में सोवियत यूनियन का कम विकसित देशों से व्यापार छँ गुना बढ़ गया है. सोवियत यूनियन साथ में तकनीकी व सर्वेक्षण की सहायता भी देता है, तथा उसके द्वारा स्थापित उद्योगों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षण भी देता है

इस अध्याय में सोवियत यूनियन द्वारा अन्य साम्यवादी देशों को सहायता इसमें शामिल नहीं है.

See particularly :

1. Bolshakov : Soviet-Indian Economic Cooperation, Soviet Land Books, 1968.
2. Arts & Letters, Daryaganj, Delhi-6, "Indo-Soviet Economic Collaboration " 1955-1965 and other issues of 'News & Views from Soviet Union.'
3. M. Sundar Rajan : Soviet aid and Indo-Soviet Trade - Yojna, June 12, 1966 & many other news items

सोवियत यूनियन द्वारा प्रदत्त ऋणों पर व्याज कम लिया जाना है और उसकी अदायगी वह आयात के रूप में ले लेता है इससे कम-विकसित देशों को ऋणों को वापिस करने में आसानी रहती है वह कम-विकसित देशों में इन उद्योगों के लाभ में से भी कोई हिस्सा नहीं लेता। जो सहायता दी जाती है उसका मुख्य भाग उद्योग स्थापित करने में काम लिया जाता है।

भारत व सोवियत यूनियन :

भारत व सोवियत यूनियन के बीच सर्वप्रथम सहायता सम्बन्धी समझौता 1955 में हुआ, जिसके अन्तर्गत भियाई स्पात कारखाना स्थापित करने का समझौता हुआ। तत्पश्चात् आज 41 projects या योजनाओं में सोवियत यूनियन का योगदान प्राप्त हो रहा है। सोवियत यूनियन ने भारत को 1227 million रुबल की सहायता मिली जो कि 1022 करोड़ रुपये के बराबर है।

41 औद्योगिक projects में से 22 अभी तक पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य करने लगे हैं। इनमें प्रमुख भियाई स्पात कारखाना, रांची का भारी इंजीनियरी के सामान का कारखाना, दुर्गापुर का कोयले की मशीन का कारखाना, हरिद्वार का बिजली का कारखाना, बरीली व फोयाली में तेलशोधक कारखाना, नेवेली में परमल पावर स्टेशन, दाहिने किनारे का भाखरा का बिजली स्टेशन तथा अन्य बहुत से कार्य हैं अब 66 projects में तकनीकी सहायता मिल रही है और 1300 से अधिक विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

सोवियत सहायता से 1968 के शुरू तक भारत में 10 मि० टन स्पात, 50000 टन भारी मशीन, 80 लाख टन तैल, 9000 m. kwh. बिजली तथा 90 लाख टन तेल शोध बनाया गया।

IV. कम-विकसित देशों के लिए आवश्यक सहायता के अनुमान :

भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों तथा "कमेटियो" ने कम-विकसित देशों के लिए उस सहायता के अनुमान लगाए हैं जिसको पाकर वे विकास के पथ पर सुनिश्चित रूप से अग्रसर हो सकते हैं Dr Rao ने इन अनुमानों की तुलना की है।

Chicago Study ने यह अनुमान लगाया था (Chicago university study for the senate committee on foreign aid) कि कम-विकसित देशों को प्रति वर्ष \$ 3 billion की आवश्यकता रहेगी, जिसमें से \$ 1 billion निजी क्षेत्र से प्राप्त हो सकेंगे। 10 या 15 वर्षों में यह मात्रा \$ 5 billion तक हो जाना चाहिए। यह अनुमान केवल गैर-कम्युनिस्ट कम-विकसित

देशों के लिए है. Chicago Study ने यह अनुमान इस मान्यता पर लगाए है कि कम-विकसित देशों में वृद्धि प्रतिशत 9-10% होगी, जनसंख्या वृद्धि केवल 1.5% प्रति वर्ष होगी विनियोजन की दर 14-16% होगी और राष्ट्रीय आय में 3-4% वृद्धि होगी.

Miltikan and Rostow ने, इस आधार पर कि कम-विकसित देशों के साधनों में 30% वृद्धि विदेशी सहायता से कर दी जाए, यह अनुमान लगाया है कि इन्हें \$ 3.5 billion की आवश्यकता रहेगी.

Dr. Rao का वचन है कि यह दोनों अनुमान कम हैं. Tinbergen ने अनुमान लगाया था कि कम-विकसित देशों को प्रति वर्ष \$ 15.2 billion की सहायता आवश्यक होगी. उन्होंने इस मात्रा का अनुमान इन देशों में 5-7% वृद्धि दर तथा 4% विकास दर की मान्यता पर आधारित किया है. यह अनुमान, डा. राव के मत में, अधिक है क्योंकि इसमें वृद्धि की मात्रा कम आई है.

U. N. O. के विशेषज्ञों ने 1951 में Measures for the Economic Development of Under-developed Countries में कम-विकसित देशों के लिए 13.9 billion डॉलर की सहायता आवश्यक समझी (इसमें चीन के लिए सहायता भी शामिल थी).

Dr. Rao के स्वयं के अनुमान के अनुसार समस्त कम विकसित देशों को 7 billion डॉलर की आवश्यकता रहेगी, जिसमें से \$ 4.5 billion गैर कम्युनिस्ट देशों के लिए होगी.

जहाँ तक अधिकतम सहायता के अनुमान का प्रश्न है Frederic Benham ने इसका अनुमान इस प्रकार लगाया है

“समस्त कम-विकसित देशों में (1961 में) 1200 Million जनसंख्या रहती है जिसकी औसत आमदनी \$ 130 प्रति व्यक्ति है. अतः

See :

Dr V. K. R. V Rao : Essays in Economic Development.

Dr O S Shrivastava op. cit : p 55-58

Frederic Benham. } as appended in the end of the chapter.
U. N. O.

M. F Miltikan & W. W. Rostow : A Proposal-Key to an Effective Foreign Policy, Harper, N. Y. 1957. p. 56 ff.

इसे हम \$ 200 प्रति व्यक्ति पहुँचाना चाहे तो \$ 85 billion की आवश्यकता पड़ेगी. इतनी मात्रा में सहायता असम्भव है."

श्री वेन्हम का मत है कि कम से कम हर वर्ष \$ 10 billion सहायता अवश्य दी जाना चाहिए यह सहायता सुनिश्चित तथा सस्ती दर पर दीर्घकाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए

✓ V कम-विकसित देशों के लिए विदेशी सहायता संबंधी नीति के आवश्यक तत्व :

(a) अधिकाधिक सहायता व अनुदान आवश्यक :

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं संयुक्तराष्ट्र महासचिव का कथन है कि हर विकसित देश को अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम एक प्रतिशत अवश्य उधार या दान के रूप में कम-विकसित देशों को देना चाहिए. इसी बात को Dr. Sjafruddin (डा० सफरुद्दीन) जो 1954 में Bank of Indonesia के गवर्नर रहे हैं I.M.F. व I.B.R.D. की बैठक में बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था :

"कम-विकसित देश कोई सुविधा विशेष नहीं मांगते बल्कि वे तो न्यायपूर्ण बर्ताव या हक मांगते हैं.. जो सहायता प्राप्त कर सकते हैं उन्हें सहायता अच्छी है. जो देश व्यापार में मौल-भाव करने की सुदृढ़ स्थिति में हैं. उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हितकर होता है. कम-विकसित देश तो न्यायोचित बर्ताव चाहते हैं. वे विश्व की आय में से न्यायपूर्ण भाग चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को केवल व्यापार की दृष्टि से ही न समझा जाए बल्कि मानवता के दृष्टिकोण से समझा जाए. यह बात भले ही हमारे I. M. F. व I. B. R. D. के जन्मदाताओं के सोचविचार से परे हो परन्तु यह उस जन्मदाता के विचारों के अनुरूप अवश्य होगी जिसने हम सबको जन्म दिया है."

कम-विकसित देशों को अधिकाधिक अनुदान मिलना चाहिए, अन्यथा विकसित व कम-विकसित देशों की आय व विकास के अन्तर कम होने के स्थान पर बढ़ते जाएंगे.

डा० राव के शब्दों में .

"अगर यह मान भी लिया जाए कि कम-विकसित देश हर वर्ष 15% विकास दर को प्राप्त कर लेते हैं तो भी वे 1974 में U. S. A.

Dr. Sjafarudin : quoted from Benjamin Higgins's : op. cit., p. 596.

व कनाडा के 1956 के स्तर के 1/10 को, फ्रांस व U.K. के 1/4 स्तर को और यूरोप व सोवियत यूनियन के 1/3 स्तर को ही पहुँच पायेंगे इस काल में उन्नत देश और उन्नत हो जाएँगे।

यह तो स्थिति उस समय होगी जब कि ये कम-विकसित देश 15% विकास दर को प्राप्त करें। वास्तव में वे तो 3 से 6% विकास दर पर ही चल रहे हैं।

अब तो यह भी आवश्यक है कि विकसित देश कुछ वर्षों के लिए अपने देश के विकास को धन्य रख कर कम-विकसित देशों को सहायता व सहयोग देकर उन्हें अपनी बराबरी पर लाएँ।”

वास्तव में स्थिति यह है कि U S A. की 2% आय वृद्धि से उनके यहाँ 40-45 डॉलर की वृद्धि हो जाती है जब कि कम-विकसित देशों में केवल 2-3 डॉलर की ही वृद्धि होती है।

जहाँ तक हो सके कम विकसित देशों को Grants या अनुदान ही अधिक मिलना चाहिए। अगर कम-विकसित देशों में मुगलान सबधी कठिनाइयाँ हैं अर्थात् उनके निर्यात कम हैं व बढ़ने भी नहीं हैं तथा आयात अधिक हैं और घटते भी नहीं हैं, तो ऐसे देशों को अधिकाधिक अनुदान की ही आवश्यकता होगी ¹

(b) Soft Loans या कम-विकसित देशों की मुद्रा में ही वापस करने वाले ऋण : अनुदान के रूप में समस्त आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो ऋण हों उनमें से अधिकाधिक Soft Loans या कम-विकसित देशों की मुद्रा में ही वापिस करने वाले ऋण होना चाहिए। इससे कम-विकसित देश अपनी वस्तुओं को बेचकर ऋण चुका सकेंगे और उन्हें वापिस करने की समस्या नहीं आएगी। ऋण देने वाले देश इन्हीं ऋणों से फिर अपने दूतावास का

1 “If the economy lacks capacity to transform because of the zero elasticity in expenditure and in import competing industries or if demand abroad has price elasticity of unity or less, which prevents expansion in exports, or if imports are of great importance to the economy—either necessities, such as food materials and fuel, or capital equipment already slated for investment projects—a grant may be needed for overhead projects or a disequilibrium system on the international front cannot be avoided.”

व्यय निकाल सकने हैं। अनुदान लेने में देश की इज्जत कम होती है परन्तु Soft Loans या नरम ऋणों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता

(c) तकनीकी सहायता अधिक मिलना चाहिए :

कम-विकसित देशों को केवल विदेशी सहायता ही पर्याप्त नहीं है। बहुधा उनके प्रयोग के लिए तकनीकी जानकारी भी आवश्यक होती है। इन दोनों प्रकार की सहायता देने में समन्वय होना चाहिए विशेषज्ञों के बगैर तो सहायता भी प्रयोग में नहीं ला पाते इसीलिए विदेशी निजी विनियोजन से यह लाभ होते हैं कि वह अपने विशेषज्ञ स्वयं ले आते हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विदेशी विशेषज्ञ देश के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित कर दें ताकि वे भविष्य में उनका स्थान ले सकें।

आज कोई भी देश अपनी स्वयं की तकनीक पूर्णरूप से उन्नत नहीं कर सकता। “विकास के 50 वर्षों के बाद भी सोवियत यूनियन आज कनाडा, फ्रान्स व अन्य यूरोपीय देशों से पूरे-पूरे plants (या कारखानों) के साथ-साथ तकनीक भी मँगाते हैं ”

(d) Hard loans या विदेशी मुद्रा में वापस करनेवाले ऋणों की चुकाने की शर्तें आसान होना चाहिए।

जो ऋण विदेशी मुद्रा में ही चुकाए जाएँ उनको चुकाने की शर्तें सुलभ होना चाहिए, अर्थात् .

(i) उन पर व्याज की दर कम होनी चाहिए।

(ii) ऋण को दीर्घकालीन होना चाहिए अर्थात् 40-50 वर्ष तक की अवधि होना चाहिए।

(iii) ऋण के शुरु के 10 वर्षों में चुकाने के दायित्व से मुक्त होना चाहिए तथा व्याज या तो विलुप्त न लिया जाये या बहुत कम होना चाहिए।

(iv) अगर आवश्यकता हो अर्थात् कम-विकसित देशों को ऋण चुकाने में कठिनाई हो तो उन्हें कुछ और मुहलत दी जानी चाहिए।

(v) ऋण के साथ राजनैतिक शर्तें नहीं होनी चाहिए

(e) Specific or project loans (कुछ कार्य विशेषों के लिए हो ऋण) तथा general loans (किसी भी कार्य के लिए ऋण) का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए।

वहुत से विकसित देश कम-विकसित देशों को Specific or project loans

अर्थात् कुछ कार्य विशेषो या बड़ी योजनाओं के लिए ही ऋण देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये बड़ी योजनाएँ विकसित देशों का Show piece या दिखावट का नमूना बन जात हैं। सहायता प्राप्त करने वाले देश की जनता दूसरे देश के योगदान को समझ तो सकती है साथ ही साथ यह योजनाएँ विकास के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इसमें जो लाभ होते हैं उनसे पूँजी निर्माण होता है परन्तु ये वे योजनाएँ होनी चाहिए जिन्हें कम-विकसित देश चाहते हैं न कि वे योजनाएँ जो कि विकसित देश स्थापित करना चाहते हैं।

आवश्यकतानुसार विकसित देशों को इस बात की भी स्वीकृति देना चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार उस सहायता को किसी भी कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो उस राशि से उन्हें अन्य देशों से भी ऋण देने की सुविधा होनी चाहिए। विकसित देशों को Cultural aid भी देना चाहिए अर्थात् कम-विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग में सुधार करने में सहायता देना चाहिए तथा पुरानी रुढ़ियों व मान्यताओं को तोड़ने में सहायता देना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण बातें :

- (1) विदेशी सहायता में समन्वय होना चाहिए अर्थात् अलग-अलग विकसित देशों को एक ही प्रकार की सहायता नहीं देना चाहिए। भिन्न-भिन्न देशों की कम-विकसित देशों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ मिल कर पूरी करना चाहिए।
- (II) विकसित देशों को काफी पहले से सहायता का वायदा कर देना चाहिए तथा कम विकसित देशों के प्रति अपने वायदों को पूरी तरह निभाना चाहिए।
- (III) सबसे प्रमुख बात यह भी है कि कम विकसित देशों को सहायता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुधा कम-विकसित देशों की सरकारें फिजूल खर्चों और भ्रष्टाचार के कारण विदेशी सहायता का सदुपयोग नहीं करते और इससे देश में उत्पादन क्षमता में विकास नहीं हो पाता और विदेशी ऋण देश की जनता पर भार बन कर रह जाते हैं।
- (IV) देश की सरकार को अपने साधन जुटाने व उचित विकास नीति अपनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए।

आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का महत्व व सीमाएँ :

आज कोई भी कम-विकसित देश बगैर विदेशी सहायता के विकास नहीं कर सकता।

ह स्वयं सक्षम राष्ट्र अमरिका तथा सोवियत यूनियन विदेशी सहायता के बगर विकास नहीं कर सकते थे

परन्तु जसा कि Mikesell तथा Allen ने कहा है

‘ There is no mechanical relationship between the volume of economic assistance and the rate of economic growth of developed countries Foreign aid is basically a means of helping countries to help themselves ’

(अर्थात् आर्थिक विकास व विदेशी सहायता में कोई सुनिश्चित सह सम्बन्ध नहीं है विदेशी सहायता तो उनकी सहायक होती है जो अपनी सहायता अपना कर लेते हैं)

एसी प्रकार से Frederic Benham का कथन है

आर्थिक विकास केवल विनियोजन की मात्रा पर ही निर्भर नहीं रहता (चाहे यह न्यूनतम आवश्यकता या वाछनीय मात्रा में ही क्यों न हो) और न ही विदेशी सहायता से ही देश स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में पहुँच जाता है इसके साथ देश के प्रयत्न भी महत्वपूर्ण होते हैं

आर्थिक सहायता से देश के विकास में क्या मदद मिली यह केवल उन विशिष्ट योजनाओं के योगदान से ही नहीं नापा जा सकता बरन उन योजनाओं से भी और याजनाएँ आगे बढ़ती हैं विदेशी सहायता से उसी क्षेत्र का ही विकास नहीं होता जिसके लिए सहायता दी गई हो बरन उन क्षेत्रों का भी विकास होता है जो विदेशी सहायता के क्षेत्रों की सहायता से विकसित होते हैं

Dr V K R V Rao के शब्दों में

‘ The net contribution of aid to productive capacity depends in the last analysis on the overall policies pursued by the recipient countries regarding their total disposable resources rather than on merely the form or the specific use of aid resources ’

अतः विकास में योगदान अन्ततः तीन चरमताओं पर निर्भर है य है

(1) विकसित देशों की सहायता देने की क्षमता

- (11) कम विकसित देशों की सहायता को प्रयोग कर सकने की क्षमता तथा
 (111) ऋणों को वापस करने की क्षमता

जहाँ तक प्रथम क्षमता का प्रश्न है वह तो विकसित देशों की इच्छा पर निर्भर करती है और हम देख चुके हैं कि विकसित देशों को और सहायता करना चाहिए दूसरी क्षमता कम विकसित देशों में तकनीकी स्तर व राज्य की नीतियों पर निर्भर रहती है और इसके लिए यह आवश्यक है कि कम विकसित देश सहायता का सदुपयोग करें

Select Bibliography

Apart from the standard works mentioned in earlier chapters, the following references were consulted particularly

- 1 Sir Roy Harrod Aid to Less Developed Countries, Commerce Annual Number, 1965
- 2 Brahmanand Prasad Foreign Aid and Economic Development Commerce, Pamphlet-7 Com June 8 1968
- 3 John Mc Diarmid International Action for Economic and Social Progress Indian Finance, 11 November, 1967
- 4 Woods (President World Bank) The Philosophy of Economic Aid Indian Finance His Lecture in Stockholm on 27th Oct
- 5 Thorkil Kristensen Aid to Under-developed Countries Commerce, Annual Number 1965
- 6 Singer, H W Ch III op cit
- 7 Gaston Ludec International Aid and Growth I E A paper
- 8 Frederic Benham Economic Aid to Under developed Countries Oxford University Press 1961, 37-42 112-18 cf G Meier op cit
- 9 U N O Deptt of Economic and Social Affairs The Capital Development Needs of Less Developed Countries N Y 1962, cf G Meier op cit
- 10 R F Mikesell & L Allen (U S Congress Joint Economic Committee) Economic Policies toward Less developed Countries-Studies Types and conditions of foreign aid , U S Govt , G Meier op cit
- 11 GATT External Financing of the Third Five Year Plan of India G Meier op cit

तीसरी क्षमता देश की उत्पादकता वृद्धि से बढ़ती है इस संबंध में Evsey Domar ने कहा है

'व समस्त व्यक्ति जो राष्ट्र के विदेशों के ऋणी होने के कारण फिर करत है उस लिखते हैं भाषण करते हैं तथा रात वगैर नींद लिए बेचनी से बिताते हैं व अगर उससे आधा समय ही राष्ट्रीय उत्पादकता व आय वृद्धि में लगावें तो समाज का कल्याण भी करेंगे और अनेक समस्या के हल करने में भी सहायक होंगे जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो राज्य की आय करो द्वारा स्वयं ही बढ़ जाती है जिससे ऋण का भार कम हो जाता है।



-
- 12 U N O 'On making foreign aid more effective' I E A Paper G Meier op cit
 - 13 Benjamin Higgins Ch 26 op cit
 - 14 Kindleberger Ch 17
 - 15 Meier & Baldwin Ch 19 op cit
 - 16 Y Bolshakov Soviet Indian Economic Cooperation Soviet Land Books 1968
 - 17 Arts & Letters 57, Daryaganj, Delhi-6 Indo Soviet Economic Collaboration 1955-1965
 - 18 K S Bhatia Soviet Land Booklets 1968 Soviet-Indian Cooperation in Agriculture
 - 19 Free Press Journal Feb 14, 1969 'U S Economic Assistance to India till Jan 1969
 - 20 Manubhai Shah Foreign Know-How Pros & Cons Commerce, Sept 14 1968.
 - 21 G L Mehta Development and Foreign Collaboration
 - 22 O S Shrivastava op cit p 55 60
 - 23 V K R V Rao Essays in Economic Development
 - 24 V K R V Rao & Dharam Narain Foreign Aid and India's Economic Development, Asia 1963
 - 25 Patriot Sept 27, 1966

विदेशी पूँजी व आर्थिक विकास

Role of Foreign Capital in Economic Development

I प्रस्तावना :

विदेशी पूँजी का योगदान व महत्व.

II. कम-विकसित देशों में विदेशी पूँजी के लाने में कठिनाइयाँ.

III. विदेशी पूँजी को कम-विकसित देशों में लाने के लिए आवश्यक बातें.

IV. कम-विकसित देशों के विकास में विदेशी पूँजी के योगदान की सम्भावित हानियाँ और सीमाएँ.

भारत का विकास व विदेशी पूँजी

I. मात्रा.

II. देश जहाँ से पूँजी प्राप्त हुई है.

III. भारत की नीति व प्रयत्न.

IV. समस्यावधि.

V. रायल्टी व लाभान.

विदेशी पूँजी व आर्थिक विकास

Role of Foreign Capital in Economic Development

I. प्रस्तावना :

योगदान व महत्व :

जैसा कि हम जानते हैं, कम-विकसित देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशों से पूँजीगत व उपभोग वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। अगर यह न मिले तो उपभोग कम रहेगा अथवा वचत व पूँजी कम रहेगी और ऐसे कार्य शुरू नहीं किए जा सकते, जो देश के विकास में सहायक हों।

हम देखते हैं कि कम-विकसित देशों को जहाँ विदेशी-मुद्रा की आवश्यकता होती है, वह मुख्यतया निर्यात, अनुदान व ऋण से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी भी महत्वपूर्ण साधन रहती है।

आजकल लगभग \$ 2 billion की वार्षिक विदेशी पूँजी कम-विकसित देशों में लगाई जाती है। विश्व के आज जो विकसित देश हैं वे भी कभी विदेशी पूँजी की सहायता से विकसित हुए थे। सोवियत यूनियन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि सभी देशों के विकास में विदेशी पूँजी सहायक रही है। ब्रिटेन ने 17वीं व 18वीं सदी में हालैंड से बहुत पूँजी प्राप्त की थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी 19वीं सदी में योरोप से पूँजी प्राप्त की थी। कनाडा ने 1900-1930 के बीच यू० के० व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से पूँजी प्राप्त की थी और इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज भी कनाडा, जो विश्व में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार, कुवैत व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद स्थान रखता है, विदेशी पूँजी का शुद्ध आयातकर्ता है।

See : References quoted in the previous chapters

U. N. "Process and Problems of Industrialisation of Under-developed Countries." 1951.

D. B. Singh : ch. XII, "External Capital : The Problem of Utilization."

अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन में विदेशी पूँजी के योगदान या महत्व को हम निम्नलिखित सूत्रों में बाँध सकते हैं :

1. विदेशी विनियोजन से देश की वास्तविक आय में वृद्धि होती है देश का पूँजी निर्माण बढ़ता है. अगर विदेशी पूँजी न आये तो कम-विकसित देशों के देश-वासियों को अपने उपभोग को कम करके पूँजी निर्माण करना पड़ता है. हम "पूँजी-निर्माण" के अध्याय में देख चुके हैं कि आज के युग में उपभोग को कम करके पूँजी-निर्माण करना बहुत से आर्थिक सामाजिक कारणों में संभव नहीं होगा.
2. विदेशी पूँजी के विनियोजन से Healthy precedent अर्थात् अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है और फिर और अधिक विदेशी पूँजी आने लगती है. प्रथम बार विदेशी विनियोजक हिचकते हैं और जब पूँजी आने लगती है तथा उसके द्वारा संचालित उद्योगों को पर्याप्त सुविधा मिलती रहती है तो विदेशी विनियोजन से काफी विकास की संभावना बढ़ जाती है. विदेशी पूँजी के आगमन का Demonstration effect भी होता है.
3. विदेशी पूँजी के विनियोजक कम-विकसित देशों में लाभ अर्जित करते हैं (जब कि श्रमणों पर व्याज दिया जाता है) और इसके लिए बहुधा वे अपने मैनेजर तथा तकनीकी विशेषज्ञ साथ लाते हैं. वे जो उन्नत तकनीक लाते हैं उससे देश में तकनीकी उन्नति होती है तथा वे देश में श्रमिकों व प्रशासकों को भी प्रशिक्षित करने हैं.
4. विदेशी विनियोजक से देश के विनियोजकों को भी विनियोजन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है. बहुधा विदेशी पूँजी के विनियोजन से देश में कुछ वस्तुएँ ऐसी पैदा होने लगती हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल बन जाती हैं और इससे देश के उद्योगों में विनियोजन बढ़ जाता है. कुछ आवश्यक कच्चे-माल या मशीनों को अगर यह विदेशी विनियोजक देश में ही उत्पादन करने लगते हैं तो और विदेशी मुद्रा व्यय किए या कम व्यय में ही, ये देश में औद्योगीकरण को संभव कर देते हैं.
5. विदेशी पूँजी वैसे तो तब देश में आती है जब कि देश में पहले से ही "बाह्य मितव्ययिताएँ" मौजूद हों परन्तु कभी-कभी विदेशी पूँजी भी देश में Infra-structure or external economies "बाह्य मितव्ययिताओं" का सृजन करती है.
6. विदेशी पूँजी से देश में मुद्रा स्फीति विहीन विकास संभव होता है अगर विदेशी पूँजी देश में न आती हो तो हम पाते हैं कि बचत से ज्यादा विनि-

योजन करने से (होनार्य प्रवन्धन करके) देश में मुद्रा स्थिति फैलती है विदेशी पूँजी के आने से यह सम्भावना समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है परन्तु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि

(1) विदेशी पूँजी से जो उत्पादन हो वह शीघ्र हो. तथा

(11) अगर उत्पादित सामान विदेशों में भेज दिया जाय तो देश के उपभोग के लिए आयात भी हो

7. विदेशी पूँजी के विनियोजक देश में बहुधा कुछ विशिष्ट कार्य या योजनाओं (Specific projects) में धन लगाते हैं. ये Specific projects देश में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विकास को बढ़ावा देते हैं.

8. विदेशी पूँजी के आने से देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति भी सुधरती है भुगतान सतुलन को विपन्न में जाने से रोकती है या पक्ष में लाती है. इससे कम-विकसित देशों की "भुगतान की शर्तें" सुधरती हैं कम-विकसित देश बहुधा विदेशी मुद्रा कमाने के लिए जल्दी से निर्यात कर देते हैं परन्तु अगर वह बहुमूल्य मुद्रा विदेशी पूँजी से प्राप्त हो जाती है तो ये कम-विकसित देश कुछ ठहर जाते हैं और मूल्य स्थिति सुधरने पर ही बेचते हैं और इस प्रकार से उनकी "भुगतान की शर्तें" सुधरती हैं. विदेशी पूँजी के आने से कम-विकसित देशों की मोल-भाव करने की शक्ति सुधरती है

9. विदेशी पूँजी से राज्य को विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त "लाभ पर कर" भी प्राप्त होता है जनता को सस्ते मूल्य पर वे वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं जो उन्हें या तो नहीं मिल पाती या फिर महँगी मिलती है.

10 सक्षेप में विदेशी पूँजी के आने से देश में उपभोग, वचत, पूँजी-निर्माण, उत्पादन, लाभ, रोजगार व आय बढ़ती है

D B Singh के शब्दों में

"Foreign capital helps in promoting economic development in the usual multiplier way"

See also : (1) G Meiers's Note on "The Contribution of Private Foreign Investment", op cit ch. III

(2) H Higgins . op cit

(3) Meier & Baldwin : op cit.

(4) H W. Singer : op cit.

(5) O S Shrivastava : op cit

II. कम-विकसित देशों में विदेशी पूंजी लाने में कठिनाइयाँ :

आज बहुत से कम-विकसित देश चाहते हैं कि विदेशी पूंजी उनके देश में आए परन्तु इसकी राह में कई रुकावटें हैं उनमें मुख्य ये हैं

1. बहुत से कम-विकसित देश में राजनैतिक अस्थिरता बनी रहती है। वियतनाम, कोरिया तथा नाइजीरिया में तो युद्ध ही चलता रहा है। स्वतन्त्रता के बाद कांगो में भी विध्वंस की क्रियाएँ चलती रही। पाकिस्तान में भी प्रेसीडेंट अयूब के सम्बन्धे शासनकाल से पहले 8—प्रधान मंत्री बदले, जब कि भारत में श्री नेहरू ही प्रधान मंत्री बने रहे। वर्मा, इरान, इराक, सीरिया आदि देशों में भी निरन्तर क्रान्तियाँ हुईं, ६० अमेरिका में तो तख्तापलट साधारण बात है। ऐसी स्थिति में विदेशी विनियोजक हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं रहता कि वे लाभ कमा सकेंगे या नहीं तथा लाभ को अपने देश भेज सकेंगे कि नहीं। राष्ट्रीयकरण का भी डर बना रहता है।
2. कम-विकसित देशों में मुद्रा स्थिति बहुत रहती है। इससे देश की मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है। गिरते हुए मूल्यों के स्थान पर विकसित देशों के विनियोजक स्थिर मूल्य स्तर या मुद्रामूल्य वाले देशों को पसन्द करते हैं।
3. कम-विकसित देश बहुधा विदेशी विनियोजकों पर कुछ समय बाद भेदभाव पूर्ण कर लगाने लगते हैं और उन्हें अपने सार्वभौमिक अधिकारों को भी पूर्णरूप से अपने देश से नहीं से जाने देते। कम-विकसित देश, अपनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई के कारण, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करते हैं और इस कारण विदेशी विनियोजकों को कठिनाई होने लगती है।
4. बहुधा कम-विकसित देशों के प्रशासन की खाली फीताशाही का भी विदेशी विनियोजक शिकार हो जाते हैं।
5. बहुधा कम-विकसित देश विदेशी विनियोजकों को आवश्यक कच्चा माल विदेशों से नहीं मँगाने देते हैं।
6. आज के युग में कम-विकसित देशों में धर्म संगठित है और बहुधा विदेशी विनियोजकों को राज्य धर्म संकट मुलम्मानों में सहायता नहीं करते।

“In recent years payment defaults, currency instability, exchange control, expropriation risks, restrictive labour laws, discriminatory taxation, government competition with private enterprise, joint participation, regulation etc. have all acted as deterrents to private and government foreign investment.” (O. S. Shrivastava : op. cit. : p. 58.)

7. विदेशी विनियोजकों के लिए साधनों, बाजार व अन्य आर्थिक घटकों के संबंध में जानकारी (*based on surveys and research*) प्राप्त नहीं होती.
8. "विदेशी विनियोजकों का कम-विकसित देशों में अधिकाधिक विनियोजन करना केवल अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की पूर्ति का ही प्रश्न नहीं है, वरन् माँग पक्ष भी महत्वपूर्ण है. बहुत से कम-विकसित देश, जो हाल में ही साम्राज्यवादियों की गुलामी से आजाद हुए हैं, विदेशी पूँजी के प्रति शक्ति रहते हैं कुछ देशों में यह भावना जम गई है कि "विदेशी-एकाधिकारी-पूँजीपति-साम्राज्यवादियों को इन देशों के "सम्पन्न साधनों" का लाभ न सूटने दिया जाए ¹
9. कम-विकसित देश बाढ़ में अनुचित रूप में विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयकरण कर लेते हैं और या तो मुआवजा देते नहीं हैं या कम देते हैं या देर से देते हैं. इन्डोनेशिया व केन्या के उदाहरण सामने हैं. आज केन्या से कई भारतीयों को निकाला जा रहा है, वर्मा ने भी भारतीयों को वगैर पर्याप्त मुआवजा दिए निकाल दिया और यही बात लंका ने भी की है
10. वेन्जामिन हिगिन्स के शब्दों में, एक और डर इन देशों में *Creeping expropriation* का है (अर्थात् धीरे धीरे सम्पत्ति जप्त्त करने का डर) यह मुख्यतया भेदभावपूर्ण नीति के कारण होता है जिससे कि विदेशी विनियोजक पर्याप्त लाभ नहीं कमा पाते या हानि उठाने लगते हैं ²

भारत के सम्बन्ध में हिगिन्स ने लिखा है कि

"भारत में हर प्रशासनिक निर्णय देर में लिया जाता है. आयात, निर्मात व विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रहता है. जनता तथा बहुत सी राजनैतिक पार्टियाँ रोज ही विदेशी विनियोजकों को "शोषक" के रूप में प्रस्तुत करते रहने हैं. भारत के व्यापारियों की व्यापार पद्धतियाँ उनकी समझ से परे रहती हैं. भारत ने अभी भी बहुत से देशों से दुहरे कर न लगने के समझौते नहीं किए हैं तथा यहाँ पर प्रशिक्षित श्रमिक व सामाजिक आर्थिक सिरोपरि व्ययों की कमी है."

III. विदेशी पूँजी को कम-विकसित देशों में लाने के लिए आवश्यक बातें

जैसा कि साधारणतया कहा जाता है "Remove the cause, remove the evil" अर्थात् कारण को समाप्त कर दो, बुराई स्वयं ही समाप्त हो जाएगी.

1. B Higgins : op cit. p. 593-4

2. " op cit p 582-3.

इसी प्रकार से कम-विकसित देशों में अगर विदेशी पूँजी को अधिकाधिक लाना है तो जिन अवरोधों के कारण पूँजी कम आती है उन्हें दूर करना होगा।

कम-विकसित देशों में अगर विदेशी पूँजी अधिकाधिक आए तो इसके लिए यह जरूरी है कि कम-विकसित देश उन्हें सुविधाएँ दे और विदेशी विनियोजक कम-विकसित देशों की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य करें

ECAFE (Economic Commission for Asia and Far East) ने विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर दल दिया है

- 1 देश में राजनैतिक स्थिरता हो
- 2 देश में जन-जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था हो
- 3 देश में लाभ कमाने के अवसर मौजूद हो
- 4 जब तक कि विदेशी विनियोजक अपनी पूँजी वसूल न कर ले तब तक उनकी पूँजी का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए और जब राष्ट्रीयकरण हो तो उचित मुआवजा चुकाया जाना चाहिए
- 5 लाभ को अपने देश भेजने पर रुकावट नहीं होना चाहिए.
6. विदेशी विनियोजकों को अपने प्रशासक व तकनीकी व्यक्ति रखने की अनुमति होना चाहिए तथा तकनीक अपनाने की सुविधा होना चाहिए.
- 7 कार्य के शुरू के वर्षों में कर कम होना चाहिए तथा कभी भी विभेदपूर्ण कर नहीं लिए जाना चाहिए
- 8 दुहरे कर (दोनों देशों की सरकारों द्वारा) नहीं लगना चाहिए
9. राज्य को अनुचित नियंत्रण लगाना व प्रतिযোগिता नहीं करना चाहिए
- 10 संक्षेप में, राज्य को विदेशी विनियोजकों के प्रति दोस्ती का व्यवहार रखना चाहिए

U.N.O. की आर्थिक काउन्सिल ने यह सिफारिश की है कि कम-विकसित देशों की सरकारों को "व्यापारिक ओखियों" के अतिरिक्त और समस्त ओखियों के प्रति "बीमा" प्रदान करना चाहिए. कर में छूट देने से ही काम नहीं चलता भेदभाव पूर्ण नीति का छोड़ना तथा लाभ कमाने देना बहुत महत्वपूर्ण है

See : U. N. "Economic Commission for Asia and Far East Committee on Industry and Trade, Second Session, Foreign Investment, Laws and Regulation in Ecafe Region" Bangkok, March 1950. p 4-5.

“The attraction of private foreign investment now depends less on fiscal action, upon which most countries have concentrated and more on other conditions and measures that guarantee protection of investment and provide wider opportunities for the foreign investment. If private investment is to be encouraged, it is necessary to allay the investor's concern over the possibilities of discriminatory legislation, exchange control, threats of expropriation. Investment guarantees may be utilized more effectively to lessen the investor's apprehension of non-business risks”

साथ ही विकसित देशों के विनियोजकों को चाहिए कि उनका विनियोजन विकास योजना के अनुरूप हो न कि कम-विकसित देशों की विकास योजना उनकी विनियोजन योजना के अनुरूप हो।

अगर अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन भी U.N.O की भांति किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से समन्वित रूप से हो तो यह और भी उपयुक्त होगा।

आज विश्व में संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, यू० के०, फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य पश्चिम योरोपीय देश विश्व के कम-विकसित देशों को पूँजी निर्यात करते हैं। आज जो भी पूँजी विदेशों में लगाई जाती है, उसमें एशिया का हिस्सा, जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम रहता है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के विनियोजकों ने जो विनियोजन विदेशों में किए हैं उसका 40% कनाडा में, 30% द० अमेरिका में, 15% योरोप तथा उनके अधीनस्थ देशों में तथा बाकी का 15% अन्य क्षेत्रों में (जिनमें एशिया व अफ्रीका शामिल हैं) लगाया। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का अधिकारा विनियोजन पेट्रोल उद्योग में है, फ्रांस ने लगभग सभी विनियोजन अफ्रीका में किया है। इसलिए यह आवश्यक है कि पूँजी को विस्तृत क्षेत्रों में लगाया जाए।

बहुधा यह कहा जाता है कि कम-विकसित देशों में, सामाजिक आर्थिक सरोपरि

सुविधाओं की कमी के कारण विनियोजन के अवसरों व लाभ कमाने के अवसरों की कमी है परन्तु National Industrial Conference Board of American Businesses ने 1951 में बताया कि विश्व में 54% विदेशी विनियोजन करनेवाली 107 में से 89 फर्में यह मानती थी कि विदेशी विनियोजन में अच्छी आय कमाई जा सकती है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के Department of Commerce ने यह जानकारी दी कि U. S. A. ने भारत, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, फिलीपाइन्स में 227 million dollars के शुद्ध विनियोजन पर कर देने से पहले 133 million dollars कमाए थे, जो कि शुद्ध विनियोजन के 58% के बराबर था।

IV. कम-विकसित देशों के विकास में विदेशी पूंजी के योगदान की सम्भावित हानियाँ और सीमाएँ

विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कम विकसित देशों को कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। बहुधा विदेशी विनियोजकों को सस्ती दरों पर पानी, जमीन या बिजली की सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। कर सबधी छूटें भी देनी पड़ती हैं। यह सब प्रत्यक्ष लागतें हैं।

कभी कभी विदेशी विनियोजक कम-विकसित देशों में उद्योगों को नहीं पतनने देते। उनसे अनुचित प्रतिযোগिता करते हैं। देश के विनियोजकों के लाभ कम कर देते हैं। इससे देश में बचन व पूंजी-निर्माण के स्तर गिर जाते हैं और देश और अधिक विदेशी विनियोजन का आश्रित हो जाता है।

विदेशी विनियोजक कभी-कभी राज्य को अपने प्रभाव में ले लेते हैं (रोडेशिया में खान के मालिकों का प्रभाव रहा, कटाणा में विदेशी विनियोजकों का ही एक प्रकार से राज्य था) देश में अर्थिकों का व देश के साधनों का शोषण करते हैं और जो

cf : 1 Study of Factors Limiting American Private Investment—Summary of Preliminary Findings and Recommendations, Deptt. of Commerce, July 1953, p. 5 quoted from Capital Formation and Foreign Investment in Under-developed Areas : Wolf and Sufrin, 1958, p. 53.

2 S. A. Paleker op cit : 119-138.

3. O. S. Shrivastava : op. cit. p. 57-58.

See : H. W. Singer : The Distribution of Gains Between Investing and Borrowing Countries, American Economic Review—

I. E. A. Papers and Proceedings, May 1950

लाभ कमाते हैं उन्हें अपने देश में ले जाते हैं और कम-विकसित देशों में ही विनियोजन करके उनके विकास में सहायता नहीं करते

विदेशी विनियोजकों द्वारा जब पूँजी या लाभ वाहर ले जाया जाती तो देश पर बहुत भार पड़ जाता है और व्यापार की शर्तें विपक्ष में जाती हैं

भारत का विकास व विदेशी पूँजी

I. मात्रा

अन्य देशों के विकास में योगदान की भाँति, विदेशी पूँजी का भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है 1965 के अन्त तक भारत में 936 करोड़ रु० की विदेशी पूँजी लगी थी. 1948-61 के बीच भारत में विदेशी पूँजी का विनियोजन 157% से बढ़ गया था और 1961 में यहाँ 680 करोड़ की विदेशी पूँजी लगी थी. भारत की तीन योजनाओं के काल में 625 करोड़ रु० की पूँजी विदेशों में आई अर्थात् योजना काल में जितना विनियोजन निजी क्षेत्र ने किया उसका 25% भाग विदेश में आया था

II. देश

भारत में जो विदेशी पूँजी लगी है उसका अधिकांश भाग यू० के० से आया है. भारत में 1967-68 के अन्त तक 2200 विदेशी सहयोग के सम्झौते हुए उसमें

Select references : For latest views and data

- (1) Reserve Bank of India Report on "Foreign Collaboration in Indian Industry" This gives data upto 1967-68. It is the most comprehensive and latest study For this analysis see Ch VI particularly—Published in late 1968
- (2) T. V. Sethuraman "Foreign Investment in India" Yojana, June 23, 1968,
- (3) G. L. Mehta "Development & Foreign Collaboration" Indian Econ Conference Paper, Dec. 1968—Golden Jubilee Session—Madras
- (4) D. T. Lakdawala : "Foreign capital & Development." as above
- (5) M. V. Arunachalam . Development and Foreign Collaboration. as above and all reference mentioned earlier.

से 1051 प्रभावशील हो गए थे. इन 1051 Collaboration या सहयोग योजनाओं में से अलग-अलग देशों का योगदान Subsidiary Companies (विदेशी कम्पनियों की शाखा के रूप में), Minority participation of foreign Capital (भारतीय कम्पनियों में 50% शेयर से कम की हिस्सेदारी) तथा Technical Collaboration (या तकनीकी सहयोग) के रूप में रहा है. पेट्रोल, यातायात सामान, बिजली का सामान, रसायन, दवाएँ आदि के उद्योगों में प्रथम दो प्रकार का सहयोग है जब कि मशीन, मशीन टूल्स, धातु तथा कपड़ा उद्योग में तकनीकी सहयोग रहा है

निम्नलिखित तालिका में भिन्न-भिन्न देशों के योगदान के आँकड़े दिए हैं .

The Countrywise Classification of Agreements.

Country	Subsidiaries	Minority Participation	Tech Collaboration	Total
1 U K.	81	181	158	420
2 U S A	24	86	84	194
3. West Germany	7	74	68	149
4. Switzerland	9	25	32	66
5 Japan	1	17	33	51
6 France	3	16	16	35
7. Netherland	3	13	8	24
8 Sweden	7	6	5	18
9. East European Countries	—	—	25	25
10. Others	9	27	33	69
	144	445	462	1051

R. B. I. Study, 1968 : op. cit.

उपरोक्त 1051 समझौतों में से 1006 औद्योगिक उत्पादन के लिए, 11 वायान, खान व पेट्रोल के तथा 34 अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में थे, 1006 औद्योगिक उत्पादन समझौतों का विवरण इस प्रकार है :

1. मशीन व मशीनी औजार	250.
2. रसायन	177
3. बिजली का सामान	162
4. यातायात सामान	115
5. धातु व धातु का सामान	107
6. बुनाई मिला (सूती व अन्य)	59.
7. साध व पेय	12.
8. अन्य	124.
	<hr/> 1006.

(Ibid)

III भारत की नीति :

म्राजादी के तुरन्त बाद भारत में विदेशी विनियोजन को बुरा तो नहीं माना जाता था परन्तु उसको प्राप्त करने के लिए भारत ने पहल नहीं की है. प्रथम योजना में यही नीति रही द्वितीय योजना काल में 1956-57 में ही प्रथम योजना काल के बराबर विदेशी विनिमय का प्रयोग किया गया और इस काल में विदेशी पूँजी को आमंत्रित किया गया. तृतीय योजना में तो बड़े उत्साह से इसका स्वागत किया गया

Dr. D T. Lakdawala के शब्दों में

“The Indian attitude to foreign capital, as it came to be slowly formed, was ambivalent. The instinctive hostility to foreign capital was greatly tempered by a recognition at least in the modern sector of the important role it plays and the lacunae its absence would create.”

तृतीय योजना में ही भारत सफट में बढ गया इस काल में दो विदेशी आक्रमण हुए, दो प्रधानमन्त्री स्वर्गवासी हुए और दो सूखे के वर्ष पड़े भारत में विदेशी पूँजी के आने की मात्रा कम होने लगी जिसके और कम होने का डर होने लगा. कुछ तो विश्व में ही पूँजी की कमी थी¹ और कुछ भारत की परिस्थितियाँ भी

1. Arunachalam's (op cit) observation :

“Currently in the context of world shortage of capital, it is almost purple to imagine that there awaits a flood of foreign capital to inundate and enliven our moribund Capital market.”

प्रतिकूल थी. भारत में पूँजी आने की सम्भावनाओं के कम होने के निम्नलिखित कारण हैं

1. भारत में हाल के वर्षों में राजनैतिक अस्थिरता है. लगभग हर प्रान्त में आगजनी, विध्वंस व अराजकता बढ़ाकर छा जाती है.
2. भारत में वैको के राष्ट्रीयकरण से भी विदेशी विनियोजक भयभीत हो सकते हैं.
3. भारत में पिछले वर्षों में मुद्रास्फोट के कारण भी भारतीय मुद्रा का मूल्य गिरा है. इससे विदेशी विनियोजक उत्साहित नहीं होते क्योंकि उनकी लागतें बढ़ जाती हैं
4. आजकल भारत का पूँजी बाजार भी तेजी में नहीं है
5. बहुत से विदेशी विनियोजक भारत में "Minority Participation" को पसन्द नहीं करते वे 50% से अधिक के शेयर के मालिक बनना चाहते हैं

भारत ने विदेशी पूँजी को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं यह कदम मुख्य रूप से 1957 के बाद उठाए गए हैं. विदेशी पूँजी को आयात कर, सम्पत्ति कर, सुपर टैक्स, वेतन पर कर पर कुछ विशेष रियायतें दी गई हैं. उनकी राखतों पर 'कारपोरेशन टैक्स' भी घटा दिया गया है. बहुत से देशों से दोहरे कर न लगने के समझौते भी किए गए हैं. भारत में विदेशी विनियोजकों के विनियोजन प्रश्नों पर गौर किया जाता है और 1964 के बाद से इसकी पद्धति भी सरल कर दी गई है और इसी कारण जैसा कि डा० लकड़ावाला का कथन है

"हम इन वर्षों में जो कठिनाई व इम्तहान के दौर में गुजरे हैं उसमें हमारा साथ विदेशी विनियोजकों ने छोड़ा नहीं है."

इतना अवश्य है कि विदेशी विनियोजकों ने कुछ शर्तें बहुत अनुचित लगा रखी हैं, जैसे कि कुछ देशों से आयात नहीं कर सकते अथवा कुछ देशों को निर्यात नहीं कर सकते

IV. Duration या समयावधि

भारत में 30 समझौते तो अनिश्चित काल के लिए हैं तथा 13% समझौते दस वर्ष की अवधि के ऊपर के हैं. अन्य समझौते 10 वर्ष या इससे कम के लिए किए गए हैं.

V Royalty and dividend payment रायल्टी व लाभांश-भुगतान

जिन उद्योगों में विदेशी विनियोजक मालिकियत रखते हैं उनमें उन्हें dividend या लाभांश प्राप्त होता है और जिनमें तकनीकी सलाह देते हैं या पेटेंट को प्रयोग में लाने की अनुमति देते हैं तो उन्हें रायल्टी मिलती है निम्नलिखित तालिकाएँ इससे संबंधित जानकारी प्रदान करती हैं

Distribution of royalty agreements linked to value of sales/production

%Rate of royalty	No of agreements
0—2	78
2—3	153
3—4	72
4—5	199
5 and above	67
	<u>569</u>

Table showing dividend remittances and royalty Crores of rupees

Year	Dividend	Royalty
1960—61	11 38	1 51
61—62	14 14	1 92
62—63	18 35	2 32
63—64	16 11	3 35
64—65	20 58	4 95
65—66	19 58	6 40
66—67	21 50	7 97
	<u>122 01</u>	<u>28 42</u>

Countrywise royalty

Between 1960-61 to 1966-67 (Crores of rupees)

U. K	11.19
U. S. A.	9.26
West Germany	4.28
Others	3.69
	<hr/> 28.42

R Bank of India के 1966 की एक रिपोर्ट के अनुसार U K. व U. S.A. ने 1958-62 के बीच अपने विनियोजनों पर क्रमशः 9 व 12% कमाया. विदेशी विनियोजक भारत में औसततः 6% लाभ या रायल्टी कमाते हैं.

अध्याय : 15

पूँजी-निपज अनुपात

Capital-Output Ratios

- I पूँजी-निपज अनुपात व उसके प्रकार.
- II. पूँजी-निपज अनुपात की विशेषताएँ.
- III. पूँजी-निपज अनुपात के अध्ययन व प्रयोग का महत्व.
- IV. पूँजी-निपज अनुपात के प्रयोग की सीमाएँ.
- V विकसित व कम-विकसित देशों में पूँजी-निपज अनुपात.

पूँजी-निपज अनुपात

Capital-Output Ratios

I. Meaning of Capital-Output Ratios and Types : पूँजी-निपज अनुपात व उसके प्रकार

George Rosen के अनुसार

“पूँजी-निपज अनुपात (Capital-output ratio or Capital Co-efficient) किसी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था या उद्योग में होने वाले विनियोजन व उसी वर्ष में होनेवाली उपज में सह सम्बन्ध बतलाता है ”

Capital-output ratio कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य हैं

- (i) Average capital-output ratio या औसत पूँजी-निपज अनुपात
- (ii) Incremental capital-output ratio (ICOR) या वृद्धि पूँजी निपज अनुपात
- (iii) Marginal capital-output ratio या सीमान्त पूँजी-निपज अनुपात
- (iv) Gross capital output ratio या कुल पूँजी-निपज अनुपात
- (v) Net capital-output ratio या शुद्ध पूँजी-निपज अनुपात
- (vi) Sectoral capital-output ratio या क्षेत्रीय पूँजी-निपज अनुपात तथा
- (vii) Capital-output ratio of the economy या सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पूँजी-निपज अनुपात.

इनके अर्थ यह हैं

Average C-O Ratio

यह अनुपात वह है जो किसी समय में पूँजी व उत्पत्ति में सह-सम्बन्ध दर्शाता है.

All references appended at the end of the chapter

इसको निकालने के लिए हमको एक वर्ष की कुल पूँजी में कुल आय से भाग देना पड़ता है

Average capital-output ratio is the value of the total stock of capital \div by total income.

Incremental capital-output ratio

यह अनुपात विकास आयोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है यह अनुपात किसी वर्ष में होने वाले पूँजी-निर्माण तथा उस पूँजी-निर्माण से अगले समय में उत्पादित शुद्ध उत्पादन के सम्बन्ध को बतलाना है बैसे तो किसी भी पूँजी विनियोजन से प्रनिफल कुछ समय बाद मिलता है परन्तु सुविधा के लिए हम इस सम्बन्ध में उसी काल के उत्पादन में सम्बन्ध निकाल लेते हैं।

Incremental capital output ratio is the value of the addition to the stock of capital (Net investment) \div by addition to income or net national income

अर्थात् वृद्धि पूँजी-निपज अनुपात निकालने के लिए किसी समय के शुद्ध अतिरिक्त पूँजी निर्माण में उस समय की शुद्ध आय वृद्धि से भाग करते हैं।

Gross Capital-Output Ratio and Net Capital-Output Ratio

“कुल पूँजी-निपज अनुपात” देश की कुल अचल पूँजी व कुल उत्पादन का सम्बन्ध है तथा शुद्ध पूँजी-निपज अनुपात देश की कुल अचल पूँजी तथा शुद्ध उत्पादन (अर्थात् कुल उत्पादन में से कच्चे माल, ईंधन व घिसावट आदि निकालने के पश्चात्) के बीच अनुपात बतलाता है

Overall Capital-output Ratio or For the Economy as a Whole

सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पूँजी-निपज अनुपात भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के C O. Ratios का औसत होता है जिसको हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उपज वृद्धि से weight देते हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण अनुपात भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार या weight पर निर्भर रहता है। यह भार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की पूँजी-माहृतता के अनुपात में दिया जाता है

W. B. Reddaway ने क्षेत्रीय पूँजी-निपज अनुपात निकालने के लिए निम्न-लिखित Summary या सारांश रूपी विवरण प्रस्तुत किया है

किसी भी देश में कुल पूँजी की आवश्यकता नापने के लिए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के पूँजी-निपज अनुपात को जानना बहुत आवश्यक होता है परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं यह अनुपात हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हमका भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के पूँजी-निपज अनुपात भानूम न हो

C.P. Kindleberger ने C.O. Ratio तथा Marginal Efficiency of Capital (M.E.C.) में अन्तर बतलाया है, जहाँ C.O. Ratio सम्पूर्ण पूँजी या पूँजी वृद्धि व सम्पूर्ण उत्पादन या उत्पादन वृद्धि में (जिसमें कि अन्य स्थिर या परिवर्तनशील उत्पादन अंगों को ध्यान में नहीं रखा जाता) सम्बन्ध बतलाता है, M. E. C में केवल विनियोजन वृद्धि से उत्पादन वृद्धि (जब कि अन्य अंगों की मात्रा स्थिर हो) का सम्बन्ध मापते हैं.

एक क्षेत्र की दो समयों के बीच की उत्पात्ति को इस प्रकार से बाँटना चाहिए

- (I) वह उत्पत्ति वृद्धि जिसमें अधिक पूँजी लगाए बगैर, अर्थात् उन्नत रीति प्रयोग करके उत्पादन बढ़े (इसे हम P for Progress से दर्शाएँ)
- (II) वह उत्पत्ति वृद्धि जो किसी कारखाने की मशीनों का, माँग बढ़ने के कारण, पूर्ण प्रयोग करने से होती है. (D for Higher production due to demand).
- (III) दो शिफ्ट या पालियों में कार्य करने से उत्पादन वृद्धि (S).
- (IV) अच्छे व अनुकूल मौसम से उत्पादन वृद्धि (W)
- (V) क्षेत्र विशेष में उचित तकनीकी अनुपात रहे जैसे श्रम की कमी न हो आदि अगर हम क्षेत्र की पूँजीगत लागत (X) मानें व पूँजी-उत्पादन

$$\text{अनुपात को } (r) \text{ मानें तो वार्षिक उत्पादन वृद्धि} = \frac{X}{r}$$

Investment किसी समय विशेष में विनियोजन की मात्रा (X) बराबर होगी, जिसमें हमें नवीनीकरण का व्यय (M) Modernization expenditure जोड़ना होगा तथा जिसमें \pm Time Lag या पूँजीगत व्यय को शुरू कर के समाप्त करने के अन्तर को adjust करना होगा.

तब Marginal capital-output ratio for a sector =

$$\frac{X+M+L}{\frac{X}{r}+P+D+S+W.}$$

(W. B. Reddaway, The Development of the Indian Economy, Homewood, 1962, p. 207-8.)

II. Main Characteristics and Features of C-Os.

पूँजी-निपज अनुपात की विशेषताएँ :

पूँजी-निपज अनुपात कभी स्थिर नहीं रहते भिन्न-भिन्न देशों में पूँजी-निपज अनुपात अलग-अलग रहते हैं कहीं वे अधिक होते हैं तो कहीं पर कम होते हैं—फिर एक ही देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पूँजी-निपज अनुपात अलग-अलग रहते हैं, इसके अतिरिक्त एक ही क्षेत्र, उद्योग व देश में समयान्तर से यह अनुपात गिर जाते हैं या बढ़ जाते हैं

निम्नलिखित पृष्ठों में उन तत्वों का वर्णन है जिनसे पूँजी निपज अनुपात बढ़ते या घटते हैं

पूँजी-निपज अनुपात किन परिस्थितियों में अधिक रहेंगे :

निम्नलिखित परिस्थितियों में पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहेंगे पूँजी-निपज अनुपात तब अधिक होता है जब पूँजी अधिक लगती हो व उत्पादन कम होता हो

1. अगर देश में भारी उद्योगों की स्थापना हो रही हो अथवा देश में भारी *Infra-Structure* या बाह्य मितव्ययिताओं पर या आर्थिक-सामाजिक सिरो पर व्यय हो रहा हो (This is called lumpy investment also) तो पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा.
2. अगर देश में विकास के लिए या किसी कारण (जैसे युद्धोपरात या बाढ़ व भूकम्प की बरबादी के बाद) मकानों, सार्वजनिक निर्माण व *public utilities* में (सार्वजनिक सेवा उद्योग) में विनियोजन हो रहा हो तो पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा.
3. अगर देश में कृषि के मुकाबले में उद्योगों को तथा छोटे उद्योगों के मुकाबले में बड़े उद्योगों को अधिक महत्व दिया जा रहा होगा तो पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा
4. अगर किसी देश में उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं अर्थात् देश में *Excess capacity* मौजूद है तो देश में पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा इसीलिए मन्दी काल में पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहता है.
5. अगर उद्योगों का फलदायक काल देर से शुरू होता है अर्थात् *gestation period* अधिक है तो भी पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा.
6. अगर देश में कर वृद्धि से, या मजदूरी वृद्धि से अथवा कच्चे माल की लागत

वृद्धि से पूँजीगत वस्तुओं (मशीनों) की लागत व कीमत बढ़ जाती है तो पूँजी-निपज अनुपात बढ़ जाएगा

7. अगर उत्पात्ति में ह्रास नियम लागू हो रहा हो तो उपज कम होने से पूँजी-निपज अनुपात बढ़ जाता है
8. औद्योगीकरण की शुरू की अवस्था में पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहता है क्योंकि भारी उद्योगों में धन लगाया जाता है परन्तु अगर विकास के साथ साथ पूँजीगहन तकनीकें भी अपनाई जाती रहें तो पूँजी-निपज अनुपात घटेगा नहीं वरन् बढ़ता ही जाएगा, जैसे U S A में हुआ है U S A में पूँजी-निपज अनुपात इस प्रकार रहा है

1879	2.98	1
1884	3 01	: 1
1889	3 21	1
1894	3 59	1
1899	3 85	1
1950-59	5 3	1

8. अगर देश में श्रम व संगठनकर्ता अनुशल* या कम कुशल है तो उत्पादकता कम होने से भी पूँजी-निपज अनुपात बढ़ जाते हैं.

पूँजी निपज अनुपात कम कम होते हैं .

पूँजी-निपज अनुपात उस समय कम होने है जबकि पूँजी कम लगे और उत्पादन अधिक हो इस प्रकार से जो परिस्थितियाँ ऊपर व्यक्त की गई हैं उनके विपरीत स्थितियों में पूँजी-निपज अनुपात कम होता है संशेष में यह स्थितियाँ इस प्रकार हैं

1. अगर देश में श्रम गहन तकनीक अपनाई गई हो.
2. अगर देश में सस्ती तकनीक अपनाई गई हो
3. अगर देश में उद्योग अपनी पूर्ण क्षमतानुसार उत्पादन कर रहे हो
4. अगर देश में श्रम उत्पादकता अधिक हो.
5. अगर उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा हो.
6. अगर उद्योगों का फलदायक काल शीघ्र शुरू हो रहा हो.

* विकास के साथ पूँजी-निपज अनुपात बढ़ेगा भयना घटेगा, इस संबंध में पाठक Leibenstein के मॉडल में पढ़ ही चुके हैं

7. अगर देश में नए साधनों का पता लग रहा हो.
8. अगर देश में आन्तरिक व बाह्य मितव्ययिताएँ उपलब्ध हो
9. अगर देश में कृषि व छोटे उद्योगों में अधिक विनियोजन हो रहा हो तो देश में पूँजी-निपज अनुपात कम रहेगा.

III Importance of the Study And Use of Capital-output Ratios पूँजी-निपज अनुपात के अध्ययन व प्रयोग का महत्व

पूँजी-निपज अनुपात का प्रयोग हम देश में पूँजी निर्माण की मात्रा निर्धारित करने के लिए करते हैं. इनके निकालने में कठिनाईयाँ अवश्य हैं परन्तु फिर भी इनके प्रयोग से हम अनुमानित विनियोजन में सम्भावित उत्पादन निकाल सकते हैं. अल्पकाल में पूँजी-निपज अनुपात बहुत अस्थिर रहते हैं परन्तु दीर्घकालिक आयोजन में हम इनका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं.

सर्वप्रथम तो यह अनुपात हमको देश में आवश्यक विनियोजन की मात्रा आकने में मदद करता है. अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय \$ 50 हो, जनसंख्या वृद्धि 1.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो, धनत्व की मात्रा राष्ट्रीय आय का 4% हो और पूँजी-निपज अनुपात 4:1 हो तो न्यूनतम विनियोजन की मात्रा जो कि अर्थव्यवस्था को उसी स्तर पर रखेगी 5.33% होगी.

इसी माप्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2% विकास के लिए 20% तथा 5% विकास के लिए 40% विनियोजन आवश्यक होगा.

पूँजी-निपज अनुपात मुख्यतः पूँजी की सामाजिक उत्पादकता दर्शाते हैं. भिन्न भिन्न क्षेत्रों व उद्योगों के पूँजी-निपज अनुपात के सम्भावित आकड़ों से हम भिन्न भिन्न उद्योगों या क्षेत्रों की पूँजी गहनता का अनुमान लगाते हैं. इससे हमको विनियोजन की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने में सहायता मिलती है.

पूँजी निपज अनुपातों के दीर्घकालीन अध्ययन से हमको भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता की प्रवृत्ति का पता चलना है (We can have an insight-into efficacy of factor combination also). इस अध्ययन से हम यह भी जान सकते हैं कि उत्पादन के किन अंगों की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए अथवा किनमें कमी की जानी चाहिए.

-
1. पूँजी निर्माण के अध्याय में भी आप C O. ratios के अध्ययन का महत्व पढ़ ही चुके हैं.

ICOR (Incremental capital-output ratios) या वृद्धि पूँजी-निपज अनुपात का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानिया अपनाना चाहिए वेन्जामिन हिगिन्स ने यह सावधानिया अपनाने को कहा है -

- 1 ICOR को निकालने के काफी समय के आकड़े (कम से कम 5 साल के) मौजूद होना चाहिए, अगर संभव हो तो एक सम्पूर्ण व्यापार-वक्र को इकाई मानकर ICOR निकालना चाहिए.
 2. जिस काल के ICOR निकाले जा रहे हो वह "सामान्य काल" होना चाहिए अर्थात् न तो वह अधिक उत्पादकता या कम उत्पादकता या अधिक या कम लागत का काल होना चाहिए.
 - 3 यह ध्यान में रखना चाहिए कि ICOR के आधार पर आयोजन के विनियोजन की मागें निर्धारित होनी हैं तो स्वयं आयोजन से ICOR भी परिवर्तित हो जाता है
 - 4 ICOR का प्रयोग केवल पूँजी की माग को आकड़े के लिए करना चाहिए. इससे प्राथमिकताएँ निर्धारित नहीं करना चाहिए अर्थात् अधिक ICOR के कारण किसी विनियोजन योजना को भीची प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए.
 5. जहाँ तक संभव हो ICOR को बहुत सही निकालना चाहिए
- संक्षेप में पूँजी-निपज अनुपात से हम किसी विनियोजन की लागत-लाभ अनुपात जानने के लिए पता लगाते हैं

IV. Limitations of the concept पूँजी-निपज अनुपात के प्रयोग की सीमाएँ

पूँजी-निपज अनुपात के महत्व पर लिखने वाले समस्त लेखक यह मानते हैं कि पूँजी-निपज अनुपात को सही रूप में निकालना कठिन है और फिर इसके प्रयोग से बहुत अधिक महत्व के निष्कर्ष भी नहीं निकाले जा सकते.

U. N. O. की रिपोर्ट के अनुसार

"यह अनुपात हमको यह नहीं बतला सकता है कि किसी एक विनियोजन से पूँजी-निपज के अनुपात के अनुसार ही उत्पादन होगा. यह अनुपात सह-संबंध की प्रवृत्ति ही बतलाता है कोई निष्कर्षात्मक सिद्धान्त नहीं देता." (The ratio does not imply a causal theory it indicates only a statistical association between investment and output.)

Dr D. Bright Singh का भी कथन है :

“विनियोजन व उत्पादन में कोई निश्चित सरलात्मक सम्बन्ध नहीं है अगर पूँजी-निपज अनुपात से यह अर्थ निकाला जाए तो यह भ्रमात्मक है सहो-सहो पूँजी-निपज अनुपात तो एक उद्योग के लिए निकालना ही कठिन होता है, सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए तो निकाल सकने का प्रश्न ही नहीं होता किसी देश में इस प्रकार के अनुमानित पूँजी-निपज अनुपात से न तो पूँजी की आवश्यक मात्रा और न ही उससे प्राप्त होनेवाली विकास-दर माँकी जा सकती है” (यह सम्पूर्ण विचार Nebulous गौहारिका समान है और घमाम्य है)

पूँजी निपज अनुपात को ठीक से न नाप सकने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ सामने आती हैं

1. सर्वप्रथम तो यह बठिनाई ही सामने आती है कि पूँजी की क्या परिभाषा ली जाए—यह व्यापक हो प्रथवा संकुचित हो बगैर इसको तय किए पूँजी की मात्रा ही नहीं निकाल सकते.
2. इसी प्रकार उत्पादन का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है बिजली के कारखाने में लगी पूँजी में बिजली का ही उत्पादन नहीं होता वरन् उससे अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ता है, फिर उससे अन्य क्षेत्रों के उत्पादन और फिर अन्य क्षेत्रों का उत्पादन प्रभावित होता है, इससे किस विनियोजन का क्या उत्पादन रहा यह बताना कठिन हो जाना है.
3. ‘समय’ को समस्या भी महत्वपूर्ण है. सामान्यतया जो विनियोजन होता उसके प्रतिफलस्वरूप उत्पादन कुछ समय बाद होता है हर विनियोजन में फलदायक काल शुरू होने में समय लगता है विनियोजन व उत्पादन के तीन रूप हो सकते हैं

(1) एक बार विनियोजन करें और उत्पादन निरन्तर होता रहे (Investment at a point of time with continuous production)

(II) एक बार विनियोजन हो और एक बार उत्पादन हो. (Point input and point output),

(III) निरन्तर विनियोजन हो व निरन्तर उत्पादन होता रहे. (Continuous investment and continuous production).

इस कारण यह समस्या होती है कि काल के विनियोजक का कौन सा उत्पादन माना जाए, सामान्यतया हम एक ही काल के विनियोजन व उत्पादन से पूँजी-निपज अनुपात निकालते हैं परन्तु ऐसा करे तो बहुत भ्रमात्मक परिणाम निकल सकते हैं जैसे जंगल लगवाने पर पूँजी 1960-1961-1962 में खर्च की जाए और उससे लाभ 1970-71 से मिलना शुरू हो तो वास्तव में 1970-71 में समस्त उत्पादन के लिए उस वर्ष में विनियोजन तो शून्य ही था और अगर उपरोक्त आधार पर पूँजी-निपज अनुपात निकालें तो परिणाम, जैसा कि जाहिर है, अति भ्रमात्मक होगा.

Kindleberger का कथन है

“When an economy undertakes all three types of investments i.e. point input and point output investment, continuous input and continuous output and point input and continuous output, the capital-output ratio that relates this year's output to this year's investment is evidently wide off the mark.”

- 4 इसके अतिरिक्त पूँजी-निपज अनुपात ऐसे कारणों से भी परिवर्तित हो सकता है जिनका सम्बन्ध पूँजी से हो ही नहीं जैसे अच्छे मौसम के कारण भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में उम्मीद से अधिक उत्पादन हुआ और उस कारण योजना में तो पूँजी निपज अनुपात 3:1 सोचा गया था पर वास्तव में वह 2:1 ही रह गया.

इन्हीं सब कारणों में पूँजी-निपज अनुपात के महत्व की सीमा है और इसी बात को हम George Rosen, Benjamin Higgins तथा Gerald Meier के शब्दों को उद्धृत कर व्यक्त कर सकते हैं.

C. F. Kindleberger * op cit p 103

He also says : “Capital output ratio is not useful for fine work. Its drawbacks include ambiguity over whether to take output net or gross, the problem of associating given outputs with given investment, whether by sectors or in time and disassociating simple growth based on capital investment from changes in output produced by changing technology, discovery of land etc.”

George Rosen :

"कम पूँजी-निपज अनुपात स्वयं में कोई आकर्षक बात नहीं है जो विनियोजन के निर्णयों को प्रभावित करे कम पूँजी-निपज अनुपात को प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीक छोड़कर पिछड़ी तकनीक नहीं अपनाई जा सकती."

Benjamin Higgins .

"इस पूँजी-निपज अनुपात का ख़तरा सोचे समझे प्रयोग नहीं करना चाहिए इसके माँवने में भी बहुत भी कठिनाइयाँ हैं."

"The use of ICOR is beset by pitfalls which must be carefully avoided if serious errors are to be prevented"

Gerald Meier भी कहते हैं

"पूँजी व उत्पादन में कारण व परिणाम रूपक सह सम्बन्ध नहीं है हम यह भी नहीं कह सकते कि समस्त उत्पादन पूँजी से ही होता है."

There are many conceptual difficulties and statistical pitfalls which surround the deviation and use of capital-output ratios."

V. Capital-Output Ratios in Developed and Under-developed Countries : विकसित व कम-विकसित देशों में पूँजी-निपज अनुपात .

पूँजी-निपज अनुपात विकसित व कम-विकसित देशों में कम रहते हैं या अधिक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता. कहीं पर यह अनुपात विकसित देशों में अधिक होता है (मुख्यतया पूँजी-गहन तकनीक अपनाने के कारण) तथा कहीं कम रहता है (मुख्यतया अधिक उत्पादकता के कारण) कहीं कम-विकसित देशों में उत्पादकता की कमी के कारण (कम पूँजी गहन तकनीक के होते हुए भी) पूँजी-अनुपात अधिक रहता है.

George Rosen : "Industrial Change in India " Asia , 1951, p 38.

B. Higgins - op. cit. p 652.

G. Meier : op. cit. p 101

निम्नलिखित तालिकाओं में इससे सम्बन्धित जानकारी देखी जा सकती है
1950-1959 के बीच कुछ देशों में ICOR

प्रथम श्रेणी के देश (\$ 500 प्रतिव्यक्ति से ऊपर आय वाले)

नार्वे	8 9	कनाडा	6 0
न्यूजीलैंड	7 8	बेल्जियम	6 0
फिनलैंड	7 0	नोदर्लैंड	5 3
डनमार्क	6 7	यू एस ए	5 3
ग्रास्ट्रोनिया	6 5	प जर्मनी	3 1
यू के	6 1		

द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के देश (\$ 350 to 499 and \$ 200 to 349 per-capita income)

अर्जेंटाइना	17 0	यूगोस्लाविया	3 2
पुर्तगाल	4 0	चिली	3 1
प्यूरटोरिको	3 7	जापान	3 0
इटली	3 6	इजराइल	2 2
ग्रीस	3 3		

चतुर्थ श्रेणी के देश (\$ 200 प्रतिव्यक्ति आय से कम)

भारत	5 5	बर्मा	3 7
यू ए आर	4 8	इक्वडोर	3 0
रोडेशिया	4 2	द कोरिया/टर्की/फारमोसा	2 5
बोलिविया	4 2	ब्राजील	2 3
लक्सा	4 0	इन्डोनेशिया/फिलीपींस/चीन	1 6

(B) सामान्यतया यह समझा जाता है कि कम-विकसित देशों में कृषि व अन्य क्षेत्रों में कम पूँजीग्रहण तकनीक के कारण पूँजी-निपज अनुपात कम रहेगा परन्तु निम्नलिखित तालिका को अध्ययन करें तो हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते.

1946-47

उद्योग	भारत	ऑस्ट्रेलिया	कनाडा	न्यूजीलैंड
गेहूँ	1.83	1.31	.35	
फल व सब्जी	1.44	.74	.85	
शक्कर	1.49		.86	
पेन्ट व बारनिश	.38	.52	.74	.89
सीमेन्ट	1.75		3.97	.87
कपड़ा	.58		.67	
इस्पात	1.30		1.04	

भारत के सम्बन्ध में पूँजी-निपज स्थिति निम्न तालिका से देखी जा सकती है :

करोड़ रुपये में

	1948 के मूल्या पर		तृतीय योजना में 1960-61 मूल्या पर
	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	
1. योजना के शुरू में राष्ट्रीय आय	8850	10480	14500
2. योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय	10480	12530	19000
3. वृद्धि (उत्पादन) (2-1)	1630	2050	4500
4. शुद्ध विनियोजन	3360	6750	10400
5. पूँजी-निपज अनुपात 4 ÷ 3	2.06	3.29	2.31